



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 106]

नई दिल्ली, बुधस्वतिवार, मार्च 3, 2011/फाल्गुन 12, 1932

No. 106]

NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 3, 2011/PHALGUNA 12, 1932

कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 मार्च, 2011

सा.का.नि. 179(अ).—केन्द्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 210क की उपधारा (1) और धारा 211 की उपधारा (3ग) के साथ पठित धारा 642 की उपधारा (1) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, लेखा मानक पर राष्ट्रीय सलाहकार समिति के परामर्श से, कंपनी (लेखा मानक) नियम, 2006 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कंपनी (लेखा मानक) संशोधन नियम, 2011 है।
- (2) ये ऐसी तारीख को प्रवृत्त होंगे जिसे केन्द्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे और कंपनियों के विभिन्न वर्गों के लिए विभिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी।
2. कंपनी (लेखा मानक) नियम, 2006 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल नियम कहा गया है) की परिभाषा में, खंड 'ग' के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-

“उपाबंध से इन नियमों का उपाबंध अभिप्रेत है”।

3. मूल नियम के नियम 3 में,-

- (i) विद्यमान उपनियम (1) और उपनियम (2) को क्रमशः उपनियम (3) और उपनियम (4) के रूप में पुनःसंख्यांकित किया जाएगा ;
- (ii) पुनःसंख्यांकित उपनियम (3) में, “उपाबंध” शब्द के स्थान पर “उपाबंध ख” शब्द और अक्षर रखे जाएंगे ;
- (iii) पुनःसंख्यांकित उपनियम (3) में, के पूर्व निम्नलिखित उपनियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

(i)

“(1) केन्द्रीय सरकार, भारतीय लेखा मानक (भा.ले.मा.) के नाम से ज्ञात उपानियम (4) में विनिर्दिष्ट कंपनियों द्वारा आवेदन के लिए उन लेखा मानकों को विहित करती है, जो इन नियमों के उपाबंध क में विनिर्दिष्ट हैं और जो कंपनियों के निम्नलिखित वर्ग को लागू होंगे।

(I) बीमा कंपनियों, बैंककारी कंपनियों और गैर बैंककारी वित्त कंपनियों से भिन्न कंपनियां

- (अ) क. वह कंपनियां जो एन.एस. ई. की भाग हैं -- निफ्टी 50
 ख. वह कंपनियां जो बी. एस. ई. की भाग हैं -- सेंसेक्स 30
 ग. वह कंपनियां जिनके शेयर या अन्य प्रतिभूतियां भारत के बाहर स्टाक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध हैं।
 घ. वह कंपनियां, चाहे वह सूचीबद्ध हों या नहीं, जिनका शुद्ध मूल्य 1,000 करोड़ रुपए से अधिक है।

(आ) कंपनियां चाहे सूचीबद्ध हों या नहीं जिनका शुद्ध मूल्य 500 करोड़ रुपए से अधिक है किंतु 1,000 करोड़ रुपए से अनधिक है ;

(इ) सूचीबद्ध कंपनियां जिनका शुद्ध मूल्य 500 करोड़ रुपए या उससे कम है।

(II) बीमा कंपनियां, बैंककारी कंपनियां और गैर बैंककारी वित्त कंपनियां।

(अ) बीमा कंपनियां ;

(आ) (क) सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक और वे शहरी सहकारी बैंक (यू.सी.बी.एस.) जिनका शुद्ध मूल्य 300 करोड़ रुपए से अधिक है ;

(ख) शहरी सहकारी बैंक जिनका शुद्ध मूल्य 200 करोड़ रुपए से अधिक है किंतु 300 करोड़ रुपए से अनधिक हैं।

(इ) क. गैर बैंककारी वित्त कंपनियां जो एन.एस.ई.-निफ्टी 50 की भाग हैं ;

ख. गैर बैंककारी वित्त कंपनियां जो बी.एस.ई.-सेंसेक्स 30 की भाग हैं ;

ग. गैर बैंककारी वित्त कंपनियां चाहे सूचीबद्ध हो या नहीं जिनका शुद्ध मूल्य 1,000 करोड़ रुपए से अधिक है।

(ई) सभी सूचीबद्ध गैर बैंककारी कंपनियां और वह असूचीबद्ध गैर बैंककारी वित्त कंपनियां जो उपरोक्त प्रवर्गों में नहीं आती हैं और जिनका शुद्ध मूल्य 500 करोड़ रुपए से अधिक हैं।

(2) कोई कंपनी जो उपाबंध “क” में विनिर्दिष्ट लेखामानकों का अनुसरण करती है, केवल ऐसे ही मानकों का अनुसरण करेगी, न कि उन मानकों का जो उपाबंध में “ख” में विनिर्दिष्ट हैं। कोई कंपनी जो उपाबंध “ख” में विनिर्दिष्ट लेखा मानकों का अनुसरण करेगी न कि उन मानकों का जो उपाबंध “क” में विनिर्दिष्ट है।

(iv) उपनियम (4) के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा:-

“परंतु आईएफआरआईसी 4 और आईएफआरआईसी 12, जहां कहीं किंहीं भी भारतीय लेखा मानक (भा.ले.मा.) में निर्दिष्ट किया गया है वहां अधिसूचित की जाने वाली तारीख से लागू होगा।”

(4) मूल नियमों में, विद्यमान उपाबंध को उपाबंध “ख” के रूप में नामित किया जाएगा और इस प्रकार पुनःनामित उपाबंध “ख” से पूर्व निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“उपाबंध ‘क’

(नियम 3 देखिए)

[भारतीय लेखा मानक (भा.ले.मा.)”

भारतीय लेखा मानक (इंड ए एस) 2**सूचीबद्ध सामान****(इन्वेंट्रीज)**

(इस भारतीय लेखा-मानक में मोटे टाइप व सामान्य टाइप में अनुच्छेद हैं। इन दोनों तरह के अनुच्छेदों का समान प्राधिकार है। मोटे टाइप में अनुच्छेद, मुख्य सिद्धान्तों के सूचक हैं।)

उद्देश्य

1. इस लेखा मानक का उद्देश्य सूचीबद्ध सामान (इन्वेंट्रीज) के लिए लेखा प्रक्रिया निर्धारित करना है। सूचीबद्ध सामान के लेखा में मुख्य मुद्दा लागत की राशि को एक आस्ति के रूप में मान्यता देना है तथा इसे आगे तब तक ले जाना है जब तक संबंधित राजस्व को मान्यता न दे दी जाती। यह मानक लागत के निर्धारण तथा निवल वसूलीयोग्य मूल्य में किसी अपलेखन सहित किसी व्यय के रूप में बाद की मान्यता का वर्णन करता है। यह उन लागत फार्मूलों का भी वर्णन करता है जिन्हें सूचीबद्ध सामान (इन्वेंट्रीज) की लागत के निर्धारण करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है।

कार्यक्षेत्र

2. यह मानक निम्नलिखित को छोड़कर सभी सूचीबद्ध सामान (इन्वेंटरी) पर लागू होता है :-

- (क) प्रत्यक्ष रूप से संबंधित सेवा संविदाओं सहित निर्माण संविदाओं से उत्पन्न निर्माणाधीन कार्य (देखिए भारतीय लेखा मानक (इंड ए एस) 11 ' निर्माण संविदाएं ');
- (ख) वित्तीय लिखतें (देखिए भारतीय लेखा मानक (इंड ए एस) 39 ' वित्तीय लिखतें: मान्यता एवं माप ' और भारतीय लेखा मानक 32 ' वित्तीय लिखतें: प्रस्तुतिकरण '); तथा
- (ग) कृषि -संबंधी गतिविधियां एवं फसल की कटाई के समय कृषि पैदावार से संबंधित जैविक आस्तियां (अर्थात् जीवित पशु या पौधे) (देखिए भारतीय लेखा मानक (इंड ए एस) 41 ' कृषि ' ¹

¹ (देखिए भारतीय लेखा मानक (इंड ए एस) 41 ' कृषि ' अभी तैयार किया जा रहा है।

3. यह मानक निम्नलिखित के सूचीबद्ध सामान (इंवेंट्रीज) के माप पर लागू नहीं होता है :-

- (क) कृषि व वन उत्पादों, फसल के बाद कृषि उत्पाद, और खनिजों व खनिज उत्पादों के उत्पादक, बशर्ते ये उत्पाद उस सीमा तक मापे जाते हैं जिस सीमा तक इस प्रकार के उद्योगों की सुस्थापित प्रथाओं / व्यवहारों के अनुसरण में निवल वसूली योग्य मूल्य मापा जाता है। जब ये सूचीबद्ध सामान (इंवेंट्रीज) निवल वसूली योग्य मूल्य पर मापे जाते हैं तो उनके इस मूल्य में परिवर्तन, परिवर्तन की अवधि के लाभ या हानि में, माना जाता है।
- (ख) पण्य (वस्तु) दलाल विक्रेता जो अपने सूचीबद्ध सामान (इंवेंट्रीज) को बिक्री लागत से घटाकर उचित मूल्य पर मापते हैं। जब ये सूचीबद्ध सामान बिक्री लागत घटाकर उचित मूल्य पर मापे जाते हैं तो बिक्री लागत घटाकर उचित मूल्य में परिवर्तन, परिवर्तन के दौरान लाभ या हानि, में माना जाता है।
4. अनुच्छेद 3 (क) में संदर्भित सूचीबद्ध सामान (इंवेंट्री) को उत्पादन के किन्हीं चरणों में निवल वसूलीयोग्य मूल्य पर मापा जाता है। उदाहरण के लिए, यह तब होता है जब कृषि की फसलें काट ली जाती हैं अथवा खनिज निकाल लिये जाते हैं और किसी वायदा संविदा अथवा सरकारी गारंटी के अधीन उसकी बिक्री सुनिश्चित हो अथवा जब एक सक्रिय बाजार उपलब्ध हो या फिर बिक्री की असफलता के जोखिम न के बराबर हो। ऐसे में इस सूचीबद्ध सामान (इंवेंट्रीज) को इस मानक के माप के कार्यक्षेत्र से हटा दिया जाता है।
5. दलाल-व्यापारी वह है जो अन्य व्यक्तियों की ओर से अथवा अपनी ओर से वस्तुओं का क्रय अथवा विक्रय करता है। अनुच्छेद 3 (ख) में संदर्भित सूचीबद्ध सामान (इंवेंट्री) मुख्यतः शीघ्र ही भविष्य में बिक्री के उद्देश्य तथा कीमत में उतार-चढ़ाव अथवा व्यापार की दलाली में मार्जिन से लाभ अर्जित करने के लिए अधिगृहीत किया जाता है तब उसे इस मानक के माप के कार्य क्षेत्र से हटा दिया जाता है। जब इस सूचीबद्ध सामान (इंवेंट्री) को उचित मूल्य से बिक्री की लागत घटाकर मापा जाता है तो उसे इस मानक के माप से हटा दिया जाता है।

परिभाषाएं

6. इस मानक में निम्नलिखित शब्दावली का प्रयोग यहां विनिर्दिष्ट अर्थों में किया गया है :-
सूचीबद्ध सामान (इंवेंट्रीज) निम्नलिखित के रूप में आस्तियां हैं -

- क) व्यवसाय के सामान्य व्यवहार में बिक्री के लिए रखा गया सामान;
- ख) ऐसी बिक्री के लिए उत्पादन प्रक्रिया में सामान ; या
- ग) उत्पादन प्रक्रिया या सेवाएं प्रदान करते समय उपभोग में लायी जाने वाली सामग्रियाँ या आपूर्तियाँ ।

निवल वसूली -योग्य मूल्य - व्यवसाय के सामान्य व्यवहार में वह अनुमानित विक्रय कीमत है जिसमें से कार्य पूरा होने तक की अनुमानित लागत और विक्रय करने के लिए आवश्यक अनुमानित लागत को घटाया जाता है।

उचित मूल्य - वह राशि जिस पर ज्ञानवान व इच्छुक पक्षों के बीच एक आस्ति का विनिमय या एक देयता का भुगतान एक स्वतंत्र लेन देन के रूप में किया जा सकता है।

7. निवल वसूली योग्य मूल्य उस निवल राशि को कहते हैं जिस पर एक प्रतिष्ठान व्यवसाय के सामान्य व्यवहार में सूचीबद्ध सामान (इवेंट्री) की बिक्री से वसूल करने की अपेक्षा करता है। उचित मूल्य उस राशि को परिलक्षित करता है जिस पर उसी इवेंट्री को बाजार में ज्ञानवान तथा इच्छुक क्रेता और विक्रेता के बीच विनिमय किया जा सकता है। इन दोनों में पहली राशि प्रतिष्ठान विशिष्ट है जबकि दूसरी राशि प्रतिष्ठान विशिष्ट नहीं है। सूचीबद्ध सामान का निवल वसूली योग्य मूल्य बिक्री की लागत को घटाकर उचित मूल्य के बराबर नहीं हो सकता।
8. सूचीबद्ध सामान (इवेंट्री) में क्रय तथा पुनः बिक्री के लिए रखी गयी वस्तुएं सम्मिलित होती हैं। उदाहरण के लिए, एक खुदरा व्यापारी द्वारा क्रय किया गया व्यापार का सामान अथवा पुनः बिक्री के लिए रखी गयी भूमि या अन्य संपत्ति ' इवेंट्री ' में सम्मिलित है। सूचीबद्ध सामान (इवेंट्री) में प्रतिष्ठान द्वारा निर्मित वस्तुएं निर्माणाधीन वस्तुएं और वह सामग्री या आपूर्ति भी शामिल है जो उत्पादन प्रक्रिया में उपयोग में लायी जाती है। एक सेवा प्रदानकर्ता के मामले में, सूचीबद्ध सामान (इवेंट्री) में अनुच्छेद 19 में यथावर्णित सेवा की लागत भी सम्मिलित है जिसके लिए प्रतिष्ठान ने अभी संबंधित राजस्व को मान्यता नहीं दी है। (देखिए भारतीय लेखा मानक 18 राजस्व)

सूचीबद्ध सामान (इवेंट्रीज) का माप

9. सूचीबद्ध सामान का माप, लागत व निवल वसूली-योग्य मूल्य, इन दोनों में जो भी कम है, उस पर किया जाएगा।

सूचीबद्ध सामान (इवेंट्रीज) की लागत

10. सूचीबद्ध सामान (इवेंट्री) की लागत में, सभी क्रय लागतें, सपरिवर्तन लागतें तथा सूचीबद्ध सामान को वर्तमान स्थान व स्थिति तक लाने की लागतें सम्मिलित की जाएंगी।

क्रय लागतें

11. सूचीबद्ध सामान की क्रय लागतों में, क्रय कीमत, आयात शुल्क और अन्य कर (लेकिन बाद में प्रतिष्ठान के द्वारा कर अधिकारियों से यदि कोई वसूली योग्य राशि प्राप्त की जाती है तो उसे छोड़कर), परिवहन, आदान-प्रदान और ऐसी अन्य लागतें जो तैयार वस्तुओं, सामग्री व सेवाएं अर्जित करने में प्रत्यक्ष रूप से निहित होती हैं, सम्मिलित होंगी। लेकिन, इस सभी के बाद, व्यापार बढ़ते (छूट) और ऐसी ही अन्य रियायती मदें क्रय लागत के निर्धारण के समय घटा ली जाती हैं।

संपरिवर्तन लागतें

12. सूचीबद्ध सामान की संपरिवर्तन लागतों में उत्पादन इकाइयों से प्रत्यक्षतः संबंधित लागतें (जैसे कि प्रत्यक्ष श्रम) शामिल होती हैं। इसमें वे उपरिव्यय भी सम्मिलित हैं जो कि सामग्री को तैयार माल में परिवर्तन करने के लिए स्थिर और परिवर्तनशील उत्पादन के लिए एक व्यवस्थित आबंटन द्वारा खर्च किए जाते हैं। स्थिर उत्पादन उपरिव्यय वे अप्रत्यक्ष लागतें हैं जो उत्पादन सापेक्ष नहीं हैं यानि, उत्पादन की मात्रा भले कोई भी हो वे स्थिर रहती हैं, जैसे कि कारखाना भवनों एवं उपस्करों का अवक्षयण (मूल्यह्रास), अनुरक्षण (रखरखाव) और कारखाना प्रबंधन व प्रशासन खर्च। परिवर्तनशील उत्पादन उपरिव्यय वे प्रत्यक्ष लागतें हैं, जो उत्पादन की मात्रा से सीधी या लगभग सीधी जुड़ी होती हैं और उत्पादन सापेक्ष हैं यानि उत्पादन की मात्रा के अनुसार हैं और परिवर्तित होती रहती हैं, जैसे की अप्रत्यक्ष सामग्रियां और अप्रत्यक्ष श्रम।
13. संपरिवर्तन की लागतों में, स्थिर उत्पादन उपरिव्यय का आबंटन उत्पादन सुविधाओं की सामान्य क्षमता पर आधारित होता है। सामान्य क्षमता सुनियोजित रखरखाव के परिणामस्वरूप उत्पादन क्षमता की हानि पर ध्यान देते हुए, सामान्य परिस्थितियों के अंतर्गत कुछ अवधियों या मौसमों में औसत तौर पर प्राप्त करने के लिए प्रत्याशित उत्पादन है। उत्पादन के वास्तविक स्तर का भी प्रयोग किया जा सकता है, बशर्ते यह सामान्य क्षमता के आसपास हो। उत्पादन की प्रत्येक इकाई को आबंटित स्थिर उत्पादन उपरिव्यय की रकम, कम उत्पादन या अप्रयुक्त संयंत्र के परिणाम स्वरूप नहीं बढ़ती। अनाबंटित उपरिव्यय, जिस अवधि में, खर्च किए जाते हैं उन्हें व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है। असामान्य तौर पर, अधिक उत्पादन की अवधियों में उत्पादन की प्रत्येक इकाई को आबंटित स्थिर उत्पादन उपरिव्यय की रकम घटती है, जिसे सूचीबद्ध सामान की लागत से ऊपर नहीं मापा जाता। परिवर्तनशील उत्पादन उपरिव्यय, उत्पादन सुविधाओं के वास्तविक प्रयोग के आधार पर उत्पादन की प्रत्येक इकाई को आबंटित किए जाते हैं।
14. किसी उत्पादन प्रक्रिया में एक साथ एक से अधिक उत्पाद भी उत्पादित किए जा सकते हैं। उदाहरण के लिए, यह वह स्थिति है, जब संयुक्त उत्पाद उत्पादित किए जाते हैं और जहां एक उत्पाद तो मुख्य उत्पाद होता है जबकि दूसरा उत्पाद एक उप-उत्पाद होता है। जब प्रत्येक उत्पाद की संपरिवर्तन लागतें अलग से मान्य नहीं होती हैं तो उन्हें उत्पादों के बीच तर्कसंगत और समान आधार पर आबंटित किया जाता है। उदाहरण के लिए, यह आबंटन प्रत्येक उत्पाद के सापेक्ष बिक्री मूल्य पर होता है जब उत्पादन प्रक्रिया के प्रक्रम में जब उत्पाद अलग से मान्य हो जाता है या फिर उत्पाद के पूरे होने पर, उसे निर्धारित किया जाता है। अधिकतर, उप-उत्पाद प्रकृतिवश मामूली होते हैं। जब ऐसा मामला हो तो उन्हें प्रायः निवल वसूलनीय मूल्य पर मापा जाता है और यह मूल्य मुख्य उत्पाद की लागत से घटाया जाता है। परिणामस्वरूप, मुख्य उत्पाद की अग्रणीत (कैरिंग) राशि उसकी लागत से कोई विशेष अलग नहीं होती है।

अन्य लागतें

15. अन्य लागतें सूचीबद्ध सामान की लागत में केवल उस सीमा तक शामिल की जाती हैं जिस सीमा तक वे सूचीबद्ध सामान को उनके वर्तमान स्थान और स्थिति में लाने के लिए खर्च की जाती हैं। उदाहरण के लिए, सूचीबद्ध सामान की लागत में, उत्पादन उपरिव्यय के अतिरिक्त अन्य उपरिव्यय

भी शामिल होते हैं जो विशिष्ट ग्राहकों के लिए तैयार किए जाने वाले उत्पादों (जैसे कि विशेष डिजाइन आदि) पर खर्च होते हैं।

16. सूचीबद्ध सामान (इंवेन्ट्रीज) की लागत में से हटायी गयी लागतों के उदाहरण यहां नीचे दिए जा रहे हैं जिनकी उरा अवधि में हुई, व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है जिसमें कि वे खर्च हुई हैं।

- (क) बेकार सामग्रियों की असामान्य राशियां, श्रम या अन्य उत्पादन लागतें ;
- (ख) भंडारण लागतें, जब तक कि ये लागतें आगामी उत्पादन प्रक्रम के पूर्व उत्पादन प्रक्रिया में आवश्यक नहीं हैं ;
- (ग) प्रशासनिक उपरिव्यय, जो सूचीबद्ध सामान को उनके वर्तमान स्थान (लोकेशन) और स्थिति में लाने में योगदान नहीं देते; और
- (घ) विक्रय लागतें

17. भारतीय लेखा मानक 23 *उधार लागतें* ऐसी कुछ सीमित परिस्थितियों की पहचान करता है जहां उधार की लागतों को सूचीबद्ध सामान (इंवेन्ट्रीज) की लागतों में सम्मिलित कर लिया जाता है।

18. एक प्रतिष्ठान अस्थगित भुगतान की शर्त पर सूचीबद्ध सामान (इंवेन्ट्री) का क्रय कर सकता है। जब की गई व्यवस्था प्रभावी रूप से वित्त तत्व को समाहित करती है तब वह तत्व उदाहरण के लिए, सामान्य ऋण शर्त की क्रय कीमत तथा किए गए भुगतान की राशि के बीच अंतर को वित्त की अवधि में ब्याज के रूप में व्यय की मान्यता देता है।

सेवा प्रदानकर्ता के सूचीबद्ध सामान (इंवेन्ट्रीज) की लागतें

19. उस सीमा तक कि सेवा प्रदानकर्ताओं के पास सूचीबद्ध सामान (इंवेन्ट्री) है वे इसे उत्पादन की लागत पर मापते हैं। इन लागतों में मुख्यतः श्रम तथा पर्यवेक्षक कर्मियों सहित सेवाएं प्रदान करने में प्रत्यक्ष रूप से संलग्न कर्मियों की अन्य लागतें तथा निहित उपरिव्यय शामिल हैं। हालांकि, बिक्री तथा सामान्य प्रशासकीय कर्मियों से जुड़ी श्रम तथा अन्य लागतों को सम्मिलित नहीं किया जाता है परंतु अवधि के दौरान खर्च किए व्यय को मान्यता दी जाती है। एक सेवा-प्रदानकर्ता की इंवेन्ट्री की लागत को लाभ मार्जिन अथवा गैर-निहित उपरिव्यय में सम्मिलित नहीं किया जाता है। इन्हें प्रायः सेवा प्रदानकर्ता द्वारा वसूल की जाने वाली कीमत में जोड़ा दिया जाता है।

जैविक आस्तियों से उत्पन्न कृषि पैदावार की लागतें²

20. भारतीय लेखा मानक 41 *कृषि* के अनुसरण में, कृषि उत्पाद के रूप में सूचीबद्ध सामान (इंवेन्ट्री), जिसे प्रतिष्ठान ने जैविक आस्तियों से पैदा किया है, उस माप की अनुमानित लागत को उचित मूल्य में से घटाकर आरंभिक मान्यता पर किया जाता है। इस मानक की लागू होने की तिथि पर इंवेन्ट्री की यह लागत है।

² भारतीय लेखा मानक (इंड ए एस) 41 *कृषि* अभी तैयार हो रहा है। तदनुसार, यह अनुच्छेद तभी प्रभावी होगा जब भारतीय लेखा मानक (इंड ए एस) 41 *कृषि* प्रभाव में आ जाएगा।

लागत माप की तकनीकें

21. यदि परिणाम लागत के नजदीक या उसके लगभग बराबर हैं तो सूचीबद्ध सामान की लागत के माप की कुछ तकनीकों, जैसे कि मानक लागत पद्धति का या फुटकर पद्धति का प्रयोग सुविधा के लिए किया जा सकता है। मानक लागतें, सामग्रियों और पूर्तियों के उपभोग, श्रम, दक्षता तथा क्षमता उपयोग के सामान्य स्तरों को ध्यान में रखती हैं। उनका नियमित रूप से पुनर्विलोकन और यदि आवश्यक हो तो विद्यमान स्थितियों को ध्यान में रखते हुए पुनरीक्षण किया जाता है।
22. फुटकर पद्धति का प्रयोग प्रायः फुटकर व्यापार में किया जाता है जहां बड़ी संख्या में तीव्र गति से बदल रही उन मर्दों के सूचीबद्ध सामान को मापने के लिए किया जाता है, जिनका लाभ-अंतर समान हो और जिनके लिए अन्य लागत पद्धतियों का प्रयोग करना अव्यवहारिक हो। सूचीबद्ध सामान की लागत, सूचीबद्ध सामान के बिक्री मूल्य से उचित सकल लाभ के प्रतिशत को घटाकर निर्धारित किया जाता है। प्रयुक्त प्रतिशत उस सूचीबद्ध सामान को ध्यान में रखता है, जो उसकी वास्तविक बिक्री कीमत से नीचे लाया जा चुका हो। प्रत्येक फुटकर विभाग के लिए, प्रायः एक औसत प्रतिशत का प्रयोग किया जाता है।

लागत सूत्र

23. ऐसी मर्दें, जिन्हें सामान्य रूप से आपस में बदला नहीं जा सकता है और जिन्हें विशिष्ट परियोजनाओं के लिए माल या सेवाओं के रूप में सूचीबद्ध सामान की मर्दें तैयार की जाती हैं और अलग की जाती हैं उनकी लागत को, पृथक लागतों की विनिर्दिष्ट पहचान द्वारा नियत किया जाएगा।
24. लागत की विनिर्दिष्ट पहचान से यह अभिप्रायः है कि विनिर्दिष्ट लागत सूचीबद्ध सामान से संबंधित है। यह उन मर्दों के लिए सही निरूपण है जो इस बात की परवाह किए बिना कि चाहे वे खरीदी या उत्पादित की गई हैं या नहीं, विशिष्ट परियोजना के लिए अलग रखी जाती हैं। तथापि जब सूचीबद्ध सामान की ऐसी मर्दों की संख्या अधिक होती है जो आमतौर पर परस्पर बदली नहीं जा सकती हैं तो उनकी लागतों की विनिर्दिष्ट पहचान अनुपयुक्त है, क्योंकि ऐसी परिस्थितियों में कोई उपक्रम सूचीबद्ध सामान में रहने वाली शेष मर्दों को अभिनिश्चित करने की विशिष्ट पद्धति का चुनाव करके अवधि के निवल लाभ या हानि पर पूर्वनिर्धारित प्रभावों को प्राप्त कर सकता है।
25. अनुच्छेद 23 में यथावर्णित सूचीबद्ध सामान से भिन्न सूचीबद्ध सामान की लागत का निर्धारण 'पहले- आना, पहले- जाना' (फीफो) या भारित औसत लागत सूत्र का प्रयोग करते हुए किया जाना चाहिए। एक प्रतिष्ठान एक ही तरह के समस्त सूचीबद्ध सामान, जिसका प्रतिष्ठान के लिए एक ही उपयोग है, के लिए एक ही लागत सूत्र का प्रयोग करेगा। लेकिन जहां सूचीबद्ध सामान की किस्म या उपयोग अलग-अलग है उनके लिए अलग लागत सूत्रों का प्रयोग तर्कसंगत है।
26. उदाहरण के लिए, एक परिचालन खंड में प्रयुक्त इवेंट्री का उपयोग एक प्रतिष्ठान के लिए एक अन्य परिचालन खंड में प्रयुक्त सूचीबद्ध सामान से भिन्न ईकाई हो सकता है। लेकिन इवेंट्री के भौगोलिक स्थान (लॉकेशन) (अथवा संबंधित कर नियमों) में अंतर विभिन्न लागत फार्मूला के प्रयोग को उचित ठहराने के लिए पर्याप्त नहीं है।

27. 'फीफो' यानि 'पहले - आना, पहले- जाना' सूत्र मानता है कि सूचीबद्ध सामान की वे मर्दे जो पहले खरीदी या उत्पादित की गई थीं उनका उपभोग पहले किया जाता है या वे पहले बेची जाती हैं, और इस तरह अवधि के अंत में सूचीबद्ध सामान की शेष रह जाने वाली मर्दे वे होती हैं जो अभी हाल ही में खरीदी या उत्पादित की गई हैं। 'भारित औसत लागत' सूत्र के अंतर्गत प्रत्येक मद की लागत का निर्धारण अवधि की शुरुआत पर सामान मर्दों की लागतों और अन्तिम के दौरान खरीदी गई या उत्पादित सामान मर्दों की लागत के भारित औसत से किया जाता है। औसत की गणना, उद्यम की परिस्थितियों पर निर्भर करते हुए, आवधिक आधार पर या प्रत्येक अतिरिक्त लादान (शिपमेंट) प्राप्त किए जाने के समय की जा सकती है।

निवल वसूली- योग्य मूल्य

28. सूचीबद्ध सामान की लागत वसूल नहीं हो सकती, यदि वह सूचीबद्ध सामान या तो क्षतिग्रस्त हो गया हो या फिर वह पूर्णतः या अंशतः अप्रचलित हो गया हो, या उसकी बिक्री कीमतें गिर गई हों। यदि कार्यपूर्ण होने की अनुमानित लागतें या बिक्री के लिए आवश्यक अनुमानित लागतें बढ़ गई हों तो भी सूचीबद्ध सामान की लागतें वसूल नहीं हो सकती हैं। सूचीबद्ध सामान की लागत को निवल वसूलीयोग्य मूल्य तक अपलिखित करने की प्रथा इस विचार के अनुरूप है कि आस्तियों को उनकी बिक्री या प्रयोग से प्राप्त होने वाली प्रत्याक्षित राशि से अधिक रकम पर नहीं लिया जाना चाहिए।
29. सूचीबद्ध सामान को सामान्यतः निवल वसूलीयोग्य मूल्य तक मद-दर-मद आधार पर उपलिखित किया जाता है। तथापि कुछ परिस्थितियों में, एक जैसी और संबंधित मदों को समूहबद्ध करना उपयुक्त हो सकता है। यह समान उत्पादन रेखा से संबंधित सूचीबद्ध सामान है, जिसके उद्देश्य या अंतिम उपयोग समान है और जो समान भौगोलिक क्षेत्र में उत्पादित और विपणित किया जाता है और जिसे व्यवहार में उस उत्पादन रेखा में अन्य मदों से अलग मूल्यांकित नहीं किया जा सकता। सूचीबद्ध सामान के वर्गीकरण के आधार पर सूचीबद्ध सामान को अपलिखित करना उपयुक्त नहीं है, उदाहरण के लिए जैसे कि तैयार माल या विशिष्ट परिचालन खंड में सभी सूचीबद्ध सामान (इन्वेंट्रीज)।
30. निवल वसूलीयोग्य मूल्य के अनुमान, सूचीबद्ध सामान द्वारा अपेक्षित मूल्य के विषय में लगाए गए अनुमानों के समय उपलब्ध अत्यधिक विश्वसनीय साक्ष्य पर आधारित हैं। यह अनुमान तुलनपत्र की तारीख के बाद घटने वाली घटनाओं से प्रत्यक्षतः संबंधित कीमत या लागत के परिवर्तनों पर उस सीमा तक विचार करते हैं, जिस तक ऐसी घटनाएं तुलनपत्र की तारीख को विद्यमान स्थितियों की पुष्टि करती हैं।
31. निवल वसूलीयोग्य मूल्य के अनुमान, सूचीबद्ध सामान को धारित करने के प्रयोजन पर विचार करते हैं। उदाहरण के लिए, पुष्टि प्राप्त विक्रय या सेवा संविदा को पूरा करने के लिए रखे गए सूचीबद्ध सामान की मात्रा का निवल वसूलनीय मूल्य, संविदा कीमतों पर आधारित होता है। यदि विक्रय संविदा रखे गए सूचीबद्ध सामान की मात्रा से कम के लिए है तो अतिरिक्त सूचीबद्ध सामान का निवल वसूलीयोग्य मूल्य सामान्य विक्रय मूल्यों पर आधारित होता है। फर्म की बिक्री संविदाओं या फर्म की क्रय संविदाओं में कुछ ऐसे प्रावधान भी हो सकते हैं जहां सूचीबद्ध सामान की मात्रा अधिक हो। ऐसे प्रावधानों पर विचार भारतीय लेखा मानक 37 प्रावधान, आकस्मिक देयताएं एवं आकस्मिक आस्तियां के अंतर्गत किया जाता है।

32. सूचीबद्ध सामान के उत्पादन में प्रयोग हेतु (रखी गई) सामग्रियों और अन्य पूर्तियों को लागत से नीचे अपलिखित नहीं किया जाता है, यदि तैयार उत्पाद जिसमें वे सम्मिलित होंगे, लागत पर या लागत से ऊपर विक्रय किए जाने के लिए प्रत्याक्षित हैं। तथापि, जब सामग्रियों की कीमत में कमी हो रही हो और यह अनुमान लगाया जा रहा हो कि तैयार उत्पादों की लागत निवल वसूलीयोग्य मूल्य से अधिक होगी, तो सामग्रियों निवल वसूलीयोग्य मूल्य तक अपलिखित की जाती हैं। ऐसी परिस्थितियों में, सामग्रियों की प्रतिस्थापना लागत, उनके वसूलीयोग्य मूल्य का सर्वोत्तम उपलब्ध माप हो सकता है।
33. प्रत्येक बाद की अवधि में निवल वसूली योग्य मूल्य की नये सिरे से समीक्षा की जाती है जब परिस्थिति जिनमें पहले सूचीबद्ध सामान (इन्वेन्ट्री) को लागत से नीचे अपलिखित किया जाना भी विद्यमान नहीं है अथवा जब परिवर्तित आर्थिक परिस्थितियों के कारण निवल वसूली योग्य मूल्य में वृद्धि का स्पष्ट साक्ष्य है, अपलिखित राशि को उलटा दिया जाता है (अर्थात् मूल अपलेखन की राशि तक ही सीमित रहेगा)। ताकि नई अग्रणीत (कैरिंग) राशि लागत तथा पुनरीक्षित निवल वसूलीयोग्य मूल्य से कम रहे । उदाहरण के लिए, जब सूचीबद्ध सामान (इन्वेन्ट्री) की एक मद जिसकी बिक्री कीमत में कमी आने पर उसे निवल वसूली योग्य मूल्य पर अग्रणीत किया जाता है, बाद की अवधि से हाथ में है तथा इसकी बिक्री कीमत में भी वृद्धि हो गयी है।

व्यय के रूप में मान्यता

34. जब सूचीबद्ध सामान (इन्वेन्ट्री) को बेचा जाता है तो इसकी अग्रणीत (कैरिंग) राशि को संबंधित संपत्ति की मान्यता वाली अवधि में व्यय के रूप में मान्यता दी जाएगी । इन्वेन्ट्री के निवल वसूली योग्य मूल्य तक अपलेखन की राशि तथा इन्वेन्ट्री की सभी हानि को अपलेखन अथवा उत्पन्न हानि की अवधि में व्यय के रूप में मान्यता होगी । निवल वसूली योग्य मूल्य में वृद्धि से उत्पन्न सूचीबद्ध सामान (इन्वेन्ट्री) का किसी अपलेखन के किसी उलटने से उत्पन्न होने वाली राशि को व्यय के रूप में सूचीबद्ध सामान (इन्वेन्ट्री) की राशि में कटौती के रूप में मान्यता दी जाएगी ।
35. कुछ सूचीबद्ध सामान (इन्वेन्ट्री) को अन्य संपत्ति खाता में आवंटित किया जा सकता है , उदाहरण के लिए , स्वयं निर्मित संपत्ति, संयंत्र अथवा उपस्कर के घटक के रूप में प्रयुक्त सूचीबद्ध सामान (इन्वेन्ट्री)। इस तरीके से, एक अन्य संपत्ति में आवंटित सूचीबद्ध सामान (इन्वेन्ट्री) को उस संपत्ति के उपयोगी जीवन तक एक व्यय के रूप में मान्यता दी जाएगी ।

प्रकटन

36. वित्तीय विवरण निम्नलिखित को प्रकट करेंगे :

- (क) प्रयुक्त लागत सूत्र सहित सूचीबद्ध सामान के मापने में अपनाई गई लेखा नीतियां ;
- (ख) सूचीबद्ध सामान की कुल अग्रणीत (कैरिंग) राशि और प्रतिष्ठान के लिए उपयुक्त वर्गीकरणों में अग्रणीत राशि ;

- (ग) बिक्री लागत को घटाकर उचित मूल्य पर ले जायी गई इन्वेंट्री की (कैरिंग) राशि ;
 - (घ) अवधि के दौरान, व्यय के रूप में मान्य सूचीबद्ध सामान (इन्वेंट्री) की राशि ;
 - (ङ) अनुच्छेद 34 के अनुसार अवधि के दौरान व्यय के रूप में मान्य सूचीबद्ध सामान (इन्वेंट्री) की अपलिखित राशि ;
 - (च) किसी उलटाए गए अपलिखन की वह राशि जिसे अनुच्छेद 34 के अनुसार अवधि के दौरान व्यय के रूप में सूचीबद्ध सामान (इन्वेंट्री) की मान्य कटौती राशि के रूप में मान्यता दी गई है ;
 - (छ) वे परिस्थितियां व घटनाएं जिनके कारण अनुच्छेद 34 के अनुसार (इन्वेंट्रीज का) अपलिखन उलटाया गया है ; और
 - (ज) देयताओं की जमानत के रूप में गिरवी रखे गये सूचीबद्ध सामान (इन्वेंट्री) की अग्रणीत (कैरिंग) राशि ।
37. सूचीबद्ध सामान के विभिन्न वर्गीकरणों में रखी गई सूचीबद्ध सामान की अग्रणीत (कैरिंग) राशियों की और इन आस्तियों में परिवर्तन की सीमा से संबंधित जानकारी वित्तीय विवरण के उपयोगकर्ताओं के लिए उपयोगी होती है। सूचीबद्ध सामान के सामान्य वर्गीकरण में वस्तुएं, उत्पादन की आपूर्तियां, निर्माणाधीन एवं तैयार वस्तुएं आती हैं।
38. [देखिये परिशिष्ट 1]
39. एक प्रतिष्ठान लाभ अथवा हानि के लिए एक फॉर्मेट को अपनाता है जिसके परिणामस्वरूप, अवधि के दौरान व्यय के रूप में मान्य सूचीबद्ध सामान (इन्वेंट्री) की लागत के अतिरिक्त राशि का प्रकटन होता है। इस फॉर्मेट के अंतर्गत, एक प्रतिष्ठान व्यय की प्रकृति पर आधारित वर्गीकरण का उपयोग कर व्यय का विश्लेषण प्रस्तुत करता है। इस मामले में, प्रतिष्ठान उन लागतों को प्रकट करेगा जो कच्चे माल और उपभोग की वस्तुओं, श्रम लागतों व अन्य लागतों के साथ-साथ अवधि के दौरान सूचीबद्ध सामान (इन्वेंट्री) के निवल परिवर्तन के रूप में खर्च की गयीं हैं।

परिशिष्ट 'क'

अन्य भारतीय लेखा मानकों में समाविष्ट मामलों के संदर्भ ।

- यह परिशिष्ट भारतीय लेखा मानक (इंड ए एस) 2 का अभिन्न अंग है ।

यह परिशिष्ट उस परिशिष्ट का उल्लेख करता है जो अन्य भारतीय लेखा मानक का अंश है और इस भारतीय लेखा मानक 2 ' सूचीबद्ध सामान ' के लिए संदर्भ का कार्य करता है ।

1. परिशिष्ट 'क' अमूर्त आस्तियां - भारतीय लेखा मानक 38 अमूर्त आस्तियां में समाविष्ट वेबसाइट लागते ।

परिशिष्ट 1

टिप्पणी - यह परिशिष्ट भारतीय लेखा मानक (इंड ए एस) 2 सूचीबद्ध सामान (इंवेंट्रीज) का अंग नहीं है। इस परिशिष्ट का प्रयोजन मात्र इतना है कि भारतीय लेखा मानक और तदनुरूपी अन्तरराष्ट्रीय लेखा मानक 2 'सूचीबद्ध सामान (इंवेंट्रीज)' के बीच अन्तर को स्पष्ट किया जाए।

अन्तरराष्ट्रीय लेखा मानक (आई ए एस) 2 सूचीबद्ध सामान (इंवेंट्रीज) के साथ तुलना

1. अन्तरराष्ट्रीय लेखा मानक (आई ए एस) 2 का अनुच्छेद 38, जो सूचीबद्ध सामान (इंवेंट्रीज) की मान्यता के संबंध में विचार करता है और 'सूचीबद्ध सामान (इंवेंट्रीज)' को कार्य अनुसार वर्गीकरण के आधार पर व्यय मानता है, इस आशय से हटा दिया गया है कि अन्तरराष्ट्रीय लेखा मानक 1 में प्रतिष्ठान के अन्दर कार्य के आधार पर वर्गीकरण का प्रयोग करते हुए लाभ या हानि में मान्य व्यय विश्लेषण की प्रस्तुति का विकल्प नहीं रह गया है और भारतीय लेखा मानक 1 में व्यय का केवल प्रकृति अनुसार वर्गीकरण आवश्यक है। फिर भी, अन्तरराष्ट्रीय लेखा मानक (आई ए एस) 2 के अनुच्छेद संख्याओं में क्रमबद्धता बनी रहे, यह अनुच्छेद संख्या भारतीय लेखा मानक 2 में रखी गयी है।

भारतीय लेखा मानक (इंड ए एस) 7

नकदी प्रवाह विवरण

(कैश फ्लो स्टेटमेंट)

(इस भारतीय लेखा-मानक में मोटे टाइप व सामान्य टाइप में अनुच्छेद हैं। इन दोनों तरह के अनुच्छेदों का समान प्राधिकार है। मोटे टाइप में अनुच्छेद, मुख्य सिद्धान्तों के सूचक हैं।)

उद्देश्य

किसी भी प्रतिष्ठान की नकदी प्रवाह संबंधी सूचना वित्तीय विवरणों के प्रयोगकर्ताओं के लिए उपयोगी होती है जिसके आधार पर वे प्रतिष्ठान द्वारा नकदी तथा नकदी-तुल्यों की सृजन की क्षमता का आंकलन कर सकते हैं और उन नकदी प्रवाहों का इस्तेमाल करने की प्रतिष्ठान की जरूरतों का पता लगा सकते हैं। प्रयोगकर्ताओं द्वारा जो आर्थिक निर्णय लिये जाते हैं उसके लिए यह जरूरी है कि प्रतिष्ठान की नकदी एवं नकदी-तुल्य के सृजन की क्षमता तथा उनके सृजन के समय एवं निश्चितता का मूल्यांकन किया जाये। इस मानक का उद्देश्य है प्रतिष्ठान की नकदी तथा नकदी-तुल्यों के नकदी प्रवाह विवरणों के माध्यम से ऐतिहासिक परिवर्तनों की जानकारी प्राप्त करना जिसमें परिचालन, निवेश और वित्तपोषण गतिविधियों से अवधि के दौरान नकदी प्रवाह के वर्गीकरण का पता लगाया जा सकता है।

कार्यक्षेत्र

1. कोई भी प्रतिष्ठान इस मानक की अपेक्षाओं के अनुसार नकदी प्रवाह विवरण तैयार करेगा और जिस अवधि के लिए वित्तीय विवरण प्रस्तुत किया जाना है उसे उस प्रत्येक अवधि के लिए वित्तीय विवरण के अभिन्न अंग के रूप में प्रस्तुत करेगा।

2. [परिशिष्ट 1 देखें] ।

- 3 किसी प्रतिष्ठान के वित्तीय विवरणों के प्रयोगकर्ताओं की रुचि इसमें होती है कि प्रतिष्ठान किस प्रकार नकदी एवं नकदी-तुल्यों का सृजन करता है और किस प्रकार इनका उपयोग करता है। यह बात सच है कि भले ही प्रतिष्ठान की गतिविधियां कुछ भी हों और भले ही प्रतिष्ठान का उत्पाद नकदी हो, जैसे कि वित्तीय प्रतिष्ठानों के मामले में है। प्रतिष्ठानों की प्रमुख राजस्व उत्पादक गतिविधियां कितनी भी अलग-अलग क्यों न हों उन्हें समान कारणों से नकदी की जरूरत होती है। उन्हें अपने परिचालनों के संचालन, अपने दायित्वों के भुगतान और अपने निवेशकों को आय प्रदान करने के लिए नकदी की आवश्यकता होती है। तदनुसार, इस मानक की यह अपेक्षा है कि सभी प्रतिष्ठान नकदी प्रवाह विवरण प्रस्तुत करें।

नकदी प्रवाह सूचना के लाभ

4. जब नकदी प्रवाह विवरण का इस्तेमाल अन्य वित्तीय विवरणों के साथ किया जाता है तो वह ऐसी सूचना प्रदान करता है जिससे प्रयोगकर्ता किसी प्रतिष्ठान की निवल आस्तियों में होने वाले परिवर्तनों, उसके वित्तीय ढांचे (उसकी अर्थ-सुलभता और शोधन-क्षमता सहित) तथा बदलती हुई परिस्थितियों और अवसरों के अनुरूप अपने को ढालने के लिए रकम एवं नकदी प्रवाह के समय को प्रभावित करने की योग्यता को जान पाता है नकदी प्रवाह सूचना किसी प्रतिष्ठान की नकदी तथा नकदी-तुल्य सृजन की क्षमता का निर्धारण करने में सहायक होती है और इसकी मदद से प्रयोगकर्ता ऐसे मॉडल तैयार कर पाता है जिससे विभिन्न प्रतिष्ठानों के भावी नकदी प्रवाह के मौजूदा मूल्य की तुलना की जा सकती है। इससे विभिन्न प्रतिष्ठानों के परिचालन कार्यनिष्पादन की रिपोर्टिंग की तुलनात्मकता भी बढ़ती है क्योंकि एक ही प्रकार के लेन-देनों और घटनाओं के लिए भिन्न-भिन्न लेखा पद्धतियों के इस्तेमाल करने के प्रभाव इससे समाप्त हो जाते हैं।
5. ऐतिहासिक नकदी प्रवाह सूचना का इस्तेमाल प्रायः भावी नकदी प्रवाह की राशि, समय और निश्चितता के लिए किया जाता है। भावी नकदी प्रवाह का अतीत में निर्धारण करने की सत्यता की जांच करने तथा लाभप्रदता एवं निवल नकदी प्रवाह के बीच संबंध पता लगाने और बदलती कीमतों का प्रभाव जानने में भी यह उपयोग होता है।

परिभाषाएं

6. इस मानक में निम्नलिखित शब्दावली का प्रयोग यहाँ विनिर्दिष्ट अर्थों में किया गया है।

'नकदी' - इसमें हाथ में नकदी तथा मांग जमा शामिल होते हैं।

'नकदी-तुल्य' - ऐसे निवेश जो अल्पावधि और बहुत अधिक अर्थ - सुलभ हों और उन्हें ज्ञात नकद-राशियों में बदला जा सकता हो तथा जिनके मूल्य में होने वाला परिवर्तन कोई विशेष न हो।

'नकदी प्रवाह' - इसका अर्थ है नकदी व नकदी-तुल्यों का अंतः एवं बहिः प्रवाह।

'परिचालन गतिविधियां' - इससे प्रतिष्ठान की राजस्व सृजन करने वाली मुख्य गतिविधियां तथा ऐसी गतिविधियां अभिप्रेत हैं जो निवेश अथवा वित्तपोषण गतिविधियां न हों।

'निवेश गतिविधियां' - इसका अर्थ है दीर्घावधि आस्तियों और ऐसे अन्य निवेशों का अधिग्रहण तथा निपटान जो नकदी-तुल्यों में सम्मिलित न हों।

'वित्तपोषण गतिविधियां' - वे गतिविधियां हैं जो प्रतिष्ठान में लगायी गई 'इक्विटी' और उधारों के आकार एवं संरचना में परिवर्तन लाती हैं।

नकदी तथा नकदी-तुल्य

7. नकदी-तुल्य केवल इसलिए रखे जाते हैं ताकि उनसे अल्पकालीन नकदी देनदारियां निपटायी जा सकें ये निवेश तथा अन्य प्रयोजनों के लिए नहीं रखे जाते हैं। कोई भी निवेश तभी नकदी- तुल्य माना जायेगा जब वह नकदी की ज्ञात राशि में तत्काल परिवर्तनीय हो और उसके मूल्य में परिवर्तन का जोखिम नाम मात्र का हो। इसलिए, आमतौर पर कोई भी निवेश नकदी- तुल्य तब कहलाता है जब उसकी परिपक्वता अवधि कम हो, उदाहरण के लिए अधिग्रहण की तारीख से तीन महीने या उससे भी कम। 'इक्विटी' निवेशों को नकदी-तुल्यों में तब तक शामिल नहीं किया जाता जब तक वे वास्तव में नकदी तुल्य न हों, उदाहरण के लिए, परिपक्वता की अल्पावधि के भीतर अधिगृहीत तथा निश्चित तिथि तक विमोचन योग्य अधिमान शेयर।

बैंक उधार प्रायः वित्तपोषण गतिविधियां माने जाते हैं। बहरहाल, जो बैंक ओवरड्राफ्ट मांग पर प्रतिदेय हों वे प्रतिष्ठान के नकदी प्रबंधन का अभिन्न अंग माने जाते हैं। बैंक ओवरड्राफ्ट नकदी तथा नकदी-तुल्यों के अवयव (अंग) माने जाते हैं। ऐसी बैंकिंग व्यवस्थाओं का एक लक्षण यह है कि बैंक-शेष में प्रायः उतारचढ़ाव आते रहते हैं और यह कभी घनात्मक शेष तथा कभी ऋणात्मक शेष में बदलता रहता है।

नकदी प्रवाह में, नकदी तथा नकदी-तुल्यों वाली वस्तुओं के परस्पर होने वाले परिवर्तनों शामिल नहीं हैं क्योंकि वे प्रतिष्ठान विशेष के नकदी प्रबंधन का अंग होते हैं न कि उसके परिचालन, निवेश तथा वित्तपोषण गतिविधियों के। नकदी प्रबंधन में नकदी तुल्यों में अधिक नकद राशि का निवेश शामिल होता है।

नकदी-प्रवाह विवरण का प्रस्तुतिकरण

10. नकदी प्रवाह विवरण में अवधि के दौरान हुए नकदी प्रवाह की सूचना, परिचालन, निवेश और वित्तपोषण गतिविधियों में वर्गीकृत की जायेगी।
11. कोई भी प्रतिष्ठान परिचालन, निवेश और वित्तपोषण गतिविधियों से होने वाले अपने नकदी प्रवाह की प्रस्तुति ऐसे ढंग से करती है जो उसके कारोबार के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। गतिविधियों के अनुसार वर्गीकरण से ऐसी सूचना मिलती है जिससे प्रयोगकर्ताओं को उन गतिविधियों का प्रतिष्ठान की वित्तीय स्थिति तथा उसकी नकदी और नकदी-तुल्यों की राशि पर प्रभाव का पता चलता है। इस सूचना से उन गतिविधियों के बीच के संबंध का भी आंकलन किया जा सकता है।
12. किसी एक एकल लेन-देन में ऐसे नकदी प्रवाह भी सम्मिलित हो सकते हैं जिन्हें अलग-अलग वर्गीकृत किया जाता है। उदाहरण के लिए, जब आस्थागित भुगतान के आधार पर ली गयी अचल आस्ति के भुगतान की राशि में ब्याज और ऋण दोनों शामिल हों तो ब्याज वाले भाग को वित्तपोषण गतिविधियों के अंतर्गत और ऋण वाले भाग को निवेश गतिविधियों के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है।

परिचालन गतिविधियां

13. परिचालन गतिविधियों से जो नकदी प्रवाह की राशि उद्भूत होती है वह इस बात का मुख्य संकेत देती है कि प्रतिष्ठान ने ऋण चुकाने, अपनी परिचालन क्षमता के रख-रखाव, लाभांशों के भुगतान तथा नये निवेश करने के लिए बाहरी वित्तपोषण के सहारे बिना पर्याप्त नकदी प्रवाह सृजित कर लिये हैं। भावी परिचालन नकदी प्रवाह की भविष्यवाणी में अन्य सूचना के साथ-साथ ऐतिहासिक परिचालन नकदी प्रवाह के विशिष्ट अवयवों के संबंध में सूचना उपयोगी होती है।

14. परिचालन गतिविधियों से होने वाला नकदी-प्रवाह मुख्य रूप से प्रतिष्ठान की राजस्व उत्पादक गतिविधियों से उद्भूत होता है। इसलिए, यह सामान्यतया उन लेन-देनों और अन्य घटनाओं के परिणामस्वरूप होता है जो लाभ या हानि के निर्धारक होते हैं। परिचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह के उदाहरण निम्नलिखित हैं :-

- क) वस्तुओं की बिक्री तथा सेवाएं प्रदान करने से मिलने वाली नकद-राशि ;
- ख) रॉयल्टी, फीस, कमीशन और अन्य प्रकार के राजस्व से मिलने वाली नकद-राशि ;
- ग) वस्तुओं और सेवाओं के आपूर्तिकर्ताओं को नकद-भुगतान ;
- घ) कर्मचारियों को तथा उनकी ओर से नकद-भुगतान ;
- ङ) बीमा प्रतिष्ठान के प्रीमियम व दावों, वार्षिकी तथा अन्य पॉलिसी लाभों से संबंधित नकद प्राप्तियां तथा नकद भुगतान ;
- च) आयकर के लिए किया गया नकद-भुगतान अथवा प्राप्त रिफंड जब तक कि उन्हें विशेष रूप से वित्तपोषण तथा निवेश गतिविधियों से न जोड़ा जा सकता हो ; और
- छ) 'डीलिंग' और 'ट्रेडिंग' प्रयोजनों के लिए की गयी संविदाओं संबंधी नकद प्राप्तियां एवं भुगतान ;

कुछ लेन-देन ऐसे भी होते हैं जैसे किसी संयंत्र की किसी मद की बिक्री, जिनसे लाभ या हानि होती है और उन्हें मान्य लाभ अथवा हानि में शामिल किया जाता है। ऐसे लेन-देन से संबंधित नकद प्रवाह निवेश-गतिविधियों से हुए नकद-प्रवाह होते हैं। लेकिन, ऐसी आस्तियों, जिन्हें तो औरों को पहले किराये पर देने के लिए और बाद में बिक्री के लिए धारित किया जाता है, उनके निर्माण या अर्जन के लिए किया जाने वाला नकद भुगतान भारतीय लेखा मानक 16 के अनुच्छेद 68 'क' के अनुराण में परिचालन गतिविधियों से नकद प्रवाह की श्रेणी में आता है। इस तरह की आस्तियों से किराया व बाद में इनकी बिक्री से नकद प्राप्तियां भी परिचालन गतिविधियों से नकद प्रवाह ही हैं।

15. कोई प्रतिष्ठान 'डीलिंग' अथवा 'ट्रेडिंग' के प्रयोजन से भी प्रतिभूतियां व ऋण रख सकती है। ऐसा होने पर वे विशेष रूप से पुनः बिक्री के लिए अर्जित सूचीबद्ध सामान (इंवेन्ट्री) मानी जायेंगी, इसलिए प्रतिभूतियों की डीलिंग अथवा ट्रेडिंग के क्रय और विक्रय से हुआ नकद-प्रवाह परिचालन गतिविधियों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। इसी प्रकार, वित्तीय प्रतिष्ठानों द्वारा दिये गये नकद-अग्रिम तथा ऋण प्रायः परिचालन गतिविधियों के रूप में वर्गीकृत किये जाते हैं क्योंकि वे उस संस्था की मुख्य राजस्व-नकद गतिविधियों से संबद्ध होते हैं।

निवेश गतिविधियां

16. निवेश गतिविधियों से उत्पन्न नकद-प्रवाह की अलग से सूचना देना महत्वपूर्ण है क्योंकि नकद-प्रवाह से यह पता चलता है कि भावी आय और नकद-प्रवाह का सृजन करने के लिए संसाधनों हेतु किस सीमा तक व्यय किया गया है। जिन खर्चों को तुलन-पत्र में मान्य आस्ति के रूप में दर्शाया जाता है केवल वही खर्च निवेश गतिविधि के रूप में वर्गीकृत किये जाने के पात्र हैं। निवेश-गतिविधियों से उत्पन्न नकदी-प्रवाह के उदाहरण निम्नलिखित हैं :-
- (क) सम्पत्ति, संयंत्र और उपस्कर, अमूर्त तथा अन्य दीर्घकालीन आस्तियों के अर्जन के लिए नकद भुगतान। इन भुगतानों में पूंजीकृत विकास की लागत तथा स्वयं निर्मित संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर शामिल हैं ;
 - (ख) सम्पत्ति, संयंत्र और उपस्कर, अमूर्त तथा अन्य दीर्घकालीन आस्तियों की बिक्री से नकद-प्राप्तियां ;
 - (ग) अन्य प्रतिष्ठानों की 'इक्विटी' अथवा ऋण लिखतों तथा संयुक्त उद्यमों में हित अर्जित करने के लिए किये गये नकद भुगतान (उन लिखतों हेतु भुगतान को छोड़कर जिन्हें या तो नकदी के तुल्य माना गया है या जो 'डीलिंग' या 'ट्रेडिंग' के प्रयोजनों के लिए किये गये हैं) ;
 - (घ) अन्य प्रतिष्ठानों की 'इक्विटी' अथवा ऋण लिखतों तथा संयुक्त उद्यमों में हित की बिक्री करने पर नकद प्राप्तियां (उन लिखतों की प्राप्तियों को छोड़कर जिन्हें या तो नकदी के तुल्य माना गया है या जो डीलिंग या 'ट्रेडिंग' के प्रयोजनों के लिए किये गये हैं) ;
 - (ङ) अन्य प्रतिष्ठानों को दिये गये नकद अग्रिम एवं ऋण (किसी वित्तीय संस्था के अग्रिमों एवं ऋणों को छोड़कर) ;
 - (च) अन्य पक्षों को दिये गये नकद अग्रिमों और ऋणों की चुकौती से नकद प्राप्तियां (किसी वित्तीय संस्था के अग्रिमों और ऋणों को छोड़कर) ;
 - (छ) भावी संविदाओं, वायदा संविदाओं, विकल्प संविदाओं और विनिमय (स्वैप) संविदाओं के नकद भुगतान सिवाय उन परिस्थितियों के जब ये संविदायें 'डीलिंग' अथवा 'ट्रेडिंग' के प्रयोजनों से की गयी हों अथवा भुगतानों को वित्तपोषण गतिविधियों के रूप में वर्गीकृत किया गया हो ;
 - (ज) भावी संविदाओं, वायदा संविदाओं, विकल्प संविदाओं और विनिमय (स्वैप) संविदाओं की नकद प्राप्तियां सिवाय उन परिस्थितियों के जब ये संविदायें 'डीलिंग' अथवा 'ट्रेडिंग' के प्रयोजनों की गयी हों अथवा प्राप्तियों को वित्तपोषण गतिविधियों के रूप में वर्गीकृत किया गया हो ।

जब किसी संविदा को पता लगायी जा सकने वाली स्थिति के बचाव (हैज) के विचार से किया गया हो तो संविदा के नकदी प्रवाह भी उसी ढंग से वर्गीकृत किये जायेंगे जिस प्रकार से स्थिति के नकदी प्रवाह का बचाव किया जा रहा हो ।

वित्तपोषण गतिविधियां

17. वित्तपोषण गतिविधियों से उत्पन्न नकद प्रवाह की अलग-से सूचना देना (प्रकटन) महत्वपूर्ण है क्योंकि प्रतिष्ठान को पूंजी प्रदान करने वालों के भावी नकदी-प्रवाह के दावों का अनुमान लगाने के लिए यह उपयोगी है। वित्तपोषण गतिविधियों से उत्पन्न होने वाले नकदी प्रवाहों के उदाहरण निम्नलिखित हैं :-

- (क) शेयरों अथवा अन्य 'इक्विटी' लिखतों के निर्गम से नकद प्राप्तियां ;
- (ख) प्रतिष्ठान के शेयरों के अर्जन अथवा प्रतिदान (रीडीम) के लिए मालिकों को नकद भुगतान ;
- (ग) ऋण-पत्रों, ऋणों, नोटों, बंध-पत्रों, बंधकों तथा अन्य अल्प अथवा दीर्घ-कालीन उधारों के निर्गम से प्राप्त नकद राशियां ;
- (घ) उधार ली गयी राशियों की नकद चुकौती , तथा
- (ङ) वित्तीय पट्टे से संबंधित बकाया देयता को कम करने के लिए पट्टाकर्ता द्वारा किया गया नकद भुगतान ।

परिचालन गतिविधियों से नकदी-प्रवाहों की रिपोर्टिंग

18. प्रतिष्ठान निम्नलिखित में से एक विधि का इस्तेमाल करते हुए परिचालन गतिविधियों से होने वाले नकदी प्रवाहों की सूचना देगी :-

- (क) प्रत्यक्ष विधि : जिसके द्वारा सकल नकद प्राप्तियां और सकल नकद भुगतान की प्रमुख श्रेणियों की जानकारी दी जाती है, अथवा
- (ख) अप्रत्यक्ष विधि : जिसके द्वारा नकदी से भिन्न किस्म के लेन-देन के प्रभावों, किसी अतीत या भावी परिचालन की नकद प्राप्तियों अथवा भुगतानों के स्थगन अथवा उपचय, एवं निवेश अथवा वित्तपोषण द्वारा नकदी प्रवाह से संबंधित आय अथवा व्यय मदों का लाभ अथवा हानि में समायोजन किया जाता है।

19. प्रतिष्ठानों को इस बात के लिए प्रोत्साहित किया जाता है कि वे प्रत्यक्ष विधि का इस्तेमाल करते हुए परिचालन गतिविधियों से होने वाले नकदी-प्रवाहों की सूचना दें । प्रत्यक्ष विधि में ऐसी सूचना होती है जो भावी नकदी प्रवाह का अनुमान लगाने में उपयोगी हो सकती है तथा वह सूचना अप्रत्यक्ष विधि में उपलब्ध नहीं होती । प्रत्यक्ष विधि में सकल नकद प्राप्तियों और सकल नकद भुगतानों की प्रमुख श्रेणियों के संबंध में सूचना निम्नलिखित में से किसी एक तरीके से प्राप्त की जा सकती है:-

- (क) प्रतिष्ठान के लेखा-संबंधी रिकार्डों से, अथवा
- (ख) निम्नलिखित के परिप्रेक्ष्य में लाभ-हानि खाते के विवरण में विक्रयों, विक्रय लागतों (वित्तीय संस्था के लिए ब्याज एवं ऐसी ही आय तथा ब्याज व्यय और ऐसे ही प्रभार) तथा लाभ-हानि विवरण की अन्य मदों का समायोजन :-

- (i) सूचीबद्ध सामान (इन्वेंट्रीज) और परिचालन प्राप्य राशियों तथा देय-राशियों में अवधि के दौरान परिवर्तन,
 - (ii) नकदी से भिन्न अन्य मदें, और
 - (iii) ऐसी अन्य मदें जिनके लिए नकदी प्रभाव निवेश अथवा वित्तपोषण नकदी प्रवाह हैं।
20. अप्रत्यक्ष विधि के अधीन परिचालन गतिविधियों से निवल नकदी प्रवाह का निर्धारण निम्नलिखित के प्रभाव से लाभ अथवा हानि का समायोजन किया जाता है :-
- (क) अवधि के दौरान सूचीबद्ध सामान तथा परिचालन प्राप्य राशियों तथा देय-राशियों में परिवर्तन ;
 - (ख) नकदी से भिन्न मदें जैसे मूल्यहास, प्रावधान, आस्थगित कर, न वसूल हुए विदेशी मुद्रा लाभ और हानियां तथा सहयोगी प्रतिष्ठानों के अवितरित लाभ, और
 - (ग) ऐसी अन्य मदें जिनके लिए नकदी प्रभाव निवेश अथवा वित्तपोषण नकदी प्रवाह हैं।

विकल्प के रूप में, परिचालन गतिविधियों से होने वाले निवल नकदी प्रवाह को अप्रत्यक्ष विधि से लाभ-हानि विवरण में राजस्व और व्यय के रूप में और अवधि के दौरान सूचीबद्ध सामान तथा परिचालन का प्राप्य और देय राशियों में प्रस्तुत किया जा सकता है।

निवेश तथा वित्तपोषण गतिविधियों से नकदी प्रवाहों की रिपोर्टिंग

21. प्रत्येक प्रतिष्ठान अनुच्छेद 22 और 24 में उल्लिखित सीमा तक के नकदी प्रवाहों को छोड़कर निवेश तथा वित्तपोषण गतिविधियों से हुई सकल नकद प्राप्तियों एवं सकल नकद भुगतानों की मुख्य श्रेणियों की अलग-अलग सूचना देगा।

निवल आधार पर नकदी-प्रवाह की सूचना देना

22. निम्नलिखित परिचालन निवेश अथवा वित्तपोषण गतिविधियों से होने वाले नकदी प्रवाहों की सूचना भी निवल आधार पर दी जा सकती है :-
- (क) ग्राहकों की ओर से नकद प्राप्तियां तथा भुगतान जब नकद-प्रवाह से संस्था की गतिविधियां नहीं बल्कि ग्राहक की गतिविधियां झलकती हों, और
 - (ख) ऐसी मदों के लिए नकद प्राप्तियां तथा भुगतान जिनमें टर्न ओवर जल्दी हो, रकम बड़ी हो और परिपक्वता अल्पकालीन हो।
23. अनुच्छेद 22 (क) में जिन प्राप्तियों और भुगतानों का उल्लेख है उनके उदाहरण निम्नलिखित हैं :-

- (क) बैंक की मांग जमा राशियों को स्वीकार करना तथा चुकाया जाना
- (ख) किसी निवेश-प्रतिष्ठान द्वारा ग्राहकों के लिए रखी गयी निधियां, और
- (ग) सम्पत्तियों के स्वामियों की ओर से इक्ट्ठे किये गये किराये तथा उन्हें किया गया किराया भुगतान।

23. (क) अनुच्छेद 22 (ख) में जिन प्राप्तियों और भुगतानों का उल्लेख है उनके उदाहरण निम्नलिखित हैं :-

- (क) क्रेडिट कार्ड ग्राहकों का मूलधन,
- (ख) निवेशों का क्रय व विक्रय, और
- (ग) अन्य अल्प-कालीन उधार, उदाहरण के लिए ऐसे उधार जिनकी परिपक्वता अवधि तीन महीने या उससे कम है।

24. किसी वित्तीय संस्था की निम्नलिखित गतिविधियों से उद्भूत नकदी-प्रवाह की सूचना निम्न आधार पर दी जानी चाहिए:-

- (क) निश्चित परिपक्वता तिथि वाली नकद प्राप्तियां तथा भुगतान जो जमा-राशियों की स्वीकृति और चुकौती के लिए हों,
- (ख) अन्य वित्तीय संस्थानों के पास धन जमा करवाना तथा उस जमा रकम को उनसे निकलवाना, और
- (ग) ग्राहकों को दिये गये नकद अग्रिम और ऋण तथा उन अग्रिमों और ऋणों की चुकौती।

विदेशी मुद्रा नकदी-प्रवाह

- 25. विदेशी मुद्रा में होने वाले लेन-देनों से उद्भूत नकदी-प्रवाहों को प्रतिष्ठान की कार्यात्मक मुद्रा में दर्ज किया जायेगा। ऐसा करने के लिए विदेशी मुद्रा की राशि पर नकदी प्रवाह की तिथि को लागू कार्यात्मक मुद्रा और विदेशी मुद्रा के बीच विनिमय दर लागू होगी।
- 26. किसी विदेशी अनुबंधी के नकदी प्रवाह को नकदी प्रवाह तारीख की कार्यात्मक मुद्रा तथा विदेशी मुद्रा के बीच विनिमय दर पर रूपांतरित किया जायेगा।
- 27. नकदी-प्रवाह जो विदेशी मुद्रा में हो उसकी सूचना भारतीय लेखा मानक 21 'विदेशी मुद्रा में परिवर्तनों का प्रभाव' के अनुरूप होगी। इससे ऐसे विनिमय दर को प्रयोग करने की अनुमति मिलती है जो

वास्तविक दर के करीब होती है। उदाहरण के लिए किसी विदेशी अनुषंगी के विदेशी मुद्रा लेन-देनों अथवा नकदी प्रवाहों को रूपांतरित करने के लिए एक अवधि की भारित औसत विनिमय दर का इस्तेमान किया जायेगा। बहरहाल, भारतीय लेखा मानक 21 इस बात की अनुमति नहीं देता कि रिपोर्टिंग अवधि के अंत में विदेशी अनुषंगी के नकदी प्रवाह को रूपांतरित करते समय लागू विनिमय दर का प्रयोग किया जाये।

28. विदेशी मुद्रा विनिमय दरों में परिवर्तनों के फलस्वरूप जो लाभ या हानियाँ हुई हों यदि वे वसूल न हुई हों तो उन्हें नकदी प्रवाह नहीं माना जाएगा। बहरहाल, विदेशी मुद्रा में रखी गई अथवा प्राप्त नकदी अथवा नकदी-तुल्य पर विदेशी विनिमय दरों के परिवर्तनों के जो प्रभाव होंगे उनकी सूचना नकदी प्रवाह विवरणों में इस तरह दी जायेगी ताकि अवधि के प्रारंभ और अंत में नकदी और नकदी तुल्यों का मिलन हो सके। यह रकम परिचालन निवेश और वित्तपोषण गतिविधियों से होने वाले नकदी-प्रवाह के अनुसार अलग-अलग दिखायी जायेगी और इसमें यदि कोई अंतर है तो इसे इस तरह शामिल किया जायेगा कि मानो वे नकद प्रवाह विनिमय दरों की अवधि के अंत में रिपोर्ट किये गये हैं।

29. (देखिये परिशिष्ट 1)

30. (देखिये परिशिष्ट 1)

ब्याज और लाभांश

31. प्राप्त तथा प्रदत्त ब्याज और लाभांश से होने वाले प्रत्येक नकदी प्रवाह की सूचना अलग-अलग दी जायेगी। वित्तीय संस्था के मामले में प्रदत्त ब्याज एवं प्राप्त ब्याज और लाभांश को परिचालन गतिविधियों से उद्भूत नकदी प्रवाहों के रूप में वर्गीकृत किया जाना चाहिए। अन्य प्रतिष्ठानों के मामले में प्रदत्त ब्याज से उद्भूत नकदी प्रवाहों को वित्तपोषण गतिविधियों से होने वाले नकदी प्रवाहों के रूप में तथा प्राप्त लाभांशों को निवेश गतिविधियों से होने वाले नकदी प्रवाहों के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा। प्रदत्त लाभांशों को वित्तपोषण गतिविधियों से होने वाले नकदी प्रवाह के रूप में वर्गीकृत किया जाना चाहिए।

32. किसी अवधि के दौरान प्रदत्त कुल ब्याज की कुल राशि, चाहे लाभ अथवा हानि में व्यय के रूप में मानी गयी हो अथवा भारतीय लेखा मानक 23 'उधार की लागत' के अनुसार पूंजीकृत की गई हो, उसे नकदी प्रवाह विवरण में सूचित किया जायेगा।

33. वित्तीय संस्था के मामले में प्रदत्त ब्याज एवं प्राप्त ब्याज और लाभांश को प्रायः परिचालन नकदी प्रवाह के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। लेकिन, अन्य प्रतिष्ठानों के मामले में इन नकदी प्रवाहों को वर्गीकृत किये जाने के संबंध में कोई एक राय नहीं है। कुछ लोगों का मत है कि प्रदत्त ब्याज और प्राप्त ब्याज और लाभांश को परिचालन नकदी प्रवाह के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है क्योंकि उनसे लाभ अथवा हानि का निर्धारण होता है। बहरहाल, यह अधिक उपयुक्त होगा कि प्रदत्त ब्याज और प्राप्त ब्याज और लाभांश क्रमशः वित्तपोषण नकदी प्रवाह तथा निवेश नकदी प्रवाह के रूप में वर्गीकृत किया जाए क्योंकि ये वित्तीय संसाधन प्राप्त करने की लागतें अथवा निवेशों से होने वाली प्राप्ति हैं।

34. कुछ लोगों का यह भी मत है कि प्रदत्त लाभांशों को परिचालन गतिविधियों से प्राप्त नकदी प्रवाह के एक अंग (अवयव) के रूप में वर्गीकृत किया जाए ताकि प्रयोगकर्ताओं को यह पता लगाने में मदद मिल सके कि परिचालन नकदी प्रवाह में से लाभांश का भुगतान करने में प्रतिष्ठान की कितनी क्षमता है। बहरहाल, यह अधिक उपयुक्त माना जाता है कि प्रदत्त लाभांशों को वित्तपोषण गतिविधियों से उद्भूत नकदी प्रवाहों के रूप में वर्गीकृत किया जाये क्योंकि वे वित्तीय संसाधन प्राप्त करने की लागत हैं।

आय पर कर

35. आयकर से होने वाले नकदी प्रवाहों की सूचना अलग-से दी जायेगी और उन्हें तब तक परिचालन गतिविधियों से होने वाले नकदी प्रवाह के रूप में वर्गीकृत किया जायेगा जब तक उन्हें विशेष रूप से वित्तपोषण और निवेश गतिविधियों के साथ संबद्ध न किया जाए।
36. आय कर ऐसे लेन-देनों पर होते हैं जिनसे ऐसे नकदी प्रवाह होते हैं जिन्हें नकदी प्रवाह विवरण में परिचालन, निवेश अथवा वित्तपोषण गतिविधियों कहा जाता है। यद्यपि कर-व्यय को तुरंत निवेश अथवा वित्तपोषण गतिविधियों से संबद्ध किया जा सकता है तथापि संबंधित कर नकदी प्रवाहों की प्रायः पहचान करना अव्यवहारिक होता है और वे अंतर्निहित लेन-देन के नकदी प्रवाह से भिन्न अवधि में उद्भूत हो सकते हैं। इसलिए, प्रदत्त करों को प्रायः परिचालन गतिविधियों से उद्भूत नकदी प्रवाह के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। बहरहाल, जब कर संबंधी नकदी प्रवाह को किसी ऐसे लेन-देन से संबद्ध करना व्यावहारिक हो जिससे ऐसे नकदी प्रवाह उद्भूत हों जिन्हें निवेश अथवा वित्तपोषण गतिविधियों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है तो उस कर-नकदी प्रवाह को, जैसा भी उचित हो, निवेश अथवा वित्तपोषण गतिविधियों के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा। जब कर-संबंधी नकदी प्रवाह को एक-से अधिक श्रेणी की गतिविधियों में बांटा गया हो तो प्रदत्त करों की कुल राशि की सूचना दी जाती है।

अनुषंगियों, सहयोगी प्रतिष्ठानों और संयुक्त उद्यमों में निवेश

37. किसी सहयोगी प्रतिष्ठान अथवा अनुषंगी में किये गये निवेश का हिसाब लगाते समय जब 'इक्विटी' या लागत प्रणाली का इस्तेमाल किया जाता है तो निवेशक नकदी प्रवाह विवरण में सूचना देते समय केवल अपने और निवेशिती के बीच होने वाले नकदी प्रवाहों की सूचना देता है। उदाहरण के लिए, लाभांशों और अप्रिमों से सम्बंधित सूचना।
38. जो प्रतिष्ठान आनुपातिक समेकन का इस्तेमाल करते हुए संयुक्त रूप से नियंत्रित किसी प्रतिष्ठान में अपने हितों [देखे भारतीय लेखा मानक 31 'संयुक्त उद्यमों में हित'] की सूचना देता है अपने नकदी प्रवाह के समेकित विवरण में संयुक्त रूप से नियंत्रित प्रतिष्ठान के नकदी प्रवाह में अपना आनुपातिक हिस्सा दर्शाता है। जो प्रतिष्ठान इक्विटी पद्धति का इस्तेमाल करते हुए ऐसे हित की सूचना देता है वह अपने नकदी प्रवाह विवरण में संयुक्त नियंत्रण वाले प्रतिष्ठान में निवेशों संबंधी नकदी प्रवाह एवं अपने तथा संयुक्त रूप से नियंत्रित प्रतिष्ठान के बीच वितरण और अन्य भुगतानों अथवा प्राप्तियों को शामिल करता है।

अनुषंगियों तथा अन्य कारोबारों के बीच स्वामित्व हितों में परिवर्तन

39. अनुषंगियों तथा अन्य कारोबारों पर अपना नियंत्रण पाने अथवा खो देने के फलस्वरूप हुआ कुल नकदी प्रवाह अलग से प्रस्तुत किया जायेगा और उसे निवेश गतिविधियों के रूप में वर्गीकृत किया जायेगा ।
40. अवधि के दौरान, अनुषंगियों अथवा अन्य कारोबारों पर नियंत्रण प्राप्त करने अथवा उन पर से नियंत्रण खो देने के संबंध में कोई प्रतिष्ठान निम्नलिखित की कुल सूचना देगा :-
- (क) कुल प्रदत्त अथवा प्राप्त प्रतिफल राशि :
 - (ख) प्रतिफल राशि का वह हिस्सा जिसमें नकदी अथवा नकदी तुल्य हों ;
 - (ग) अनुषंगियों अथवा अन्य कारोबारों जिन पर नियंत्रण प्राप्त किया गया है अथवा खो दिया गया है उनमें नकदी अथवा नकदी तुल्यों की राशि ; और
 - (घ) जिन अनुषंगियों अथवा अन्य कारोबारों पर नियंत्रण प्राप्त किया गया है अथवा खो दिया गया है उनकी नकदी अथवा नकदी तुल्यों को छोड़कर आस्तियों और देयताओं की राशि, जिनकी प्रत्येक प्रमुख श्रेणी का सार प्रस्तुत किया जायेगा ।
41. अनुषंगियों अथवा अन्य कारोबारों पर नियंत्रण प्राप्त करने अथवा उन पर से नियंत्रण खो देने के नकदी प्रवाह प्रभावों का एक लाइन मदों के रूप में अलग से प्रस्तुतिकरण तथा अर्जित या निपटायी गयी आस्तियों एवं देयताओं की राशि की जानकारी से उन नकदी प्रवाहों तथा अन्य परिचालन, निवेश और वित्तपोषण गतिविधियों संबंधी नकदी प्रवाहों का अंतर पता लगाता है। नियंत्रण खोने के कारण नकदी-प्रवाह के प्रभावों को नियंत्रण पाने के नकदी प्रवाहों में से कम नहीं किया जाता ।
42. अनुषंगियों अथवा अन्य कारोबारों पर नियंत्रण प्राप्त करने अथवा उन पर से नियंत्रण छोड़ने के प्रदत्त अथवा प्राप्त प्रतिफल की कुल राशि ऐसे लेन-देन स्थितियों अथवा परिस्थितियों में परिवर्तन के कारण अर्जित अथवा निपटायी गयी नकदी अथवा नकदी तुल्यों की सूचना नकदी प्रवाह विवरणी में निबल दी जाती है।
- 42 क. किसी अनुषंगी के स्वामित्व हितों में हुए परिवर्तनों के फलस्वरूप जिन नकदी प्रवाहों से नियंत्रण नहीं खोना पड़ता उन्हें वित्तपोषण गतिविधियों से उद्भूत नकदी प्रवाह माना जाएगा ।
- 42 ख. किसी अनुषंगी के स्वामित्व हितों में हुए जिन परिवर्तनों के परिणामस्वरूप जैसे कि मूल प्रतिष्ठान द्वारा बाद में अनुषंगी की इक्विटी लिखतों का क्रय अथवा विक्रय होता है उन्हें इक्विटी लेन-देन के रूप में दिखाया जाता है [देखें भारतीय लेखा मानक 27 'समेकित एवं पृथक् वित्तीय विवरण'] । तदुसार, उसके परिणाम के रूप में होने वाले नकदी प्रवाहों को उसी रूप में वर्गीकृत किया जाता है जैसा कि अनुच्छेद 17 में वर्णित स्वामित्व सहित अन्य लेन-देन को किया जाता है।

गैर-नकदी लेन-देन

43. जिन निवेश और वित्तपोषण लेन-देन में नकदी अथवा नकदी तुल्यों की जरूरत नहीं होती नकदी प्रवाह विवरणी में शामिल नहीं किया जाएगा। इस तरह के लेन-देन को अन्यत्र वित्तीय विवरणों में इस रूप में दर्शाया जाएगा कि निवेश और वित्तपोषण गतिविधियों के संबंध में पूर्ण प्रासंगिक सूचना मिल जाये।
44. बहुत-सी निवेश व वित्तपोषण गतिविधियां, मौजूदा नकदी प्रवाह को प्रभावित नहीं करती। उनका प्रतिष्ठान की पूंजी और आस्ति संरचना पर प्रत्यक्ष प्रभाव होता है। नकदी प्रवाह विवरण में से नकदी से भिन्न लेन-देन को निकाल देना नकदी प्रवाह विवरण के उद्देश्य के अनुरूप ही है क्योंकि इन मदों में मौजूदा अवधि का नकदी प्रवाह शामिल नहीं है। नकदी से भिन्न लेन-देन के उदाहरण निम्नलिखित हैं :-
- (क) सीधे ही देयताओं को अपना कर आस्तियों का अधिग्रहण अथवा वित्तीय पट्टे के माध्यम से
 - (ख) इक्विटी निर्गम द्वारा किसी प्रतिष्ठान का अधिग्रहण, और
 - (ग) ऋण को 'इक्विटी' में बदलना

नकदी और नकदी- तुल्यों के घटक

45. कोई भी प्रतिष्ठान नकदी और नकदी तुल्यों के घटकों की जानकारी देगा और अपने नकदी प्रवाह विवरण में रकमों का मिलान तुलन पत्र में बतायी गयी समान मदों से प्रस्तुत करेगा।
46. विश्वभर में नकदी प्रबंध की अनेक प्रथायें तथा बैंकिंग व्यवस्थाएं प्रचलित हैं। इसे ध्यान में रखते हुए, भारतीय लेखा-मानक 1 'वित्तीय विवरणों का प्रस्तुतिकरण' का अनुपालन करते हुए प्रत्येक प्रतिष्ठान अपनी नीति प्रकट करता है जो नकदी और नकदी तुल्यों के स्वरूप को तय करने के लिए अपनाता है।
47. नकदी और नकदी तुल्यों का स्वरूप तय करने वाली किसी भी नीति (पॉलिसी) में किसी परिवर्तन का प्रभाव, उदाहरण के लिए, जो वित्तीय लिखतें अतीत में प्रतिष्ठान के निवेश पोर्टफोलियों का हिस्सा मानी जाती थी उन्हें वर्गीकरण में परिवर्तित करके भारतीय लेखा मानक 8 'लेखा नीतियां, लेखा प्राक्कलनों में परिवर्तन और त्रुटियाँ' के अनुसार सूचित किया जाता है।

अन्य प्रकटन

48. प्रत्येक प्रतिष्ठान, प्रबंधन की टिप्पणियों के साथ प्रतिष्ठान के पास रखे गये प्रमुख नकदी और नकदी तुल्यों के शेषों की राशि का प्रकटन करेगा जो समूह¹ द्वारा इस्तेमाल के लिए उपलब्ध नहीं है।
49. ऐसी बहुत-सी परिस्थितियां होती हैं जिनमें प्रतिष्ठान की नकदी और नकदी तुल्य समूह² के प्रयोग के लिए उपलब्ध नहीं होती। इन उदाहरणों में शामिल हैं अनुषंगी के पास नकदी और नकदी तुल्य के शेष हैं

लेकिन वह किसी ऐसे देश में कार्य कर रही हैं जहां विदेशी मुद्रा नियंत्रण और अन्य विधिक प्रतिबंध लागू होते हैं और मुख्य प्रतिष्ठान और इसकी अनुषंगियों के अपने आम प्रयोग के लिए यह शेष राशि उपलब्ध न हो।

50. किसी प्रतिष्ठान की वित्तीय स्थिति अथवा तरलता को समझने के लिए प्रयोगकर्ताओं के लिए अतिरिक्त सूचना प्रासंगिक होती है। प्रबंधन की टिप्पणी सहित इस सूचना के प्रकटन को प्रोत्साहित किया जाता है और इसमें निम्नलिखित शामिल हो सकते हैं :-

- (क) अनहरित उधार सुविधाओं की राशि, जो भावी परिचालन गतिविधियों के संचालन तथा पूंजीगत प्रतिबद्धताओं के भुगतान लिए उपलब्ध हो। इन सुविधाओं पर यदि किसी प्रकार के प्रतिबंध हैं तो उनके संकेत दें ;
- (ख) आनुपातिक समेकन का इस्तेमाल करते हुए संयुक्त उद्यमों में हितों से संबंधित परिचालन, निवेश और वित्तपोषण गतिविधियों में से प्रत्येक से नकदी प्रवाह की कुल राशि;
- (ग) नकदी प्रवाह की ऐसी कुल राशि जो परिचालन क्षमता में वृद्धि का प्रतिनिधित्व करती हो तथा उस नकदी-प्रवाह से भिन्न हो जो परिचालन क्षमता बनाये रखने के लिए अपेक्षित हो; और
- (घ) प्रत्येक रिपोर्ट करने योग्य भाग की परिचालन, निवेश और वित्तपोषण गतिविधियों से उद्भूत नकदी- प्रवाह की राशि (देखें भारतीय लेखा मानक 108 ' परिचालन खण्ड ') ।

51. जो नकदी- प्रवाह परिचालन वृद्धि की जानकारी देते हैं तथा जो नकदी-प्रवाह परिचालन क्षमता को बनाये रखने के लिए जरूरी हैं उनकी अलग- अलग जानकारी देने से प्रयोगकर्ता को यह पता लगता है कि क्या प्रतिष्ठान परिचालन क्षमता को बनाये रखने के लिए पर्याप्त निवेश कर रहा है या नहीं। यदि वह ऐसा नहीं कर रहा है तो संभव है वह अपनी मौजूदा तरलता और मालिकों को वितरण के लिए भावी लाभप्रदता को संकट में डाल रहा होगा।

52. खण्डों के नकदी प्रवाह की जानकारी से प्रयोगकर्ताओं को समग्र रूप से प्रतिष्ठान के कारोबार के नकदी-प्रवाह तथा उसके घटक के बीच संबंधों एवं खण्डों के नकदी प्रवाह की उपलब्धता और उनकी परिवर्तनशीलता का पता चलता है।

-
1. पृथक वित्तीय विवरणों के मामले में भी अपेक्षाएं समान रूप से लागू होंगी।
 2. पूर्वोक्त

परिशिष्ट 'क'**दृष्टान्त उदाहरण****वित्तीय संस्थान से भिन्न प्रतिष्ठान के नकदी-प्रवाह विवरण**

यह परिशिष्ट भारतीय लेखा मानक 7 के साथ संलग्न है परन्तु यह उसका अंग नहीं है।

1. उदाहरणों में केवल मौजूदा अवधि की राशियां दर्शायी गयी हैं। पिछली अवधि के अनुरूपी आंकड़ों को भारतीय लेखा- मानक 1 ' वित्तीय विवरणों का प्रस्तुतिकरण ' के अनुसार प्रस्तुत किया जाएगा।
2. लाभ-हानि विवरण तथा तुलन-पत्र की सूचना इसलिए दी जाती है ताकि यह पता लग सके कि प्रत्यक्ष विधि और अप्रत्यक्ष विधि के अंतर्गत नकदी प्रवाह विवरण कैसे तैयार किये गये हैं। न तो लाभ-हानि विवरण और न ही तुलन-पत्र अन्य मानकों के प्रकटन और प्रस्तुति की अपेक्षाओं के अनुरूप तैयार किये गये हैं।
3. नकदी प्रवाह विवरण तैयार करने के लिए निम्नलिखित अतिरिक्त सूचना भी प्रासंगिक है :
 - अनुबंधी के सभी शेयर 590 के लिए अर्जित किये गये थे। अर्जित आस्तियों और परिकल्पित देयताओं के उचित मूल्य इस प्रकार हैं :-

सूचीबद्ध सामान (इन्वेंट्री)	100
प्राप्य खाते	100
नकदी	40
सम्पत्ति, संयंत्र और उपस्कर	650
व्यापार देय	100
दीर्घावधि ऋण	200

- शेयर पूंजी के निर्गम से 250 प्राप्त हुए थे और दीर्घकालीन उधारों से 150 तथा 100 अल्प-कालीन उधारों से प्राप्त हुए थे।
- ब्याज-व्यय 400 था जिसमें से अवधि के दौरान 170 का भुगतान किया गया। साथ ही, पूर्व अवधि के ब्याज व्यय 100 का भुगतान भी इस अवधि के दौरान किया गया।
- प्रदत्त लाभांश 1,200 थे।

- अवधि के प्रारम्भ तथा अंत में कर-देयता क्रमशः 1,000 और 400 थी । अवधि के दौरान, 200 कर प्रावधान किया गया । प्राप्त लाभांशों पर कर रोके रखना 100 था ।
- अवधि के दौरान समूह ने कुल 1250 लागत की संपत्ति , संयंत्र और उपस्कर अधिगृहीत किये जिनमें से 900 वित्तीय पट्टे से अधिगृहीत किये गये । संपत्ति , संयंत्र और उपस्कर के लिए 350 का नकद भुगतान किया गया ।
- 80 की मूल लागत तथा 60 के संचित मूल्यहास वाला संयंत्र 20 में बेचा गया ।
- 20x2 के अंत में प्राप्य लेखों में प्राप्य ब्याज के रूप में 100 सम्मिलित हैं ।

20x2 ^(क) को समाप्त अवधि के लिए लाभ हानि का समेकित विवरण

बिक्रियां	30,650
बिक्रियों की लागत	<u>(26,000)</u>
सकल लाभ	4650
मूल्यहास	(450)
प्रशासनिक तथा बिक्री खर्च	(910)
ब्याज खर्च	(400)
निवेश आय	500
विदेशी विनिमय हानि	<u>(40)</u>
कर-पूर्व लाभ	3,350
आय पर कर	<u>(300)</u>
लाभ	<u>3,050</u>

(क) 20x2 को समाप्त अवधि में प्रतिष्ठान ने अन्य व्यापक आय के किसी घटक को मान्यता नहीं दी ।

20x2 के अंत में समेकित तुलन-पत्र

	20x2	20x1
आस्तियां		
नकदी और नकदी तुल्य	230	160
प्राप्य खाते	1,900	1,200
सूचीबद्ध सामान (इन्वेंट्री)	1,000	1,950
पोर्टफोलियो निवेश	2,500	2,500
सम्पत्ति, संयंत्र और उपस्कर लागत पर	3,730	1,910
संचित मूल्यह्रास	<u>(1,450)</u>	<u>(1,060)</u>
सम्पत्ति, संयंत्र और उपस्कर-निवल	2,280	850
कुल आस्तियां	<u>7,910</u>	<u>6,660</u>
देयताएं		
व्यापार देय	250	1,890
देय ब्याज	230	100
देय आयकर	400	1,000
दीर्घावधि ऋण	<u>2,200</u>	<u>1,040</u>
अत्पावधि उधार	<u>100</u>	-----
कुल देयतायें	<u>3,180</u>	<u>4,030</u>
शेयरधारकों की इक्विटी		
शेयर पूंजी	1,500	1,250

प्रतिधारित आय	<u>3,230</u>	<u>1,380</u>
शेयरधारकों की कुल इक्विटी	<u>4,730</u>	<u>2,630</u>
कुल देयतायें और शेयरधारकों की इक्विटी	<u>7,910</u>	<u>6,660</u>

नकदी प्रवाहों का विवरण - प्रत्यक्ष विधि (अनुच्छेद 18 (क))

20x2

परिचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह

ग्राहकों से नकद प्राप्तियां	30,150
आपूर्तिकर्ताओं और कर्मचारियों को किया गया नकद भुगतान	<u>(27,600)</u>
परिचालनों से सृजित नकदी	2,550
प्रदत्त आयकर	<u>(900)</u>

परिचालन गतिविधियों से निवल नकदी

1,650

निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह

अनुषंगी X का अधिग्रहण, अर्जित निवल नकदी (टिप्पणी 'क')	(550)
संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर की खरीद (टिप्पणी 'ख')	(350)
उपस्कर की बिक्री से प्राप्त राशि	20
प्राप्त ब्याज	200
प्राप्त लाभांश	<u>200</u>

निवेश गतिविधियों में प्रयुक्त निवल नकदी

(480)

वित्तपोषण गतिविधियों से नकदी प्रवाह

शेयर पूंजी के निर्गम से प्राप्त राशि	250	
दीर्घकालीन उधारों से प्राप्त राशि	150	
अल्पकालीन उधारों से प्राप्त राशि	100	
वित्त पट्टा देयताओं का भुगतान	(90)	
प्रदत्त ब्याज	(270)	
प्रदत्त लाभांश	(1200)	
वित्तपोषण गतिविधियों में प्रयुक्त निवल नकदी		<u>(1,060)</u>
नकदी तथा नकदी तुल्यों में निवल वृद्धि		110
अवधि के प्रारंभ में नकदी तथा नकदी तुल्य (टिप्पणी ग)		<u>120</u>
अवधि की समाप्ति पर नकदी तथा नकदी तुल्य (टिप्पणी ग)		<u><u>230</u></u>

नकदी प्रवाह का विवरण अप्रत्यक्ष विधि (अनुच्छेद 18 (ख))

20x2

परिचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह

कर-पूर्व लाभ	3,350
निम्नलिखित के लिए समायोजन :-	
मूल्यहास	450
विदेशी विनिमय हानि	40
निवेश आय	(500)
ब्याज व्यय	<u>400</u>
	3740
व्यापार तथा अन्य प्राप्य राशियों में वृद्धि	(500)
माल सूची में कमी	1,050
व्यापार देय-राशियों में कमी	<u>(1,740)</u>

परिचालनों से सृजित नकदी	2550	
प्रदत्त आयकर	(900)	
परिचालन गतिविधियों से निवल नकदी		1650

निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह

अनुषंगी X का अधिग्रहण - अर्जित निवल नकदी (टिप्पणी 'क')	(550)	
सम्पत्ति , संयंत्र व उपस्कर की खरीद (टिप्पणी 'ख')	(350)	
उपस्करों की बिक्री से प्राप्त राशि	20	
प्राप्त ब्याज	200	
प्राप्त लाभांश	200	
निवेश गतिविधियों में प्रयोग में लायी गयी निवल नकदी		(480)

वित्तपोषण गतिविधियों से नकदी प्रवाह

शेयर पूंजी के निर्गम से प्राप्त राशि	250	
दीर्घकालीन उधारों से प्राप्त राशि	150	
अल्पकालीन उधारों से प्राप्त राशि	100	
वित्तीय पट्टा देयताओं का भुगतान	(90)	
प्रदत्त ब्याज	(270)	
प्रदत्त लाभांश	(1200)	
वित्तपोषण गतिविधियों में प्रयुक्त निवल नकदी		(1,060)

नकदी तथा नकदी तुल्यों में निवल वृद्धि	110
अवधि के प्रारंभ में नकदी तथा नकदी तुल्य (टिप्पणी ग)	120
अवधि की समाप्ति पर नकदी तथा नकदी तुल्य (टिप्पणी ग)	230

नकदी प्रवाहों के विवरणों पर टिप्पणियां (प्रत्यक्ष विधि एवं अप्रत्यक्ष विधि)

क. अनुषंगी पर नियंत्रण पाना

अवधि के दौरान, समूह ने अनुषंगी X पर नियंत्रण प्राप्त किया। अर्जित आस्तियों तथा अनुमानित देयताओं का उचित मूल्य निम्नलिखित था।

नकदी	40
सूचीबद्ध सामान (इन्वेंट्री)	100
प्राप्य खाते	100
संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर	650
व्यापार की देय राशियां	(100)
दीर्घकालीन ऋण	(200)
नकद रूप में प्रदत्त कुल क्रय मूल्य	590
घटाइए : अर्जित अनुषंगी X की नकदी	(40)
अर्जित नकदी घटाकर नियंत्रण हेतु प्रदत्त नकदी	550

ख. सम्पत्ति, संयंत्र और उपस्कर

अवधि के दौरान समूह ने सम्पत्ति, संयंत्र और उपकरण अर्जित किये जिनकी कुल लागत 1250 थी जिसमें से 900 का अर्जन वित्तीय पट्टे के माध्यम से किया गया। सम्पत्ति, संयंत्र और उपस्कर की खरीद के लिए 350 का नकद भुगतान किया गया।

ग. नकदी तथा नकदी-तुल्य

नकदी तथा नकदी तुल्यों में हाथ में नकदी और बैंकों के पास शेष एवं मुद्रा बाजार लिखतों (मनी मार्केट इन्स्ट्रुमेंट्स) में निवेश शामिल हैं। नकदी प्रवाह विवरण में शामिल नकदी और नकदी तुल्यों में तुलन पत्र की निम्नलिखित राशियां सम्मिलित हैं :

	20x2	20x1
हाथ में नकदी तथा बैंकों पास शेष	40	25
अल्पकालीन निवेश	190	135
पहले सूचित नकदी तथा नकदी तुल्य	230	160

विनिमय दर परिवर्तनों का प्रभाव	--	(40)
पुनर्कथित नकदी और नकदी तुल्य	230	120

अवधि के अंत में नकदी और नकदी तुल्यों में अनुषंगी की ओर से बैंकों के पास 100 जमा राशियां हैं जो धारक कम्पनी को मुद्रा विनिमय प्रतिबंधों के कारण स्वतंत्र रूप से देय नहीं हैं।

समूह के पास 2000 अनहरित उधार सुविधायें हैं जिनमें से 700 का उपयोग केवल भावी विस्तार के लिए किया जायेगा।

घ. खण्डीय सूचना

	खण्ड 'क'	खण्ड 'ख'	जोड़
निम्नलिखित से नकदी प्रवाह			
परिचालन गतिविधियां	1,790	(140)	1650
निवेश गतिविधियां	(640)	160	(480)
वित्तपोषण गतिविधियां	(840)	(220)	(1060)
	<u>310</u>	<u>(200)</u>	<u>110</u>

वैकल्पिक प्रस्तुति (अप्रत्यक्ष विधि)

एक विकल्प के रूप में, नकदी प्रवाह विवरण की अप्रत्यक्ष विधि में कार्यकारी पूंजी के परिवर्तनों से पूर्व परिचालन लाभ कभी कभी निम्नलिखित ढंग से प्रस्तुत किया जाता है :-

निवेश आय को छोड़कर राजस्व	30,650	
मूल्यहास को छोड़कर परिचालन व्यय	<u>(26,910)</u>	
कार्यकारी पूंजी परिवर्तनों से पूर्व परिचालन लाभ		<u>3,740</u>

परिशिष्ट 'ख'**दृष्टांत उदाहरण****वित्तीय संस्थान के लिए नकदी प्रवाह विवरण**

यह परिशिष्ट भारतीय लेखा मानक 7 के साथ संलग्न है परन्तु उसका अंग नहीं है

1. यह उदाहरण केवल मौजूदा अवधि की राशि दर्शाता है। पिछली अवधि के तुलनीय आंकड़े भारतीय लेखा मानक 1 'वित्तीय विवरणों का प्रस्तुतिकरण' के अनुसार प्रस्तुत किए जाएंगे।
2. इस उदाहरण में प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग किया गया है।

20x2**परिचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह**

ब्याज एवं कमीशन प्राप्तियां	28,447
ब्याज भुगतान	(23,463)
पूर्व में बट्टे खाते डाले गए ऋणों की वसूली	237
कर्मचारियों और आपूर्तिकर्ताओं को नकद भुगतान	(997)
	<hr/> 4,224

परिचालन आस्तियों में (वृद्धि) कमी :

अल्पकालीन निधियां	(650)
विनियामक अथवा मौद्रिक नियंत्रण के प्रयोजनों से धारित जमा राशियां	234
ग्राहकों को अग्रिम के रूप में दी गई निधियां	(288)
क्रेडिट कार्ड प्राप्त राशियों में निवल वृद्धि	(360)
अन्य अल्पकालिक परक्राम्य प्रतिभूतियां	(120)

परिचालन देयताओं में वृद्धि (कमी)

ग्राहकों से जमा राशि	600
परक्राम्य जमा प्रमाण-पत्र	(200)

आयकर से पूर्व परिचालन गतिविधियों से निवल नकदी	3,440	
प्रदत्त आयकर	<u>(100)</u>	
परिचालन गतिविधियों में निवल नकदी		3,340

निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह

अनुषंगी 'वाई' का निपटान	50	
प्राप्त लाभांश	200	
प्राप्त ब्याज	300	
गैर डीलिंग प्रतिभूतियों से प्राप्तियां	1200	
गैर डीलिंग प्रतिभूतियों की खरीद	(600)	
संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों की खरीद	<u>(500)</u>	
निवेश गतिविधियों से निवल नकदी		650

वित्तपोषण गतिविधियों से नकदी प्रवाह

ऋण पूंजी का निर्गम	1000	
अनुषंगी उपक्रम द्वारा अधिमान शेयरों का निर्गम	800	
दीर्घकालीन उधारों की चुकौती	(200)	
अन्य उधारों में निवल कमी	(1000)	
प्रदत्त लाभांश	<u>(400)</u>	
वित्तपोषण गतिविधियों में निवल नकदी		200
नकदी तथा नकदी तुल्यों पर विनिमय दरों के परिवर्तनों का प्रभाव		600
नकदी तथा नकदी तुल्यों में निवल वृद्धि		<u>4790</u>
अवधि के प्रारम्भ में नकदी तथा नकदी तुल्य		<u>4050</u>
अवधि के अंत में नकदी तथा नकदी तुल्य		<u>8840</u>

परिशिष्ट 1

टिप्पणी : यह परिशिष्ट भारतीय लेखा मानक का अंग नहीं है। इस परिशिष्ट का प्रयोजन मात्र इतना है कि यदि भारतीय लेखा मानक (इंड ए एस) 7 और तदनुसूची अंतरराष्ट्रीय लेखा मानक (आईएस) 7 - 'नकदी प्रवाह विवरण' के बीच यदि कोई प्रमुख अंतर है तो उसे स्पष्ट किया जाये।

अंतरराष्ट्रीय लेखा मानक (आईएस) 7 'नकदी प्रवाह विवरण' के साथ तुलना

भारतीय लेखा मानक 7 और अंतरराष्ट्रीय लेखा-मानक 7, 'नकदी प्रवाह विवरण' में मुख्य अंतर निम्नलिखित हैं :

1. वित्तीय प्रतिष्ठानों से भिन्न प्रतिष्ठानों के मामले में अंतरराष्ट्रीय लेखा-मानक 7 यह विकल्प देता है कि प्रदत्त ब्याज और प्राप्त लाभांशों को परिचालन नकदी प्रवाह की मद के रूप में वर्गीकृत किया जाये। लेकिन, भारतीय लेखा मानक 7 ऐसा कोई विकल्प नहीं देता और यह अपेक्षा करता है कि इन मदों को क्रमशः वित्तपोषण गतिविधि और निवेश गतिविधि के रूप में वर्गीकृत किया जाये (कृपया अनुच्छेद 33 देखें)
2. अंतरराष्ट्रीय लेखा मानक 7 यह विकल्प देता है कि प्रदत्त लाभांश को परिचालन गतिविधि की मद के रूप में वर्गीकृत किया जाये। परंतु भारतीय लेखा मानक 7 इसे केवल वित्तपोषण गतिविधि के अंग के रूप में वर्गीकृत करने की अनुमति देता है।
3. इस मानक में भिन्न शब्दावली का प्रयोग किया गया है, उदाहरणतया, शब्दों 'वित्तीय स्थिति का विवरण' के स्थान पर शब्द 'तुलन-पत्र' और शब्दों 'व्यापक आय का विवरण' के स्थान पर शब्द 'लाभ-हानि विवरण' का प्रयोग किया गया है।
4. अन्तरराष्ट्रीय लेखा मानक 7 के अनुच्छेद 2 में यह उल्लेख किया गया है कि इसी लेखा मानक अर्थात् आई ए एस 7 के पूर्ववर्ती संस्करण का अधिक्रमण कर दिया गया है अतः उसे भारतीय लेखा मानक (इंड ए एस) 7 से हटा दिया गया है क्योंकि इस लेखा मानक अर्थात् इंड ए एस 7 में यह प्रासंगिक नहीं है। लेकिन, अनुच्छेद संख्या 2 को इंड ए एस 7 में रख लिया गया ताकि अन्तरराष्ट्रीय लेखा मानक (आई ए एस) 7 के अनुच्छेदों से क्रमबद्धता बनी रहे।
5. अन्तरराष्ट्रीय लेखा मानक 7 में निम्नलिखित अनुच्छेद 'हटाया गया' इंगित हैं। अन्तरराष्ट्रीय लेखा मानक (आई ए एस) 7 में अनुच्छेदों की संख्या के साथ क्रमबद्धता बनाये रखने के लिए इन (निम्नलिखित) अनुच्छेद संख्याओं को रहने दिया गया है -

(i) अनुच्छेद 29

(ii) अनुच्छेद 30

भारतीय लेखा मानक (इंड ए एस) 8

लेखा नीतियां, लेखा प्राक्कलनों में परिवर्तन एवं त्रुटियां

(इस भारतीय लेखा-मानक में मोटे टाइप व सामान्य टाइप में अनुच्छेद हैं। इन दोनों तरह के अनुच्छेदों का समान प्राधिकार है। मोटे टाइप में अनुच्छेद, मुख्य सिद्धान्तों के सूचक हैं।)

उद्देश्य

1. इस मानक का उद्देश्य है लेखा नीतियों के चयन व परिवर्तन के साथ-साथ लेखा नीतियों में परिवर्तनों के प्रकटन एवं लेखा व्यवहार तथा लेखा प्राक्कलनों में परिवर्तन व त्रुटियों को ठीक करने के लिए मानदंड निर्धारित करना। इस मानक का उद्देश्य यह भी है कि एक प्रतिष्ठान के वित्तीय विवरणों की प्रसंगिता व विश्वसनीयता के साथ-साथ उनकी किन्हीं दूसरे प्रतिष्ठानों के साथ तुलनात्मकता कैसे बढ़ायी जाए।
2. लेखा नीतियों में परिवर्तनों को छोड़कर, लेखा नीतियों के प्रकटन की अपेक्षाओं को भारतीय लेखा मानक (इंड ए एस) 1 'वित्तीय विवरणों की प्रस्तुति' के अंतर्गत दिया गया है।

कार्यक्षेत्र

3. इस मानक का प्रयोग लेखा नीतियों के चयन व इस्तेमाल और लेखा नीतियों में परिवर्तनों के लेखे, लेखा प्राक्कलनों में परिवर्तन और पूर्व अवधि की त्रुटियों को ठीक करने के लिए किया जाएगा।
4. पूर्व अवधि की त्रुटियों को ठीक करने और लेखा नीतियों में परिवर्तनों को लागू करने से गत प्रभाव से किये गये समायोजनों से कर प्रभावों का लेखा व प्रकटन भारतीय लेखा मानक (इंड ए एस) 12 'आयकर' के अनुसरण में किया जाएगा।

परिभाषाएं

5. इस मानक में निम्नलिखित शब्दावली यहां विनिर्दिष्ट अर्थों में प्रयोग की गयी है :-

लेखा नीतियां से अभिप्रायः है एक प्रतिष्ठान द्वारा अपने वित्तीय विवरणों को तैयार व प्रस्तुत करने के लिए कुछ विशिष्ट सिद्धान्तों, आधारों, प्रथाओं, नियमों व व्यवहारों को लागू करना।

लेखा प्राक्कलन में परिवर्तन से अभिप्राय है आस्ति या देयता की अग्रणीत (कैरिंग) राशि अथवा आस्तियों व देयताओं से संबंधित लाभों व दायित्वों के वर्तमान या भविष्य में प्रत्याशित स्तर के मूल्यांकन के फलस्वरूप किसी आस्ति के आवधिक उपभोग की राशि के समायोजन। लेखा प्राक्कलनों (अनुमानों) में परिवर्तन नयी सूचना अथवा नये परिवर्तनों के फलस्वरूप होते हैं। अतः इन्हें त्रुटियों को ठीक करना नहीं कहा जा सकता।

भारतीय लेखा मानक (इंड ए एस) से अभिप्राय: उन मानकों (स्टैंडर्ड) से हैं जिन्हें कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 211 (3 ग) के अंतर्गत निर्धारित किया गया है।

महत्वपूर्ण त्रुटि या मदों की त्रुटिपूर्ण व्याख्या उसी अर्थ में महत्वपूर्ण है जो अकेले या संयुक्त रूप से उन आर्थिक निर्णयों को प्रभावित करती हैं जिन्हें प्रयोगकर्ता वित्तीय विवरणों के आधार पर लेते हैं। महत्वपूर्ण होना इस बात पर निर्भर करता है कि त्रुटि या त्रुटिपूर्ण कथन संबंधित हालात के अनुसार आकार में कितना बड़ा या प्रकृति में कैसा है या फिर दोनों ही इसके निर्धारक तत्व हैं।

पूर्व अवधि की त्रुटियाँ से अभिप्राय: उन त्रुटियों या त्रुटिपूर्ण कथनों से हैं जो एक प्रतिष्ठान की एक या एक से अधिक की पूर्व अवधियों की वित्तीय विवरणों से संबंधित हैं और जो निम्नलिखित स्थितियों में विश्वस्त सूचना के प्रयोग या दुरुपयोग के कारण हुई हैं:

- क) यह सूचना उस समय उपलब्ध थी जब उन अवधियों के संबंध में वित्तीय विवरण जारी करने के लिए अनुमोदित थे।
- ख) वह सूचना उन वित्तीय विवरणों के तैयार करने और प्रस्तुत करने के समय आसानी से प्राप्त की जा सकती थी।

इन त्रुटियों में गणितीय त्रुटियों, लेखनीतियों के प्रयोग की त्रुटियों, तथ्यों की अनदेखी या उन्हें गलत रूप से प्रस्तुत करना और धोखाधड़ी (फ्राड) के प्रभाव सम्मिलित हैं।

पूर्व प्रभावी प्रयोग का अभिप्राय: यह है कि एक नई लेखा नीति को लेनदेनों, अन्य घटनाओं व परिस्थितियों पर ऐसे लागू करना कि मानों वह नीति पहले से ही प्रयोग में लायी जा रही थी।

पूर्व प्रभावी पुनर्कथन से अभिप्राय: वित्तीय विवरणों के घटकों की राशियों की मान्यता (या पहचान), माप व प्रकटन को ऐसे ठीक करना कि मानो यह त्रुटि पहले कभी हुई ही नहीं थी।

अव्यवहार्य से अभिप्राय: उस स्थिति से है जब कोई प्रतिष्ठान हर संभव प्रयास करने पर भी उसे लागू नहीं कर सकता। एक विशेष पूर्व अवधि में एक लेखा नीति में पूर्व प्रभाव से परिवर्तन का प्रयोग या पूर्व प्रभाव से पुनर्कथन निम्नलिखित स्थितियों में त्रुटि को ठीक करना अव्यवहार्य हो सकता है:

- क) पूर्ववर्ती प्रयोग या पूर्ववर्ती पुनर्कथन के प्रभाव निश्चित नहीं किये जा सकते हों।
- ख) पूर्ववर्ती प्रयोग या पूर्ववर्ती पुनर्कथन में ऐसी कुछ पूर्व धारणाएं अपेक्षित हों जिनसे यह पता चले कि उस अवधि के दौरान प्रबंधन का आशय या उद्देश्य क्या था।
- ग) पूर्ववर्ती प्रयोग या पूर्ववर्ती पुनर्कथन में राशियों के महत्वपूर्ण प्राक्कलन (अनुमान) अपेक्षित हों और इन प्राक्कलनों की सूचना का वस्तुनिष्ठ रूप में पता लगाना निम्नलिखित स्थितियों में असंभव है:

1. उस तारीख (उन तारीखों) पर जिन पर कि उन राशियों को मान्यता दी जाती है, वे मापी जाती हैं या जिन्हें किया जाता है, सूचना दी जाती है उन पर मौजूदा परिस्थितियों का साक्ष्य (प्रमाण) देना।

2. जब उस पूर्ववर्ती अवधि के वित्तीय विवरण किसी अन्य सूचना के आधार पर जारी करने के लिए अनुमोदित किए जाते हैं ऐसी स्थिति में वास्तविक सूचना की उपलब्धता।

संभावित प्रयोग लेखा नीति में परिवर्तन के संभावित प्रयोग और लेखा प्राक्कलन में संभावित परिवर्तन के प्रभाव की मान्यता क्रमशः इस प्रकार से है:

- क) नीति परिवर्तन की तारीख के बाद नई लेखा नीति को उन लेन-देनों, अन्य घटनाओं और परिस्थितियों पर लागू करना जो उस तारीख के बाद घटित हुई हों।
- ख) परिवर्तन से प्रभावित वर्तमान व भावी अवधियों के लेखा प्राक्कलन में परिवर्तन के प्रभाव का पता लगाना।
6. इस बात का मूल्यांकन करना कि त्रुटियां या त्रुटिपूर्ण कथन प्रयोगकर्ताओं के आर्थिक निर्णयों को किस हद तक प्रभावित कर सकते हैं और ये कितने महत्वपूर्ण हैं इसके लिए उन प्रयोगकर्ताओं की विशेषताओं पर भी विचार करना आवश्यक है। भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी वित्तीय विवरणों को तैयार करने और उन्हें प्रस्तुत करने की मूलभूत पद्धति के अनुच्छेद 26 में यह उल्लेख है कि "यह आशा की जाती है कि प्रयोगकर्ताओं के अपने कारोबार व आर्थिक गतिविधियों के साथ-साथ लेखे की आवश्यक जानकारी है और वे सूचना का प्रयोग पूरी सावधानी से करते हैं।" अतः किये गये मूल्यांकन में यह जानना आवश्यक है कि प्रयोगकर्ता इन अपेक्षाओं में आर्थिक निर्णय लेते हुए किस प्रकार प्रभावित हो सकते हैं।

लेखा नीतियां

लेखा नीतियों का चयन एवं प्रयोग

7. जब कोई भारतीय लेखा मानक (इंड ए एस) विशेष तौर पर किसी लेन-देन, अन्य घटना या परिस्थिति पर प्रयोग किया जाता है, तो उस मद पर लागू लेखा नीति या नीतियां इस भारतीय लेखा मानक द्वारा निर्धारित होंगी।
8. भारतीय लेखा मानक लेखा नीतियां निर्धारित करते हैं। ये नीतियां उन वित्तीय विवरणों का सृजन करती हैं जो लेनदेनों, व अन्य घटनाओं व परिस्थितियों के बारे में प्रासंगिक व विश्वसनीय सूचना प्रदान करती हैं। उन नीतियों को प्रयोग में लाने की आवश्यकता नहीं है जिनका प्रभाव मामूली हो। लेकिन एक प्रतिष्ठान की वित्तीय स्थिति, कार्य निष्पादन या नकदी प्रवाह की विशेष प्रस्तुति की प्राप्ति के लिए लेखा के किसी भी त्रुटिपूर्ण व मामूली विचलन की उपस्थिति या उसकी उपेक्षा उचित नहीं है।
9. लेखा मानकों के साथ प्रतिष्ठानों की सहायता के लिए मार्गदर्शन भी संलग्न किया जाता है। इस मार्गदर्शन में यह उल्लेख किया जाता है कि क्या यह मार्गदर्शन भारतीय लेखा मानक का अभिन्न अंग है या नहीं। जहां मार्गदर्शन भारतीय लेखा मानक का अभिन्न अंग है वहां इसका प्रयोग अनिवार्य है। जहां यह मार्गदर्शन लेखा मानकों का अभिन्न अंग नहीं है वहां वित्तीय विवरणों के लिए उसकी अपेक्षा नहीं है।

10. किसी लेन देन, अन्य घटना या परिस्थिति के प्रयोग के लिए जहां कोई विशेष भारतीय लेखा मानक लागू नहीं होता है, प्रबंधन अपने विवेकानुसार एक ऐसी लेखा नीति के विकास व प्रयोग का निर्णय लेगा जोकि निम्नलिखित प्रकार की सूचना प्रदान करेगा:
- क) ऐसी सूचना जो प्रयोगकर्ताओं की आवश्यकता अनुसार उनके आर्थिक निर्णयों के लिए आवश्यक हो।
- ख) सूचना विश्वसनीय हो और वित्तीय विवरण निम्नलिखित की पूर्ति कर सकें :
- विवरण प्रतिष्ठान की वित्तीय स्थिति, वित्तीय कार्य निष्पादन और नकदी प्रवाह का सही चित्रण हों ;
 - विवरण मात्र वैधानिक अपेक्षा की पूर्ति न होकर वे प्रतिष्ठान के लेन-देनों, अन्य घटनाओं व परिस्थितियों के सारतत्त्व को भी प्रदर्शित कर सकें ;
 - वे किसी पूर्वाग्रह से ग्रस्त न होकर तटस्थ हों ;
 - वे विवेकपूर्ण हों ; तथा
 - वे हर प्रकार से पूर्ण हों यानि उनमें सभी महत्वपूर्ण सूचनाएं समाविष्ट हों।
11. उपर्युक्त अनुच्छेद 10 में यथा वर्णित निर्णय लेने के लिए, प्रबंधन निम्नलिखित स्रोतों का भी संदर्भ लेगा और उनके लागू करने की व्यवहार्यता पर भी घटते क्रम में विचार करेगा:
- क) ऐसे ही मामलों या इनसे संबंध मामलों के लिए लागू लेखा मानकों की क्या अपेक्षाएं हैं ?
- ख) मूलभूत पद्धति में आस्तियों, देयताओं, आय व व्यय की परिभाषाएं, मान्यता - मानदंड व माप संकल्पनाएं क्या हैं ?
12. उपर्युक्त अनुच्छेद 10 में यथावर्णित निर्णय लेने के लिए, प्रबंधन पहले अन्तरराष्ट्रीय लेखा मानक बोर्ड द्वारा हाल ही में की गई घोषणाओं, और इसके अभाव में, लेखा संबंधी साहित्य और उद्योग में स्वीकृत व्यवहारों, अन्य मानक निर्धारक निकायों द्वारा लेखा मानकों के विकास के लिए प्रयोग में लायी जा रही मूलभूत पद्धति के अनुसार की गयी घोषणाओं को विचार में लाएगा। लेकिन, उस सीमा तक कि इनका अनुच्छेद 11 में दिये गये स्रोतों के साथ कोई अन्तर्विरोध नहीं होना चाहिए।

लेखा नीतियों की एकरूपता

13. जब तक कोई भारतीय लेखा मानक ऐसी मदों के वर्गीकरण के लिए जिनमें अलग नीतियां उपयुक्त हो सकती हैं, आवश्यक न समझे या छूट दे, एक प्रतिष्ठान एक जैसे लेनदेनों, अन्य घटनाओं व परिस्थितियों के लिए एक ही तरह की लेखा नीतियों को चयन एवं प्रयोग करेगा। यदि कोई भारतीय लेखा मानक ऐसे वर्गीकरण के लिए आवश्यक समझता है या छूट देता है, तो उपयुक्त लेखा नीति का चयन करके उसे प्रत्येक श्रेणी में समान रूप से लागू किया जाएगा।

लेखा नीतियों में परिवर्तन

14. कोई भी प्रतिष्ठान निम्नलिखित स्थितियों में ही लेखा नीति में परिवर्तन करेगा :

- क) यदि परिवर्तन भारतीय लेखा मानक के अनुसार अपेक्षित है
- ख) यदि परिवर्तन से प्रतिष्ठान की वित्तीय स्थिति, वित्तीय कार्य निष्पादन या नकदी प्रवाह (कैश फ्लो) पर उसके लेनदेनों, अन्य घटनाओं या परिस्थितियों के प्रभाव के बारे में वित्तीय विवरण विश्वस्त और अधिक प्रासांगिक सूचना प्रदान करते हैं।

15. वित्तीय विवरणों के प्रयोगकर्ताओं को एक प्रतिष्ठान की वित्तीय विवरणों को अलग-अलग समय में तुलना करने की आवश्यकता पड़ती है ताकि वह प्रतिष्ठान की वित्तीय स्थिति, वित्तीय कार्य निष्पादन या नकदी प्रवाह (कैश फ्लो) में परिवर्तन के रुख को जान सकें। इसके लिए, यह आवश्यक है कि प्रत्येक अवधि और एक अवधि से दूसरी अवधि में तब तक उन्हीं लेखा मानकों का प्रयोग किया जाएगा जब तक अनुच्छेद 14 में दिये गये मानदंडों में किसी एक मानदंड के अनुसार परिवर्तन करना आवश्यक न हो।

16. निम्नलिखित स्थितियों को लेखा नीतियों में परिवर्तन नहीं कहा जाएगा:

- क) एक लेखा नीति का प्रयोग जिसमें विचाराधीन अवधि और गत अवधि के लेनदेनों, अन्य घटनाओं या परिस्थितियों में विशेष अंतर हो, और
- ख) एक नई लेखा नीति का प्रयोग जिसमें विचाराधीन अवधि की तुलना में गत अवधि में वे लेनदेन, अन्य घटनाओं या परिस्थितियां या तो विद्यमान न थीं या फिर कोई विशेष नहीं थीं।

17. भारतीय लेखा मानक (इंड ए एस) 16 'सम्पत्ति, संयंत्र एवं उपस्कर' अथवा भारतीय लेखा मानक (इंड ए एस) 26 'अमूर्त आस्तियां' के अनुसरण में आस्तियों के पुनर्मूल्यांकन के लिए नीति के प्रारंभिक प्रयोग को भारतीय लेखा मानक 10 या भारतीय लेखा मानक 26 न कि इस मानक के अनुसरण में पुनर्मूल्यांकन के लिए लेखा नीति में परिवर्तन माना जाएगा।

18. उपर्युक्त अनुच्छेद 17 में यथा उल्लिखित परिवर्तन नीचे अनुच्छेद 19 - 31 पर लागू नहीं होगा।

लेखा नीतियों में परिवर्तनों का प्रयोग

19. अनुच्छेद 23 के अधीन

- क) कोई भी प्रतिष्ठान भारतीय लेखा मानक (इंड ए एस) को प्रारंभिक प्रयोग के परिणामस्वरूप लेखा नीति में यदि कोई परिवर्तन करता है तो उसे वह परिवर्तन उस भारतीय लेखा मानक (इंड ए एस) के विशिष्ट संक्रमणकालीन उपबंधों के, यदि कोई हैं, अनुसरण में ही करेगा।
- ख) जब प्रतिष्ठान उस भारतीय लेखा मानक जिसमें लेखा नीति में स्वेच्छिक रूप से एक या एक से अधिक परिवर्तन करने के विशिष्ट संक्रमणकालीन उपबंध नहीं हैं, भारतीय लेखा मानक के प्रारंभिक प्रयोग पर लेखा नीति में परिवर्तन करता है तो वह इस परिवर्तन का प्रयोग पूर्व प्रभाव से ही करेगा।

20. इस मानक के प्रयोजन के लिए, किसी भारतीय लेखा मानक (इंड ए एस) का पूर्ववर्ती प्रयोग लेखा नीति में स्वैच्छिक परिवर्तन नहीं कहा जाएगा।
21. यदि किसी लेन-देन, अन्य घटना या परिस्थिति के लिए कोई विशेष भारतीय लेखा मानक (इंड ए एस) प्रयोग में नहीं लाया जा सकता तो प्रतिष्ठान का प्रबंधन उपर्युक्त अनुच्छेद 12 के अनुसार अन्तरराष्ट्रीय लेखा मानक बोर्ड द्वारा हाल ही में की गई घोषणाओं में से और इसके अभाव में, अन्य ऐसे मानक निर्धारक निकायों की, जो इसी तरह का संकल्पनात्मक मूल्यवृद्धि के अनुरूप लेखा मानक तैयार करते हैं, घोषणाओं के अनुरूप लेखा नीति का प्रयोग कर सकता है। यदि इस प्रकार की घोषणा के परिपेक्ष्य में संशोधन का अनुसरण करते हुए वह प्रतिष्ठान लेखा नीति में परिवर्तन का चुनाव करता है तो ऐसा परिवर्तन लेखा नीति में स्वैच्छिक परिवर्तन माना जाएगा और वह उसी रूप में प्रकट होगा।

पूर्व प्रभावी प्रयोग

22. अनुच्छेद 23 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार जब लेखा नीति में परिवर्तन उपर्युक्त अनुच्छेद 19 (क) या (ख) के अंतर्गत किया जाता है, तो प्रतिष्ठान प्रस्तुत सबसे पुरानी अवधि की इक्विटी के प्रत्येक प्रभावित अवयव के प्रारम्भिक शेष और प्रस्तुत प्रत्येक पूर्वावधि की प्रकट तुलनात्मक राशियों को यह मानकर समायोजित करेगा कि नई लेखा नीति पहले से ही लागू थी।

पूर्व प्रभावी प्रयोग की सीमाएं

23. जहां अनुच्छेद 19 (क) या (ख) के अनुसार पूर्व प्रभावी प्रयोग अपेक्षित है, लेखा नीति में परिवर्तन, इस सीमा को छोड़कर जहां अवधि विशेष के प्रभावों या परिवर्तन के संचित प्रभाव का निर्धारण करना अव्यवहार्य है, पूर्व प्रभाव से ही किया जाएगा।
24. जब इस बात का पता लगाना अव्यवहार्य हो कि एक लेखा नीति के परिवर्तन से एक या एक से अधिक प्रस्तुत अवधियों की तुलनात्मक सूचना पर क्या प्रभाव पड़ेगा, प्रतिष्ठान नयी लेखा नीति को लागू करने के लिए आस्तियों व देयताओं के आंकड़ों को उस पुरानी अवधि के आरंभ में ले जाएगा जिसका पूर्व प्रभाव से प्रयोग व्यवहार्य हो। यह अवधि चालू अवधि भी हो सकती है। इसमें प्रतिष्ठान उस अवधि की पूंजी के प्रत्येक प्रभावित अवयव के प्रारंभिक शेष में तदनुसारी समायोजन करेगा।
25. जब इस बात का पता लगाना अव्यवहार्य हो कि नई लेखा नीति दो सभी पूर्व अवधियों पर लागू करने से चालू अवधि के प्रारंभ में संचित प्रभाव कैसा रहा, प्रतिष्ठान नई लेखा नीति को आने वाले समय की यथा व्यवहार्य अधिक से अधिक नई तारीख से लागू करने के लिए तुलनात्मक सूचना का समायोजन करेगा।
26. जब प्रतिष्ठान एक नयी लेखा नीति को पूर्व प्रभाव से लागू करता है तो वह उसे यथा संभव पुरानी से पुरानी पूर्व अवधियों की तुलनात्मक सूचना पर लागू करता है। पुरानी अवधि पर पूर्व प्रभावी प्रयोग तब तक व्यवहार्य नहीं है जब तक उस अवधि के आदि व अन्त के तुलन पत्रों पर संचित प्रभाव का निर्धारण व्यवहार्य है। वित्तीय विवरणों के समायोजन की राशि प्रस्तुत पुरानी से पुरानी अवधि की ईक्विटी के प्रत्येक प्रभावित अवयव के आदि शेष में शामिल की जाती है। आमतौर पर समायोजन प्राप्त अर्जन राशि

में ही किया जाता है लेकिन कभी-कभी यह समायोजन ईक्विटी के किसी अन्य अवयव में भी किया जा सकता है (उदाहरणार्थ जैसे कि किसी भारतीय लेखा मानक के अनुपालन के लिए) पुरानी अवधियों की कोई अन्य सूचना जैसे वित्तीय आंकड़ों का ऐतिहासिक सारांश, भी यथा व्यवहार्य पुरानी से पुरानी अवधि तक समयोजित किया जा सकता है।

27. जब किसी प्रतिष्ठान के लिए एक नई लेखा नीति को पूर्व प्रभाव से लागू करना इसलिए अव्यवहार्य होता है क्योंकि यह नई लेखा नीति को पुरानी सभी अवधियों पर लागू करने से संचित प्रभाव का निर्धारण नहीं कर सकता तो प्रतिष्ठान अनुच्छेद 25 के अनुसार नयी नीति को यथा व्यवहार्य शीघ्र से शीघ्र भावी अवधि के प्रारंभ से ही लागू करेगा, अतः वह उस तारीख से पूर्व की आस्तियों, देयताओं व इक्विटी के संचित समायोजन के उस अंश की गणना नहीं करेगा। लेखा नीति में परिवर्तन की अनुमति उस स्थिति में भी दी जाती है जब किसी पूर्व अवधि में नीति का संभावित प्रयोग व्यवहार्य न हो। अनुच्छेद 50 - 53 में इस संबंध में मार्गदर्शन दिया गया है कि नई लेखा नीति एक या एक से अधिक पूर्व अवधियों में कब अव्यवहार्य होती है।

प्रकटन

28. जब किसी भारतीय लेखा मानक के प्रारंभिक प्रयोग का प्रभाव वर्तमान अवधि या किसी पूर्व अवधि पर पड़ता हो तो उसका प्रभाव उस स्थिति को छोड़कर पड़ेगा जहां समायोजन की राशि का निर्धारण अव्यवहार्य हो अथवा उसका प्रभाव भावी अवधियों पर भी पड़ता हो को ऐसे में, प्रतिष्ठान निम्नलिखित बातों को प्रकट करेगा:

- क) भारतीय लेखा मानक का शीर्षक
- ख) जब लागू होगा तो लेखा नीति में परिवर्तन इसके संक्रमणकालीन उपबंधों के अनुसार किया जाएगा ;
- ग) लेखा नीति में परिवर्तन की प्रकृति है ;
- घ) जब यहां लागू होगा तो इसके संक्रमणकालीन उपबंधों का वर्णन ;
- ङ.) जब यह लागू होगा तो इसके संक्रमणकालीन उपबंधों का भावी अवधियों पर प्रभाव ;
- च) प्रस्तुत वर्तमान अवधि और पूर्व की प्रत्येक अवधि में यथा व्यवहार्य सीमा तक, समायोजन की राशि इसे निम्न हेतु प्रकट किया जाएगा :
 - i) प्रत्येक वित्तीय विवरण की समरूपी प्रभावित मद हेतु ; तथा
 - ii) यदि भारतीय लेखा मानक 33 'प्रत्येक शेयर की लागत' प्रतिष्ठान पर लागू होता है तो प्रत्येक शेयर की मूल व परिवर्तित लागत हेतु ;
- छ) प्रस्तुत अवधियों से पूर्व की अवधियों से संबंधित समायोजन की राशि, यथा व्यवहार्य सीमा तक ; तथा
- ज) यदि अनुच्छेद 19 (क) या (ख) के अनुसार एक निश्चित पूर्व अवधि या प्रस्तुत प्रस्तुत अवधियों से पूर्व की अवधियों का पूर्व प्रभावी प्रयोग अव्यवहार्य है तो उन परिस्थितियों का

उल्लेख जिनके फलस्वरूप यह स्थिति उत्पन्न हुई है और इस बात का विवरण कि प्रयुक्त लेखा नीति में परिवर्तन कैसे और कब से हुआ है।

प्रकटन में बाद की अवधियों के वित्तीय विवरणों को दोहराने की आवश्यकता नहीं है।

29. जब लेखा नीति में स्वैच्छिक परिवर्तन का प्रभाव वर्तमान अथवा किसी पूर्ण अवधि पर पड़ता हो लेकिन जिसमें समायोजन की राशि का निर्धारण अव्यवहार्य हो अथवा उसका प्रभाव भावी अवधियों पर भी पड़ता हो, ऐसी स्थितियों को छोड़कर शेष मामलों में प्रतिष्ठान निम्नलिखित बातों को प्रकट करेगा:

- क) लेखा नीति में परिवर्तन की प्रकृति।
- ख) उन कारणों का उल्लेख जिनमें यह स्पष्ट होगा कि उस नयी लेखा नीति का प्रयोग इस प्रयोजन के लिए किया गया है और यह कि उससे विश्वस्त व अधिक प्रासांगिक सूचना उपलब्ध होगी।
- ग) प्रस्तुत वर्तमान अवधि और प्रत्येक पूर्व अवधि के लिए, यथा व्यवहार्य सीमा तक समायोजन की राशि। इसे निम्नलिखित हेतु प्रकट किया जाएगा :
 - i) प्रभावित प्रत्येक वित्तीय विवरण की समरूप प्रभावित मव हेतु, और
 - ii) यदि भारतीय लेखा मानक 33 उस प्रतिष्ठान पर लागू होता है तो उसके प्रत्येक शेयर की आधारभूत व परिवर्तित आय हेतु।
- घ) प्रस्तुत अवधियों से पूर्व की अवधियों से संबंधी व समायोजन की राशि, यथा व्यवहार्य सीमा तक।
- ङ.) यदि निश्चित पूर्व अवधि या प्रस्तुत अवधियों से पूर्व की अवधियों का पूर्व प्रभावी प्रयोग अव्यवहार्य है तो उन परिस्थितियों का उल्लेख जिनके फलस्वरूप यह स्थिति उत्पन्न हुई है और इस बात का विवरण कि प्रयुक्त लेखा नीति में परिवर्तन कैसे और कब से हुआ है।

प्रकटन में बाद की अवधियों के वित्तीय विवरणों को दोहराने की आवश्यकता नहीं है।

30. जब कोई प्रतिष्ठान उस नये भारतीय लेखा मानक का प्रयोग नहीं करता जो जारी तो हो चुका है लेकिन अभी प्रभावी नहीं हुआ है तो यह प्रतिष्ठान अपने प्रकटन में निम्नलिखित बातों का उल्लेख करेगा:

- क) यह तथ्य, और
- ख) उस सूचना का उल्लेख जो या तो ज्ञात है या फिर उसका ठीक प्रकार से अनुमान लगाया जा सकता है कि नये भारतीय लेखा मानक के प्रयोग प्रतिष्ठान की प्रारम्भिक प्रयोग की अवधि की वित्तीय विवरणों पर क्या प्रभाव पड़ सकता है।

31. अनुच्छेद 30 के अनुपालन में, यदि प्रतिष्ठान अपने प्रकटन पर विचार करता है तो निम्नलिखित बातों का उल्लेख करेगा:

- (क) नये भारतीय लेखा मानक का शीर्षक

- (ख) लेखा नीति में तत्काल पड़ने वाले एक या एक से अधिक परिवर्तनों की प्रकृति
- (ग) भारतीय लेखा मानक प्रयोग करने की अपेक्षित तारीख
- (घ) उस तिथि का उल्लेख जिस पर प्रतिष्ठान भारतीय लेखा मानक प्रथमतया प्रयोग में लाना चाहता है।
- (ङ.) इन दोनों में से किसी एक का उल्लेख
 - i) भारतीय लेखा मानक के प्रारम्भिक प्रयोग से प्रतिष्ठान के वित्तीय विवरणों पर क्या प्रभाव पड़ सकता है इस बारे में विचार विमर्श अथवा
 - ii) यदि उस प्रभाव की जानकारी नहीं है और न ही उसका कोई ठीक से अनुमान लगाया जा सकता है, तो उसके बारे में विवरण।

लेखा प्राक्कलनों में परिवर्तन

32. कारोबार की गतिविधियों में अन्तर्निहित अनिश्चितताओं के फलस्वरूप, वित्तीय विवरणों में अनेक मदों को ठीक-ठीक से मापा नहीं जा सकता लेकिन उन्हें अनुमानित रूप में ही प्रस्तुत किया जाता है जिसे प्राक्कलन कहते हैं। प्राक्कलन में हाल ही में उपलब्ध और विश्वसनीय सूचना के आधार पर निर्णय शामिल किये जाते हैं। उदाहरणतया निम्नलिखित पर अनुमान लगाए जाते हैं:
- क) अशोध्य ऋण
 - ख) कालातीत सूचीबद्ध सामान (इन्वेन्ट्री)
 - ग) वित्तीय आस्तियों या वित्तीय देयताओं का उचित मूल्य
 - घ) मूल्यहासयोग्य आस्तियों में शामिल आस्तियों का उपयोगी जीवन, अथवा अन्तर्निहित भावी आर्थिक लाभों के उपभोग का संभावित प्रतिमान, और
 - ङ.) वारंटी दायित्व
33. तर्कसंगत अनुमान वित्तीय विवरण तैयार करने का अनिवार्य अंग है और इनकी विश्वसनीयता को कम नहीं आंका जा सकता।
34. किसी भी प्राक्कलन अनुमान को संशोधित किया जा सकता है जो उस स्थिति में संभव है कि जिन परिस्थितियों में प्राक्कलन किया गया वे ही बदल जाएं या फिर नई सूचना या अधिक अनुभव के बाद ऐसा करना आवश्यक हो जाए। प्रकृतिवश, एक प्राक्कलन का संशोधन पूर्व अवधियों से संबंधित नहीं होता है और न ही यह त्रुटियों को ठीक करता है।
35. जब माप के आधार में परिवर्तन कर दिया जाता है तो यह एक लेखा नीति में परिवर्तन है, न कि लेखे के प्राक्कलन में परिवर्तन लेकिन जब लेखा नीति में परिवर्तन और लेखा प्राक्कलन में परिवर्तन का अन्तर स्पष्ट न हो या दोनों में भेद करना कठिन हो जाए तो उस परिवर्तन को लेखा प्राक्कलन में परिवर्तन ही माना जाएगा।

36. अनुच्छेद 37 के परिवर्तन को छोड़कर, लेखा प्राक्कलन में परिवर्तन का प्रभाव लाभ-हानि में शामिल कर नीचे की दो स्थितियों में संभावित परिवर्तन के रूप में देखा जाता है:

क) परिवर्तन की अवधि - यदि परिवर्तन केवल अवधि को प्रभावित करता है।

ख) परिवर्तन की अवधि और भावी अवधियां यदि परिवर्तन दोनों को प्रभावित करता है।

37. उस सीमा तक कि लेखा प्राक्कलन में परिवर्तन आस्तियों व देयताओं में परिवर्तन करते हैं या फिर वह 'ईक्विटी' की किसी एक मद से संबंधित है, तो उसे संबंधित आस्ति देयता या 'ईक्विटी' की मद की अग्रणीत राशि को परिवर्तन की अवधि में समायोजित करके देखा (माना) जाएगा।

38. एक लेखा प्राक्कलन में परिवर्तन के प्रभाव की संभावित मान्यता का अर्थ है कि परिवर्तन प्राक्कलन के परिवर्तन की तारीख से लेन-देनों, अन्य घटनाओं व परिस्थितियों पर लागू होता है। लेखा प्राक्कलन में परिवर्तन केवल वर्तमान अवधि के लाभ या हानि या वर्तमान के साथ-साथ भावी अवधियों के लाभ या हानि को प्रभावित कर सकता है। उदाहरणतया चूंकि अशोध्य ऋणों की राशि में प्राक्कलन में परिवर्तन केवल वर्तमान अवधि के लाभ या हानि को प्रभावित करता है अतः उसे वर्तमान अवधि में ही देखा (माना) जाता है। लेकिन, मूल्यहास-योग्य आस्ति के अनुमानित लाभकारी जीवन या उसके भावी आर्थिक लाभों के उपभोग के प्रतिमान से आस्ति के मूल्यहास, व्यय को प्रभावित करता है और यह प्रभाव न केवल वर्तमान अवधि तक रहता अपितु जब तक उस आस्ति का लाभकारी जीवन है तब तक की प्रत्येक अवधि में भी रहेगा। दोनों ही मामलों में वर्तमान अवधि के परिवर्तन का प्रभाव वर्तमान अवधि में आय या व्यय के रूप में ही देखा जाएगा। इसी तरह, भावी अवधियों की आय या व्यय उन्हीं अवधियों में देखे जाएंगे।

प्रकटन

39. एक प्रतिष्ठान लेखा प्राक्कलन में हुए परिवर्तन के प्रभाव की प्रकृति व राशि वर्तमान अवधि में और इसी तरह भावी अवधियों में संभावित प्रभाव की प्रकृति व राशि का प्रकटन करेगी लेकिन, भावी अवधियों के मामले में यह प्रकटन तभी होगा जबकि उस प्रभाव का अनुमान लगाना अव्यवहार्य होगा।

40. लेकिन यदि भावी अवधियों में परिवर्तन के प्रभाव की राशि का प्रकटन इस नाते नहीं किया गया कि उसका अनुमान लगाना अव्यवहार्य है तो प्रतिष्ठान इस तथ्य का उल्लेख अपने प्रकटन में करेगा।

त्रुटियां

41. त्रुटियां वित्तीय विवरणों के अवयवों की मान्यता (पहचान), प्रस्तुति अथवा प्रकटन कहीं भी हो सकती है यदि प्रतिष्ठान की वित्तीय स्थिति वित्तीय कार्यनिष्पादन या नकदी प्रवाह (कैश फ्लो) के विशेष प्रस्तुतिकरण के समय जानबूझकर विशेष अथवा मामूली भी त्रुटियां की जाती हैं तो उसे यह माना जाएगा कि प्रतिष्ठान ने वित्तीय विवरण तैयार करने में भारतीय लेखा मानकों का अनुपालन नहीं किया है। वर्तमान अवधि की संभावित त्रुटियां यदि उसी अवधि में दूढ़ ली जाती हैं तो उन्हें विवरणों को जारी करने और अनुमोदन से पूर्व ही ठीक कर लिया जाता है। लेकिन, कई बार विशेष त्रुटियां भी उस अवधि में नहीं

ढूँढी जा पातीं लेकिन जब उनका बाद की किसी अवधि में पता चलता है तो उन्हें ठीक करके उस अवधि के वित्तीय विवरणों की तुलनात्मक सूचना में प्रस्तुत किया जाता (देखिए अनुच्छेद 42 - 47)

42. अनुच्छेद 43 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार, प्रतिष्ठान पूर्व अवधि की विशेष त्रुटियों को पूर्व प्रभाव से ठीक करके जारी करने के लिए अनुमोदित वित्तीय विवरणों के प्रथम सैंट में ही निम्नलिखित के अनुसार प्रस्तुत करेगा:

क) जिस अवधि (जिन अवधियों) में त्रुटियां हुई हैं उस अवधि (उन अवधियों) की तुलनात्मक राशियों के साथ पुनः वर्णित करेगा, अथवा

ख) यदि त्रुटि प्रस्तुत पुरानी अवधि में हुई है तो इस स्थिति में आस्तियों, देयताओं व 'इक्वीटी' की उस प्रस्तुत बहुत ही पुरानी अवधि के प्रारम्भिक शेष पुनः वर्णित किये जाएंगे।

पूर्व प्रभावी पुनर्कथन की सीमाएं

43. जब तक विशेष अवधि के प्रभावों या त्रुटि के संचित प्रभाव का निर्धारण अव्यवहार्य न हो, पुरानी अवधि की त्रुटि पूर्व प्रभाव से पुनर्कथन या पुनः वर्णन द्वारा ठीक की जाएगी।
44. जब प्रस्तुत एक या एक से अधिक पूर्व अवधियों की तुलनात्मक सूचना में किसी त्रुटि की अवधि विशेष प्रभाव निर्धारित करना अव्यवहार्य हो तो ऐसी स्थिति में प्रतिष्ठान उस पुरानी अवधि की आस्तियों, देयताओं व 'इक्वीटी' के प्रारम्भिक शेषों की पुनर्व्याख्या या पुनर्कथन करेगा, जिस पुरानी अवधि का पुनर्कथन व्यवहार्य है (यह अवधि वर्तमान अवधि भी हो सकती है)
45. त्रुटि की सभी पुरानी अवधियों का संचित प्रभाव वर्तमान अवधि के प्रारंभ में किस प्रकार पड़ा यह निर्धारित करना जब अव्यवहार्य हो तो प्रतिष्ठान भावी उस अवधि से, जो व्यवहार्य है, त्रुटि को ठीक करते हुए तुलनात्मक सूचना के रूप में पुनर्कथन प्रस्तुत करेगा।
46. पुरानी अवधि की त्रुटि जब ठीक कर ली जाती है तो वह उस अवधि के लाभ या हानि में शामिल नहीं की जाएगी जिसमें की वह त्रुटि ढूँढी जाती है। पुरानी अवधियों की प्रस्तुत कोई भी सूचना, जिसमें वित्तीय आंकड़ों का ऐतिहासिक सारांश शामिल है, यथा व्यवहार्य, पुरानी से पुरानी अवधि से पुनर्कथन के रूप में प्रस्तुत की जाएगी।
47. जब पूर्व की सभी अवधियों में किसी त्रुटि की राशि का निर्धारण करना अव्यवहार्य हो (जैसे लेखा नीति के प्रयोग में त्रुटि करना) तो प्रतिष्ठान अनुच्छेद 45 के अनुसरण में जो भी व्यवहार्य रूप से पुरानी से पुरानी अवधि से आगे की अवधि की तुलनात्मक सूचना का पुनर्कथन करेगा। अतः इस स्थिति में वह इस तारीख से पहले की आस्तियों, देयताओं व 'इक्वीटी' के संचित पुनर्कथन के अंश पर कोई ध्यान नहीं देगा। अनुच्छेद 50-53 में इस बारे में मार्गदर्शन दिया गया है कि जब पूर्व की एक या एक से अधिक की अवधियों की त्रुटि का निराकरण अव्यवहार्य हो तो क्या किया जाए।
48. त्रुटियों का निराकरण और लेखा प्राक्कलनों में परिवर्तन दो अलग-अलग चीजें हैं। लेखा प्राक्कलन प्रकृतिवश वे अनुमान हैं जिन्हें अतिरिक्त सूचना प्राप्त होने पर संशोधित किया जा सकता है। उदाहरणतया, किसी आकस्मिकता के फलस्वरूप लाभ या हानि की मान्यता (पहचान) त्रुटि का निराकरण नहीं है।

गत अवधि की त्रुटियों का प्रकटन

49. अनुच्छेद 42 का अनुसरण करते हुए, प्रतिष्ठान निम्नलिखित बातों का प्रकटन करेगा:

- क) पूर्व अवधि की त्रुटि की प्रकृति ;
- ख) प्रस्तुत प्रत्येक पूर्व अवधि के लिए व्यवहार्य सीमा तक निम्नलिखित दो स्थितियों में निराकरण की राशि जिसे निम्नलिखित हेतु प्रकट किया जाएगा:
 - i) प्रत्येक वित्तीय विवरण में समरूपी प्रभावित मद ; और
 - ii) यदि भारतीय लेखा मानक 33 प्रतिष्ठान पर लागू होता है तो प्रति शेयर की मूल या परिवर्तित आय ।
- ग) प्रस्तुत सबसे पुरानी अवधि के प्रारंभ में निराकरण की राशि ; और
- घ) यदि किसी विशेष पुरानी अवधि के लिए पूर्व प्रभावी पुनर्कथन अव्यवहार्य है तो उन परिस्थितियों का उल्लेख किया जाएगा जिनके कारण वह स्थिति बनी थी और इस बात का भी उल्लेख किया जाएगा कि त्रुटि का निराकरण कैसे और कब से किया गया है।

इसके बाद की अवधियों के वित्तीय विवरणों में इन प्रकटनों को दोहराने की आवश्यकता नहीं है।
पूर्व प्रभावी प्रयोग एवं पूर्व प्रभावी पुनर्कथन के संबंध में अव्यवहार्यता

50. कुछ परिस्थितियों में, एक या एक से अधिक पुरानी अवधियों और वर्तमान अवधि की तुलना करने के लिए पुरानी अवधि (अवधियों) को समायोजित करना अव्यवहार्य होता है। उदाहरणतया, नयी लेखा नीति को जब पूर्व प्रभाव से प्रयोग में लाया जाना है (इसमें अनुच्छेद 51-53 का प्रयोजन भी शामिल है) और पूर्व में इस अनुसार आंकड़े एकत्र ही नहीं किये गये थे अथवा पूर्व की त्रुटि को ठीक करने के लिए पूर्व प्रभावी पुनर्कथन और यह भी अव्यवहार्य हो सकता है कि वह अपेक्षित सूचना फिर से एकत्र न हो पाए।
51. अन्य घटनाओं अथवा परिस्थितियों के संबंध में की गयी मान्यता (पहचान) का प्रकटन करते समय जब वित्तीय विवरणों के अवयवों पर एक लेखा नीति के प्रयोग करने पर कई बार कुछ अनुमान लगाना आवश्यक होते हैं। प्राक्कलन (अनुमान) प्रक्रिया मूलतः व्यक्तिनिष्ठ होती है और अनुमान सूचित अवधि के बाद भी लगाये जा सकते हैं। लेकिन जब कोई लेखा नीति पूर्व प्रभाव से लागू की जाती है या पूर्व अवधि की त्रुटि का पूर्व प्रभाव से पुनर्कथन किया जाता है तो इस स्थिति में अनुमान लगाना और कठिन हो जाता है क्योंकि प्रभावित लेन-देन घटी अन्य घटना या परिस्थिति का लम्बा समय निकल चुका होता है। फिर भी अनुमान लगाने का जो उद्देश्य वर्तमान अवधि का है, वही पुरानी अवधियों का भी है। जैसे कि जब समूह लेन-देन अन्य घटना या परिस्थिति जब घटित हुए तब क्या हालात थे और उन्हें इन अनुमानों में उन हालात को प्रदर्शित करना।
52. अतः जब किसी नयी लेखा नीति का पूर्व प्रभाव से प्रयोग किया जाता है या किसी पुरानी अवधि की त्रुटि का निराकरण किया जाता है तो इसके लिए अलग-अलग सूचना अपेक्षित होती है जो:
- क) सूचना उन हालात का साक्ष्य दे जो हुए लेन-देन, घटित अन्य घटना या परिस्थिति की तारीख को विद्यमान थे।

ख) जब पुरानी अवधि के वित्तीय विवरण जारी करने के लिए अनुमोदित किए गए थे तब वह सूचना उपलब्ध हो सकती थी।

प्राक्कलनों (अनुमानों) की कुछ किस्मों के लिए (उदाहरणतया उचित मूल्य का अनुमान जो दृष्टि योग्य कीमत या दृष्टि योग्य इनपुट पर आधारित नहीं है) यह अव्यवहार्य है कि उनमें भेद या अन्तर किया जाए। जब पूर्व प्रभाव से प्रयोग या पूर्व प्रभाव के पुनर्कथन के लिए कोई विशेष प्राक्कलन (अनुमान) अपेक्षित हों और उनमें इस प्रकार की दो सूचनाओं में अंतर करना संभव न हो तो ऐसी स्थिति में नई लेखा नीति का प्रयोग या पूर्व अवधि की त्रुटि को पूर्व प्रभाव से ठीक करना अव्यवहार्य हो जाता है।

53. नयी लेखा नीति का प्रयोग करते समय या पूर्व अवधि की राशियों को ठीक करते समय पूर्व अवधि में प्रबंधन की क्या मान्यताएं थी या पूर्व अवधि में पहचान की गयी, मापी गयी और प्रकट की गयी राशियों के अनुमान क्या इस बारे में पश्चदृष्टि का प्रयोग नहीं किया जा सकता। उदाहरणतया, जब प्रतिष्ठान भारतीय लेखा मानक 39 'वित्तीय लिखतें' - मान्यता एवं माप अनुसरण में उन वित्तीय आस्तियों के माप की पूर्व अवधि की त्रुटि को ठीक करती है जिन्हें पहले परिपक्वता धारित निवेश के रूप में वर्गीकृत किया गया था तो वह उस अवधि में तब तक माप के आधार को परिवर्तित नहीं करती जब तक कि प्रबंधन यह निर्णय नहीं ले लेता कि इन्हें परिपक्वता तक रखा नहीं जाएगा। इसके अलावा जब प्रतिष्ठान पूर्व अवधि की उस त्रुटि को ठीक करती जो भारतीय लेखा मानक 19 'कर्मचारियों के लाभ' के अनुसरण कर्मचारियों की जमा बीमारी की छुट्टी की देयता की गणना की त्रुटि को ठीक करती है, तो वह उस सूचना पर ध्यान नहीं देगी जोकि असामान्य तौर पर फैले इन्फ्लूजा सीजन से संबंधित है और वह सूचना बाद के समय में उस समय प्राप्त हुई जब कि पिछली अवधि के वित्तीय विवरण जारी करने के लिए अनुमोदित हो चुके थे। यह तथ्य कि महत्वपूर्ण प्राक्कलन बार बार करना अपेक्षित हो जाते हैं तो संबंधित विश्वसनीय समायोजन या तुलनात्मक सूचना को ठीक करना आवश्यक हो जाता है।

परिशिष्ट 'क'

अन्य लेखा मानकों में समाविष्ट मामलों के संदर्भ

यह परिशिष्ट लेखा मानक 8 का अभिन्न अंग है।

परिशिष्ट 'ख' ---- विशिष्ट बाजार ---- अवशिष्ट विद्युत एवं इलैक्ट्रानिक उपस्कर में भागीदारी से उत्पन्न देयताएं ---- भारतीय लेखा मानक 37 प्रावधान, आकस्मिक देयताएं एवं आकस्मिक आस्तियां भारतीय लेखा मानक 8 के लिए संदर्भ का कार्य करता है।

परिशिष्ट 'ख'**भारतीय लेखा मानक (इंड ए एस) 8 लेखा-नीतियां, लेखा प्रावक्तलों में परिवर्तन एवं त्रुटियां - कार्यान्वयन संबंधी मार्गदर्शन**

[यह मार्गदर्शन भारतीय लेखा मानक 8 के साथ संलग्न है लेकिन यह इसका अंग नहीं है]

उदाहरण 1 त्रुटियों का पूर्व प्रभाव से पुनर्कथन

1.1 20 x 2 के दौरान, बीटा कम्पनी ने पाया कि कुछ उत्पाद 20 x 1 के दौरान 6500 रुपये में बेचे गये थे लेकिन त्रुटिवश 31 दिसम्बर 20 x 1 की संचयन बद्ध माल (इन्वेंट्री) में शामिल किये गये हैं।

1.2 बीटा के लेखा रिकार्ड 20 x 2 में बिक्रियां 104000 रुपये थी। बिक्री किये गये माल की लागत 86500 रुपये थी (इसमें 6500 रुपये की त्रुटि राशि प्रारंभिक शेष में शामिल है) और आयकर की राशि 5250 रुपये है।

1.3 20 x 1 में बीटा कम्पनी ने रिपोर्ट किया है:

बिक्रियां	73500
बेचे गये माल की लागत	<u>(53500)</u>
आयकर से पूर्व लाभ	20000
आयकर	<u>(6000)</u>
लाभ	14000

1.4 20 x 1 में प्राप्त आय का प्रारंभिक शेष 20000 रुपये था और अथशेष 34000 रुपये था

1.5 बीटा कम्पनी के आयकर की दर 20 x 2 व 20 x 1 के लिए 30 प्रतिशत थी। इनकी कोई अन्य आय या व्यय नहीं था।

1.6 बीटा कम्पनी की प्रारंभ से अंत तक शेयर पूंजी 5000 रुपये थी और प्रतिधारित आय के अलावा 'इक्विटी' का कोई अन्य अवयव (कम्पोनेन्ट) नहीं था। कम्पनी के शेयरों की पब्लिक ट्रेडिंग नहीं की जाती और यह प्रति शेयर आय को भी प्रकट नहीं करती है।

[बीटा कम्पनी के लाभ हानि विवरण का सारांश]

	रुपये 20 x 2	रुपये (पुनर्कथित) 20 x 1
बिक्रियां	104000	73500
बेचे गये माल की लागत	<u>(80000)</u>	<u>(60000)</u>

आयकर से पूर्व लाभ	24000	13500
आयकर	<u>(7200)</u>	<u>(4050)</u>
लाभ	<u>16800</u>	<u>9450</u>

बीटा कम्पनी की इक्विटी में परिवर्तन का विवरण

	शेयर पूंजी	प्रतिधारित आय	कुल
शेष यथा 31 दिसम्बर 20 x 0	5000	20000	25000
31 दिसम्बर 20 x 1 को समाप्त वर्ष का लाभ यथा पुनर्कथित	-	<u>9450</u>	<u>9450</u>
शेष यथा 31 दिसम्बर 20 x 1	5000	29450	34450
31 दिसम्बर 20 x 2 को समाप्त वर्ष का लाभ	-	<u>16800</u>	<u>16800</u>
शेष यथा 31 दिसम्बर 20 x 2	<u>5000</u>	<u>46250</u>	<u>51250</u>

टिप्पणियों से सारांश

- कुछ उत्पाद यद्यपि वर्ष 20 x 1 में बेचे गये थे लेकिन त्रुटिवश 31 दिसम्बर 20 x 1 के सूचीबद्ध सामान (इन्वेंट्री) में शामिल किये गये हैं। इनकी बिक्री राशि 6500 रुपये थी। वर्ष 20 x 1 की वित्तीय विवरणों में इस त्रुटि को ठीक करके पुनर्कथित किया गया है। इस पुनर्कथन से वित्तीय विवरणों पर जो प्रभाव पड़ा है उस का सार नीचे दिया गया है। वर्ष 20 x 2 में इसका कोई प्रभाव नहीं है।

उदाहरण 2 - जब लेखा नीति में पूर्व प्रभाव प्रयोग व्यवहार्य न हो तो लेखा नीति में परिवर्तन का संभावित प्रयोग।

- वर्ष 20 x 2 के दौरान, डेल्टा कम्पनी ने संपत्ति, संयंत्र व उपस्कर के मूल्यहास के लिए लेखा नीति में परिवर्तन किया ताकि अवयव दृष्टिकोण का पूरी तरह से प्रयोग किया जाए और इसके साथ ही पुनर्मूल्यांकन माडल भी अपनाया जाए।
- 20 x 2 से पूर्व के वर्षों में डेल्टा के संपत्ति रिकार्ड में अवयव दृष्टिकोण के पूर्ण अनुपालन का ठीक से ब्यौरा नहीं मिलता। वर्ष 20 x 1 के अन्त में कम्पनी के प्रबंधकों ने एक इंजीनियरी सर्वेक्षण किया। इस

सर्वेक्षण ने वर्ष 20 x 2 के प्रारंभ में कम्पनी के पास रखे गये अवयवों और उनके उचित मूल्यों, लाभदायक जीवन, अनुमानित शेष मूल्य व मूल्यहास योग्य राशियों की सूचना का ब्यौरा दिया। लेकिन इस सर्वेक्षण से ऐसा पर्याप्त आधार नहीं मिला जिससे उन अवयव की लागत के अनुमान को विश्वसनीय रूप से आंका जा सके जिनकी पहले से अलग से कोई ऐसी गणना नहीं की गयी थी। कम्पनी के उपलब्ध रिकार्ड से सर्वेक्षण से पूर्व की यह सूचना भी प्राप्त नहीं हो सकती थी।

- 2.3 डेल्टा कम्पनी ने इस बात पर विचार किया कि लेखा में परिवर्तन के इन दोनों पहलुओं को लेखे में कैसे शामिल किया जाए। उन्होंने यह निश्चय लिया कि पूर्व प्रभाव से इस अवयव दृष्टिकोण के परिवर्तन को पूरी तरह से लागू करला व्यवहार्य नहीं है। इसी तरह, इस परिवर्तन को 20 x 2 से पूर्व की किसी तारीख को भावी प्रभाव से भी लागू करना व्यवहार्य नहीं। इसके अलावा लागत माडल से पुनर्मूल्यांकन माडल में परिवर्तन को भावी प्रभाव से ही लागू किया जा सकता है। अतः अंत में कम्पनी के प्रबंधकों ने यह निर्णय लिया कि कम्पनी की नई नीति को 20 x 2 से भावी प्रभाव से लागू किया जाए।

2.4 अतिरिक्त सूचना

डेल्टा कम्पनी की कर दर 30 प्रतिशत है।

वर्ष 20 x 1 के अंत में सम्पत्ति, संयंत्र व उपस्कर	रुपये
लागत	25000
मूल्यहास	(14000)
निबल अंकित मूल्य	11000
भावी मूल्यहास व्यय वर्ष 20 x 2 (पुराने आधार पर)	1500
इंजीनियरी सर्वेक्षण के कुछ परिणाम	
मूल्यहास	17000
अनुमानित अवशिष्ट मूल्य	3000
सम्पत्ति का औसत शेष (वर्षों में)	7
वर्तमान सम्पत्ति संयंत्र व उपस्कर का वर्ष 20 x 2 में मूल्यहास स्वरूप व्यय (नये आधार पर)	2000

टिप्पणियों से सारांश

- वर्ष 20 x 2 के प्रारंभ से, डेल्टा ने सम्पत्ति संयंत्र व उपस्कर के मूल्यहास की लेखा नीति में परिवर्तन किया ताकि वह अवयव दृष्टिकोण (कम्पोनेन्ट एप्रोच) का अधिक से अधिक प्रयोग कर सके और उसके साथ-साथ पुनर्मूल्यांकन माडल भी ग्रहण कर सके। कम्पनी के प्रबंधकों ने यह पाया कि यह नीति सम्पत्ति, संयंत्र व उपस्कर के अवयवों को ज्यादा ठीक से लेती है और यह उनके अद्यतन मूल्य पर

आधारित है। इस तरह से यह अधिक विश्वसनीय व अधिक संगत सूचना देने में सहायक है। यह नीति वर्ष 20 x 2 के प्रारंभ से लागू की गयी क्योंकि नीति को पूर्व प्रभाव से या पूर्व की किसी तारीख से भावी प्रभाव से लागू कर पाना व्यवहार्य नहीं था। इस तरह नयी नीति के अपनाने से वर्षों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। वर्तमान वर्ष पर पड़ने वाले प्रभावों सम्पत्ति संयंत्र व उपस्कर का आगे ले जाएगा शेष 6000 रुपये अधिक होगा आस्थगित कर प्रावधान का आदि शेष 1800 रुपये बढ़ जाएगा, वर्ष के प्रारंभ में पुनर्मूल्यांकन अतिरिक्त राशि 4200 होगी। मूल्यहास स्वरूप व्यय 500 रुपये बढ़ जाएगा और कर व्यय स्वरूप राशि 150 रुपये कम हो जाएगी।

परिशिष्ट 1

टिप्पणी - यह परिशिष्ट भारतीय लेखा मानक का अंग नहीं है। इस परिशिष्ट का प्रयोजन मात्र इतना है कि भारतीय लेखा मानक (इंड ए एस) 8 और तदनुरूपी अन्तरराष्ट्रीय लेखा मानक (आई ए एस) 8 *लेखा नीतियां, लेखा प्राक्कलनों में परिवर्तन एवं त्रुटियां* के बीच यदि कोई अंतर हों तो उन्हें स्पष्ट किया जाए।

अन्तरराष्ट्रीय लेखा मानक (आई ए एस) 8 'लेखा नीतियां, लेखा प्राक्कलनों में परिवर्तन एवं त्रुटियां' के साथ तुलना

1. इसमें अलग शब्दावली का प्रयोग किया गया है, उदाहरणतया, शब्दों 'वित्तीय स्थिति का विवरण' के स्थान पर शब्द 'तुलन-पत्र' और शब्दों 'व्यापक आय का विवरण' के स्थान पर शब्दों 'लाभ-हानि विवरण' का प्रयोग किया गया है। इसी तरह, रिपोर्टिंग अवधि के बाद की घटनाओं के प्रयोजन के निमित्त वित्तीय विवरणों के संदर्भ में शब्दों 'वित्तीय विवरण जारी करने के लिए प्राधिकार' के स्थान पर शब्दों 'वित्तीय विवरण जारी करने के लिए अनुमोदन' का प्रयोग किया गया है।
2. भारतीय लेखा मानक 8 के अनुच्छेद 12 में यह वर्णित किया गया है कि किसी भारतीय लेखा मानक की अनुपस्थिति में प्रबंधन अन्तरराष्ट्रीय लेखा मानक बोर्ड की हाल ही की घोषणाओं को विचार में लेगा।

भारतीय लेखा मानक (इंड ए एस) 10

रिपोर्टिंग अवधि के बाद की घटनाएं

(इस भारतीय लेखा-मानक में मोटे टाइप व सामान्य टाइप में अनुच्छेद हैं। इन दोनों तरह के अनुच्छेदों का समान प्राधिकार है। मोटे टाइप में अनुच्छेद, मुख्य सिद्धान्तों के सूचक हैं।)

उद्देश्य:

1. इस मानक का उद्देश्य यह निर्धारित करना है कि:

- (क) एक प्रतिष्ठान को रिपोर्टिंग अवधि के बाद की घटनाओं को अपने वित्तीय विवरणों में कब समायोजित करना चाहिए, और
- (ख) एक प्रतिष्ठान द्वारा अपने वित्तीय विवरणों को जारी करने की अनुमोदित तिथि एवं रिपोर्टिंग अवधि के बाद की घटनाओं का प्रकटन।

यह मानक यह भी आवश्यक समझता है कि एक प्रतिष्ठान को अपने वित्तीय विवरण चलायमान प्रतिष्ठान के आधार पर तैयार नहीं करने चाहिए अगर रिपोर्टिंग अवधि के बाद की घटनाओं से यह संकेत मिलता है कि चलायमान प्रतिष्ठान की अवधारणा उसके लिए उचित नहीं है।

कार्यक्षेत्र :

2. यह मानक रिपोर्टिंग अवधि के बाद की घटनाओं के लेखांकन एवं प्रकटन पर लागू होता है।

परिभाषाएं :

3. इस मानक में निम्नलिखित शब्दावली का प्रयोग यहां विनिर्दिष्ट अर्थों में किया गया है :-
 'रिपोर्टिंग अवधि के बाद की घटनाएं' ये वे घटनाएं हैं, जो चाहे अनुकूल हों फिर या प्रतिकूल, जो कि रिपोर्टिंग अवधि के अंत और उस तिथि, जिसको कम्पनी के मामले में निदेशक-मंडल द्वारा और अन्य किसी प्रष्ठान के मामले में तदनुसूची अनुमोदन प्राधिकारी द्वारा वित्तीय विवरणों को जारी करने के लिए अनुमोदित करने के बीच घटित हुई हों। ये घटनाएं निम्नलिखित दो प्रकार की हो सकती हैं :-
 (क) एक, वे जो रिपोर्टिंग अवधि के अन्त में विद्यमान परिस्थितियों के साक्ष्य स्वरूप हों (रिपोर्टिंग अवधि के बाद समायोज्य घटनाएं)। और -
 (ख) दूसरे, वे जो रिपोर्टिंग अवधि के बाद उत्पन्न परिस्थितियों की ओर संकेत करती हैं (रिपोर्टिंग अवधि के बाद गैर-समायोज्य घटनाएं)।
4. वित्तीय विवरणों को अनुमोदन के बाद जारी करने की व्याप्त प्रक्रिया प्रबंधन संरचना, सांविधिक अपेक्षाओं और वित्तीय विवरणों के तैयार करने एवं उन्हें अंतिम रूप देने की प्रक्रियाओं पर निर्भर करती है और यह अलग-अलग मामलों में अलग-अलग हो सकती है।
5. कुछ मामलों में, प्रतिष्ठान को अपने वित्तीय विवरण निदेशकों द्वारा अनुमोदन के बाद निवेशकों के समक्ष अनुमोदन के लिए प्रस्तुत करने होते हैं। ऐसी स्थिति में, वित्तीय विवरणों के जारी किये जाने की तिथि निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदन की तिथि मानी जाएगी, न कि निवेशकों द्वारा अनुमोदन की तिथि।
6. कुछ मामलों में, प्रतिष्ठान के प्रबंधन को वित्तीय विवरण जारी करने से पूर्व पर्यवेक्षी बोर्ड (गैर कार्यकारी अधिकारियों से गठित) को अनुमोदन के लिए प्रस्तुत करने होते हैं। ऐसी स्थिति में, वित्तीय विवरणों को जारी करने के लिए तभी अनुमोदित माना जाता है जबकि वे प्रबंधन द्वारा पर्यवेक्षी बोर्ड को प्रस्तुत किये जाते हैं।

उदाहरण

18 मार्च 20x2 को, प्रतिष्ठान के प्रबंधन ने अपने वित्तीय विवरणों को पर्यवेक्षी बोर्ड को निर्गम के लिए मंजूरी दी है। पर्यवेक्षी बोर्ड पूरी तरह से गैर कार्यकारी अधिकारियों से गठित किया गया है और कर्मचारियों के प्रतिनिधियों के अलावा वे लोग भी शामिल हैं जिनका प्रतिष्ठान में हित है। पर्यवेक्षी बोर्ड ने 26 मार्च 20x2 को वित्तीय विवरण अनुमोदित कर दिये। ये विवरण शेयरधारकों एवं अन्य को 1 अप्रैल 20x2 को उपलब्ध करा दिये जाते हैं। शेयर धारक 15 मई 20x2 को सम्पन्न अपनी वार्षिक बैठक में इन वित्तीय विवरणों को अनुमोदित कर देते हैं। अब प्रतिष्ठान इन वित्तीय विवरणों को 17 मई 20x2 को सम्बन्धित नियामक निकाय को प्रस्तुत कर देता है।

इस स्थिति में, वित्तीय विवरणों को जारी करने के अनुमोदन की तिथि 18 मार्च 20x2 मानी जाएगी (जिस पर कि प्रबंधन ने पर्यवेक्षी बोर्ड को प्रस्तुत करने के लिए मंजूरी दी थी)

7. रिपोर्टिंग अवधि के बाद घटित होने वाली घटनाओं में वे सभी घटनाएं सम्मिलित होती हैं जो कि वित्तीय विवरणों को जारी करने के लिए अनुमोदित की तारीख तक घटित हुई हैं भले ही वे घटनाएं लाभ या अन्य चयनित वित्तीय सूचना की सार्वजनिक घोषणा के बाद कभी भी घटित हुई हैं।

मान्यता और माप

रिपोर्टिंग अवधि के बाद की घटनाओं का समायोजन

8. एक प्रतिष्ठान रिपोर्टिंग अवधि के बाद की समायोज्य घटनाओं को प्रतिबिम्बित करने के लिए अपने वित्तीय विवरणों में मान्यता प्राप्त राशियों को समायोजित करेगा।
9. नीचे रिपोर्टिंग अवधि के बाद उन घटनाओं के समायोजन के उदाहरण दिये जा रहे हैं जो प्रतिष्ठान के लिए वित्तीय विवरणों में मान्यता प्राप्त राशियों को समायोजित करना या उन मदों को मान्यता देना आवश्यक है जिन्हें पहले मान्यता दी गयी है:-
- (क) रिपोर्टिंग अवधि के बाद एक कोर्ट मामले का निपटान होता है जिसमें यह पुष्टि होती है कि रिपोर्टिंग अवधि के बाद प्रतिष्ठान का दायित्व विद्यमान था। प्रतिष्ठान भारतीय लेखामानक 37 'प्रावधान, आकस्मिक देयताएं तथा आकस्मिक आस्तियां', के अनुसरण में इस कोर्ट मामले से सम्बन्धित मान्यता-प्राप्त किसी पिछले प्रावधान या मान्यता-प्राप्त नए प्रावधान को समायोजित करेगा। प्रतिष्ठान आकस्मिक देयता का प्रकटन इसलिए नहीं करेगा कि निपटान में यह एक अतिरिक्त साक्ष्य है और जो भारतीय लेखामानक 37 के अनुच्छेद 16 के अधीन विचारणीय है।
- (ख) रिपोर्टिंग अवधि के बाद यह सूचना मिलना कि आस्ति रिपोर्टिंग अवधि के अन्त तक क्षतिग्रस्त हो चुकी है या उस आस्ति की पहले से मान्य क्षति के कारण हुई हानि का समायोजन किया जाना है। उदाहरणार्थ:
- (i) रिपोर्टिंग अवधि के बाद एक ग्राहक का दिवालियापन, आमतौर पर यह पुष्टि करता है कि रिपोर्टिंग अवधि के अन्त में व्यापार प्राप्य में नुकसान हुआ है और प्रतिष्ठान के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि वह व्यापार प्राप्य की अग्रणीत (कैरिंग) राशि को समायोजित करे।
- (ii) रिपोर्टिंग अवधि के बाद माल की बिक्री जब यह साक्ष्य दे कि रिपोर्टिंग अवधि के अन्त में माल का निबल वसूली योग्य मूल्य था।
- (ग) रिपोर्टिंग अवधि के पश्चात क्रय की गयी आस्तियों की लागत या रिपोर्टिंग अवधि के अन्त से पूर्व विक्रय की गयी आस्तियों से प्राप्त राशियों का निर्धारण।
- (घ) यदि प्रतिष्ठान को रिपोर्टिंग अवधि के पश्चात, पूर्व की किन्हीं घटनाओं के परिणामस्वरूप किसी विद्यमान विधिक (कानूनी) या संरचनात्मक वाध्यता के कारण लाभ-वितरण या बोनस के रूप में कोई भुगतान करना आवश्यक है तो उसका निर्धारण। [देखें भारतीय लेखा मानक 19 'कर्मचारियों के लाभ']
- (ङ) किसी धोखाधड़ी (फ्रॉड) या त्रुटि का पता चलना और जिससे यह प्रदर्शित हो कि वित्तीय विवरण त्रुटिपूर्ण या गलत हैं।

रिपोर्टिंग अवधि के बाद की गैर-समायोज्य घटनाएं

10. कोई भी प्रतिष्ठान रिपोर्टिंग अवधि के बाद गैर समायोज्य घटनाओं को प्रतिबिम्बित करने के लिए वित्तीय विवरणों में मान्य राशियों को समायोजित नहीं करेगा।

11. रिपोर्टिंग अवधि के बाद गैर-समायोज्य घटना का एक उदाहरण है - रिपोर्टिंग अवधि के अन्त और वित्तीय विवरणों के जारी करने के लिए अनुमोदन की तारीख के बीच निवेशों के मार्केट मूल्य में गिरावट होना। मार्केट मूल्य में गिरावट आमतौर पर रिपोर्टिंग अवधि के अन्त में निवेशों की स्थिति से संबंधित नहीं होती बल्कि वह उन परिस्थितियों को प्रतिबिम्बित करती है जो उसके बाद उत्पन्न हुई हो। अतः प्रतिष्ठान अपने वित्तीय विवरणों में निवेशों की मान्यताप्राप्त राशियों को समायोजित नहीं करता। इसी तरह, प्रतिष्ठान रिपोर्टिंग अवधि के अन्त में निवेशों की प्रकट राशियों की अद्यतन स्थिति की भी जानकारी नहीं देता हालाँकि उसे अनुच्छेद 21 के अनुसार अतिरिक्त सूचना के रूप में प्रकटन करना पड़ सकता है।

लाभांश

12. यदि कोई प्रतिष्ठान 'इक्विटी' की लिखतों के धारकों को कोई लाभांश [भारतीय लेखा मानक 32 'वित्तीय लिखतें : रिपोर्टिंग' में यथा परिभाषित] घोषित करता है तो वह रिपोर्टिंग अवधि के अन्त पर इन लाभांशों को देयता के रूप में मान्यता नहीं देगा।
13. अगर लाभांश रिपोर्टिंग अवधि के बाद लेकिन वित्तीय विवरणों को जारी करने के लिए अनुमोदित करने से पहले घोषित किये जाते हैं तो इन लाभांशों को रिपोर्टिंग अवधि के अंत में एक देयता के रूप में मान्यता नहीं दी जाएगी क्योंकि उस समय इस सम्बंध में प्रतिष्ठान का कोई दायित्व नहीं है, ऐसे लाभांश भारतीय लेखा मानक 1 'वित्तीय विवरणों की प्रस्तुति' के अनुसरण में टिप्पणियों में प्रकट किये जाएंगे।

चलायमान प्रतिष्ठान

14. एक प्रतिष्ठान अपनी वित्तीय विवरणों को चलायमान प्रतिष्ठान के आधार पर तैयार नहीं करेगा यदि प्रबंधन यह निर्धारित करता है कि रिपोर्टिंग अवधि के बाद प्रतिष्ठान का कारोबार बन्द कर दिया जाएगा या उसका व्यापार बन्द कर दिया जाएगा या फिर उसके पास ऐसा कोई ठोस विकल्प नहीं है कि वह इस सम्बंध में क्या करेगा।
15. रिपोर्टिंग अवधि के बाद, परिचालन परिणामों और वित्तीय स्थिति में गिरावट इस बात की आवश्यकता महसूस करवाती है कि क्या चलायमान प्रतिष्ठान की अवधारणा अब भी उचित है? यदि यह अवधारणा आगे उचित नहीं लगती तो इसका प्रभाव व्यापक होगा और यह मानक यह अपेक्षा करता है कि लेखांकन के आधार में मूलभूत परिवर्तन की आवश्यकता है न कि लेखांकन के मूल आधार के अन्तर्गत मान्यता-प्राप्त राशियों का कोई समायोजन किया जाए।
16. भारतीय लेखा मानक 1 अपेक्षित प्रकटन को इस प्रकार विनिर्दिष्ट करता है:

- (क) वित्तीय विवरण चलायमान प्रतिष्ठान के आधार पर तैयार नहीं किये गये हैं, अथवा
- (ख) प्रबंधन को यह अहसास है कि घटनाओं या स्थितियों के सम्बंध में क्या महत्वपूर्ण (या सारवान) अनिश्चितताएं हैं जो प्रतिष्ठान को चलायमान प्रतिष्ठान के रूप में जारी रहने की योग्यता पर एक बड़ा सन्देह प्रकट करती हैं। ऐसी घटनाएं या परिस्थितियां जो प्रकटन की अपेक्षा करती हैं वे रिपोर्टिंग अवधि के पश्चात् उत्पन्न हो सकती हैं।

प्रकटन

निर्गम की अनुमोदन तिथि

17. प्रतिष्ठान उस तिथि को प्रकट करेगा जिस तिथि को उसके वित्तीय विवरण जारी करने (निर्गम) के लिए अनुमोदित किये गये हैं और यह अनुमोदन किसने दिया है। यदि प्रतिष्ठान के मालिकों या अन्य व्यक्तियों के पास वित्तीय विवरणों को जारी करने के बाद संशोधन करने की शक्ति है, तो वह प्रतिष्ठान इस तथ्य को भी साथ ही प्रकट करेगा।

18. उपयोगकर्ताओं के लिए यह जानना महत्वपूर्ण है कि वित्तीय विवरण को निर्गम के लिए कब अनुमोदित किया गया है क्योंकि ये वित्तीय विवरण निर्गम की तिथि के बाद की घटनाओं को प्रतिबिंबित नहीं करते।

रिपोर्टिंग अवधि के अंत में परिस्थितियों का अद्यतन प्रकटन

19. यदि एक प्रतिष्ठान को रिपोर्टिंग अवधि के बाद उन परिस्थितियों के बारे में सूचना प्राप्त होती है जो कि रिपोर्टिंग अवधि के अंत में विद्यमान थीं, तो वह उस नई सूचना के अनुसार उन परिस्थितियों के प्रकटन को अद्यतन करेगा।
20. कुछ मामलों में, प्रतिष्ठान को अपनी वित्तीय विवरणों के प्रकटन को अद्यतन करना आवश्यक हो जाता है ताकि इनमें रिपोर्टिंग अवधि के बाद की सूचना प्रतिबिम्बित हो सके भले वह सूचना वित्तीय विवरणों में मान्यता को प्रभावित न भी करती हो। इसका एक उदाहरण यह है कि जब रिपोर्टिंग अवधि के अंत में एक आकस्मिक देयता विद्यमान थी और इसके होने का साक्ष्य रिपोर्टिंग अवधि के बाद उपलब्ध हो जाता है। इसके अतिरिक्त, भारतीय लेखा मानक 37 के तहत इस आशय से कि क्या इसे मान्यता दी जाये या फिर प्रावधान में परिवर्तन किया जाए, प्रतिष्ठान आकस्मिक देयता के प्रकटन को प्राप्त साक्ष्य की दृष्टि से अद्यतन करे।

रिपोर्टिंग अवधि के बाद गैर समायोज्य घटनाएं

21. अगर रिपोर्टिंग अवधि के बाद, गैर समायोज्य घटनाएं महत्वपूर्ण या सारवान हैं और इन घटनाओं का प्रकटन नहीं किया जाता तो इससे वित्तीय विवरणों के उन उपयोगकर्ताओं के वे आर्थिक निर्णय प्रभावित हो सकते हैं जो उन्होंने इन विवरणों के आधार पर लिये हैं। इस प्रकार प्रतिष्ठान रिपोर्टिंग अवधि के बाद निम्नलिखित की दृष्टि से प्रत्येक गैर-समायोज्य घटना की महत्वपूर्ण श्रेणी को प्रकट करेगा :-

(क) घटना की प्रकृति, और

(ख) इसके वित्तीय प्रभाव का अनुमान अथवा यह विवरण कि प्रभाव का अनुमान लगाया जाना संभव नहीं है।

22. नीचे रिपोर्टिंग अवधि के बाद की उन गैर समायोज्य घटनाओं के उदाहरण दिये जा रहे हैं जो आमतौर पर प्रकटन में पाये जाते हैं :-

(क) रिपोर्टिंग अवधि के बाद, एक प्रमुख कारोबारी संयोजन, जिसका भारतीय लेखामानक 103 'व्यावसायिक संयोजन', के अनुसार विशेष प्रकटन अपेक्षित है अथवा प्रतिष्ठान के प्रमुख अनुषंगी का निपटान ;

(ख) परिचालन बंद करने की योजना की घोषणा ;

(ग) आस्तियों का बड़ी मात्रा में खरीद, 'विक्रय के लिए रखी गयी आस्तियों का वर्गीकरण भारतीय लेखामानक 105 'बिक्री के लिए धारित गैर-चालू आस्तियां एवं बन्द परिचालन' के अनुसरण में, आस्तियों के अन्य निपटान या सरकार द्वारा प्रमुख आस्तियों का अधिग्रहण ;

(घ) रिपोर्टिंग अवधि के बाद, एक प्रमुख उत्पादन संयंत्र में आग लगना और उसका विनाश ;

(ङ) एक बड़े पुनर्गठन की घोषणा करना या ऐसी किसी घोषणा का कार्यान्वयन प्रारम्भ करना (देखें भारतीय लेखा मानक 37) ;

- (च) रिपोर्टिंग अवधि के बाद, साधारण शेयरों का कोई बड़ा लेनदेन और संभावी साधारण शेयरों का कोई बड़ा लेनदेन (भारतीय लेखा मानक 33 'प्रति शेयर आय', जिसमें एक प्रतिष्ठान के लिए यह आवश्यक है कि वह ऐसे लेन देन को प्रकट करे लेकिन उन्हें छोड़कर जो भारतीय लेखा मानक 33 के अनुसार जब ये लेन देन पूंजीकरण या बोनस मामलों शेयरों का विभाजन या उनका विपरीत विभाजन से सम्बंधित हैं और इस मानक के अन्तर्गत इनका समायोजन आवश्यक है) ;
- (छ) आस्ति मूल्य अथवा विदेशी विनिमय दरों में रिपोर्टिंग अवधि के बाद असामान्य रूप से बड़े परिवर्तन ;
- (ज) रिपोर्टिंग अवधि के बाद, कर दरों में या लागू कर कानूनों में परिवर्तन या इस प्रकार की कोई घोषणा जो कि वर्तमान आर आस्थगित कर आस्तियों और देयताओं पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालती हो [देखिए भारतीय लेखा मानक 12 'आयकर'] ;
- (झ) महत्वपूर्ण वचनबद्धताओं या आकस्तिमक देयताओं में प्रवेश, उदाहरण के लिए जैसे कोई महत्वपूर्ण गारंटियां जारी करना ; और
- (ञ) रिपोर्टिंग अवधि के बाद की किन्ही घटनाओं से उत्पन्न कोई बड़ा मुकदमा शुरू होना ।

परिशिष्ट 'क'

स्वामियों को गैर नगद आस्तियों का वितरण¹

यह परिशिष्ट भारतीय लेखा मानक (इंड ए एस) 10 का अभिन्न अंग है ।

पृष्ठभूमि

1. कभी-कभी एक प्रतिष्ठान अपने मालिकों (स्वामियों)² को, स्वामियों की हैसियत से, ऐसी आस्तियों का लाभांश के रूप में वितरण करता है जो प्रकृति में नकद नहीं होतीं और जिन्हें गैर-नकद आस्तियां या परिसम्पत्तियां कहा जाता है। ऐसी परिस्थितियों में, वह प्रतिष्ठान मालिकों (स्वामियों) को यह विकल्प देता है वे लाभांश को गैर-नकद आस्तियों (परिसम्पत्तियों) या नकद विकल्प के रूप में प्राप्त करें ।
2. भारतीय लेखा मानक (इंड ए एस) यह मार्गदर्शन नहीं देते कि प्रतिष्ठान अपने स्वामियों को ऐसे वितरणों (जिन्हें सामान्यतया लाभांश कहा जाता है) माप कैसे करें । भारतीय लेखा मानक 1 एक प्रतिष्ठान से यह अपेक्षा करता है कि मालिकों को दिए जाने वाले ऐसे लाभांश का ब्यौरा तुलनपत्र के साथ संलग्न 'ईक्विटी' में परिवर्तन या वित्तीय विवरणों की टिप्पणियों में दें ।

कार्य-क्षेत्र

3. यह परिशिष्ट एक प्रतिष्ठान द्वारा अपने स्वामियों (मालिकों) को, जो मालिक की हैसियत से काम करते हैं, आस्तियों के निम्नलिखित प्रकार के गैर पारस्परिक वितरणों पर लागू होता है :
 - (क) गैर नकदी आस्तियों का वितरण [उदाहरणार्थ संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर, कारोबार आदि जैसी मदों जिन्हें भारतीय लेखा मानक 103 में परिभाषित किया गया है और अन्य प्रतिष्ठान या निपटान समूहों में स्वामित्व हित जिन्हें भारतीय लेखा मानक 105 में परिभाषित किया गया है] ।
 - (ख) ऐसे वितरण, जो मालिकों (स्वामियों) को गैर नकद आस्तियों या नकद तुल्य में से किसी एक में प्राप्त करने का विकल्प देते हैं ।

¹ यह परिशिष्ट अन्य बातों के साथ-साथ, इस बात पर भी विचार करता है कि स्वामियों को देय लाभांश का प्रकटन कब किया जाये ।

² भारतीय लेखा मानक 1 का अनुच्छेद 7 यह परिभाषित करता है कि
हैं ।

'ईक्विटी' के रूप में वर्गीकृत लिखतों के धारक

4. यह परिशिष्ट केवल उन वितरणों पर लागू होता है जहाँ 'ईक्विटी' लिखतों की एक श्रेणी के मालिकों को एक समान रूप से लिया जाता है।
5. यह परिशिष्ट ऐसी गैर नकदी आस्ति के वितरण पर लागू नहीं होता है जो कि वितरण से पहले और वितरण के बाद केवल एक ही पक्ष (पार्टी) या पक्षों (पार्टियों) द्वारा नियंत्रित की जाती हैं। यह अपवर्जन, वितरणकर्ता प्रतिष्ठान की उन वित्तीय विवरणों पर लागू होता है जो अलग, व्यक्तिगत व समेकित हैं।
6. अनुच्छेद 5 के अनुसार, यह परिशिष्ट उस स्थिति में लागू नहीं होता है जब गैर नकद आस्ति वितरण से पहले और वितरण के बाद उन्हीं पक्षों (पार्टियों) द्वारा नियंत्रित हो। भारतीय लेखा मानक 103 के अनुच्छेद ख 2 में यह कहा गया है कि 'व्यक्तियों व एक समूह जब एक प्रतिष्ठान में किसी संविदात्मक व्यवस्था के परिणामस्वरूप सामूहिक रूप से वित्तीय व परिचालनात्मक नीतियों को शासित करने की शक्ति रखता है और प्रतिष्ठान के क्रिया कलापों से लाभान्वित होता है तो यह माना जाएगा कि समूह के वे व्यक्ति प्रतिष्ठान को नियंत्रित करते हैं'। अतः यह वितरण इस परिशिष्ट के कार्यक्षेत्र से बाहर है जहां वितरण से पूर्व और बाद में एक ही व्यक्ति आस्तियों को नियंत्रित करता है। इस परिशिष्ट कार्यक्षेत्र से बाहर रहने के लिए यह आवश्यक है कि शेयर धारकों का ऐसा समूह जो वितरण प्राप्त कर रहा है वह एक प्रतिष्ठान में एक संविदात्मक व्यवस्था के परिणाम स्वरूप एक सामूहिक शक्ति का एक अंग हो।
7. अनुच्छेद 5 के अनुसार, यह परिशिष्ट उस स्थिति में भी लागू नहीं होता है जब एक प्रतिष्ठान अपने कुछ स्वामित्व हित अपनी एक अनुषंगी कम्पनी में वितरित करती है लेकिन अनुषंगी कंपनी पर अपना नियंत्रण बरकरार रखती है। प्रतिष्ठान का ऐसा वितरण भारतीय लेखा मानक 27 के अनुसरण वितरण में अनुषंगी लेखे में गैर-नियंत्रणकारी हित की मान्यता के अन्तर्गत आता है।
8. यह परिशिष्ट प्रतिष्ठान के एक ऐसे लेखे पर लागू होता है जो गैर-नकद आस्तियों के वितरण से सम्बंधित हो। यह उन शेयरधारकों के लेखांकन पर लागू नहीं होता है जो यह वितरण प्राप्त करते हैं।

मुद्दे

9. जब एक प्रतिष्ठान वितरण की घोषणा करता है और उस पर अपने मालिकों को संबंधित संपत्ति वितरित करने का दायित्व है, तब उसे देय लाभांश की देयता को मान्यता देनी ही होगी। नतीजतन, यह परिशिष्ट निम्नलिखित मुद्दों पर विचार करता है:
 - (क) प्रतिष्ठान देय लाभांश की मान्यता कब करेगा;
 - (ख) प्रतिष्ठान देय लाभांश का माप कैसे करेगा;
 - (ग) जब प्रतिष्ठान देय लाभांश का निर्धारण करता है तो वह वितरित आस्तियों की दृढ़ अग्रणीत (कैरिंग) राशि और देय लाभांश की कैरिंग राशि के बीच के अंतर का लेखांकन कैसे करेगा।

लेखांकन सिद्धान्त

देय लाभांश की मान्यता कब की जाये ?

10. लाभांश के भुगतान की देयता तब मान्य होगी जब लाभांश समुचित रूप से प्राधिकृत हो और वह प्रतिष्ठान के विवेक पर बिलकुल न हो। यह निम्नलिखित में से किसी एक की तिथि पर होगा :
 - (क) उस तिथि से जब, लाभांश की घोषणा पर, जैसे कि प्रबंधन या निदेशक मंडल के साथ-साथ शेयरधारकों जैसे अन्य सम्बंधित प्राधिकारी का अनुमोदन आवश्यक हो।
 - (ख) उस तिथि से जब लाभांश की घोषणा हो, उदाहरण के लिए प्रबंधन या निदेशक मंडल के अनुमोदन पर की जानी है और जहां किसी अन्य प्राधिकारी का अनुमोदन आवश्यक न हो।

देय लाभांश का माप

11. एक प्रतिष्ठान अपने मालिकों को गैर नगद आस्ति के रूप में दिए गए लाभांश की देयता का माप वितरित की जाने वाली आस्तियों के उचित मूल्य पर करेगा।
12. यदि प्रतिष्ठान अपने मालिकों को गैर नकद आस्ति या नकद रूप में से एक को चुनने का विकल्प देता है, तो वह देय लाभांश का अनुमान लगाने के लिए प्रत्येक विकल्प के उचित मूल्य और मालिकों द्वारा चयनित विकल्प की प्राधिकता दोनों पर विचार किया जाएगा।
13. प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में और निपटान की तारीख को, प्रतिष्ठान यह समीक्षा करेगा कि क्या वितरण के लिए देय लाभांश की अग्रणीत (कैरिंग) राशि देय 'ईक्विटी' में मान्य इस अग्रणीत (कैरिंग) राशि में कोई परिवर्तन है तो वह उसका समायोजन करेगा।

जब एक प्रतिष्ठान देय लाभांश का निपटान करता है, वितरित की जाने वाली आस्तियों की अग्रणीत (कैरिंग) राशि और देय लाभांश की अग्रणीत (कैरिंग) राशि में अंतर का लेखांकन:

14. जब एक प्रतिष्ठान देय लाभांश का निपटान करता है तो वह लाभ या हानि वितरित की जाने वाली आस्तियों की अग्रणीत (कैरिंग) राशि और देय लाभांश के अग्रणीत राशि के अंतर की, यदि कोई हो, मान्यता करेगा।

प्रस्तुति और प्रकटन

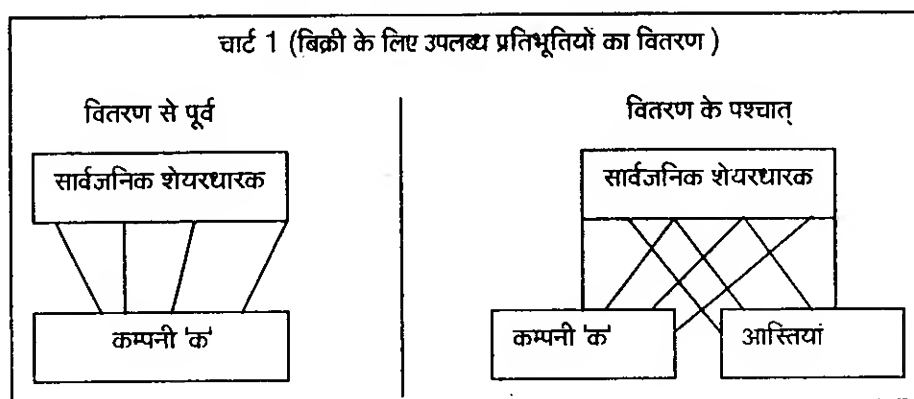
15. प्रतिष्ठान अनुच्छेद 14 में यथावर्णित अंतर को लाभ या हानि में एक अलग रेखीय मद (लाइन आइटम) के रूप में प्रकट करेगा।
16. प्रतिष्ठान निम्नलिखित जानकारी को, यदि लागू हो, प्रकट करेगा:

- (क) अवधि के प्रारम्भ और अंत में देय लाभांश की अग्रणीत (कैरिंग) राशि; और
- (ख) वितरित की जाने वाली आस्तियों के उचित मूल्य में परिवर्तन के परिणामस्वरूप, अनुच्छेद 13 के अनुसार, इस अवधि में मान्य अग्रणीत (कैरिंग) राशि में वृद्धि या कमी।
17. अगर एक प्रतिष्ठान एक रिपोर्टिंग अवधि के अंत के बाद, लेकिन वित्तीय विवरणियां जारी करने के अनुमोदन से पहले, एक गैर नकद आस्ति को लाभांश के रूप में वितरित करने की घोषणा करता है तो वह निम्नलिखित को भी प्रकट करेगा:
- (क) वितरित की जा रही आस्ति (संपत्ति) की प्रकृति ;
- (ख) रिपोर्टिंग अवधि के अंत में वितरित की जाने वाली आस्ति की अग्रणीत (कैरिंग) राशि; और
- (ग) यदि अग्रणीत (कैरिंग) राशि उचित मूल्य से अलग है तो रिपोर्टिंग अवधि के अंत में वितरित की जाने वाली आस्ति का अनुमानित उचित मूल्य क्या होगा। साथ ही प्रतिष्ठान भारतीय लेखा मानक 107 अनुच्छेद 27 (क) और (ख) के अनुसरण में उस विधि को भी प्रकट करेगा जिस पर उचित मूल्य निर्धारित किया गया है।

दृष्टांत उदाहरण

यहां दिये गये उदाहरण इस परिशिष्ट के साथ संलग्न हैं लेकिन उसके अंग नहीं हैं।

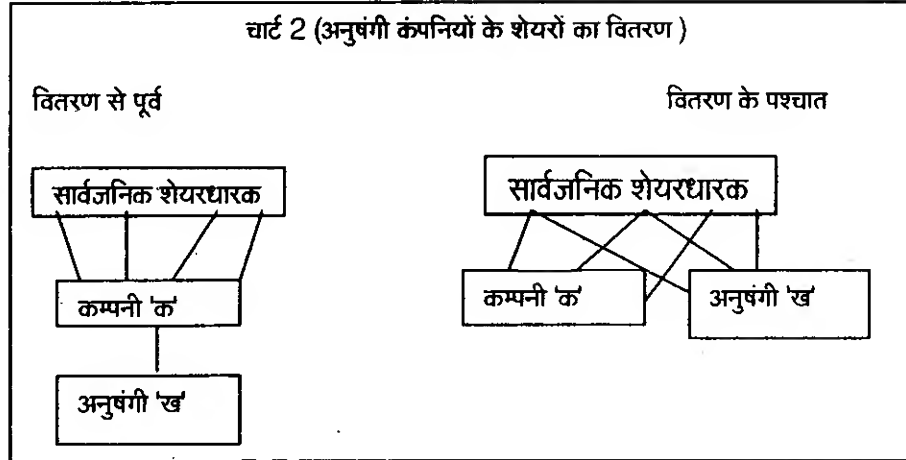
परिशिष्ट का कार्य-क्षेत्र (अनुच्छेद 3-8)



उदाहरण दृष्टांत 1: मान लें कि कंपनी 'क' का स्वामित्व सार्वजनिक शेयरधारकों के पास है। न तो कंपनी का नियंत्रण एक शेयरधारक के पास है और न ही शेयरधारकों का कोई समूह है जो किसी संविदात्मक अनुबंध के अधीन संयुक्त रूप से कंपनी का नियंत्रण कार्य करता है। कम्पनी 'क' निश्चित आस्तियों को (जैसे बिक्री के लिये उपलब्ध प्रतिभूतियां) शेयरधारकों को आनुपातिक रूप से वितरित करती है। यह लेन-देन परिशिष्ट के कार्यक्षेत्र (दायरे) में आता है।

उदाहरण दृष्टांत 2: लेकिन, अगर एक शेयरधारक (या शेयरधारकों का समूह जो संविदात्मक अनुबंध के अंतर्गत एक-साथ कार्य करता है) और लेन देन से पहले और बाद में कम्पनी 'क' को नियंत्रित करता है। तब, सम्पूर्ण लेन देन (गैर नियंत्रक

शेयरधारकों के वितरण सहित) इस परिशिष्ट के दायरे में नहीं आएगा। इसका कारण यह है कि एक ही वर्ग के सभी इक्विटी लिखतों को मालिकों को आनुपातिक आधार पर वितरित किया गया है क्योंकि वितरण के बाद भी नियंत्रक शेयरधारक (शेयरधारकों का समूह) गैर-नकद आस्तियों का नियंत्रण जारी रखेंगे।



उदाहरण दृष्टांत 3: मान लें कि कंपनी 'क' का स्वामित्व सार्वजनिक शेयरधारकों के पास है। न तो कंपनी का नियंत्रण एक शेयरधारक के पास है और न ही शेयरधारकों का कोई समूह है किसी संविदात्मक अनुबंध से बाध्य होकर एक साथ कार्य करते हुए संयुक्त रूप से कंपनी 'क' को नियंत्रित करते हैं। कंपनी 'क' की एक अनुषंगी कंपनी 'ख' है जिसके सभी शेयरधारकों का स्वामित्व है। कंपनी 'क' अपनी अनुषंगी कंपनी 'ख' के सभी शेयरों को अपने शेयरधारकों को आनुपातिक आधार पर वितरित करती है जिसके परिणाम स्वरूप अनुषंगी कंपनी 'ख' का नियंत्रण नहीं रहेगा। यह लेन देन परिशिष्ट के दायरे के भीतर है।

उदाहरण दृष्टांत 4: लेकिन अगर कंपनी 'क' अपने शेयरधारक को अनुषंगी कंपनी 'ख' गैर नियंत्रित हित वाले शेयरों अपने को वितरित करती है और अनुषंगी कंपनी 'क' का नियंत्रण बरकरार रखती है तब यह लेन देन, परिशिष्ट के दायरे में नहीं आएगा। कंपनी वितरण का लेखांकन, भारतीय लेखा मानक 27 के अनुसार करेगी। कंपनी 'क' कंपनी 'ख' पर नियंत्रण लेन-देन से पहले और बाद दोनों समय बरकरार रखती है।

परिशिष्ट 1

टिप्पणी - यह परिशिष्ट भारतीय लेखा मानक का अंग नहीं है। इस परिशिष्ट का प्रयोजन मात्र इतना है कि भारतीय लेखा मानक (इंड ए एस) 10 और तदनुसूची अन्तरराष्ट्रीय लेखा मानक (आई ए एस) 10 'रिपोर्टिंग अवधि के बाद की घटनाएं' के बीच यदि कोई अंतर हो तो उन्हें स्पष्ट किया जाए।

अन्तरराष्ट्रीय लेखा मानक (आई ए एस) 10 'रिपोर्टिंग अवधि के बाद की घटनाएं' एवं 'आई एफ आर सी व्याख्या 17' के साथ तुलना

1. इस मानक में अलग शब्दावली का प्रयोग किया गया है, उदाहरणतया, शब्दों 'वित्तीय स्थिति का विवरण' के स्थान पर शब्द 'तुलन-पत्र' का प्रयोग किया गया है। इसी तरह, रिपोर्टिंग अवधि के बाद की घटनाओं के प्रयोजन के निमित्त वित्तीय विवरणों के संदर्भ में शब्दों 'वित्तीय विवरण जारी करने के लिए प्राधिकार' के स्थान पर शब्दों 'वित्तीय विवरण जारी करने के लिए अनुमोदन' का प्रयोग किया गया है।

भारतीय लेखा मानक (इंड ए एस) 20

सरकारी अनुदानों का लेखा एवं सरकारी सहायता का प्रकटन

(इस भारतीय लेखा मानक में मोटे टाईप व सामान्य टाईप में अनुच्छेद हैं। इन दोनों तरह के अनुच्छेदों का समान प्राधिकार है। मोटे टाईप में अनुच्छेद मुख्य सिद्धान्तों के सूचक हैं।)

कार्य-क्षेत्र:

1. यह मानक सरकारी अनुदान के लेखा एवं सरकारी सहायता के प्रकटन और अन्य प्रकार की सरकारी सहायता के प्रकटन पर लागू होगा।
2. यह मानक निम्नलिखित पर चर्चा नहीं करता :-
 - क) वित्तीय विवरणों में बदलती कीमतों के प्रभावों या इसी प्रकार के प्रभावों को अनुपूरक सूचना में परिलक्षित करते हुए सरकारी अनुदान के लेखा में उत्पन्न होने वाली विशेष समस्याएं।
 - ख) सरकारी सहायता जिसे लाभ के रूप में एक प्रतिष्ठान को प्रदान किया गया है और जो करयोग्य लाभ अथवा कर राशि के निर्धारण में उपलब्ध है अथवा आयकर देयता के आधार पर निर्धारित अथवा सीमित है। इस प्रकार के लाभ के उदाहरण हैं: - आयकर छूट, निवेश कर क्रेडिट, मूल्यहास में वृद्धि आदि।
 - ग) प्रतिष्ठान के स्वामित्व में सरकारी सहभागिता।
 - घ) भारतीय लेखा मानक 'कृषि'¹ में व्याप्त सरकारी अनुदान।

परिभाषाएं:

3. इस मानक में निम्नलिखित शब्दावली का प्रयोग यहां विनिर्दिष्ट अर्थों में किया गया है :-

'सरकार' से तात्पर्य सरकार, सरकारी एजेंसियां तथा इसी प्रकार के निकाय चाहे वे स्थानीय, राष्ट्रीय अथवा अन्तरराष्ट्रीय क्यों न हों।

'सरकारी सहायता' से तात्पर्य है किन्हीं निश्चित मापदंडों के अन्तर्गत अहर्ता प्राप्त प्रतिष्ठान अथवा अनेक प्रतिष्ठान को आर्थिक लाभ प्रदान करने की कार्रवाई। इस मानक के प्रयोजन के लिए, सरकारी सहायता में वे लाभ नहीं हैं जो कार्रवाई द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से सामान्य व्यापारिक परिस्थितियों को प्रभावित करते हैं जैसे कि विकास क्षेत्रों में मूलभूत ढांचा उपलब्ध करवाने का प्रावधान अथवा प्रतिस्पर्धी कर्ताओं पर व्यापारिक प्रतिबंध लगाना।

¹ यह लेखा मानक अभी तैयार किया जा रहा है।

'सरकारी अनुदान' से तात्पर्य उस सहायता से है जो सरकार द्वारा एक प्रतिष्ठान को उसकी परिचालन गतिविधियों से संबंधित कुछ शर्तों की विगत अथवा भावी अनुपालना के प्रतिफल के रूप में संसाधनों के अंतरण द्वारा प्रदान की जाती है। इसमें सरकारी सहायता के वे स्वरूप सम्मिलित नहीं हैं जिन पर तर्कसंगत आधार पर एक मूल्य नहीं रखा जाता है और सरकार के साथ होने वाले लेन-देनों को प्रतिष्ठान के सामान्य व्यापारिक लेन-देनों से अलग नहीं किया जा सकता।²

'आस्तियों से संबंधित अनुदान' से तात्पर्य उस सरकारी अनुदान से है जिसकी प्राथमिक शर्त यह है कि उसका अहर्ता प्राप्त प्रतिष्ठान दीर्घकालीन आस्तियों का क्रय निर्णय अथवा अन्य रूप से अधिगृहण करे। सहायक शर्तों के रूप में, ये प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं जैसे कि आस्तियों की किस्म या स्थान या अवधियों जिसमें कि वे आस्तियां प्राप्त या रखी जा सकें।

'आय से संबंधित अनुदान' वह सरकारी अनुदान है जो आस्तियों से सम्बंधित नहीं है।

'माफी योग्य ऋण' वे ऋण हैं जिन्हें ऋणदाता कुछ निर्धारित शर्तों के अन्तर्गत वापस न लेने की वचनबद्धता देता है।

'उचित मूल्य' से अभिप्राय उस राशि से है जो जिस पर आस्ति का विनिमय एक ज्ञानवान इच्छुक क्रेता तथा ज्ञानवान इच्छुक विक्रेता के मध्य स्वतंत्र लेनदेन द्वारा किया जा सकता हो।

4. सरकारी सहायता के अनेक स्वरूप हो सकते हैं जो दी जाने वाली सहायता की प्रकृति तथा इसके साथ जुड़ी शर्तों के अनुसार भिन्न-भिन्न हों। सहायता देने का प्रयोजन यह है एक प्रतिष्ठान उस कार्यवाही करने के लिए प्रोत्साहित हो जो सामान्यतः वह उस स्थिति में नहीं करता यदि उसे वह सहायता न दी जाए।
5. एक प्रतिष्ठान द्वारा सरकारी सहायता की प्राप्ति दो कारणों से वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए महत्वपूर्ण हो सकती है। प्रथम यह कि यदि संसाधन अंतरित कर दिये गये हैं तो अंतरण को लेखों के लिए कोई उपयुक्त कार्य पद्धति का पता लगाया जाए। दूसरा यह संकेत देना कि इस सहायता से सम्बंधित प्रतिष्ठान रिपोर्टिंग अवधि में किस सीमा तक लाभान्वित हुआ है। इससे प्रतिष्ठान के वित्तीय विवरणों को गत अवधि तथा अन्य प्रतिष्ठानों के वित्तीय विवरणों से तुलना करने में सुलभता प्रदान होती है।
6. सरकारी अनुदान को कभी - कभी अन्य संज्ञाओं जैसे सहायता, आर्थिक सहायता अथवा प्रिन्सिपम से भी अभिहित किया जाता है।

देखिए परिशिष्ट 'क' - सरकारी सहायता - परिचालन सम्बंधी गतिविधियों के साथ कोई विशिष्ट सम्बंध नहीं है।

सरकारी अनुदान

7. उचित मूल्य पर गैर मौद्रिक अनुदान सहित सरकारी अनुदान को तब तक मान्यता नहीं दी जायेगी जब तक यह तर्कसंगत आश्वासन न हो कि ---

(क) प्रतिष्ठान उनके साथ जुड़ी शर्तों का पालन करेगा, तथा

(ख) अनुदान प्राप्त हो जाएगा ।

8. एक सरकारी अनुदान को तब तक मान्यता नहीं दी जाती है जब तक एक तर्कसंगत आश्वासन न हो कि प्रतिष्ठान इससे जुड़ी शर्त की अनुपालना करेगा तथा यह कि अनुदान प्राप्त हो जायगा । अनुदान की प्राप्ति स्वयं में पूर्ण साक्ष्य प्रदान नहीं करता है कि अनुदान से जुड़ी शर्त को पूरा कर लिया गया है अथवा पूरा कर दिया जायगा ।
9. जिस ढंग से अनुदान प्राप्त किया जाता है वह अनुदान के संबंध में अपनाये जाने वाली लेखांकन विधि को प्रभावित नहीं करता । इसलिए एक अनुदान को उसी विधि से लेखांकित किया जाता है चाहे वह अनुदान नकद रूप में प्राप्त हो अथवा एक ही सरकार की देयता में कटौती के रूप में प्राप्त हुआ हो ।
10. सरकार से माफीयोग्य ऋण को सरकारी अनुदान ही माना जाता है जब इस बात का तर्कसंगत आश्वासन हो कि प्रतिष्ठान ऋण की माफी की सभी शर्तों को पूरा करेगा ।
- 10क बाजार से कम दर पर ब्याज पर सरकारी ऋण के लाभ को भी सरकारी अनुदान माना जाता है । ऋण को भारतीय लेखा मानक 39 *वित्तीय लिखतें: मान्यता एवं माप* के अनुसरण में मान्यता एवं माप को मान्यता दी जाती है । ब्याज की बाजार से कम दर के लाभ को भारतीय लेखा मानक 39 के अनुसार निर्धारित ऋण की आरंभिक अग्रणीत (कैरिंग) मूल्य तथा प्राप्त राशि के बीच अंतर के रूप में मापा जायगा । लाभ को इस मानक के अनुसार लेखांकित किया जाता है । प्रतिष्ठान उन शर्तों तथा दायित्वों पर विचार करेगा जो लिखतों की पहचान के लिए ऋण के लाभ की क्षतिपूर्ति करती है और जिन्हें पूरा किया गया है अथवा अवश्य पूरा किया जाएगा ।
11. जब एक बार सरकारी अनुदान की मान्यता हो जाती है तो किसी भी सम्बंधित आकस्मिक देयता अथवा आकस्मिक आस्ति को भारतीय लेखा मानक 37 *प्रावधान: आकस्मिक देयताएं एवं आकस्मिक आस्तियां* के अनुसरण में माना जाता है ।
12. एक प्रतिष्ठान सम्बंधित लागतों को क्षतिपूर्ति के विचार से जिस अवधि में व्यय के रूप में मान्यता देता है उसी अवधि की लाभ या हानि में एक व्यवस्थित आधार पर सरकारी अनुदान को मान्यता देता है ।
13. सरकारी अनुदान के लेखों के लिए दो वृहत दृष्टिकोण हैं, एक पूंजी दृष्टिकोण जिसके अन्तर्गत अनुदान को लाभ अथवा हानि के बाहर मान्यता दी जाती है तथा दूसरा आय दृष्टिकोण जिसके अन्तर्गत अनुदान को एक अथवा एक से अधिक अवधियों में लाभ अथवा हानि के रूप में मान्यता दी जाती है ।
14. वे जो पूंजी दृष्टिकोण के समर्थक हैं वे ये तर्क देते हैं कि : -

- क) सरकारी अनुदान एक प्रकार के वित्तीय यंत्र हैं और उन्हें तुलनपत्र में इसी रूप में लेना चाहिए न कि लाभ या हानि में व्यय की प्रतिपूर्ति के रूप में उनकी मान्यता की जानी चाहिए।
- ख) सरकारी अनुदान को लाभ अथवा हानि में मान्यता देना अनुपयुक्त होगा क्योंकि उन्हें अर्जित नहीं किया जाता। वे बिना किसी लागत के सरकार द्वारा किये जाने वाले प्रोत्साहन हैं।
15. आय दृष्टिकोण के समर्थन में ये तर्क दिये जाते हैं :-
- क) क्योंकि सरकारी अनुदान अंशधारकों से अलग एक स्रोत से प्राप्तियां हैं, उनकी सीधे रूप से 'इक्विटी' में मान्यता नहीं दी जा चाहिए परन्तु उन्हें उपयुक्त अवधि में लाभ अथवा हानि में मान्यता देनी चाहिए।
- ख) ऐसा बहुत कम होता है जब सरकारी अनुदान किसी बिना प्रयोजन के होती है। प्रतिष्ठान उन्हें उनकी शर्तों के अनुपालन और विचाराधीन दायित्वों को पूरा करके अर्जित करता है। अतः सम्बंधित लागतों को क्षतिपूर्ति के विचार से जिस अवधि में व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है उसी अवधि में इन अनुदानों की लाभ या हानि में मान्यता दी जाएगी।
- ग) क्यों कि आय और अन्य कर व्यय है, और चूँकि सरकारी अनुदान सरकार की आर्थिक नीतियों का एक अंश है, अतः उन्हें लाभ-हानि में इन पर भी इसी रूप से विचार करना तर्कसंगत है।
16. यह आय दृष्टिकोण का मूल है कि प्रतिष्ठान सम्बंधित मामलों को क्षतिपूर्ति के विचार से जिस अवधि में व्यय के रूप में मान्यता देता है उसी अवधि की लाभ या हानि व्यवस्थित आधार पर सरकारी अनुदान को मान्यता देती है। प्राप्ति के आधार पर लाभ या हानि में सरकारी अनुदान की मान्यता उपचित लेखांकन पूर्वधारणा के अनुसार नहीं है। [देखें भारतीय लेखा मानक 'वित्तीय विवरणों की प्रस्तुति'] तथा यह केवल तभी स्वीकार्य है यदि जिस अवधि में यह अनुदान प्राप्त किया गया था उससे भिन्न किसी अवधि में इसके आबंटन के लिए कोई आधार विद्यमान न हो।
17. ज्यादातर मामलों में जिन अवधियों में एक प्रतिष्ठान एक सरकारी अनुदान से सम्बंधित लागत अथवा व्यय को मान्यता देता है वे तुरंत ज्ञातव्य होती हैं। अतः विशिष्ट व्यय की मान्यता में अनुदानों की मान्यता उसी अवधि के लाभ अथवा हानि में की जाती है जिसमें कि वह व्यय हुआ है। इसी प्रकार, मूल्यहास-योग्य आस्तियों से सम्बंधित अनुदान को प्रायः विभिन्न अवधियों में तथा उसी अनुपात में मान्यता दी जाती है जिस अनुपात में इन आस्तियों को मूल्य हास व्यय को मान्यता दी जाती है।
18. गैर मूल्यहास-योग्य आस्तियों से सम्बंधित अनुदानों में कुछ दायित्वों को पूरा करने की भी आवश्यकता हो सकती है। अतः जिस अवधि में दायित्व को पूरा करने की लागत को वहन किया जाता है उसी अवधि के लाभ अथवा हानि में मान्यता दी जाती है। उदाहरण के रूप में, भूमि के रूप में अनुदान स्थान पर भवन का निर्माण सशर्त हो सकता है तथा अनुदान को लाभ अथवा हानि में भवन के जीवन के आधार पर मान्यता देना उपयुक्त होगा।

19. कभी - कभी एक अनुदान को वित्तीय या आर्थिक सहायता के पैकेज के एक भाग के रूप में प्राप्त किया जाता है जिसके साथ कई शर्तें जुड़ी होती हैं। इस प्रकार के मामले में लागत तथा व्यय सम्बंधी उस शर्त की पहचान पर ध्यान करने की आवश्यकता है जो अवधि का निर्धारण करती है और उसमें वह अनुदान अर्जित किया जायगा। अनुदान के एक भाग को एक आधार पर तथा दूसरे भाग को एक अन्य आधार पर आबंटित करना उपयुक्त होगा।
20. एक सरकारी अनुदान, जो पहले से उत्पन्न व्यय अथवा हानि के लिए क्षतिपूर्ति के रूप में अथवा भविष्य से सम्बंधित लागत के बिना प्रतिष्ठान को तुरंत वित्तीय सहायता के प्रयोजन से प्राप्य हो उसकी मान्यता उसी अवधि के लाभ अथवा हानि में की जाएगी जिसमें कि वह प्राप्त होती है।
21. कुछ परिस्थितियों में, एक सरकारी अनुदान को प्रतिष्ठान के विशिष्ट व्यय का करने के लिए एक प्रोत्साहन की बजाय तुरंत वित्तीय सहायता देने के प्रयोजन से प्रदान किया जा सकता है। इस प्रकार का अनुदान एक विशेष प्रतिष्ठान तक सीमित हो सकता है तथा वह हितग्रहियों की समस्त श्रेणी के लिए उपलब्ध नहीं हो सकता। इन परिस्थितियों के अनुसार, प्रतिष्ठान जिस अवधि में इसे प्राप्त करने के लिए अर्हता प्राप्त करता है उस अवधि के लाभ अथवा हानि में अनुदान की मान्यता की जाएगी, इस प्रकटन के साथ कि यह सुनिश्चित हो कि प्रभाव को स्पष्ट रूप से समझ लिया गया है।
22. सरकारी अनुदान गत अवधि में हुए व्यय हानि की क्षतिपूर्ति के रूप में प्रतिष्ठान प्राप्य हो सकता है। इस प्रकार के अनुदान को अवधि के लाभ अथवा हानि में मान्यता दी जाती है जिससे यह प्राप्य हो जाता है, इस प्रकटन के साथ कि यह सुनिश्चित रहे कि इसके प्रभाव को स्पष्ट रूप से समझ लिया गया है।

गैर मौद्रिक सरकारी अनुदान

23. एक सरकारी अनुदान गैर मौद्रिक आस्ति के अंतरण का स्वरूप ले सकता है जैसे प्रतिष्ठान के उपयोग के लिए भूमि अथवा अन्य संसाधन। इन परिस्थितियों में, गैर मौद्रिक आस्ति के उचित मूल्य का निर्धारण करना तथा अनुदान तथा आस्ति दोनों उचित मूल्य पर लेखांकन करना आम बात है। एक वैकल्पिक तरीका यह है कि कभी - कभी दोनों आस्ति तथा अनुदान को एक नाम मात्र राशि पर रिकार्ड कर लिया जाता है।

आस्तियों से सम्बंधित अनुदान की प्रस्तुति

24. उचित मूल्य पर गैर मौद्रिक अनुदान सहित आस्तियों से सम्बंधित सरकारी अनुदान को तुलनपत्र में या तो आस्थगित आय की स्थापना के द्वारा अथवा आस्ति की अग्रणीत (कैरिंग) राशि में पहुंचने के लिए अनुदान को प्रस्तुत किया जायगा।
25. [देखिये परिशिष्ट 1]
26. एक तरीके में, अनुदान को आस्थगन आय के रूप में मान्यता देता है जिसे लाभ अथवा हानि में आस्ति की उपयोगी जीवन में एक व्यवस्थित आधार पर मान्यता दी जाती है।
27. [देखिये परिशिष्ट 1]

28. आस्तियों के क्रय तथा सम्बंधित अनुदान की प्राप्ति से एक प्रतिष्ठान के नकदी प्रवाह में प्रमुख परिवर्तन उत्पन्न हो सकते हैं। इस कारण तथा आस्तियों में सकल निवेश को प्रदर्शित करने के लिए इस प्रकार के परिवर्तन प्रायः नकदी प्रवाह के विवरण में पृथक मद के रूप में प्रकट किये जाते हैं।

आय से सम्बंधित अनुदान की प्रस्तुति

29. आय से सम्बंधित अनुदान को कभी-कभी लाभ अथवा हानि विवरण में या तो पृथक रूप से अथवा सामान्य शीर्ष जैसे 'अन्य आय' के अन्तर्गत क्रेडिट में दिखाया जाता है। विकल्प के रूप में, उन्हें सम्बंधित व्यय की रिपोर्टिंग में घटाया जाता है।
- 29क [देखिये परिशिष्ट 1]
30. प्रथम तरीके के समर्थक यह दावा करते हैं कि आय तथा व्यय मदों को निवल करना अनुपयुक्त है तथा व्यय से अनुदान को अलग करने से अनुदान द्वारा प्रभावित न होने वाले अन्य व्यय के साथ तुलना सुलभ होती है। दूसरे तरीके में, यह तर्क दिया जाता है कि यदि अनुदान उपलब्ध नहीं होता तो व्यय को भी नहीं किया जाता तथा इस प्रकार अनुदान को समायोजित (ऑफसेट) किये बिना व्यय की प्रस्तुति भ्रामक हो सकती है।
31. आय से सम्बंधित अनुदान की प्रस्तुति के लिए दोनों तरीके को स्वीकार्य माना जाता है। अनुदान का प्रकटन वित्तीय विवरण के उपयुक्त ज्ञान के लिए आवश्यक हो सकता है। आय अथवा व्यय की किसी मद पर अनुदानों के प्रभाव का प्रकटन, जिसे पृथक रूप से प्रकट करने की आवश्यकता है, आमतौर पर उपयुक्त है।

सरकारी अनुदान का पुनर्भुगतान

32. एक सरकारी अनुदान जो पुनर्भुगतान योग्य बन जाता है लेखा प्राक्कलन (अनुमान) में परिवर्तन के रूप में लेखांकित किया जायगा। (देखें भारतीय लेखा मानक 8 *लेखा नीतियां, लेखा प्राक्कलनों में परिवर्तन एवं त्रुटियां*) आय से सम्बंधित अनुदान के पुनर्भुगतान को पहले अनुदान के सम्बंध में मान्य किसी गैर परिशोधित आस्थगित क्रेडिट पर लागू किया जाएगा। इस सीमा तक जब पुनर्भुगतान इस प्रकार के किसी आस्थगित, क्रेडिट से अधिक है अथवा जहां पर कोई आस्थगित, क्रेडिट विद्यमान ही नहीं है, पुनर्भुगतान की तुरंत लाभ अथवा हानि में मान्यता दी जायगी। भुगतान योग्य राशि द्वारा आस्थगित आय शेष को कम कर मान्यता दी जायगी।

33. [देखिये परिशिष्ट 1]

सरकारी सहायता

34. अनुच्छेद 3 में सरकारी अनुदान की परिभाषा से अलग, सरकारी सहायता के कुछ ऐसे स्वरूप हैं जिन पर उचित रूप से कोई मूल्य नहीं लगाया जा सकता तथा सरकार के साथ ऐसे लेनदेनों को प्रतिष्ठान के सामान्य व्यापारिक लेनदेनों से अलग नहीं किया जा सकता।
35. ऐसी सहायता के उदाहरण, जिन पर उचित रूप से कोई मूल्य नहीं लगाया जा सकता, हैं:- निःशुल्क तकनीकी अथवा विपणन सलाह तथा गारंटी का प्रावधान। सहायता का वह उदाहरण, जिसे प्रतिष्ठान के सामान्य व्यापारिक लेनदेनों से अलग नहीं किया सकता, हैं -- सरकार की

आपूर्ति नीति जो प्रतिष्ठान की बिक्री के भाग के लिए उत्तरदायी है। लाभ की विद्यमानता पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता परन्तु सरकारी सहायता से व्यापारिक गतिविधि को अलग करने का प्रयास एक पक्षीय हो सकता है।

36. उपर्युक्त उदाहरण में लाभ का महत्व इस प्रकार का है कि सहायता की प्रकृति, सीमा तथा अवधि का प्रकटन आवश्यक है ताकि वित्तीय विवरण भ्रामक न हो।
37. [देखिये परिशिष्ट 1]
38. इस मानक में, सरकारी सहायता में सामान्य परिवहन और संचार नेटवर्क के सुधार द्वारा तथा मूलभूत ढांचे की व्यवस्था और सुधरी सुविधाओं की आपूर्ति, जैसे सिंचाई अथवा जल प्रदाय पर समस्त स्थानीय समुदाय के लाभ के लिए आधार पर उपलब्ध है, सम्मिलित नहीं हैं।

प्रकटन

39. निम्नलिखित मामलों का प्रकटन किया जाएगा :-

- (क) वित्तीय विवरणों में अपनायी जाने वाली प्रस्तुति पद्धतियों सहित सरकारी अनुदानों के लिए अपनायी गयी लेखा नीति ;
- (ख) वित्तीय विवरणों में मान्य सरकारी अनुदानों का स्वरूप और सरकारी सहायता की अन्य किस्मों का संकेत जिनसे प्रतिष्ठान प्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित हुआ है ; और
- (ग) मान्य की गई सरकारी सहायता से संबद्ध अपूर्ण शर्तें एवं अन्य आकस्मिकताएं।

परिशिष्ट 'क'

सरकारी सहायता - परिचालन गतिविधियों में कोई विशिष्ट सम्बंध नहीं है।

यह परिशिष्ट भारतीय लेखा मानक (इंड ए एस) 20 का अभिन्न अंग है।

मुद्दा

1. कुछ देशों में, प्रतिष्ठानों को सरकारी सहायता का उद्देश्य कुछ क्षेत्रों अथवा उद्योग क्षेत्रों में या तो व्यापारिक गतिविधियों के प्रोत्साहन अथवा दीर्घकालीन सहायता के रूप में है। इस प्रकार की सहायता प्राप्त करने की शर्त प्रतिष्ठान की परिचालन गतिविधि से विशिष्ट रूप से जुड़ी नहीं हो सकती। इस प्रकार की सहायता का उदाहरण सरकार द्वारा उन प्रतिष्ठानों को संसाधनों का अंतरण है जो ---
 - क) एक विशेष उद्योग में परिचालन करते हैं ;
 - ख) हाल में, निजिकृत उद्योगों में परिचालन जारी रखते हैं।
 - ग) अविकसित क्षेत्रों में व्यापार को चलाना जारी रखते हैं अथवा आरंभ करते हैं।
2. मुद्दा यह है कि क्या इस प्रकार की 'सरकारी सहायता' भारतीय लेखा मानक 20 के कार्य-क्षेत्र के अन्तर्गत सरकारी सहायता में आती है तो इस मानक के अनुसार लेखांकन किया जाना चाहिए।

लेखांकन सिद्धांत

3. प्रतिष्ठानों को 'सरकारी सहायता' की परिभाषा भारतीय लेखा मानक 20 में दी गयी है और कुछ देशों अथवा उद्योग क्षेत्र में परिचालन करने की आवश्यकता के अतिरिक्त प्रतिष्ठान की परिचालन सम्बंधी गतिविधियों के सम्बंध में विशेष रूप से कोई शर्तें नहीं हैं। इसलिए, इस प्रकार के अनुदान को सीधे रूप से अंशधारकों के हितों में क्रेडिट नहीं करना चाहिए।

परिशिष्ट 1

टिप्पणी - यह परिशिष्ट इस भारतीय लेखा मानक का अंग नहीं है। इस परिशिष्ट का प्रयोजन मात्र इतना है कि भारतीय लेखा मानक (इंड ए एस) 20 और तदनुरूपी अन्तरराष्ट्रीय लेखा मानक (आई ए एस) 20 ' सरकारी अनुदानों का लेखा एवं सरकारी सहायता का प्रकटन' के बीच यदि कोई अंतर हों तो उन्हें स्पष्ट किया जाए।

अन्तरराष्ट्रीय लेखा मानक (आई ए एस) 20 'सरकारी अनुदानों का लेखा एवं सरकारी सहायता का प्रकटन' के साथ तुलना

1. अन्तरराष्ट्रीय लेखा मानक (आई ए एस) 20 यह विकल्प देता है कि गैर-मौद्रिक सरकारी अनुदानों को या तो उनके उचित मूल्य पर मापा जाए या फिर उनके नाम मात्र मूल्य पर। इस प्रकार भारतीय लेखा मानक 20 के अंतर्गत इन अनुदानों को नाममात्र के मूल्य पर मापने का विकल्प उपलब्ध नहीं है।
2. अन्तरराष्ट्रीय लेखा मानक (आई ए एस) 20 आस्तियों से संबंधित अनुदानों को, जिनमें गैर-मौद्रिक अनुदान भी सम्मिलित है, अनुदान को आस्थगित आय के रूप में निर्धारित कर या आस्ति की अग्रणीत राशि निकालने के लिए अनुदान को घटा कर तुलन-पत्र में उचित मूल्य पर प्रस्तुत करने का विकल्प प्रदान करता है। भारतीय लेखा मानक 20 इन अनुदानों को तुलन-पत्र में केवल आस्थगित आय के रूप में निर्धारित कर प्रस्तुति की अपेक्षा करता है। अतः भारतीय लेखा मानक 20 में इन अनुदानों को आस्ति की अग्रणीत राशि निकालने के लिए अनुदान की राशि घटाकर इन अनुदानों को प्रस्तुत करने का विकल्प उपलब्ध नहीं है। इसके परिणाम स्वरूप अनुच्छेद 32 को संशोधित किया गया है और अन्तरराष्ट्रीय लेखा मानक 20 के निम्नलिखित अनुच्छेद, जो आस्तियों से संबंधित अनुदानों की प्रस्तुति के विकल्पों के संदर्भ में हैं, भारतीय लेखा मानक 20 में से हटा दिये गये हैं। फिर भी, अन्तरराष्ट्रीय लेखा मानक 20 की अनुच्छेद संख्याओं के साथ क्रमबद्धता रखने के लिए इन अनुच्छेदों की संख्या का उल्लेख भारतीय लेखा मानक 20 में किया गया है।
 - (i) अनुच्छेद 25
 - (ii) अनुच्छेद 27
 - (iii) अनुच्छेद 33
3. अलग-से आय विवरण में आय से संबंधित अनुदानों की प्रस्तुति के बारे में वे अपेक्षाएं हटा दी गयी हैं जिनके बारे में अन्तरराष्ट्रीय लेखा मानक 20 के अनुच्छेद 29 'क' के अंतर्गत अलग-से आय विवरण प्रस्तुत किया जाता है। यह परिवर्तन भारतीय लेखा मानक 1 की दो विवरणों के दृष्टिकोण के बारे में विकल्प को हटाने के परिणामस्वरूप है। भारतीय लेखा मानक 1 यह अपेक्षा करता है कि लाभ या हानि के घटक और अन्य व्यापक आय के घटक लाभ-हानि विवरण के अंग के रूप में प्रस्तुत किये जाएंगे। फिर भी, अनुच्छेद संख्या 29 'क' को भारतीय लेखा मानक 20 में इस कारण रखा गया है ताकि अन्तरराष्ट्रीय लेखा मानक 20 की अनुच्छेद संख्याओं से उसकी क्रमबद्धता बनी रहे।

4. इस मानक में भिन्न शब्दावली का प्रयोग किया गया है। उदाहरणार्थ, शब्दों 'वित्तीय स्थिति का विवरण' के स्थान पर शब्द 'तुलन-पत्र' और शब्दों 'व्यापक आय का विवरण' के स्थान पर शब्द 'लाभ-हानि विवरण' का प्रयोग किया गया है।
5. अन्तरराष्ट्रीय लेखा मानक (आई ए एस) 20 में अनुच्छेद संख्या 37 'हटाया गया' के रूप में प्रदर्शित है। लेकिन, अन्तरराष्ट्रीय लेखा मानक 20 की अनुच्छेद संख्याओं के साथ क्रमबद्धता रखने के लिए यह अनुच्छेद संख्या भारतीय लेखा मानक 20 में रखी गयी है।

भारतीय लेखा मानक (इंड ए एस) 21 **विदेशी विनिमय दरों में परिवर्तन के प्रभाव**

(इस भारतीय लेखा मानक में मोटे टाईप व सामान्य टाईप में अनुच्छेद हैं। इन दोनों तरह के अनुच्छेदों का समान प्राधिकार है। मोटे टाईप में अनुच्छेद मुख्य सिद्धान्तों के सूचक हैं।)

उद्देश्य

1. एक प्रतिष्ठान अपनी विदेशी गतिविधियों को दो प्रकार से संचालित कर सकता है अर्थात् एक विदेशी मुद्रा में लेन-देनों के द्वारा, दूसरे, इसका विदेशी परिचालन। इसके अतिरिक्त, प्रतिष्ठान अपने वित्तीय विवरणों को विदेशी मुद्रा में भी प्रस्तुत कर सकता है। इस मानक का उद्देश्य यह निर्धारित करना है कि प्रतिष्ठान के विदेशी मुद्रा लेन-देनों व परिचालन को उसका वित्तीय विवरणियों में कैसे शामिल किया जाये और वित्तीय विवरणों को प्रस्तुत मुद्रा में कैसे रूपांतरित किया जाये।
2. प्रमुख मुद्दे ये हैं कि विनिमय की किस दर का उपयोग किया जाए तथा वित्तीय विवरणों में विनिमय दर परिवर्तन के प्रभाव को किस प्रकार रिपोर्ट किया जाये।

कार्यक्षेत्र

3. यह मानक निम्नलिखित पर लागू होगा :-

- क) भारतीय लेखा-मानक (इंड ए एस) 39 'वित्तीय लिखतें : मान्यता तथा माप' के कार्यक्षेत्र के अंदर आने वाले व्युत्पन्न (डेरिवेटिव) लेन-देनों तथा शेषों को छोड़कर विदेशी मुद्राओं के लेन-देनों तथा शेषों के लेखे में ;
 - ख) विदेशी परिचालनों के परिणामों तथा वित्तीय स्थिति के रूपांतरण में जिन्हें समेकन, आनुपातिक समेकन अथवा साम्या (इक्विटी) विधि द्वारा प्रतिष्ठान के वित्तीय विवरणों में सम्मिलित किया गया है ; तथा
 - ग) प्रस्तुति मुद्रा में एक प्रतिष्ठान के परिणामों तथा वित्तीय स्थिति को प्रस्तुत करने में।
4. भारतीय लेखा-मानक (इंड ए एस) 39 कई विदेशी मुद्रा व्युत्पन्न (डेरिवेटिवों) पर लागू होता है अतः तदनुसार इन व्युत्पन्न को इस मानक के कार्यक्षेत्र से हटा दिया गया है। वे विदेशी मुद्रा व्युत्पन्न (डेरिवेटिव) जो भारतीय लेखा-मानक (इंड ए एस) 39 के कार्यक्षेत्र में नहीं हैं (उदाहरणतया कुछ विदेशी मुद्रा व्युत्पन्न (डेरिवेटिव) जो अन्य संविदाओं में सन्निहित हैं) वे इस लेखामानक के कार्यक्षेत्र में हैं। इसके अतिरिक्त, यह भारतीय लेखा मानक उस स्थिति में भी लागू होता है जब एक प्रतिष्ठान व्युत्पन्न (डेरिवेटिव) से संबंधित राशि का कार्यात्मक मुद्रा से प्रस्तुति मुद्रा में रूपांतरित करता है।

5. यह मानक विदेशी मुद्रा की मदों के प्रतिरक्षा (हेज) लेखांकन जिसमें विदेशी परिचालन में निवल निवेश की प्रतिरक्षा (हैजिंग) सम्मिलित है, पर लागू नहीं होता। भारतीय लेखा-मानक (इंड ए एस) 39 हेज लेखांकन पर लागू होता है।
6. यह मानक एक प्रतिष्ठान की विदेशी मुद्रा में वित्तीय विवरणों की प्रस्तुति पर लागू होता है तथा भारतीय लेखा मानकों की अनुपालना के रूप में रुपान्तरण पर परिणामी वित्तीय विवरणों की अपेक्षाएं निर्धारित करता है। विदेशी मुद्रा में जहाँ ये अपेक्षाएं पूरी नहीं होतीं, यह भारतीय लेखा मानक प्रकट की जाने वाली सूचना को विनिर्दिष्ट करता है।
7. यह मानक विदेशी मुद्रा के लेन-देनों से अथवा विदेशी परिचालन के नकद प्रवाह से उत्पन्न नकदी प्रवाह (कैश फ्लो) विवरणों की प्रस्तुति पर लागू नहीं होता [देखें भारतीय लेखा-मानक (इंड ए एस) 7 नकदी प्रवाहों के विवरण]

परिभाषाएं :

8. इस मानक में निम्नलिखित शब्दावली का प्रयोग यहां विनिर्दिष्ट अर्थों में किया गया है।

अन्तिम दर - वह तत्काल विनिमय दर है जो रिपोर्ट करने की अवधि के अन्त में होती है।

विनिमय अंतर - वह अंतर है जो विभिन्न विनिमय दरों पर एक मुद्रा की दी गयी यूनिटों के अन्य मुद्रा में रुपान्तरित करने से उत्पन्न होता है।

'विनिमय दर' - दो मुद्राओं के विनिमय का अनुपात है।

'उचित मूल्य' वह राशि है जिस पर आस्ति का विनिमय या देयता का भुगतान दो ज्ञानवान व इच्छुक पक्षों के बीच स्वतंत्र लेन-देन के रूप में किया जा सकता है।

'विदेशी मुद्रा' - वह मुद्रा है जो प्रतिष्ठान की कार्यात्मक मुद्रा से भिन्न है।

'विदेशी परिचालन' - विचाराधीन प्रतिष्ठान का वह स्वरूप है जो उसकी अनुषंगी सहयोगी, संयुक्त उद्यम या शाखा के रूप में है और जिसकी गतिविधियां रिपोर्टिंग प्रतिष्ठान के देश से विदेश या उसकी मुद्रा से भिन्न मुद्रा पर आधारित अथवा परिचालित होती हैं।

'कार्यात्मक मुद्रा' - वह मुद्रा है जिसमें प्रतिष्ठान 'प्राथमिक आर्थिक वातावरण' में परिचालन करता है।

'समूह' - वह स्वरूप है जिसमें मूल प्रतिष्ठान के साथ-साथ उसके सभी अनुषंगी प्रतिष्ठान भी सम्मिलित होते हैं।

'भौतिक मदें' रखी मुद्रा की इकाइयां और आस्तियाँ व देयताओं का उस मुद्रा की निश्चित या निर्धारण - योग्य संख्या में या तो प्राप्ति होती है या उसमें उनका भुगतान किया जाता।

'विदेशी परिचालन में निवल निवेश' विचाराधीन प्रतिष्ठान के हित की वह राशि है जो उसके परिचालन में निवल आस्तियों के रूप में व्याप्त है।

'प्रस्तुति मुद्रा' वह मुद्रा है जिसमें प्रतिष्ठान के वित्तीय विवरण प्रस्तुत किये जाते हैं।

'तत्काल विनिमय दर' वह विनिमय दर है जिसमें सुपुर्दगी तुरन्त की जाती है।

परिभाषाओं का विस्तार

कार्यात्मक मुद्रा

9. प्राथमिक आर्थिक वातावरण जिसमें सामान्यतया एक प्रतिष्ठान अपने परिचालन में प्राथमिक रूप से नकदी का अर्जन व व्यय करता है। एक प्रतिष्ठान अपनी कार्यात्मक मुद्रा के निर्धारण में निम्नलिखित तत्वों पर विचार करता है :-

(क) मुद्रा ;

- i. यह मुख्यतया प्रतिष्ठानों की वस्तुओं व सेवाओं की बिक्रय कीमत को प्रभावित करती है। प्रायः यह वह मुद्रा होगी जिसमें किसी प्रतिष्ठान की वस्तुओं व सेवाओं की बिक्रय कीमत अंकित होती है और उसी में इनका निपटान किया जाता है ; तथा
- ii. यह किसी देश की है जिसकी प्रतिस्पर्द्धात्मक शक्तियां तथा विनियम वस्तुओं व सेवाओं की बिक्रय कीमत को मुख्यतया निर्धारित करते हैं।

ख) वह मुद्रा है जो मुख्यतया वस्तुओं अथवा सेवाओं को प्रदान करने वाले श्रम, सामग्री तथा अन्य की लागतों को प्रभावित करती है। [यह प्रायः वह मुद्रा है जिसमें वस्तुओं या सेवाओं लागतों को अंकित किया जाता है और उसमें इनका निपटान किया जाता है।]

10. निम्नलिखित तत्व भी एक प्रतिष्ठान की कार्यात्मक मुद्रा का साक्ष्य प्रदान कर सकते हैं :-

(क) मुद्रा जिसमें वित्तपोषण गतिविधियों से (जैसे ऋण और 'इक्विटा' लिखतें जारी करना) निधियाँ अर्जित की जाती हैं।

(ख) मुद्रा जिसमें आमतौर पर परिचालन गतिविधियों से प्राप्तियां रखी जाती हैं।

11. विदेशी परिचालन की कार्यात्मक मुद्रा के निर्धारण में निम्नलिखित कुछ और तत्वों पर भी विचार किया जाता है तथा जिसमें यह भी शामिल है कि क्या इसकी कार्यात्मक मुद्रा वही है जो 'विचाराधीन प्रतिष्ठान' की है। (इस संदर्भ में 'विचाराधीन प्रतिष्ठान' वह है जिसकी विदेशी परिचालन के रूप में एक अनुषंगी, शाखा, सहयोगी अथवा संयुक्त उद्यम है।)

(क) यह कि, क्या विदेशी परिचालन की गतिविधियों को विचाराधीन प्रतिष्ठान के विस्तार के रूप में चलाने के बजाय इसके कि इसे स्वायत्तता रूप से चलाया जा रहा है। इन दोनों स्थितियों में, पहली स्थिति का उदाहरण है-जब विदेशी परिचालन केवल विचाराधीन प्रतिष्ठान से माल का आयात कर बिक्री करता है और उसे बिक्री राशियां भेजता है। दूसरी स्थिति के उदाहरण में, जब परिचालन से नकदी व अन्य मौद्रिक मदों का संग्रहण करता है, व्यय पर खर्च करता है, आय का अर्जन करता है और ऋण की व्यवस्था करता है और यह सब वह मुख्य रूप से स्थानीय मुद्रा में ही करता है।

- (ख) क्या विचाराधीन प्रतिष्ठान के साथ लेन-देन विदेशी परिचालन की गतिविधियों के अनुपात में ज्यादा है या कम ?
- (ग) क्या विदेशी परिचालन की गतिविधियों से नकद प्रवाह (कैश फ्लो) विचाराधीन प्रतिष्ठान के नकद प्रवाह को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है और क्या यह नकदी उस प्रतिष्ठान को तुरन्त भेजी जा सकती है ?
- (घ) क्या विदेशी परिचालन के पास अपनी गतिविधियों से नकद प्रवाह अपने वर्तमान व सामान्यतया अपेक्षित ऋण दायित्वों को अदा करने के लिए पर्याप्त है और इसके लिए उसे विचाराधीन परिचालन से कोई निधि (फंड) प्राप्त करने की कोई आवश्यकता नहीं है ?
12. जब उपर्युक्त संकेतक मिश्रित हैं और कार्यात्मक मुद्रा स्पष्ट नहीं है, प्रबन्धन कार्यात्मक मुद्रा के निर्धारण के लिए अपनी विवेक का ऐसा उपयोग करता है जो अन्तर्निहित लेन-देनों, घटनाओं तथा परिस्थितियों के आर्थिक प्रभाव का सर्वाधिक निष्ठापूर्वक प्रतिनिधित्व करता है। इस दृष्टि से, प्रबन्धन अनुच्छेद 10 तथा 11 में दिये गये संकेतकों पर विचार करने से पूर्व अनुच्छेद 9 में दिये गये प्राथमिक संकेतकों को वरीयता देता है क्योंकि अनुच्छेद 10 तथा 11 के संकेतक एक प्रतिष्ठान की कार्यात्मक मुद्रा के निर्धारण के लिए अतिरिक्त सहायक साक्ष्य के रूप में तैयार किये गये हैं।
13. एक प्रतिष्ठान की कार्यात्मक मुद्रा इसके अन्तर्निहित लेन-देनों, घटनाओं व परिस्थितियों को परिलक्षित करती है जो इसके लिए प्रासंगिक है। तदनुसार, जब एक बार कार्यात्मक मुद्रा का निर्धारण कर लिया जाता है तो उसे तब तक नहीं बदला जाता जब तक अन्तर्निहित लेन-देनों, घटनाओं तथा परिस्थितियों में परिवर्तन न हो जाए।
14. यदि प्रतिष्ठान की कार्यात्मक मुद्रा एक अति मुद्रास्फीति पूर्ण अर्थव्यवस्था की मुद्रा है तो उस प्रतिष्ठान के वित्तीय विवरणों को भारतीय लेखा मानक 29 'अति मुद्रास्फीतिपूर्ण अर्थव्यवस्थाएं' के अनुसार पुनः वर्णित किया जाता है। कोई भी प्रतिष्ठान भारतीय लेखा मानक 29 'अति मुद्रास्फीतिपूर्ण अर्थव्यवस्थाएं' के अनुसरण में इनके पुनर्वर्णन से बच नहीं सकता। यदि, उदाहरणस्वरूप, उसने इस भारतीय लेखा मानक के अनुसार निर्धारित कार्यात्मक मुद्रा से भिन्न किसी अन्य मुद्रा को अपनी कार्यात्मक मुद्रा के रूप में अपनाया है (जैसे कि वह मुद्रा उसके मूल प्रतिष्ठान की कार्यात्मक मुद्रा है)

विदेशी परिचालन में निवल निवेश

15. एक प्रतिष्ठान की कोई ऐसी मौद्रिक मद हो सकती है जो विदेशी परिचालन से या तो प्राप्य हो या फिर भुगतान योग्य है। इसी तरह, एक मद जिसका निपटान न तो नियोजित है और न ही निकट भविष्य में इसके उत्पन्न होने की संभावना है, सार रूप में यह उस प्रतिष्ठान का अपने विदेशी परिचालन में निवल निवेश का एक भाग है तथा इसका लेखा अनुच्छेद 32 तथा 33 के अनुसार किया जाएगा। इस प्रकार की मौद्रिक मदों में दीर्घकालीन प्राप्य राशियाँ अथवा ऋण तो सम्मिलित किये जा सकते हैं लेकिन, उनमें व्यापारिक प्राप्य राशियाँ अथवा व्यापारिक भुगतान योग्य राशियाँ सम्मिलित नहीं की जा सकतीं।

- 15क. अनुच्छेद 15 में यथा वर्णित एक प्रतिष्ठान जिसकी विदेशी परिचालन से प्राप्य राशि भुगतान योग्य राशि के रूप में कोई मौद्रिक मद है वह प्रतिष्ठान एक समूह की अनुषंगी भी हो सकती है। उदाहरणार्थ एक प्रतिष्ठान का दो अनुषंगी प्रतिष्ठान 'क' तथा 'ख' हैं। इनमें से अनुषंगी 'ख' एक विदेशी परिचालन है। अनुषंगी 'क' अनुषंगी 'ख' को ऋण प्रदान करता है। अब अनुषंगी 'क' का अनुषंगी 'ख' से प्राप्य ऋण प्रतिष्ठान का अनुषंगी 'ख' में निवल निवेश के एक भाग के रूप में होगा बशर्ते ऋणका निपटान न तो नियोजित है और न ही निकट भविष्य में इसके निपटान की कोई संभावना है। यह उस स्थिति में भी सत्य होगा यदि अनुषंगी 'क' स्वयं में एक विदेशी परिचालन हो।

मौद्रिक मदें

16. मौद्रिक मद की मुख्य विशेषता यह है कि मुद्रा की एक निश्चित मात्रा अथवा निर्धारण- योग्य इकाइयों में प्राप्त करने का अधिकार (अथवा सुपुर्दगी का दायित्व)। उदाहरणार्थ - पेंशन तथा अन्य कर्मचारी लाभों का नकद भुगतान करना, प्रावधान जिनका नकद भुगतान किया जाना है, और नकद लाभांश जिन्हें देयता के रूप में मान्यता दी गई है। इसी तरह, प्रतिष्ठान की अपनी 'इक्विटी' लिखतों की परिवर्तनशील राशि की प्राप्ति (अथवा सुपुर्दगी) की संविदा या आस्तियों की परिवर्तनशील राशि जिसे उचित मूल्य में प्राप्त (सुपुर्द) किया जाना है और वह मुद्रा की निश्चित मात्रा अथवा निर्धारण योग्य इकाइयों की संख्या के समान है वह एक मौद्रिक मद है। इसके विपरीत, एक गैर-मौद्रिक मद की मुख्य विशेषता यह है कि मुद्रा में एक निश्चित अथवा निर्धारण योग्य इकाइयों की संख्या में प्राप्त करने का अधिकार (अथवा सुपुर्द करने का दायित्व) नहीं होता। उदाहरणतया, वस्तुओं व सेवाओं के लिए पूर्व भुगतान राशियां (जैसे कि अग्रिम किराया) 'गुडविल', अमूर्त आस्तियां, सूचीबद्ध सामान, (इन्वेंट्री) सम्पत्ति, संयंत्र व उपस्कर तथा ऐसे प्रावधान जिनका निपटान गैर-मौद्रिक आस्तियों की सुपुर्दगी द्वारा किया जाना है।

इस लेखा-मानक के लिए आवश्यक दृष्टिकोण का सारांश

17. वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए, प्रत्येक प्रतिष्ठान, चाहे वह एक 'एकल' (स्टैंड अलोन) प्रतिष्ठान है या विदेशी परिचालन के रूप में एक प्रतिष्ठान है (जैसे एक मूल प्रतिष्ठान) या विदेशी परिचालन (जैसे कि एक अनुषंगी अथवा शाखा) - अनुच्छेद 9-14 के अनुसार अपनी कार्यात्मक मुद्रा का निर्धारण करता है। प्रतिष्ठान विदेशी मुद्रा मदों को अपनी कार्यात्मक मुद्रा में रूपांतरित करता है तथा अनुच्छेद 20-37 व 50 के अनुसार इस प्रकार के रूपांतरण के प्रभाव को रिपोर्ट करता है।
18. कई रिपोर्टिंग प्रतिष्ठान अनेक अलग-अलग प्रतिष्ठानों से मिलकर बने होते हैं। [जैसेकि, एक समूह एक मूल प्रतिष्ठान तथा इसकी एक अथवा एक से अधिक अनुषंगी प्रतिष्ठानों से मिलकर बना होता है]। विभिन्न प्रकार के प्रतिष्ठानों का, चाहे वे समूह के सदस्य हैं अथवा नहीं, सहायक प्रतिष्ठानों अथवा संयुक्त उद्यमों में निवेश हो सकता है। इन प्रतिष्ठानों की शाखाएं हो सकती हैं। विचाराधीन रिपोर्टिंग प्रतिष्ठान में सम्मिलित प्रत्येक व्यक्तिगत प्रतिष्ठान के लिए यह आवश्यक है कि वह अपनी वित्तीय स्थिति तथा परिणामों को उस मुद्रा में रूपांतरित करें जिसमें विचाराधीन प्रतिष्ठान अपने वित्तीय विवरणों को प्रस्तुत करता है। यह भारतीय लेखा मानक विचाराधीन प्रतिष्ठान की प्रस्तुति मुद्रा को किसी मुद्रा (अथवा किन्हीं मुद्राओं) में होने की अनुमति प्रदान करता है। यदि विचाराधीन प्रतिष्ठान के अंदर किसी व्यक्तिगत प्रतिष्ठान की

कार्यात्मक मुद्रा, प्रस्तुति मुद्रा से भिन्न है तो उसके वित्तीय परिणाम व वित्तीय स्थिति अनुच्छेद 38-50 के अनुसार रुपांतरित की जाएगी।

19. यह भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरण तैयार करने वाले 'एकल'(स्टैंड अलोन) प्रतिष्ठान अथवा भारतीय लेखा मानक 27 'समेकित तथा पृथक वित्तीय विवरण' के अनुसरण में अलग-से वित्तीय विवरण तैयार करने वाले प्रतिष्ठान को किसी मुद्रा अथवा मुद्राओं में प्रस्तुत करने की अनुमति देता है। यदि प्रतिष्ठान की प्रस्तुति मुद्रा इसकी कार्यात्मक मुद्रा से भिन्न है तो इसके वित्तीय परिणाम एवं स्थिति अनुच्छेद 38-50 के अनुसार प्रस्तुति मुद्रा में रुपांतरित किये जाएंगे।

कार्यात्मक मुद्रा में विदेशी मुद्रा के लेन-देनों की रिपोर्टिंग

प्रारम्भिक मान्यता

20. विदेशी मुद्रा में एक लेन देन एक ऐसा लेन-देन है जिसे विदेशी मुद्रा में ही अंकित किया जाता है और उसका निपटान भी उसी मुद्रा में करना आवश्यक है। इसमें निम्नलिखित रूप से उत्पन्न लेन-देन भी शामिल हैं :-
- (क) जब एक प्रतिष्ठान वस्तुओं अथवा सेवाओं का क्रय अथवा विक्रय विदेशी मुद्रा में अंकित कीमत में करता है ;
 - (ख) जब प्रतिष्ठान निधि (फंड) को ऋण पर लेता अथवा उधार देता है और भुगतान अथवा प्राप्ति राशि एक विदेशी मुद्रा में करना आवश्यक होती है ; अथवा
 - (ग) या फिर, प्रतिष्ठान आस्तियों का अधिग्रहण या निपटान अथवा देयताओं पर व्यय या निपटान विदेशी मुद्रा में करता है।
21. विदेशी मुद्रा में लेन-देन प्रारम्भिक मान्यता पर कार्यात्मक मुद्रा में रिकार्ड किया जाएगा। इसके लिए, विदेशी मुद्रा की राशि पर कार्यात्मक मुद्रा और विदेशी मुद्रा के बीच लेन-देन की तारीख की तत्काल विनिमय दर (स्पाट एक्सचेंज रेट) लागू होगा।
22. लेनदेन की तिथि वह है जिस पर लेनदेन भारतीय लेखा मानकों के अनुसार पहली बार मान्यता के लिए अहर्ता प्राप्त करता है। व्यावहारिक कारणों से, जो दर लेनदेन की तिथि पर वास्तविक दर के करीब है प्रायः उसे ही प्रयुक्त किया जाता है। उदाहरण के लिए, एक सप्ताह अथवा माह की औसत दर को उस अवधि के दौरान हुए प्रत्येक विदेशी मुद्रा से सभी लेनदेनों के लिए प्रयुक्त किया जाता है। लेकिन, यदि एक अवधि की विनिमय दर में बहुत उतार-चढ़ाव रहता है तो इस स्थिति में उस अवधि के लिए औसत दर का उपयोग उपयुक्त नहीं है।

उत्तरवर्ती रिपोर्ट अवधियों के अंत में रिपोर्टिंग

23. प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अन्त में -

(क) विदेशी मुद्रा मौद्रिक मदों का रूपांतरण अंतिम दर पर किया जाएगा।

- (ख) गैर-मौद्रिक मदों को, जिन्हें एक विदेशी मुद्रा में ऐतिहासिक लागत पर मापा जाता है, लेनदेन की तिथि पर विनिमय दर पर रुपांतरित किया जाएगा।
- (ग) गैर-मौद्रिक मदों को, जिन्हें एक विदेशी मुद्रा में उचित मूल्य पर मापा जाता है, उस तिथि की विनियम दर पर रुपांतरित किया जाएगा जिस तिथि पर उचित मूल्य निर्धारित किया गया था।
24. एक मद की अग्रणीत (कैरिंग) राशि का निर्धारण अन्य प्रासंगिक लेखा-मानकों के साथ सम्बद्ध करके निर्धारित किया जाता है। उदाहरण के लिए, सम्पत्ति, संयंत्र तथा उपस्कर को भारतीय लेखा मानक 16 'सम्पत्ति, संयंत्र तथा उपस्कर' के अनुसरण में उचित मूल्य अथवा ऐतिहासिक लागत के संदर्भ में मापा जा सकता है। चाहे अग्रणीत(कैरिंग) राशि का निर्धारण ऐतिहासिक लागत के आधार पर हो या उचित मूल्य के आधार हो, लेकिन जब राशि का निर्धारण एक विदेशी मुद्रा में किया है तब यह इस मानक के अनुसार इस राशि को कार्यात्मक मुद्रा में ही रुपांतरित किया जाएगा।
25. कुछ मदों की अग्रणीत (कैरिंग) राशि का निर्धारण दो अथवा दो से अधिक राशियों की तुलना करके निर्धारित किया जाता है। उदाहरण के लिए, सूचीबद्ध सामान (इंवेटरी) की (कैरिंग) राशि भारतीय लेखा मानक 2 'सूचीबद्ध सामान' '(इंवेट्रीज)' के अनुसार लागत तथा शुद्ध वसूली योग्य मूल्य, इनमें जो राशि कम है, उस पर रहेगी। इसी तरह भारतीय लेखा मानक 36 'क्षतिग्रस्त आस्तियाँ' के अनुसार, एक ऐसी सम्पत्ति जिसमें क्षतिग्रस्त होने के संकेत हैं उसकी कैरिंग राशि संभावित क्षतिग्रस्तता हानियों और प्राप्य राशि पर विचार के पूर्व की राशि से कम होगी। जब इस प्रकार की सम्पत्ति गैर मोद्रिक हो तथा उसे एक विदेशी मुद्रा में मापा जाना है तो ऐसी स्थिति में अग्रणीत (कैरिंग) राशि का निर्धारण निम्नलिखित अनुसार तुलना के आधार पर किया जाएगा:-
- (क) लागत अथवा अग्रणीत(कैरिंग) राशि, जैसा उचित हो, का रुपांतरण उस तिथि की विनिमय दर पर होगा, जब उस राशि का निर्धारण किया गया था। (अर्थात् उस दर पर जो लेन-देन की तारीख को थी और मद ऐतिहासिक लागत पर मापी गयी थी)
- (ख) निवल वसूली योग्य मूल्य अथवा वसूली योग्य राशि, जैसा उचित हो, उस तिथि की विनिमय दर पर रुपांतरित होगा जिस तिथि पर उसका मूल्य निर्धारित किया गया था (उदाहरणतया रिपोर्टिंग अवधि के अंत की अंतिम दर)।
- इस तुलना का यह प्रभाव हो सकता है कि क्षति से हुई हानि की मान्यता कार्यात्मक मुद्रा में की जाएगी न कि विदेशी मुद्रा में, और इसके विपरीत की स्थिति तदनुसार ही होगी।
26. जब विनिमय की अनेक दरें उपलब्ध हों तो ऐसी स्थिति में केवल वही एक दर प्रयोग में लायी जाएगी जिस पर भविष्य में लेन-देन का नकदी प्रवाह प्रस्तुत किया जाएगा या फिर शेष का निपटान किया जाएगा बशर्ते और नकदी प्रवाह व माप की तारीख एक ही रही हो। लेकिन जब दो मुद्राओं में विनियमता अस्थायी रूप से नहीं हो रही हो उस स्थिति में वही बाद की प्रथम विनियम दर लागू रहेगी जिस पर विनिमय संभव हो सके।

विनिमय अन्तरों की मान्यता

27. जैसा अनुच्छेद 3 (क) तथा 5 में नोट किया गया है कि भारतीय लेखा-मानक 39 विदेशी मुद्रा की मदों के प्रतिरक्षा (हैज) लेखांकन पर लागू होता है। प्रतिरक्षा (हैज) लेखांकन का प्रयोग प्रतिष्ठान से यह अपेक्षा करता है कि वह विनिमय के कुछ अंतरों को इस मानक द्वारा अपेक्षित विनिमय अंतरों के व्यवहार से भिन्न रूप से ले और उसका लेखांकन भी अलग से करे। उदाहरण के लिए भारतीय लेखा-मानक 39 यह अपेक्षा करता है ऐसी मुद्रा मदों पर विनिमय अन्तर, जो नकदी प्रवाह हेज में हैजिंग लिखतों के रूप में अहर्ता प्राप्त हैं वे प्रारम्भ में उस सीमा तक अन्य व्यापक आय मान्यताप्राप्त होंगे जिस सीमा तक प्रतिरक्षा (हैज) प्रभावी है।
28. मौद्रिक मदों के निपटान अथवा मौद्रिक मदों के उन दरों पर जिन पर अवधि के दौरान या पिछले वित्तीय विवरणों की प्रारम्भिक मान्यता पर जिन दरों पर रुपान्तरण किया गया था उनसे भिन्न दरों पर रुपान्तरण से यदि विनिमय अंतर उत्पन्न होते हैं उन्हें निम्नलिखित को छोड़कर उस अवधि के लाभ या हानि में मान्यता दी जाएगी :-
- (i) अनुच्छेद 32 में यथावर्णित, रिपोर्टिंग प्रतिष्ठान के विदेशी परिचालन में निवल निवेश के अंग के रूप में मौद्रिक मद में उत्पन्न विनिमय अंतर ;
 - (ii) जहां एक प्रतिष्ठान दीर्घकालीन मौद्रिक मदों के संबंध में अनुच्छेद 29क में दिये गये विकल्प का प्रयोग करता है।
29. जब किसी विदेशी मुद्रा के लेनदेन से मौद्रिक मद उत्पन्न होती है तथा लेनदेन की तिथि तथा निपटान की तिथि के बीच विनिमय दर पर कोई परिवर्तन हो तो उससे भी एक विनिमय अंतर उत्पन्न होता है। जब लेन-देन उसी लेखा अवधि में निपटा दिया जाता है जिसमें कि वह लेनदेन किया जाता है तो इस अवधि के सभी विनिमय अंतरों की मान्यता उसी अवधि में दी जाएगी। लेकिन, जब लेनदेन का निपटान बाद की लेखा अवधि में किया जाता है तो निपटान अवधि तक की प्रत्येक अवधि तक के विनिमय अंतर उस दौरान की विनिमय दरों के आधार पर निर्धारित किये जाएंगे। अनुच्छेद 29 क कुछ दीर्घावधि के मौद्रिक आस्तियों और दीर्घावधिक मौद्रिक देयताओं के विदेशी से कार्यात्मक मुद्रा में रुपान्तरण से उत्पन्न अप्राप्त विनिमय के अंतरों की मान्यता का विकल्प देता है।
- 29 क. एक प्रतिष्ठान दीर्घावधि मौद्रिक मदों के विदेशी मुद्रा से कार्यात्मक मुद्रा में रुपान्तरण करने से उत्पन्न विनिमय अंतरों की मान्यता के संबंध में विकल्प का प्रयोग निम्नलिखित अनुसार कर सकता है :-
- (i) विदेशी मुद्रा में दीर्घावधिक मौद्रिक आस्तियों और दीर्घावधिक मौद्रिक देयताओं से उत्पन्न अप्राप्त विनिमय अंतरों को मान्यता सीधे इक्विटी में दी जाएगी और उसे 'इक्विटी' के अलग घटक में संग्रहीत किया जाएगा। इस तरह से संग्रहीत राशि को इन दीर्घकालिक अवधि मदों की परिपक्वता अवधि के दौरान उपयुक्त तरीके से लाभ या हानि में अंतरित किया जाएगा। 'इक्विटी' का यह घटक अन्य किसी ऐसे घटक से अलग होगा जो व्यापक आय में संग्रहीत किसी अन्य विनिमय अंतर के रूप में हो ;
 - (ii) जहां एक प्रतिष्ठान दीर्घकालीन मौद्रिक मदों के संबंध में अनुच्छेद 29क का विकल्प दीर्घकालिक मौद्रिक देयताओं के लिए उस अवधि उपलब्ध नहीं होगा जब भारतीय लेखा मानक 39 के अनुसार लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वर्गीकृत किया जाता

है क्योंकि यह तो वे इसलिए है कि वे व्यापार के लिए धारित है या फिर इसलिए कि वे लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य के रूप में पदनामित हैं।

- (iii) अनुच्छेद 29क का विकल्प (i) में दिया गया विकल्प पहली बार तभी प्रयोग में लाया जाएगा जब इसी अनुच्छेद अर्थात् 29 क (i) में उल्लिखित दीर्घकालिक मौद्रिक आस्ति या दीर्घकालिक मौद्रिक देयता से उत्पन्न विनिमय अंतर को मान्यता दी जाती है। जब एक बार विकल्प का प्रयोग कर दिया जाता है तो उसकी वापसी नहीं होगी और उसका प्रयोग उसी अनुच्छेद यानि 29 क (i) में उल्लिखित सभी दीर्घकालिक मौद्रिक आस्तियों और दीर्घकालिक मौद्रिक देयताओं में किया जाएगा।
 - (iv) इस अनुच्छेद के प्रयोजन के लिए, मौद्रिक आस्ति या एक मौद्रिक देयता को दीर्घकालिक माना जाएगा यदि वह आस्ति या देयता उसकी प्रारंभिक मान्यता की तिथि से 12 माह या इससे अधिक की अवधि में परिपक्व होती है।
30. जब एक गैर मौद्रिक मद पर लाभ या हानि की अन्य व्यापक आय में मान्यता दी जाती है, उस लाभ या हानि का कोई भी विनिमय घटक अन्य विस्तृत आय में मान्य होगा। इसके विपरीत, जब एक गैर मौद्रिक दर पर लाभ या हानि की मान्यता लाभ या हानि में होती है, तो उस लाभ या हानि के विनिमय घटक की मान्यता भी लाभ या हानि में होगा।
 31. अन्य भारतीय लेखा मानकों में यह अपेक्षा की गयी है कि कुछ लाभ व हानियों की मान्यता अन्य व्यापक आय में की जाए। उदाहरण के लिए, भारतीय लेखा मानक 16 के अनुसार सम्पत्ति, संयंत्र तथा उपस्कर के पुनर्मूल्यांकन पर कोई लाभ व हानि होती है तो उसकी मान्यता अन्य व्यापक आय में की जाएगी। जब इस प्रकार की सम्पत्ति को विदेशी मुद्रा में मापा जाता है तो इस मानक के अनुच्छेद 23 (ग) के अनुसार पुनर्मूल्यांकित राशि को निर्धारण की तिथि दर पर रूपांतरित किया जाता है। यदि ऐसा करने से कोई विनिमय अंतर आता है तो उसे अन्य व्यापक आय में मान्यता दी जाएगी।
 32. एक मौद्रिक मद से उत्पन्न विनिमय अंतर जो विचाराधीन प्रतिष्ठान के विदेशी परिचालन (अनुच्छेद 15 देखें) में निवल निवेश का भाग बनता है तो उसे प्रतिष्ठान के पृथक वित्तीय विवरणों अथवा विदेशी परिचालन के व्यक्तिगत वित्तीय विवरणों में, जैसा भी उपयुक्त हो, लाभ अथवा हानि में मान्यता दी जायगी। वित्तीय विवरणों में, विदेशी परिचालन के साथ-साथ विचाराधीन प्रतिष्ठान दोनों शामिल हैं। (उदाहरणतया, समेकित वित्तीय विवरण, जब विदेशी परिचालन प्रतिष्ठान की एक अनुषंगी है) इस में विनिमय अन्तरों को प्रारम्भ में अन्य व्यापक आय में माना जाएगा और बाद में अनुच्छेद 48 के अनुसार निवल निवेश के निपटान के बाद इक्विटी से लाभ या हानि में पुनर्वर्गीकृत किया जाएगा।
 33. जब एक मौद्रिक मद विदेशी परिचालन में एक विचाराधीन प्रतिष्ठान के निवल निवेश का एक भाग बनती है और वह उस रिपोर्टिंग प्रतिष्ठान की कार्यात्मक मुद्रा में दर्शायी जाती है तो अनुच्छेद 28 के अनुसार विदेशी परिचालन के व्यक्तिगत वित्तीय विवरणों में विनिमय अंतर उत्पन्न होता है। यदि ऐसी किसी मद को विदेशी परिचालन की कार्यात्मक मुद्रा में दर्शाया जाता है तो अनुच्छेद 28 के अनुसार विचाराधीन प्रतिष्ठान के अलग-से तैयार किये जाने वाले वित्तीय विवरणों में विनिमय अन्तर उत्पन्न होता है। यदि इस तरह की मद जो कि रिपोर्टिंग प्रतिष्ठान या विदेशी परिचालन की कार्यात्मक मुद्रा से भिन्न मुद्रा में दर्शायी गयी है, रिपोर्टिंग प्रतिष्ठान के पृथक वित्तीय विवरणों व विदेशी परिचालन के व्यक्तिगत वित्तीय विवरणों में अनुच्छेद 28 के अनुसार विनिमय अन्तर उत्पन्न होता है, इस तरह के विनिमय अंतर वित्तीय विवरणों में अन्य

व्यापक आय में मान्यता दी जाती है, जिनमें विदेशी परिचालन और रिपोर्टिंग प्रतिष्ठान सम्मिलित हैं, [उदाहरणतया, ऐसे वित्तीय विवरण जिनमें विदेशी परिचालन समेकित किये गये हैं, आनुपातिक रूप से समेकित किये गये हैं या फिर इक्विटी पद्धति का प्रयोग करते हुए लेखांकित किये गये हैं] ।

34. जब कोई प्रतिष्ठान अपनी पुस्तकें व रिकार्ड अपनी कार्यात्मक मुद्रा से भिन्न किसी अन्य मुद्रा में रखता है तो वित्तीय विवरण तैयार करते समय वह सभी राशियों को अनुच्छेद 20-26 के अनुसार अपनी कार्यात्मक मुद्रा में रूपांतरित करेगा । इस प्रकार, कार्यात्मक मुद्रा में रूपांतरण में भी वही राशियां प्राप्त होंगी जैसे कि आरम्भ में कार्यात्मक मुद्रा के प्रयोग से प्राप्त होनी थीं । उदाहरणतया, मौद्रिक मदें अन्तिम दर के प्रयोग द्वारा कार्यात्मक मुद्रा में रूपांतरित की जाती हैं और गैर मौद्रिक मदें ऐतिहासिक लागत के आधार पर मापी जाती हैं और मान्यता अनुसार लेनदेन की तारीख की विनिमय दर का प्रयोग कर रूपांतरित की जाती है ।

कार्यात्मक मुद्रा में परिवर्तन

35. जब एक प्रतिष्ठान की कार्यात्मक मुद्रा में परिवर्तन होता है, तब प्रतिष्ठान परिवर्तन की तिथि से आगे की नयी कार्यात्मक मुद्रा पर लागू रूपांतरण प्रक्रिया का प्रयोग करेगा ।
36. जैसे अनुच्छेद 13 में नोट किया गया है एक प्रतिष्ठान की कार्यात्मक मुद्रा उन अन्तर्निहित लेन-देनों घटनाओं तथा परिस्थितियों को परिलक्षित करता है जो प्रतिष्ठान के लिए प्रासंगिक हैं । तदनुसार, जब एक बार कार्यात्मक मुद्रा निर्धारित कर ली जाती है इसे तभी बदला जा सकता है यदि उन अन्तर्निहित लेनदेनों, घटनाओं तथा परिस्थितियों में परिवर्तन हो । उदाहरण के लिए, मुद्रा में परिवर्तन मुख्यतया वस्तु की तथा सेवाओं विक्रय कीमतों को प्रभावित करता है अतः इससे एक प्रतिष्ठान की कार्यात्मक मुद्रा में परिवर्तन संभव है ।
37. कार्यात्मक मुद्रा में परिवर्तन भावी प्रभाव से लेखांकित किया जाता है । दूसरे शब्दों में, एक प्रतिष्ठान परिवर्तन की तिथि पर विनिमय दर का उपयोग कर सभी मदों को नई कार्यात्मक मुद्रा में रूपांतरित करता है । गैर मौद्रिक मदों की परिणाम स्वरूप रूपांतरित राशियां उनकी ऐतिहासिक लागत के रूप में ली जाती हैं । अनुच्छेद 32 तथा 39 (ग) के अनुसार अन्य व्यापक आय में पहले से मान्यता प्राप्त एक विदेशी परिचालन के रूपांतरण से उत्पन्न विनिमय अंतर को परिचालन के निपटान तक इक्विटी से लाभ अथवा हानि में पुनः वर्गीकृत नहीं किया जाता । जब अनुच्छेद 29 क में दिये गये विकल्प का प्रयोग किया जाता है, वे विनिमय अंतर जिन्हें पहले इक्विटी में सीधे ही मान्यता दे दी गयी थी और उक्त अनुच्छेद के अनुसरण में इक्विटी में अलग घटक के रूप में संग्रहीत है ; प्रतिष्ठान की कार्यात्मक मुद्रा में परिवर्तन पर उन्हें तत्काल लाभ या हानि में अन्तरित नहीं किया जाएगा । वे उस अनुच्छेद के अनुसार ही लाभ व हानि में अन्तरित होते रहेंगे जैसे पहले होते थे ।

कार्यात्मक मुद्रा से भिन्न प्रस्तुति मुद्रा का उपयोग

प्रस्तुति मुद्रा में रूपांतरण

38. एक प्रतिष्ठान अपने वित्तीय विवरणों को किसी एक मुद्रा (अथवा मुद्राओं) में प्रस्तुत कर सकता है। यदि प्रस्तुति मुद्रा प्रतिष्ठान की कार्यात्मक मुद्रा से भिन्न है, तो वह अपने वित्तीय परिणामों तथा वित्तीय स्थिति को प्रस्तुति मुद्रा में रूपान्तरित करता है। उदाहरणतया, जब एक समूह में विभिन्न प्रतिष्ठान हैं और प्रत्येक प्रतिष्ठान की कार्यमुद्रा अलग-अलग है तो प्रत्येक प्रतिष्ठान के वित्तीय परिणाम तथा स्थिति को एक सामान्य मुद्रा में व्यक्त किया जाएगा ताकि समेकित वित्तीय विवरण प्रस्तुत किये जा सकें।
39. एक प्रतिष्ठान के, जिसकी कार्यात्मक मुद्रा अति मुद्रास्फीतिपूर्ण अर्थव्यवस्था की मुद्रा नहीं है, वित्तीय परिणाम तथा स्थिति निम्नलिखित प्रक्रिया का उपयोग कर एक अलग प्रस्तुति मुद्रा में रूपांतरित किये जाएंगे।
- (क) प्रस्तुत प्रत्येक तुलन-पत्र (तुलनात्मक सहित) की आस्तियों तथा देयताओं को तुलन पत्र की तिथि की अंतिम दर पर रूपांतरित किया जायगा।
 - (ख) प्रस्तुत लाभ तथा हानि के प्रत्येक विवरण (तुलनात्मक सहित) के आय तथा व्यय को लेनदेनों की तिथियों की विनिमय-दर पर रूपांतरित किया जायगा; तथा
 - (ग) सभी परिणामस्वरूप विनिमय अंतर अन्य व्यापक आय में मान्य होंगे।
40. व्यावहारिक कारणों से, एक दर को, जो लेनदेनों की तिथियों की विनिमय दरों के लगभग है, उदाहरणार्थ, एक अवधि की औसत दर, प्रायः आय व व्यय की मदों के रूपांतरण के लिए प्रयुक्त की जाती है। यदि विनिमय दरों में बहुत अधिक उतार-चढ़ाव है तो ऐसी स्थिति में उस अवधि के लिए औसत दर का उपयोग करना उपयुक्त नहीं है।
41. अनुच्छेद 39 (ग) में संदर्भित विनिमय अंतर निम्नलिखित कारणों से उत्पन्न होते हैं -
- (क) आय एवं व्यय को लेन-देनों की तारीखों की विनिमय दरों पर तथा आस्तियों एवं देयताओं को अन्तिम दर पर रूपान्तरित करना।
 - (ख) प्रारंभिक निवल आस्तियों को अंतिम दर पर, जो कि पिछली अंतिम दर से भिन्न होगी, रूपांतरित करना।

इन विनिमय अन्तरों को लाभ तथा हानि में मान्यता नहीं दी जाती क्योंकि विनिमय दरों में परिवर्तनों का परिचालनों के वर्तमान तथा भविष्य की प्रवृत्तियों पर कम अथवा कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जब तक विदेशी परिचालन का निपटारा नहीं कर दिया जाता, विनिमय अन्तरों को राशि को 'इक्विटी' के एक अलग घटक के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। ऐसे विदेशी परिचालन, जो केवल समेकित हैं लेकिन पूर्णतया स्वामित्व में नहीं हैं, से सम्बन्धित है विनिमय अंतर और रूपांतरण से उत्पन्न और गैर-नियंत्रक हितों से सम्बन्धित एकत्रित विनिमय अंतर, समेकित तुलनपत्र में गैर-नियंत्रक हितों के रूप में आबंटित किये जाते हैं और उनको तदनुरूप और एक भाग के रूप में मान्यता दी जाती है।

42. एक प्रतिष्ठान के वित्तीय परिणामों तथा स्थिति को, जिसकी कार्यात्मक मुद्रा एक अति मुद्रास्फीतिपूर्ण अर्थव्यवस्था की मुद्रा है, निम्नलिखित प्रक्रिया द्वारा एक-अलग प्रस्तुत मुद्रा में रूपांतरित किया जाएगा :-

- (क) सभी राशियों को (अर्थात् आस्तियां, देयताएं, 'इक्विटी' की मदें, आय व व्यय जिनमें तुलनात्मक भी सम्मिलित हैं) बिल्कुल हाल ही के तुलनपत्र की तिथि की अंतिम दर पर रूपांतरित किया जायेगा। लेकिन इसका निम्नलिखित अपवाद होगा :-
- (ख) जब राशियों को गैर-अति मुद्रास्फीतिपूर्ण अर्थव्यवस्था की मुद्रा द्वारा रूपांतरित किया जाता है तो इस स्थिति में तुलनात्मक राशियां वे होंगी जिन्हें गत वर्ष के वित्तीय विवरणों में चालू वर्ष की राशियों के रूप में प्रस्तुत किया गया था। (यानि उन्हें कीमत स्तर में बाद के परिवर्तन या विनिमय दरों के बाद में परिवर्तनों में समायोजित नहीं किया गया है)

43. जब प्रतिष्ठान की कार्यात्मक मुद्रा एक अति मुद्रास्फीतिपूर्ण अर्थव्यवस्था की मुद्रा है तो वह प्रतिष्ठान अनुच्छेद 42 में दी गयी रूपान्तरण विधि का प्रयोग करने से पूर्व अपने वित्तीय विवरणों को भारतीय लेखा मानक 29 'अति मुद्रास्फीतिपूर्ण अर्थ व्यवस्थाएं' के अनुसरण में पुनः वर्णित करेगा। लेकिन, यह बात तुलनात्मक राशियों पर लागू नहीं होगी क्योंकि वे गैर-अति मुद्रास्फीतिपूर्ण अर्थव्यवस्था (देखिए अनुच्छेद 42(ख)) की मुद्रा में रूपान्तरित की जाती है। लेकिन जब अर्थव्यवस्था अति मुद्रास्फीतिपूर्ण अर्थव्यवस्था वाली नहीं रहती तथा प्रतिष्ठान भारतीय लेखा मानक 29 अति मुद्रास्फीतिपूर्ण अर्थव्यवस्था में वित्तीय रिपोर्टिंग के अनुसार वित्तीय विवरणों को पुनः वर्णित नहीं करता तो वह प्रतिष्ठान जिस तारीख को अपने वित्तीय विवरणों का पुनः वर्णन करना बंद कर देता है उसी तारीख के कीमत स्तर की पुनर्वर्णित राशियों के प्रस्तुति मुद्रा में रूपान्तरण के लिए ऐतिहासिक लागतों का उपयोग करेगा।

विदेशी परिचालन का रूपांतरण

- 44. अनुच्छेद 38-43 के अतिरिक्त अनुच्छेद 45-47, तब लागू होता है जब एक विदेशी परिचालन के वित्तीय परिणाम तथा स्थिति का प्रस्तुति मुद्रा में रूपांतरण किया जाता है ताकि विचाराधीन प्रतिष्ठान विदेशी परिचालन को अपने विवरणों में समेकन, अनुपातिक समेकन या 'इक्विटी' विधि द्वारा सम्मिलित कर सके।
- 45. विचाराधीन प्रतिष्ठान के वित्तीय परिणामों व स्थिति में विदेशी परिचालन का समावेश करने के लिए समेकन की सामान्य प्रक्रिया का अनुपालन किया जाता है जिसमें समूह की अनुषंगियों के साथ परस्पर शेषों व लेन-देनों को हटाना पड़ता है। (देखिए भारतीय लेखा मानक 27) व भारतीय लेखा मानक 31 'संयुक्त उद्यमों में हित, लेकिन, इसमें मौद्रिक आस्ति (या देयता), चाहे वह लघु अवधि की हैं या दीर्घावधि की हैं, समेकित वित्तीय विवरण में मुद्रा के उतार चढ़ाव के प्रभाव को दर्शाये बिना तदनुरूपी समूह की पारस्परिक देयता (आस्ति) से नहीं हटाया जा सकता। ऐसा यं है क्योंकि मौद्रिक मद उस वचनबद्धता को प्रदर्शित करती है जो एक मुद्रा से दूसरी मुद्रा में परिवर्तन से विचाराधीन प्रतिष्ठान को मौद्रिक उतार-चढ़ाव के कारण कुछ लाभ या हानि होती है। इस तरह विचाराधीन प्रतिष्ठान के वित्तीय विवरणों में विनिमय अन्तर को लाभ या हानि में मान्यता की जाती है। यदि यह अनुच्छेद 32 के अनुसार परिस्थितियों के कारण है तो इसकी अन्य व्यापक आय में मान्यता कर दी जाती है और इसे 'इक्विटी' के एक अलग घटक में तब तक

- एकत्र किया जाता है जब तक कि विदेशी परिचालन का निपटान नहीं हो जाता है। जब रिपोर्ट करने वाले प्रतिष्ठान के समेकित विवरणों में अनुच्छेद 29 क में दिये गये विकल्प का प्रयोग किया जाता है तो इस प्रकार का विनिमय अंतर इक्विटी में सीधे ही मान्य है और उसका इस अनुच्छेद में वर्णित ढंग से निपटान किया जाता है।
46. जब विदेशी परिचालन के वित्तीय विवरण विचाराधीन प्रतिष्ठान के वित्तीय विवरणों की तिथि से भिन्न हो तो विदेशी परिचालन विचाराधीन प्रतिष्ठान के विवरणों की तिथि पर अपने वित्तीय विवरण प्रायः अतिरिक्त रूप से तैयार करता है। जब ऐसा नहीं किया जाता तब भारतीय लेखा मानक 27 एक अन्य तिथि की अनुमति प्रदान करता है बशर्ते इस तिथि का अंतर तीन माह से अधिक न हो तथा इन अलग-अलग तिथियों के मध्य उत्पन्न होने वाले महत्वपूर्ण लेनदेनों व अन्य घटनाओं के प्रभाव के लिए आवश्यक समायोजन कर लिया जाता है। इस प्रकार के मामले में, विदेशी परिचालन की आस्तियां एवं देयताओं का विदेशी परिचालन की रिपोर्टिंग अवधि के अंत पर विनिमय दर पर रूपांतरित किया जाता है। भारतीय लेखा मानक 27 के अनुसार विनिमय दर के महत्वपूर्ण परिवर्तन को रिपोर्टिंग प्रतिष्ठान की रिपोर्टिंग अवधि के अंत तक समायोजन कर लिया जाता है। भारतीय लेखा मानक 28 'सहयोगी प्रतिष्ठानों में निवेश' और भारतीय लेखा मानक 31 के अनुसरण में यही दृष्टिकोण सहयोगी व संयुक्त उद्यमों में इक्विटी विधि और संयुक्त उद्यमों में आनुपातिक समेकन का प्रयोग करने में उपयोग में लाया जाता है।
47. विदेशी परिचालन के अधिग्रहण पर उत्पन्न किसी गुडविल तथा विदेशी परिचालन के अधिग्रहण पर उत्पन्न आस्तियां एवं देयताओं की अग्रणीत(कैरिंग) राशियों के उचित मूल्य पर किन्हीं समायोजनों को विदेशी परिचालन की आस्तियां व देयताएं माना जायेगा। अतः उन्हें विदेशी परिचालन की कार्यात्मक मुद्रा में व्यक्त किया जाएगा तथा उन्हें अनुच्छेद 39 तथा 42 के अनुसार अंतिम दर पर रूपांतरित किया जायेगा।

विदेशी परिचालन का निपटान अथा आंशिक निपटान

48. एक विदेशी परिचालन के निपटान पर उसके विनिमय अंतरों की संचित राशि जिसकी अन्य व्यापक आय में मान्यता दी गयी थी और 'इक्विटी' के एक अलग घटक में संग्रहण किया गया था उसे इक्विटी से लाभ या हानि में पुनः वर्गीकृत (एक पुनर्वर्गीकरण समायोजना के रूप में) किया जाएगा जब निपटान पर लाभ या हानि मान्यता होगी। [देखिए भारतीय लेखा मानक 1 *वित्तीय विवरणों का प्रस्तुतिकरण*]
- 48 क. एक विदेशी परिचालन के समस्त हितों का निपटान करने के अतिरिक्त, निम्नलिखित को भी निपटान के रूप में ही लेखांकित किया जाता है चाहे प्रतिष्ठान पूर्ववर्ती अनुषंगी, सहयोगी अथवा संयुक्त रूप से नियंत्रित प्रतिष्ठान में अपना हित जारी रखता है।
- (क) एक अनुषंगी पर नियंत्रण की समाप्ति जिसमें विदेशी परिचालन भी सम्मिलित है।
 - (ख) एक सहयोगी के ऊपर महत्वपूर्ण प्रभाव की समाप्ति जिसमें विदेशी परिचालन भी सम्मिलित है; तथा
 - (ग) संयुक्त रूप से नियंत्रित प्रतिष्ठान के ऊपर संयुक्त नियंत्रण की समाप्ति जिसमें विदेशी परिचालन भी सम्मिलित है।

- 48 ख. एक अनुषंगी, जिसमें विदेशी परिचालन भी सम्मिलित है, के निपटान पर उस विदेशी परिचालन से संबंधित विनिमय अंतर की संग्रहीत राशि जो गैर-नियंत्रित हित से जुड़ी है उसे अमान्य किया जाएगा लेकिन उसे लाभ अथवा हानि में पुनः वर्गीकृत नहीं किया जाएगा।
- 48 ग. यदि अनुषंगी का, जिसमें विदेशी परिचालन भी सम्मिलित है, आंशिक निपटान किया जाता है तो प्रतिष्ठान अन्य व्यापक आय में मान्य विनिमय अंतर की संग्रहीत राशि का अनुपातिक अंश को उस विदेशी परिचालन में गैर नियंत्रित हित में पुनः बांटेगी। विदेशी परिचालन के किसी अन्य आंशिक निपटान में प्रतिष्ठान अन्य व्यापक आय में मान्य विनिमय अंतर की संग्रहीत राशि के केवल अनुपातिक अंश को ही लाभ अथवा हानि में पुनः वर्गीकृत करेगा।
- 48 घ. एक विदेशी परिचालन में एक प्रतिष्ठान के हित का आंशिक निपटान प्रतिष्ठान के स्वामित्व हित में विदेशी परिचालन तक की कटौती है न कि अनुच्छेद 48क अनुसार कटौतियां क्योंकि उनका लेखांकन निपटान के रूप में किया जाता है।
49. एक प्रतिष्ठान अपने विदेशी परिचालन की बिक्री, समापन, शेयर पूंजी का पुनर्भुगतान अथवा समस्त अथवा एक भाग के त्याग के जरिये अपने हित का पूर्ण निपटान अथवा आंशिक निपटान कर सकता है। एक विदेशी परिचालन की अग्रणीत (केरिंग) राशि का अपलिखन, इस कारण कि स्वयं हानियों या क्षति निवेशक द्वारा मान्य की गयी है को आंशिक निपटान नहीं कहा जाएगा। तदनुसार, अन्य व्यापक आय में मान्य विदेशी विनिमय के लाभ अथवा हानि के किसी भाग को अपलिखन के समय लाभ अथवा हानि में पुनः वर्गीकृत नहीं किया जाएगा।

सभी विनिमय अंतरों का कर - प्रभाव

50. एक प्रतिष्ठान (विदेशी परिचालन सहित) जब कोई विदेशी मुद्रा में कोई लेन-देन करता है और उससे कोई लाभ व हानि होती है और वित्तीय परिणामों व स्थिति का किस अन्य मुद्रा में रूपांतरण किया जाता है। भारतीय लेखा मानक 12 'आयकर' इन प्रभावों पर लागू होता है।

प्रकटन

51. अनुच्छेद 53 तथा 55-57 में 'कार्यात्मक मुद्रा' के संदर्भ समूह के साथ-साथ मूल प्रतिष्ठान की कार्यात्मक मुद्रा पर भी लागू होते हैं।
52. एक प्रतिष्ठान निम्नलिखित को प्रकट करेगा :-
- क) लाभ तथा हानि में मान्यता प्राप्त विनिमय अंतरों की राशि, अपवाद भारतीय लेखा मानक 39 के अनुसरण में लाभ अथवा हानि के जरिये उचित मूल्य पर मापी गयी वित्तीय लिखतों से उत्पन्न अन्तर ;
 - ख) अन्य व्यापक आय में मान्य तथा 'इक्विटी' साम्या के एक पृथक घटक में संग्रहीत निवल विनिमय अंतर, तथा अवधि के आरम्भ तथा अंत में इस प्रकार के विनिमय अंतरों की राशि का मिलान, तथा

(ग) इक्विटी में सीधे मान्य और अनुच्छेद 29 क के अनुसरण में 'इक्विटी' में अलग घटक में संग्रहीत निवल विनिमय अंतर और अवधि के प्रारंभ के अंत में ऐसे विनिमय अंतरों की राशि का मिलान ।

53. जब प्रस्तुति मुद्रा कार्यात्मक मुद्रा से भिन्न हो तो उस तथ्य का उल्लेख कार्यात्मक मुद्रा के प्रकटन और अलग प्रस्तुति मुद्रा के प्रयोग के कारण के साथ ही किया जाएगा ।
54. जब विचाराधीन(रिपोर्टिंग) प्रतिष्ठान अथवा उसके किसी विशेष विदेशी परिचालन की कार्यात्मक मुद्रा में परिवर्तन हो इस तथ्य का उल्लेख और कार्यात्मक मुद्रा में परिवर्तन के कारण और तिथि को प्रकट किया जाएगा ।
55. जब कोई प्रतिष्ठान उस मुद्रा में वित्तीय विवरण प्रस्तुत करता है जो उसकी कार्यात्मक मुद्रा से भिन्न है तो उसे भारतीय लेखा मानकों की अनुपालन के रूप में वित्तीय विवरणों में उल्लेख करना होगा कि अनुच्छेद 39 तथा 42 के अनुसार उसने रूपांतरण की विधि सहित लागू प्रत्येक भारतीय मानक की सभी अपेक्षाओं को पूरा कर लिया है ।
56. कई बार प्रतिष्ठान अपने वित्तीय विवरणों अथवा अन्य वित्तीय सूचना को ऐसी मुद्रा में प्रस्तुत करता है जो उसकी कार्यात्मक मुद्रा नहीं होती और वह अनुच्छेद 55 की अपेक्षाओं को भी पूरा नहीं करता है । उदाहरण के लिए, एक प्रतिष्ठान वित्तीय विवरणों में कुछ चुनी हुई मदों को अन्य मुद्रा में परिवर्तित करता है अथवा उसकी कार्यात्मक मुद्रा एक अति मुद्रास्फीतिपूर्ण अर्थव्यवस्था की मुद्रा नहीं है और सर्वाधिक नवीन अंतिम दर पर वित्तीय विवरणों की सभी मदों को रूपांतरित करता है। इस प्रकार के परिवर्तन भारतीय लेखा मानकों के अनुसार नहीं हैं तथा उनका अनुच्छेद 57 में दी गयी व्यवस्था अनुसार प्रकटन आवश्यक है ।
57. जब कोई प्रतिष्ठान अपने वित्तीय विवरण अथवा अन्य वित्तीय सूचना को एक मुद्रा में प्रदर्शित करता है जो उसकी कार्यात्मक मुद्रा अथवा प्रस्तुति मुद्रा से भिन्न है तथा अनुच्छेद 55 की अपेक्षाएं भी पूरी नहीं की गयी हैं, तो वह प्रतिष्ठान निम्नलिखित कार्रवाई करेगा : -
 - (क) उस सूचना को अनुपूरक सूचना के रूप में भारतीय लेखा मानक द्वारा अपेक्षित के साथ अंतर को स्पष्ट करेगा ।
 - (ख) उस मुद्रा को प्रकट करेगा जिसमें अनुपूरक सूचना को प्रदर्शित किया गया है ।
 - (ग) प्रतिष्ठान की कार्यात्मक मुद्रा तथा अनुपूरक सूचना को निर्धारित करने के लिए प्रयुक्त रूपांतरण विधि को भी प्रकट करेगा ।

परिशिष्ट 'क'

अन्य भारतीय लेखा मानकों में समाविष्ट मामलों के संदर्भ

यह परिशिष्ट भारतीय लेखा मानक 21 का अभिन्न अंग है ।

इस परिशिष्ट में उस परिशिष्ट का उल्लेख किया गया है जो अन्य लेखा मानक का अंग है और जो भारतीय लेखा मानक 21 'विदेशी विनिमय दरों में परिवर्तन के प्रभाव के लिए संदर्भ का कार्य करता है ।

1 परिशिष्ट -घ - विदेशी परिचालन में निवल निवेश की प्रतिरक्षा (हैज) - भारतीय लेखा मानक 39 'वित्तीय लिखतें : मान्यता एवं माप' में समाविष्ट है और इस मानक के लिए संदर्भ का कार्य करता है ।

परिशिष्ट 'ख'

यह परिशिष्ट भारतीय लेखा मानक 21 के साथ संलग्न है लेकिन, यह इसका अंग नहीं है।

दृष्टांत उदाहरण - अनुच्छेद 14

प्रतिष्ठान 'प' का एक अनुषंगी प्रतिष्ठान 'स' है। प्रतिष्ठान 'प' और 'स' की कार्यात्मक मुद्राएं भारतीय लेखा मानक 21 के अनुसरण में क्रमशः 'रुपया' व 'मुद्रा इकाई' (सी यू) निश्चित हैं। इसके साथ ही, मुद्रा 'मुद्रा इकाई' (सी यू) भारतीय लेखा मानक 29 के अर्थ में उच्च मुद्रास्फीतिशील अर्थव्यवस्था की मुद्रा निश्चित की गयी है। अतः भारतीय लेखा मानक 29 के अनुसरण में प्रतिष्ठान 'स' के वित्तीय विवरणों को पुनर्कथित किया जाएगा। यह अपेक्षा अपरिहार्य है। उदाहरणार्थ, प्रतिष्ठान 'स' की कार्यात्मक मुद्रा रुपये के रूप में अपनाना।

दृष्टांत उदाहरण क्षतिग्रस्तता हानि - अनुच्छेद 25

प्रतिष्ठान 'क' की कार्यात्मक मुद्रा 'रुपया' है। इस प्रतिष्ठान ने अमेरिका ('यू एस') में एक भवन का अधिग्रहण किया है जिसकी लागत "यू एस" डालर 10000 थी जबकि उस समय विनिमय दर 1 "यू एस" डालर = 50 रुपये थी। इस भवन को प्रतिष्ठान 'क' के वित्तीय विवरणों में लागत पर लिया गया है। इस उदाहरण के प्रयोजन के लिए मूल्यहास की अनदेखी की गयी है। तुलन पत्र की तिथि को, इस भवन में क्षतिग्रस्तता का संकेत है। इसके परिणामस्वरूप, तुलन पत्र की तिथि पर क्षतिग्रस्तता परीक्षण भारतीय लेखा मानक 36 के अनुसरण में किया गया और उसके अनुसार इस भवन की वसूलीयोग्य राशि "यू एस" डालर 9500 निश्चित की जाती है। तुलन पत्र की तिथि को विनिमय दर 1 "यू एस" डालर = 53 रुपये थी।

रुपये

अधिग्रहण की तिथि की विनिमय दर 1 "यू एस" डालर
= 50 रुपये के आधार पर रूपांतरित लागत = 500000

तुलन-पत्र की तिथि को विनिमय दर 1 "यू एस" डालर
= 53 रुपये के अनुसार रूपांतरित वसूलीयोग्य राशि = 503500

हालांकि, विदेशी मुद्रा के संदर्भ में 'यू एस' डालर 500 ('यू एस' डालर 10000 - 'यू एस' डालर 9,500) की क्षतिग्रस्तता हानि है, लेकिन कार्यात्मक मुद्रा के संदर्भ में इस प्रकार की कोई हानि नहीं है। यह इस कारण से है क्योंकि कार्यात्मक मुद्रा (रुपये 503500) की वसूलीयोग्य राशि कार्यात्मक मुद्रा (500000 रुपये) के संदर्भ में अग्रणीत राशि (अर्थात् इस उदाहरण में लागत) से अधिक है। अतः इस भवन पर किसी क्षतिग्रस्तता हानि को मान्यता नहीं दी गयी है।

दृष्टांत उदाहरण - अनुच्छेद 33

प्रतिष्ठान 'प' का एक विदेशी अनुषंगी प्रतिष्ठान 'स 1' है। प्रतिष्ठान 'प' व प्रतिष्ठान 'स 1' की कार्यात्मक मुद्राएं क्रमशः 'रुपया' व 'यू एस' डालर' हैं। दोनों प्रतिष्ठान वित्तीय वर्ष को ही लेखा वर्ष मानते हैं। दोनों प्रतिष्ठानों का लेखा वर्ष 31 मार्च को समाप्त होता है। प्रतिष्ठान 'प' की प्रस्तुति मुद्रा पृथक व समेकित दोनों विवरणों में रुपया ही है।

निम्नलिखित सभी स्थितियों में, यह माना है कि ऋण प्रतिष्ठान की विदेशी परिचालन का एक अंग है।

स्थिति 1

प्रतिष्ठान 'स 1' की प्रतिष्ठान 'प' के प्रति 'यू एस' डालर 1000 की ऋण देयता है। यह ऋण उसने कुछ वर्ष पहले लिया था। 31 मार्च 20X0 और 31 मार्च 20X1 को विनिमय दर क्रमशः 1 'यू एस' डालर = 48 रुपये व 1 'यू एस' डालर 50 रुपये थी। इस स्थिति में, प्रतिष्ठान 'स 1' के व्यक्तिगत वित्तीय विवरणों में कोई विनियम अंतर उत्पन्न नहीं होता है क्योंकि यह इसकी अपनी कार्यात्मक मुद्रा में प्रदर्शित किया गया है।

प्रतिष्ठान 'प' के पृथक वित्तीय विवरणों में निम्नलिखित के अनुसार विनिमय लाभ के रूप में 2000 रुपये की राशि उद्भूत होती है जिसे इस प्रकार प्रस्तुत किया जा सकता है :-

- रुपांतरित ऋण आस्ति राशि 'यू एस' डालर 1000 पर -	रुपये
31 मार्च 20X1 को विनिमय दर @ 1 'यू एस' डालर = 50 रुपये पर	= 50000
31 मार्च 20X0 मार्च के विनिमय दर @ 1 'यू एस' डालर = 48 रुपये पर	= 48000
विनिमय लाभ	= 2000

प्रतिष्ठान 'प' के समेकित वित्तीय विवरणों में, 2000 रुपये का विनिमय लाभ अन्य व्यापक आय में माना जाएगा और इसे इक्विटी में संचित किया जाएगा।

स्थिति 2

प्रतिष्ठान 'स 1' की प्रतिष्ठान 'प' के प्रति 48000 रुपये की ऋण देयता है। यह ऋण उसने कुछ वर्ष पहले ही लिया था। इस उदाहरण के प्रयोजन के लिए यह माना गया है कि औसत विनिमय दर का प्रयोग वर्ष के दौरान तत्काल दरों की लगभग विश्वसनीय दर है। 31 मार्च 20X0 और 31 मार्च 20X1 की विनिमय दरें क्रमशः 1 'यू एस' डालर = 48 रुपये और 1 'यू एस' डालर 50 रुपये थीं। 31 मार्च 20X1 को समाप्त वित्त वर्ष के दौरान औसत विनिमय दर 1 'यू एस' डालर = 49 रुपये थीं।

उपर्युक्त स्थिति में, प्रतिष्ठान 'प' के पृथक वित्तीय विवरणों में ऋण पर कोई विनियम अंतर उद्भूत नहीं होता क्योंकि यह उसकी अपनी ही कार्यात्मक मुद्रा में प्रदर्शित किया गया है।

प्रतिष्ठान 'स 1' के व्यक्तिगत वित्तीय विवरणों में विनिमय लाभ 'यू एस' 40 निम्नलिखित के अनुसार प्रदर्शित किया गया है -

रुपांतरित ऋण देयता 48000 रुपये पर -	'यू एस' डालर
31 मार्च 20X1 को विनिमय दर @ 1 'यू एस' डालर = 50 रुपये पर	= 960
31 मार्च 20X0 को विनिमय दर @ 1 'यू एस' डालर = 48 रुपये पर	= 1000
विनिमय लाभ	= 40

भारतीय लेखा मानक 21 के अनुच्छेद 38-47 के अनुसरण में, प्रतिष्ठान 'स 1' के वित्तीय विवरणों को रुपये में रुपांतरित करने के बाद प्रतिष्ठान के समेकित वित्तीय विवरणों में 'यू एस' डालर 40 अर्थात् 1960 रुपये ('यू एस' डालर 40 @ 49 रुपये) के अनुरूप रुपये में विनिमय लाभ होगा जो अन्य विस्तृत आय में मान्य होगा और 'इक्विटी' में संचित किया जाएगा।

स्थिति 3

प्रतिष्ठान 'स 1' की प्रतिष्ठान 'प' के प्रति 1000 यूरो की ऋण देयता है। यह ऋण उसने कुछ वर्ष पहले लिया था।

विनिमय दरें

31 मार्च 20X0 को	31 मार्च 20X1 को
यूरो 1 = 60 रुपये	यूरो 1 = 61 रुपये
यूरो 1 = 'यू एस' डालर 1.3	यूरो 1 = 'यू एस' डालर 1.4

31 मार्च 20X1 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष में 'यू एस' डालर व रुपये के बीच औसत विनिमय दर 1 'यू एस' डालर = 45 रुपये थीं। इस उदाहरण के प्रयोजन के लिए यह माना गया है कि वर्ष के दौरान औसत विनिमय दर का प्रयोग तत्काल दरों के लगभग विश्वसनीय दर है।

प्रतिष्ठान 'प' के पृथक वित्तीय विवरणों में निम्नलिखित के अनुसार विनिमय लाभ के रूप में 1000 रुपये का उद्भूत विनिमय लाभ निम्नलिखित अनुसार प्रदर्शित होता है :-

रुपांतरित ऋण आस्ति यूरो 1000 पर	रुपये
- 31 मार्च 20X1 को @ 1 यूरो = 61 रुपये	= 61000
- 31 मार्च 20X0 को @ 1 यूरो = 60 रुपये	= 60000
विनिमय लाभ	= 1000

प्रतिष्ठान 'प' के समेकित वित्तीय विवरणों में 1000 का विनिमय लाभ अन्य व्यापक आय में मान्य होगा और इसे इक्विटी में संचित किया जाएगा।

प्रतिष्ठान 'स 1' के पृथक वित्तीय विवरणों में 'यू एस' डालर 100 की उद्भूत विनिमय हानि निम्नलिखित के अनुसार प्रदर्शित होती है :-

रुपांतरित ऋण देयता यूरो 1000 पर	'यू एस' \$
31 मार्च 20X1 की विनिमय दर @ 1 यूरो = 1.4 'यू एस' डालर	= 1400
31 मार्च 20X0 की विनिमय दर @ 1 यूरो = 1.3 'यू एस' डालर	= 1300
विनिमय हानि	= 100

भारतीय लेखा मानक 21 के अनुच्छेद 38-47, के अनुसरण में प्रतिष्ठान 'स 1' के वित्तीय विवरणों के रुपये में रुपांतरण पर प्रतिष्ठान 'प' के समेकित वित्तीय विवरणों में रुपये के संदर्भ में विनिमय हानि 'यू एस' डालर 100 अर्थात् 4500 रुपये ('यू एस' डालर 100 @ 45 रुपये) के अनुरूप अन्य विस्तृत आय में मान्य होगी और 'इक्विटी' में संचित की जाएगी।

दृष्टांत उदाहरण - अनुच्छेद 37

प्रारम्भ से ही, प्रतिष्ठान 'क' की कार्यात्मक मुद्रा रुपया रही है। इसका एक विदेशी परिचालन है जिसकी कार्यात्मक मुद्रा यूरो है। हालात में परिवर्तन के फलस्वरूप इस प्रतिष्ठान के परिचालन प्रभावित होते हैं और प्रबंधन यह निश्चय करता है कि 1 जनवरी 20X से, प्रतिष्ठान की कार्यात्मक मुद्रा 'यू एस' डालर में होगी। इस तिथि को विनिमय दर 1 'यू एस' डालर = 50 रुपये है। इस तिथि को अग्रणीत (कैरिंग) लागत गत कार्यात्मक मुद्रा के अनुसार 100000 रुपये है। प्रतिष्ठान ने अन्य व्यापक आय में विदेशी परिचालन के रुपान्तरण को मान्यता दी है और 'इक्विटी' में विदेशी मुद्रा रुपान्तरण कोष (एफ सी टी आर) के रूप में संचित किया है। 1 जनवरी 20X1 को गत कार्यात्मक मुद्रा के संदर्भ में संचित 'एफ सी टी आर' 50000 रुपये होता है। विदेशी परिचालन की कार्यात्मक मुद्रा में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं है। प्रतिष्ठान का लेखा वर्ष कैलेंडर वर्ष है।

प्रतिष्ठान 'क' नयी कार्यात्मक मुद्रा में अर्थात् 'यू एस' डालर के लिए रुपान्तरण पद्धति को पूर्व प्रभाव यानि कार्यात्मक मुद्रा में परिवर्तन की तिथि से लागू करेगा। तदनुसार, 1 जनवरी 20X1 को तुलन पत्र की सभी मदें विनिमय दर 1 'यू एस' डालर = 50 रुपये पर रुपांतरित की जाएंगी।

नयी कार्यात्मक मुद्रा में सूचीबद्ध सामान (इंवेंट्रीज) की 1 जनवरी 20X1 को अग्रणीत राशि 'यू एस' डालर 2000 होगी (रुपये 100000 की 1 'यू एस' डालर = 50 रुपये दर पर रुपांतरित) यह 'यू एस' डालर 2000 सूचीबद्ध सामान की ऐतिहासिक लागत होगी। यह तब भी वही होती यदि सूचीबद्ध सामान 1 जनवरी 20X1 से पूर्व अधिगृहीत किया जाता।

1 जनवरी 20X1 को नयी कार्यात्मक मुद्रा पर संचित एक सी टी आर 'यू एस' डालर 1000 (50000 रुपये पर 1 'यू एस' डालर = 50 रुपये की दर पर रुपान्तरित) होगा। जब तक विदेशी परिचालन का निपटान नहीं कर दिया जाता, इस राशि को 'इक्विटी' से लाभ या हानि में पुनर्वर्गीकृत नहीं किया जाएगा।

परिशिष्ट 1

टिप्पणी - यह परिशिष्ट भारतीय लेखा मानक का अंग नहीं है। इस परिशिष्ट का प्रयोजन मात्र इतना है कि भारतीय लेखा मानक (इंड ए एस) 21 और तदनुरूपी अन्तरराष्ट्रीय लेखा मानक (आई ए एस) 21 विदेशी विनिमय दरों में परिवर्तन के प्रभाव के बीच अन्तर को स्पष्ट किया जाए।

अन्तरराष्ट्रीय लेखा मानक (आई ए एस) 21 विदेशी विनिमय दरों में परिवर्तन के प्रभाव के साथ तुलना

1. अन्तरराष्ट्रीय लेखा मानक (आई ए एस) 21 में दिये गये संक्रमणकालीन प्रावधान भारतीय लेखा मानक 21 में इस दृष्टि से नहीं दिये गये हैं क्योंकि भारतीय लेखा मानकों से संबंधित सभी संक्रमणकालीन प्रावधान, जहां उचित है, भारतीय लेखा मानक 101 'भारतीय लेखा मानकों का प्रथमवार अंगीकरण' में सम्मिलित कर दिये गये हैं।
2. भारतीय लेखा मानक 21 उस विकल्प की अनुमति देता है जो कुछ दीर्घकालिक मदों का विदेशी मुद्रा से कार्यात्मक मुद्रा में रुपान्तरण से उत्पन्न विनिमय अंतरों की मान्यता को इक्विटी में सीधे मान्यता देने की अनुमति देता है। भारतीय लेखा मानक 21 यह अपेक्षा करता है कि संग्रहीत विनिमय अंतरों को लाभ-हानि में उपयुक्त रूप से अंतरित करे। अन्तरराष्ट्रीय लेखा मानक 21 इस प्रकार के व्यवहार की अनुमति नहीं देता। परिणामतया, भारतीय लेखा मानक 21 में अन्तरराष्ट्रीय लेखा मानक 21 की तुलना में एक नया अनुच्छेद 29 'क' जोड़ा गया है।
3. कुछ विनिमय अंतरों के लिए निर्धारित विकल्प व्यवहार के परिणामस्वरूप (उपर्युक्त 2 में यथावर्णित) भारतीय लेखा मानक 21 के अनुच्छेद 52 में अतिरिक्त प्रकटन जोड़ा गया है।
4. भारतीय लेखा मानक 21 में अनुच्छेद 14, 25, 33 व 37 के दृष्टांत उदाहरण परिशिष्ट के रूप में सम्मिलित किये गये हैं।
5. रिपोर्टिंग मुद्रा या विशेष विदेशी परिचालन की कार्यात्मक मुद्रा में यदि कोई परिवर्तन होता है, तो अन्तरराष्ट्रीय लेखा मानक 21 यह अपेक्षा करता है कि इस तथ्य का प्रकटन किया जाए और यह भी कि किस कारण से कार्यात्मक मुद्रा में परिवर्तन किया गया है। भारतीय लेखा मानक 21 कार्यात्मक मुद्रा में परिवर्तन की तिथि के अतिरिक्त प्रकटन की अपेक्षा करता है।
6. इस मानक में भिन्न शब्दावली का प्रयोग किया गया है, उदाहरणार्थ, शब्दों 'वित्तीय स्थिति का विवरण' के स्थान पर शब्द 'तुलन-पत्र' और शब्दों 'व्यापक आय का विवरण' के स्थान पर शब्द 'लाभ-हानि विवरण' का प्रयोग किया गया है।

भारतीय लेखा मानक (इंड ए एस) 23

उधार की लागतें

(इस भारतीय लेखा-मानक में मोटे टाइप व सामान्य टाइप में अनुच्छेद हैं। इन दोनों तरह के अनुच्छेदों का समान प्राधिकार है। मोटे टाइप में अनुच्छेद मुख्य सिद्धान्तों के सूचक हैं।)

मुख्य सिद्धांत

1. उधार की लागतों का प्रत्यक्षतया संबंध अर्हक आस्ति के अर्जन, निर्माण या उत्पादन से है और ये लागतें उस आस्ति की लागत का हिस्सा बनती हैं। शेष उधार लागतें व्यय के रूप में मान्य हैं।

कार्यक्षेत्र

2. एक प्रतिष्ठान, इस मानक को उधार की लागतों के लेखे के लिए लागू करेगा।
3. यह मानक, और अधिमानी पूंजी, जिसे देयता में वर्गीकृत नहीं किया गया है, सहित 'इक्विटी' की वास्तविक या अभ्यारोपित 'इक्विटी' लागत पर विचार नहीं करता है।
4. कोई भी प्रतिष्ठान इस भारतीय लेखा मानक को उन उधार की लागतों पर लागू नहीं करेगा जो प्रत्यक्ष रूप से निम्नलिखित के अधिग्रहण, निर्माण या उत्पादन से सम्बन्धित हैं :-
 - 1) एक अर्हक आस्ति जिसका उचित मूल्य पर मप किया गया है। (उदाहरणतया एक जैविक आस्ति)
 - 2) सूचीबद्ध माल जिसका या तो निर्माण किया जाता है या फिर उसका उत्पादन किया जाता है और वह निर्माण/उत्पादन एक बड़े स्तर पर और बार-बार किया जाता है।

परिभाषाएं

5. इस मानक में निम्नलिखित शब्दावली का प्रयोग यहाँ विनिर्दिष्ट अर्थों में किया गया है -
 उधार की लागतें - एक प्रतिष्ठान जब निधियां को उधार के रूप में लेता है और ब्याज व अन्य लागतों के रूप में जिस राशि का व्यय करता है।

अर्हक आस्ति - वह आस्ति है जिसके वांछित उपयोग या विक्रय के लिए आवश्यक रूप से जब एक विशेष समय लगता है।

6. उधार की लागतों में निम्नलिखित शामिल हैं :-

- (क) भारतीय लेखा मानक 39 - वित्तीय लिखतें - मान्यता एवं माप में यथावर्णित प्रभावी ब्याज विधि का प्रयोग करते हुए ब्याज स्वरूप व्यय का आकलन। ;
- (ख) [देखिये परिशिष्ट 1]
- (ग) [देखिये परिशिष्ट 1]
- (घ) पट्टे के अनुसार मान्यता प्राप्त वित्तीय पट्टों के वित्तीय प्रभार ; और
- (ङ.) ऐसे विनिमय अन्तर जो विदेशी मुद्रा के रूप में लिये गये उधारों से सम्बन्धित हैं और उन्हें ब्याज लागत के रूप में समायोजित करने के लिए माना जाता है।

6.(क) अनुच्छेद 6 (ङ) के अनुसरण में उधार लागतों के रूप में अपेक्षित विनिमय अंतर के संबंध में उसमें वर्णित समायोजनों का तरीका इस प्रकार होगा -

- (i) समायोजन उस राशि का होगा जो उस सीमा के समान है जिसमें विनिमय हानि कार्यात्मक मुद्रा में उधार लागत और विदेशी मुद्रा में उधार लागत के अंतर से अधिक नहीं होगी।
- (ii) जहां कहीं भी अप्राप्त विनिमय हानि होती है जो ब्याज के समायोजन के रूप में ली जाती है और बाद में उसी उधार के निपटान या रुपान्तरण के संबंध में प्राप्त या अप्राप्त लाभ होता है तो उस लाभ को पिछली बार मान्य हानि की सीमा तक समायोजन को ब्याज के रूप में मान्यता दी जाती है।

7. परिस्थितियों के अनुसार, निम्नलिखित में से कोई भी अर्हक आस्ति हो सकती है :-

- (क) सूचीबद्ध माल
- (ख) विनिर्माणकारी संयंत्र
- (ग) ऊर्जा उत्पादन सुविधाएं
- (घ) अमूर्त आस्तियाँ
- (ङ) निवेश संपत्तियाँ

वित्तीय आस्तियां और वह सूचीबद्ध माल जो कम समय में या तो निर्मित किये जाते हैं या उत्पादित किए जाते हैं, अर्हक आस्तियों की श्रेणी में नहीं आते हैं। इसी तरह, वे आस्तियां जब अर्जित या जो ग्रहण की जाती हैं और वांछित उपयोग या विक्रय के लिए तैयार होती हैं, वे भी अर्हक आस्तियां नहीं हैं।

मान्यता

8. एक प्रतिष्ठान उन उधार लागतों का पूंजीकरण करेगा जो अर्हक आस्ति के अधिग्रहण, निर्माण या उत्पादन से प्रत्यक्षतया व्यय हैं और आस्ति की लागत का एक भाग है। प्रतिष्ठान अन्य लागतों को कुल अवधि के व्यय के रूप में मान्यता देगा और उस अवधि के व्यय के रूप में करेगा जिसमें कि वे खर्च की गयी हैं।
9. उधार लागतें जो प्रत्यक्ष रूप से एक अर्हक आस्ति के ग्रहण या अर्जन, निर्माण या उत्पादन से सम्बन्धित हैं, इन लागतों को आस्ति की लागत के भाग के रूप में पूंजीकृत किया जाता है जब यह संभावना होती है कि वे प्रतिष्ठान के भावी आर्थिक लाभ हो सकते हैं और उनका ठीक-ठीक माप हो सकता है, उस आस्ति की लागत के अंतर्गत आती हैं। जब प्रतिष्ठान भारतीय लेखा मानक 29 उच्च मुद्रास्फीतिपूर्ण अर्थव्यवस्थाओं में रिपोर्टिंग करता है तो वह इस व्यय को उधार लागतों का अंश मानता है और इस मानक के अनुच्छेद 21 के अनुसरण में यह इस अवधि में मुद्रास्फीति की प्रतिपूर्ति करता है।

पूंजीकरण के लिए पात्र उधार की लागतें

10. उधार की लागतें, जो प्रत्यक्ष रूप से एक अर्हक आस्ति के अधिग्रहण, निर्माण या उत्पादन से सम्बन्धित हैं, उस स्थिति में बचाई जा सकती थी अगर उन्हें अर्हक आस्ति पर व्यय नहीं किया जाता। जब एक प्रतिष्ठान निधि को केवल एक विशिष्ट अर्हक आस्ति प्राप्त करने के लिए उधार के रूप में लेता है और ये उधार लागतें अर्हक आस्ति से प्रत्यक्ष रूप से सम्बन्धित हैं उन्हें आसानी से पहचाना जा सकता है।
11. कई बार यह जानना कठिन होता है कि विशिष्ट उधारों और एक अर्हक आस्ति के बीच प्रत्यक्ष रूप से क्या संबंध है और उस उधार का निर्धारण कैसे किया जाए जो परिहार्य हो यानि जिससे बचा जा सकता हो। उदाहरण के लिए ऐसी कठिनाई तब होती है जब प्रतिष्ठान की वित्तीय गतिविधियों का समन्वय केन्द्रीय रूप से होता है। कठिनाईयों तब भी होती हैं जब एक समूह उधार कि अनेक भिन्न-भिन्न व्याज दरों पर और ऋण के विभिन्न ऋण लिखतों का उपयोग करता है और अपने ही समूह के अन्य प्रतिष्ठानों को राशि उधार देता है। दूसरी जटिलताएं तब आती हैं जब उधार राशियां विदेशी मुद्रा में हो और समूह उच्च मुद्रास्फीतिपूर्ण अर्थव्यवस्थाओं और लोचपूर्ण विनिमय दरों में परिचालन करता है। परिणामस्वरूप, उन उधार लागतों का निर्धारण करना कठिन हो जाता है जो सीधे अर्हक आस्ति के अर्जन से सम्बद्ध हैं और इसके लिए अधिक विवेक की आवश्यकता होती है।
12. उस सीमा तक जब प्रतिष्ठान विशेष रूप से अर्हक आस्ति के अर्जन के लिए निधियां उधार लेता है, प्रतिष्ठान उन उधार लागतों की राशि का निर्धारण करेगा जो पूंजीकरण के लिए पात्र हैं। एक अवधि में वास्तव में उधार लागतों के रूप में खर्च की गयी राशि में से उधारों का अस्थायी निवेश से प्राप्त आय को घटा दिया जाता है।

13. एक प्रतिष्ठान एक अर्हक आस्ति पर कुल या समस्त निधियां खर्च करने से पूर्व, अर्हक आस्ति के वित्त पोषण के लिए राशियां उधार लेता है और संबद्ध उधार लागतों पर खर्च करता है। इन परिस्थितियों में, निधियों को जब तक अर्हक आस्ति पर खर्च न हों अस्थायी रूप से निवेश कर दी जाती है व इस अवधि के दौरान पूंजीकरण के लिए पात्र उधार लागतों की राशि का निर्धारण करने के लिए खर्च की गई लागतों में से निवेश से प्राप्त आय घटा दी जाती है।
14. एक प्रतिष्ठान आमतौर पर निधियां उधार लेकर अर्हक आस्ति की प्राप्ति के प्रयोजन के लिए जिस सीमा तक खर्च करता है, वह अर्हक आस्ति पर किये गये व्यय पर पूंजीकरण की दर लागू कर पूंजीकरण के लिए पात्र लागतों की राशि का निर्धारण करता है। पूंजीकरण की दर उधार लागतों की भारयुक्त औसत होगी जो अर्हक आस्ति के प्रयोजन से प्राप्त उधार राशि की बजाय प्रतिष्ठान की एक अवधि की बकाया उधार राशि पर लागू होगी। प्रतिष्ठान एक अवधि में जितनी उधार लागत का पूंजीकरण करता है वह उस राशि से अधिक नहीं होगी जोकि वह उस अवधि में खर्च करता है।
15. कुछ परिस्थितियों में, उधार की लागतों की भारयुक्त औसत की गणना करते समय यह उचित होगा कि मूल प्रतिष्ठान और उसके अनुषंगी प्रतिष्ठानों की उधार राशियों को इकट्ठा कर लिया जाए। अन्य परिस्थितियों में प्रत्येक अनुषंगी के लिए यह उचित होगा कि वह अपने उधारों पर लागू उधार लागतों की भारयुक्त औसत का प्रयोग करें।

अर्हक आस्ति की अग्रणीत राशि का वसूली योग्य राशि से आधिक्य

16. जब अर्हक आस्ति की अग्रणीत (कैरिंग) राशि या प्रत्याशित अंतिम लागत उसकी वसूली योग्य राशि से या निवल प्राप्य मूल्य से अधिक हो, तो अन्य भारतीय लेखा मानकों के अनुसरण में वहन राशि को अवलिखित या अपलिखित कर दिया जाता है। कुछ परिस्थितियों में अन्य भारतीय लेखा मानकों की अपेक्षाओं के अनुसरण में अवलिखित या अपलिखित राशि को प्रतिलिखित कर दिया जाता है।

पूंजीकरण का प्रारम्भ

17. एक प्रतिष्ठान अर्हक आस्ति की लागत के एक अंश के रूप में उधार की लागत का पूंजीकरण प्रारम्भ करेगा और प्रारम्भ की तारीख से पूंजीकरण की प्रारम्भिक तारीख वही होगी जिस पर प्रतिष्ठान प्रथम बार निम्नलिखित सभी शर्तों को पूरी करता है :
 - (क) वह आस्ति पर व्यय खर्च करता है ;
 - (ख) वह उधार की लागत खर्च करता है ; और
 - (ग) वह क्रियाकलाप करता है जो आस्ति को प्रत्याशित उपयोग या बिक्री के लिए तैयार करने में आवश्यक है।
18. अर्हक आस्ति पर व्यय में केवल वही खर्च शामिल होंगे जो कि नकद भुगतान, अन्य आस्तियों के अन्तरण या ब्याजयुक्त देयताओं के रूप में हैं। इस व्यय में से वह राशि घटा दी जाती है जो

प्रगति भुगतान या आस्ति के संबंध में अनुदान के रूप में प्राप्त हुई है। [देखिए भारतीय लेखा मानक 20 सरकारी अनुदान एवं सरकारी सहायता का प्रकटन] एक अवधि में औसत अग्रणीत राशि आमतौर पर उस व्यय राशि के करीब होगी जिस पर उस अवधि में पूंजीकरण की दर पर लगायी गयी है।

19. एक आस्ति को प्रत्याशित प्रयोग में लाने या बिक्री के लिए जो भी गतिविधियां या क्रियाकलाप आवश्यक हैं वे आस्ति के भौतिक निर्माण के अतिरिक्त हैं। इनमें निर्माण प्रारम्भ करने से पूर्व तकनीकी व प्रशासनिक कार्य शामिल हैं जैसे कि निर्माण से पूर्व कोई परमिट लेना। लेकिन, इन गतिविधियों में आस्ति की देखरेख जैसे कार्य शामिल नहीं हैं जब कोई निर्माण कार्य न हो रहा हो या आस्ति की स्थिति में कोई परिवर्तन न हो। उदाहरणार्थ, भूमि के विकास के लिए खर्च की गयी उधार लागतें उस समय पूंजीकृत की गयीं जब विकास-संबंधी गतिविधियां चल रही थी। लेकिन, जब भूमि भवन बनाने के लिए ग्रहण कर ली गई है और उसमें कोई विकास कार्य नहीं है तो वह पूंजीकरण के योग्य नहीं है।

पूंजीकरण का निलंबन

20. एक प्रतिष्ठान उधार लागतों का पूंजीकरण उस समय निलम्बित रखेगा जब बढ़ायी गयी अवधि में वह अर्हक आस्ति का सक्रिय विकास निलम्बित रखता है।
21. एक प्रतिष्ठान ऐसे समय में या ऐसी अवधि में उधार लागतें खर्च कर सकता है जिसमें वह आस्ति को प्रत्याशित उपयोग या बिक्री के लिए तैयार करने की आवश्यक गतिविधियों को स्थगित रखता है। ये गतिविधियां अंशतः पूर्ण आस्तियों की ग्रहण लागतें हैं और वे पूंजीकरण के योग्य नहीं हैं। लेकिन जब प्रतिष्ठान तकनीकी व प्रशासनिक कार्य विशेष रूप से कर रहा होता है तब वह उधार लागतों के पूंजीकरण को स्थगित नहीं करता। इसी तरह, जब आस्ति के प्रत्याशित उपभोग या बिक्री की प्रक्रिया अस्थायी रूप से देरी करना आवश्यक हो तो तब भी उधार लागतों का पूंजीकरण स्थगित नहीं होता। उदाहरणतया, एक पुल निर्माण का कार्य इस लिए विलम्बित करना पड़ रहा होता है कि उस दौरान भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से पानी भरने जैसे स्थितियाँ रहती हैं और निर्माण कार्य विलम्ब से चलता है।

पूंजीकरण की समाप्ति

22. एक प्रतिष्ठान उधार की लागतों का पूंजीकरण तब बन्द कर देता है जब वे क्रियाकलाप पूरे हो जाते हैं, जो अर्हक आस्ति का प्रत्याशित उपयोग या बिक्री की तैयारी के लिए किये जा रहे थे।
23. एक आस्ति साधारणतया अपने प्रत्याशित उपयोग या बिक्री के लिए तैयार समझी जाती है जबकि उसका भौतिक निर्माण कार्य खत्म हो चुका होता है भले ही कुछ कठोर प्रशासनिक काम चल रहे होते हैं। अगर मामूली संशोधन शेष है, जैसे कि खरीददार या उपभोगता की अपेक्षा के अनुसार संपत्ति की सजावट शेष है, यह प्रकट करता है कि मुख्य रूप से सारे क्रियाकलाप खत्म हो गये हैं।

24. एक प्रतिष्ठान अर्हक आस्ति का निर्माण विभिन्न चरणों या भागों में खत्म करता है। एक चरण अथवा भाग उपयोग के लिए उपयुक्त हो और दूसरे चरणों का निर्माण चल रहा हो प्रतिष्ठान उधार खर्च का पूंजीकरण रोक देगा जब उस भाग का उसके प्रत्याशित उपयोग या बिक्री के लिए तैयार करने के सारे क्रियाकलाप खत्म हो गये हों।
25. उपर्युक्त का सही उदाहरण एक कारोबार (बिजनेस) पार्क हो सकता है जिसमें कई भवन होते हैं। इसमें जो-जो भाग पूर्ण हो जाता है उसका उपयोग कर लिया जाता है जबकि शेष भाग निर्माणाधीन होते हैं। प्रतिष्ठान प्रत्येक भाग के मामले में उधार लागत का पूंजीकरण उस समय बन्द कर देता है जब वह भाग प्रत्याशित उपयोग या बिक्री के लिए तैयार हो जाता है। उदाहरण है एक औद्योगिक संपदा जिसमें कई प्रसंस्करण शामिल हैं और जो एक अनुक्रम में किए जाते हैं संपदा के विभिन्न भागों में, उसी स्थल पर किये जाते हैं, जैसे कि एक इस्पात मिल।

प्रकटन

26. एक प्रतिष्ठान निम्नलिखित को प्रकट करेगा :

- (क) अवधि के दौरान पूंजीकृत की गयी उधार की राशि ; तथा
- (ख) पूंजीकरण के लिए पात्र उधार लागतों की राशि के निर्धारण के लिए प्रयोग में लायी गई पूंजीकरण दर

परिशिष्ट 'क'

अन्य भारतीय लेखा मानकों में समाविष्ट मामलों के संदर्भ

यह परिशिष्ट भारतीय लेखा मानक 23 का एक अभिन्न अंग है।

1. भारतीय लेखा मानक 16 सम्पत्ति, संयंत्र एवं उपकरण में समाविष्ट परिशिष्ट 'क' [मौजूद विस्थापन, पुनर्बहाली एवं इसी तरह की देयताएँ] भी इस लेखामानक के लिए संदर्भ है।
2. भारतीय लेखा मानक 11 निर्माण संविदाएँ, में समाविष्ट परिशिष्ट 'क' (सेवा रियायत व्यवस्थाएँ) भी इस भारतीय लेखा मानक के लिए संदर्भ है।

परिशिष्ट 1

टिप्पणी - यह परिशिष्ट भारतीय लेखा मानक का अंग नहीं है। इस परिशिष्ट का प्रयोजन मात्र इतना है कि भारतीय लेखा मानक (इंड ए एस) 23 और तदनुरूपी अन्तरराष्ट्रीय लेखा मानक (आई ए एस) 23 उधार की लागतों के बीच यदि कोई अंतर है तो उन्हें स्पष्ट किया जाए।

अन्तरराष्ट्रीय लेखा मानक (आई ए एस) 23 उधार की लागतों के साथ तुलना

1. अन्तरराष्ट्रीय लेखा मानक (आई ए एस) 23 इस संबंध में कोई मार्गदर्शन नहीं देता है कि अनुच्छेद 6 (ड) में निर्धारित समायोजन का निर्धारण कैसे किया जाए। अनुच्छेद 6 'क' को भारतीय लेखा मानक 23 में इसी मार्गदर्शन के प्रयोजन से जोड़ा गया है।
2. अन्तरराष्ट्रीय लेखा मानक (आई ए एस) 23 में निम्नलिखित अनुच्छेद संख्याएं 'हटाया गया' के रूप में प्रदर्शित हैं। लेकिन, भारतीय लेखा मानक 23 में इन अनुच्छेद संख्याओं को इस आशय से रखा गया है ताकि अन्तरराष्ट्रीय लेखा मानक (आई ए एस) 23 की अनुच्छेद संख्याओं से क्रमबद्धता बनी रहे।

(i) अनुच्छेद 6 (क)

(ii) अनुच्छेद 6 (ख)

3. अन्तरराष्ट्रीय लेखा मानक (आई ए एस) 23 के संक्रमणकालीन प्रावधान भारतीय लेखा मानक (इंड ए एस) 23 में नहीं दिये गये हैं क्योंकि भारतीय लेखा मानकों से संबंधित सभी संक्रमणकालीन प्रावधान, जहां उचित समझा गया, आई एफ आर एस 1 अन्तरराष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग का प्रथमवार अंगीकरण मानकों के अनुरूप भारतीय लेखा मानक (इंड ए एस) 101 भारतीय लेखा मानकों का प्रथमवार अंगीकरण में समाविष्ट कर लिये गये हैं।

भारतीय लेखा मानक (इंड ए एस) 24

सम्बन्धित पक्ष के सम्बंध में प्रकटन

(इस भारतीय लेखा-मानक में मोटे टाइप व सामान्य टाइप में अनुच्छेद हैं। इन दोनों तरह के अनुच्छेदों का समान प्राधिकार है। मोटे टाइप में अनुच्छेद, मुख्य सिद्धान्तों के सूचक हैं।)

उद्देश्य:

1. इस मानक का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि प्रतिष्ठान के वित्तीय विवरणों में इस आशय का भी प्रकटन किया जाए कि संबंधित पक्षों (पार्टियों) के विद्यमान रहने के कारण इन पक्षों के लेनदेनों और बकाया शेषों के जिनमें किये गये वायदे भी सम्मिलित हैं, प्रभाव प्रतिष्ठान की वित्तीय स्थिति और लाभ और हानि पर पड़ सकते हैं।

कार्यक्षेत्र:

2. प्रस्तुत मानक निम्नलिखित मामलों में लागू किया जायेगा :-
- (क) संबंधित पक्ष के संबंधों और लेनदेनों की पहचान ;
 - (ख) प्रतिष्ठान और इससे संबंधित पक्षों के बीच वायदों सहित बकाया शेषों की पहचान ;
 - (ग) उन परिस्थितियों की पहचान जिनमें मद (क) और (ख) के तहत प्रकटन की आवश्यकता है ; एवं
 - (घ) उन मदों के बारे में किये गये प्रकटनों का निर्धारण।
3. यह मानक मूल प्रतिष्ठान, उद्यमी या निवेशक के संबंधित पक्ष के सम्बंधों, लेनदेनों व किये गये वायदों सहित बकाया शेषों के समेकित या पृथक वित्तीय विवरणों का प्रकटन भारतीय लेखा मानक 27 समेकित एवं पृथक वित्तीय विवरण के अनुसरण में अपेक्षा करता है। यह मानक व्यक्तिगत वित्तीय विवरणों पर भी लागू होता है।
4. एक समूह के अन्य प्रतिष्ठानों के साथ संबंधित पक्ष के लेनदेनों और बकाया शेष एक प्रतिष्ठान के वित्तीय विवरणों में प्रकट किये जायेंगे। पक्ष (पार्टी) के अंतरसमूह लेनदेनों और बकाया शेषों को समेकित विवरणों में समाप्त कर दिया जाता है।

- 4(क) प्रस्तुत मानक में निर्धारित सम्बंधित पक्ष के प्रकटन की अपेक्षाएं उन परिस्थितियों में लागू नहीं की जाएंगी जहां इस प्रकार का प्रकटन रिपोर्टिंग अथवा विचाराधीन प्रतिष्ठान के गोपनीयता-सम्बंधी उन कर्तव्यों के साथ अन्तर्विरोध रखता है जो किसी कानून, नियामक अथवा इसी प्रकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा विशेष रूप से अपेक्षित हैं।
- 4(ख) यदि किसी कानून, नियामक अथवा इसी प्रकार के सक्षम प्राधिकारी के द्वारा अधिशासित किसी प्रतिष्ठान को इस प्रकार की निषेधाज्ञा दी गयी है कि वह प्रतिष्ठान इस भारतीय लेखा मानक द्वारा अपेक्षित सूचनाओं को प्रकट न करे तो इस प्रकार की सूचना प्रकट नहीं की जाएगी। उदाहरण के लिए, बैंकों को कानून में अधिकार दिये गये हैं कि वे अपने ग्राहकों के लेनदेनों को गोपनीय रखें, अतः यह मानक ग्राहकों की गोपनीयता को प्रकट करने के बारे में कोई जोर नहीं देगा।

सम्बंधित पक्ष के संबंध में प्रकटन का प्रयोजन

5. पक्षों (पार्टियों) के आपसी संबंध किसी भी वाणिज्य अथवा व्यवसाय की सामान्य प्रक्रिया है। उदाहरण के लिए, प्रतिष्ठान कार्यों को अपनी अनुषंगी कम्पनियों, संयुक्त उद्यमों और सहायक कम्पनियों के साथ बार-बार आदान-प्रदान करते हैं। इन परिस्थितियों में, प्रतिष्ठान अपने नियंत्रण, संयुक्त नियंत्रण अथवा महत्वपूर्ण प्रभाव द्वारा निवेशिती की वित्तीय और परिचालन सम्बंधी गतिविधियों को प्रभावित करने में सक्षम हो जाता है।
6. सम्बंधित पक्षीय संबंध प्रतिष्ठान की वित्तीय स्थिति अथवा लाभ या हानि पर प्रभाव डाल सकते हैं। सम्बंधित पक्ष (पार्टियाँ) ऐसे लेनदेन कर सकते हैं जो असम्बंधित पक्षों के बीच नहीं होते। उदाहरण के लिये, एक प्रतिष्ठान अपनी वस्तुओं को अपने मूल प्रतिष्ठान को लागत पर बेचता है, उन शर्तों पर वह अन्य ग्राहकों को शायद न बेचें। इसके साथ-साथ सम्बंधित पक्षों के लेन-देन की राशियां असम्बंधित पक्षों जैसी नहीं हो सकती।
7. प्रतिष्ठान के लाभ या हानि और वित्तीय स्थिति सम्बंधित पक्ष के सम्बंध के कारण प्रभावित हो सकती है, बेशक इन दोनों के बीच कोई लेनदेन हुआ हो या नहीं भी। दोनों के बीच मात्र सम्बंध से ही प्रतिष्ठान व सम्बंधित पक्षों के बीच लेनदेन प्रभावित हो जाते हैं। उदाहरण के लिये, एक अनुषंगी प्रतिष्ठान अपने एक व्यापार सहभागी के साथ सम्बंध समाप्त कर सकता है इसलिए कि उसके मूल प्रतिष्ठान इसी प्रकार के व्यवसाय में एक सह-अनुषंगी को खरीद लिया है। इसके विपरीत, एक पक्ष इसलिए कार्य करने से हट जाता है कि दूसरा पक्ष अधिक प्रभावशील है। उदाहरणतया मूल प्रतिष्ठान जब अपनी अनुषंगी को यह निर्देश दे कि वह अनुसंधान व विकास कार्य न करे।
8. इन कारणों से, प्रतिष्ठान के लेनदेनों, बकाया शेषों, जिनमें वायदे भी सम्मिलित हैं, और सम्बंधित पक्षों (पार्टियों) के साथ संबंध की जानकारी, वित्तीय विवरणों के, जिनमें प्रतिष्ठान द्वारा सामना किये जा रहे जोखिमों व अवसरों का मूल्यांकन सम्मिलित है, उपयोगकर्ताओं के मूल्यांकनों को प्रभावित कर सकती है।

परिभाषाएं:

9. इस मानक में निम्नलिखित शब्दावली का प्रयोग यहां विनिर्दिष्ट अर्थों में किया गया है:

संबंधित पक्ष (या पार्टी) से आशय उस व्यक्ति अथवा प्रतिष्ठान से है, जो उस प्रतिष्ठान से जुड़ा है जो वित्तीय विवरणों को तैयार करता है, (प्रस्तुत मानक में इसे 'रिपोर्टिंग या विचाराधीन प्रतिष्ठान' कहा गया है)। इसमें निम्नलिखित सम्मिलित हैं :-

(क) एक व्यक्ति अथवा उस व्यक्ति के परिवार का नजदीकी सदस्य जो उस व्यक्ति के रिपोर्टिंग प्रतिष्ठान से जुड़ा हुआ है, और वह व्यक्ति -

- i. रिपोर्टिंग प्रतिष्ठान पर अकेले अथवा संयुक्त रूप से नियंत्रण रखता हो;
- ii. रिपोर्टिंग प्रतिष्ठान पर महत्वपूर्ण प्रभाव रखता हो;
- iii. रिपोर्टिंग प्रतिष्ठान अथवा उसके मूल प्रतिष्ठान के प्रबंधन का एक महत्वपूर्ण व्यक्ति हो।

(ख) एक प्रतिष्ठान रिपोर्टिंग प्रतिष्ठान से संबंधित है यदि निम्नलिखित में से कोई भी शर्त पूरी करता हो ;

- i. प्रतिष्ठान और रिपोर्टिंग प्रतिष्ठान एक ही समूह के सदस्य हों (इसका अर्थ है कि मूल प्रतिष्ठान, उसकी अनुषंगी तथा सम-अनुषंगी कम्पनी किसी दूसरे से संबंधित है)।
- ii. एक प्रतिष्ठान दूसरे प्रतिष्ठान का सहायक अथवा संयुक्त उद्यम हो (अथवा एक सहायक अथवा संयुक्त उद्यम उसी समूह के सदस्य हों, जिसका दूसरा प्रतिष्ठान सदस्य है)।
- iii. दोनों प्रतिष्ठान तीसरे पक्ष (पार्टी) के संयुक्त उद्यम हों;
- iv. एक प्रतिष्ठान तीसरे पक्ष का संयुक्त उद्यम है जबकि दूसरा प्रतिष्ठान तीसरे पक्ष का सहायक प्रतिष्ठान है ;
- v. प्रतिष्ठान उन कर्मचारियों की नियोजन पश्चात् लाभ योजना है जो रिपोर्टिंग प्रतिष्ठान या उससे संबंधित प्रतिष्ठान से सम्बंधित हों। यदि रिपोर्टिंग प्रतिष्ठान स्वयं ही ऐसी एक योजना हो तो नियोक्ताओं के प्रयोजक भी रिपोर्टिंग प्रतिष्ठान से संबंधित हैं।

- vi. प्रतिष्ठान पर मद सं. (क) में दिये गये किसी व्यक्ति का नियंत्रण अथवा संयुक्त नियंत्रण हों;
- vii. व्यक्ति जिसकी पहचान मद सं. (क) (i) के तहत की गई है, उसका प्रतिष्ठान के ऊपर महत्वपूर्ण प्रभाव हो, अथवा वह प्रतिष्ठान अथवा मूल प्रतिष्ठान के प्रमुख प्रबंध तंत्र के कर्मचारी - वर्ग का सदस्य हो।

सम्बंधित पक्ष का लेन-देन का तात्पर्य उन संसाधनों, सेवाओं और दायित्वों के अन्तरण से है जो रिपोर्टिंग प्रतिष्ठान और सम्बंधित पक्ष के बीच में होते हैं और चाहे उसके लिए कोई कीमत ली जाती हो या नहीं।

एक व्यक्ति के परिवार के निकट के सदस्य से आशय उन व्यक्तियों से है जो कि कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत 'संबंधी' है और उनमें उनके घरेलू पार्टनर, उनके घरेलू पार्टनर के बच्चे और उनके घरेलू पार्टनर के आश्रित भी सम्मिलित हैं।

क्षतिपूर्ति से तात्पर्य उन सभी कर्मचारी लाभों से है जो भारतीय लेखा मानक 19 कर्मचारी लाभ में यथा परिभाषित हैं और वे कर्मचारी लाभ जिन पर भारतीय लेखा मानक 102 शेयर आधारित भुगतान लागू होता है। उन सभी प्रकार के लाभों को कर्मचारी लाभ माना जायेगा जिनका भुगतान द्वारा किया गया है अथवा किया जाना है या जिनका प्रावधान किया गया है अथवा प्रतिष्ठान की ओर से ली गई सेवाओं के बदले में देय हों। इसमें वे भुगतान भी सम्मिलित हैं जो प्रतिष्ठान द्वारा मूल कम्पनी की ओर से किये गये हैं। क्षतिपूर्ति में निम्नलिखित शामिल हैं :--

- (क) वर्तमान कर्मचारियों को देय अल्प अवधि कर्मचारी लाभ, जैसे मजदूरी, वेतन और सामाजिक सुरक्षा अंशदान, वार्षिक छुट्टियों अथवा बीमारी की छुट्टियों का भुगतान, लाभ भाग और बोनस (यदि अवधि के 12 महीनों के अंदर देय हों) तथा गैर आर्थिक लाभ (जैसे चिकित्सा सुविधा, आवास, कार और निःशुल्क एवं रियायती मूल्य पर वस्तुयें तथा सेवायें);
- (ख) नियोजन पश्चात् लाभ जैसे पेंशन, सेवा निवृत्ति के उपरांत लाभ, सेवा निवृत्ति के उपरांत बीमा और सेवा निवृत्ति के उपरांत चिकित्सा सुविधा;
- (ग) अन्य दीर्घकालीन कर्मचारी लाभ, जैसे दीर्घकालीन अवकाश, विशेष प्रकार के अवकाश के लाभ जैसे अध्ययन या विश्राम अवकाश, दीर्घकालीन सेवा लाभ, दीर्घकालीन अपंगता लाभ और जो अवधि के अन्त से 12 माह की अवधि तक पूर्णतया देय नहीं हैं, लाभ भाग, बोनस तथा आस्थगिक क्षतिपूर्ति भुगतान शामिल।
- (घ) सेवा समाप्ति पर देय लाभ; और
- (ङ) शेयर आधारित भुगतान।

नियंत्रण से तात्पर्य प्रतिष्ठान की वित्तीय और परिचालन सम्बंधी नीतियों को अधिशासित करने की शक्ति ताकि उसकी गतिविधियों से लाभ प्राप्त किये जा सकें ।

संयुक्त नियंत्रण नियंत्रण के बंटवारे के लिए सहमतिप्राप्त संविदा है, जो प्रतिष्ठान की आर्थिक गतिविधियों पर होता है ।

प्रबंध-तंत्र के महत्वपूर्ण व्यक्ति वे व्यक्ति हैं जो प्रतिष्ठान के आयोजन, दिशा निर्धारण तथा नियंत्रण से संबंधित गतिविधियों में दखल रखते हों चाहे ये दखल प्रत्यक्ष रूप से हों अथवा अप्रत्यक्ष रूप से । इनमें प्रतिष्ठान के निदेशक (चाहे वे कार्यकारी हों अथवा अन्य) भी शामिल हैं ।

महत्वपूर्ण प्रभाव से आशय ऐसी शक्ति से है जो प्रतिष्ठान के वित्तीय और परिचालन से संबंधित कार्यों के नीतिपरक निर्णयों में निहित होती है, किन्तु वह उन नीतियों पर नियंत्रण न रखती हो । महत्वपूर्ण प्रभाव, शेयरों के स्वामित्व, कानून अथवा किसी प्रकार के करार के तहत हासिल किया जा सकता है ।

सरकार से तात्पर्य सरकार, सरकारी एजेंसियों और ऐसे निकायों से है, चाहे वे स्थानीय, राष्ट्रीय अथवा अंतर्राष्ट्रीय क्यों न हों ।

सरकार से संबंधित प्रतिष्ठान वह प्रतिष्ठान है जो कि या तो सरकार द्वारा नियंत्रित है अथवा संयुक्त रूप से नियंत्रित है या फिर जिस पर महत्वपूर्ण सरकारी प्रभाव हो ।

10. प्रत्येक पक्ष-सम्बंधी संभावित सम्बंध का विचार करते समय संबंध सार पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है न कि मात्र उसके विधिक (कानूनी) स्वरूप पर ।
11. इस मानक के संदर्भ में, निम्नलिखित पक्ष, संबंधित पक्ष (पार्टियां) नहीं हैं :
 - (क) कोई दो प्रतिष्ठान मात्र इतना चूंकि उनका निदेशक एक ही व्यक्ति है अथवा दोनों प्रतिष्ठानों के प्रबंधतंत्र में महत्वपूर्ण सदस्य सामान्य है या चूंकि एक प्रतिष्ठान का ऐसा कोई एक सदस्य दूसरे प्रतिष्ठान में महत्वपूर्ण प्रभाव रखता हो ;
 - (ख) कोई दो उद्यमी केवल इस कारण से कि उनका संयुक्त उद्यम में साझा नियंत्रण, है ;
 - (ग)
 - (i) वित्त प्रदाता;
 - (ii) ट्रेड यूनियन;
 - (iii) जन उपयोगी संस्थान; और
 - (iv) सरकारी विभाग और एजेंसियां जिनका रिपोर्टिंग प्रतिष्ठान पर कोई नियंत्रण, संयुक्त नियंत्रण अथवा कोई महत्वपूर्ण प्रभाव न हो;

उनका प्रतिष्ठान के साथ सम्बंध मात्र लेन-देन की सामान्य प्रक्रिया से है (भले ही वे प्रतिष्ठान की कार्य स्वतंत्रता को प्रभावित करे अथवा किसी निर्णय लेने संबंधित प्रक्रिया में सम्मिलित हों) ।

(घ) कोई ग्राहक, आपूर्तिकर्ता (सप्लायर), फ्रेंचाइजर, वितरक अथवा सामान्य एजेंसी, जिनके साथ प्रतिष्ठान का महत्वपूर्ण व्यवसाय होता है और इस तरह मात्र केवल कि उन पर प्रतिष्ठान की आर्थिक निर्भरता है;

12. संबंधित पक्ष (पार्टी) की परिभाषा में किसी सहायक प्रतिष्ठान में अनुषंगी प्रतिष्ठान और संयुक्त उद्यम में उसके अनुषंगी प्रतिष्ठान भी सम्मिलित हैं। अतः उदाहरणार्थ, एक सहायक प्रतिष्ठान का अनुषंगी प्रतिष्ठान और एक निवेशक जिसका सहायक प्रतिष्ठान में महत्वपूर्ण प्रभाव है, वे एक दूसरे से सम्बंधित हैं।

प्रकटन

सभी प्रतिष्ठान

13. मूल प्रतिष्ठान और उसकी अनुषंगी कम्पनियों के बीच के संबंधों का प्रकटन किया जायेगा, भले ही उनके बीच किसी भी प्रकार के लेन-देन होते हैं या नहीं । कोई प्रतिष्ठान अपने मूल प्रतिष्ठान और अपने अन्तिम नियंत्रक पक्ष (पार्टी), यदि अलग हैं, के नाम का प्रकटन करेगा। यदि मूल प्रतिष्ठान अथवा उसका अन्तिम नियंत्रक पक्ष समेकित वित्तीय विवरण जन-साधारण के उपयोग के लिए उपलब्ध नहीं करवाता तो वह उस वरिष्ठतम मूल प्रतिष्ठान का नाम प्रकट करेगा जो यह समेकित वित्तीय विवरण उपलब्ध करवाता है ।
14. किसी प्रतिष्ठान के वित्तीय विवरणों के उपयोगकर्ताओं को इस बात की जानकारी देने के लिये कि प्रतिष्ठान पर सम्बंधित पक्ष (पार्टी) के संबंध के क्या प्रभाव हैं, यह उपयुक्त होगा कि जब नियंत्रण मौजूद है तो सम्बंधित पक्ष के साथ सम्बंधों को प्रकट किया जाए बेशक उनके बीच किसी प्रकार के लेन देन होते हैं या नहीं । ऐसा इसलिये है कि मौजूद नियंत्रण संबंध के कारण रिपोर्टिंग प्रतिष्ठान को अपने वित्तीय एवं परिचालन सम्बंधी निर्णय स्वतंत्र रूप से लेने में रुकावट होती है । जहां नियंत्रण विद्यमान रहता है, संबंधित पक्ष (पार्टी) के नाम और सम्बंधित पक्ष (पार्टी) के स्वरूप का प्रकटन कभी कभी प्रतिष्ठान की भावी संभावनाओं के मूल्यांकन के लिए कम से कम उतना प्रासंगिक तो होता ही है, जितना कि वित्तीय विवरण में प्रस्तुत परिचालन सम्बंधी परिणाम व वित्तीय स्थिति होती है । इस प्रकार का सम्बंधित पक्ष (पार्टी) यह स्थापित करता है कि प्रतिष्ठान की साख की स्थिति (क्रेडिट स्टैंडिंग) क्या है, कच्चे माल के स्रोत व मूल्य का निर्धारण कैसे किया जाए और यह निर्धारित करना कि उत्पाद किन्हीं बेचा जाएगा और वह किस मूल्य पर बेचा जाएगा ।
15. मूल प्रतिष्ठान और उसकी अनुषंगी कम्पनियों के बीच सम्बंधित पक्ष सम्बंधों के प्रकटन की अपेक्षा भारतीय लेखा मानक 27 समेकित एवं पृथक वित्तीय विवरण भारतीय लेखा मानक 28

सहायक प्रतिष्ठानों में निवेश और भारतीय लेखा मानक 31 संयुक्त उद्यमों में हित की अपेक्षाओं के अतिरिक्त है।

16. अनुच्छेद 13 क्रम में अगले वरिष्ठतम मूल प्रतिष्ठान से सम्बंधित है। यह समूह के प्रथम मूल प्रतिष्ठान से ऊपर का मूल प्रतिष्ठान जो जन-साधारण के प्रयोग के लिये समेकित वित्तीय विवरण तैयार करता है।

17. प्रतिष्ठान महत्वपूर्ण प्रबंध कार्मिकों को देय समग्र और निम्नलिखित श्रेणियों की मदवार राशि का प्रकटन करेगा:

(क) अल्प अवधि कर्मचारी लाभ;

(ख) नियोजन पश्चात् लाभ;

(ग) अन्य दीर्घावधि लाभ

(घ) सेवा समाप्ति लाभ; और

(ङ) शेयर आधारित लाभ।

18. यदि किसी प्रतिष्ठान के वित्तीय विवरण प्रस्तुत किये जाने की अवधि के दौरान संबंधित पक्ष के साथ लेन-देन होते हैं तो प्रतिष्ठान के लिए यह आवश्यक होगा कि वह संबंधित पार्टी के साथ संबंधों के स्वरूप और उस सूचना को प्रकट करेगा जो हुए लेन देनों और बकाया शेषों जिनमें वायदे भी सम्मिलित हैं, से सम्बंधित हों। यह सूचना वित्तीय विवरणों के उपयोगकर्ताओं को यह जानने के लिए आवश्यक है कि इन विवरणों पर इन सम्बंधों का क्या संभावित प्रभाव होगा। प्रकटन की ये अपेक्षाएं अनुच्छेद 17 के तहत दी गयी अपेक्षाओं के अतिरिक्त हैं। इन प्रकटनों के तहत कम से कम निम्नलिखित मदों का विवरण प्रस्तुत किया जायेगा:

(क) लेनदेनों की राशि;

(ख) बकाया शेषों की राशि जिनमें किये गये वायदे भी सम्मिलित हैं; और

(i) उनकी शर्तें व निबंधन, साथ ही कि क्या वे सुरक्षित हैं और निपटान में प्रतिफल का स्वरूप क्या होगा;

(ii) दी गई अथवा ली गई किन्हीं गारंटीयों का विवरण;

(ग) बकाया शेष राशि से संबंधित संदिग्ध ऋणों के लिये किया गया प्रावधान; तथा

(घ) संदर्भित अवधि के दौरान, संबंधित पक्षों (पार्टियों) से प्राप्त अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के लिये मान्य प्राप्त व्यय।

19. अनुच्छेद 18 के तहत प्रकटन निम्नलिखित श्रेणियों की प्रत्येक मदों के लिए अलग अलग किए जाएंगे :

- (क) मूल प्रतिष्ठान;
- (ख) संयुक्त नियंत्रण वाले प्रतिष्ठान अथवा वे प्रतिष्ठान जिनका प्रतिष्ठान पर महत्वपूर्ण प्रभाव हो ;
- (ग) अनुषंगी प्रतिष्ठान ;
- (घ) सहायक प्रतिष्ठान ;
- (ङ) संयुक्त उद्यम जिनमें प्रतिष्ठान उद्यमी के रूप में हो ;
- (च) प्रतिष्ठान अथवा मूल प्रतिष्ठान के प्रबंध तंत्र के प्रमुख कार्मिक ; एवं
- (छ) अन्य संबंधित पक्ष ।

20. जहां तक तुलनपत्र या टिप्पणियों में प्रस्तुत की जाने वाली सूचना का सम्बंध है, अनुच्छेद 19 के तहत विभिन्न श्रेणियों से संबंधित पक्षों को देय अथवा उनसे प्राप्य राशियों का वर्गीकरण, भारतीय लेखा मानक 1 *वित्तीय विवरणों की प्रस्तुति* के तहत अपेक्षित प्रकटन की अपेक्षाओं के अतिरिक्त होगा । श्रेणियों को विस्तृत किया गया है ताकि संबंधित पक्ष के बकाया शेषों का व्यापक विश्लेषण प्राप्त हो सके और इसका प्रयोग संबंधित पक्ष के लेनदेनों के लिए किया जा सके ।

21. निम्नलिखित लेन-देन यदि संबंधित पक्ष के साथ होते हैं तो उनका प्रकटन किया जाएगा -

- (क) खरीदी गई अथवा बिक्री की गई वस्तुएं (तैयार अथवा निर्माणाधीन);
- (ख) खरीदी गई अथवा बिक्री की गई संपत्ति अथवा अन्य आस्तियां;
- (ग) सेवाओं का लिया जाना अथवा प्रदान किया जाना ;
- (घ) पट्टे ;
- (ङ) अनुसंधान और विकास का हस्तांतरण;
- (च) अनुज्ञा-अनुबंधों के अधीन हस्तांतरण;
- (छ) वित्तीय प्रबंधों के अंतर्गत हस्तांतरण (नकद अथवा अन्य प्रकार के ऋण और इक्विटी अंशदानों सहित)
- (ज) गारंटियों अथवा संपाक्षिकों के प्रावधान ;

- (झ) भविष्य में किसी विशेष किसी घटना के होने या न होने पर कुछ करने की वचनबद्धताएं जिनमें निष्पादित की जाने वाली संविदाएं¹ (मान्यता प्राप्त व अमान्य) भी शामिल हैं ;
- (ण) प्रतिष्ठान की ओर से अथवा प्रतिष्ठान के द्वारा संबंधित पाटी की ओर से देयताओं के किये गये निपटान; और
- (ट) प्रबंधन (मैनेजमेंट) से संबंधित संविदायें, जिनमें कर्मचारियों की प्रतिनियुक्ति भी शामिल है ।
22. परिभाषित लाभ योजना, जो समूह के बीच समूह प्रतिष्ठानों में जोखिमों का बंटवारा करती है, के तहत मूल प्रतिष्ठान अथवा अनुषंगी प्रतिष्ठान द्वारा की गई सहभागिता, जोकि संबंधित पक्षों के बीच एक लेनदेन है । [देखें भारतीय लेखा मानक 19 का अनुच्छेद 34 ख] ।
23. संबंधित पक्षों के लेन-देनों के प्रकटन उन्हीं शर्तों पर किये जाते हैं जो स्वतंत्र लेनदेनों के समान हों और यदि ये शर्तें पूरी हो सकती हों ।
24. एक ही प्रकार की मदों का प्रकटन समेकित रूप में किया जा सकता है, सिवाय इसके कि जब प्रतिष्ठान के वित्तीय विवरणों में संबंधित पक्ष के बीच हुए लेन-देनों के प्रभाव को समझने के लिए पृथक रूप में प्रकट करना आवश्यक हो ।
- 24क व्यक्तिगत संबंधित पक्षों के बीच हुए विशेष प्रकार के लेन-देनों का प्रकटन आमतौर पर अधिक विस्तार के कारण आसानी से समझ पाना संभव नहीं होता । इस प्रकार, एक प्रकार के संबंधित पक्षों की एक ही प्रकार की मदों का प्रकटन समेकित रूप में किया जा सकता है । फिर भी, ऐसा इस तरह से न हो कि मुख्य लेन-देनों का महत्व ही अस्पष्ट हो जाये। इस कारण से स्थिर आस्तियों की बिक्री अथवा खरीद को अन्य वस्तुओं की खरीद अथवा बिक्री के साथ समेकित रूप में न दर्शाया नहीं जाता । न ही किसी व्यक्तिगत पक्ष का किसी सम्बंधित पक्ष के लेन-देनों को समेकित करके दर्शाया जाए ।

सरकार से संबंधित प्रतिष्ठान :

25. किसी रिपोर्टिंग प्रतिष्ठान को संबंधित पक्ष के लेनदेनों और वायदों सहित बकाया शेषों के बारे में अनुच्छेद 18 के तहत अपेक्षित प्रकटन से छूट दी गई है :
- (क) सरकार जिसका रिपोर्टिंग प्रतिष्ठान पर नियंत्रण, संयुक्त नियंत्रण अथवा महत्वपूर्ण प्रभाव है;

¹भारतीय लेखा मानक 37 'प्रावधान, आकस्मिक देयताएं एवं आकस्मिक आस्तियां' निष्पादित की जाने वाली ऐसी संविदाओं को परिभाषित करता है जो ऐसी संविदायें हैं जहां दोनों में से किसी भी पक्ष ने अपने दायित्वों में से किसी भी दायित्व का निर्वहन नहीं किया है अथवा दोनों ने अपने दायित्वों को समान रूप से और आंशिक रूप निर्वहन किया है ।

(ख) कोई दूसरा प्रतिष्ठान, जो संबंधित पक्ष (पार्टी) है अगर प्रतिष्ठान व सम्बंधित पक्ष दोनों पर उसी सरकार का नियंत्रण, संयुक्त नियंत्रण अथवा महत्वपूर्ण प्रभाव हो।

26. यदि रिपोर्टिंग प्रतिष्ठान अनुच्छेद 25 के तहत दी गई छूट का प्रयोग करता है तो उसे अनुच्छेद 25 के तहत लेन-देनों और सम्बंधित बकाया शेषों के बारे में निम्नलिखित का प्रकटन करना होगा :

(क) सरकार का नाम और रिपोर्टिंग प्रतिष्ठान के साथ उसके संबंधों की प्रकृति (यानि नियंत्रण, संयुक्त नियंत्रण अथवा महत्वपूर्ण प्रभाव);

(ख) निम्नलिखित की पर्याप्त और विस्तृत रूप में जानकारी जिससे कि प्रतिष्ठान के वित्तीय विवरणों के उपयोगकर्ता इस बात का समझ सकें कि संबंधित पक्षों के लेन-देन का प्रतिष्ठान के वित्तीय विवरणों पर क्या प्रभाव पड़ा है :

(i) प्रत्येक महत्वपूर्ण लेन-देन का स्वरूप और राशि; और

(ii) अन्य लेनदेन जो व्यक्तिगत आधार पर न होकर सामूहिक आधार पर महत्वपूर्ण हों, उनकी गुणात्मक व परिमाणात्मक विशेषता का संकेत। इन लेन-देनों के प्रकार अनुच्छेद 21 में सूचीबद्ध किये गये हैं :

27. अनुच्छेद 26 (ख) में की गयी अपेक्षा के अनुसार किस स्तर तक प्रकटन किया जाए इसके निर्णय के विवेक के लिए रिपोर्टिंग प्रतिष्ठान सम्बंधित पक्ष के सम्बंध की समीपता और अन्य उन सम्बंधी तत्वों पर विचार करेगा कि लेनदेन को महत्व का स्तर क्या है और निम्नलिखित किस प्रकार से हैं : ---

(क) आकार के संबंध में महत्व;

(ख) गैर-विपणन शर्तों पर संचालन;

(ग) दिन-प्रतिदिन के सामान्य व्यवसायिक परिचालनों से हटकर, जैसे, व्यवसाय की खरीद और बिक्री;

(घ) विनियामक अथवा पर्यवेक्षी प्राधिकारियों को प्रकटन;

(ङ) वरिष्ठ प्रबंधकतंत्र को रिपोर्ट करना;

(च) शेयर धारकों की स्वीकृति के अधीन।

दृष्टांत उदाहरण

निम्नलिखित उदाहरण भारतीय लेखा मानक 24 संबंधित पक्ष के सम्बंध में प्रकटन के साथ संलग्न हैं लेकिन ये इसके अंग नहीं हैं ।

ये व्याख्या करते हैं : -

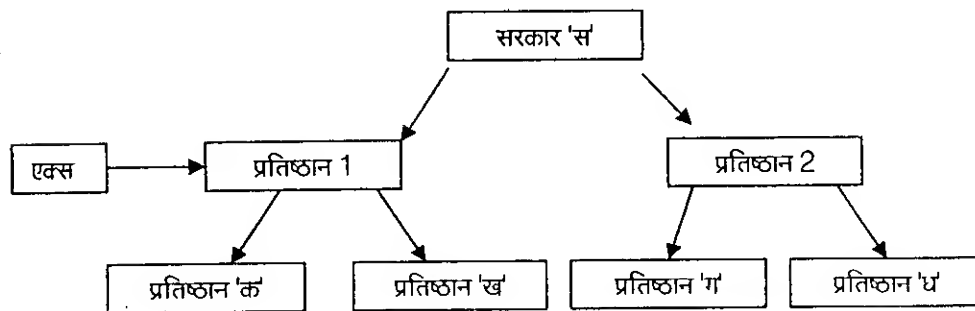
- सरकार से संबंधित प्रतिष्ठानों के मामलों में आंशिक छूट ; और
- विशेष परिस्थितियों में संबंधित पार्टी की परिभाषा को किस प्रकार लागू किया जायेगा ।

इन उदाहरणों में वित्तीय विवरणों का संदर्भ व्यक्तिगत, पृथक अथवा समेकित वित्तीय विवरणों से है ।

सरकार से संबंधित प्रतिष्ठानों के मामलों में आंशिक छूट

उदाहरण 1 - प्रकटन की छूट (अनुच्छेद 25)

दृष्टांत-1: सरकार 'स' प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से प्रतिष्ठान 1 और 2 और प्रतिष्ठान 'क', 'ख', 'ग' और 'घ' को नियंत्रित करती हैं । व्यक्ति 'एक्स' प्रतिष्ठान 1 के प्रबंधन का एक महत्वपूर्ण सदस्य है:



दृष्टांत-2: प्रतिष्ठान 'क' के वित्तीय विवरणों के लिये अनुच्छेद 25 में दी गई छूट लागू होगी :

- सरकार 'स' के साथ लेन-देन; और
- प्रतिष्ठान 1 और 2 तथा प्रतिष्ठान 'ख', 'ग' और 'घ' के साथ किये गये लेन-देन।

लेकिन व्यक्ति 'एक्स' के साथ किये गये लेन-देन के मामलों में यह छूट लागू नहीं होगी।

जिन मामलों में छूट लागू होती है उनके प्रकटन के सम्बंध में अपेक्षार्ये : (अनुच्छेद 26)

दृष्टांत-3: प्रतिष्ठान 'क' के वित्तीय विवरणों में अनुच्छेद 26 (ख)(i) का पालन किये जाने हेतु प्रकटन के उदाहरण, जो व्यक्तिगत रूप से महत्वपूर्ण लेन-देन के बारे में हो सकते हैं :

गैर-विपणन शर्तों के आधार पर संचालित व्यक्तिगत रूप से महत्वपूर्ण लेन-देन के प्रकटन का उदाहरण

15 जनवरी 20x1 को प्रतिष्ठान 'क' ने जिसमें सरकार 'स' की बकाया शेयरों के आधार पर अप्रत्यक्ष रूप में 75 प्रतिशत की हिस्सेदारी है, 50 लाख रु. में अपनी 10 हैक्टेयर भूमि सरकार से संबंधित एक-दूसरी जन-उपयोगी कम्पनी को बेच दी। 31 दिसम्बर, 20x0 को उसी स्थान पर स्थित एक प्लॉट जो उसी आकार का और ठीक उसी प्रकार का था, को 30 लाख रु. में बेचा गया। इस अवधि में भूमि के मूल्यों के बारे में कोई कमी अथवा वृद्धि नहीं हुई थी। भारतीय लेखा मानक 20 सरकारी अनुदान का लेखांकन एवं सरकारी सहायता के प्रकटन द्वारा अपेक्षित सरकारी सहायता का प्रकटन की टिप्पणी 'एक्स' (वित्तीय विवरणों की) और अन्य प्रासंगिक भारतीय लेखा मानकों के अनुपालन के लिये टिप्पणियां 'वाई' और 'जेड' टिप्पणियां (वित्तीय विवरणों की) देखें।

लेन-देन के आकार के कारण व्यक्तिगत रूप से महत्वपूर्ण लेन-देन के प्रकटन का उदाहरण:

दिसम्बर 2011 को समाप्त वर्ष में, सरकार 'स' द्वारा, प्रतिष्ठान 'क', जो एक जन-उपयोगी कम्पनी है, जिसमें सरकार 'स' की बकाया शेयरों के आधार पर अप्रत्यक्ष रूप से 75 प्रतिशत की भागीदारी है, ने व्यवस्था की है कि निधियों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए सरकारी 'स' द्वारा प्रतिष्ठान 'क' की आवश्यकता की पूर्ति के लिए 50 प्रतिशत के बराबर का ऋण दिया गया है, जिसे तिमाही किस्तों में आगामी 5 वर्षों की अवधि में चुकाया जाना है। इस ऋण पर 3 प्रतिशत की दर से ब्याज लिया जाएगा, जो तुलनात्मक दृष्टि से प्रतिष्ठान 'क' द्वारा बैंक से लिये गये ऋण* के ब्याज के बराबर है। अन्य प्रासंगिक भारतीय लेखा मानकों के अनुपालन के लिए टिप्पणी 'वाई' और 'जेड' (वित्तीय विवरण की) देखें।

सामूहिक रूप से महत्वपूर्ण लेन-देनों के प्रकटन का उदाहरण

अनुच्छेद 26 (ख)(ii) के अनुपालन में सामूहिक रूप से महत्वपूर्ण लेन-देनों के प्रकटन के बारे में प्रतिष्ठान 'क' के वित्तीय विवरणों का उदाहरण इस प्रकार हो सकता है :-

* यदि रिपोर्टिंग प्रतिष्ठान द्वारा यह निष्कर्ष निकाला गया है कि ये लेन-देन सरकारी सहायता के अन्तर्गत आते हैं तो इन पर भारतीय लेखा मानक 20 के तहत अपेक्षित प्रकटन पर विचार करना आवश्यक होगा।

सरकार 'स' अप्रत्यक्ष रूप में बकाया शेयरों के आधार पर प्रतिष्ठान 'क' के 75 प्रतिशत बकाया शेयर पर अपना स्वामित्व रखती है। प्रतिष्ठान 'क' के सरकार 'स' के साथ तथा अन्य उन प्रतिष्ठानों के साथ महत्वपूर्ण लेनदेन हैं जो सरकार 'स' द्वारा नियंत्रित, संयुक्त रूप से नियंत्रित अथवा महत्वपूर्ण प्रभाव में हैं। [कच्चे माल की बिक्री और खरीद का अधिकांश भाग] अथवा [वस्तुओं की बिक्री का लगभग 50 प्रतिशत और कच्ची माल की खरीद का लगभग 35 प्रतिशत]।

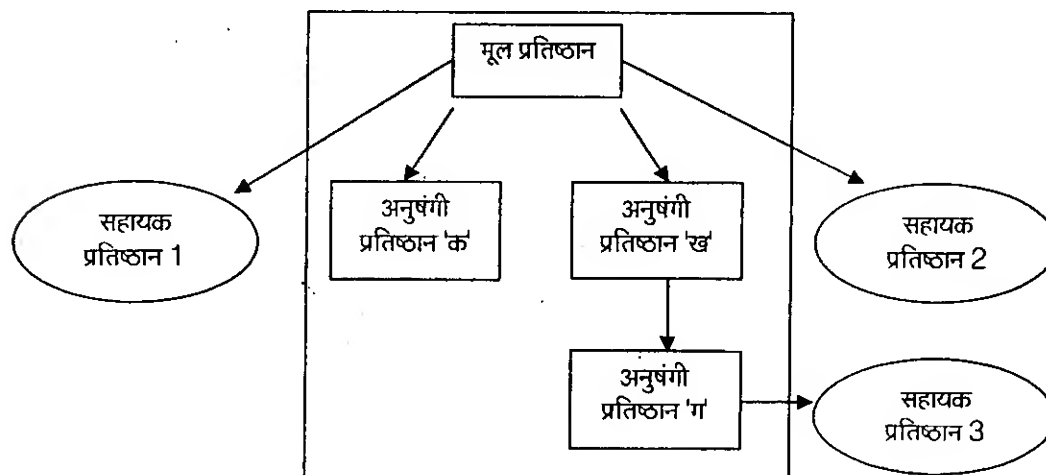
इसके साथ साथ, कम्पनी द्वारा बैंकों से जो ऋण लिये गये हैं उनके लिये उसे सरकार 'स' से गारंटी लाभ प्राप्त है। सरकारी सहायता के प्रकटन के लिए, भारतीय लेखा मानक 20 'सरकारी अनुदान का लेखांकन और सरकारी सहायता का प्रकटन' के अनुसार टिप्पणी (वित्तीय विवरण की) 'एक्स' और अन्य प्रासंगिक लेखा-मानकों के अनुसार टिप्पणी 'वाई' व 'जैड' (वित्तीय विवरणों की) देखें।

संबंधित पक्ष (पार्टी) की परिभाषा :

प्रस्तुत संदर्भ भारतीय लेखा मानक 24 के अनुच्छेद 9 में दी गई संबंधित पक्ष की परिभाषा के उप अनुच्छेद हैं।

उदाहरण 2 - सहायक और अनुषंगी प्रतिष्ठान :

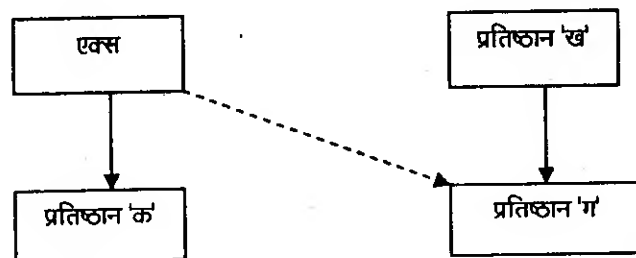
दृष्टांत-4: मूल प्रतिष्ठान का अनुषंगी प्रतिष्ठानों 'क' 'ख' और 'ग' पर नियंत्रण हित है और सहायक कम्पनी 1 और 2 पर महत्वपूर्ण प्रभाव है। अनुषंगी 'ग' का सहायक प्रतिष्ठान 3 पर महत्वपूर्ण प्रभाव है :



- दृष्टांत-5: मूल प्रतिष्ठान के पृथक वित्तीय विवरणों के लिए, अनुषंगी प्रतिष्ठान 'क', 'ख' और 'ग' तथा सहायक प्रतिष्ठान 1, 2 और 3 संबंधित पक्ष हैं। [अनुच्छेद 9 (ख) (i) और (ii)]
- दृष्टांत-6: अनुषंगी प्रतिष्ठान 'क' के वित्तीय विवरणों के लिए, मूल प्रतिष्ठान, अनुषंगी प्रतिष्ठान 'ख' और 'ग' तथा सहायक प्रतिष्ठान 1, 2 और 3 संबंधित पक्ष हैं। अनुषंगी प्रतिष्ठान 'ख' के पृथक वित्तीय विवरणों के लिए, मूल प्रतिष्ठान, अनुषंगी 'क' व 'ग' और और सहायक प्रतिष्ठान 1, 2 और 3 संबंधित पार्टियां हैं। अनुषंगी प्रतिष्ठान 'ग' के वित्तीय विवरणों के लिए मूल प्रतिष्ठान, अनुषंगी प्रतिष्ठान 'क' और 'ख' तथा सहायक प्रतिष्ठान 1, 2 और 3 संबंधित पार्टियां हैं। [अनुच्छेद 9 (ख) (i) - और (iii)]
- दृष्टांत-7: सहायक प्रतिष्ठान 1, 2 और 3 के वित्तीय विवरणों के लिए, मूल तथा अनुषंगी प्रतिष्ठान 'क', 'ख' और 'ग' संबंधित पक्ष (पार्टियां) हैं। सहायक प्रतिष्ठान 1, 2 और 3 एक दूसरे से संबंधित नहीं हैं [अनुच्छेद 9 (ख) (ii)]।
- दृष्टांत-8: मूल प्रतिष्ठान के समेकित वित्तीय विवरणों के लिए, सहायक प्रतिष्ठान 1, 2 और 3 समूह से संबंधित हैं। [अनुच्छेद 9 (ख) (ii)]।

उदाहरण 3 - प्रबंधक-तंत्र में महत्वपूर्ण कार्मिक

- दृष्टांत-9: एक व्यक्ति 'एक्स' का प्रतिष्ठान 'क' में 100 प्रतिशत निवेश है और वह व्यक्ति प्रतिष्ठान 'ग' के प्रबंधक-तंत्र में महत्वपूर्ण पद पर है। प्रतिष्ठान 'ख' का प्रतिष्ठान 'ग' में 100 प्रतिशत निवेश है।



- दृष्टांत-10: प्रतिष्ठान 'ग' वित्तीय विवरणों के लिये, प्रतिष्ठान 'क' प्रतिष्ठान 'ख' से संबंधित है क्योंकि व्यक्ति 'एक्स' का प्रतिष्ठान 'क' पर नियंत्रण है और वह प्रतिष्ठान 'ग' के प्रबंधक वर्ग का महत्वपूर्ण सदस्य है। [अनुच्छेद 9 (ख) (vi)-(क)(iii)]।
- दृष्टांत-11: प्रतिष्ठान 'ग' के वित्तीय विवरणों के लिये, प्रतिष्ठान 'क' प्रतिष्ठान 'ग' से भी संबंधित है, यदि व्यक्ति 'एक्स' प्रतिष्ठान 'ख' के प्रबंधक तंत्र में महत्वपूर्ण पद पर है और न कि प्रतिष्ठान 'ग' के प्रबंधक तंत्र में। [अनुच्छेद 9 (ख) (vi)-(क)(iii)]।

दृष्टांत-12: पुनः अनुच्छेद दृष्टांत 10 और दृष्टांत -11 के परिणाम एक समान होंगे, यदि व्यक्ति 'एक्स' का प्रतिष्ठान 'क' पर संयुक्त नियंत्रण हो। [अनुच्छेद 9 (ख) (vi)-(क)(iii)]।

दृष्टांत-12 क: अनुच्छेद 10 और 11 में दर्शाये गये परिणाम भिन्न होंगे, यदि व्यक्ति 'एक्स' का प्रतिष्ठान 'क' पर केवल महत्वपूर्ण प्रभाव हो और न कि नियंत्रण अथवा संयुक्त नियंत्रण। इस प्रकार प्रतिष्ठान 'क' और 'ग' एक दूसरे से संबंधित नहीं माने जायेंगे।

दृष्टांत-13: प्रतिष्ठान 'क' वित्तीय विवरण के लिये, प्रतिष्ठान 'ग' का संबंध प्रतिष्ठान 'क' से है क्योंकि व्यक्ति 'एक्स' का नियंत्रण प्रतिष्ठान 'क' पर है और वह प्रतिष्ठान 'ग' के प्रबंधक तंत्र का महत्वपूर्ण सदस्य है। [अनुच्छेद 9 (ख) (vii)-(क) (i)]।

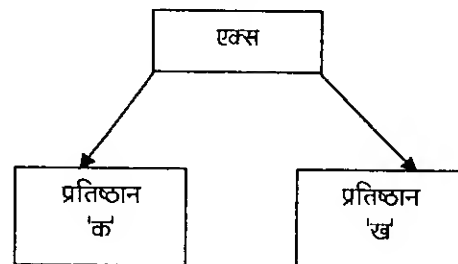
दृष्टांत-14: पुनः अनुच्छेद दृष्टांत 13 में दिया गया परिणाम वही होगा, यदि व्यक्ति 'एक्स' का प्रतिष्ठान 'क' पर संयुक्त नियंत्रण है।

दृष्टांत-14क: अनुच्छेद दृष्टांत 13 में दिये गये परिणाम भी वही होंगे यदि व्यक्ति 'एक्स' प्रतिष्ठान 'ख' के प्रबंधक तंत्र का महत्वपूर्ण सदस्य हो और न कि प्रतिष्ठान 'ग' का। [अनुच्छेद 9 (ख) (vii)-(क) (i)]।

दृष्टांत 15 प्रतिष्ठान 'ख' की समेकित वित्तीय विवरणियों के लिये, प्रतिष्ठान 'क' को समूह की संबंधित पक्ष समझा जायेगा, यदि व्यक्ति 'एक्स' समूह के प्रबंधक तंत्र का महत्वपूर्ण सदस्य हो। [अनुच्छेद 9 (ख) (vi)-(क) (iii)]।

उदाहरण 4 - व्यक्ति निवेशक के रूप में:

दृष्टांत 16 एक व्यक्ति 'एक्स' का प्रतिष्ठान 'क' और 'ख' में निवेश है।



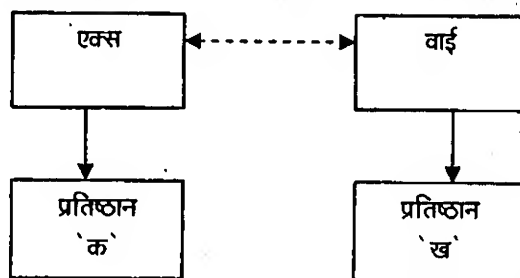
दृष्टांत 17: प्रतिष्ठान 'क' की वित्तीय विवरणियों के लिये, यदि व्यक्ति 'एक्स' का नियंत्रण अथवा संयुक्त नियंत्रण प्रतिष्ठान 'क' पर हो, तो प्रतिष्ठान 'ख' प्रतिष्ठान 'क' से संबंधित है, जब प्रतिष्ठान 'ख' पर व्यक्ति 'एक्स' का नियंत्रण, संयुक्त नियंत्रण अथवा महत्वपूर्ण प्रभाव हो। [अनुच्छेद 9 (ख) (vi)-(क)(i) तथा 9 (ख) (vii)-(क)(ii)]।

दृष्टांत 18: प्रतिष्ठान 'ख' की वित्तीय विवरणियों के लिये, यदि व्यक्ति 'एक्स' का नियंत्रण अथवा संयुक्त नियंत्रण प्रतिष्ठान 'क' पर हो, तो प्रतिष्ठान 'क' प्रतिष्ठान 'ख' से संबंधित है, जब कि व्यक्ति 'एक्स' का नियंत्रण, संयुक्त नियंत्रण अथवा महत्वपूर्ण प्रभाव प्रतिष्ठान 'ख' हो। [अनुच्छेद 9 (ख) (vi)-(क)(i) और अनुच्छेद 9 (ख) (vi)-(क)(ii)]।

दृष्टांत-19: यदि व्यक्ति 'एक्स' का महत्वपूर्ण प्रभाव प्रतिष्ठान 'क' और प्रतिष्ठान 'ख' पर हो, तो प्रतिष्ठान 'क' तथा प्रतिष्ठान 'ख' का संबंध एक दूसरे से नहीं है।

उदाहरण 5 - परिवार के निकट के सदस्य, जिनका प्रतिष्ठान में निवेश हो:

दृष्टांत -20 एक व्यक्ति 'एक्स' जो कि व्यक्ति 'वाई' का घरेलू साझीदार है, व्यक्ति 'एक्स' का 'क' में निवेश है तथा व्यक्ति 'वाई' का प्रतिष्ठान 'ख' में निवेश है।



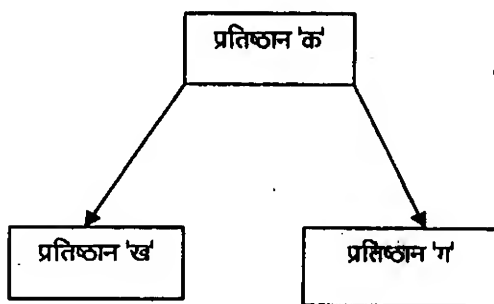
दृष्टांत-21: प्रतिष्ठान 'क' की वित्तीय विवरणियों के लिये, यदि 'एक्स' का प्रतिष्ठान 'क' पर नियंत्रण अथवा संयुक्त नियंत्रण हो तो प्रतिष्ठान 'ख' प्रतिष्ठान 'क' से संबंधित है जब 'वाई' का नियंत्रण, संयुक्त नियंत्रण या महत्वपूर्ण प्रभाव प्रतिष्ठान 'ख' पर है ; [अनुच्छेद 9 (ख) (vi)-(क)(i) और अनुच्छेद 9 (ख) (vii)-(क) (i)] ।

दृष्टांत-22: प्रतिष्ठान 'ख' के वित्तीय विवरणियों के लिये, यदि 'एक्स' का प्रतिष्ठान 'क' पर नियंत्रण अथवा संयुक्त नियंत्रण है, तो प्रतिष्ठान 'क' प्रतिष्ठान 'ख' से संबंधित है, जब 'वाई' का नियंत्रण, संयुक्त नियंत्रण अथवा महत्वपूर्ण प्रभाव प्रतिष्ठान 'ख' पर हो [(अनुच्छेद 9 (ख) (vi)-(क) (i) और अनुच्छेद 9 (ख) (vi)-(क) (ii)] ।

दृष्टांत-23: यदि व्यक्ति 'एक्स' का प्रतिष्ठान 'क' पर और व्यक्ति 'वाई' का प्रतिष्ठान 'ख' पर महत्वपूर्ण प्रभाव हो, तब प्रतिष्ठान 'क' और 'ख' एक दूसरे से संबंधित नहीं हैं ।

उदाहरण 6 - प्रतिष्ठान, जो कि संयुक्त नियंत्रण में हो:

दृष्टांत-24: प्रतिष्ठान 'क' का प्रतिष्ठान 'ख' पर संयुक्त नियंत्रण है और प्रतिष्ठान 'ग' पर संयुक्त नियंत्रण या महत्वपूर्ण प्रभाव है :



दृष्टांत-25: प्रतिष्ठान 'ख' के वित्तीय विवरणों के लिये, प्रतिष्ठान 'ग' प्रतिष्ठान 'ख' से संबंधित है [अनुच्छेद 9 (ख) (iii) और (iv)] ।

दृष्टांत-26: इसी प्रकार, प्रतिष्ठान 'ग' के वित्तीय विवरणों के लिये, प्रतिष्ठान 'ख' प्रतिष्ठान 'ग' से संबंधित है । [(अनुच्छेद 9 (ख) (iii) और (iv)] ।

परिशिष्ट 1

टिप्पणी - यह परिशिष्ट भारतीय लेखा मानक का अंग नहीं है। इस परिशिष्ट का प्रयोजन मात्र इतना है कि भारतीय लेखा मानक (इंड ए एस) 24 और तदनुरूपी अन्तरराष्ट्रीय लेखा मानक (आई ए एस) 24 संबंधित पार्टी के सम्बंध में प्रकटन के बीच यदि कोई अंतर हों तो उन्हें स्पष्ट किया जाए।

अन्तरराष्ट्रीय भारतीय लेखा मानक 24, संबंधित पार्टी के सम्बंध में प्रकटन के साथ तुलना:

1. भारतीय लेखा मानक 24 में प्रकटन, जो वैधानिक/नियामक गोपनीयता अपेक्षाओं के अन्तर्विरोधी है, उनका प्रकटन अपेक्षित नहीं है, क्योंकि भारतीय लेखा मानक किसी वैधानिक/नियामक अपेक्षाओं के प्रतिकूल नहीं जा सकता। (भारतीय लेखा मानक 24 के अनुच्छेद 4क और 4 ख)।
2. कंपनी अधिनियम में उल्लिखित 'संबंधी' जिस अर्थ में प्रयोग किया गया है, भारतीय लेखा मानक 24 में भी उसी अर्थ में **एक व्यक्ति के परिवार के निकटवर्ती सदस्य** की परिभाषा में सम्मिलित है।
3. भारतीय लेखा मानक 24 में अनुच्छेद 24 में 'क' जोड़ा गया है। यह प्रकटन लेनदेनों के जोड़ के संबंध में स्पष्टीकरण-संबंधी मार्गदर्शन देता है।
4. इस मानक में भिन्न शब्दावली का प्रयोग किया गया है, उदाहरणतया **वित्तीय स्थिति का विवरण** के स्थान पर शब्द **तुलन-पत्र** का प्रयोग किया गया है।

भारतीय लेखा मानक (इंड ए एस) 28

सहयोगी प्रतिष्ठानों (एसोसिएट्स) में निवेश

(इस भारतीय लेखा-मानक में मोटे टाइप व सामान्य टाइप में अनुच्छेद हैं। इन दोनों तरह के अनुच्छेदों का समान प्राधिकार है। मोटे टाइप में अनुच्छेद, मुख्य सिद्धान्तों के सूचक हैं।)

कार्य-क्षेत्र:

1. यह मानक सहयोगी प्रतिष्ठानों (एसोसिएट्स) में निवेशों के लेखा के लिए प्रयुक्त होगा। लेकिन यह निम्नलिखित द्वारा धारित सहयोगी प्रतिष्ठानों के निवेशों के लिए लागू नहीं होता:

(क) जोखिम पूर्ण पूंजीगत संगठन, या

(ख) [देखिये परिशिष्ट 1]

यह कि, प्रारंभिक मान्यता पर लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर नामोद्विष्ट किये जाते हैं या भारतीय लेखा मानक 39 **वित्तीय लिखतें : मान्यता एवं माप** के अनुसरण में व्यापार के लिए धारित हैं और लेखा के लिए वर्गीकृत हैं। ऐसे निवेशों का माप भारतीय लेखा मानक 39 के अनुसार परिवर्तन की अवधि में लाभ या हानि में मान्य प्राप्त उचित मूल्य में परिवर्तनों के साथ किया जाएगा। इस प्रकार के निवेश रखने वाले प्रतिष्ठान अनुच्छेद 37 (च) द्वारा अपेक्षित प्रकटन करेंगे।

परिभाषाएं:

2. इस मानक में निम्नलिखित शब्दावली का प्रयोग यहां विनिर्दिष्ट अर्थों में किया गया है :-

सहयोगी प्रतिष्ठान एक ऐसा प्रतिष्ठान है, जिसमें साझेदारी जैसा गैर निगमित प्रतिष्ठान सम्मिलित हैं जैसे कि साझेदारी फर्म, और जिस पर निवेशक का पर्याप्त प्रभाव रहता है। यह न तो अनुषंगी प्रतिष्ठान है और न ही ऐसा प्रतिष्ठान जिसका संयुक्त उद्यम में कोई हित है।

समेकित वित्तीय विवरण समूह के वे वित्तीय विवरण हैं जिन्हें एक आर्थिक प्रतिष्ठान की ओर से प्रस्तुत किया जाता हो।

नियंत्रण वह शक्ति है जिसके द्वारा एक प्रतिष्ठान की वित्तीय एवं परिचालन सम्बंधी नीतियां अधिशासित की जाती हैं और इसकी गतिविधियों से लाभ प्राप्त किये जाते हैं।

इक्विटी विधि वह लेखा विधि है जिसमें निवेश आरम्भ में लागत पर मान्य होता है और निवेशिती की निवल आस्तियों (परिसंपत्तियों) के निवेशक के शेयर में अधिग्रहण के पश्चात परिवर्तन के लिए समायोजित किया जाता है। निवेशक के लाभ या हानि में निवेशिती के लाभ या हानि में निवेशक का अंश (शेयर) शामिल है।

संयुक्त नियंत्रण आर्थिक गतिविधि पर संविदात्मक रूप से सम्मत नियंत्रण की भागीदारी है और यह केवल तभी अस्तित्व में होता है जब गतिविधि से संबंधित रणनीतिक वित्तीय तथा परिचालनकारी निर्णयों में उन पक्षों (पार्टियों) की सर्वसम्मति आवश्यक होती है जिनके बीच नियंत्रण संयुक्त रूप से बंटा होता है (इन्हें उद्यमी भी कहा जा सकता है)।

पृथक वित्तीय विवरण वे वे विवरण हैं जो मूल प्रतिष्ठान या सहयोगी प्रतिष्ठान में एक निवेशक द्वारा और संयुक्त रूप से नियंत्रित प्रतिष्ठान में एक उद्यमी द्वारा प्रस्तुत किये जाते हैं जिसमें निवेशों का लेखा प्रत्यक्ष 'इक्विटी' हित के आधार पर किया जाता है न कि निवेशितियों द्वारा रिपोर्ट किए गए परिणामों व निवल आस्तियों के आधार पर।

महत्वपूर्ण प्रभाव से अभिप्राय है निवेशितियों की वित्तीय तथा परिचालन सम्बंधी नीतिपरक निर्णयों में सहभागिता की शक्ति है लेकिन उन नीतियों पर नियंत्रण या संयुक्त नियंत्रण करना नहीं है।

अनुषंगी एक प्रतिष्ठान है, जिसमें साझेदारी जैसे गैर निगमित प्रतिष्ठान भी सम्मिलित हैं, जो दूसरे प्रतिष्ठान द्वारा नियंत्रित होता है (उस दूसरे प्रतिष्ठान को मूल प्रतिष्ठान कहते हैं।)

3. जिन वित्तीय विवरणों में 'इक्विटी' प्रणाली प्रयुक्त की जाती है वे पृथक वित्तीय विवरण नहीं हैं और न ही वे ऐसे किसी प्रतिष्ठान के वित्तीय विवरण हैं जिसकी कोई अनुषंगी या सहयोगी प्रतिष्ठान है या किसी संयुक्त उद्यम में उद्यमी (जोखिमकर्ता) का हित है।
4. पृथक वित्तीय विवरण वे विवरण हैं जो समेकित वित्तीय विवरणों के अलावा प्रस्तुत किये जाते हैं। ऐसे विवरणों में 'इक्विटी' प्रणाली का प्रयोग करते हुए निवेशों का लेखा किया जाता है और ये वे वित्तीय विवरण हैं जिनमें उद्यमियों (जोखिमकर्ताओं) का संयुक्त उद्यमों में हित आनुपातिक आधार पर समेकित किया जाता है। इन वित्तीय विवरणों के साथ, जब तक विधि द्वारा अपेक्षित न हो, पृथक वित्तीय विवरण संलग्न किये भी जाते हैं और नहीं भी।
5. [देखिये परिशिष्ट 1]

महत्वपूर्ण प्रभाव

6. यदि एक निवेशक, निवेशिती की वोट करने की शक्ति (वोटिंग पावर) का 20 प्रतिशत या उससे अधिक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष (अर्थात् अनुषंगियों के माध्यम से) शक्ति रखता है तो यह समझा जाता है कि उस प्रतिष्ठान में निवेशक का महत्वपूर्ण प्रभाव है जब तक यह स्पष्टतया नहीं बताया जाता कि मामला यह नहीं है। इसके विपरीत, यदि निवेशक निवेशिती की 'वोटिंग पावर' का 20 प्रतिशत से कम प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष (अर्थात् अनुषंगियों के माध्यम से) शक्ति रखता है तो यह समझा जाता है कि निवेशक का महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं है जब तक कि ऐसे प्रभाव को स्पष्टतया प्रदर्शित नहीं किया जा सकता हो। दूसरे निवेशक का जब प्रतिष्ठान में पर्याप्त या अधिकांश स्वामित्व हो तो उस निवेशक को महत्वपूर्ण प्रभाव से आवश्यक रूप से कोई बाधा नहीं होती।
7. एक निवेशक द्वारा महत्वपूर्ण प्रभाव का अस्तित्व सामान्यतया निम्नलिखित तरीकों में किसी एक या अधिक में देखा जा सकता है :
 - (क) निवेशिती के निदेशक मंडल या समकक्ष अधिशासी निकाय में प्रतिनिधित्व ;
 - (ख) लाभांशों या अन्य संवितरणों सहित नीति निर्माण प्रक्रियाओं में सहभागिता ;
 - (ग) निवेशक एवं निवेशिती के बीच सारवान (महत्वपूर्ण) लेनदेन ;
 - (घ) प्रबंधकीय कार्मिकों में फेरबदल
 - (ङ) अनिवार्य तकनीकी सूचना का प्रावधान
8. एक प्रतिष्ठान उन शेयर वारंटों, शेयर काल विकल्पों, ऋण या 'इक्विटी' लिखतों का स्वामित्व रख सकता है जिसे साधारण शेयरों¹ या इसी प्रकार की अन्य लिखतों में परिवर्तित किया जा सकता हो और उनके प्रयोग या परिवर्तन में ऐसी संभावना बनती है कि वे उस दूसरे प्रतिष्ठान के वित्तीय एवं परिचालन सम्बंधी नीतियों में प्रतिष्ठान को अतिरिक्त वोटिंग पावर देते हों या दूसरे पक्ष (पार्टी) की वोटिंग पावर (अर्थात् संभावित वोटिंग अधिकार) को कम किया जा सके। इससे यह पता चलता है कि प्रतिष्ठान में महत्वपूर्ण प्रभाव है या नहीं। संभावित वोटिंग अधिकार वर्तमान में प्रयोगयोग्य या परिवर्तनीय नहीं है जब तक उदाहरण के लिए, संभावित वोटिंग अधिकार भावी तिथि के आने से पूर्व या भावी घटना घटने से पूर्व प्रयोग में नहीं लाये जा सकते या परिवर्तित नहीं किये जा सकते।
9. यह मूल्यांकन करने के लिए कि क्या संभावित वोटिंग अधिकार महत्वपूर्ण प्रभाव में योगदान करते हैं या नहीं, प्रतिष्ठान उन सभी तथ्यों व परिस्थितियों (संभावित वोटिंग अधिकार के प्रयोग तथा कोई अन्य संविदात्मक व्यवस्थाओं सहित भले ही उन पर व्यक्तिगत रूप से या संयुक्त तौर पर विचार किया गया हो या नहीं) की जांच करता है जो प्रबंधन की मंशा तथा वित्तीय क्षमता को छोड़कर संभावित अधिकारों को प्रभावित करती है।
10. एक प्रतिष्ठान को किसी निवेशिती में तब महत्वपूर्ण प्रभाव की हानि होती है जब यह प्रतिष्ठान उस निवेशिती के वित्तीय एवं परिचालन सम्बंधी नीतिपरक निर्णयों में सहभागिता की शक्ति खो देता है। महत्वपूर्ण प्रभाव का खोना पूर्ण या सापेक्ष स्वामित्व स्तरों में परिवर्तन के साथ या उसके बिना घटित हो सकता है। उदाहरण के लिए, यह तब घटित हो सकता है जब एक सहयोगी प्रतिष्ठान (एसोसिएट) सरकार, न्यायालय, प्रशासक या विनियामक के नियंत्रण के अधीन हो जाता है। यह संविदात्मक समझौते के परिणामस्वरूप भी घटित हो सकता है।

¹ भारतीय संदर्भ में, 'साधारण शेयर, इक्विटी शेयर' के समान हैं।

'इक्विटी' विधि

11. 'इक्विटी' विधि के अंतर्गत, सहयोगी प्रतिष्ठान (एसोसिएट) में निवेश आरंभिक रूप से लागत पर मान्य होता है और अग्रणीत राशि अधिग्रहण की तारीख के बाद निवेशिती के लाभ या हानि के निवेशक के शेयर को मान्य करने के लिए बढ़ायी या घटायी जाती है। निवेशिती के लाभ या हानि के निवेशक का शेयर निवेशक का लाभ या हानि में मान्य होता है, निवेशिती से प्राप्त किए गए संवितरण निवेश की अग्रणीत राशि को कम करते हैं। अग्रणीत राशि के लिए समायोजनों को निवेशिती की अन्य व्यापक आय में परिवर्तनों से उद्भूत निवेशिती में निवेशक के आनुपातिक हित में परिवर्तनों के लिए भी आवश्यक हो सकते। ऐसे परिवर्तनों में संपत्ति, संयंत्र एवं उपस्कर के पुनर्मूल्यांकन से और विदेशी विनिमय रुपान्तरण अंतरों से उद्भूत भी शामिल हैं। उन परिवर्तनों में निवेशक का शेयर निवेशक की अन्य व्यापक आय में मान्य होता है [देखिये भारतीय लेखा मानक 1 वित्तीय विवरणों का प्रस्तुतीकरण]।
12. जब संभावित मताधिकार अस्तित्व में है तो निवेशिती के लाभ या हानि निवेशक का शेयर और निवेशिती की इक्विटी में परिवर्तनों को मौजूदा स्वामित्व हितों के आधार पर निर्धारित किया जाता है और संभावित वोटिंग अधिकारों के संभव प्रयोग या संपरिवर्तन को प्रतिबिंबित नहीं करता।

'इक्विटी' विधि का प्रयोग

13. एक सहयोगी प्रतिष्ठान (एसोसिएट) में निवेश का लेखांकन निम्नलिखित को छोड़ कर इक्विटी विधि के प्रयोग द्वारा किया जाएगा :
 - क) जब निवेश को भारतीय लेखा मानक 104 बिक्री के लिए धारित गैर चालू आस्तियां एवं बन्द परिचालन के अनुसार बिक्री के लिए धारण के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
 - ख) [देखिये परिशिष्ट 1]।
 - ग) [देखिये परिशिष्ट 1]।
14. अनुच्छेद 13 (क) में वर्णित निवेशों को भारतीय लेखा मानक 105 बिक्री के लिए धारित के रूप में गैर आस्तियां एवं बन्द परिचालन के अनुसार लेखा किया जाएगा।
15. जब किसी सहयोगी प्रतिष्ठान में निवेश जिसे पहले बिक्री के लिए धारण के रूप में वर्गीकृत किया गया था लेकिन वह अब इस मानदंड की पूर्ति न करता हो उसे बिक्री के लिए धारण के वर्गीकरण की तारीख से 'इक्विटी' प्रणाली का प्रयोग करने के लिए लेखांकित किया जाएगा। बिक्री के लिए रखे गए वर्गीकरण से अवधियों के लिए वित्तीय विवरणों को तदनुसार संशोधित किया जाएगा।
16. [देखिये परिशिष्ट 1]
17. प्राप्त किए गए संवितरणों के आधार पर आय की मान्यता सहयोगी प्रतिष्ठान में निवेश पर निवेशक द्वारा अर्जित आय का पर्याप्त आय नहीं हो सकती। चूंकि प्राप्त किए गए संवितरण का सहयोगी प्रतिष्ठान के कार्य-निष्पादन से थोड़ा संबंध हो सकता है। चूंकि निवेशक का सहयोगी प्रतिष्ठान पर महत्वपूर्ण प्रभाव होता है अतएव निवेशक को सहयोगी प्रतिष्ठान (एसोसिएट) के कार्य निष्पादन में रुचि होती है और जिसके परिणामतः इसके निवेश पर आय होती है। निवेशक ऐसे सहायक प्रतिष्ठान के लाभ या हानियों के इसके शेयर को शामिल करने के लिए इसके वित्तीय विवरणों की संभावना का विस्तार करते हुए इसका लेखा करता है। इसके परिणामतः,

इक्विटी प्रणाली के लागू करने से निवेशक की निवल आस्तियों तथा लाभ या हानि की और अधिक सूचनात्मक रिपोर्टिंग उपलब्ध होती है।

18. एक निवेशक इस तिथि से 'इक्विटी' विधि का प्रयोग बंद कर देगा, जब से उसका एक सहयोगी प्रतिष्ठान पर महत्वपूर्ण प्रभाव समाप्त हो जाता है और इस तिथि से भारतीय लेखा मानक 39 के अनुसार निवेश का लेखा किया जायेगा बशर्ते कि यह सहयोगी प्रतिष्ठान भारतीय लेखा मानक 31 में यथा परिभाषित अनुसार अनुषंगी या संयुक्त उद्यम नहीं बनता है। महत्वपूर्ण प्रभाव समाप्त हो जाने पर निवेशक पूर्ववर्ती सहयोगी प्रतिष्ठान में बना रहता है तो यह निवेशक किसी निवेश के उचित मूल्य पर माप कर सकेगा। निवेशक निम्नलिखित के बीच किसी लाभ या हानि के अंतर की मान्यता करेगा :
 - क) सहयोगी प्रतिष्ठान में किये गए निवेश का उचित मूल्य और उसमें (सहयोगी प्रतिष्ठान) में आंशिक हित का निपटान करने से प्राप्त हुई कोई आय
 - ख) जब महत्वपूर्ण प्रभाव समाप्त होता है तो उस तिथि से निवेश की अग्रणीत (कैरिंग) राशि
19. जब कोई निवेश सहयोगी प्रतिष्ठान के रूप में समाप्त हो जाता है और उसका लेखा, भारतीय लेखा मानक 39 के अनुसार किया जाता है तो उस तिथि से जिससे वह सहयोगी प्रतिष्ठान के रूप में समाप्त होता है उसमें निवेश का उचित मूल्य, भारतीय लेखा मानक 39 के अनुसार वित्तीय आस्तियों के रूप में आरंभिक मान्यता पर उसका उचित मूल्य माना जायेगा।
- 19क यदि कोई निवेशक किसी सहयोगी प्रतिष्ठान में महत्वपूर्ण प्रभाव खो देता है तो वह निवेशक उसी आधार पर उस सहयोगी प्रतिष्ठान के संबंध में अन्य व्यापक आय में मान्य सभी राशियों को हिसाब में लेगा, जिस पर यदि कोई सहयोगी प्रतिष्ठान संबंधित आस्तियों या देयताओं को सीधे ही निपटान करता तो उसकी अपेक्षा होती। यदि किसी सहयोगी प्रतिष्ठान द्वारा अन्य व्यापक आय में पूर्व में मान्य किये गए किसी लाभ या हानि को संबंधित आस्तियों या देयताओं के निपटान करने पर लाभ या हानि का पुनर्वर्गीकरण होगा। निवेशक इक्विटी से लाभ या हानि का पुनर्वर्गीकरण लाभ या हानि के रूप में (पुनर्वर्गीकरण समायोजन के रूप में) तब करता है जब वह सहयोगी प्रतिष्ठान पर महत्वपूर्ण प्रभाव खो देता है। उदाहरणार्थ, यदि कोई सहयोगी प्रतिष्ठान वित्तीय आस्तियों को बिक्री के लिए उपलब्ध करता है और निवेशक सहयोगी प्रतिष्ठान पर महत्वपूर्ण प्रभाव खो देता है तो वह निवेशक उन आस्तियों के संबंध में अन्य व्यापक आय में पूर्व में मान्य लाभ या हानि को लाभ या हानि के रूप में पुनर्वर्गीकृत करेगा। यदि किसी निवेशक का मालिकाना हित किसी सहयोगी प्रतिष्ठान में कम हो जाता है लेकिन वह निवेश सहयोगी प्रतिष्ठान के रूप में बना रहता है तो वह निवेशक अन्य व्यापक आय में पूर्व में मान्य लाभ या हानि की केवल आनुपातिक राशि को लाभ या हानि में पुनर्वर्गीकृत करेगा।
20. इक्विटी विधि के प्रयोग के लिए उपयुक्त बहुत-सी कार्य-विधियाँ, भारतीय लेखा मानक 27 में यथावर्णित समेकन कार्यविधियों के समान हैं। इसके अतिरिक्त, किसी अनुषंगी के अधिग्रहण के लिए लेखांकन में इस्तेमाल की गई कार्यविधियों में कोई संकल्पनाओं को महत्व दिया गया हो तो उसे सहयोगी प्रतिष्ठान में निवेश की प्राप्ति के लिए भी लेखा में लिया जाएगा।
21. किसी सहयोगी प्रतिष्ठान में किसी समूह का शेयर, उस सहयोगी प्रतिष्ठान में मूल और उसके अनुषंगी प्रतिष्ठान द्वारा होल्डिंग का समग्र होता है। समूह के अन्य सहायक या संयुक्त उद्यमों की होल्डिंग को इस प्रयोजन के लिए ध्यान में नहीं लिया जाता है। जब किसी सहयोगी प्रतिष्ठान की अनुषंगियाँ सहयोगी प्रतिष्ठान या संयुक्त उद्यम होती हैं तो लाभ या हानि और निवल आस्तियाँ, इक्विटी विधि के प्रयोग लेखा में ली गई वह होती जो सहयोगी प्रतिष्ठान के वित्तीय विवरणों में सहयोगी प्रतिष्ठान के लाभ या हानि के शेयर और उसके सहयोगी प्रतिष्ठान

(संयुक्त उद्यमों को निवल आस्तियों सहित) एक समान लेखा नीतियों (देखिये अनुच्छेद 26 और 27) को लागू करने के लिए आवश्यक किसी समायोजन के बाद मान्य की गई है।

22. किसी निवेशक (उसके समेकित अनुबंधियों सहित) और एक सहयोगी प्रतिष्ठान के बीच 'अपस्ट्रीम' और डाउन स्ट्रीम लेनदेनों के परिणामस्वरूप लाभ और हानि को निवेशक के वित्तीय विवरणों में केवल सहयोगी प्रतिष्ठान में निवेशक के हितों से असंबंधित सीमा तक मान्य किया जाता है। उदाहरणतया, 'अपस्ट्रीम' लेनदेन वे हैं जो सहायक प्रतिष्ठान से निवेशक को आस्तियों की बिक्री से किये जाते हैं और 'डाउन स्ट्रीम' लेनदेन इसके विपरीत हैं यानि निवेशक से सहयोगी प्रतिष्ठान के साथ किये जाते हैं।
23. सहयोगी प्रतिष्ठान में एक निवेश उस तारीख से इक्विटी विधि के प्रयोग के द्वारा लेखांकित किया जाता है जिस तारीख से प्रतिष्ठान एक सहयोगी प्रतिष्ठान बन जाता है। निवेश के प्राप्त होने पर निवेश की लागत और सहयोगी प्रतिष्ठान की विनिर्दिष्ट करने योग्य आस्तियों और देयताओं के निवल उचित मूल्य के निवेशक के शेयर के बीच किसी अंतर का निम्नानुसार लेखांकित किया जाएगा:-
 - क) किसी सहयोगी प्रतिष्ठान से संबंधित प्रतिष्ठा (गुडविल) के निवेशक की अग्रणीत राशि में शामिल किया जाता है। उस प्रतिष्ठा के परिशोधन की अनुमति नहीं दी जाती है।
 - ख) सहयोगी प्रतिष्ठान के निवेश की लागत से अधिक पहचान योग्य आस्तियों और देयताओं के निवल उचित मूल्य पर निवेशक के शेयर कोई आधिक्य उस अवधि में, जिसमें निवेश अधिगृहीत किया गया है, 'इक्विटी' में सीधे प्रारक्षित पूंजी के रूप में मान्य होती है।
24. सहयोगी प्रतिष्ठान की अत्यन्त वर्तमान में उपलब्ध वित्तीय विवरण क इस्तेमाल निवेशक द्वारा इक्विटी विधि को प्रयोग करने में किया जाता है। जब निवेशक की रिपोर्ट करने की अवधि की समाप्ति सहयोगी प्रतिष्ठान से भिन्न हो तो सहयोगी प्रतिष्ठान निवेशक के इस्तेमाल के लिए उसी तारीख की वित्तीय विवरणों को तैयार करता है जिस तारीख को निवेशक की वित्तीय विवरण होते हैं जब तक कि ऐसा करना अव्यवहार्य न हो।
25. जब अनुच्छेद 24 के अनुसार किसी सहयोगी प्रतिष्ठान के वित्तीय विवरणों, इक्विटी विधि के प्रयोग के लिए इस्तेमाल करते हुए, निवेशक की भिन्न तारीख को तैयार किया जाता है तो उनके समायोजनों को, उस तारीख से तथा निदेशक के वित्तीय विवरणों की तारीख के बीच उत्पन्न महत्वपूर्ण लेन-देनों या घटनाओं के प्रभावों के लिए किया जायेगा। किसी मामले में सहयोगी प्रतिष्ठान की रिपोर्टिंग अवधि के समाप्त होने और निवेशक की अवधि के बीच कोई अंतर तीन माह से अधिक नहीं होगा जब तक ऐसा करना अव्यवहार्य न हो। रिपोर्टिंग अवधि के समय और रिपोर्टिंग अवधियों की समाप्ति में कोई अंतर अवधि से अवधि तक के लिए एक समान होगा।
26. जब तक यह अव्यवहार्य न हो, एक ही प्रकार के लेनदेनों के लिए और एक ही प्रकार के हालात की घटनाओं के लिए निवेशक के वित्तीय विवरण का एक समान लेखा नीतियों का प्रयोग करते हुए तैयार किये जायेंगे, जैसे कि मिलती-जुलती परिस्थितियों में लेन-देन और घटनाएं।
27. यदि कोई निवेशक से भिन्न अन्य लेखा नीतियों को मिलती-जुलती परिस्थितियों में समान लेन-देनों और घटनाओं के लिए अपनाता है, समायोजनों को उन निवेशकों के सहयोगी प्रतिष्ठान की लेखा नीतियों के अनुसार किया जायेगा जब निवेशक द्वारा सहयोगी प्रतिष्ठान के वित्तीय विवरणों को इक्विटी विधि के प्रयोग करते हुए किया जाता है।

28. यदि कोई सहयोगी प्रतिष्ठान बकाया संचयी अधिमान्य शेयर रखता है जैसे कि निवेशक के अलावा अन्य पार्टियों के पास होते हैं और इक्विटी के रूप में वर्गीकृत की जाती है तो निवेशक, ऐसे शेयरों पर लाभांशों के लिए समायोजन के पश्चात लाभों या हानियों के उनके शेयर को गणना में लेता है चाहे लाभांशों को घोषित किया गया या नहीं ।
29. यदि किसी सहयोगी प्रतिष्ठान के निवेशक की हानियों का भाग सहयोगी प्रतिष्ठान में उसके हित के बराबर है या अधिक है तो निवेशक आगे की हानियों में उसके भाग को मान्यता नहीं देता है । एक सहयोगी प्रतिष्ठान में हित, कोई दीर्घावधि निवेशों सहित इक्विटी विधि के अन्तर्गत सहयोगी प्रतिष्ठान में निवेश की अग्रणीत राशि होती है जो सहयोगी प्रतिष्ठान में निवेशक के निवल निवेश के रूप में होती है । उदाहरणार्थ कोई मद, जिसके लिए निपटान न तो नियोजित है न ही भविष्य में सार रूप से उत्पन्न होने वाला है, उस सहयोगी प्रतिष्ठान में प्रतिष्ठान के निवेश का विस्तार है । ऐसी मदों में अधिमान्य शेयरों और दीर्घावधि प्राप्यों या भाग को शामिल किया जा सकता है लेकिन इसमें व्यापारिक प्राप्तियों, व्यापारिक देयों या किसी दीर्घावधि प्राप्यों, जिनके पर्याप्त संपादिक हैं, जैसे कि प्रतिभूत ऋणों को शामिल नहीं किया जाता है । साधारण शेयरों में निवेशक के निवेश से अधिक इक्विटी विधि के अन्तर्गत मान्य हानियों को एक सहयोगी प्रतिष्ठान में निवेशकों के हित के अन्य घटकों को उनकी वरिष्ठता के विपरीत क्रम में (अर्थात् परिसमापन में प्राथमिकता) इस्तेमाल किया जाता है ।
30. निवेशक का हित शून्य तक घट जाने के बाद अतिरिक्त हानियों की व्यवस्था की जाती है और देयताओं की पहचान केवल उस सीमा तक की जाती है जहाँ तक विधिक या रचनात्मक दायित्वों या यदि सहयोगी प्रतिष्ठान बाद में लाभ दर्शाता है तो निवेशक केवल उन लाभों के उनके शेयर को, मान्य न की गई हानियों के शेयर के बराबर लाभों के उनके शेयर के बाद मान्य करना पुनः आरम्भ कर देगा ।

क्षतिग्रस्त हानियाँ

31. इक्विटी विधि के लागू करने के पश्चात् जिसमें अनुच्छेद 29 के अनुसार सहयोगी प्रतिष्ठान की हानियों की पहचान भी शामिल हैं, निवेशक यह निश्चित करने के लिए कि क्या सहयोगी प्रतिष्ठान में निवेशक के निवल निवेश के बारे में किसी अतिरिक्त क्षतिग्रस्त हानि को मान्य करना आवश्यक है, भारतीय लेखा मानक 39 की अपेक्षाओं को लागू करता है ।
32. निवेशक इस बात को निश्चित करने के लिए कि क्या सहयोगी प्रतिष्ठान में निवेशक के हित के बारे में किसी अतिरिक्त क्षतिग्रस्त हानि को मान्य किया गया है जो कि निवल निवेश का गठित भाग नहीं है और राशि उस क्षतिग्रस्त हानि की है, भारतीय लेखा मानक 39 की अपेक्षाओं को लागू करता है ।
33. क्योंकि प्रतिष्ठा, किसी सहयोगी प्रतिष्ठान में एक निवेश की अग्रणीत राशि का भाग होती है अतः उसे अलग से मान्य नहीं किया जाता है उसे भारतीय लेखा मानक 36 में क्षतिग्रस्त जाँच प्रतिष्ठा के लिए अपेक्षाओं को लागू करने के लिए अलग से क्षतिग्रस्तता के लिए परीक्षण नहीं किया गया है । आस्तियों की क्षति इसके बजाय निवेश की समस्त अग्रणीत राशि को एक मात्र आस्ति के रूप में भारतीय लेखा मानक 36 के अनुसार क्षति के लिए जाँच की जाती है जो कि उसकी अग्रणीत राशि के साथ उसकी वसूली योग्य राशि (इस्तेमाल में उच्च मूल्य और बिक्री करने हेतु लागत घटाकर उचित मूल्य दोनों में जो भी ज्यादा हो) की तुलना करके की जाती है । जब कभी भारतीय लेखा मानक 39 में अपेक्षाओं को लागू करने से यह लगता है कि निवेश से हानि हो सकती है । ऐसी परिस्थितियों मान्य की गई क्षतिग्रस्त हानि किसी आस्ति में आबंटित नहीं की जाती है । जिसमें प्रतिष्ठा भी शामिल है जो कि सहयोगी प्रतिष्ठान में निवेश की अग्रणीत राशि का भाग होती है । तदनुसार उस क्षतिग्रस्त हानि की विपरीत स्थिति को भारतीय लेखा मानक 36 उस सीमा तक मान्य किया जाता है जहाँ तक निवेश की वसूली योग्य राशि की बाद

में वृद्धि होती है। निवेश के इस्तेमाल का मूल्य निर्धारित करने के लिए एक प्रतिष्ठान में निम्नलिखित को आकलित किया जाता है :-

- क) सहयोगी प्रतिष्ठान द्वारा उत्पन्न संभावित अनुमानित भावी नकदी प्रवाह के वर्तमान मूल्य का उसका शेयर, जिसमें सहयोगी प्रतिष्ठान के प्रचालनों से नकदी प्रवाह भी शामिल हैं और निवेश के अंतिम निपटान की आय भी शामिल है।
- ख) निवेश से और उसके अंतिम निपटान से प्राप्त होने वाले लाभों से उत्पन्न संभावित अनुमानित भावी नकदी प्रवाहों का वर्तमान मूल्य।

उपयुक्त मान्यताओं के अन्तर्गत, दोनों विधियों से एक समान परिणाम मिलते हैं।

34. एक सहयोगी प्रतिष्ठान में निवेश की वसूलीयोग्य राशि का निर्धारण प्रत्येक सहयोगी प्रतिष्ठान के लिए होता है, जब तक कि सहयोगी प्रतिष्ठान लगातार प्रयोग से नकदी प्रवाहों को उत्पन्न नहीं करता है जो कि प्रतिष्ठान की उन अन्य आस्तियों से प्रमुखतः स्वतंत्र होते हैं।

पृथक वित्तीय विवरण

35. एक सहयोगी प्रतिष्ठान में किसी निवेश की गणना, निवेशक की अलग वित्तीय विवरणों में भारतीय लेखा मानक 27 के अनुच्छेद 38-43 के अनुसार की जायेगी।
36. यह मानक यह घोषणा नहीं करता कि किन प्रतिष्ठानों को जनसाधारण के प्रयोग के लिए अलग वित्तीय विवरण तैयार करना अनिवार्य है।

प्रकटन

37. निम्नलिखित प्रकटन किए जाएंगे :

- क) सहयोगी प्रतिष्ठान में निवेशों का उचित मूल्य जिसके लिए प्रकाशित मूल्य कोटेशन हैं;
- ख) सहयोगी प्रतिष्ठानों की संक्षिप्त वित्तीय सूचना जिसमें आस्तियों, देयताओं, राजस्व एवं लाभ या हानि की कुल रकम शामिल हैं ;
- ग) वे कारण जिनसे यह पूर्वधारणा दूर होती है कि एक निवेशक का उन स्थिति में पूर्व-प्रभाव नहीं है जब वह (निवेशक) अनुषंगी प्रतिष्ठानों के माध्यम से निवेशिती की 20 प्रतिशत-से कम की मतशक्ति है अथवा संभावित मतशक्ति धारण करता है और यह निष्कर्ष निकालता है कि उसका महत्वपूर्ण प्रभाव है ;
- घ) वे कारण जिनसे यह पूर्वधारणा दूर होती है कि एक निवेशक का उस स्थिति में पूर्व-प्रभाव है जब वह (निवेशक) अनुषंगी प्रतिष्ठानों के माध्यम से निवेशिती का 20 प्रतिशत और अधिक का मतदान करता है अथवा संभावित मतशक्ति धारण करता है और यह निष्कर्ष निकालता है कि उसका महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं है ;
- ङ) सहयोगी प्रतिष्ठान की वित्तीय विवरणों की रिपोर्टिंग अवधि के अंत में जब ऐसे वित्तीय विवरणों को इक्विटी विधि को लागू करने में प्रयुक्त किया जाता है और उस

तारीख या उस अवधि के लिए होता है जो निवेशक से भिन्न होती है और भिन्न तारीख या भिन्न अवधि के प्रयोग के कारण है ;

- च) नकद लाभांशों या ऋणों या अग्रिमों का पुनर्भुगतान के रूप में निवेशक को निधियों के अंतरण के लिए सहयोगी प्रतिष्ठान की योग्यता पर किसी महत्वपूर्ण प्रतिबंधों (अर्थात् ऋण प्रबंधों या विनियमनकारी अपेक्षाओं से उद्भूत) की प्रकृति तथा सीमा ;
- छ) सहयोगी प्रतिष्ठान की हानियों का अवधि तथा संचयी दोनों रूप से गैर मान्य शेयर, यदि निवेशक ने सहयोगी प्रतिष्ठान की हानियों के अपने शेयर की मान्यता को समाप्त कर दिया है ;
- ज) यह तथ्य कि सहयोगी प्रतिष्ठान को अनुच्छेद 13 के अनुसार इक्विटी विधि के प्रयोग द्वारा लेखा नहीं किया गया है ; और
- झ) सहयोगी प्रतिष्ठान की अलग अलग या समूह में संक्षिप्त वित्तीय सूचना जिसे कुल आस्तियों, कुल देयताओं, राजस्व एवं लाभ या हानि सहित इक्विटी विधि के प्रयोग द्वारा लेखा नहीं किया गया है ।

38. इक्विटी विधि का प्रयोग करते हुए सहयोगी प्रतिष्ठान में निवेशों को गैर चालू आस्तियों के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा । ऐसे सहयोगी प्रतिष्ठान के लाभ या हानि का निवेशक का शेयर तथा उन निवेशों की अग्रणीत राशि को अलग से प्रकट किया जाएगा । ऐसे सहयोगी प्रतिष्ठान के किसी समाप्त परिचालनों का निवेशक का शेयर अलग से भी प्रकट किया जाएगा ।

39. सहयोगी प्रतिष्ठान द्वारा अन्य संपूर्ण आय में मान्य परिवर्तनों का निवेशक का शेयर अन्य संपूर्ण आय में निवेशक द्वारा मान्य होगा ।

40. भारतीय लेखा मानक 37, प्रावधान, आकस्मिक देयताएं तथा आकस्मिक आस्तियां के अनुसार निवेशक निम्नलिखित को प्रकट करेगा :

- क) अन्य निवेशकों के साथ संयुक्त रूप से अपने ऊपर ली गई सहयोगी प्रतिष्ठान की आकस्मिक देयताओं में इसका शेयर ; और
- ख) वे आकस्मिक देयताएं जो इस कारण उद्भूत होती हैं चूंकि निवेशक अलग से सहयोगी प्रतिष्ठान की सभी देयताओं या हिस्से के लिए उत्तरदायी होगा ।

परिशिष्ट 'क'

अन्य भारतीय लेखा मानकों में समाविष्ट मामलों के संदर्भ

यह परिशिष्ट भारतीय लेखा मानक 28 का अभिन्न अंग है ।

1. भारतीय लेखा मानक 37, प्रावधान, आकस्मिक देयताएं तथा आकस्मिक आस्तियां में समाविष्ट विस्थापन, पुनर्बहाली एवं पर्यावरण सम्बंधी पुनर्वास निधियों से उत्पन्न हितों के अधिकार परिशिष्ट 'क' इस लेखा मानक को संदर्भित करता है ।

परिशिष्ट 1

टिप्पणी - यह परिशिष्ट भारतीय लेखा मानक का अंग नहीं है। इस परिशिष्ट का प्रयोजन मात्र इतना है कि भारतीय लेखा मानक (इंड ए एस) 28 और तदनुरूपी अन्तरराष्ट्रीय लेखा मानक (आई ए एस) 28 सहयोगी प्रतिष्ठानों (एसोशिएट्स) में निवेश के बीच यदि कोई अंतर हो तो उन्हें स्पष्ट किया जाए।

अन्तरराष्ट्रीय लेखा मानक (आई ए एस) 28 सहयोगी प्रतिष्ठानों (एसोशिएट्स) में निवेश के साथ तुलना

1. जहां एक सहयोगी प्रतिष्ठान (एसोशिएट) के वित्तीय विवरण इक्विटी विधि का प्रयोग करते हुए उस तिथि के तैयार किये जाते हैं जो निवेशक की तिथि के वित्तीय विवरण की तिथि से भिन्न है, अन्तरराष्ट्रीय लेखा मानक (आई ए एस) 28 यह अपेक्षा करता है कि यह अंतर 3 माह से अधिक नहीं होना चाहिए। लेकिन, भारतीय लेखा मानक 28 का अनुच्छेद 25 यह व्यवस्था देता है जब तक यह अव्यवहार्य न हो तब तक यह अंतर 3 माह से अधिक नहीं होना चाहिए। इसी तरह, भारतीय लेखा मानक 28 का अनुच्छेद 26 यह अपेक्षा करता है कि जब तक यह अव्यवहार्य न हो एक-जैसी लेखा नीतियों का ही प्रयोग किया जाएगा, जिसकी अन्तरराष्ट्रीय लेखा मानक 28 में कोई व्यवस्था नहीं है। ये परिवर्तन कर दिये गये हैं क्योंकि निवेशक का सहयोगी प्रतिष्ठान (एसोशिएट) पर नियंत्रण नहीं होता है। यह सहयोगी प्रतिष्ठान पर यह प्रभाव नहीं डाल सकता कि वह अतिरिक्त वित्तीय विवरण तैयार करे अथवा उन लेखा नीतियों का अनुसरण करे जिनका कि वह (निवेशक) पालन करता है।
2. अन्तरराष्ट्रीय लेखा मानक (आई ए एस) 28 का अनुच्छेद 1 (ख) भारतीय लेखा मानक (इंड ए एस) 28 से हटा दिया गया है क्योंकि कंपनी अधिनियम 1956 म्यूचल फंडों, यूनिट ट्रस्टों और निवेश संबद्ध बीमा निधियों (फंडों) सहित इसी प्रकार के प्रतिष्ठानों पर लागू नहीं होता और इस तरह यह मानक भी इन प्रतिष्ठानों पर लागू नहीं होगा। लेकिन, भारतीय लेखा मानक 28 में अनुच्छेद संख्या 1 (ख) को इस आशय से रखा गया है ताकि अन्तरराष्ट्रीय लेखा मानक (आई ए एस) 28 के साथ अनुच्छेद संख्याओं से क्रमबद्धता बनी रहे।
3. अनुच्छेद संख्या 5, 13 (ख) और 13 (ग) को इस आशय से हटा दिया गया है क्योंकि भारतीय लेखा मानकों की प्रयोज्यता अथवा छूट कंपनी अधिनियम और उसके अधीन बनाए गये नियमों द्वारा अधिशासित होती है। लेकिन, अनुच्छेद संख्याओं को भारतीय लेखा मानक 28 में इसे प्रयोजन से रखा गया है ताकि उस भारतीय लेखा मानक की अन्तरराष्ट्रीय लेखा मानक के साथ अनुच्छेद संख्याओं की क्रमबद्धता बनी रहे।
4. अन्तरराष्ट्रीय लेखा मानक 28 में अनुच्छेद संख्या 16 'हटाया गया' प्रदर्शित होता है। लेकिन, अन्तरराष्ट्रीय लेखा मानक के साथ भारतीय लेखा मानक की अनुच्छेद संख्याओं की क्रमबद्धता बनी रहे, अतः भारतीय लेखा मानक 28 में इस अनुच्छेद संख्या को रखा गया है।
5. अनुच्छेद 23 (ख) का भारतीय लेखा मानक 103 के अनुसार इस आशय से संशोधन कर दिया गया है कि सहयोगी प्रतिष्ठान की पहचान वाली निवल उचित मूल्य पर आस्तियों व देयताओं में निवेश की लागत से आधिक्य में निवेशक का निवल उचित मूल्य का हिस्सा पूंजी प्रारक्षित निधि में स्थानांतरित किया जाना चाहिए जब कि अन्तरराष्ट्रीय लेखा मानक 28 में इसे लाभ या हानि में दर्शाया गया है।

भारतीय लेखा मानक (इंड ए एस) 31

संयुक्त उद्यमों में हित

(इस भारतीय भारतीय लेखा मानक में मोटे टाइप व सामान्य टाइप में अनुच्छेद हैं। इन दोनों तरह के अनुच्छेदों का समान प्राधिकार है। मोटे टाइप में अनुच्छेद, मुख्य सिद्धान्तों के सूचक हैं।)

कार्य-क्षेत्र

1. इस मानक को संयुक्त उद्यमों में हितों के लेखा के लिए तथा संयुक्त उद्यमों की आस्तियों, देयताओं आय व व्ययों से संबंधित उद्यमियों व निवेशकों के वित्तीय विवरणों की रिपोर्टिंग के लिए प्रयोग किया जाएगा बेशक वह संरचना या स्वरूप कुछ भी हो जिसके अन्तर्गत संयुक्त उद्यमों की गतिविधियां घटित होती हैं। तथापि, यह निम्नलिखित संयुक्त नियंत्रित प्रतिष्ठानों के उद्यमियों के हितों पर लागू नहीं होते:

क) जोखिमपूर्ण पूंजीगत संगठन,

ख) [देखिये परिशिष्ट 1]

यह कि प्रारंभिक मान्यता पर लाभ व हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर नामोद्दिष्ट किये जाते हैं अथवा भारतीय लेखा मानक 39 वित्तीय लिखते: मान्यता व माप के अनुसरण में व्यापार के लिए धारित तथा लेखा के लिए वर्गीकृत किये जाते हैं। इस प्रकार के निवेशों का माप भारतीय लेखा मानक 39 के अनुसार परिवर्तन की अवधि में लाभ अथवा हानि में मान्यता प्राप्त उचित मूल्य में परिवर्तनों के साथ किया जाएगा। इस प्रकार का हित रखने वाला उद्यमी अनुच्छेद 55 तथा 56 में की गई अपेक्षा के अनुसार प्रकटन करेगा।

2. संयुक्त नियंत्रित प्रतिष्ठान में हित रखने वाला उद्यमी अनुच्छेद 30 (आनुपतिक समेकन) तथा 38 (ईक्विटी विधि) से छूट प्राप्त करेगा जब वह निम्नलिखित शर्तें पूरी करता हो :

क) भारतीय लेखा मानक 105 'बिक्री के लिए धारित के रूप में गैर चालू आस्तियां एवं बन्द परिचालन' के अनुसरण में बिक्री के लिए धारित के रूप में, हित का वर्गीकरण

ख) [देखिये परिशिष्ट 1]

ग) [देखिये परिशिष्ट 1]

परिभाषाएं

3. इस मानक में निम्नलिखित शब्दावली का प्रयोग यहां विनिर्दिष्ट अर्थों में किया गया है :-

नियंत्रण से अभिप्राय: किसी आर्थिक क्रिया कलाप की वित्तीय तथा परिचालन नीतियों को शासित करने की शक्ति है ताकि इससे लाभ प्राप्त किये जा सकें।

ईक्विटी विधि लेखांकन की वह विधि है जिसके द्वारा किसी संयुक्त नियंत्रित प्रतिष्ठान में हित प्रारंभिक तौर पर लागत पर रिकार्ड किया जाता है और उसके बाद संयुक्त नियंत्रित प्रतिष्ठान की निबल आस्तियों के उद्यमी के भाग (शेयर) में अधिग्रहण के बाद परिवर्तन के लिए समायोजित किया जाता है। उद्यमी के लाभ अथवा हानि में, संयुक्त नियंत्रित प्रतिष्ठान के लाभ अथवा हानि में उद्यमी का भाग भी सम्मिलित होता है।

संयुक्त उद्यम में निवेशक संयुक्त उद्यम का एक पक्षकार है लेकिन संयुक्त उद्यम में उसका कोई संयुक्त नियंत्रण नहीं है।

संयुक्त नियंत्रण किसी आर्थिक कार्य कलाप के ऊपर नियंत्रण की हिस्सेदारी की संविदात्मक सहमति है और इसका तभी आस्तित्व है जब क्रिया-कलाप से संबंधित नीतिगत वित्तीय व परिचालन संबंधी निर्णय नियंत्रण हिस्सेदार पक्षकारों के बीच सर्वसम्मत सहमति से लिये जाते हों।

संयुक्त उद्यम एक संविदात्मक व्यवस्था है जिसके अंतर्गत दो या दो से अधिक पक्षकार उस आर्थिक कार्य कलाप को करते हैं जो कि संयुक्त नियंत्रण के अधीन है।

आनुपातिक समेकन लेखांकन की एक विधि है जिसके द्वारा संयुक्त नियंत्रित प्रतिष्ठान की आस्तियां, देयताएं, आय व व्यय में उद्यमी के प्रत्येक हिस्से को उसके वित्तीय विवरणों में समान मर्दों के साथ पंक्ति दर पंक्ति जोड़ा जाता है अथवा पृथक पंक्ति की मर्दों के रूप में सूचित किया जाता है।

पृथक वित्तीय विवरण वे विवरण हैं जो मूल प्रतिष्ठान, सहायक प्रतिष्ठान में एक निवेशक या संयुक्त नियंत्रित प्रतिष्ठान में एक उद्यमी द्वारा प्रस्तुत किये जाते हैं। इन प्रतिष्ठानों में निवेश का लेखा प्रत्यक्ष ईक्विटी हित के आधार पर किया जाता है न कि निवेशितियों के रिपोर्ट किये गये परिणामों एवं निबल आस्तियों के आधार पर।

महत्वपूर्ण प्रभाव वह शक्ति है जिससे कि किसी आर्थिक कार्य कलाप के वित्तीय तथा परिचालन संबंधी नीतिगत निर्णयों में हिस्सा लिया जा सके। लेकिन, वह उन नीतियों को अकेले या संयुक्त रूप से नियंत्रित न करे।

जोखिमी वह व्यक्ति है जो किसी संयुक्त उद्यम का एक पक्षकार है और संयुक्त उद्यम में संयुक्त नियंत्रण रखता है।

4. वित्तीय विवरणों में आनुपातिक समेकन अथवा इक्विटी विधि को प्रयोग में लाया जाता है। ये न तो पृथक वित्तीय विवरण हैं और न ही किसी ऐसे प्रतिष्ठान के वित्तीय विवरण हैं जिसका कोई अनुषंगी सहायक प्रतिष्ठान या संयुक्त नियंत्रण प्रतिष्ठान में उद्यमी हित नहीं है।
5. पृथक वित्तीय विवरण वे वित्तीय विवरण हैं जोकि समेकित वित्तीय विवरण के अतिरिक्त प्रस्तुत किये जाते हैं वित्तीय विवरण जिसमें इक्विटी विधि का प्रयोग करते हुए निवेशों को हिसाब में लिया जाता है और वित्तीय विवरण जिनमें कि संयुक्त उद्यमियों के संयुक्त हितों को आनुपातिक आधार पर समेकित किया जाता है। पृथक वित्तीय विवरणों को इन विवरणों के साथ अथवा उनके नीचे लगाने की आवश्यकता नहीं है।
6. [देखिये परिशिष्ट 1] ।

संयुक्त उद्यम के स्वरूप

7. संयुक्त उद्यमों के विभिन्न स्वरूप व संरचनाएं हैं। मोटेतौर पर तीन प्रकारों की पहचान की जाती है अर्थात् संयुक्त नियंत्रित परिचालन, संयुक्त नियंत्रित आस्तियां तथा संयुक्त नियंत्रित प्रतिष्ठान जोकि आमतौर पर संयुक्त उद्यमों के रूप में वर्णित किये जाते हैं और इनकी परिभाषा संयुक्त उद्यम की परिभाषा में ही समाविष्ट है। सभी संयुक्त उद्यमों में आमतौर पर निम्नलिखित लक्षण होते हैं :-

- क) दो या दो से अधिक उद्यमी एक संविदात्मक व्यवस्था से आबद्ध होते हैं, और
- ख) संविदात्मक व्यवस्था संयुक्त नियंत्रण स्थापित करती है।

संयुक्त नियंत्रण

8. संयुक्त नियंत्रण उस स्थिति में प्रतिषिद्ध हो जाता है जब कोई निवेशिती कानूनी पुनर्गठन की प्रक्रिया में हो अथवा दिवालिया हो जाए अथवा उद्यमी की निधियों को नियंत्रित करने के लिए इसकी सामर्थ्यता पर लम्बी अवधि के अनेक प्रतिबंध लगा दिये जाएं। यदि संयुक्त नियंत्रण जारी रहता है ये घटनाएं अपने आप में पर्याप्त नहीं हैं कि इस मानक के अंतर्गत संयुक्त उद्यमों का लेखा न हो।

संविदात्मक व्यवस्था

9. संविदात्मक व्यवस्था की मौजूदगी इन हितों में अन्तर करती है जिसमें कि ऐसे प्रतिष्ठानों में निवेशों से संयुक्त नियंत्रण सम्मिलित होता है जिसमें कि निवेशक का महत्वपूर्ण प्रभाव हो। [देखें भारतीय लेखा

मानक 28] । ऐसे कार्य कलाप जिनकी संयुक्त नियंत्रण स्थापित करने के लिए कोई संविदात्मक व्यवस्था नहीं है, इस मानक के प्रयोजनों के लिए वे संयुक्त उद्यम नहीं हैं।

10. संविदात्मक व्यवस्था का साक्ष्य कई प्रकार से हो सकता है, उदाहरण के लिये, उद्यमियों के बीच में संविदा का निष्पादन अथवा उद्यमियों के बीच हुए विचार-विमर्श का कार्यवृत्त। कुछ मामलों में, इसे प्रबंधन की नियमावली (आर्टिकल) में निगमित कर दिया जाता है या फिर संयुक्त उद्यम की उप-नियमावली में सम्मिलित कर दिया जाता है। संविदात्मक प्रबंध आमतौर पर लिखत में होता है और ऐसे मामलों पर कार्रवाई करता है जैसे कि :
 - क) संयुक्त उद्यम के कार्यकलाप, अवधि और रिपोर्ट करने के दायित्व ;
 - ख) संयुक्त उद्यम के संचालक मंडल अथवा समान अधिशासी निकाय की नियुक्ति तथा उद्यमियों के मताधिकार का प्रयोग ;
 - ग) उद्यमियों द्वारा पूंजीगत अंशदान ; और
 - घ) संयुक्त उद्यम के उत्पादन, आय, व्ययों अथवा परिणामों में उद्यमियों की हिस्सेदारी।
11. संविदात्मक व्यवस्था संयुक्त उद्यम पर संयुक्त नियंत्रण स्थापित करती है। इस प्रकार की अपेक्षा यह सुनिश्चित करती है कि कोई भी उद्यमी इस स्थिति में नहीं रहता कि वह अकेले ही कार्यकलाप पर नियंत्रण कर सके और, जैसा वह चाहे वैसे ही, उन कार्य-कलापों का संचालन करे।
12. संविदात्मक व्यवस्था किसी उद्यमी की संयुक्त उद्यम के परिचालक अथवा प्रबंधक के रूप में पहचान कर सकती है। परिचालक संयुक्त उद्यम पर नियंत्रण नहीं करता परंतु उन वित्तीय तथा परिचालन नीतियों के अंतर्गत कार्य करता है जो संविदात्मक व्यवस्था के अनुसार उद्यमियों द्वारा सहमत है और परिचालक को सौंपी गई हैं। यदि परिचालक आर्थिक कार्य कलाप की वित्तीय तथा परिचालन नीतियों को शासित करने की शक्ति रखता है तो यह उद्यम पर नियंत्रण रखता है और उद्यम परिचालक की अनुषंगी है न संयुक्त उद्यम ।

संयुक्त नियंत्रित परिचालन

13. कुछ संयुक्त उद्यमों के परिचालन में उद्यमियों की आस्तियां तथा अन्य संसाधनों का प्रयोग किया जाना सम्मिलित हैं न कि किसी निगम, साझेदार अथवा अन्य प्रतिष्ठान अथवा वित्तीय संरचना का स्थापित करना जोकि उद्यमियों से अलग हैं। प्रत्येक उद्यमी अपनी ही सम्पत्ति, संयंत्र व उपकरणों का प्रयोग करता है और अपना ही सूचीबद्ध माल (इन्वेन्ट्री) रखता है। साथ ही, यह अपने व्यय स्वयं करता है और दायित्वों के निर्वाह के लिए अपने वित्तीय संसाधन जुटाता है। इस तरह वह अपने ही दायित्वों का निर्वहन स्वयं करता है। संयुक्त उद्यमी के कर्मचारी उद्यम कार्य-कलाप और इसी तरह के अन्य कार्य-कलाप करते हैं।

संयुक्त उद्यम करारनामा सामान्यता ऐसी व्यवस्था करता है जिसके द्वारा संयुक्त उत्पाद की बिक्री की आय तथा किये गये कोई भी खर्च उद्यमियों द्वारा आपस में बांट लिए जाते हैं।

14. संयुक्त नियंत्रित परिचालन का एक उदाहरण यह है कि जब दो या दो से अधिक उद्यमी संयुक्त रूप से किसी एक विशेष उत्पाद को तैयार करने, विपणन करने और वितरित करने के लिए अपने परिचालनों, संसाधनों तथा निपुणता को संयोजित करते हैं, जैसे कि एक वायुयान का निर्माण। प्रत्येक उद्यमी अपनी लागत स्वयं खर्च करता है और वायुयान की बिक्री की आय का हिस्सा प्राप्त करता है और इस प्रकार का हिस्सा संविदात्मक व्यवस्था के अनुसार निर्धारित होता है।
15. संयुक्त रूप से नियंत्रित परिचालनों में अपने हितों के संबंध में, उद्यमी अपने वित्तीय विवरणों में निम्नलिखित सूचित करेगा:
 - क) आस्तियां जिनका वह नियंत्रण करता है और देयताएं जिन पर वह खर्च करता है, तथा
 - ख) खर्च जो वह करता है और आय का हिस्सा संयुक्त उद्यम द्वारा वस्तुओं के संबंध की बिक्री के फलस्वरूप वह अर्जित करता है।
16. क्योंकि आस्तियां, देयताएं, आय तथा व्यय उद्यमी के वित्तीय विवरणों में मान्य होते हैं अतः जब उद्यमी समेकित वित्तीय विवरण प्रस्तुत करता है तो इन मदों के संबंध में किसी भी समायोजन अथवा समेकन प्रक्रिया की अपेक्षा नहीं है।
17. संयुक्त उद्यम को अपना अलग से लेखा रिकार्ड रखने की आवश्यकता नहीं है अतः संयुक्त उद्यम के लिए वित्तीय विवरण तैयार नहीं करेगा। तथापि, उद्यमी अपना प्रबंधकीय लेखा तैयार कर सकते हैं और वे संयुक्त उद्यम के कार्य के निष्पादन का मूल्यांकन कर सकते हैं।

संयुक्त रूप से नियंत्रित आस्तियां

18. एक या एक से अधिक की आस्तियों के उद्यमी संयुक्त उद्यम में संयुक्त नियंत्रण और प्रायः संयुक्त स्वामित्व रखते हैं और इस प्रयोजन के लिए अंशदान करते हैं और अधिगृहीत करते हैं। आस्तियों का प्रयोग उद्यमियों के लाभ के लिये किया जाता है। प्रत्येक उद्यमी जिसे आस्तियों से आय का हिस्सा लेना है वह किये गये खर्चों को भी हिस्से के अनुसार वहन करता है।
19. ये संयुक्त उद्यमी किसी निगम, साझेदारी अथवा अन्य प्रतिष्ठान अथवा वित्तीय संरचना की संस्थापना में सम्मिलित नहीं होते क्योंकि ये सभी उद्यमियों से अलग हैं। प्रत्येक उद्यमी संयुक्त नियंत्रित आस्ति के माध्यम से भावी आर्थिक लाभों के हिस्से पर नियंत्रण रखता है।

20. तेल, गैस तथा रसायनिक निष्कर्षण उद्योग में बहुत से कार्य कलाप संयुक्त नियंत्रित आस्तियों को सम्मिलित करते हैं। उदाहरण के लिए तेल उत्पादन की बहुत सी कंपनियां किसी तेल पाईपलाइन को संयुक्त रूप से नियंत्रित तथा परिचालित कर सकती हैं। प्रत्येक उद्यमी अपने उत्पाद को ले जाने के लिये इस पाईपलाइन का प्रयोग करता है जिसके बदले में वह पाईपलाइन के परिचालन के खर्चों को एक सहमत अनुपात में वहन करता है। संयुक्त नियंत्रित आस्ति का एक दूसरा उदाहरण है कि जब दो प्रतिष्ठान संयुक्त रूप से किसी संपत्ति का संयुक्त नियंत्रण करते हैं और प्रत्येक उद्यमी आय स्वरूप प्राप्त किराये का हिस्सा प्राप्त करता है तथा किये गये खर्चों के एक हिस्से को वहन करता है।
21. संयुक्त रूप से नियंत्रित आस्तियों में अपने हित के संबंध में एक उद्यमी अपने वित्तीय विवरणों में निम्नलिखित को मान्यता देगा:
- क) आस्तियों की प्रकृति के अनुसार वर्गीकृत संयुक्त नियंत्रित आस्तियों में इसका हिस्सा ;
 - ख) कोई भी देयताएं जो इसके द्वारा खर्च की गई हैं ;
 - ग) संयुक्त उद्यम के संबंध में, अन्य उद्यमियों के साथ खर्च की गई किसी भी देयता में इसका हिस्सा ;
 - घ) संयुक्त उद्यमी के उत्पादन के हिस्से की बिक्री करने से अथवा इसका प्रयोग करने से प्राप्त कोई आय, संयुक्त उद्यमी द्वारा किये गये खर्च के हिस्से को मिलाकर ; तथा
 - ङ.) ऐसे कोई भी खर्च जो उद्यमी ने संयुक्त उद्यम में अपने हित के संबंध में खर्च किये हैं।
22. संयुक्त रूप से नियंत्रित आस्तियों में अपने हित के संबंध में प्रत्येक उद्यम अपने लेखा रिकार्ड में निम्नलिखित को सम्मिलित करता है तथा वित्तीय विवरणों में मान्यता देता है:
- क) संयुक्त रूप से नियंत्रित आस्तियों का इसका हिस्सा आस्तियों की प्रकृति के अनुसार वर्गीकृत करना, न कि निवेश के रूप में। उदाहरण के लिए संयुक्त रूप से नियंत्रित तेल पाईपलाइन के एक हिस्से को संपत्ति, संयंत्र तथा उपकरण के रूप में वर्गीकृत करना।
 - ख) कोई भी देयताएं जो इसने खर्च की हैं। उदाहरण के लिए, आस्तियों के अपने हिस्से को वित्तपोषित करने के लिए खर्च करना।
 - ग) संयुक्त उद्यम के संबंध में, अन्य उद्यमियों के साथ संयुक्त रूप से खर्च की गई किन्हीं भी देयताओं में इसका हिस्सा।
 - घ) संयुक्त उद्यम के उत्पादन में अपने हिस्से की बिक्री करने अथवा प्रयोग में लाने से प्राप्त कोई भी आय के साथ-साथ संयुक्त उद्यमी द्वारा किये गये खर्च में उसका हिस्सा ।

ड.) ऐसे कोई भी खर्च जो उद्यमी ने संयुक्त उद्यम में अपने हित के संबंध में खर्च किये हैं। उदाहरण के लिए, आस्तियों में उद्यमी के हित को वित्तपोषित करने के लिए तथा उत्पादन में इसके हिस्से की बिक्री के लिए खर्च किये गये हों।

क्योंकि आस्तियां, देयताएं, आय तथा व्यय उद्यमी के वित्तीय विवरणों में मान्य होते हैं, अतः जब उद्यमी समेकित वित्तीय विवरण प्रस्तुत करता है तो इन मदों के संबंध में किसी भी समायोजन अथवा अन्य समेकन प्रक्रिया की अपेक्षा नहीं है।

23. संयुक्त रूप से नियंत्रित आस्तियों के संव्यवहार से यह प्रतिबिम्बित होता है कि संयुक्त उद्यम का आधार, आर्थिक वास्तविकता और आमतौर पर उसकी कानूनी स्थिति क्या है। संयुक्त उद्यम के अपने लेखा रिकार्ड उन खर्चों तक ही सीमित हो सकते हैं जो उद्यमियों द्वारा आमतौर पर खर्च किये जाते हैं और जो अन्ततः सहमत हिस्सों के अनुसार उद्यमियों द्वारा उठाए जाते हैं। संयुक्त उद्यम के लिए वित्तीय विवरण तैयार करने की आवश्यकता नहीं है। तथापि, उद्यमी प्रबंधकीय लेखों को तैयार कर सकते हैं ताकि वे संयुक्त उद्यम के कार्य निष्पादन का मूल्यांकन कर सकें।

संयुक्त रूप से नियंत्रित प्रतिष्ठान

24. संयुक्त रूप से नियंत्रित प्रतिष्ठान एक संयुक्त उद्यम है जोकि निगम, साझेदारी अथवा अन्य प्रतिष्ठान की संस्थापना में सम्मिलित रहता है जिसमें प्रत्येक उद्यमी का अपना हित है। यह प्रतिष्ठान उसी प्रकार से परिचालित होता है जैसाकि अन्य प्रतिष्ठान, सिवाय इसके कि इसमें एक संविदात्मक व्यवस्था है जो उद्यमियों के बीच प्रतिष्ठान के आर्थिक कार्य-कलाप के उपर संयुक्त नियंत्रण स्थापित करता है।
25. एक संयुक्त रूप से नियंत्रित प्रतिष्ठान, संयुक्त उद्यम की आस्तियों पर नियंत्रण करता है, देयताओं को अपने ऊपर लेता है एवं खर्च उठाता है और आय अर्जित करता है। यह अपने नाम में संविदाएं निष्पादित कर सकता है और संयुक्त उद्यम के कार्य-कलापों के प्रयोजनों के लिए वित्त प्राप्त कर सकता है। प्रत्येक उद्यम संयुक्त रूप से नियंत्रित प्रतिष्ठान के लाभों में हिस्सेदारी के लिए हकदार है, अपितु कुछ संयुक्त रूप से नियंत्रित प्रतिष्ठान, संयुक्त उद्यम के उत्पादन में हिस्सेदारी में सम्मिलित होते हैं।
26. संयुक्त रूप से नियंत्रित प्रतिष्ठान का एक सामान्य उदाहरण यह है कि जब दो प्रतिष्ठान संबंधित आस्तियां तथा देयताओं को संयुक्त रूप से नियंत्रित प्रतिष्ठान में सौंपांतरित करके कारोबार की एक विशेष लाईन में अपने कार्य कलापों को एक साथ मिला लेते हैं। इसका दूसरा उदाहरण यह है कि जब कोई प्रतिष्ठान विदेश में एक पृथक् प्रतिष्ठान स्थापित करके उस देश की सरकार अथवा उसकी एजेंसी के साथ मिलकर कार्य आरंभ करता है जो प्रतिष्ठान तथा उस सरकार अथवा उसकी एजेंसी द्वारा संयुक्त रूप से नियंत्रित किया जाता है।

27. बहुत से संयुक्त रूप से नियंत्रित प्रतिष्ठान, उन संयुक्त उद्यमों के आधार के समान हैं जिनका उल्लेख संयुक्त रूप से नियंत्रित परिचालनों अथवा संयुक्त नियंत्रित आस्तियों के रूप में किया गया है। उदाहरण के लिए, उद्यमी कर अथवा अन्य कारणों से किसी संयुक्त रूप से नियंत्रित आस्ति, जैसा कि एक तेल पाईपलाईन, को किसी संयुक्त रूप से नियंत्रित प्रतिष्ठान में सौंप सकता है। इसी प्रकार से उद्यमी संयुक्त नियंत्रित प्रतिष्ठान की आस्तियों में अंशदान कर सकते हैं जिन्हें संयुक्त रूप से परिचालित किया जाता है। कुछ संयुक्त रूप से नियंत्रित परिचालन उत्पाद के डिजाईन, विपणन, संवितरण अथवा बिक्री के बाद की सेवा जैसे कार्य-कलापों के विशेष पहलुओं पर कार्रवाई करने के लिए किसी संयुक्त रूप से नियंत्रित प्रतिष्ठान की संस्थापना में भी सम्मिलित हो सकते हैं।
28. एक संयुक्त रूप से नियंत्रित प्रतिष्ठान अपने लेखांकन के रिकार्ड का स्वयं रखरखाव करता है और उसी रूप में वित्तीय विवरण तैयार करता है और प्रस्तुत करता है, जैसे कि अन्य प्रतिष्ठान भारतीय लेखा मानकों के अनुसार करते हैं।
29. प्रत्येक उद्यमी सामान्यतया संयुक्त नियंत्रित रूप से प्रतिष्ठान में नकदी अथवा अन्य संसाधनों का अंशदान करता है। ये अंशदान उद्यमी के लेखा रिकार्ड में सम्मिलित किये जाते हैं और अपने संयुक्त नियंत्रित प्रतिष्ठान में निवेश के रूप में दी जाती हैं।

उद्यमी के वित्तीय विवरण

आनुपातिक समेकन

30. एक उद्यमी आनुपातिक समेकन अथवा अनुच्छेद 38 में वर्णित वैकल्पिक विधि का प्रयोग करते हुए किसी संयुक्त रूप से नियंत्रित प्रतिष्ठान में अपने हिस्से को मान्यता देगा। जब आनुपातिक समेकन का प्रयोग किया जाता है नीचे दिये गये दो रिपोर्टिंग प्रपत्रों (फार्मेटों) में से किसी एक का प्रयोग किया जाएगा।
31. एक उद्यमी आनुपातिक समेकन के लिये दो में से एक रिपोर्ट प्रपत्र (फार्मेट) का प्रयोग करते हुए संयुक्त रूप से नियंत्रित प्रतिष्ठान में अपने हित को मान्यता देगा चाहे अनुषंगी कपनियों में भी उद्यमी का निवेश हो अथवा नहीं, अथवा समेकित वित्तीय विवरणों को वर्णित करता है अथवा नहीं।
32. किसी संयुक्त रूप से नियंत्रित प्रतिष्ठान में जब हित को मान्यता दी जाती है, तो यह आवश्यक है कि एक उद्यमी व्यवस्था के एवं आर्थिक वास्तविकता को प्रतिबिम्बित करे, न कि संयुक्त उद्यमी की विशिष्ट संरचना अथवा स्वरूप को किसी भी संयुक्त रूप से नियंत्रित प्रतिष्ठान में उद्यम की आस्तियों तथा देयताओं के हिस्से के जरिये भावी आर्थिक लाभों के अपने हिस्से पर उद्यमी नियंत्रण करता है। यह सार तथा आर्थिक वास्तविकता उद्यमी के समेकित वित्तीय विवरणों में प्रतिबिम्बित होती है जब उद्यमी अनुच्छेद

34 में वर्णित आनुपातिक समेकन के लिए दो में से एक रिपोर्टिंग प्रपत्र (फार्मेट) का प्रयोग करके संयुक्त रूप से नियंत्रित प्रतिष्ठान की आस्तियों, देयताओं, आय तथा व्ययों में अपने हितों को मान्यता देता है।

33. आनुपातिक समेकन को लागू करने से यह अभिप्राय है कि उद्यमी के तुलन पत्र में आस्तियों में हिस्सा तथा इसी तरह इसकी देयताओं में वह हिस्सा सम्मिलित होता है जिसे कि वह संयुक्त रूप से नियंत्रित करता है जिसके लिए वह उत्तरदायी है। उद्यमी के लाभ व हानि के विवरण में संयुक्त रूप से नियंत्रित प्रतिष्ठान की आय तथा खर्चों का उसका हिस्सा सम्मिलित होता है। आनुपातिक समेकन को लागू करने के लिए बहुत सी प्रक्रियाएं उपयुक्त हैं और वे अनुषंगी कंपनियों में निवेशों के समेकन के लिए प्रक्रियाओं के समान हैं। ये प्रक्रियाएं भारतीय लेखा मानक (इंड ए एस) 21 में निर्दिष्ट की गई हैं।

34. आनुपातिक समेकन को लागू करने के लिए विभिन्न रिपोर्ट प्रपत्रों को प्रयोग में लाया जा सकता है। उद्यमी अपने वित्तीय विवरणों में पंक्ति दर पंक्ति समान मदों के साथ संयुक्त रूप से नियंत्रित प्रतिष्ठान की आस्तियों, देयताओं, आय तथा व्यय के प्रत्येक अपने हिस्से को मिला सकता है। उदाहरण के लिए, यह संयुक्त रूप से नियंत्रित प्रतिष्ठान के सूचीबद्ध सामान में अपने हिस्से को अपने सूचीबद्ध सामान (इंवेंट्री) और संयुक्त रूप से नियंत्रित प्रतिष्ठान की संपत्ति, संयंत्र एवं उपस्कर में अपने हिस्से को अपनी संपत्ति, संयंत्र एवं उपस्कर में सम्मिलित कर सकता है। विकल्प के रूप में, उद्यमी अपने वित्तीय विवरणों में संयुक्त रूप से नियंत्रित प्रतिष्ठान की आस्तियों, देयताओं, आय तथा व्यय के अपने हिस्से के लिये पृथक लाईन मदों को सम्मिलित कर सकता है। उदाहरण के लिए, यह संयुक्त रूप से नियंत्रित प्रतिष्ठान में वर्तमान के अपने हिस्से को वर्तमान आस्तियों के हिस्से के रूप में दिखा सकता है। संयुक्त रूप से नियंत्रित प्रतिष्ठान की सम्पत्ति, संयंत्र तथा उपस्कर के अपने हिस्से को पृथक रूप में अपनी सम्पत्ति, संयंत्र एवं उपस्कर के हिस्से के रूप में दिखा सकता है। इन दोनों ही रिपोर्टिंग प्रपत्रों में लाभ व हानि की समान राशियां प्राप्त होती हैं तथा आस्तियों, देयताओं, आय व व्ययों के प्रत्येक प्रमुख वर्गीकरण के लिए दोनों ही फार्मेट इस मानक के प्रयोजनों के लिये स्वीकार्य हैं।

35. आनुपातिक समेकन के प्रभाव के लिए हम चाहे किसी भी प्रपत्र (फार्मेट) का प्रयोग क्यों न करें लेकिन यह अनुचित होगा कि हम किसी भी आस्ति या देयता में देयता या आस्ति की कटौती और आय या व्यय में व्यय या आय की कटौती का परस्पर समायोजन (आफसेट) करें जब तक परस्पर समायोजन (सैट आफ) का कानूनी अधिकार विद्यमान न हो और यह समायोजन (आफ सैटिंग) आस्तियों की वसूली या देयता का निपटान की प्रत्याशा का प्रतिनिधित्व न करे।

36. एक उद्यमी आनुपातिक समेकन का प्रयोग उस तिथि से बंद कर देगा जिस तिथि को वह संयुक्त रूप से नियंत्रित प्रतिष्ठान पर अपना संयुक्त नियंत्रण बन्द कर देता है।

37. एक उद्यमी आनुपातिक समेकन का प्रयोग उस तिथि से बन्द करता है जिस तिथि से वह संयुक्त रूप से नियंत्रित प्रतिष्ठान पर अपना नियंत्रण बन्द कर देता है। उदाहरणार्थ, यह तभी हो सकता है जब उद्यमी अपने हित का निपटान कर देता है अथवा जब संयुक्त रूप से नियंत्रित प्रतिष्ठान पर ऐसे बाह्य प्रतिबंध लगा दिये जाते हैं जिससे उद्यमी का आगे कोई संयुक्त नियंत्रण रह ही नहीं जाता।

इक्विटी विधि

38. उपर्युक्त अनुच्छेद 30 में वर्णित आनुपातिक समेकन के एक विकल्प के रूप में एक उद्यमी संयुक्त रूप से नियंत्रित प्रतिष्ठान में अपने हित की मान्यता के लिए इक्विटी विधि का प्रयोग करेगा।
39. एक उद्यमी चाहे अपनी अनुषंगी कंपनियों में निवेश है अथवा नहीं अथवा वह अपने वित्तीय विवरणों को समेकित वित्तीय विवरणों के रूप में वर्णित करता है अथवा नहीं, वह संयुक्त रूप से नियंत्रित प्रतिष्ठान में अपने हित की मान्यता के लिए इक्विटी विधि का प्रयोग करता है।
40. कुछ उद्यमी 'इक्विटी' विधि का प्रयोग करके किसी संयुक्त रूप से नियंत्रित प्रतिष्ठान में अपने हितों को मान्यता देते हैं जैसा कि भारतीय लेखा मानक 28 में वर्णित किया गया है। 'इक्विटी' विधि के प्रयोग का समर्थन उन लोगों द्वारा किया जाता है जो यह तर्क देते हैं कि संयुक्त रूप से नियंत्रित मदों के साथ नियंत्रित मदों को मिश्रित (सम्मिलित) करना उपयुक्त नहीं होगा तथा उन लोगों द्वारा समर्थन किया जाता है जो इस बात में विश्वास करते हैं कि उद्यमी का संयुक्त रूप से नियंत्रित प्रतिष्ठान में महत्वपूर्ण प्रभाव रहेगा, न कि उसमें संयुक्त नियंत्रण होगा। यह मानक 'इक्विटी' विधि के प्रयोग की सिफारिश नहीं करता क्योंकि आनुपातिक समेकन किसी संयुक्त रूप से नियंत्रित प्रतिष्ठान में किसी उद्यमी के हित के सार तथा आर्थिक वास्तविकता अर्थात् भावी आर्थिक लाभों में उद्यमी के हिस्से पर नियंत्रण को बेहतर ढंग से प्रस्तुत करता है। इसके बावजूद, यह मानक संयुक्त रूप से नियंत्रित प्रतिष्ठानों के हितों की मान्यता के लिए वैकल्पिक संव्यवहार के रूप में इक्विटी विधि के प्रयोग की अनुमति देता है।
41. एक उद्यमी 'इक्विटी' विधि के प्रयोग को उस तिथि से बन्द कर देगा जिससे वह किसी संयुक्त रूप से नियंत्रित प्रतिष्ठान पर नियंत्रण बन्द कर देता है अथवा उस पर अपना महत्वपूर्ण प्रभाव खो देता है।

आनुपातिक समेकन तथा 'इक्विटी' विधि के अपवाद

42. संयुक्त रूप से नियंत्रित प्रतिष्ठान में हितों का, जोकि भारतीय लेखा मानक 105 बिक्री के लिए धारित गैर चालू आस्तियां एवं बंद हुए परिचालन के अनुसरण में बिक्री के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत किये जाते हैं लेखा उस मानक के अनुसार किया जायेगा।
43. जब किसी संयुक्त रूप से नियंत्रित प्रतिष्ठान में कोई हित, जोकि पहले बिक्री के लिये आधार के रूप में वर्गीकृत किया गया था, वर्गीकरण के मानदंड को अब पूरा नहीं करता है तो इसको आनुपातिक समेकन अथवा इक्विटी विधि का प्रयोग करने के वास्ते बिक्री के लिए धारित वर्गीकरण की उस तारीख से हिसाब में लिया जायेगा। बिक्री के लिये धारित के रूप में वर्गीकरण से उन अवधियों के लिये वित्तीय विवरणों को तदनुसार संशोधित कर लिया जायेगा।
44. [देखिये परिशिष्ट 1]

45. जब किसी निवेशक का किसी प्रतिष्ठान पर संयुक्त नियंत्रण समाप्त हो जाता है तो वह उस तिथि से भारतीय लेखा मानक 39 के अनुसार शेष निवेश का लेखा करेगा बशर्ते पूर्ववर्ती संयुक्त नियंत्रित प्रतिष्ठान एक अनुषंगी अथवा सहायक प्रतिष्ठान न बन जाये। जिस तिथि को जब कोई संयुक्त रूप से नियंत्रित प्रतिष्ठान एक निवेशक का अनुषंगी प्रतिष्ठान बन जाता है तो निवेशक भारतीय लेखा मानक 27 तथा भारतीय लेखा मानक 103 'व्यवसाय संयोजन' के अनुसार अपने हित का लेखा करेगा। जिस तिथि पर कोई संयुक्त रूप से नियंत्रित प्रतिष्ठान एक निवेशक का सहायक प्रतिष्ठान बन जाता है तो निवेशक भारतीय लेखा मानक 28 के अनुसरण में अपने हित का लेखा करेगा। संयुक्त नियंत्रण गंवा देने पर वह निवेशक किसी भी निवेश का माप उचित मूल्य पर करेगा जो निवेशक पूर्ववर्ती संयुक्त नियंत्रित प्रतिष्ठान में प्रतिधारण करता था। निवेशक लाभ अथवा हानि में निम्नलिखित में से किसी भी अंतर की मान्यता करेगा :

क) किसी भी प्रतिधारण किये गये निवेश के उचित मूल्य तथा संयुक्त रूप से नियंत्रित प्रतिष्ठान में आंशिक हित के निपटान से कोई भी प्राप्तियां, तथा

ख) उस तारीख को निवेश की अग्रणीत (कैरिंग) राशि जब संयुक्त रूप से नियंत्रण की समाप्ति हो जाती है।

45 क) जब कोई निवेश संयुक्त रूप से नियंत्रित प्रतिष्ठान के रूप में समाप्त हो जाता है तो उसका भारतीय लेखा मानक 39 के अनुसार किया जाता है तो उस तिथि का उचित मूल्य जिस पर वह निवेश संयुक्त रूप से नियंत्रित प्रतिष्ठान के रूप में नहीं रहता है भारतीय लेखा मानक 39 के अनुसार वित्तीय आस्ति के रूप में आरंभिक मान्यता को उचित मूल्य के रूप में लिया जाएगा ।

45 ख) यदि कोई निवेशक एक प्रतिष्ठान का संयुक्त नियंत्रण खो देता है तो वह अन्य व्यापक आय में मान्य सभी राशियों का लेखा इस तरह से करेगा जैसे कि संयुक्त नियंत्रित प्रतिष्ठान ने संबंधित आस्तियों व देयताओं का प्रत्यक्ष रूप से निपटान किया हो। अतः यदि अन्य व्यापक आय में कोई लाभ या हानि पहले मान्य हुई है तो उसे आस्तियों या देयताओं के निपटान पर लाभ या हानि में पुनर्वर्गीकृत किया जाएगा । जैसे ही निवेशक प्रतिष्ठान में संयुक्त नियंत्रण खो देता है, तो वह लाभ या हानि को (पुनर्वर्गीकृत समायोजन के रूप में) 'इक्विटी' से लाभ या हानि में पुनर्वर्गीकृत करेगा। उदाहरण के रूप में, संयुक्त रूप से नियंत्रित प्रतिष्ठान के पास बिक्री के लिए उपलब्ध वित्तीय आस्तियां हैं और निवेशक ने उस प्रतिष्ठान में अपना संयुक्त नियंत्रण खो दिया है तो निवेशक पुनः आस्तियों के सापेक्ष में अन्य व्यापक आय में मान्य लाभ या हानि को लाभ या हानि में पुनर्वर्गीकृत करेगा। लेकिन, यदि वह निवेशक प्रतिष्ठान के संयुक्त नियंत्रण में अपना स्वमित्व हित समाप्त न करके कम कर देता है तो ऐसे में वह अन्य विस्तृत आय में से अपने लाभ या हानि का लाभ या हानि में पुनर्वर्गीकरण आनुपातिक आधार पर ही करेगा।

उद्यमी के पृथक वित्तीय विवरण

46. भारतीय लेखा मानक 27 के अनुच्छेद 38-43 के अनुसरण में संयुक्त रूप से नियंत्रित प्रतिष्ठान में हित का लेखा उद्यमी के पृथक वित्तीय विवरणों में किया जाएगा।
47. यह मानक इसका वर्णन नहीं करता कि कौन से प्रतिष्ठान सार्वजनिक प्रयोग के लिए पृथक वित्तीय विवरण अनिवार्य रूप से तैयार करेंगे।

उद्यमी और संयुक्त उद्यम के बीच लेन-देन

48. जब एक उद्यमी, संयुक्त उद्यम को आस्तियां अंशदान के रूप में देता है या बेचता है तो लेनदेन से हुए लाभ या हानि के किसी भी भाग की मान्यता लेनदेन के सार में प्रतिबिम्बित होगी। जबकि आस्तियां संयुक्त उद्यम द्वारा रखी जाती हैं और बशर्ते उद्यमी स्वामित्व के महत्वपूर्ण जोखिम व प्रतिफल को अंतरित कर चुका है तो उद्यमी के लाभ या हानि में से केवल उस भाग को मान्यता देनी होगी जो अन्य उद्यमियों के हितों के प्रति है।¹ उद्यमी किसी भी हानिकी पूरी राशि को मान्यता तभी देगा जब अंशदान या बिक्री चालू आस्तियों के निबल वसूली योग्य मूल्य की कटौती या क्षतिग्रस्तता हानि का साक्ष्य है।
49. जब एक उद्यमी संयुक्त उद्यम से आस्तियां खरीदता है तो उद्यमी को लेनदेन से संयुक्त उद्यम के लाभों में अपने भाग को तब तक मान्यता नहीं देनी होगी जब तक कि वह आस्तियों को एक स्वतंत्र पक्षकार को न बेच दे। एक उद्यमी को इन लेनदेनों से उत्पन्न हो रही हानियों में अपने भाग के लाभों की तरह ही मान्यता देनी होगी, सिवाय इसके कि हानियों को उस समय तुरंत मान्यता दे दी जाए जब वे चालू आस्तियों के निबल वसूली योग्य मूल्य में कटौती और क्षतिग्रस्तता हानि प्रस्तुत करें।
50. यह मूल्यांकन करने के लिए कि उद्यमी और संयुक्त उद्यमी के बीच लेन देन आस्ति को हास का साक्ष्य प्रदान करता है या नहीं, उद्यमी आस्तियों के हास पर भारतीय लेखा मानक 36 आस्तियों की क्षतिग्रस्तता के अनुसार आस्ति की वसूली योग्य राशि निर्धारित करता है। प्रयोग से मूल्य का निर्धारण करने में संयुक्त उद्यम द्वारा आस्ति के अविरल प्रयोग और इसके अन्ततः निपटान के आधार पर आस्तियों से प्राप्त भावी नकदी प्रवाहों का अनुमान लगाया जाता है।

¹ इस मानक का परिशिष्ट 'क' - संयुक्त नियंत्रित प्रतिष्ठान उद्यमियों द्वारा गैर मौद्रिक अंशदान भी देखें।

निवेशक के वित्तीय विवरणों में संयुक्त उद्यमों के हित की रिपोर्टिंग

51. एक निवेशक जिसका संयुक्त उद्यम में संयुक्त नियंत्रण नहीं है वह अपने निवेश का लेखा, भारतीय लेखा मानक 39 के अनुसार करेगा अथवा यदि उसका संयुक्त उद्यम में महत्वपूर्ण प्रभाव है तो उसका लेखा, वह भारतीय लेखा मानक 28 के अनुसार करेगा।

संयुक्त उद्यमों के परिचालक

52. संयुक्त उद्यम के परिचालक या प्रबंधक अपनी फीस का लेखा भारतीय लेखा मानक 18 राजस्व के अनुसरण में करेंगे।
53. एक या एक से अधिक उद्यमी एक संयुक्त उद्यम के परिचालक या प्रबंधक के रूप में कार्य कर सकते हैं। सामान्यतया, परिचालकों को ऐसे कार्यों के लिए प्रबंधन फीस दी जाती है। संयुक्त उद्यम इस फीस का लेखा व्यय के रूप में करता है।

प्रकटन

54. एक उद्यमी निम्नलिखित आकस्मिक देयताओं की कुल राशि को अन्य आकस्मिक देयताओं की राशि से अलग प्रकट करेगा बशर्ते हानि की संभावना बहुत कम हो।
- क) उद्यमी द्वारा संयुक्त उद्यम में अपने हितों के वास्ते खर्च की गयी कोई आकस्मिक देयता या ऐसा व्यय जो उसने अन्य उद्यमियों के साथ संयुक्त रूप से किया गया तो उसमें उसका अपना भाग जो उसने खर्च किया है।
 - ख) संयुक्त उद्यम में आकस्मिक देयताओं में उसका भाग जिसके प्रति वह आकस्मिक रूप से उत्तरदायी है।
 - ग) वे आकस्मिक देयताएं यदि वे इस कारण उत्पन्न होंगी क्योंकि वह उनके लिए आकस्मिक रूप से उत्तरदायी है और वे देयताएं संयुक्त उद्यम से अन्य उद्यमियों के कारण हैं।
55. एक उद्यमी संयुक्त उद्यम के हितों के संबंध में निम्नलिखित वचनबद्धताओं की कुल राशि का अन्य वचनबद्धताओं से अलग प्रकटन करेगा:
- क) उद्यमी की संयुक्त उद्यम में हितों के संबंध में कोई पूंजीगत वचनबद्धताएं और अन्य उद्यमियों के साथ संयुक्त रूप से खर्च की गयी पूंजीगत वचनबद्धताओं में उसका भाग ; और
 - ख) संयुक्त उद्यमियों की अपनी पूंजीगत वचनबद्धताओं में उसका भाग

56. एक उद्यमी महत्वपूर्ण संयुक्त उद्यमों में अपने हितों की सूची व विवरण और संयुक्त रूप से नियंत्रित प्रतिष्ठानों में अपने स्वामित्व हित के अनुपात का विवरण प्रकटन करेगा। एक उद्यमी जो संयुक्त नियंत्रित प्रतिष्ठानों में अपने हितों को मान्यता देता है और इसके लिए वह आनुपातिक समेकन अथवा 'इक्विटी' विधि के लिए रिपोर्टिंग फार्मेट की प्रत्येक पंक्ति का प्रयोग करते हुए संयुक्त उद्यम में अपने हितों के संबंध में चालू आस्तियों, दीर्घावधि आस्तियों, चालू देयताओं, दीर्घावधि देयताओं, आय व व्यय में प्रत्येक की कुल राशि का प्रकटन करेगा।
57. एक उद्यमी संयुक्त नियंत्रित प्रतिष्ठानों में अपने हितों की मान्यता के लिए जिस भी विधि का प्रयोग करता है उसे वह प्रकट करेगा।

परिशेष क

संयुक्त रूप से नियंत्रित प्रतिष्ठान - उद्यमियों द्वारा गैर मौद्रिक अंशदान

मुद्दे

1. भारतीय लेखा मानक 31 का अनुच्छेद 48 एक उद्यमी तथा संयुक्त उद्यम के बीच अंशदान तथा बिक्री दोनों ही का उल्लेख करता है जोकि इस प्रकार है 'जब कोई उद्यमी किसी संयुक्त उद्यम को आस्तियों का अंशदान करता है अथवा इनकी बिक्री करता है, तो इस लेन देन से लाभ अथवा हानि के किसी भी अंश का मान्यता से लेन देन का सार प्रतिबिम्बित करेगा। इसके अतिरिक्त भारतीय लेखा मानक 31 को अनुच्छेद 24 यह कहता है कि 'एक संयुक्त रूप से नियंत्रित प्रतिष्ठान एक संयुक्त उद्यम है जोकि एक निगम, साझेदारी प्रतिष्ठान अथवा अन्य प्रतिष्ठान की संस्थापना को सम्मिलित करता है जिसमें प्रत्येक उद्यमी का एक हित है।' उन लाभ तथा हानियों की मान्यता पर कोई स्पष्ट मार्गदर्शन नहीं है जोकि संयुक्त रूप से नियंत्रित प्रतिष्ठानों (सनिप्र) में गैर मौद्रिक आस्तियों के अंशदानों के फलस्वरूप हैं।
2. किसी 'जेसी ई' में अंशदान 'सनिप्र' में किसी इक्विटी हित के लिये उसके बदले में उद्यमियों द्वारा आस्तियों का अन्तरण है। इस प्रकार के अंशदान विभिन्न प्रकार के रूप ले सकते हैं। उद्यमियों द्वारा अंशदान या तो 'सनिप्र' संस्थापना पर या बाद में किये जा सकते हैं। 'सनिप्र' में अंशदान की गई आस्तियों के बदले में उद्यमी (यों) द्वारा प्राप्त मूल्य नकदी अथवा किसी अन्य प्रतिफल पर हो सकता है जोकि 'सनिप्र' (अतिरिक्त प्रतिफल) के भावी नकदी प्रवाहों पर आधारित नहीं है।
3. मुद्दे निम्नलिखित हैं :
 - क) उद्यमी द्वारा उन लाभों अथवा हानियों के उपयुक्त अंश को लाभ अथवा हानि में कब मान्यता दी जाए जोकि 'सनिप्र' में किसी 'इक्विटी' हित के बदले में किसी गैर मौद्रिक आस्ति के किसी 'सनिप्र' में अंशदान के फलस्वरूप हुए हों।
 - ख) अतिरिक्त प्रतिफल को उद्यमी द्वारा हिसाब में कैसे लिया जाए, और

- ग) किसी वसूले न गए लाभ अथवा हानि को उद्यमी द्वारा समेकित वित्तीय विवरणों में कैसे प्रस्तुत किया जाए।
4. यह परिशिष्ट 'सनिप्र' में इक्विटी हित के बदले में गैर मौद्रिक अंशदानों के लिए उद्यमी के लेखा के मामले में कार्रवाई करता है जोकि या तो 'इक्विटी' विधि अथवा आनुपातिक समेकन के प्रयोग के लिये हिसाब में लिया जाता है।

लेखा सिद्धांत

5. 'सनिप्र' में किसी इक्विटी हित के बदले में किसी 'सनिप्र' में गैर मौद्रिक अंशदानों के मामले में भारतीय लेखा मानक 31 के अनुच्छेद 48 के अनुसार उद्यमी अन्य उद्यमियों के साम्या हितों अन्तर्हित योग्य लाभ अथवा हानि के अंश को अवधि के लिए लाभ अथवा हानि में मान्य करेगा। सिवाय इसके कि :-
- क) अंशदायी गैर मौद्रिक आस्ति (यों) के स्वामित्व के महत्वपूर्ण जोखिमों तथा पुरस्कारों को 'सनिप्र' में अन्तरित नहीं किया गया है, अथवा
- ख) गैर मौद्रिक अंशदान से लाभ अथवा हानि को विश्वसनीय तौर पर मापा नहीं जा सकता, अथवा
- ग) अंशदान के लेन देन में वाणिज्यिक सार, जिस शब्द का वर्णन भारतीय लेखा मानक 16 में किया गया है, कमी है। यदि अपवाद (क) (ख) अथवा (ग) को प्रयोग में लाया जाता है तो लाभ अथवा हानि को वसूल न किये जाने योग्य के रूप में माना जाता है और अनुच्छेद 6 का प्रयोग किए बिना इसकी लाभ अथवा हानि में मान्यता नहीं दी जाती है।
6. यदि, 'सनिप्र' में किसी 'इक्विटी' हित को प्राप्त करने के अतिरिक्त कोई उद्यमी मौद्रिक अथवा गैर मौद्रिक आस्तियां प्राप्त करता है तो उद्यमी द्वारा लेन देन पर लाभ अथवा हानि के उपयुक्त अंश को लाभ अथवा हानि में मान्यता दी जायेगी।
7. 'सनिप्र' अंशदान की गई गैर मौद्रिक आस्तियों पर न वसूल किये गये लाभों अथवा हानियों को आनुपातिक समेकन विधि के अंतर्गत स्पष्ट की गई आस्तियों के प्रति अथवा 'इक्विटी' विधि के अंतर्गत निवेश के प्रति समाप्त कर दिया जायेगा। इस प्रकार वसूल न किये गये लाभ अथवा हानियों को, उद्यमी द्वारा समेकित तुलन पत्र में आस्थगित लाभों अथवा हानियों के रूप में प्रस्तुत नहीं किया जायेगा।

परिशिष्ट 'ख'

अन्य भारतीय लेखा मानकों में समाविष्ट मामलों के संदर्भ

यह परिशिष्ट भारतीय लेखा मानक 31 का अभिन्न अंग है।

1. परिशिष्ट कः भारतीय लेखा मानक 37 प्रावधान, आकस्मिक देयताएं एवं आकस्मिक आस्तियां में समाहित विस्थापन पुनर्बहाली एवं पर्यवरण संबंधी पुनर्वास निधियों से उत्पन्न हितों के अधिकार - इस मानक के लिए भी संदर्भ का कार्य करता है।

परिशिष्ट 1

टिप्पणी - यह परिशिष्ट भारतीय लेखा मानक का अंग नहीं है। इस परिशिष्ट का प्रयोजन मात्र इतना है कि भारतीय लेखा मानक (इंड ए एस) 31 और तदनुरूपी अन्तरराष्ट्रीय लेखा मानक (आई ए एस) 31 'संयुक्त उद्यमों में हित' तथा अन्तरराष्ट्रीय लेखा मानक बोर्ड द्वारा जारी एस आई सी 13 'संयुक्त रूप से नियंत्रित प्रतिष्ठान-उद्यमियों द्वारा गैर मौद्रिक अंशदान' के बीच यदि कोई अंतर हो तो उन्हें स्पष्ट किया जाए।

अन्तरराष्ट्रीय लेखा मानक (आई ए एस) 31 संयुक्त उद्यमों में हित के साथ तुलना

1. अन्तरराष्ट्रीय लेखा मानक (आई ए एस) 31 में दिये गये के संक्रमणकालीन प्रावधान भारतीय लेखा मानक (इंड ए एस) 31 में इस आशय से नहीं दिये गये हैं क्योंकि भारतीय लेखा मानकों से संबंधित सभी संक्रमणकालीन प्रावधान जहां भी उचित समझा गया, अन्तरराष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग मानक ('आई एफ आर एस 1') 'अन्तरराष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग मानकों' का प्रथमवार अंगीकरण के अनुरूप भारतीय लेखा मानकों 101 'भारतीय लेखा मानकों की प्रथमवार अंगीकरण' में सम्मिलित कर दिये गये हैं।
2. मौजूदा कानूनों में प्रयुक्त शब्दावली से भिन्न शब्दावली का प्रयोग किया गया है उदाहरणतया, शब्दों 'वित्तीय स्थिति का विवरण' के स्थान पर शब्द 'तुलन-पत्र' और शब्दों 'व्यापक आय का विवरण' के स्थान पर शब्दों 'लाभ-हानि विवरण' प्रयोग किया गया है।
3. चूंकि कंपनी अधिनियम 1956 म्यूचल फंडों, यूनिट ट्रस्टों और निवेश संबद्ध बीमा निधियों (फंडों) सहित इसी प्रकार के प्रतिष्ठानों पर लागू नहीं होता अतः इस प्रकार के प्रतिष्ठानों पर यह मानक (इंड ए एस) 31 लागू नहीं होता है। अतः अन्तरराष्ट्रीय लेखा मानक (आई ए एस) 31 का अनुच्छेद संख्या 1 (ख) भारतीय लेखा मानक (इंड ए एस) 31 से हटा दिया गया है। फिर भी, भारतीय लेखा मानक (इंड ए एस) 31 में अनुच्छेद संख्या 1 (ख) को इस आशय से जारी रखा गया है ताकि अन्तरराष्ट्रीय लेखा मानक 31 के साथ उसकी अनुच्छेद संख्याओं से क्रमबद्धता बनी रहे।
4. चूंकि भारतीय लेखा मानकों की प्रयोज्यता अथवा छूट कंपनी अधिनियम और उसके अंतर्गत बनाये गये नियमों द्वारा अधिशासित होती है अतः इस लेखा मानक (अर्थात् इंड ए एस 31) से उप-अनुच्छेद 2 (ख) और (ग) तथा 6 अनुच्छेद हटा दिये गये हैं। फिर भी, अनुच्छेद संख्या 6 को भारतीय लेखा मानक 31 में इस आशय से रहने दिया गया है ताकि अन्तरराष्ट्रीय लेखा मानक 31 के साथ उसकी अनुच्छेद संख्याओं की क्रमबद्धता बनी रहे।
5. अन्तरराष्ट्रीय लेखा मानक बोर्ड (आई ए एस बी) द्वारा अनुच्छेद 44 हटा दिया गया है। लेकिन, भारतीय लेखा मानक 31 में यह अनुच्छेद संख्या इस आशय से जारी रखी गयी है ताकि अन्तरराष्ट्रीय लेखा मानक 31 के साथ उसकी अनुच्छेद संख्याओं से क्रमबद्धता बनी रहे।

भारतीय लेखा मानक (इंड ए एस) 40

निवेश सम्पत्ति

(इस भारतीय लेखा-मानक में मोटे टाइप व सामान्य टाइप में अनुच्छेद हैं। इन दोनों तरह के अनुच्छेदों का समान प्राधिकार है। मोटे टाइप में अनुच्छेद, मुख्य सिद्धान्तों के सूचक हैं।)

उद्देश्य:

1. इस भारतीय लेखा मानक का उद्देश्य निवेश सम्पत्ति का लेखा व्यवहार तथा सम्बंधित प्रकटन अपेक्षाओं का निर्धारण करना है।

कार्य-क्षेत्र:

2. यह मानक निवेश सम्पत्ति की मान्यता, माप एवं प्रकटन पर लागू होगा।
3. अन्य बातों के साथ-साथ, यह मानक पट्टाधारी के वित्तीय विवरणों में लेखांकित वित्त पट्टा के अन्तर्गत धारित निवेश सम्पत्ति हित का वित्तीय विवरण में माप तथा पट्टादाता वित्तीय विवरण में परिचालित पट्टा के अन्तर्गत पट्टाधारी को प्रदान निवेश सम्पत्ति के माप पर लागू होता है। यह मानक भारतीय लेखा मानक 17 पट्टा में व्याप्त मामलों पर लागू नहीं होता है जिनमें निम्नलिखित सम्मिलित हैं -
 - (क) पट्टों का वित्तीय पट्टों अथवा परिचालन पट्टों के रूप में वर्गीकरण।
 - (ख) निवेश सम्पत्ति से पट्टा आय की मान्यता [भारतीय लेखा मानक 18 राजस्व को भी देखें]
 - (ग) एक परिचालन पट्टा के रूप में लेखांकित पट्टा के अन्तर्गत सम्पत्ति हित के पट्टाधारी के वित्तीय विवरण का माप।
 - (घ) एक वित्तीय पट्टा में पट्टादाता के अपने निवल निवेश के वित्तीय विवरण में माप;
 - (ङ) बिक्री तथा लीज वापसी (लीज बैक) सम्बंधी लेन-देनों (सौदों) का लेखांकन; तथा
 - (च) वित्तीय पट्टा तथा परिचालन पट्टा के बारे में प्रकटन
4. यह मानक निम्नलिखित पर लागू नहीं होता :-
 - (क) कृषि-कार्य से सम्बंधित जैविक आस्तियां [देखें भारतीय लेखा मानक 41 'कृषि' ¹]; और

¹ भारतीय लेखा मानक 41 'कृषि' तैयार किया जा रहा है।

- (ख) खनिज अधिकार तथा खनिज कोष (रिजर्व) जैसे तेल, प्राकृतिक गैस तथा इसी प्रकार के गैर पुनरुत्पादक संसाधन।

परिभाषाएं:

5. इस मानक में निर्दिष्ट निम्नलिखित शब्दावली यहां विनिर्दिष्ट अर्थों में उपयोग की गयी है : -
अग्रणीत (कैरिंग) राशि वह राशि है जिस पर एक सम्पत्ति को तुलन पत्र में मान्यता दी जाती है।

लागत निर्माण अथवा अधिग्रहण के समय एक सम्पत्ति के अधिग्रहण के लिए दी गयी नकद अथवा नकद-समतुल्य राशि है अथवा अन्य प्रतिफल का उचित मूल्य है, अथवा जहां पर लागू हो उस सम्पत्ति से जुड़ी वह राशि है जिसे अन्य लेखामानकों द्वारा, उदाहरणतया, भारतीय लेखा मानक 102 शेयर-आधारित भुगतान की विशिष्ट अपेक्षाओं के अनुसार आरंभ में मान्यता दी गयी है।

उचित मूल्य वह राशि है जिस पर एक सम्पत्ति का स्वतंत्र लेन-देन के रूप में ज्ञानवान एवं इच्छुक पक्षों के बीच विनिमय किया जा सके।

निवेश सम्पत्ति से अभिप्रायः, निम्नलिखित के उपयोग की बजाय, किराया अर्जित करने अथवा पूंजी की वृद्धि करने अथवा दोनों के लिए (स्वामी के द्वारा अथवा वित्तीय पट्टा के अन्तर्गत पट्टाधारी के द्वारा) धारित सम्पत्ति (जमीन अथवा एक भवन अथवा भवन का हिस्सा अथवा दोनों) से है।

- (क) वस्तुओं अथवा सेवाओं के उत्पादन अथवा आपूर्ति अथवा प्रशासकीय प्रयोजनों के उपयोग में लायी जाने वाली सम्पत्ति; और

- (ख) व्यवसाय के सामान्य व्यवहार में बिक्री।

स्वामी द्वारा ग्रहीत सम्पत्ति से अभिप्राय उस सम्पत्ति से है जो वस्तुओं या सेवाओं के उत्पादन अथवा आपूर्ति अथवा सेवाओं अथवा प्रशासकीय प्रयोजन में उपयोग के लिए (स्वामी के द्वारा अथवा वित्तीय पट्टा के अन्तर्गत पट्टाधारी के द्वारा) धारित है।

6. [देखिये परिशिष्ट 1]

7. निवेश सम्पत्ति को किराया अर्जित करने अथवा पूंजी की वृद्धि के लिए अथवा दोनों के लिए धारित किया जाता है। अतः एक निवेश सम्पत्ति एक प्रतिष्ठान द्वारा धारित अन्य सम्पत्तियों से स्वतंत्र नकद प्रवाह को सृजित करती है। इससे स्वामी (मालिक) द्वारा ग्रहीत सम्पत्ति और निवेश सम्पत्ति में अंतर स्पष्ट होता है। वस्तुओं अथवा सेवाओं के उत्पादन अथवा आपूर्ति (अथवा प्रशासकीय प्रयोजन के लिए) सम्पत्ति का उपयोग नकद प्रवाहों को सृजित करता है जो न केवल सम्पत्ति से जुड़ा है परन्तु उत्पादन अथवा आपूर्ति प्रक्रिया में प्रयुक्त अन्य सम्पत्तियों से भी जुड़ा है। भारतीय लेखा मानक 16 सम्पत्ति, संयंत्र एवं उपस्कर स्वामी द्वारा ग्रहीत सम्पत्ति पर लागू होता है।

8. निवेश-सम्पत्ति के निम्नलिखित उदाहरण हैं :—

- (क) व्यवसाय के सामान्य व्यवहार में जमीन को अल्पकालीन बिक्री की बजाय दीर्घकालीन पूंजी वृद्धि के लिए धारित
- (ख) जमीन को वर्तमान में गैर निर्धारित भविष्य में उपयोग के लिए धारित किया है (यदि एक प्रतिष्ठान ने यह निर्धारित नहीं किया है कि यह जमीन को स्वामी गृहीत सम्पत्ति अथवा व्यापार के सामान्य व्यवहार में अल्पकालीन बिक्री के लिए उपयोग करेगा तो जमीन को पूंजी वृद्धि के लिए धारित माना जाएगा।
- (ग) प्रतिष्ठान के स्वामित्व में (अथवा वित्तीय पट्टा के अन्तर्गत प्रतिष्ठान द्वारा धारित) एक भवन तथा एक अथवा एक-से अधिक परिचालन पट्टा के अन्तर्गत पट्टा पर धारित एक भवन।
- (घ) भवन जो खाली है परन्तु एक अथवा एक-से अधिक परिचालन पट्टा के अन्तर्गत पट्टे पर देने के लिए रखा है।
- (ङ) सम्पत्ति जिसे भविष्य में निवेश सम्पत्ति के रूप में प्रयुक्त करने के लिए निर्मित अथवा विकसित किया है।

9. निम्नलिखित उदाहरणों में वे मदें दी गयी हैं जो कि निवेश सम्पत्ति नहीं हैं। अतः, इन्हें इस मानक के कार्यक्षेत्र से बाहर रखा गया है:

- (क) व्यवसाय के सामान्य व्यवहार में बिक्री अथवा इस प्रकार के प्रयोजन (बिक्री) हेतु निर्माणाधीन अथवा विकास प्रक्रिया में सम्पत्ति [देखें भारतीय लेखा मानक 2 सूचीवद्ध सामान (इन्वेंटरी)] उदाहरण के लिए, एक सम्पत्ति को केवल इस प्रयोजन के लिए अधिग्रहीत किया गया है कि उसे निकट भविष्य के बाद, विकसित करके और पुनः बिक्री द्वारा निपटाया जाएगा।
- (ख) तृतीय पक्ष की ओर से निर्मित अथवा विकसित की जा रही सम्पत्ति [देखें भारतीय लेखा मानक 11 निर्माण संविदाएं]
- (ग) स्वामी द्वारा ग्रहीत सम्पत्ति [देखिए भारतीय लेखा मानक 16] जिसमें (अन्य बातों के साथ-साथ) भविष्य के उपयोग के लिए स्वामी द्वारा ग्रहीत सम्पत्ति के रूप में सम्मिलित है। भविष्य में विकास के लिए और बाद में स्वामी द्वारा ग्रहीत सम्पत्ति, कर्मचारियों द्वारा ग्रहीत सम्पत्ति (चाहे कर्मचारी बाजार दर पर किराया का भुगतान करते हैं अथवा नहीं) तथा निपटान की प्रतीक्षा में स्वामी द्वारा ग्रहीत स्वामी गृहीत सम्पत्ति।
- (घ) [देखिये परिशिष्ट 1]
- (ङ) सम्पत्ति जिसे वित्तीय पट्टा के अन्तर्गत एक अन्य प्रतिष्ठान को पट्टे पर दिया गया है।

10. कुछ सम्पत्तियां ऐसी भी हो सकती हैं जिनका एक भाग किराया अर्जित करने अथवा पूंजी वृद्धि के लिए धारित किया जाता हो तथा एक अन्य भाग वस्तुओं या सेवाओं के उत्पादन अथवा आपूर्ति अथवा प्रशासकीय उपयोग के लिए धारित किया जाता हो। यदि इन भागों को पृथक रूप से बेचा जाता है (अथवा वित्त पट्टे के अन्तर्गत पृथक रूप से पट्टे पर दिया जाता है), एक प्रतिष्ठान इन भागों का लेखा भी पृथक रूप से करता है। यदि इन भागों को पृथक रूप से बेचा नहीं जा सकता हो, सम्पत्ति तब भी निवेश सम्पत्ति होगी यदि उसका एक तुच्छ भाग वस्तुओं अथवा सेवाओं के उत्पादन अथवा की आपूर्ति अथवा प्रशासकीय प्रयोजन के उपयोग के लिए धारित किया हो।

11. कुछ मामलों में, एक प्रतिष्ठान ग्रहीत सम्पत्ति के निवासियों को सहायक सेवाएं भी प्रदान करता है। ऐसे में, यदि सेवा पूरी व्यवस्था में तुच्छ है, तो वह प्रतिष्ठान इस प्रकार की सम्पत्ति को निवेश सम्पत्ति मानता है। इसका उदाहरण है, जब एक कार्यालय भवन का स्वामी इसके पट्टाधारियों को, जिनके अधिकार में भवन है, सुरक्षा तथा अनुरक्षण (रखरखाव) सम्बंधी सेवाएं प्रदान करता है।
12. अन्य मामलों में, जब प्रदान की गयी सेवा महत्वपूर्ण होती है, उदाहरण के लिए जैसे यदि प्रतिष्ठान एक होटल का स्वामी है और उसका प्रबन्ध भी वही करता है, अतिथियों को प्रदान की जाने वाली सेवाएं सम्पूर्ण व्यवस्था के लिए चूंकि महत्वपूर्ण हैं अतः वह स्वामी प्रबन्धित होटल निवेश सम्पत्ति की बजाय स्वामी ग्रहीत सम्पत्ति है।
13. यह निर्धारित करना कठिन हो सकता है कि सहायक सेवाएं इतनी महत्वपूर्ण हैं कि एक सम्पत्ति निवेश सम्पत्ति की अहर्ता प्राप्त नहीं कर पाती है। उदाहरण के लिए, जैसे कि होटल का स्वामी एक प्रबन्धन-संविदा के अन्तर्गत अपने कुछ उत्तरदायित्व तृतीय पक्ष को अन्तरित कर देता है। इस प्रकार की संविदा की शर्तें काफी हद तक अलग-अलग हो सकती हैं। एक क्रम के अंत में, स्वामी की स्थिति एक निष्क्रिय निवेशक तक सीमित हो सकती है। क्रम के दूसरे अंत में, स्वामी मात्र दैनिक कार्यों को आउटसोर्स कर सकता है जबकि होटल के परिचालन द्वारा सृजित नकद प्रवाहों में परिवर्तन उसी के नियंत्रण में रहते हैं।
14. क्या सम्पत्ति निवेश सम्पत्ति के रूप में अहर्ता प्राप्त करती है इसके निर्धारण के लिए विवेक की आवश्यकता रहती है। प्रतिष्ठान एक मानदंड को विकसित करता है ताकि यह निवेश सम्पत्ति की परिभाषा तथा अनुच्छेद 7-13 में दिये गये मार्गदर्शन के अनुसार निरन्तर रूप से उस विवेक का उपयोग करता है। अनुच्छेद 75 (ग) के अनुसार, प्रतिष्ठान उस मानदंड को प्रकट करेगा जब वर्गीकरण करना कठिन हो।
15. कुछ मामलों में, एक स्वामी के पास सम्पत्ति का स्वामित्व है जिसे वह अपने मूल प्रतिष्ठान अथवा अनुषंगी प्रतिष्ठान को पट्टे पर देता है तथा सम्पत्ति मूल अथवा अनुषंगी द्वारा ग्रहीत में है। सम्पत्ति समेकित वित्तीय विवरण में निवेश सम्पत्ति के रूप में अहर्ता प्राप्त नहीं करता है क्योंकि वह सम्पत्ति समूह के दृष्टिकोण से स्वामी अधिगृहीत है। यद्यपि, प्रतिष्ठान के दृष्टिकोण से वह सम्पत्ति जिसके स्वामित्व में है, एक निवेश सम्पत्ति है यदि यह अनुच्छेदों में दी गयी परिभाषा को पूरा करती है। इसलिए, पट्टाकर्ता सम्पत्ति को व्यक्तिगत वित्तीय विवरण में निवेश सम्पत्ति के रूप में लेखांकित करता है।

मान्यता

16. निवेश सम्पत्ति को एक आस्ति के रूप में मान्यता दी जाती है जब तथा केवल जब :-
 - (क) यह संभव है कि निवेश सम्पत्ति से जुड़े भावी आर्थिक लाभ प्रतिष्ठान को प्रवाहित होंगे; तथा
 - (ख) निवेश सम्पत्ति की लागत को विश्वसनीय रूप से मापा जा सकता है।
17. एक प्रतिष्ठान इस मान्यता सिद्धांत के अन्तर्गत, सभी निवेश सम्पत्ति लागतों को उसी समय मान्यता देता है जब इन लागतों पर व्यय खर्च होता है। इन लागतों में, आरंभ में एक निवेश

सम्पत्ति को अधिग्रहीत करने में व्यय की गयी लागत तथा बाद में उस सम्पत्ति में जोड़ने, उसके एक भाग के प्रतिस्थानापन्न अथवा एक सम्पत्ति की सेवा में उत्पन्न लागतें सम्मिलित हैं।

18. अनुच्छेद 16 में दिये गये मान्यता सिद्धांत के अन्तर्गत, एक प्रतिष्ठान एक निवेश सम्पत्ति की अग्रणीत राशि में इस प्रकार की सम्पत्ति की प्रतिदिन सर्विसिंग की लागत को मान्यता नहीं देता है। अपितु इन लागतों को जैसी भी खर्च हुई, लाभ अथवा हानि के रूप में मान्यता दी जाती है। प्रतिदिन सर्विसिंग की लागत मुख्यतः मजदूरी तथा उपभोग की लागतें हैं जिनमें छोटे पुर्जों की लागतें सम्मिलित हो सकती हैं। इन व्ययों का प्रयोजन को प्रायः सम्पत्ति की 'मरम्मत तथा अनुरक्षण' के रूप में वर्णित किया जाता है।
19. निवेश सम्पत्तियों के कुछ भाग प्रतिस्थानापन्न रूप से अधिग्रहीत किया जा सकते हैं। उदाहरण के लिए, आंतरिक दीवारें मूल दीवारों का प्रतिस्थानापन्न हो सकती हैं। मान्यता सिद्धांत के अन्तर्गत, एक प्रतिष्ठान निवेश सम्पत्ति की अग्रणीत (कैरिंग) राशि में लागत के उत्पन्न होने के समय विद्यमान निवेश सम्पत्ति के हिस्से के प्रतिस्थानापन्न की लागत को मान्यता देता यदि मान्यता मानदंड पूरा होता हो। वे भाग जिनका प्रतिस्थानापन्न किया है उनकी अग्रणीत राशि की मान्यता इस मानक के गैर मान्यता प्रावधान के अनुसार समाप्त कर दी जाती है।

मान्यता पर माप

20. एक निवेश सम्पत्ति को आरंभ में उसकी लागत पर मापा जायगा। लेनदेनों (सौदा) की लागत आरंभ माप में सम्मिलित होंगी।
21. क्रय की गयी निवेश सम्पत्ति की लागत इसकी क्रय कीमत तथा सीधे रूप से जुड़े किसी भी व्यय से मिलकर बनती है। सीधे रूप से जुड़े व्यय में सम्मिलित हैं, उदाहरण के लिए, कानूनी सेवाओं के लिए पेशेवर शुल्क, सम्पत्ति हस्तांतरण कर तथा अन्य लेनदेन लागतें।
22. [देखिये परिशिष्ट 1]
23. निवेश सम्पत्ति की लागत निम्नलिखित द्वारा बढ़ायी नहीं जाती :-
 - (क) स्टार्ट अप लागतें (प्रबन्धन द्वारा ऐच्छिक तरीके से परिचालन के समर्थ सम्पत्ति को लाने के लिए जब तक वे आवश्यक न हों)।
 - (ख) जब तक निवेश सम्पत्ति अधिभोग या नियोजित स्तर प्राप्त करने से पूर्व की परिचालन सम्बंधी हानियां,
 - (ग) सम्पत्ति के निर्माण अथवा विकास में नष्ट सामग्री, श्रम अथवा अन्य संसाधनों की व्यय की गयी असामान्य राशि।
24. यदि एक निवेश सम्पत्ति के लिए भुगतान को आस्थगित किया जाता है, इसकी लागत नकद कीमत समतुल्य है। इस राशि तथा कुल भुगतान के बीच अंतर को ऋण (क्रेडिट) की अवधि के ब्याज व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है।

25. एक पदों के अन्तर्गत धारित तथा निवेश सम्पत्ति के रूप में वर्गीकृत एक सम्पत्ति हित की आरंभिक लागत भारतीय लेखा मानक 17 के अनुच्छेद 20 के द्वारा वित्त पदों के लिए निर्धारित होगी, अर्थात् सम्पत्ति के उचित मूल्य तथा न्यूनतम पदों भुगतान के वर्तमान मूल्य में से, जो भी राशि कम है, उस पर आस्ति को मान्यता दी जायगी। एक समतुल्य राशि को उसी अनुच्छेद के अनुसार देयता के रूप में मान्यता दी जायगी।
26. एक पदों के लिए किसी प्रीमियम के भुगतान को इस प्रयोजन के लिए न्यूनतम पदों भुगतान का भाग माना जायगा। अतः इसे सम्पत्ति की लागत में तो सम्मिलित किया जाएगा लेकिन देयता से अलग रखा जाएगा। यदि एक पदों के अन्तर्गत धारित सम्पत्ति हित को निवेश सम्पत्ति के रूप में वर्गीकृत किया गया है, तो वह उचित मूल्य पर लेखांकित मद है न कि अर्न्तनिहित सम्पत्ति। सम्पत्ति हित का उचित मूल्य पर निर्धारण सम्बंधी मार्गदर्शन अनुच्छेद 33-52 में उचित मूल्य मॉडल के अन्तर्गत दिया गया है। वह मार्गदर्शन उचित मूल्य के निर्धारण के लिए भी प्रासंगिक है जब उस मूल्य को आरंभिक मान्यता के प्रयोजनों के लिए लागत के रूप में प्रयुक्त किया है।
27. एक अथवा एक से अधिक निवेश सम्पत्तियों को गैर मौद्रिक सम्पत्ति अथवा सम्पत्तियों अथवा मौद्रिक तथा गैर मौद्रिक सम्पत्तियों के संयोजन के विनिमय में अधिगृहीत किया जा सकता है। निम्नलिखित चर्चा एक गैर मौद्रिक सम्पत्ति का एक अन्य सम्पत्ति के विनिमय के संदर्भ में है परन्तु यह पहले के वाक्य में वर्णित सभी प्रकार के विनिमयों पर लागू होती है। इस प्रकार की एक निवेश सम्पत्ति की लागत को उचित मूल्य पर मापा जाता है जब तक (क) विनिमय लेनदेनों में वाणिज्यिक सार का अभाव हो अथवा (ख) प्राप्त सम्पत्ति अथवा छोड़ी गयी सम्पत्ति का उचित मूल्य को विश्वसनीय रूप से मापा न जा सके। अधिगृहीत सम्पत्ति को इस तरीके से मापा जाता है चाहे यदि एक प्रतिष्ठान छोड़ी गयी सम्पत्ति को तुरंत गैर मान्य न करे। यदि अधिगृहीत सम्पत्ति को उचित मूल्य पर मापा नहीं जाता तो उसकी लागत को छोड़ी गयी सम्पत्ति की अग्रणीत (कैरिंग) राशि पर मापा जाता है।
28. एक प्रतिष्ठान एक हद तक कि लेनदेन के परिणाम के परिणामस्वरूप भविष्य के नकद प्रवाहों में परिवर्तन हो सकता है इस पर विचार करते हुए यह निर्धारित करेगा कि क्या एक विनिमय लेनदेन का कोई वाणिज्यिक सार है। एक विनिमय लेनदेन का वाणिज्यिक सार तब होता है यदि
- (क) प्राप्त सम्पत्ति का नकद प्रवाह का विन्यास (जोखिम, समय तथा राशि) अंतर्गत सम्पत्ति के नकद प्रवाह के विन्यास से भिन्न है, अथवा
 - (ख) विनिमय के परिणामस्वरूप लेनदेनों के परिवर्तनों से प्रभावित प्रतिष्ठान के परिचालनों के एक भाग का प्रतिष्ठान विशिष्ट मूल्य, और
 - (ग) उपर्युक्त (क) अथवा (ख) में अंतर विनिमय सम्पत्तियों के उचित मूल्य के सापेक्ष में महत्वपूर्ण है।
- यह निर्धारित करने के प्रयोजन के लिए कि क्या एक विनिमय लेनदेन का वाणिज्यिक सार है, लेनदेन द्वारा प्रभावित प्रतिष्ठान के प्रचालन को भाग का प्रतिष्ठान विशिष्ट मूल्य करोपरांत नकद-प्रवाह को परिलक्षित करेगा। इन विश्लेषणों को परिणाम प्रतिष्ठान द्वारा कोई विस्तृत गणना किये बिना ही स्पष्ट हो सकते हैं।
29. एक सम्पत्ति का उचित मूल्य, जिसके लिए तुलना योग्य बाजार लेनदेन विद्यमान नहीं हैं, विश्वसनीय रूप से मापा जा सकता है यदि (क) तर्कसंगत उचित मूल्य के अनुमानों की रेंज में

परिवर्तनशीलता उस सम्पत्ति के लिए महत्वपूर्ण नहीं है, अथवा, (ख) रेंज के अंदर विभिन्न अनुमानों की संभावना का उचित रूप से निर्धारण और उचित मूल्य के अनुमान में प्रयुक्त किया जा सकता है। यदि प्रतिष्ठान विश्वसनीय रूप से प्राप्त सम्पत्ति अथवा छोड़ी गयी सम्पत्ति का उचित मूल्य निर्धारित करने में समर्थ है, तब छोड़ी गयी सम्पत्ति के उचित मूल्य को लागत की माप में प्रयुक्त किया जाता है जब तक प्राप्त सम्पत्ति का उचित मूल्य साफ तौर पर स्पष्ट न हो।

मान्यता के पश्चात् माप

लेखनीति

30. एक प्रतिष्ठान अपनी समस्त निवेश संपत्ति के लिए अनुच्छेद 56 में निर्धारित लागत मॉडल के रूप में लेखा नीति को अपनाएगा।
31. [देखिये परिशिष्ट 1]।
32. यह मानक सभी प्रतिष्ठानों से यह अपेक्षा करता है कि प्रकटन के प्रयोजन के लिए (बेशक उनसे लागत मॉडल को प्रयोग की अपेक्षा है) निवेश सम्पत्ति के उचित मूल्य का निर्धारण करें। एक प्रतिष्ठान को इस बात के लिए प्रोत्साहित किया जाता है कि वह एक स्वतंत्र मूल्यांकक से, जिसके पास मान्यता प्राप्त तथा प्रासंगिक व्यवसायिक योग्यता है तथा स्थान तथा मूल्यांकन की जाने वाली निवेश सम्पत्ति का हाल का अनुभव है, मूल्यांकन के आधार पर निवेश सम्पत्ति के उचित मूल्य का निर्धारण करे परन्तु उसके लिए यह आवश्यक नहीं है कि वह ऐसा अवश्य ही करे।
- 32(क) - (ग) [देखिये परिशिष्ट 1]

उचित मूल्य निर्धारण

33. - 35. [देखिये परिशिष्ट 1]।

36. निवेश सम्पत्ति का उचित मूल्य वह कीमत है जिस पर स्वतंत्र लेनदेन (अनुच्छेद 5) के रूप में ज्ञानवान एवं इच्छुक पक्षों के बीच सम्पत्ति का विनिमय किया जा सकता है। उचित मूल्य विशेष रूप से विशेष शर्तों अथवा परिस्थितियों, जैसे विशेष प्रकार का वित्त पोषण, बिक्री तथा पट्टे की वापसी व्यवस्था, बिक्री से जुड़े किसी पक्ष के द्वारा प्रदान विशेष व्यवहार अथवा रियायत के द्वारा घटायी गयी अथवा बढ़ायी गयी अनुमानित कीमत को अलग करता है।
37. एक प्रतिष्ठान लेनदेन लागत में, जो बिक्री अथवा अन्य निपटान पर खर्चा होता है, किसी कटौती के बिना उचित मूल्य का निर्धारण करता है।
38. निवेश सम्पत्ति का उचित मूल्य रिपोर्टिंग अवधि के अंत की बाजार स्थितियों को परिलक्षित करेगा।
39. उचित मूल्य दी गयी तिथि का समय निर्दिष्ट मूल्य है। क्योंकि बाजार की परिस्थितियां बदल सकती हैं अतः उचित मूल्य की राशि, जिसका किसी अन्य समय के लिए अनुमान लगाया गया है, गलत अथवा अनुपयुक्त हो सकती है। उचित मूल्य की परिभाषा यह भी मानती है कि कीमत में

किसी परिवर्तन के बिना एक साथ विनिमय तथा बिक्री के लिए संविदा की पूर्णता ज्ञानवान एवं इच्छुक पक्षों के बीच एक स्वतंत्र लेनदेन में की जा सकती है यदि विनिमय तथा पूर्णता एक-साथ नहीं भी हैं।

40. निवेश सम्पत्ति का उचित मूल्य, अन्य बातों के साथ-साथ, वर्तमान पट्टा से किराया आय तथा उचित तथा समर्थनयोग्य पूर्वधारणा को परिलक्षित करता है जो प्रतिनिधित्व करता है कि ज्ञानवान एवं इच्छुक पक्ष वर्तमान परिस्थिति के प्रकाश में भविष्य पट्टा से किराया आय के बारे में क्या मानते हैं। यह भी परिलक्षित करता है कि इसी आधार पर, कोई नकद बाह्य प्रवाह (किराया भुगतान तथा अन्य बाह्य प्रवाह सहित) जिसकी सम्पत्ति के सम्बंध में अपेक्षा की जा सकती है। उन में कुछ बाह्य प्रवाह देयता के रूप में परिलक्षित किये जाते हैं जबकि दूसरे वे बाह्य प्रवाह हैं जिन्हें बाद की तिथि तक वित्तीय विवरणों में मान्यता नहीं दी जाती है (उदाहरणतः आवधिक भुगतान जैसे कि आकस्मिक किराये)
41. [देखिये परिशिष्ट 1]
42. उचित मूल्य की परिभाषा 'ज्ञानवान एवं इच्छुक पक्षों' को संदर्भित करती है। इस संदर्भ में, ज्ञानवान का अर्थ है कि दोनों इच्छुक क्रेता तथा इच्छुक विक्रेता निवेश सम्पत्ति की प्रकृति तथा इसकी विशेषता, इसका वास्तविक तथा संभावित उपयोग और रिपोर्टिंग अवधि के अंत में बाजार की स्थिति के बारे में उचित रूप से परिचित हैं। एक इच्छुक क्रेता प्रेरित है परन्तु क्रय के लिए मजबूर नहीं है। क्रेता किसी भी कीमत पर क्रय के लिए न तो अधिक उत्सुक है और न ही कृतसंकल्प है। काल्पनिक क्रेता ज्ञानवान व इच्छुक क्रेताओं तथा विक्रेताओं के बाजार की सामान्य कीमत से अधिक कीमत का भुगतान नहीं करेगा।
43. एक इच्छुक विक्रेता न तो अधिक उत्सुक है और न ही इस दबाव में कि वर्तमान बाजार स्थिति में उचित समझे जाने वाली कीमत से नीचे अथवा किसी भी कीमत पर बेचने के लिए तैयार है। इच्छुक विक्रेता सर्वोत्तम उपलब्ध कीमत के लिए बाजार शर्तों पर निवेश सम्पत्ति को बेचने के लिए प्रेरित है। वास्तविक निवेश सम्पत्ति स्वामी की तथ्यात्मक परिस्थिति प्रतिफल का भाग नहीं है क्योंकि इच्छुक विक्रेता एक काल्पनिक स्वामी (मालिक) है। (उदाहरणतः एक इच्छुक विक्रेता वास्तविक निवेश स्वामी की वास्तविक कर परिस्थिति को ध्यान में नहीं रखेगा।)
44. उचित मूल्य की परिभाषा स्वतंत्र लेन देन का संदर्भ करती है। स्वतंत्र लेनदेन उन पक्षों के बीच है जिनका परस्पर कोई विशेष सम्बंध नहीं है और इन लेनदेनों की कीमत बाजार परिस्थितियों से असामान्य नहीं है। लेन-देने स्वतंत्र रूप से कार्य कर रहे असम्बंध पक्षों के बीच माना गया है।
45. उचित मूल्य का सर्वोत्तम साक्ष्य उसी स्थान तथा परिस्थिति में है जो इसी प्रकार की सम्पत्ति के लिए सक्रिय बाजार में वर्तमान कीमतों द्वारा दिया जाता है और यह उसी प्रकार के पट्टा तथा अन्य संविदाओं के तहत है। एक प्रतिष्ठान सम्पत्ति की प्रकृति, स्थान अथवा स्थिति अथवा सम्पत्ति से सम्बंधित पट्टा तथा अन्य संविदाओं की संविदात्मक शर्तों में किसी अंतर की पहचान का ध्यान रखता है।
46. अनुच्छेद 45 में यथावर्णित एक प्रकार के सक्रिय बाजार में वर्तमान कीमतों के अभाव में, एक प्रतिष्ठान विविध स्रोतों से प्राप्य सूचना पर विचार करता है, जिसमें निम्नलिखित सम्मिलित हैं :

- (क) उन अंतर्गत्तों को परिलक्षित करने के समायोजन के साथ, विभिन्न प्रकृति, स्थिति अथवा स्थान (अथवा विभिन्न पट्टा अथवा अन्य संविदाओं के अन्तर्गत) की सम्पत्तियों के लिए एक सक्रिय बाजार में वर्तमान कीमतें ;
- (ख) कम सक्रिय बाजार में इसी प्रकार की सम्पत्ति की हाल की कीमत उन कीमतों पर उत्पन्न लेनदेनों की तिथि से आर्थिक स्थिति में किसी परिवर्तन को परिलक्षित करने की समायोजन सहित ; और
- (ग) किसी विद्यमान पट्टा और अन्य ठेके तथा (जहां पर संभव है) बाहरी साक्ष्य जैसे इसी तरह के स्थान तथा स्थिति में इसी प्रकार की सम्पत्ति के लिए वर्तमान बाजार किराया द्वारा समर्थित, तथा नकदी प्रवाह की राशि तथा समय में अनिश्चितता की वर्तमान बाजार निर्धारण को परिलक्षित करने वाली बट्टा दर का उपयोग कर भविष्य नकद प्रवाह के विश्वसनीय अनुमान पर आधारित बट्टागत नकद प्रवाह अनुमान ।
47. कुछ मामलों में, पिछले अनुच्छेद में सूचीबद्ध विभिन्न स्रोत निवेश सम्पत्ति के उचित मूल्य के बारे में अलग निष्कर्षों को सुझाव दे सकते हैं। एक प्रतिष्ठान उचित मूल्य के अनुमानों की श्रृंखला के अंदर सर्वाधिक विश्वसनीय अनुमान पर पहुँचने के लिए उन अंतर्गत्तों के कारणों पर विचार कर सकता है।
48. अपवादस्वरूप मामलों में, स्पष्ट साक्ष्य है जब प्रतिष्ठान पहले एक निवेश सम्पत्ति को अधिग्रहीत करता है (अथवा जब एक मौजूदा सम्पत्ति उपयोग में परिवर्तन के पश्चात् निवेश सम्पत्ति बन जाती है) तर्कसंगत उचित मूल्य अनुमानों की रेंज में परिवर्तनशीलता इतनी अधिक होगी तथा विभिन्न परिणामों की संभाव्यता का मूल्यांकन करना इतना कठिन होगा कि उचित मूल्य का एकल अनुमान की उपयोगिता निरर्थक हो जाएगी । इससे यह संकेत मिलता है कि सम्पत्ति का उचित मूल्य निरन्तर आधार पर विश्वसनीय रूप से निर्धारणयोग्य नहीं होगा (अनुच्छेद 53 देखें)
49. उचित मूल्य उपयोग में मूल्य से भिन्न है जैसा कि लेखामानक 36 *आस्तियों की क्षतिग्रस्तता* में परिभाषित है। उचित मूल्य ज्ञानवान एवं इच्छुक क्रेताओं तथा विक्रेताओं के ज्ञान व अनुमान को परिलक्षित करता है। इसके विपरीत, उपयोग में मूल्य प्रतिष्ठान के अनुमानों को परिलक्षित करता है जिसमें कारकों के प्रभाव भी सम्मिलित हैं । ये कारक प्रतिष्ठान-विशेष हो सकते हैं और प्रायः सभी प्रतिष्ठानों पर लागू नहीं होते हैं । उदाहरण के लिए, उचित मूल्य निम्नलिखित किसी भी कारक को परिलक्षित नहीं करता क्योंकि ये कारक सामान्यतः ज्ञानवान एवं इच्छुक क्रेताओं तथा विक्रेताओं को उपलब्ध नहीं होते हैं:-
- (क) विभिन्न स्थानों में सम्पत्तियों के पोर्टफोलियों के सृजन से प्राप्त अतिरिक्त मूल्य;
- (ख) निवेश सम्पत्ति तथा अन्य आस्तियों के बीच संश्लेषण
- (ग) कानूनी अधिकार अथवा कानूनी प्रतिबंध जो केवल वर्तमान स्वामी तक विशिष्ट हैं ; तथा
- (घ) कर लाभ अथवा कर भार जो वर्तमान स्वामी तक विशिष्ट हैं ।
50. [देखिये परिशिष्ट 1] ।

51. निवेश सम्पत्ति का उचित मूल्य भावी पूंजीगत व्यय को परिलक्षित नहीं करता जो कि सम्पत्ति में सुधार अथवा उसमें वृद्धि करता है तथा वह इस भावी व्यय से सम्बंधित भावी लाभ को परिलक्षित नहीं करता।

52. [देखिये परिशिष्ट 1]

उचित मूल्य को विश्वसनीय रूप से निर्धारण करने में असमर्थता

53. यह खंडन योग्य मान्यता है कि एक प्रतिष्ठान विश्वसनीय रूप से लगातार आधार पर एक निवेश सम्पत्ति के उचित मूल्य का विश्वसनीय रूप में निर्धारण कर सकता है। फिर भी, अपवादस्वरूप मामलों में, स्पष्ट साक्ष्य है कि जब एक प्रतिष्ठान पहले एक निवेश सम्पत्ति को अधिग्रहीत करता है (अथवा जब एक मौजूदा सम्पत्ति उपयोग में परिवर्तन के पश्चात् निवेश सम्पत्ति बन जाती है) तो एक निवेश सम्पत्ति के उचित मूल्य का लगातार आधार पर विश्वसनीय रूप से निर्धारण नहीं हो सकता। ऐसा तभी होता है जब, और केवल जब, बाज़ार के तुलनीय लेनदेन कभी-कभी होते हैं और उचित मूल्य के (उदाहरणतया, जब यह बट्टागत नकदी प्रवाह अनुमानों पर आधारित होता है) वैकल्पिक व विश्वसनीय अनुमान उपलब्ध नहीं होते यदि एक प्रतिष्ठान यह निर्धारित करता है कि निर्माणाधीन निवेश सम्पत्ति के उचित मूल्य का माप विश्वसनीय रूप से नहीं हो सकता लेकिन वह यह आशा करता है कि निर्माण पूरा होने पर वह निर्माण संपत्ति के उचित मूल्य का निर्धारण करेगा जब तक कि उसका उचित मूल्य विश्वसनीय रूप से निर्धारण योग्य बन जाता या फिर निर्माण पूरा हो जाता (इनमें से जो भी स्थिति पहले हो)। यदि एक प्रतिष्ठान निर्धारित करता है कि एक निवेश सम्पत्ति (निर्माणाधीन निवेश सम्पत्ति से भिन्न) के उचित मूल्य का लगातार आधार पर विश्वसनीय रूप से निर्धारण नहीं हो सकता है तो प्रतिष्ठान अनुच्छेद 79 (ड) (i), (ii) व (iii) द्वारा अपेक्षित प्रकटन करेगा।

53क जब एक प्रतिष्ठान निर्माणाधीन निवेश सम्पत्ति को, जिस के लिए पहले उचित मूल्य निर्धारित नहीं किया गया था, उचित मूल्य पर विश्वसनीय रूप से मापने में समर्थ हो जाता है, तो वह उस सम्पत्ति के उचित मूल्य का निर्धारण करेगा। एक बार जब उस सम्पत्ति का निर्माण पूर्ण हो जाता है तो यह माना जाता है कि उचित मूल्य को विश्वसनीय रूप से मापा जा सकता है। यदि अनुच्छेद 53 के अनुसार यह मामला ऐसा नहीं है, तो प्रतिष्ठान अनुच्छेद 79 (ड) (i), (ii) व (iii) द्वारा अपेक्षानुसार प्रकटन करेगा।

53ख निर्माणाधीन निवेश सम्पत्ति के उचित मूल्य को विश्वसनीय रूप से मापा जा सकता है, इस पूर्व धारणा का खंडन केवल आरंभिक मान्यता पर ही किया जा सकता है। एक प्रतिष्ठान जिसने निर्माणाधीन निवेश सम्पत्ति की एक मद को उचित मूल्य पर निर्धारण किया है यह निष्कर्ष नहीं निकाल सकता है कि पूर्ण निवेश सम्पत्ति का उचित मूल्य का निर्धारण विश्वसनीय रूप से नहीं किया जा सकता।

54. अपवादस्वरूप मामलों में जब एक प्रतिष्ठान अनुच्छेद 53 में दिये गये कारण से प्रतिष्ठान अनुच्छेद 79 (ड) (i), (ii) व (iii) द्वारा अपेक्षित प्रकटन के लिए विवश होता है, यह निर्माणाधीन निवेश सम्पत्ति सहित अन्य समस्त निवेश सम्पत्ति को उचित मूल्य पर निर्धारित करेगा। इन मामलों में, यद्यपि प्रतिष्ठान एक निवेश सम्पत्ति के लिए प्रतिष्ठान अनुच्छेद 79 (ड) (i), (ii) व (iii) द्वारा अपेक्षित प्रकटन करता है। तो प्रतिष्ठान बाकी सम्पत्तियों में से प्रत्येक के लिए प्रतिष्ठान अनुच्छेद 79 (ड) द्वारा अपेक्षित प्रकटन के अनुसार उचित मूल्य का निर्धारण जारी रखेगा।

55. यदि एक प्रतिष्ठान ने एक निवेश सम्पत्ति को पहले उचित मूल्य पर निर्धारण किया है यह निपटान तक सम्पत्ति का उचित मूल्य पर निर्धारण जारी रखेगा (अथवा जब तक सम्पत्ति स्वामी द्वारा ग्रहीत सम्पत्ति नहीं बन जाती है अथवा प्रतिष्ठान व्यवसाय के सामान्य व्यवहार में, बाद में बिक्री के लिए सम्पत्ति को विकसित करना आरंभ नहीं कर देता) वेशक बाजार के तुलनीय लेनदेन कभी कभार होते हैं अथवा बाजार की कीमतें तुरंत उपलब्ध नहीं होती।

लागत मॉडल

56. आरंभिक मान्यता के पश्चात्, एक प्रतिष्ठान अपने सभी निवेश सम्पत्तियों को, भारतीय लेखा मानक 105 बिक्री के लिए धारित के रूप में गैर चालू सम्पत्तियाँ तथा बंद परिचालन के अनुसार बिक्री के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत (अथवा बिक्री के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत निपटान समूह में सम्मिलित) का मापदंड पूरा करने के अतिरिक्त, लागत मॉडल के लिए भारतीय लेखा मानक 16 की आवश्यकता के अनुसार मापेगा। वे निवेश सम्पत्तियाँ जो, बिक्री के लिए धारित रूप में वर्गीकृत की गयी हैं (अथवा बिक्री के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत और निपटान समूह में सम्मिलित हैं), मानदंड को पूरा करती हैं उन्हें भारतीय लेखा मानक 105 के अनुसार मापा जायगा।

अन्तरण

57. निवेश सम्पत्ति में अथवा निवेश सम्पत्ति से अन्तरण तब, और केवल तब ही किया जायगा, जब उपयोग में परिवर्तन हो और जिसका निम्नलिखित द्वारा प्रमाण हो :-

- (क) निवेश सम्पत्ति से स्वामी द्वारा ग्रहीत सम्पत्ति में अन्तरण के लिए स्वामी द्वारा अधिभोग का आरंभ;
- (ख) निवेश सम्पत्ति से सूचीबद्ध सामान (इन्वेंट्रीज) में अन्तरण के लिए बिक्री के विचार से विकास का आरंभ;
- (ग) स्वामी द्वारा ग्रहीत सम्पत्ति से निवेश सम्पत्ति में अन्तरण के लिए स्वामी के अधिभोग की समाप्ति; अथवा
- (घ) सूचीबद्ध माल सम्पत्ति (इन्वेंट्रीज) से निवेश सम्पत्ति में अन्तरण के लिए एक अन्य पक्ष के हित में एक परिचालन पट्टा का आरंभ;
- (ङ) [देखिये परिशिष्ट 1]

58. अनुच्छेद 57 (ख) के अनुसार एक प्रतिष्ठान निवेश सम्पत्ति से सूचीबद्ध माल (सम्पत्ति) में तभी और केवल तभी, अन्तरित करता है जब बिक्री के विचार से मद का विकास आरंभ करने के साक्ष्य में सम्पत्ति के उपयोग में परिवर्तन होता है। जब प्रतिष्ठान बिना विकास के निवेश सम्पत्ति के निपटान का निर्णय लेता है तो वह सम्पत्ति का निवेश सम्पत्ति ही मानता है तब तक जब तक इसे गैर मान्य (तुलनेपत्र से हटा न दे) तथा इसे सूचीबद्ध सामान (इन्वेंट्री) के रूप में लेता है। इसी तरह, यदि एक प्रतिष्ठान निवेश सम्पत्ति के रूप में भविष्य के लगातार उपयोग के लिए एक मौजूदा निवेश सम्पत्ति को पुनः विकसित करना आरंभ करता है, तो वह सम्पत्ति एक निवेश

सम्पत्ति रहती है तथा उसे पुनः विक्रय के दौरान स्वामी द्वारा ग्रहीत सम्पत्ति के रूप में पुनः वर्गीकृत नहीं किया जाता ।

59. निवेश सम्पत्ति स्वामी द्वारा अधिग्रहीत सम्पत्ति तथा सूचीबद्ध माल (इंवेन्ट्रीज) के बीच किसी भी अन्तरण से सम्पत्ति की अग्रणीत राशि में परिवर्तन नहीं होता और न ही माप अथवा प्रकटन के प्रयोजन के लिए उस सम्पत्ति की लागत में कोई परिवर्तन होता ।

60.- 65 [देखिये परिशिष्ट 1] ।

निपटान

66. एक निवेश सम्पत्ति का जब निपटान कर दिया जाता है अथवा उसे स्थायी रूप से उपयोग से हटा लिया जाता है तथा इस निपटान से भविष्य में किसी आर्थिक लाभ की उम्मीद नहीं रहती तो उस निवेश सम्पत्ति को गैर मान्य कर दिया जाएगा (तुलनपत्र से हटाया) ।
67. एक निवेश सम्पत्ति का निपटान बिक्री अथवा वित्तीय पट्टे में प्रवेश करके प्राप्त किया जा सकता है। निवेश सम्पत्ति के लिए निपटान की तिथि के निर्धारण के लिए एक प्रतिष्ठान वस्तुओं की बिक्री से राजस्व की मान्यता के लिए भारतीय लेखा मानक 18 के मापदंड को लागू करता है तथा भारतीय लेखा मानक 18 के परिशिष्ट ड में दिये गये सम्बंधित मार्गदर्शन पर विचार करता है। भारतीय लेखा मानक 17 उस निपटान पर लागू होता है जो वित्तीय पट्टे में प्रवेश, बिक्री व लीज बैक द्वारा किया जाता है।
68. अनुच्छेद 16 में वर्णित मान्यता सिद्धांत के अनुसार, यदि एक प्रतिष्ठान एक आस्ति की अग्रणीत राशि में एक निवेश सम्पत्ति के एक भाग के लिए प्रतिस्थापन की लागत को मान्यता देता है, तो यह प्रतिस्थापित भाग की अग्रणीत राशि को गैर मान्य करता है। एक प्रतिस्थापित भाग वह भाग नहीं हो सकता जिसे पृथक रूप से मूल्य हासित किया गया हो । यदि एक प्रतिष्ठान के लिए प्रतिस्थापित भाग की अग्रणीत राशि का निर्धारण करना व्यावहारिक नहीं है, यह प्रतिस्थापन की लागत को प्रतिस्थापित भाग की अधिग्रहण अथवा निर्माण के समय लागत के संकेत के रूप में उपयोग कर सकता है।
69. निवेश सम्पत्ति की निवृत्ति अथवा निपटान से उत्पन्न लाभ अथवा हानि का निर्धारण उसी प्रकार निवल निपटान राशि तथा सम्पत्ति की अग्रणीत राशि के बीच अन्तर का निर्धारण किया जाता है तथा उसकी निवृत्ति अथवा निपटान की अवधि में लाभ अथवा हानि में मान्यता दी जायगी (बशर्ते भारतीय लेखा मानक 17 के अनुसार बिक्री तथा लीज की वापसी पर अन्यथा आवश्यक न हो)
70. निवेश सम्पत्ति के निपटान पर प्राप्य प्रतिफल को आरंभ में उचित मूल्य पर मान्यता दी जाती है। विशेष रूप से, यदि एक निवेश सम्पत्ति के भुगतान को आस्थगित किया जाता है, तो प्राप्त प्रतिफल को आरम्भ में नकद कीमत के समतुल्य पर मान्यता दी जाती है। प्रतिफल की अंकित राशि तथा नकद कीमत समतुल्य के बीच अन्तर को प्रभावी ब्याज तरीके का उपयोग करते हुए भारतीय लेखा मानक 18 के अनुसार ब्याज राजस्व के रूप में मान्यता दी जाती है।
71. एक प्रतिष्ठान भारतीय लेखा मानक 37 या अन्य मानकों, जो भी उचित हो, उन देयताओं पर लागू करता है जिन्हें वह निवेश सम्पत्ति के निपटान के बाद रखता है।

72. क्षतिग्रस्त गुमशुदा या परित्यक्त निवेश सम्पत्ति के लिए तीसरे पक्ष से प्राप्त क्षतिपूर्ति को लाभ या हानि में तभी मान्य किया जाएगा जब कि वह (क्षतिपूर्ति) प्राप्य हो जाती है।
73. निवेश सम्पत्ति की क्षतिग्रस्तता या हानियां, तीसरे पक्षों से सम्बंधित दावे या उनसे प्राप्त क्षतिपूर्ति और स्थानापन्न आस्तियों की बाद की खरीद या निर्माण अलग-अलग आर्थिक घटनाएं हैं और इनका लेखा भी अलग-अलग किया जाता है जो इस प्रकार से किया जाता है :
- (क) निवेश सम्पत्ति की क्षतिग्रस्तता को भारतीय लेखा मानक 36 के अनुसरण में मान्यता दी जाती है ;
 - (ख) निवेश सम्पत्ति की निवृत्ति या निपटान को इस लेखामानक के अनुच्छेद 66-71 के अनुसरण में मान्यता दी जाती है ;
 - (ग) क्षतिग्रस्त, गुमशुदा या परित्यक्त निवेश सम्पत्ति के लिए तीसरे पक्षों से प्राप्त क्षतिपूर्ति को मान्यता लाभ या हानि में तब दी जाती है जब वह प्राप्य होती है।
 - (घ) स्थानापन्न के रूप में बहाल की गयी, खरीदी गयी या निर्मित आस्तियों की लागत का निर्धारण इस मानक के अनुच्छेद 20-29 के अनुसरण में किया जाता है।

प्रकटन

74. नीचे दिये गये प्रकटन भारतीय लेखा मानक 17 में दिये गये प्रकटनों के अतिरिक्त लागू होते हैं। भारतीय लेखा मानक 17 के अनुसरण में निवेश सम्पत्ति के स्वामी किये गये पट्टों के सम्बंध में पट्टाकर्ताओं के प्रकटन प्रदान करता है। एक प्रतिष्ठान वित्तीय पट्टे या परिचालन पट्टे के अन्तर्गत एक निवेश सम्पत्ति को धारित करता है और किये गये पट्टों में वित्तीय पट्टे के मामले में पट्टादाता के प्रकटन और परिचालन पट्टे के मामले में पट्टाकर्ता के प्रकटन प्रदान करता है।
75. एक प्रतिष्ठान निम्नलिखित को प्रकट करेगा ---
- (क) निवेश सम्पत्ति के माप के लिए उसकी लेखानीति ।
 - (ख) [देखिये परिशिष्ट 1]।
 - (ग) जब वर्गीकरण करना कठिन हो, (देखें अनुच्छेद 14), तो निवेश सम्पत्ति, स्वामी द्वारा ग्रहीत सम्पत्ति व व्यवसाय के सामान्य व्यवहार में बिक्री के लिए धारित सम्पत्ति के बीच भेद करने के लिए प्रतिष्ठान कौन से मापदण्ड का प्रयोग करता है ।
 - (घ) वे विधियां व महत्वपूर्ण धारणाएं जो निवेश सम्पत्ति के उचित मूल्य के निर्धारण के लिए प्रयोग में लायी गयी हैं । इसके साथ एक यह विवरण भी दिया जाएगा कि उचित मूल्य का निर्धारण किसी बाजार साक्ष्य के साथ समर्थित है या नहीं या फिर वह अन्य कारकों पर अधिक निर्भर है (प्रतिष्ठान इनका प्रकटन करेगा) क्योंकि सम्पत्ति की प्रकृति कैसी है और बाजार के तुलनीय आंकड़े भी उपलब्ध नहीं हैं ।
 - (ङ) उस सीमा तक जिस पर कि क्या निवेश सम्पत्ति का उचित मूल्य (जैसा कि वित्तीय विवरणों में मापा अथवा प्रकट किया गया है) एक स्वतंत्र मूल्यांकक के द्वारा, जिसके

पास एक मान्यताप्राप्त तथा सम्बंधित व्यावसायिक योग्यता है तथा निवेश सम्पत्ति जिसका मूल्यांकन किया जा रहा है, के स्थान तथा श्रेणी में नवीन अनुभव है, किये गये मूल्यांकन पर आधारित है। यदि नहीं है, तो उस तथ्य को भी प्रकट किया जाएगा।

(च) निम्नलिखित के लिए लाभ अथवा हानि में मान्य राशियां -

- i) निवेश सम्पत्ति से किराये के रूप में आय
- ii) निवेश सम्पत्ति, जिससे अवधि के दौरान किराये के रूप में आय सृजित हुई है, के प्रत्यक्ष परिचालन व्यय (मरम्मत तथा अनुरक्षण सहित); तथा
- iii) निवेश सम्पत्ति जिससे अवधि के दौरान किराया सृजित नहीं किया से उत्पन्न प्रत्यक्ष परिचालन व्यय (मरम्मत तथा अनुरक्षण सहित)
- iv) [देखिये परिशिष्ट 1]

(छ) निवेश सम्पत्ति की वसूली अथवा निपटान की आय व राशि के प्रेषण पर प्रतिबंध की विद्यमानता तथा राशियां ।

(ज) निवेश सम्पत्ति के क्रय, निर्माण अथवा विकास अथवा मरम्मत, अनुरक्षण अथवा वृद्धि के लिए संविदात्मक दायित्व ।

76. - 78. [देखिये परिशिष्ट 1]।

79. अनुच्छेद 75 के द्वारा आवश्यक प्रकटन के अतिरिक्त, एक प्रतिष्ठान निम्नलिखित को प्रकट करेगा :

- (क) प्रयुक्त मूल्य ह्रास तरीके ;
- (ख) उपयोगी जीवन अथवा प्रयुक्त मूल्य ह्रास दरें ;
- (ग) अवधि के आरंभ तथा अंत में सकल अग्रणीत राशि तथा संग्रहीत मूल्य ह्रास (संग्रहीत क्षति हानि के साथ योग) ;
- (घ) अवधि के आरंभ तथा अंत में निम्नलिखित को प्रदर्शित करते हुए निवेश सम्पत्ति की अग्रणीत राशि का मिलान :
 - i) जोड़, अधिग्रहण के परिणामस्वरूप जोड़ तथा एक सम्पत्ति की अग्रणीत राशि में मान्यता बाद के व्यय के परिणामस्वरूप जोड़ का अलग-अलग प्रकटन ;
 - ii) व्यापारिक संयोजन के जरिये अधिग्रहण से परिणामतः जोड़ ;
 - iii) भारतीय लेखा मानक 105 तक के अनुसार बिक्री के लिए धारण के रूप में वर्गीकृत अथवा बिक्री के लिए धारण के रूप में वर्गीकृत निपटान समूह में तथा अन्य निपटान में सम्पत्तियां ;
 - iv) मूल्य ह्रास ;

- v) भारतीय लेखा मानक 36 के अनुसार अवधि के दौरान, मान्य क्षति हानियां तथा उलटायी गयी क्षति हानि की राशि ;
 - vi) एक विभिन्न प्रस्तुति करेंसी में वित्तीय विवरणों के रूपांतरण तथा रिपोर्टिंग प्रतिष्ठान की प्रस्तुति करेंसी में विदेशी परिचालन के रूपांतरण से उत्पन्न निवल विनिमय अंतर ;
 - vii) सूचीबद्ध माल तथा स्वामी द्वारा ग्रहीत सम्पत्ति का आपस में अंतरण; तथा
 - viii) अन्य अंतर ; तथा
- (ड) निवेश सम्पत्ति का उचित मूल्य । अनुच्छेद 53 में वर्णित अपवाद स्वरूप मामलों में, जब एक प्रतिष्ठान निवेश सम्पत्ति को उचित मूल्य का निर्धारण विश्वसनीय रूप से नहीं कर सकता तो वह निम्नलिखित को प्रकट करेगा :-
- i) निवेश सम्पत्ति का एक विवरण ;
 - ii) एक स्पष्टीकरण कि उचित मूल्य का विश्वसनीय रूप से निर्धारण क्यों नहीं किया जा सकता; तथा
 - iii) यदि संभव है तो, अनुमानों की रेंज जिसमें उचित मूल्य पर रहने की अधिक संभावना है ।

परिशिष्ट 'क'

अन्य भारतीय लेखा मानकों में समाविष्ट मामलों के संदर्भ

यह परिशिष्ट भारतीय लेखा मानक 40 निवेश सम्पत्ति का अभिन्न भाग है।

- 1 भारतीय लेखा मानक 12 आयकर में समाविष्ट परिशिष्ट 'क' पुनः मूल्यांकित गैर मूल्य हास योग्य सम्पत्तियों की आयकर वसूली इस मानक में भी संदर्भ का कार्य करता है।

परिशिष्ट 1

टिप्पणी : यह परिशिष्ट भारतीय लेखा मानक का अंग नहीं है। इस परिशिष्ट का प्रयोजन मात्र इतना है कि यदि भारतीय लेखा मानक (इंड ए एस) 40 और तदनुसूची अंतरराष्ट्रीय लेखा मानक (आईएस) 40 - निवेश संपत्ति के बीच यदि कोई प्रमुख अंतर है तो उन्हें स्पष्ट किया जाये ।

अंतरराष्ट्रीय लेखा मानक (आईएस) 40 निवेश संपत्ति के साथ तुलना

1. अंतरराष्ट्रीय लेखा मानक 40 प्रारंभिक मान्यता के पश्चात् निवेश संपत्तियों के माप के लिए लागत मॉडल और उचित मूल्य मॉडल दोनों के प्रयोग की (कुछ परिस्थितियों को छोड़कर) अनुमति प्रदान करता है जबकि भारतीय लेखा मानक 40 भाग लागत मॉडल के प्रयोग की अनुमति देता है। अतः भारतीय लेखा मॉडल 40 में से अंतरराष्ट्रीय लेखा मानक 40 के उचित मूल्य के प्रयोग के निम्नलिखित अनुच्छेदों को हटा दिया गया है। फिर भी, भारतीय लेखा मानक 40 की अनुच्छेद संख्याओं के साथ क्रमबद्धता रखने के लिए भारतीय लेखा मानक 40 में इन अनुच्छेद संख्याओं का उल्लेख किया गया है।

- (i) अनुच्छेद 6
- (ii) अनुच्छेद 31
- (iii) अनुच्छेद 32 क - 32 ग

- (iv) अनुच्छेद 33 - 35
- (v) अनुच्छेद 41
- (vi) अनुच्छेद 50
- (vii) अनुच्छेद 52
- (viii) अनुच्छेद 60 - 65
- (ix) अनुच्छेद 75 (ख)
- (x) अनुच्छेद 75 (च) (iv)
- (xi) अनुच्छेद 76 - 78

2. अंतरराष्ट्रीय लेखा मानक 40 में दिये गये संक्रमणकालीन प्रावधान भारतीय लेखा मानक 40 में सम्मिलित नहीं किये गये हैं क्योंकि भारतीय लेखा मानकों से संबंधित सभी संक्रमणकालीन प्रावधान जहां उचित समझा गया है, आई एफ आर एस 1 अंतरराष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग मानकों का प्रथमवार अंगीकरण के अनुरूप भारतीय लेखा मानक 101 भारतीय लेखा मानकों का प्रथमवार अंगीकरण में सम्मिलित कर दिये गये हैं।
3. जब लागत मॉडल का प्रयोग किया जाता है, भारतीय लेखा मानक 40 निवेश संपत्ति के उचित मूल्यों के प्रकटन की अपेक्षा करता है। चूंकि इस अपेक्षा को भारतीय लेखा मानक 40 में जारी रखा गया है, अतः अंतरराष्ट्रीय लेखा मानक 40 के अनुच्छेद 53, 53 क, 53 ख, 54 व 55 और कुछ अन्य अनुच्छेदों को संशोधित कर दिया गया है। इन संशोधनों में उचित मूल्य माप का निर्धारण उचित मूल्य प्रकटन के साथ प्रतिस्थापन और जब उचित मूल्य का निर्धारण अविश्वसनीय हो तो लागत मॉडल के प्रयोग के संदर्भ का विलोप सम्मिलित है।
4. जब निवेश संपत्ति की परिभाषा अन्यथा पूरी होती है और उचित मूल्य मॉडल का प्रयोग किया जाता है तो अंतरराष्ट्रीय लेखा मानक 40 निवेश संपत्ति के रूप में एक परिचालन पट्टे में धारित संपत्ति हित के व्यवहार की अनुमति देता है। ऐसे मामलों में, परिचालन पट्टे का लेखा इस प्रकार से किया जाएगा जैसे कि वह एक वित्तीय पट्टा हो। चूंकि भारतीय लेखा मानक 40 उचित मूल्य मॉडल के प्रयोग को निषिद्ध करता है, अतः यह प्रतिषेद्ध भारतीय लेखा मानक पर भी लागू होता है परिणामस्वरूप अन्तरराष्ट्रीय लेखा मानक 40 का अनुच्छेद 6 भारतीय लेखा मानक 40 [देखिये उपर्युक्त मद 1 (i)] में से हटा दिया गया है। इसके अतिरिक्त 'एक वित्तीय अथवा परिचालन पट्टे के अन्तर्गत अन्तरराष्ट्रीय लेखा मानक 40 के अनुच्छेद 74 में प्रस्तुत' निवेश संपत्ति की व्याख्या भारतीय लेखा मानक 40 में संशोधित करके 'एक वित्तीय पट्टे के अन्तर्गत निवेश संपत्ति के रूप में कर दी गयी है।
5. भारतीय लेखा मानक 40 में उचित मूल्य मॉडल के प्रयोग के प्रतिषेद्ध के परिणामस्वरूप अनुच्छेद 26 की शब्दावली में कुछ संशोधन किये गये हैं ; अर्थात् अन्तरराष्ट्रीय लेखा मानक 40 में प्रयुक्त शब्दावली की तुलना में (शब्दों 'उचित मूल्य मॉडल' का हटाया जाना), अनुच्छेद 30 और 32 (लेखनीति), अनुच्छेद 33 के ऊपर शीर्षक 'उचित मूल्य मॉडल' बजाय 'उचित मूल्य निर्धारण', अनुच्छेद 56, अनुच्छेद 59 (उचित मूल्य मॉडल से संबंधित भाग का हटाया जाना), अनुच्छेद 68 (उचित मूल्य मॉडल से संबंधित अंश का हटाया जाना), अनुच्छेद 74 के ऊपर शीर्षक ('उचित मूल्य मॉडल एवं लागत मॉडल' शीर्षक का हटाया जाना) और 75 (क) (लेखनीति का प्रकटन) ।
6. इस मानक में अलग शब्दावली का प्रयोग किया गया है, उदाहरणतया, शब्दों 'वित्तीय स्थिति का विवरण' के स्थान पर शब्द 'तुलन-पत्र' का प्रयोग किया गया है।

7. अन्तरराष्ट्रीय लेखा मानक (आई ए एस) 40 में निम्नलिखित अनुच्छेद 'हटाया गया' के रूप में उल्लिखित है। अन्तरराष्ट्रीय लेखा मानक 40 के साथ अनुच्छेद संख्याओं की क्रमबद्धता के लिए इन अनुच्छेद संख्याओं का भारतीय लेखा मानक 40 में उल्लिख किया गया है : -

- (i) अनुच्छेद 9 (घ)
- (ii) अनुच्छेद 22
- (iii) अनुच्छेद 57 (ड)

भारतीय लेखा मानक (इंड ए एस) 108

परिचालन खण्ड

(इस भारतीय लेखा-मानक में मोटे टाइप व सामान्य टाइप में अनुच्छेद हैं। इन दोनों तरह के अनुच्छेदों का समान प्राधिकार है। मोटे टाइप में अनुच्छेद, मुख्य सिद्धान्तों के सूचक हैं।)

मुख्य सिद्धांत

1. प्रतिष्ठान द्वारा अपने व्यावसायिक कार्यकलापों की, जिन्हें वह कर रहा है, और उस आर्थिक परिदृश्य जिसमें वह उन कार्य-कलापों का सम्पादन कार्य कर रहा है, सूचना प्रकट करेगा ताकि वित्तीय विवरणों के प्रयोगकर्ता उनकी प्रकृति तथा वित्तीय प्रभावों की जानकारी प्राप्त कर सकें।

कार्यक्षेत्र

2. यह लेखा मानक उन कंपनियों पर लागू होता है जिन पर कंपनी (लेखा मानक) नियमावली के भाग 1 के अन्तर्गत अधिसूचित लेखा मानक लागू होते हैं।
3. यदि कोई प्रतिष्ठान जिसे यह भारतीय लेखा मानक लागू करना अपेक्षित न हो, ऐसे खण्डों के संबंध में जानकारी प्रकट करने के लिए चयन करता है जो इस लेखा मानक का अनुपालन न करते हों, वह सूचना को खण्डीय सूचना के रूप में प्रकट नहीं करेगा।
4. यदि किसी मूल प्रतिष्ठान की वित्तीय रिपोर्ट में समेकित वित्तीय विवरण, जो इस भारतीय लेखा मानक के कार्यक्षेत्र के भीतर हैं, एवं मूल प्रतिष्ठान का पृथक विवरण दोनों समाविष्ट हैं, तो खण्ड सूचना केवल समेकित वित्तीय विवरण के संबंध में ही अपेक्षित है।

परिचालन खण्ड

5. प्रतिष्ठान के परिचालन खण्ड के निम्नलिखित घटक होते हैं :-

- (क) वह ऐसे व्यवसायिक कार्यकलापों में लगा हो जिससे उसे राजस्व की प्राप्ति हो तथा जिसमें उसके द्वारा खर्च वहन किए जाते हों। इसमें वे राजस्व व व्यय भी सम्मिलित हैं जो उसी प्रतिष्ठान के अन्य लेन देनों से संबंधित हैं।
- (ख) जिसके परिचालन संबंधी परिणामों की प्रतिष्ठान के मुख्य परिचालन निर्णयकर्ता द्वारा नियमित रूप से समीक्षा की जाती हो ताकि वह संसाधनों के खण्डीय आवंटन के प्रति निर्णय ले सके और कार्य निष्पादन की भी समीक्षा कर सके।

(ग) जिसके संबंध में अलग से वित्तीय सूचना उपलब्ध हो ।

परिचालन खण्ड ऐसे कार्य कलापों को सम्पादित कर सकता है जिनसे अभी उसे राजस्व प्राप्त होना है । उदाहरणतया, जैसे कि, प्रारंभिक परिचालन राजस्व अर्जित करने की पूर्व स्थिति ।

6. यह आवश्यक नहीं है कि प्रतिष्ठान का प्रत्येक अंग परिचालन खण्ड अथवा उसका एक भाग हो। उदाहरणतया, निगम का प्रधान कार्यालय अथवा कुछ इसके कार्यात्मक विभाग राजस्व अर्जित नहीं करते अथवा वे प्रतिष्ठान के प्रासंगिक कार्यकलापों से कोई राजस्व प्राप्त कर लें तथा वे कोई परिचालन खण्ड न हों। इस भारतीय लेखा मानक के प्रयोजन के लिए प्रतिष्ठान की नियोजनोपरांत लाभ योजनाएं परिचालन खण्ड नहीं हैं ।
7. मुख्य परिचालन निर्णयकर्ता शब्द कार्य का परिचायक है और प्रतिष्ठान में यह प्रबंधक जैसा कोई विशिष्ट पद नहीं है । उसका कार्य, संसाधनों को आवंटित करना तथा प्रतिष्ठान के परिचालन खण्ड के कार्य निष्पादन की समीक्षा करना है । सामान्यतः मुख्य परिचालन निर्णयकर्ता प्रतिष्ठान का मुख्य कार्यपालक अधिकारी अथवा मुख्य परिचालन अधिकारी होता है । उदाहरण के लिए वह कार्यपालक निदेशकों का अथवा अन्य कार्यकारी अधिकारियों का समूह भी हो सकता है ।
8. अधिकतर प्रतिष्ठानों के लिए, अनुच्छेद 5 में परिचालन खण्ड की दी गई तीन विशिष्टताएं इसके परिचालन खण्ड की द्योतक हैं । फिर भी, प्रतिष्ठान अपनी रिपोर्टों को विभिन्न प्रकारों से प्रस्तुत कर सकता है जिनमें व्यवसाय के कार्यकलापों को संपादित किया जाता है । यदि मुख्य परिचालन निर्णयकर्ता एक से अधिक खण्डों की सूचना के सम्मुख्य (सैट) का प्रयोग करे तो एक अन्य घटक सम्मुख्य में उन कारकों की भी सूचना दी जाएगी जो प्रतिष्ठान के परिचालन खण्ड के विभिन्न भागों के व्यवसायी कार्य कलापों की प्रकृति, उनके लिए कौन प्रबंधक जिम्मेदार हैं तथा निदेशक मंडल को प्रस्तुत की जाने वाली सूचना आदि की जानकारी दी जाएगी ।
9. सामान्यतः, परिचालन खण्ड का एक खण्ड प्रबंधक होता है जो परिचालन के कार्य कलापों, वित्तीय परिणामों, पूर्वानुमानों अथवा खण्ड के लिए योजना बनाने जैसे पक्षों के लिए मुख्य परिचालन निर्णयकर्ता से नियमित सम्पर्क बनाए रखता है। 'खण्ड प्रबंधक' शब्द कार्य का परिचायक है और यह आवश्यक नहीं कि परिचालन में इस नाम का कोई विशिष्ट पद हो । मुख्य परिचालन निर्णयकर्ता भी कुछ परिचालन खण्डों के खण्ड प्रबंधक हो सकते हैं । इसी तरह एक प्रबंधक एक से अधिक परिचालन खण्डों का खण्ड प्रबंधक हो सकता है। यदि अनुच्छेद 5 में दी गई विशिष्टताएं संगठन के एक से अधिक भागों पर लागू होती हों परंतु खण्ड प्रबंधक केवल एक समुच्चय (सैट) के लिए ही उत्तरदायी हों तो परिचालन खण्ड के उसी सम्मुख्य (सैट) में सभी कारकों की सूचना सम्मिलित होगी ।
10. अनुच्छेद 5 में दी गई विशिष्टताएं दो या दो से अधिक घटकों के अधिव्याप्त सम्मुख्यों (सैटों) पर लागू हो सकती हैं जिनके लिए प्रबंधक उत्तरदायी हों । ऐसी संरचना संगठनात्मक ढांचे का सांचागत स्वरूप (मैट्रिक्स फार्म) कहलाता है । उदाहरणतया, कुछ प्रतिष्ठानों में कुछ प्रबंधक विभिन्न उत्पादों तथा सेवाओं की लाइन के लिए विश्व स्तर पर उत्तरदायी होते हैं जबकि अन्य प्रबंधक विशेष भौगोलिक क्षेत्र के लिए उत्तरदायी होते हैं । मुख्य परिचालन निर्णयकर्ता द्वारा दोनों भागों के सम्मुख्य (सैटों) के परिचालन परिणामों की नियमित रूप से समीक्षा की जाती है तथा उसके पास

निम्नलिखित में से दोनों की वित्तीय सूचना उपलब्ध रहती है। ऐसी स्थिति में प्रतिष्ठान द्वारा मुख्य सिद्धांत के संदर्भ में निर्धारण करना होगा कि इन दोनों भागों में कौन - सा भाग परिचालन खण्ड कहलाएगा।

रिपोर्ट-योग्य खण्ड

11. प्रतिष्ठान द्वारा निम्नलिखित में से प्रत्येक परिचालन खण्ड के लिए अलग-अलग सूचना दी जाएगी:

- (क) जिनकी पहचान अनुच्छेद 5-10 के अनुसार हुई हो अथवा अनुच्छेद 12 के अनुसार दो या अधिक खण्डों के समूहन के परिणामस्वरूप हुई हो। तथा
- (ख) अनुच्छेद 13 की मात्रात्मक सीमा से अधिक हो।
अनुच्छेद 14-19 उन अन्य परिस्थितियों को विनिर्दिष्ट करते हैं जिनमें किसी परिचालन खण्ड की पृथक सूचना रिपोर्ट की जानी चाहिए।

समूहन मानदण्ड

12. परिचालन खण्डों की यदि एक समान आर्थिक विशेषताएं हों तो वे सामान्यतः एक जैसे दीर्घावधि वित्तीय कार्य निष्पादन दर्शाते हैं। उदाहरणतया, दो परिचालन खण्डों का दीर्घावधि औसत सकल लाभ एक जैसा होने की आशा की जा सकती है यदि उनकी आर्थिक विशेषताएं एक समान हों। दो अथवा अधिक परिचालन खण्डों का एकल परिचालन खण्ड में समूहन किया जा सकता है बशर्ते समूहन इस भारतीय लेखा मानक के मुख्य सिद्धांत के अनुकूल हो अर्थात् खण्डों की एक समान आर्थिक विशेषताएं हों तथा खण्ड निम्न लिखित प्रत्येक मामले में एक समान हों :

- (क) उत्पाद तथा सेवाओं की प्रकृति
- (ख) उत्पादन प्रक्रिया की प्रकृति
- (ग) उत्पाद तथा सेवाओं के ग्राहकों का वर्ग
- (घ) उत्पाद वितरण तथा सेवाएं प्रदान करने की पद्धतियाँ, तथा
- (ङ) यदि लागू हो, नियामक वातावरण, उदाहरणतः बैंकिंग, बीमा अथवा जन-उपयोगी सेवाएं।

मात्रात्मक सीमाएं

13. प्रतिष्ठान द्वारा प्रत्येक परिचालन खण्ड के लिए पृथक सूचना दी जाएगी जो निम्नलिखित मात्रात्मक सीमाएं पूरी करते हों :

- (क) उसका रिपोर्ट किया गया राजस्व जिसमें बाह्य ग्राहकों की बिक्री तथा अन्तर खण्ड बिक्री अथवा अंतरण जो आंतरिक अथवा बाहरी सभी परिचालन खण्डों के संयुक्त राजस्व का 10% अथवा अधिक हो, सम्मिलित है।
- (ख) उसके द्वारा रिपोर्ट किए गए लाभ अथवा हानि की समग्र राशि 10% अथवा अधिक की समग्र राशि, इन दोनों में से जो अधिक है (i) सभी प्रचालन खण्डों के रिपोर्ट किए गए संयुक्त लाभ जिन्होंने हानि की रिपोर्टिंग न की हो (ii) सभी परिचालन खण्डों की रिपोर्ट की गई संयुक्त हानियाँ, जिन्होंने हानि रिपोर्ट की हो।
- (ग) इसकी आस्तियाँ सभी परिचालन खण्डों की संयुक्त आस्तियों के 10% अथवा अधिक हों।

परिचालन खण्ड को, जो उपर्युक्त किसी भी मात्रात्मक सीमा से मेल न खाते हों, रिपोर्ट योग्य माना जा सकता है तथा उसका प्रकटन पृथक रूप से किया जा सकता है, यदि प्रबंधन के विचार में खण्ड से संबंधित जानकारी वित्तीय विवरणों के प्रयोगकर्ताओं के लिए उपयोगी है।

14. प्रतिष्ठान ऐसे परिचालन खण्डों की, जिनकी मात्रात्मक सीमाओं की सूचना का मेल न हो, और अन्य परिचालन खण्डों, जिनकी मात्रात्मक सीमाओं की सूचना का मेल न हो, को रिपोर्ट योग्य खण्ड बनाने के लिए परस्पर मिला सकते हैं बशर्ते परिचालन खण्डों की आर्थिक विशिष्टताएं एक समान हों तथा अनुच्छेद 12 में सूचीबद्ध समूहन के मापदण्डों को प्रमुख रूप से पूरा करते हों।
15. यदि परिचालन खण्ड द्वारा रिपोर्ट किया गया कुल बाह्य राजस्व का भाग प्रतिष्ठान के राजस्व के 75% से कम हो, रिपोर्ट योग्य खण्ड के रूप में अतिरिक्त परिचालन खण्ड को मिलाना होगा (बेशक वे अनुच्छेद 13 के मानदण्डों को पूरा न करते हों) जब तक कि कम से कम 75% राजस्व रिपोर्ट योग्य खण्ड में सम्मिलित न हो जाए।
16. रिपोर्ट योग्य न होने वाले अन्य व्यवसायिक कार्य कलापों तथा परिचालन खण्डों को सम्मिलित किया जाएगा तथा अनुच्छेद 28 के द्वारा अपेक्षित मिलान हेतु अन्य मिलान मदों से 'अन्य सभी खण्ड' श्रेणी के अंतर्गत पृथक रूप से प्रकट किए जाने चाहिए। 'अन्य सभी खण्ड' श्रेणी में सम्मिलित राजस्व के स्रोतों के ब्यौरे दिए जाने चाहिए।
17. यदि प्रबंधन यह अनुभव करे कि पूर्ववर्ती अवधि में जिस परिचालन खण्ड की पहचान रिपोर्ट योग्य खण्ड के रूप में की गई है उससे खण्ड के संबंध में निरंतर महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हो रही हो तो उसे चालू अवधि में भी पृथक रूप से रिपोर्ट करना जारी रखा जाएगा बेशक वह अनुच्छेद 13 में दिए गए रिपोर्ट योग्य मानदण्डों को अब पूरा न भी कर रहा हो।
18. यदि चालू अवधि में परिचालन खण्ड की पहचान रिपोर्ट योग्य खण्ड के रूप में मात्रात्मक सीमाओं के अनुसार की गई हो, पूर्व अवधि के लिए तुलनात्मक उद्देश्य से प्रस्तुत किए गए आंकड़ों (डाटा) को नए रिपोर्ट योग्य खण्ड में प्रभाव दिखाने के लिए पुनः वर्णित करना चाहिए, चाहे उस खण्ड ने अनुच्छेद 13 के अनुसार रिपोर्ट योग्यता के मानदण्डों को पूरा न किया हो। जब तक कि आवश्यक सूचना उपलब्ध न हो अथवा इसे विकसित करने की लागत बहुत अधिक हो।

19. किसी प्रतिष्ठान द्वारा पृथक रूप से प्रकट की जाने वाले रिपोर्ट योग्य खण्डों की संख्या को सीमित करना व्यवहारिक होगा क्योंकि सीमा से अधिक खण्ड की सूचना आवश्यकता से अधिक विस्तृत हो सकती है। यद्यपि अनुच्छेद 13-18 के अनुसरण में रिपोर्ट योग्य खण्डों की कोई निश्चित सीमा निर्धारित नहीं की गई है, जब संख्या दस से ऊपर हो जाती है तो प्रतिष्ठान को समझना चाहिए कि क्या अब व्यवहार्य सीमा पूरी हो चुकी है।

प्रकटन

20. प्रतिष्ठान द्वारा अपने व्यवसायिक कार्यकलापों की, जिन्हें वह कर रहा है, और उस आर्थिक परिदृश्य, जिसमें वह उन कार्य-कलापों का सम्पादन कार्य कर रहा है, सूचना प्रकट करेगा ताकि वित्तीय विवरणों के प्रयोगकर्ता उनकी प्रकृति तथा वित्तीय प्रभावों की जानकारी प्राप्त कर सकें।

21. अनुच्छेद 20 में दिए गए सिद्धांत को लागू करने के लिए प्रत्येक अवधि, जिसके संबंध में लाभ तथा हानि की विवरणी प्रस्तुत की गई हो, प्रतिष्ठान को निम्नलिखित प्रकटन करने होंगे :

- (क) अनुच्छेद 22 में यथा वर्णित सामान्य सूचनाएं।
- (ख) रिपोर्ट किए गए खण्ड के लाभ या हानि के संबंध में सूचना जिसमें राजस्व तथा व्यय सहित, खण्ड आस्तियाँ, खण्ड देयताओं तथा अनुच्छेद 23-27 के अनुसार माप का आधार का उल्लेख भी सूचित किया जाएगा।
- (ग) खण्ड के राजस्व का सकल योग, रिपोर्ट किए गए खण्ड की लाभ या हानि, खण्ड आस्तियाँ, खण्ड देयताएं तथा अनुच्छेद 28 में वर्णित प्रतिष्ठान की राशियों के तदनु रूप अन्य महत्वपूर्ण खण्डीय मदों का मिलान।

रिपोर्ट योग्य खण्ड की राशियों का प्रतिष्ठान के तुलन पत्र की राशियों से मिलान प्रस्तुत किए गए तुलन पत्र की प्रत्येक तारीख के लिए करना आवश्यक है। पूर्व अवधियों संबंधी सूचना अनुच्छेद 29 तथा 30 में यथावर्णित पुनः प्रस्तुत की जाएंगी।

सामान्य सूचना

22. प्रतिष्ठान द्वारा निम्नलिखित सूचनाएं प्रकट की जाएंगी :-

- (क) प्रतिष्ठान के रिपोर्ट योग्य खण्डों की, संगठन के आधार सहित, पहचान के लिए प्रयुक्त कारक (उदाहरणतया, क्या प्रबंधन द्वारा प्रतिष्ठान के संगठन के विभिन्न उत्पाद तथा सेवाओं, भौगोलिक क्षेत्रों, विनियामक वातावरण के बीच अथवा कारकों के सम्मिलित रूप में संचालित करने के लिए चयन किया गया है तथा क्या परिचालन खण्डों को मिलाया गया है।), तथा

- (ख) उत्पाद तथा सेवाओं के प्रकार, जिनके द्वारा प्रत्येक रिपोर्ट योग्य खण्ड राजस्व प्राप्त करते हैं ।

लाभ या हानि तथा आस्तियों एवं देयताओं संबंधी सूचना

23. एक प्रतिष्ठान द्वारा प्रत्येक रिपोर्ट योग्य खण्ड के लाभ या हानि के माप राशि की रिपोर्ट देनी होगी। एक प्रतिष्ठान द्वारा प्रत्येक रिपोर्ट योग्य खण्ड की कुल आस्तियों एवं देयताओं के माप की रिपोर्ट देनी होगी, यदि ऐसी राशियाँ नियमित रूप से मुख्य परिचालन निर्णयकर्ता को प्रस्तुत की जाती हों । प्रतिष्ठान द्वारा प्रत्येक रिपोर्ट योग्य खण्ड के संबंध में निम्न को भी प्रकट करना होगा यदि मुख्य परिचालन निर्णयकर्ता की समीक्षा के लिए विशिष्ट राशियाँ खण्ड के लाभ या हानि के माप में शामिल नियमित रूप से उसे प्रस्तुत की जाती हों या बेशक उन्हें खण्ड के लाभ या हानि के माप में शामिल न भी किया गया हो ।

- (क) बाह्य ग्राहकों से प्राप्त राजस्व
- (ख) उसी प्रतिष्ठान के अन्य प्रचालन खण्डों से लेन-देन से प्राप्त राजस्व
- (ग) ब्याज राजस्व
- (घ) ब्याज व्यय
- (ङ) मूल्यहास तथा परिशोधन
- (च) भारतीय लेखा मानक 1 *वित्तीय विवरणों का प्रस्तुतिकरण* के अनुच्छेद 97 के अनुसरण में प्रकट आय तथा व्यय की महत्वपूर्ण मदें
- (छ) सहायक प्रतिष्ठान अथवा संयुक्त उद्यम में इक्विटी विधि से लेखाबद्ध प्रतिष्ठान के हित
- (ज) आय कर खर्च अथवा आय, तथा
- (झ) मूल्यहास तथा परिशोधन के अलावा महत्वपूर्ण गैर नकदी मदें ।

प्रतिष्ठान द्वारा प्रत्येक रिपोर्ट योग्य खण्ड के ब्याज राजस्व को ब्याज व्यय से अलग दर्शाना चाहिए बशर्ते खण्ड का अधिकतर राजस्व ब्याज से प्राप्त हो तथा मुख्य परिचालन निर्णयकर्ता खण्ड के निष्पादन का मूल्यांकन तथा खण्डों को संसाधन आवंटित करने के निर्णय के लिए प्राथमिक रूप से निवल ब्याज आय पर ही निर्भर न हो ।

24. प्रतिष्ठान प्रत्येक रिपोर्ट करने योग्य खण्ड के संबंध में निम्नलिखित को प्रकट करेगा बशर्ते खण्ड आस्तियों के माप में विशिष्ट राशियाँ सम्मिलित की गई हों और इन खण्ड आस्तियों की मुख्य परिचालन निर्णायक रागीक्षा करता है या फिर उसे ये नियमित रूप से प्रस्तुत की जाती हों और चाहे खण्ड आस्तियों के माप में विशिष्ट राशियाँ सम्मिलित न भी हों ।

- (क) सहायक प्रतिष्ठानों एवं संयुक्त उद्यमों में 'इक्विटी' विधि से लेखाबद्ध निवेश की राशि, और

- (ख) वित्तीय लिखतों, आस्थगित कर आस्तियों, नियोजनोपरांत लाभ आस्तियों (देखें भारतीय लेखा मानक 19 *कर्मचारी लाभ* के अनुच्छेद 54-58 तथा बीमा संविदाओं से उत्पन्न अधिकारों के अलावा गैर- चालू आस्तियों¹ में परिवर्धनों की राशियाँ ।

माप

25. रिपोर्ट किए गए प्रत्येक खण्ड मद की राशि मुख्य परिचालन निर्णयकर्ता को रिपोर्ट किया गया माप होगा ताकि वह खण्ड को संसाधन आवंटित करने तथा कार्य निष्पादन के मूल्यांकन के संबंध में निर्णय ले सके । प्रतिष्ठान के वित्तीय विवरणों को तैयार करते समय यदि कोई समायोजन तथा बहिष्करण किया जाता है तथा राजस्व, व्यय तथा लाभ हानियों का आवंटन खण्ड के रिपोर्ट किए गए लाभ- हानि के निर्धारण में तभी सम्मिलित किए जाएंगे यदि वे खण्ड के लाभ या हानि के माप में सम्मिलित हों और उसका उपयोग मुख्य परिचालन निर्णायक द्वारा किया जाता हो। इसी प्रकार, खण्ड की वही आस्तियाँ तथा देयताएँ रिपोर्ट की जाएंगी जो उस खण्ड की आस्तियों तथा देयताओं के माप में शामिल की गई हों और उसका उपयोग मुख्य परिचालन निर्णायक द्वारा किया जाता हो । यदि खण्ड के रिपोर्ट किए गए लाभ या हानि और आस्तियों अथवा देयताओं को राशियाँ आवंटित की जाती हैं, तो उन राशियों को तर्क पूर्ण ढंग से आवंटित किया जाएगा ।
26. यदि मुख्य परिचालन निर्णयकर्ता परिचालन खण्ड के कार्य निष्पादन के मूल्यांकन तथा खण्ड के लाभ या हानि और आस्तियों तथा देयताओं के आवंटन का निर्णय करने के उद्देश्य से परिचालन खण्ड के लाभ अथवा हानि और खण्ड की आस्तियों अथवा देयताओं के माप के लिए केवल एक माप का प्रयोग करें तो खण्ड के लाभ या हानि और आस्तियों तथा देयताओं की रिपोर्टिंग उसी माप द्वारा की जाएगी । यदि मुख्य परिचालन निर्णयकर्ता परिचालन खण्ड के लाभ या हानि और खण्ड की आस्तियों अथवा देयताओं के माप के लिए एक से अधिक माप का प्रयोग करे तो रिपोर्ट के माप प्रबंधन के मतानुसार प्रतिष्ठान के वित्तीय विवरणों में उनके समान राशियों के माप के लिए प्रयुक्त मापन के सिद्धांतों के अनुरूप निर्धारित किए जाने चाहिए ।
27. प्रतिष्ठान को खण्डीय लाभ या हानि, खण्डीय आस्तियों तथा खण्डीय देयताओं की प्रत्येक रिपोर्ट योग्य खण्ड के लिए माप का स्पष्टीकरण देना आवश्यक है । प्रतिष्ठान कम से कम निम्नलिखित का प्रकटन करेगा :-
- (क) रिपोर्ट योग्य खण्डों के बीच लेन -देनों के लेखांकन का आधार ।
- (ख) रिपोर्ट योग्य खण्डों के लाभ या हानियाँ, प्रतिष्ठान के आय कर व्यय अथवा आय से पूर्व लाभ या हानि, तथा बंद किए गए परिचालन के मापों के बीच के अंतरों की प्रकृति (यदि अनुच्छेद 28 में वर्णित मिलान से स्पष्ट न हो)। इन अंतरों में रिपोर्ट की गई खण्ड जानकारी को समझने के लिए लेखा नीतियों तथा संयुक्त रूप से प्रयुक्त आस्तियों के आवंटन की नीतियाँ शामिल हो सकती हैं ।

¹ तरलता प्रस्तुति के अनुसरण में आस्तियों के वर्गीकरण के उद्देश्य के लिए गैर चालू आस्तियों में वे आस्तियाँ शामिल होती हैं जिनकी वसूली रिपोर्टिंग अवधि के पश्चात 12 महीनों से अधिक की अवधि के अंदर प्रत्याशित है ।

- (ग) रिपोर्ट योग्य खण्ड देयताओं तथा प्रतिष्ठान की आस्तियों के माप में अंतरों की प्रकृति (यदि अनुच्छेद 28 में वर्णित मिलान से स्पष्ट न हो) इन अंतरों में रिपोर्ट की गई खण्ड जानकारी को समझने के लिए लेखा नीतियाँ तथा संयुक्त रूप से प्रयुक्त आस्तियों के आवंटन की नीतियाँ शामिल हो सकती हैं।
- (घ) रिपोर्ट योग्य खण्ड देयताओं तथा प्रतिष्ठान की देयताओं के माप में अंतरों की प्रकृति (यदि अनुच्छेद 28 में वर्णित मिलान से स्पष्ट न हो) इन अंतरों में रिपोर्ट की गई खण्ड जानकारी को समझने के लिए लेखा नीतियाँ तथा संयुक्त रूप से प्रयुक्त देयताओं के आवंटन की नीतियाँ शामिल हो सकती हैं।
- (ङ) रिपोर्ट किए गए खण्ड लाभ अथवा हानि तथा उसके प्रभाव के निर्धारण के लिए प्रयुक्त माप पद्धति की, उन परिवर्तनों पर जो खण्ड माप से लाभ या हानि से पूर्व अवधि से परिवर्तन यदि हुए हों, की प्रकृति।
- (च) रिपोर्ट योग्य खण्ड के किसी विषम आवंटन की प्रकृति तथा प्रभाव। उदाहरणतः, प्रतिष्ठान द्वारा किसी खण्ड के मूल्यहास व्यय आवंटित किए गए हों परंतु उस खण्ड की संबंधित मूल्यहास योग्य आस्तियों को आवंटित न किए हों।

मिलान

28. प्रतिष्ठान को निम्न का मिलान करना होगा :-

- (क) खण्ड के रिपोर्ट योग्य राजस्व का योग प्रतिष्ठान के कुल राजस्व से।
- (ख) प्रतिष्ठान के कुल कर पूर्व खर्चों (कर आय) तथा बंद किए गए परिचालनों से लाभ या हानि के रिपोर्ट योग्य खण्डों के लाभ या हानि मापन का योग। परंतु यदि प्रतिष्ठान रिपोर्ट योग्य खण्ड को कर पूर्व खर्चों (कर आय) आवंटित करे, तो प्रतिष्ठान द्वारा खण्ड के लाभ या हानि के मापन का प्रतिष्ठान के उस मद के लाभ या हानि से मिलान किया जा सकता है।
- (ग) खण्ड की रिपोर्ट योग्य आस्तियों के योग का प्रतिष्ठान की कुल आस्तियों से।
- (घ) खण्ड की रिपोर्ट योग्य देयताओं के योग का प्रतिष्ठान की कुल देयताओं से यदि खण्ड की देयताओं की रिपोर्ट अनुच्छेद 23 के अनुसार की गई हो।
- (ङ) खण्ड की रिपोर्ट योग्य अन्य सारवान (महत्वपूर्ण) मदों की सूचना के योग का प्रतिष्ठान प्रकट की गई समरूप सारवान (महत्वपूर्ण) मदों की सूचना से।

सभी सारवान मदों को पृथक रूप से पहचाना तथा वर्णित किया जाएगा। उदाहरणार्थ रिपोर्ट योग्य खण्ड के लाभ या हानि के लिए आवश्यक प्रत्येक सारवान समायोजन की राशि प्रतिष्ठान के विभिन्न लेखानीतियों से उत्पन्न लाभ या हानि की पहचान तथा प्रकटन पृथक रूप से किया जाएगा।

पूर्व में रिपोर्ट की गई जानकारी का पुनर्कथन

29. यदि प्रतिष्ठान अपने आंतरिक संगठन में परिवर्तन इस ढंग से करे कि उसके रिपोर्ट योग्य खण्ड के गठन में परिवर्तन हो जाए, तो पूर्व अवधियों की समकक्ष जानकारी, अंतरिम अवधि सहित, का पुनर्कथन किया जाएगा जब तक कि सूचना उपलब्ध न हो अथवा उसे विकसित करने की लागत बहुत अधिक हो। सूचना उपलब्ध न होने अथवा उसे विकसित करने की लागत बहुत अधिक होने का निर्धारण प्रकटन की प्रत्येक मद के संबंध में पृथक से किया जाएगा। उसके रिपोर्ट योग्य खण्ड के गठन में परिवर्तन के फलस्वरूप, प्रतिष्ठान को यह प्रकट करना होगा कि क्या उन्होंने पूर्ववर्ती अवधि की समकक्ष खण्ड जानकारी का पुनर्कथन कर दिया है।
30. यदि प्रतिष्ठान अपने आंतरिक संगठन में परिवर्तन इस ढंग से करे कि उसके रिपोर्ट योग्य खण्ड के गठन में परिवर्तन हो जाए, तो पूर्व अवधियों की समकक्ष जानकारी, अंतरिम अवधि सहित, परिवर्तनों को दिखाने के लिए पुनर्कथन नहीं किया गया हो प्रतिष्ठान को जिस वर्ष में परिवर्तन हुए हैं चालू वर्ष के लिए खण्ड जानकारी खण्डीकरण के नए तथा पुराने आधार पर देनी होगी जब तक कि सूचना उपलब्ध न हो अथवा उसे विकसित करने की लागत बहुत अधिक हो।

प्रतिष्ठान व्यापी प्रकटन

31. इस भारतीय लेखा मानक के होते हुए अनुच्छेद 32-34 एकल रिपोर्ट योग्य खण्डों सहित सभी प्रतिष्ठानों पर लागू हैं

कुछ प्रतिष्ठानों की व्यावसायिक गतिविधियाँ संबंधित उत्पादों तथा सेवाओं अथवा परिचालनों के भौगोलिक क्षेत्रों की भिन्नता के आधार पर संपादित नहीं होती हैं। ऐसे प्रतिष्ठान के रिपोर्ट योग्य खण्ड व्यापक रूप से भिन्न तथा सेवाओं की भिन्नता राजस्व को रिपोर्ट कर सकते हैं अथवा इसके एक से अधिक रिपोर्ट योग्य खण्ड अनिवार्यतः वही उत्पाद तथा सेवाएं प्रदान करें। इसी प्रकार किसी प्रतिष्ठान के रिपोर्ट योग्य खण्डों की आस्तियाँ भिन्न-भिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में हो सकती हैं तथा भिन्न-भिन्न भौगोलिक क्षेत्रों के ग्राहकों से प्राप्त राजस्व की रिपोर्ट कर सकते हैं अथवा इसके एक से अधिक रिपोर्ट योग्य खण्ड एक ही भौगोलिक क्षेत्र से परिचालन कर सकते हैं। अनुच्छेद 32-34 द्वारा अपेक्षित सूचना तभी दी जाए यदि इस भारतीय लेखा मानक के अनुसार अपेक्षित रिपोर्ट योग्य खण्ड जानकारी प्रदान नहीं की हो।

उत्पादों तथा सेवाओं संबंधी सूचना

32. प्रतिष्ठान को बाहरी ग्राहकों से प्राप्त राजस्व की प्रत्येक उत्पाद तथा सेवा अथवा समान उत्पाद तथा सेवाओं के समूह के लिए रिपोर्ट करना होगा जब तक कि आवश्यक जानकारी उपलब्ध न हो अथवा उरो उपलब्ध कराने की अत्यधिक लागत हो ऐसे मामलों में यह तथ्य भी सूचित करना होगा। राजस्व की राशि रिपोर्ट प्रतिष्ठान के वित्तीय विवरणों को तैयार करने में प्रयुक्त सूचनाओं पर आधारित होनी चाहिए।

भौगोलिक क्षेत्रों संबंधी सूचना

33. प्रतिष्ठान निम्नलिखित भौगोलिक सूचना प्रदान करेंगे जब तक कि सूचना उपलब्ध न हो अथवा उसे विकसित करने की लागत बहुत अधिक हो :-

- (क) बाहरी ग्राहकों से प्राप्त राजस्व (i) जो प्रतिष्ठान के अपने अधिवासी देश से संबंधित है (ii) बाहर के उन देशों, जिनसे प्रतिष्ठान राजस्व प्राप्त कर रहा हो, से संबंधित कुल राजस्व। यदि किसी एक देश से प्राप्त राजस्व अधिक है तो उस राजस्व को पृथक् रूप से प्रकट किया जाएगा। प्रतिष्ठान को किसी एक देश से बाहरी ग्राहकों से प्राप्त राजस्व प्राप्त होने का आधार प्रकट करना होगा।
- (ख) वित्तीय लिखतें, आस्थगित कर आस्तियाँ, नियोजनोपरांत लाभ आस्तियाँ तथा बीमा संविदाओं के अधीन उत्पन्न अधिकार के अतिरिक्त गैर-चालू आस्तियाँ² जो (i) प्रतिष्ठान के अपने अधिवासी देश में स्थित हैं, और (ii) बाहर के उन सभी देशों में स्थित हैं जहां प्रतिष्ठान की आस्तियाँ हैं। यदि बाहर के किसी देश में आस्तियाँ अधिक हैं तो उनको अलग से प्रकट किया जाएगा।

राजस्व की राशि रिपोर्ट प्रतिष्ठान के वित्तीय विवरणों को तैयार करने में प्रयुक्त सूचनाओं पर आधारित होनी चाहिए यदि आवश्यक जानकारी उपलब्ध न हो अथवा उसे उपलब्ध कराने की अत्यधिक लागत हो तो यह तथ्य सूचित करना होगा। प्रतिष्ठान इस अनुच्छेद द्वारा अपेक्षित जानकारी के अतिरिक्त देशों के समूह से संबंधित भौगोलिक जानकारी के उप-योग सूचित कर सकते हैं।

प्रमुख ग्राहकों संबंधित सूचना

34. प्रतिष्ठान अपने प्रमुख ग्राहकों पर निर्भरता की सूचना प्रदान करेंगे। यदि एकल बाहरी ग्राहक के प्रति संव्यवहारों से प्राप्त राजस्व प्रतिष्ठान के कुल राजस्व के 10% से अधिक होने पर प्रतिष्ठान इस तथ्य को प्रकट करेंगे तथा प्रत्येक ऐसे ग्राहक से प्राप्त कुल राजस्व, तथा रिपोर्ट करने वाले खण्ड या खण्डों की पहचान सूचित करेंगे। प्रतिष्ठान के लिए प्रत्येक प्रमुख ग्राहक अथवा प्रत्येक खण्ड से ऐसे ग्राहक से प्राप्त रकम का प्रकटन आवश्यक नहीं है। इस भारतीय लेखा मानक के उद्देश्य से रिपोर्ट करने वाले प्रतिष्ठान की जानकारी वाली एक नियंत्रण के अधीन प्रतिष्ठानों के समूह को एक ग्राहक माना जाएगा। परंतु, यह जानने के लिए कि एक सरकार (सरकारी एजेंसियों तथा समान निकायों जैसे-स्थानीय, राष्ट्रीय अथवा अंतरराष्ट्रीय सहित) तथा रिपोर्ट करने वाले प्रतिष्ठान की जानकारी वाली सरकार के नियंत्रण के अधीन एक ग्राहक माना जाएगा, का निर्णय लिया जाना अपेक्षित होगा। यह जानने के लिए रिपोर्टिंग प्रतिष्ठान इन प्रतिष्ठानों के बीच आर्थिक एकीकरण की सीमा पर विचार करना होगा।

² तरलता प्रस्तुति के अनुसरण में आस्तियों के वर्गीकरण के उद्देश्य के लिए गैर चालू आस्तियों में वे आस्तियाँ शामिल होती हैं जिनकी वसूली रिपोर्टिंग अवधि के पश्चात 12 महीनों से अधिक की अवधि के अंदर प्रत्याशित है।

परिशिष्ट 'क'

परिभाषित शब्दावली

परिचालन खण्ड

एक परिचालन खण्ड प्रतिष्ठान का ऐसा घटक है :

- (क) जो ऐसी व्यावसायिक गतिविधियों में संलग्न है जिनसे वह राजस्व प्राप्त करता है और व्यय खर्च करता है (जिसमें उसी प्रतिष्ठान के अन्य घटकों के लेनदेनों के राजस्व व व्यय भी सम्मिलित हैं) ;
- (ख) जिसके परिचालन परिणामों की नियमित रूप से मुख्य परिचालन निर्णायक द्वारा समीक्षा की जाती है और खण्ड के संसाधनों के आवंटित करने और कार्य निष्पादन का मूल्यांकन करने के लिए निर्णय लिए जाते हैं ; तथा
- (ग) जिसके लिए अलग से वित्तीय सूचना उपलब्ध रहती है ।

परिशिष्ट 'ख'

विषय-सूची

भारतीय लेखा मानक 108 परिचालन खण्ड को कार्यान्वित करने के दिशानिर्देश

परिचय

का दि 1

किसी प्रतिष्ठान के रिपोर्ट योग्य खण्डों के बारे में वर्णनात्मक सूचना

का दि 2

उत्पादों तथा सेवाओं के प्रकारों का वर्णन जिनसे प्रत्येक रिपोर्ट योग्य खण्ड

राजस्व प्राप्त करते हैं [अनुच्छेद 22 (ख)]

परिचालन खण्ड के लाभ या हानि तथा आस्तियों एवं देयताओं के

परिचालन खण्ड का माप (अनुच्छेद 27)

प्रतिष्ठान के रिपोर्ट योग्य खण्डों की पहचान के लिए प्रबंधन द्वारा

उपयोग में लाए जा रहे कारक [अनुच्छेद 22(क)]

रिपोर्ट योग्य खण्ड के लाभ या हानि तथा आस्तियों एवं देयताओं की सूचना का दि 3

रिपोर्ट योग्य खण्ड के राजस्व लाभ या हानि, आस्तियों एवं देयताओं का दि 4

का मिलान

भौगोलिक सूचना का दि 5

प्रमुख ग्राहकों संबंधी सूचना का दि 6

रिपोर्ट योग्य खण्डों की पहचान के लिए सहायक आरेख का दि 7

भारतीय लेखा मानक 108 परिचालन खण्ड को कार्यान्वित करने के दिशानिर्देश

ये दिशानिर्देश भारतीय लेखा मानक 108 के साथ संलग्न हैं लेकिन उनके अंग नहीं हैं।
परिचय

का दि 1 ये कार्यान्वयन दिशानिर्देश (का दि) भारतीय लेखा मानक 108 द्वारा अपेक्षित प्रकटन के उदाहरण तथा रिपोर्ट योग्य खण्डों की पहचान करने में सहायता प्रदान करने के लिए एक रेखाचित्र प्रस्तुत करते हैं। उदाहरणों में दिए गए फार्मेट अपेक्षित नहीं हैं। जो फार्मेट विशिष्ट परिस्थितियों में सर्वाधिक समझने योग्य सूचना प्रदान करे, उसे अपनाया जा सकता है। निम्नलिखित उदाहरण एक काल्पनिक प्रतिष्ठान का अपेक्षित है जिसे 'विविध कम्पनी' के रूप में संबोधित किया गया है।

किसी प्रतिष्ठान के रिपोर्ट योग्य खण्डों के बारे में विस्तृत वर्णनात्मक सूचना

का दि 2 किसी प्रतिष्ठान के रिपोर्ट योग्य खण्डों के बारे में विस्तृत सूचना प्रकट करने के लिए नीचे एक उदाहरण दिया गया है। (भारतीय लेखा मानक से संबंधित अपेक्षाओं के लिए अनुच्छेदों का संदर्भ दिया गया है)

उत्पादों तथा सेवाओं के प्रकारों का वर्णन जिनसे प्रत्येक रिपोर्ट योग्य खण्ड राजस्व प्राप्त करता है [अनुच्छेद 22 (ख)]

'विविध कम्पनी' के पाँच रिपोर्ट योग्य खण्ड हैं : कार के पुर्जे, मोटर पोत, साफ्टवेयर, इलैक्ट्रॉनिक तथा वित्त। कार के पुर्जे का खण्ड बदलने वाले कार पुर्जे खुदरा विक्रेताओं को बिक्री के लिए उत्पादित करता है। मोटर पोत खण्ड समुद्र के किनारे स्थित तेल उद्योग व इसी प्रकार के व्यवसायों के लिए छोटे मोटर पोत उत्पादित करता है। साफ्टवेयर खण्ड कम्प्यूटर विनिर्माताओं तथा खुदरा विक्रेताओं के लिए अनुप्रयोग साफ्टवेयर उत्पादित करता है। इलैक्ट्रॉनिक खण्ड एकीकृत सर्किट तथा संबंधित उत्पादों को कम्प्यूटर विनिर्माताओं को बिक्री के लिए उत्पादित करता है। वित्त खण्ड कम्पनी के वित्तीय परिचालनों के भाग के लिए ग्राहकों को अन्य खण्डों के उत्पादों की खरीद के वित्त पोषण तथा परिसंपत्ति पर ऋण परिचालनों के लिए उत्तरदायी है।

परिचालन खण्ड के लाभ या हानि, आस्तियों तथा देयताओं का माप (अनुच्छेद 27)

परिचालन खण्डों की लेखा नीतियाँ महत्वपूर्ण लेखनीतियों के सार में वर्णित लेखनीतियों के समान ही हैं सिवाय प्रत्येक परिचालन खण्ड के पेंशन के खर्च पेंशन प्लान के प्रति नकद भुगतान के आधार पर पहचाने तथा मापे जाते हैं। 'विविध कम्पनी' द्वारा कर पूर्व खर्चों से लाभ या हानि के आधार पर निष्पादन का मूल्यांकन किया जाता है जिनमें अनावर्तित न होने वाले लाभ तथा हानियाँ तथा विदेशी विनिमय लाभ या हानियाँ शामिल नहीं होते।

'विविध कम्पनी' अन्तः खण्ड बिक्रियों तथा अंतरणों का लेखा उसी प्रकार करती है मानों कि बिक्री तथा अंतरण तृतीय पार्टी को अर्थात् वर्तमान बाजार मूल्य पर किए गये हों।

प्रतिष्ठान के रिपोर्ट योग्य खण्डों की पहचान के लिए प्रबंधन द्वारा उपयोग में लाए जा रहे कारक [अनुच्छेद 22 (क)]

'विविध कम्पनी' के रिपोर्ट योग्य खण्ड महत्वपूर्ण व्यावसायिक ईकाइयाँ हैं जो विभिन्न उत्पाद तथा सेवाएं प्रदान करती हैं। उनका पृथक रूप से प्रबंधन किया जाता है क्योंकि प्रत्येक व्यवसाय के लिए अलग तकनीक तथा विपणन नीतियाँ अपेक्षित होती हैं। अधिकतर कारोबार एक इकाई के रूप में अधिगृहीत हुए थे, तथा उनके अधिग्रहण के समय प्रबंधन को जारी किया गया था।

प्रतिष्ठान के लाभ या हानि, आस्तियों तथा देयताओं के रिपोर्ट योग्य खण्डों की सूचना

का दि 3 निम्नलिखित सारणी लाभ या हानि और आस्तियों तथा देयताओं (अनुच्छेद 23 तथा 24) के रिपोर्ट योग्य खण्डों का प्रस्तावित नमूना प्रस्तुत करती है। इसी प्रकार की सूचना संबंधित प्रत्येक वर्ष के लाभ- हानि विवरण प्रस्तुत करने के लिए अपेक्षित है। विविधिकृत कम्पनी कर व्ययों (कर आय) अथवा अनावर्ती लाभों अथवा हानियों को रिपोर्ट योग्य खण्डों में आवंटित नहीं करती है। इसके अतिरिक्त, सभी रिपोर्ट योग्य खण्डों के पास लाभ या हानि के अंतर्गत मूल्यहास तथा परिशोधन के अलावा सारवान (महत्वपूर्ण) गैर नकदी मदें नहीं होती। इस दृष्टांत में दी गई राशियाँ मुख्य परिचालन निर्णयकर्ता द्वारा प्रयुक्त रिपोर्टों की राशियाँ परिकल्पित की गई हैं।

	कार पुर्जें रु.	के रु.	मोटर पोत रु.	साफ्टवेयर रु.	इलेक्ट्रॉनिक रु.	वित्त रु.	अन्य सभी रु.	योग रु.
बाहरी ग्राहकों से प्राप्त राजस्व	3,000	5,000	9,500	12,000	5,000	1,000 ^क		35,500
विनिधान राजस्व	-	-	3,000	1,500	-	-		4,500
ब्याज राजस्व	450	800	1,000	1,500	-	-		3,750
ब्याज व्यय	350	600	700	1,100	-	-		2,750
शुद्ध ब्याज राजस्व ^ख	-	-	-	-	1,000	-		1,000
मूल्यहास तथा परिशोधन	200	100	50	1,500	1,100	-		2,950
रिपोर्टयोग्य खण्ड लाभ	200	70	900	2,300	500	100		4,070
अन्य सारवान गैर नकदी मदें :-								
आस्तियों की हानि	-	200	-	-	-	-		200
रिपोर्ट योग्य खण्ड आस्तियाँ	2,000	5,000	3,000	12,000	57,000	2,000		81,000
रिपोर्ट योग्य खण्ड गैर चालू आस्तियों के प्रति व्यय	300	700	500	800	600	-		2,900
रिपोर्ट योग्य खण्ड देयताएं	1,050	3,000	1,800	8,000	30,000	-		43,850

- (क) खण्ड से मात्रात्मक सीमा से कम राजस्व 'विविध कम्पनी' के चार प्रचालन खण्डों से संबंधित हैं इन खण्डों में लघु संपत्ति कारोबार, इलैक्ट्रॉनिक उपस्कर किराए पर देने का कारोबार, साफ्टवेयर परामर्श तथा गोदाम लीज पर देने के परिचालन शामिल हैं। इनमें से किसी भी खण्ड द्वारा रिपोर्ट योग्य खण्ड के निर्धारण की मात्रात्मक सीमा को कभी भी पूरा नहीं किया गया है।
- (ख) वित्तीय खण्ड अपने राजस्व का अधिकांश भाग ब्याज से प्राप्त करता है। प्रबंधन इस खण्ड के प्रबंधन के लिए मुख्य रूप से निवल ब्याज राजस्व पर निर्भर करता है न कि सकल राजस्व तथा खर्चों की रकम पर। अतः, जैसा कि अनुच्छेद 23 के अनुसार अनुमति दी गई है, केवल निवल रकम का प्रकटन किया जाता है।

प्रतिष्ठान के लाभ या हानि, आस्तियों तथा देयताओं के रिपोर्ट योग्य खण्डों का मिलान

का दि 4 रिपोर्ट योग्य खण्ड के राजस्व, लाभ या हानि, आस्तियों तथा देयताओं के प्रतिष्ठान की तदनुसूचि रकमों के साथ समाधान के दृष्टांत नीचे दिए जा रहे हैं (पैरा 28 (क)-(घ)) प्रकट की गई (अनुच्छेद 28(ड)) अन्य सभी सारवान मदों के लिए भी समाधान अपेक्षित है। यह माना जाता है कि प्रतिष्ठान के वित्तीय विवरणों में बंद किए गए परिचालनों को शामिल नहीं किया होगा। जैसा कि अनुच्छेद का दि 2 में वर्णित किया गया है प्रतिष्ठान रिपोर्ट योग्य खण्ड के अन्तर्गत पेंशन के खर्च पेंशन प्लान के प्रति नकद भुगतान के आधार पर पहचाने तथा मापे जाते हैं तथा कुछ मदों को रिपोर्ट योग्य खण्ड में आवंटित नहीं किया जाता है।

राजस्व	रु.
रिपोर्ट योग्य खण्ड से कुल राजस्व	39,000
अन्य राजस्व	1,000
अन्तः खण्ड राजस्व कम करना	(4,500)
प्रतिष्ठान का राजस्व	35,500

लाभ या हानि	रु.
रिपोर्ट योग्य खण्ड से कुल लाभ या हानि	3,970
अन्य लाभ या हानि	100
अन्तः खण्ड लाभ कम करना	(500)
गैर आवंटित रकमों :	
मुकदमों के निपटान से प्राप्त राशि	500
अन्य निगमित खर्च	(750)
पेंशन खर्चों का समेकित रूप से समायोजन	(250)
आय कर से पूर्व आय	3,070

आस्तियाँ	रु.
रिपोर्ट योग्य खण्ड की कुल आस्तियाँ	79,000
अन्य आस्तियाँ	2,000
निगमित हेड क्वार्टर से प्राप्य कम करना	(1,000)
अन्य गैर आवंटित रकमें	1,500
प्रतिष्ठान की आस्तियाँ	81,500

आस्तियाँ	रु.
रिपोर्ट योग्य खण्ड की कुल आस्तियाँ	79,000
अन्य आस्तियाँ	2,000
निगमित हेड क्वार्टर से प्राप्य कम करना	(1,000)
अन्य गैर आवंटित रकमें	1,500
प्रतिष्ठान की आस्तियाँ	81,500

देयताएं	रु.
रिपोर्ट योग्य खण्ड की कुल देयताएं	43,850
गैर आवंटित सूचित पेंशन लाभ देयताएं	25,000
प्रतिष्ठान की देयताएं	68,850

अन्य सारवान मदें	रिपोर्ट योग्य	समायोजन	प्रतिष्ठान का योग
खण्ड योग	रु.	रु.	रु.
ब्याज राजस्व	3,750	75	3,825
ब्याज व्यय	2,750	(50)	2,700
शुद्ध ब्याज राजस्व (केवल वित्त खण्ड)	1,000	-	1,000
आस्तियों के लिए खर्च	2,900	1,000	3,900
अवक्षयण तथा परिशोधन	2,950	-	2,950
आस्तियों की हानि	200	-	200

आस्तियों के खर्चों के समायोजन के लिए निगम के प्रधान कार्यालय भवन के लिए खर्च हुई रकम समाधान संबंधी मद है जिसे खण्ड जानकारी में शामिल नहीं किया गया है। अन्य कोई भी समायोजन सारवान नहीं है।

भौगोलिक सूचना

का दि 5 अनुच्छेद 33 के अनुसार अपेक्षित भौगोलिक जानकारी के दृष्टांत नीचे दिए जा रहे हैं। (चूंकि 'विविध कम्पनी' के रिपोर्ट योग्य खण्ड उत्पादों तथा सेवाओं की भिन्नताओं पर आधारित है, उत्पादों तथा सेवाओं के संबंध में राजस्व की अतिरिक्त जानकारी के प्रकटन की आवश्यकता नहीं है। (अनुच्छेद 32))

भौगोलिक सूचना रु.	राजस्व ^० रु.	गैर चालू आस्तियाँ रु.
संयुक्त राष्ट्र	19,000	11,000
कनाडा	4,200	-
चीन	3,400	6,500
जापान	2,900	3,500
अन्य देश	6,000	3,00
योग	35,500	24,000

(क) देशों में राजस्व का वर्णन ग्राहकों की अवस्थिति के आधार पर है।

प्रमुख ग्राहकों संबंधी सूचना

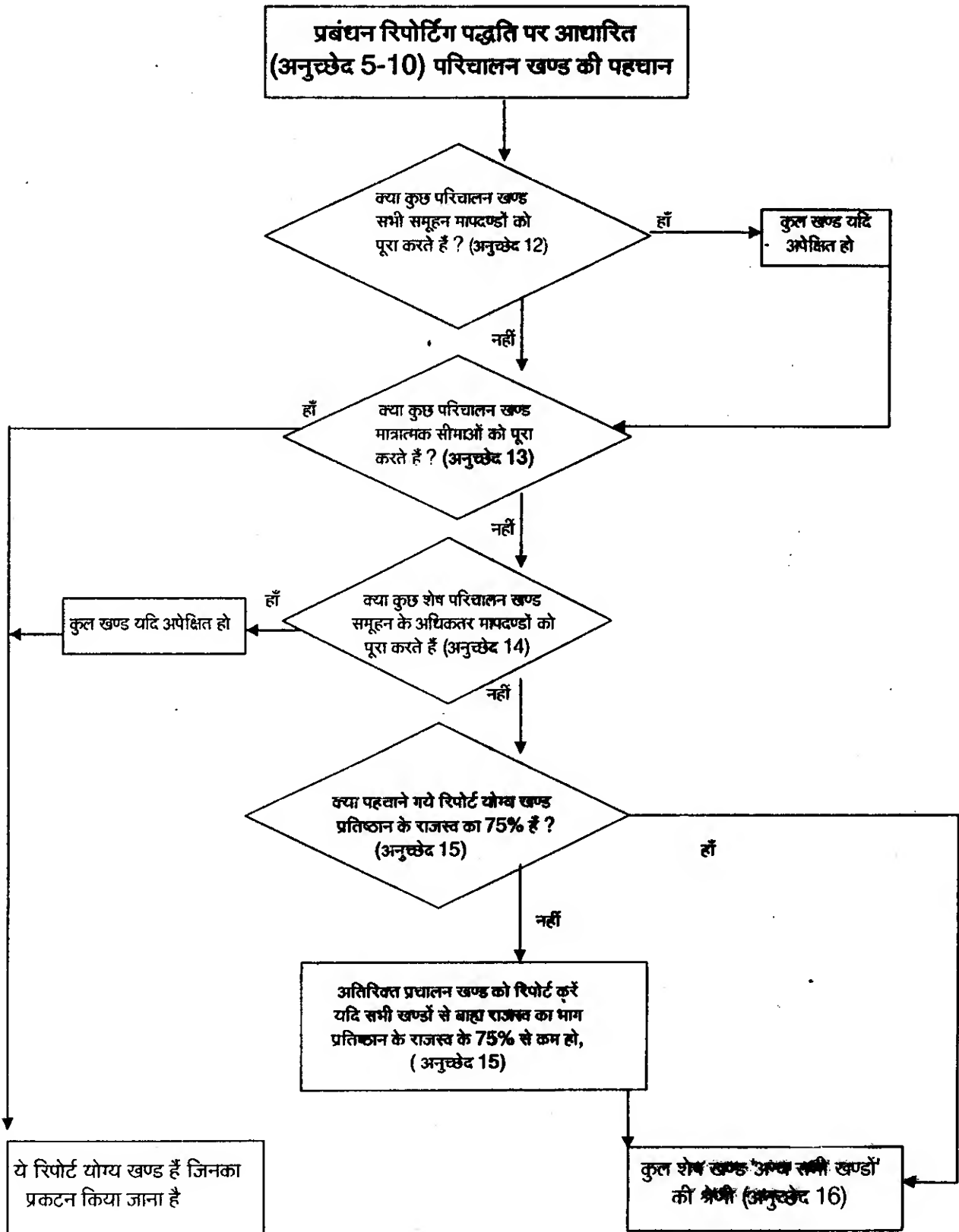
का दि 6 अनुच्छेद 34 के अनुसार प्रमुख ग्राहकों की जानकारी संबंधी दृष्टांत नीचे दिए जा रहे हैं। प्रत्येक परिचालन खण्ड के लिए न तो ग्राहक की पहचान और न ही राजस्व की रकम अपेक्षित है।

'विविध कम्पनी' के सॉफ्टवेयर तथा इलेक्ट्रॉनिक खण्ड से कम्पनी के कुल राजस्व से किसी एक ग्राहक का राजस्व लगभग रु. 5000 है।

रिपोर्ट योग्य खण्डों की पहचान में सहायता के लिए सहायक आरेख

का दि 7 निम्न आरेख लेखा मानकों में यथा परिभाषित रिपोर्ट योग्य खण्डों की पहचान के लिए मुख्य उपबंधों को लागू करने की विधि दर्शाता है। यह आरेख भारतीय लेखा मानक का दृश्य संपूरक है। इसकी व्याख्या भारतीय लेखा मानक की किसी अपेक्षा को बदले अथवा जोड़े गए रूप में न की जाए न ही इसे किसी अपेक्षा के विकल्प के रूप में माना जाए।

रिपोर्टयोग्य खण्डों की पहचान का आरेख



परिशिष्ट 1

टिप्पणी - यह परिशिष्ट भारतीय लेखा मानक का अंग नहीं है। इस परिशिष्ट का प्रयोजन मात्र इतना है कि भारतीय लेखा मानक (इंड ए एस) 108 और तदनुरूपी अन्तरराष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग मानक (आई एफ आर एस) 8 *परिचालन खण्ड* के बीच अंतर को स्पष्ट किया जाए।

'आई एफ आर एस' 8 *परिचालन खण्ड* के साथ तुलना

1. 'आई एफ आर एस' 108 में दिये गये संक्रमणकालीन प्रावधान भारतीय लेखा मानक 108 में इस दृष्टि से नहीं दिये गये हैं क्योंकि भारतीय लेखा मानकों से संबंधित सभी संक्रमणकालीन प्रावधान, जहां उचित है, भारतीय लेखा मानक 101 *भारतीय लेखा मानकों का प्रथमवार अंगीकरण* में सम्मिलित कर दिये गये हैं। जो कि आई एफ आर एस 1, *भारतीय लेखा मानकों का प्रथमवार अंगीकरण* के तदनुरूप है।
2. इस भारतीय लेखा मानक में मौजूदा कानूनों में प्रयुक्त शब्दावली से भिन्न शब्दावली का प्रयोग किया गया है, उदाहरणार्थ, शब्दों 'वित्तीय स्थिति का विवरण' के स्थान पर शब्द 'तुलन-पत्र' और शब्दों 'व्यापक आय का विवरण' के स्थान पर शब्द 'लाभ-हानि विवरण' का प्रयोग किया गया है।

भारतीय लेखा मानक (इंड ए एस) 1

वित्तीय विवरणों का प्रस्तुतिकरण

(इस भारतीय लेखा मानक में *मोटे टाइप* व सामान्य टाइप में अनुच्छेद हैं। इन दोनों तरह के अनुच्छेदों का समान प्राधिकार है। मोटे टाइप में अनुच्छेद मुख्य सिद्धान्तों के सूचक हैं।)

उद्देश्य

1. यह भारतीय लेखा मानक सामान्य प्रयोजन वाले वित्तीय विवरणों के प्रस्तुतिकरण का आधार निर्धारित करता है ताकि प्रतिष्ठान वित्तीय विवरणों का पूर्व अवधियों और अन्य प्रतिष्ठानों के वित्तीय विवरणों से तुलनात्मकता सुनिश्चित की जा सके। यह वित्तीय विवरणों के प्रस्तुतिकरण, उनकी संरचना के लिए मार्गदर्शन और उनकी विषय-वस्तु की न्यूनतम आवश्यकताओं सम्बन्धी समग्र अपेक्षाओं को निश्चित करता है।

कार्यक्षेत्र

2. एक प्रतिष्ठान अपने सामान्य प्रयोजन वाले वित्तीय विवरणों को तैयार करने और प्रस्तुत करने के लिए इस मानक का प्रयोग करेगा ताकि भारतीय लेखा मानकों का अनुपालन किया जा सके।
3. अन्य भारतीय लेखा मानक विशिष्ट लेन-देनों और अन्य घटनाओं की मान्यता, माप और प्रकटन जैसी अपेक्षाओं को निश्चित करते हैं।
4. यह भारतीय लेखा मानक, भारतीय लेखा मानक (इंड ए एस) 34 '*अन्तरिम वित्तीय रिपोर्टिंग*' के अनुसार तैयार की गई संघनित अन्तरिम वित्तीय विवरणों की संरचना और विषय वस्तु पर लागू नहीं होता है। लेकिन, अनुच्छेद 15-35 ऐसे वित्तीय विवरणों पर लागू होते हैं। यह मानक

समेकित वित्तीय विवरणों के प्रस्तुतकर्ता और पृथक वित्तीय विवरणों के प्रस्तुतकर्ता, जैसा कि भारतीय लेखा मानक 27 'समेकित और पृथक वित्तीय विवरण' में परिभाषित है, सहित सभी प्रतिष्ठानों के वित्तीय विवरणों पर समान रूप से लागू होता है।

5. यह भारतीय लेखा मानक ऐसी शब्दावली का प्रयोग करता है, जो सार्वजनिक क्षेत्र के व्यावसायिक प्रतिष्ठानों सहित लाभ मूलक प्रतिष्ठानों के लिए उपयुक्त है। यदि निजी क्षेत्र या सार्वजनिक क्षेत्र के गैर-लाभकारी गतिविधियों वाले प्रतिष्ठान इस मानक को लागू करते हैं तो वे उन्हें अपने वित्तीय विवरणों में और वित्तीय विवरणों की विशेष रेखीय मदों के वर्णन में तदनुसार संशोधन करना पड़ सकता है।
6. इसी तरह, वे प्रतिष्ठान जिनकी शेयर पूंजी 'ईक्विटी' नहीं होती तब वित्तीय विवरण के प्रस्तुतिकरण को सदस्यों के हितों के लिए तदनुसार सामंजस्य स्थापित करने की आवश्यकता पड़ सकती है।

परिभाषाएं

7. इस भारतीय लेखा मानक में निम्नलिखित शब्दावली का प्रयोग यहां विनिर्दिष्ट अर्थों में किया गया है:

सामान्य प्रयोजन वाले वित्तीय विवरण (जिनका उल्लेख वित्तीय विवरणों के रूप में किया जाता है) वे विवरण हैं जो उन उपयोगकर्ताओं की सूचना संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, जो इस स्थिति में नहीं हैं कि वे प्रतिष्ठान को अपनी विशेष सूचनाओं के लिए रिपोर्ट तैयार करने के लिए कह सकें।

अव्यवहार्य : जब कोई प्रतिष्ठान सभी युक्तिसंगत प्रयासों के बाद भी एक अपेक्षा को लागू न कर पाये तो ऐसी स्थिति में वह अपेक्षा अव्यवहार्य मानी जायेगी।

भारतीय लेखा मानक (इंड ए एस) वे मानक हैं जो कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 211 (3 ग) के अंतर्गत नियत हैं।

मदों की **सारवान** (महत्त्वपूर्ण) चूक या त्रुटिपूर्ण कथन तब तक सारवान (महत्त्वपूर्ण) होते हैं, जब तक कि वे व्यक्तिशः या सामूहिक रूप से उन आर्थिक निर्णयों को प्रभावित करते हैं जिन्हें वित्तीय विवरणों के आधार पर प्रयोगकर्ता लेते हैं। 'सारवानता' चूक या त्रुटिपूर्ण कथन के आकार और प्रकृति पर निर्भर करती है और इसका निर्णय इसके इर्द-गिर्द की परिस्थितियों पर आधारित होता है। मद का आकार या प्रकृति, या फिर दोनों का मिश्रण, निर्धारक तत्व हो सकता है।

यह निर्धारित करना कि चूक या त्रुटिपूर्ण कथन उपयोगकर्ताओं के आर्थिक निर्णयों को प्रभावित कर सकता है, और इस प्रकार यह सारवान है, इसके लिए उन उपयोगकर्ताओं की विशेषताओं पर भी ध्यान देने की आवश्यकता होती है। **वित्तीय विवरण तैयार करना एवं उनके प्रस्तुतिकरण विषयक मूलभूत कार्यपद्धति** के बारे में जो भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा अनुच्छेद 25 में यह कल्पित है कि उपयोगकर्ताओं को कारोबार, आर्थिक गतिविधियों और लेखांकन का काफी हद तक ज्ञान है और वे सूचना का अध्ययन ध्यानपूर्वक करने में इच्छुक हैं। अतः यह ध्यान रखने की आवश्यकता है कि इन लक्षणों के होते हुए वे उपयोगकर्ता आर्थिक निर्णय लेने में किस प्रकार से प्रभावित हो सकते हैं।

टिप्पणियां ये वे उल्लेख हैं जो तुलन पत्र, लाभ-हानि व नकदी प्रवाह विवरण में दी गयी सूचना के अतिरिक्त हैं (इनमें तुलन पत्र के साथ संलग्न ईक्विटी में परिवर्तन का विवरण भी सम्मिलित है) इन टिप्पणियों में वर्णनात्मक उल्लेख या विवरणों में प्रस्तुत मदों का ब्यौरा और उन मदों की सूचना दी जाती जो विवरणों में मान्यता के लिए अहर्ता प्राप्त नहीं करती हैं।

अन्य व्यापक आय में उस आय और व्यय (पुनर्वर्गीकरण समायोजन सहित) की वे मदें आती हैं जो अन्य भारतीय लेखा मानकों की अपेक्षा या अनुमति के अनुसार लाभ या हानि में मान्यता प्राप्त नहीं है।

अन्य व्यापक आय में निम्नलिखित घटक या अवयव सम्मिलित हैं : -

- (क) पुनर्मूल्यांकन अधिशेष में परिवर्तन [देखिये भारतीय लेखा मानक 16 : 'सम्पत्ति, संयंत्र और उपकरण' तथा भारतीय लेखा मानक 38 : 'अमूर्त आस्तियां'] ;
- (ख) भारतीय लेखा मानक 19 *कर्मचारी लाभ* के अनुच्छेद 92 व 129 'क' के अनुसार मान्य निश्चित लाभ योजनाओं पर बीमांकिक लाभ व हानियां ;
- (ग) विदेशी परिचालन के वित्तीय विवरणों के रुपान्तरण के फलस्वरूप लाभ और हानियां [देखिये भारतीय लेखा मानक 21 : *विदेशी विनिमय दरों में परिवर्तनों के प्रभाव*] ;
- (घ) बिक्री के लिए उपलब्ध वित्तीय आस्तियां के पुनर्माप पर लाभ और हानियां [देखिये भारतीय लेखा मानक 39 : *वित्तीय लिखतें, मान्यता और माप*] ;
- (ङ) एक नकदी प्रवाह प्रतिरक्षा (हैजिंग) में प्रतिरक्षा लिखतों पर लाभ और हानियों का प्रभावी भाग [देखिये भारतीय लेखा मानक 39]

स्वामी वे व्यक्ति हैं जो उन लिखतों के धारक हैं जिन्हें ईक्विटी के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

लाभ या हानि कुल आय में से व्यय घटाने (लाभ) या व्यय में से आय घटाने (हानि) की स्थिति है, लेकिन इस कुल आय में अन्य व्यापक आय के अवयव सम्मिलित नहीं होंगे।
पुनर्वर्गीकृत समायोजन वे राशियां हैं जिन्हें वर्तमान अवधि में लाभ या हानि हेतु वर्गीकृत किया गया है और वे वर्तमान या पूर्व अवधियों में व्यापक आय के रूप में मान्य थीं।

कुल व्यापक आय : एक अवधि के दौरान, 'ईक्विटी' में हुआ परिवर्तन है जो कि लेन देनों और अन्य घटनाओं से उत्पन्न हुआ हो, लेकिन इन में वे परिवर्तन शामिल नहीं हैं जो स्वामियों की हैसियत के रूप में स्वामियों के साथ लेन-देनों के परिणाम स्वरूप उत्पन्न हुए हों।

कुल व्यापक आय में लाभ या हानि और अन्य व्यापक आय के सभी अवयव सम्मिलित हैं।

8. [देखिये परिशिष्ट 1]

8(क) इस मानक में भारतीय लेखा मानक 32 '*वित्तीय लिखतों का प्रस्तुतिकरण*' तथा भारतीय लेखा मानक 32 में यथा वर्णित और उसी में यथा विनिर्दिष्ट अर्थों में निम्नलिखित शब्दावली का प्रयोग किया गया है : -

- (क) अंकनयोग्य लिखतें वे हैं जो 'ईक्विटी' लिखतों के रूप में वर्गीकृत की गयी हैं।
[भारतीय लेखा मानक 32 के अनुच्छेद 16 क और 16 ख में यथा वर्णित]

- (ख) एक लिखत, जो केवल परिसमापन की अवस्था में तथा वह जो एक इक्विटी लिखत के रूप में वर्गीकृत हो, प्रतिष्ठान की निवल आस्तियों का आनुपातिक भाग अन्य पक्ष को सौंपने का दायित्व प्रतिष्ठान पर डालती हो [भारतीय लेखा मानक 32 के अनुच्छेद 16 ग और 16 घ में यथा वर्णित]

वित्तीय विवरण

वित्तीय विवरणों का प्रयोजन

9. वित्तीय विवरण किसी प्रतिष्ठान की वित्तीय स्थिति और वित्तीय कार्य-निष्पादन की संरचित प्रस्तुति है। वित्तीय विवरणों का उद्देश्य किसी प्रतिष्ठान की वित्तीय स्थिति, वित्तीय कार्य-निष्पादन और नकदी प्रवाहों (कैश फ्लो) के बारे में सूचना प्रदान करना है ताकि अनेक प्रकार के उपयोगकर्ताओं को आर्थिक निर्णय लेने में उपयोगी हों। वित्तीय विवरण इस बात के भी प्रतीक है कि प्रबंधन को जो संसाधन उपलब्ध करवाए गये थे उनका उसने किस बाखूबी ढंग से उपयोग किया है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए वित्तीय विवरण एक प्रतिष्ठान के बारे में निम्नलिखित सूचना प्रदान करते हैं: -

- (क) आस्तियां ;
- (ख) देयताएं ;
- (ग) इक्विटी ;
- (घ) लाभ और हानि सहित आय एवं व्यय ;
- (ङ) स्वामियों द्वारा स्वामियों की हैसियत से किया गया अंशदान तथा उनको उसी हैसियत से किया गया वितरण, और
- (च) नकदी प्रवाह (कैश फ्लो)

यह सूचना, टिप्पणियों में दी गई अन्य सूचना के साथ, वित्तीय विवरणों के उपयोगकर्ताओं को प्रतिष्ठान के भावी नकदी प्रवाहों को और विशेषकर उनकी समय-अवधि और निश्चितता के सम्बन्ध में पूर्वानुमान लगाने में सहायता करती है।

वित्तीय विवरणों का सम्पूर्ण समुच्चय (सैट)

10. वित्तीय विवरणों के एक सम्पूर्ण समुच्चय (सैट) में निम्नलिखित विवरण / उल्लेख होते हैं:-
- (क) एक अवधि की समाप्ति पर एक तुलन पत्र (ईक्विटी में परिवर्तन के विवरण सहित जो इसके साथ संलग्न रहता है);
 - (ख) एक अवधि का लाभ हानि विवरण ;

- (ग) [देखिये परिशिष्ट 1] ;
- (घ) एक अवधि के नकदी प्रवाह का विवरण ;
- (ङ) टिप्पणियां जिनमें महत्वपूर्ण लेखा नीतियां का सारांश और अन्य व्याख्यात्मक सूचनाएं दी जाती हैं; और
- (च) सबसे से पुरानी तुलनात्मक अवधि के प्रारम्भ का तुलन पत्र, जब प्रतिष्ठान एक लेखा नीति को पूर्व प्रभाव से लागू करता है या वित्तीय विवरणों की मदों के बारे में पूर्व प्रभाव से पुनर्कथन करता है या फिर वह वित्तीय विवरणों में मदों का पुनर्वर्गीकरण करता है।
11. एक प्रतिष्ठान वित्तीय विवरणों के एक सम्पूर्ण समुच्चय (सैट) में सम्मिलित सभी वित्तीय विवरणों को एक-समान प्रमुखता के साथ प्रस्तुत करेगा ।
12. अनुच्छेद 81 के अनुसार, एक प्रतिष्ठान लाभ या हानि के घटकों अथवा अवयवों और अन्य व्यापक आय के घटकों को लाभ और हानि के एक एकल विवरण के भाग के रूप में प्रस्तुत करेगा ।
13. अनेक प्रतिष्ठान, वित्तीय विवरणों के अतिरिक्त, प्रबन्धन की ओर से एक वित्तीय समीक्षा पत्र भी प्रस्तुत करते हैं, जिसमें प्रतिष्ठान के वित्तीय कार्य निष्पादन और वित्तीय स्थिति के मुख्य पक्षों और इसके समक्ष प्रमुख अनिश्चितताओं का उल्लेख किया जाता है। ऐसे समीक्षा पत्र या रिपोर्ट में निम्नलिखित सम्मिलित हो सकते हैं :
- (क) वित्तीय कार्य निष्पादन के निर्धारक प्रमुख घटक और जिस वातावरण में प्रतिष्ठान कार्य कर रहा है, उसमें हुए या हो रहे परिवर्तन, उन परिवर्तनों का प्रतिष्ठान पर प्रभाव और प्रतिष्ठान की इन परिवर्तनों के प्रति प्रतिक्रिया, प्रतिष्ठान की कार्य निष्पादन को बढ़ाने व लाभांश की नीति ;
- (ख) प्रतिष्ठान के निधि स्रोत और इसका देयता-ईक्विटी अनुपात का लक्ष्य ; तथा
- (ग) प्रतिष्ठान के वे संसाधन जिन्हें भारतीय लेखा मानकों के अनुसार तुलन पत्र में मान्यता नहीं दी गई है।
14. बहुत-से प्रतिष्ठान वित्तीय विवरणों के अतिरिक्त अन्य रिपोर्ट और विवरण भी प्रस्तुत करते हैं। ये रिपोर्टें या विवरण हालांकि भारतीय लेखा मानकों के कार्य क्षेत्र के अन्तर्गत तो नहीं आते लेकिन वे अन्य प्रयोजनों से महत्वपूर्ण व उपयोगी हो सकते हैं जैसे पर्यावरणात्मक रिपोर्टें व मूल्यवर्धक विवरण विशेष रूप से उन उद्योगों के लिए जिनका पर्यावरण से सीधा सम्बन्ध है। साथ ही, इन उद्योगों के कर्मचारी भी महत्वपूर्ण उपयोगकर्ता की श्रेणी में आते हैं। रिपोर्ट एवं विवरण जो वित्तीय विवरणों के बाहर प्रस्तुत किए गये हों वे इस भारतीय लेखा मानक के कार्यक्षेत्र से बाहर हैं।

सामान्य लक्षण

सत्य और उचित दृश्य का प्रस्तुतिकरण और भारतीय लेखा मानकों का अनुपालन

15. वित्तीय विवरण, प्रतिष्ठान की वित्तीय स्थिति, वित्तीय कार्य निष्पादन और नकदी प्रवाहों का सत्य और उचित दृश्य प्रस्तुत करेंगे। सत्य और उचित दृश्य की प्रस्तुति के लिए मूलभूत कार्य विधि के ढांचे में दी गयीं आस्तियों, देयताओं, आय और व्यय की परिभाषाओं और मान्यता मानदण्डों के अनुसार लेन-देनों अन्य घटनाओं और परिस्थितियों के प्रभावों का सत्य और उचित दृश्य प्रस्तुत करना आवश्यक होता है। भारतीय लेखा मानकों का प्रयोग और जहां अतिरिक्त प्रकटन आवश्यक हो, यह माना जाता है कि वित्तीय विवरण प्रतिष्ठान की वित्तीय स्थिति का सत्य और उचित दृश्य प्रस्तुत करते हैं।
16. एक प्रतिष्ठान जब वित्तीय विवरणों को तैयार व प्रस्तुत करने में भारतीय लेखा मानकों का अनुपालन करता है तो वह इस आशय का टिप्पणियों में साफ और स्पष्ट वर्णन करेगा। भारतीय लेखा मानकों के अनुपालन का तात्पर्य यह है कि वित्तीय विवरण उनका अनुपालन पूर्ण रूप से करें और तभी उसे अनुपालन माना जाएगा।
17. वास्तव में, सभी परिस्थितियों में, सत्य और उचित दृश्य की प्रस्तुति केवल प्रतिष्ठान पर लागू भारतीय लेखा मानकों के अनुपालन द्वारा ही प्राप्त की जा सकती है। सत्य और उचित दृश्य की प्रस्तुति के लिए प्रतिष्ठान को निम्नलिखित की भी आवश्यकता होती है :-
 - (क) भारतीय लेखा मानक 8 *लेखा नीतियां, लेखा प्राक्कलन में परिवर्तन और त्रुटियों* के अनुसार लेखा नीतियों का चयन और प्रयोग। भारतीय लेखा मानक 8 प्राधिकृत मार्गदर्शन की एक क्रमबद्ध श्रृंखला निर्धारित करता है, जब किसी मद पर कोई भारतीय लेखा मानक विशिष्ट रूप से लागू न हो तो उस स्थिति में प्रबंधन इस श्रृंखला से मार्गदर्शन प्राप्त कर विचार कर सकता है।
 - (ख) लेखा नीतियों सहित सूचना को इस तरह से प्रस्तुत करना कि वह प्रासांगिक, विश्वसनीय, तुलनीय, और बोधगम्य हो।
 - (ग) जब भारतीय लेखा मानकों के अनुसार अपेक्षाओं का अनुपालन उपयोगकर्ता के लिए विशिष्ट लेन-देनों, अन्य घटनाओं और परिस्थितियों में प्रतिष्ठान की वित्तीय स्थिति और वित्तीय कार्य-निष्पादन पर प्रभाव समझने के लिए अपर्याप्त हो तो अतिरिक्त सूचना का प्रकटन करना।
18. एक प्रतिष्ठान अनुपयुक्त लेखा नीतियों का शोधन, प्रयोग में लायी गयी लेखा नीतियों के प्रकटन या टिप्पणियों द्वारा या व्याख्यात्मक सामग्री देकर नहीं कर सकता।
19. अत्यन्त असामान्य परिस्थितियों में, जहां प्रबंधन यह निष्कर्ष निकालता है कि एक भारतीय लेखा मानक की आवश्यकताओं का अनुपालन इतना भ्रामक है कि वह मूलभूत विधि ढांचे में यथावर्णित वित्तीय विवरणों के उद्देश्य के साथ अन्तर्विरोध उत्पन्न कर रहा है तो प्रतिष्ठान इस अपेक्षा से अनुच्छेद 20 में उल्लिखित विधि द्वारा विचलित करेगा बशर्ते नियामक मूलभूत

विधि ढांचा इस प्रकार के विचलन की अपेक्षा करता हो या इस तरह के विचलन को अन्यथा प्रतिबंधित न करता हो ।

20. जब कोई प्रतिष्ठान, अनुच्छेद 19 के अनुसार भारतीय लेखा मानक की अपेक्षा से विचलन करता है तो इसको यह प्रकट करना होगा :

- (क) प्रतिष्ठान का प्रबंधन इस निष्कर्ष पर पहुँचा है कि वित्तीय विवरण प्रतिष्ठान की वित्तीय स्थिति, वित्तीय कार्य निष्पादन और नकदी प्रवाहों का सत्य और उचित दृश्य प्रस्तुत करते हैं।
- (ख) प्रतिष्ठान ने लागू भारतीय लेखा मानकों का अनुपालन तो किया है लेकिन इसने सत्य और उचित दृश्य प्रस्तुत करने की विशेष अपेक्षा से विचलन किया है।
- (ग) भारतीय लेखा मानक का शीर्षक या नाम जिससे प्रतिष्ठान ने विचलन किया है, विचलन की प्रकृति और इसके लिए भारतीय लेखा मानक द्वारा की गयी अपेक्षा, कारण कि इन परिस्थितियों में अपेक्षित लेखा विधि के अनुपालन से इतना भ्रम क्यों होगा और मूलभूत विधि ढांचे में वित्तीय विवरणों के प्रयोजन से यह कैसे अन्तर्विरोधी है, ऐसी परिस्थितियों का उल्लेख, और
- (घ) प्रस्तुत प्रत्येक अवधि के लिए अपेक्षा, वित्तीय विवरणों के प्रत्येक मद पर विचलन का वित्तीय प्रभाव जिसे भारतीय लेखा मानकों की अपेक्षा के अनुपालन में दर्शाया गया है।

21. जब एक प्रतिष्ठान पूर्व अवधि में, एक भारतीय लेखा मानक की अपेक्षा से विचलित हुआ हो, और ऐसा विचलन वर्तमान अवधि के वित्तीय विवरणों की राशियों को प्रभावित करता हो, तो वह प्रतिष्ठान अनुच्छेद 20 (ग) और (घ) में दी गयी व्यवस्था के अनुसार प्रकटन करेगा ।

22. अनुच्छेद 21 लागू होता है जब, उदाहरणार्थ, एक प्रतिष्ठान आस्तियों या देयताओं के माप के लिए एक भारतीय लेखा मानक की अपेक्षा का पूर्व अवधि में विचलन करता हो और वह विचलन वर्तमान अवधि के वित्तीय विवरणों में मान्य सम्पत्तियों और देयताओं के परिवर्तन के माप को भी प्रभावित करता हो ।

23. अत्यंत दुर्लभ परिस्थितियों में, जब प्रबन्धन यह निष्कर्ष निकालता है कि एक भारतीय लेखा मानक की अपेक्षा का अनुपालन इतना भ्रामक होगा कि मूलपद्धति में यथा वर्णित वित्तीय विवरणों के उद्देश्य के साथ इसका अन्तर्विरोध होगा, परन्तु प्रासंगिक नियामक ढांचा इस अपेक्षा से विचलन को प्रतिबन्धित करता है तो प्रतिष्ठान यथा संभव सीमा तक, अनुपालन के ज्ञात भ्रामक पहलूओं को निम्नलिखित को प्रकट करते हुए कम करेगा : -

- (क) विवादित भारतीय लेखा मानक का शीर्षक, अपेक्षा की प्रकृति और वह कारण जिससे कि प्रबन्धन ने यह निष्कर्ष क्यों निकाला कि इस अपेक्षा का अनुपालन इन परिस्थिति में इतना भ्रामक होगा कि इससे मूलपद्धति ढांचे में यथा वर्णित वित्तीय विवरणों के उद्देश्य से इसका अन्तर्विरोध होगा ; और

(ख) प्रस्तुत प्रत्येक अवधि के लिए, वित्तीय विवरणों में उल्लिखित प्रत्येक मद के लिए समायोजन जो कि प्रबन्धन के निष्कर्ष के अनुसार जरूरी है ताकि सत्य एवं उचित स्थिति प्रस्तुत की जा सके।

24. अनुच्छेदों 19-23 के प्रयोजनार्थ, सूचना की एक मद वित्तीय विवरणों के उद्देश्य के साथ अन्तर्विरोध रखती है। जब यह लेन-देनों, अन्य घटनाओं या परिस्थितियों की सही प्रस्तुति नहीं करती, जो या तो इसका अभिप्राय है या यथोचित प्रस्तुति के लिए उम्मीद की जा सकती है, तो इससे परिणामतया वित्तीय विवरणों के उपयोगकर्ताओं द्वारा लिये गये आर्थिक निर्णय प्रभावित होंगे। जब यह निर्धारण करते हैं कि एक भारतीय लेखा मानक की विशेष अपेक्षा की अनुपालना द्वारा भ्रम की स्थिति होती है जो कि मूल-पद्धति ढांचे में वर्णित वित्तीय विवरणों के उद्देश्य के साथ अन्तर्विरोध करेगी तो प्रबंधन निम्नलिखित पर विचार करता है :

- (क) विशेष परिस्थितियों में वित्तीय विवरणों का उद्देश्य क्यों पूरा नहीं होता है; और
- (ख) इस प्रतिष्ठान की परिस्थितियां अन्य उन प्रतिष्ठानों से कैसे भिन्न हों, जो इस अपेक्षा का अनुपालन कर रहे हैं। यदि इसी प्रकार की परिस्थितियों में अन्य प्रतिष्ठान इस अपेक्षा का अनुपालन कर रहे हैं तो यह पूर्व धारणा खण्डनीय है कि प्रतिष्ठान द्वारा इस अपेक्षा का अनुपालन इतना भ्रामक नहीं होगा कि वह मूल पद्धति ढांचे में निर्धारित वित्तीय विवरणों के उद्देश्य का विरोध करेगा।

चलायमान समुत्थान

25. वित्तीय विवरणों को तैयार करते समय, प्रबन्धन प्रतिष्ठान के चलायमान समुत्थान के रूप में निरन्तर चलते रहने की योग्यता का निर्धारण करेगा। एक प्रतिष्ठान चलायमान समुत्थान के आधार पर तब तक वित्तीय विवरण तैयार करेगा जब तक प्रबन्धन का इरादा या तो प्रतिष्ठान बन्द करने का न हो या व्यापार बन्द न करे या फिर इसके पास इसके सिवाय ऐसा कोई वास्तविक विकल्प न हो। जब प्रबन्धन अपने निर्धारण में इस स्थिति के प्रति अवगत है कि महत्वपूर्ण अनिश्चितताओं से संबंधित घटनाएं या परिस्थितियां प्रतिष्ठान के उन चलायमान समुत्थान के रूप में जारी रहना सन्देहास्पद है तो प्रतिष्ठान उन अनिश्चितताओं को प्रकट करेगा। जब प्रतिष्ठान वित्तीय विवरण चलायमान समुत्थान के आधार पर तैयार नहीं करता, तो यह इस तथ्य को प्रकट करेगा और साथ ही यह उल्लेख करेगा कि वित्तीय विवरण किस आधार पर तैयार किये गये हैं और किन कारणों से प्रतिष्ठान को चलायमान समुत्थान क्यों नहीं माना गया है।

26. चलायमान समुत्थान की संकल्पना की उपयुक्तता के निर्धारण में प्रबन्धन भविष्य के बारे में सभी उपलब्ध सूचना को ध्यान में रखकर विचार करता है जो कि कम से कम रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति के 12 महीने तक हो, परन्तु इतने तक ही सीमित भी न हो। विचार की सीमा प्रत्येक मामले में तथ्यों पर निर्भर करती है। जब एक प्रतिष्ठान का लाभकारी परिचालन का इतिहास रहा हो और उसकी वित्तीय संसाधनों तक पहुँच सुगम हो, तो वह प्रतिष्ठान बिना किसी विस्तृत विश्लेषण के इस निष्कर्ष पर पहुँच सकता है कि चलायमान समुत्थान का आधार उसके लिए

उपयुक्त है। लेकिन अन्य मामलों में, इससे पूर्व अपने आपको यह संतुष्ट करने के लिए कि उनके लिए चलायमान समुत्थान का आधार उपयुक्त है, प्रतिष्ठानों को अपनी वर्तमान और संभावित लाभ-योग्यता, ऋण पुनर्भुगतान की समयसूचियाँ और प्रतिस्थापन वित्त के संभावित स्रोत आदि अनेक घटकों पर विचार करना आवश्यक है।

लेखा का प्रोद्भूत आधार

27. एक प्रतिष्ठान अपने वित्तीय विवरण, नकदी प्रवाह विवरण को छोड़कर, लेखा प्रोद्भव आधार पर तैयार करेगा।
28. जब लेखों का प्रोद्भवन आधार का उपयोग किया जाता है, तो प्रतिष्ठान मूलपद्धति के ढाँचे में दी गयी परिभाषा व मान्यता मानदण्ड की सन्तुष्टि के आधार पर आस्तियाँ, देयताएँ, ईक्विटी आय और व्यय जैसी मदों (वित्तीय विवरणों के घटक) को मान्यता देता है।

सारवानता एवं एकीकरण

29. एक प्रतिष्ठान एक समान मदों के प्रत्येक महत्त्वपूर्ण (सारवान) वर्ग को अलग से प्रस्तुत करेगा। जबकि असमान प्रकृति या कार्य वाली मदों को, जब तक वे सारहीन नहीं हैं, अलग-से प्रस्तुत करेगा। लेकिन, जब विधि द्वारा ऐसी अपेक्षा हो तो उन्हें तदनुसार ही प्रस्तुत किया जाएगा।
30. वित्तीय विवरण बड़ी संख्या में उन लेन देनों और अन्य घटनाओं के फलस्वरूप तैयार किये जाते हैं जिन्हें प्रकृति या कार्य के आधार पर वर्गों में एकीकृत किया जा सकता है। एकीकरण और वर्गीकरण प्रक्रिया का अन्तिम चरण आंकड़ों को संघनित और वर्गीकृत रूप से प्रस्तुत करना, जो कि वित्तीय विवरणों की रेखीय मदों (लाईन आयटम) का निर्माण करते हैं। यदि कोई एक रेखीय मद अपने में महत्त्वपूर्ण नहीं है, तो उसे विवरणों या टिप्पणियों में अन्य मदों के साथ एकीकृत कर दिया जाता है। यदि कोई मद पर्याप्त रूप से महत्त्वपूर्ण नहीं है और उसे विवरण में दिखाना आवश्यक नहीं है तो उसे टिप्पणियों में अलग-से प्रस्तुत किया जा सकता है।
31. एक प्रतिष्ठान भारतीय लेखा मानक के अनुसार एक मद का, जो महत्त्वपूर्ण नहीं है, तब तक प्रकटन नहीं करेगा, जब तक कि विधि द्वारा उसके प्रकटन की कोई अपेक्षा न की गयी हो।

परस्पर समायोजन (ऑफ-सेटिंग)

32. जब तक किसी भारतीय लेखा मानक की अपेक्षा या अनुमति न हो, एक प्रतिष्ठान आस्तियों एवं देयताओं, और आय एवं व्यय को परस्पर समायोजित या 'ऑफ सेट' नहीं करेगा।
33. एक प्रतिष्ठान आस्तियों एवं देयताओं और आय एवं व्यय दोनों को अलग-अलग प्रस्तुत करता है। लाभ और हानि या तुलन पत्र के विवरणों में जब कोई परस्पर समायोजन (ऑफ सेट) किया जाता है, ऐसी स्थिति को छोड़कर जब परस्पर समायोजन (ऑफ सेटिंग) लेन देन या घटना का

सार प्रकट करता है, वित्तीय विवरणियों के उपयोगकर्ताओं की उस जानकारी को वाधित या न्यून करता है जो लेन-देनों, अन्य घटनाओं और परिस्थितियों को समझने और उसके साथ-साथ प्रतिष्ठान के भावी नकदी प्रवाहों का निर्धारण करने के लिए आवश्यक है। उदाहरणार्थ : सूचीबद्ध सामान से वे अप्रचलित माल के अंश और प्राप्तियों में अशोध्य ऋण के अंश माप परस्पर समायोजन (ऑफ सेटिंग) की श्रेणी में नहीं आता।

34. भारतीय लेखा मानक 18 'राजस्व' - राजस्व को परिभाषित करता है। एक प्रतिष्ठान द्वारा दिये गये किसी भी व्यापारिक बट्टे की राशि और परिमाण छूट को ध्यान में रखते हुए प्राप्तियों या प्राप्तियोग्य प्रतिफल के उचित मूल्य पर माप की अपेक्षा करता है। एक प्रतिष्ठान अपनी सामान्य गतिविधियों के दौरान उन लेन-देनों को भी करता है जो कि राजस्व तो उत्पन्न नहीं करते परन्तु मुख्य राजस्व - उत्पत्ति की गतिविधियों में सहायक है। एक प्रतिष्ठान लेन-देनों की प्रस्तुति में लेन-देन या अन्य घटना का सार जो उस लेन-देन से संबंधित व्यय से, आय को, यदि कोई हो, घटाकर वह अपनी प्रस्तुति में निम्नलिखित प्रकट करता है - उदाहरणार्थ,
- (क) एक प्रतिष्ठान निवेशों और परिचालन आस्तियों सहित गैर-चालू आस्तियों के निपटान पर लाभ और हानि को सम्पत्ति के निपटान पर प्राप्त राशि में से आस्ति की अग्रणीत राशि व विक्रय व्यय घटाकर प्रस्तुत करता है।
- (ख) एक प्रतिष्ठान भारतीय लेखा मानक 37 'प्रावधान, आकस्मिक देयताएं एवं आकस्मिक आस्तियां' के अनुसरण में मान्य एक प्रावधान से सम्बद्ध व्यय को निवल कर सकता है और किसी तीसरे पक्ष के साथ प्रतिपूर्ति के सम्बन्ध में किये गये संविधात्मक समझौते के अन्तर्गत (उदाहरणार्थ एक आपूर्तिकर्ता का वारंटी करार) प्रतिपूर्ति प्राप्त कर सकता है।
35. इसके अतिरिक्त एक प्रतिष्ठान इसी प्रकार के लेन देनों के समूह जैसे कि विदेशी विनिमय लाभ और हानि या खरीद-बिक्री के लिए धारित वित्तीय लिखतों से लाभ और हानि से उत्पन्न निवल आधारित लाभ और हानि को भी प्रस्तुत करता है। परन्तु यदि ये लाभ और हानियां सारवान या (महत्वपूर्ण) है तो प्रतिष्ठान उन्हें अलग से प्रस्तुत करता है।

रिपोर्टिंग करने की आवृत्ति

36. एक प्रतिष्ठान कम से कम वर्ष में एक बार सम्पूर्ण समुच्चय (सेट) तुलनात्मक सूचना के साथ प्रस्तुत करेगा। जब प्रतिष्ठान रिपोर्टिंग अवधि की सीमा में कोई परिवर्तन करता है और एक वर्ष से अधिक या कम समय के लिए वित्तीय विवरण प्रस्तुत करता है तो वह प्रतिष्ठान इस बारे में और साथ ही वित्तीय विवरणों में अवधि के ब्यौरे के साथ-साथ निम्नलिखित के बारे में प्रकटन करेगा :
- (क) लम्बी या कम अवधि के प्रयोग का कारण ; और
- (ख) यह तथ्य कि वित्तीय विवरणों में प्रस्तुत की गयी राशियां पूर्णतया तुलनात्मक नहीं है।

37. [देखिये परिशिष्ट 1]

तुलनात्मक सूचना

38. सिवाय इसके कि भारतीय लेखा मानक इसकी अनुमति दे या अन्यथा अपेक्षा करे, एक प्रतिष्ठान वर्तमान अवधि के वित्तीय विवरणों में उल्लिखित सभी राशियों के बारे में पूर्व अवधि से संबंधित तुलनात्मक सूचना प्रकट करेगा। एक प्रतिष्ठान जब वर्तमान अवधि के वित्तीय विवरणों को समझने के लिए आवश्यक हो, व्याख्यात्मक और वर्णात्मक सूचना की तुलनात्मक सूचना भी सम्मिलित करेगा।
39. एक प्रतिष्ठान तुलनात्मक सूचना के प्रकटन में कम से कम दो तुलन-पत्र एवं दो-दो अन्य विवरण तथा सम्बद्ध टिप्पणियां प्रस्तुत करेगा। जब एक प्रतिष्ठान लेखा नीति को पूर्वप्रभाव से लागू करता है या वित्तीय विवरणों में मदों का पूर्वप्रभाव से पुनर्वर्गीकरण करता है या अपने वित्तीय विवरणों में मदों का पुनर्वर्गीकरण करता है तो ऐसे में वह कम से कम तीन तुलन-पत्र, अन्य विवरणों में प्रत्येक के दो-दो विवरण और सम्बद्ध टिप्पणियां प्रस्तुत करेगा।

एक प्रतिष्ठान तुलन-पत्र निम्नलिखित तिथियों पर प्रस्तुत करेगा : -

- (क) वर्तमान अवधि के अन्त पर,
 - (ख) पूर्व अवधि के अन्त पर (जो कि वर्तमान अवधि के प्रारंभ के अनुरूप है), और
 - (ग) पुरानी से पुरानी तुलनात्मक अवधि के प्रारम्भ पर।
40. कुछ मामलों में, पूर्व अवधि (यों) के वित्तीय विवरणों में प्रदत्त वर्णनात्मक सूचना वर्तमान अवधि के लिए भी प्रासांगिक बनी रहती है। उदाहरणार्थ, एक प्रतिष्ठान तत्काल पूर्ववर्ती रिपोर्टिंग अवधि के अन्त में किसी कानूनी विवाद को जिसका परिणाम अनिश्चित था और जो अभी भी सुलझाया जाना है, वर्तमान अवधि में प्रकट करेगा। उपयोगकर्ता तत्काल पूर्ववर्ती रिपोर्टिंग अवधि के अन्त में, मौजूद अनिश्चितता और इस अवधि के दौरान इसे सुलझाने के लिए उठाये गये कदमों के संबंध में प्राप्त सूचना से लाभान्वित होते हैं।
41. जब प्रतिष्ठान अपने वित्तीय विवरणों में मदों के प्रस्तुति या वर्गीकरण में कोई परिवर्तन करता है तो वह तुलनात्मक राशियों का भी पुनर्वर्गीकरण करेगा बशर्ते पुनर्वर्गीकरण करना अव्यवहार्य न हो। प्रतिष्ठान जब तुलनात्मक राशियों का पुनर्वर्गीकरण करता है, तो उसे निम्नलिखित को भी प्रकट करना होगा : -
- (क) पुनर्वर्गीकरण का स्वरूप ;
 - (ख) पुनर्वर्गीकृत प्रत्येक पद या मदों की श्रेणी की राशि ; और
 - (ग) पुनर्वर्गीकरण का कारण
42. जब तुलनात्मक राशियों का पुनर्वर्गीकरण अव्यवहार्य हो तो प्रतिष्ठान निम्नलिखित का प्रकटन करेगा :
- (क) राशियों को पुनर्वर्गीकृत न करने का कारण, और
 - (ख) यदि राशियां पुनर्वर्गीकृत कर दी जाती हैं तो किये जाने वाले समायोजनों का स्वरूप।

43. सूचना की अन्तर-अवधि तुलनात्मकता में वृद्धि उपयोगकर्ताओं को आर्थिक निर्णय लेने के लिए विशेषतया पूर्वानुमान प्रयोजनों के लिए वित्तीय सूचना में प्रवृत्ति का मूल्यांकन करने में सहायता करती है। कुछ परिस्थितियों में, वर्तमान अवधि में तुलनात्मकता प्राप्त करने के लिए तत्काल पूर्व अवधि में तुलनात्मक सूचना पुनर्वर्गीकरण अव्यवहार्य होती है। उदाहरणार्थ, किसी प्रतिष्ठान ने पूर्व अवधि (यों) में आकड़ों का संग्रह इस प्रकार न किया हो कि पुनर्वर्गीकरण किया जा सके और अब सूचना फिर से एकत्रित करना भी अव्यवहार्य हो सकती है।
44. भारतीय लेखा मानक 8, तुलनात्मक सूचना में समायोजनों के बारे में अपेक्षा करता है जब कोई प्रतिष्ठान लेखा नीति में परिवर्तन करता है या किसी त्रुटि को ठीक करता है।

प्रस्तुतिकरण की एकरूपता

45. एक प्रतिष्ठान एक अवधि से अगली अवधि तक वित्तीय विवरणों में मदों का प्रस्तुतिकरण और वर्गीकरण निम्नलिखित को छोड़कर उसी रूप में जारी रखेगा।
- (क) यह स्पष्ट है, कि प्रतिष्ठान के परिचालन की प्रकृति में महत्वपूर्ण परिवर्तन या वित्तीय विवरणों के पुनरावलोकन को ध्यान में रखते हुए भारतीय लेखा मानक 8 के अधीन लेखा नीतियों के चयन और प्रयोग के मानदंडों के अनुरूप अन्य प्रस्तुतिकरण या वर्गीकरण और अधिक उपयुक्त होगा ; या
- (ख) एक भारतीय लेखा मानक प्रस्तुतिकरण में परिवर्तन की अपेक्षा करता है।
46. उदाहरणार्थ, एक महत्वपूर्ण अधिग्रहण या निपटान, या वित्तीय विवरणों के प्रस्तुतिकरण का पुनरावलोकन, वित्तीय विवरणों को अलग से ढंग से प्रस्तुत करने की आवश्यकता का सुझाव देता है। एक प्रतिष्ठान अपने वित्तीय विवरणों का प्रस्तुतिकरण तभी परिवर्तित करता जब के परिवर्तित प्रस्तुतिकरण उपयोगकर्ताओं को अधिक विश्वसनीय तथा और अधिक संगत सूचना प्रदान करता हो तथा संशोधित संरचना की एकरूपता बरकरार रहे ताकि तुलनात्मकता क्षीण न हो। परिवर्तित प्रस्तुतिकरण करते समय प्रतिष्ठान अपनी तुलनात्मक सूचना का वर्गीकरण अनुच्छेद 41 और 42 के अनुरूप करता है।

संरचना एवं विषय-वस्तु

परिचय

47. यह मानक, तुलन पत्र (इसके साथ संलग्न ईक्विटी में परिवर्तन के विवरण सहित) या लाभ और हानि विवरण के विशेष प्रकटन के साथ-साथ अन्य रेखीय मदों को टिप्पणियों में या उन विवरणों में प्रकटन की अपेक्षा करता है। भारतीय लेखा मानक 7 'नकदी प्रवाहों का विवरण' नकद प्रवाह सूचना के प्रस्तुतिकरण की आवश्यकताएं स्पष्ट करता है।
48. यह मानक कभी-कभी 'प्रकटन' शब्द को विस्तृत अर्थ में प्रयोग करता है, जिसमें वित्तीय विवरणों में प्रस्तुत मदों का समावेश होता है। अन्य भारतीय लेखा मानक भी प्रकटन की अपेक्षा करते हैं।

जब तक इस मानक में या अन्य भारतीय लेखा मानकों में कही विपरीत उल्लेख न किया गया हो, ऐसे प्रकटनों का उल्लेख वित्तीय विवरणों में किया जा सकता है।

वित्तीय विवरणों की पहचान

49. एक प्रतिष्ठान वित्तीय विवरणों की स्पष्ट पहचान करेगा और एक ही प्रकाशित दस्तावेज में दी गई अन्य सूचना से उसकी भिन्नता को भी स्पष्ट करेगा
50. भारतीय लेखा मानक केवल वित्तीय विवरणों पर लागू होते हैं और यह जरूरी नहीं है कि वे एक वार्षिक रिपोर्ट में प्रस्तुत अन्य सूचनाओं, एक विनियामक प्राधिकारी को प्रस्तुत की गयी सूचना, या अन्य किसी दस्तावेज पर भी लागू हों। अतएव यह महत्वपूर्ण है कि उपयोगकर्ता भारतीय लेखा मानकों के अनुसार तैयार की गयी सूचना, जो उसके लिए उपयोगी है, और अन्य सूचना, जो भारतीय लेखा मानकों की अपेक्षा का विषय न हों, इन दोनों में अन्तर कर सकें।
51. एक प्रतिष्ठान प्रत्येक वित्तीय विवरण और टिप्पणियों की स्पष्ट पहचान करेगा। इसके अतिरिक्त निम्नलिखित सूचना का प्रमुखता से प्रदर्शन करेगा और यदि आवश्यक हों तो प्रस्तुत सूचना को समझने के लिए उसे दोहरायेगा भी : -
 - (क) रिपोर्ट करने वाले प्रतिष्ठान का नाम या पहचान के अन्य तरीके और तत्काल रिपोर्ट अवधि के अन्त से उस सूचना में कोई परिवर्तन ;
 - (ख) यह कि, वित्तीय विवरण किसी व्यक्तिगत प्रतिष्ठान के हैं या प्रतिष्ठानों के एक समूह के हैं ;
 - (ग) रिपोर्टिंग अवधि के समापन की तिथि या वित्तीय विवरणों के समुच्चय (सेट) या टिप्पणियों में व्याप्त अवधि ;
 - (घ) प्रस्तुतिकरण की मुद्रा राशियां भारतीय लेखा मानक 21 द्वारा यथा परिभाषित ; तथा
 - (ङ) वित्तीय विवरणों को प्रस्तुत करने के लिए उन्हें पूर्णांकित (राउन्ड) करने का स्तर।
52. एक प्रतिष्ठान अनुच्छेद 51 में उल्लिखित आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सभी पृष्ठों, विवरणों, टिप्पणियों, कॉलमों और इसी तरह अन्य स्थानों पर उपयुक्त शीर्षक प्रदान करता है। ऐसी सूचना की सर्वोत्तम प्रस्तुति के निर्धारण के लिए सूझ-बूझ की आवश्यकता होती है। उदाहरणार्थ, जब एक प्रतिष्ठान वित्तीय विवरणों का इलैक्ट्रॉनिक प्रस्तुतिकरण करता है, तो इसके लिए वह हमेशा अलग पृष्ठों का उपयोग नहीं करता है तब प्रतिष्ठान मदों को इस तरह से प्रस्तुत करता है कि यह सुनिश्चित किया जाये कि वित्तीय विवरणों में दी गई सूचना समझ में आ सके।
53. एक प्रतिष्ठान प्रायः वित्तीय विवरणों को और अधिक समझने लायक बनाने के लिए सूचना को प्रस्तुति मुद्रा में हजारों, लाखों, मिलियन या करोड़ों की ईकाइयों में प्रस्तुत करता है। ऐसा करना स्वीकार्य है जब तक प्रतिष्ठान द्वारा राशियों को पूर्णाकों के स्तर का प्रकटन करता है और कहीं कोई सारवान सूचना नहीं छूटती है।

तुलन-पत्र

तुलन-पत्र में प्रस्तुत की जानी वाली सूचना

54. तुलन-पत्र में प्रस्तुत की जाने वाली सूचना में कम से कम, तुलन-पत्र में रेखीय मदों की निम्नलिखित राशियां सम्मिलित होंगी : -

- (क) सम्पत्ति, संयंत्र और उपस्कर ;
- (ख) निवेश सम्पत्ति ;
- (ग) अमूर्त आस्तियां ;
- (घ) वित्तीय आस्तियां ((ङ), (ज), (झ) के अन्तर्गत दिखायी गयी राशियों को छोड़कर) ;
- (ङ) ईक्विटी विधि के प्रयोग द्वारा लेखांकित निवेश ;
- (च) जैविक आस्तियां ;
- (छ) सूचीबद्ध सामान (इन्वेंट्रीज) ;
- (ज) व्यापारिक एवं अन्य प्राप्य राशियां ;
- (झ) नकदी एवं नकदी-तुल्य ;
- (ञ) 'बिक्री के लिए धारित' रूप में वर्गीकृत कुल आस्तियां और निपटान समूह में सम्मिलित वे आस्तियां जिनको भारतीय लेखा मानक 105 बिक्री के लिए धारित गैर-चालू आस्तियां और बंद परिचालन के अनुसरण में बिक्री के लिए धारित रूप में वर्गीकृत किया गया है ;
- (ट) व्यापारिक एवं अन्य देय राशियां ;
- (ठ) प्रावधान ;
- (ड) वित्तीय देयताएं [(ट) तथा (ठ) में दिखायी गयी राशियों को छोड़कर] ;
- (ढ) भारतीय लेखा मानक 12 'आयकर' में यथा परिभाषित वर्तमान कर हेतु देयताएं और आस्तियां ;
- (ण) भारतीय लेखा मानक 12 'आयकर' में यथा परिभाषित आस्थगित कर देयताएं एवं आस्थगित कर आस्तियां ;
- (त) भारतीय लेखा मानक 105 के अनुसार 'निपटान समूहों में बिक्री के लिए धारित' के रूप में वर्गीकृत देयताएं ;
- (थ) गैर-नियंत्रक हित जिन्हें 'ईक्विटी' के अन्दर ही प्रस्तुत किया गया है ; और
- (द) जारी पूंजी तथा कोष जो मूल प्रतिष्ठान के स्वामियों से सम्बन्धित हैं।

55. एक प्रतिष्ठान तुलन पत्र में अतिरिक्त रेखीय मदों, शीर्षकों और उप-योगों (जोड़ों) को प्रस्तुत करेगा जब उस प्रतिष्ठान की वित्तीय स्थिति को समझने के लिए ऐसा प्रस्तुतिकरण आवश्यक है।
56. जब एक प्रतिष्ठान अपने तुलन-पत्र में अलग वर्गीकरणों के रूप में चालू एवं गैर-चालू आस्तियां और चालू एवं गैर-चालू देयताओं को प्रस्तुत करता है, तो यह आस्थगित कर आस्तियों (देयताओं) को चालू आस्तियों (देयताओं) के रूप में वर्गीकृत नहीं करेगा।
57. यह मानक प्रतिष्ठान द्वारा प्रस्तुत मदों के लिए कोई अनुक्रम या पत्र (फार्मेट) नियत नहीं करता। अनुच्छेद 54 केवल मदों की सूची प्रस्तुत करता है जो कि प्रकृति या कार्य में इतनी अलग होती है जिन्हें तुलन पत्र में अलग प्रस्तुत करना आवश्यक हो जाता है। इसके अतिरिक्त :
- (क) रेखीय मदों को सम्मिलित किया जाता है जब किसी मद का आकार, प्रकृति या कार्य, या ऐसी समान मदों का समूहन ऐसा हो कि अलग प्रस्तुतिकरण प्रतिष्ठान की वित्तीय स्थिति को समझने के लिए आवश्यक हो ;
- (ख) प्रयुक्त निरूपण और मदों का अनुक्रम या समान मदों का समूहन प्रतिष्ठान की प्रकृति और इसके लेन-देनों के अनुसार इसलिए संशोधित किये जाते हैं ताकि प्रतिष्ठान की वित्तीय स्थिति को समझने के लिए आवश्यक सूचना प्रदान की जा सके। उदाहरणार्थ, एक वित्तीय संस्थान उपर्युक्त निरूपण को ऐसे संशोधित कर सकता है ताकि वित्तीय संस्थान के परिचालन से संबंधित अपेक्षित सूचना प्रदान की जा सके।
58. एक प्रतिष्ठान निम्नलिखित के आधार पर यह निर्णय लेता है कि क्या अतिरिक्त मदों को अलग से प्रस्तुत किया जाये या नहीं : -
- (क) आस्तियों की प्रकृति और तरलता ;
- (ख) प्रतिष्ठान के भीतर आस्तियों का कार्य ; और
- (ग) देयताओं की राशियां, प्रकृति और समय-सारणी।
59. विभिन्न श्रेणियों की आस्तियों के विभिन्न माप आधारों का प्रयोग यह सुझाव देता है कि उनकी प्रकृति या कार्य भिन्न हैं तथा अतएव, एक प्रतिष्ठान उनको अलग रेखीय मदों के रूप में प्रस्तुत करता है। उदाहरणार्थ, सम्पत्ति, संयंत्र और उपस्कर की विभिन्न श्रेणियों को भारतीय लेखा मानक 16 के अनुसार लागत या पुनर्मूल्यांकित राशियों पर अग्रणीत किया जा सकता है।

चालू / गैर-चालू में अन्तर

60. एक प्रतिष्ठान अनुच्छेद 66-76 के अनुसार अपने तुलन-पत्र में चालू और गैर-चालू आस्तियों तथा चालू और गैर-चालू देयताओं का अलग से वर्गीकरण करता है, सिवाय इसके जब कि तरलता आधारित प्रस्तुतीकरण द्वारा प्रदत्त सूचना विश्वसनीय तथा और अधिक प्रासंगिक हो। जब यह अपवाद लागू होता है तो प्रतिष्ठान सभी आस्तियों और देयताओं को तरलता अनुक्रम में ही प्रस्तुत करेगा।

61. प्रस्तुतिकरण का कोई भी तरीका अपनाया जाये, प्रतिष्ठान प्रत्येक आस्ति और देयता की रेखीय मद की राशि को प्रकट करेगा जो बारह माह से अधिक समय पश्चात् वसूल या निपटान पर प्राप्त होगी जोकि उन राशियों को मिलाकर है जिनकी वसूली या निपटान संभावित है :
- (क) रिपोर्टिंग अवधि के पश्चात् बारह माह से अधिक नहीं, और
- (ख) रिपोर्टिंग अवधि के पश्चात् बारह माह से अधिक ।
62. जब एक प्रतिष्ठान एक स्पष्ट पहचानयोग्य परिचालन चक्र में वस्तुओं या सेवाओं की आपूर्ति करता है, तो तुलन-पत्र में चालू और गैर-चालू आस्तियों तथा देयताओं का अलग वर्गीकरण प्रस्तुत किया जाता है। इसमें निवल आस्तियों, जो कि कार्यशील पूंजी के रूप में निरन्तर परिचालन में कार्यरत रहती हैं तथा जो कि प्रतिष्ठान के दीर्घकालीन परिचालन में प्रयोग में रहती हैं, इन दोनों में अन्तर कर उपयोगी सूचना प्रदान करता है। यह उन आस्तियों, जो कि वर्तमान परिचालन चक्र में ही वसूल हो जाएंगी, और उन देयताओं, जो कि उसी अवधि में निपटान के लिए परिशोध्य हो जाएंगी, की ओर भी ध्यान आकर्षित करता है।
63. कुछ प्रतिष्ठानों, जैसे कि वित्तीय संस्थान के मामले में जब आस्तियों और देयताओं का तरलता के बढ़ते या घटते अनुक्रम में प्रस्तुतिकरण होता है तो वह ऐसी सूचना प्रदान करता है जो चालू और गैर-चालू प्रस्तुतिकरण की तुलना में विश्वसनीय तथा और अधिक प्रासंगिक होती है क्योंकि प्रतिष्ठान (वित्तीय संस्थान) एक सुस्पष्ट पहचानयोग्य परिचालन चक्र वस्तुओं या सेवाओं की आपूर्ति नहीं करता ।
64. अनुच्छेद 60 को लागू करने में, एक प्रतिष्ठान को यह अनुमति है कि वह कुछ आस्तियों और देयताओं को चालू और गैर-चालू वर्गीकरण में तथा अन्य को तरलता में प्रस्तुत करे। ऐसा करने से प्रदत्त सूचना विश्वसनीय तथा और अधिक प्रासंगिक होती है। जब प्रतिष्ठान के विविध परिचालन हों तो प्रस्तुतिकरण के लिए उपर्युक्त मिश्रित आधार की आवश्यकता होती है।
65. आस्तियों और देयताओं की वसूली की प्रत्याक्षित तिथियों संबंधी सूचना एक प्रतिष्ठान की तरलता तथा शोधक्षमता के निर्धारण में उपयोगी होती है। भारतीय लेखा मानक 107 ' वित्तीय लिखतें: प्रकटन ' वित्तीय आस्तियों और वित्तीय देयताओं की परिपक्वता तिथियों के प्रकटन की अपेक्षा करता है। वित्तीय आस्तियों में व्यापारिक और अन्य प्राप्य राशियां और वित्तीय देयताओं में व्यापारिक और अन्य देय राशियां सम्मिलित होती हैं। आस्तियां और देयताएं चाहे चालू और गैर-चालू रूप में वर्गीकृत की जायें या नहीं, और गैर-मौद्रिक आस्तियों जैसे सूचीबद्ध सामान (इन्वेंट्रीज) की वसूली की प्रत्याक्षित तिथि तथा देयताओं जैसे प्रावधान के निपटान की प्रत्याक्षित तिथि के बारे में सूचना भी उपयोगी होती है। उदाहरणार्थ, एक प्रतिष्ठान सूचीबद्ध सामान (इन्वेंट्रीज) की उस राशि को प्रकट करता है जिसकी उसे रिपोर्टिंग अवधि के पश्चात् बारह माह से अधिक समय में वसूल होने की आशा है।

चालू आस्तियां

66. एक प्रतिष्ठान किसी आस्ति को चालू आस्ति के रूप में तब वर्गीकृत करेगा, जब : -

- (क) वह सामान्य परिचालन चक्र में आस्ति की वसूली की आशा करता है या उसके विक्रय या उपभोग का इरादा रखता है ;
- (ख) वह आस्ति का धारण मुख्य रूप से व्यापारिक प्रयोजन के लिए करता है ;
- (ग) वह यह आशा करता है कि रिपोर्टिंग अवधि के पश्चात् के बारह माह के अंदर आस्ति की वसूली हो जाएगी ; या
- (घ) आस्ति नकद या एक नकदी तुल्य है [जैसा कि भारतीय लेखा मानक 7 में परिभाषित है] सिवाय इसके कि रिपोर्टिंग अवधि के पश्चात् कम से कम बारह माह तक वह आस्ति विनिमय या किसी देयता के निपटान के लिए प्रतिबंधित न हो ।

एक प्रतिष्ठान अन्य आस्तियों को गैर-चालू आस्तियों के रूप में वर्गीकृत करेगा ।

67. यह मानक शब्द 'गैर-चालू' का प्रयोग दीर्घकालीन प्रकृति की मूर्त, अमूर्त और वित्तीय आस्तियों को सम्मिलित करने के लिए करता है। जब तक अर्थ स्पष्ट है यह किसी अन्य वैकल्पिक निरूपण के प्रयोग पर कोई रोक नहीं लगाता ।
68. एक प्रतिष्ठान का परिचालन चक्र, प्रसंस्करण हेतु आस्तियों के अधिग्रहण और उनकी नकद या नकदी-तुल्य में वसूली के बीच का समय है। जब प्रतिष्ठान का सामान्य परिचालन चक्र स्पष्टतः पहचानयोग्य न हो तो इसे बारह माह माना जाता है। चालू आस्तियों में वे आस्तियां [जैसे कि सूचीबद्ध सामान (इन्वेंट्रीज) और व्यापारिक प्राप्य राशियां] सम्मिलित होती हैं जो सामान्य परिचालन चक्र के अंग के रूप में बेची जाती हैं, उपयोग में लायी जाती हैं या वसूल की जाती हैं, भले ही रिपोर्टिंग अवधि के पश्चात् बारह माह के भीतर उनकी वसूली की आशा न हो । चालू आस्तियों में वे आस्तियां सम्मिलित हैं जो कि मुख्यतया व्यापारिक प्रयोजन के लिए धारित हैं [जैसे कि भारतीय लेखा मानक 39 के अनुरूप व्यापार के लिए धारित वर्गीकृत कुछ वित्तीय आस्तियां] और गैर-चालू वित्तीय आस्तियों का चालू भाग है।

चालू देयताएं

69. एक प्रतिष्ठान देयता को चालू देयता के रूप में तब वर्गीकृत करेगा, जब -
 - (क) वह देयता को सामान्य परिचालन चक्र में निपटाने की आशा करता हो ;
 - (ख) वह देयता को मुख्यतया व्यापारिक प्रयोजन के लिए धारित करता हो ;
 - (ग) वह देयता रिपोर्टिंग अवधि के पश्चात् बारह माह में ही निपटान के लिए देय हो ; या
 - (घ) इसके पास रिपोर्टिंग अवधि के पश्चात् कम से कम बारह माह के लिए निपटान स्थगित करने का शर्तरहित अधिकार न हो (देखिये अनुच्छेद 73) यदि प्रतिपक्ष के विकल्प पर देयता की शर्तों पर निपटान 'ईक्विटी' लिखतों के निर्गम द्वारा किया जाता है तो इससे वर्गीकरण प्रभावित नहीं होता ।

एक प्रतिष्ठान अन्य सभी देयताओं को गैर-चालू देयताओं के रूप में वर्गीकृत करेगा ।

70. कुछ चालू देयताएं जैसे कि व्यापार से संबंधित देय राशियां और कर्मचारियों के लिए कुछ उपार्जन तथा अन्य परिचालन लागतें, प्रतिष्ठान के सामान्य परिचालन चक्र में प्रयोग में लायी गयी कार्यशील पूंजी के ही भाग होते हैं। एक प्रतिष्ठान ऐसी परिचालन मदों को चालू देयता के रूप में ही वर्गीकृत करता है भले ही वे रिपोर्टिंग अवधि के पश्चात् बारह माह से अधिक समय में निपटान के लिए देय हो। ऐसा ही सामान्य परिचालन चक्र एक प्रतिष्ठान की आस्तियों और देयताओं के वर्गीकरण पर भी लागू होता है। जब प्रतिष्ठान का सामान्य परिचालन चक्र स्पष्टतः पहचानयोग्य न हो तो यह बारह माह ही माना जाएगा।
71. अन्य चालू देयताएं सामान्य परिचालन चक्र के भाग के रूप में नहीं निपटायी जाती, लेकिन वे रिपोर्टिंग अवधि के पश्चात् बारह माह के अन्दर निपटान के लिए देय होती हैं या मुख्यतया व्यापारिक प्रयोजनों के लिए धारित की जाती हैं। भारतीय लेखा मानक 39 के अनुरूप कुछ वित्तीय देयताएं जो कि व्यापार हेतु धारित के रूप में वर्गीकृत हैं जैसे बैंक ओवरड्रॉफ्ट और गैर-चालू वित्तीय देयताएं का चालू भाग, देय लाभांश, आयकर और अन्य गैर-व्यापारिक देय इसके उदाहरण हैं। अनुच्छेद 74 और 75 के अधीन वे वित्तीय देयताएं, जो कि दीर्घ-कालीन आधार पर वित्त प्रदान करती हैं (प्रतिष्ठान के सामान्य परिचालन चक्र में प्रयुक्त कार्यशील पूंजी का भाग नहीं हैं) और रिपोर्टिंग अवधि के पश्चात् बारह माह के अन्दर निपटान के लिए देय न हों, गैर-चालू देयताएं हैं।
72. एक प्रतिष्ठान अपनी वित्तीय देयताओं को तब चालू देयताओं के रूप में वर्गीकृत करता है जब वे रिपोर्टिंग अवधि के पश्चात् बारह माह के अन्दर निपटान के लिए देय हो, भले ही :
- (क) मूल अवधि बारह माह से अधिक की अवधि हो, और
 - (ख) दीर्घावधि आधार पर पुनर्वित्त या भुगतान पुनर्सूचीयन करार रिपोर्टिंग अवधि के पश्चात् और वित्तीय विवरणों के जारी करने के अनुमोदन से पूर्व पूरा होता हो।
73. यदि एक प्रतिष्ठान को यह आशा है और उसे ऐसा करने का विवेकाधिकार है कि वह किसी मौजूदा ऋण सुविधा के अधीन रिपोर्टिंग अवधि के पश्चात् कम से कम बारह माह आगे के लिए पुनर्वित्त करने या दायित्व को अगली अवधि में अन्तरित कर ले, तो वह इस दायित्व को गैर-चालू दायित्व के रूप में वर्गीकृत करता है भले ही अन्यथा यह अल्प-काल में ही देय क्यों न हो। लेकिन, जब प्रतिष्ठान के पास पुनर्वित्त करने या दायित्व को अगली अवधि में अन्तरित करने का विवेकाधिकार न हो (उदाहरणार्थ, पुनर्वित्त करने की कोई व्यवस्था नहीं है), तो प्रतिष्ठान दायित्व के पुनर्वित्त करने की संभावना पर विचार नहीं करता और दायित्व को चालू दायित्व के रूप में वर्गीकृत करता है।
74. जब एक प्रतिष्ठान एक दीर्घावधि ऋण व्यवस्था के प्रावधान का रिपोर्टिंग अवधि पर या उसके समापन से पूर्व उल्लंघन करता है और उसके परिणामस्वरूप देयता मांग पर देय हो जाती है तो वह देयता को चालू देयता के रूप में वर्गीकृत करेगा, भले ही ऋणदाता रिपोर्टिंग अवधि के पश्चात् और वित्तीय विवरण जारी करने के अनुमोदन पूर्व इस उल्लंघन के फलस्वरूप भुगतान की मांग न करने के लिए सहमत हो गया हो। प्रतिष्ठान ऐसी देयता को रिपोर्टिंग अवधि के अन्त

पर चालू देयता के रूप में वर्गीकृत करता है, निपटान को उस तिथि के बाद कम से कम बारह माह के लिए स्थगित करने का इसके पास कोई शर्तरहित अधिकार नहीं है।

75. लेकिन, प्रतिष्ठान ऐसी देयता को गैर-चालू देयता के रूप में वर्गीकृत करेगा, यदि ऋणदाता रिपोर्टिंग अवधि के अंत सहमत हो जाए कि रियायत अवधि जो रिपोर्टिंग अवधि के पश्चात् कम से कम बारह माह होगी, इस अवधि में प्रतिष्ठान उल्लंघन का सुधार कर सकता है और इस बीच ऋणदाता तत्काल पुनर्भुगतान की मांग नहीं कर सकता।
76. चालू देयताओं के रूप में वर्गीकृत ऋणों के मामलों में, रिपोर्टिंग अवधि के अंत और वित्तीय विवरण जारी करने हेतु अनुमोदन के बीच यदि निम्नलिखित घटनाएं उत्पन्न होती हैं तो भारतीय लेखा मानक 10 'रिपोर्टिंग अवधि के बाद की घटनाएं' के अनुरूप उन घटनाओं को गैर-समायोजित घटनाओं के रूप में प्रकट किया जाता है :
 - (क) दीर्घ-कालीन अवधि पर पुनर्वित्त प्रदान करना ;
 - (ख) दीर्घ-कालीन ऋण व्यवस्था के उल्लंघन का सुधार, और
 - (ग) ऋणदाता द्वारा दीर्घ-कालीन ऋण उल्लंघन के सुधार हेतु रिपोर्टिंग अवधि के पश्चात् कम से कम बारह माह की समाप्ति तक रियायत अवधि बढ़ाने की स्वीकृति।

तुलन-पत्र या टिप्पणियों में प्रस्तुत की जाने वाली सूचना

77. एक प्रतिष्ठान अपने तुलन-पत्र या टिप्पणियों में प्रस्तुत उन रेखीय मदों का उपवर्गीकरण प्रकट करेगा, जो प्रतिष्ठान के परिचालनों के लिए उपयुक्त हो
78. उपवर्गीकरणों में प्रदत्त जानकारी भारतीय लेखा मानकों की अपेक्षाओं तथा संबंधित राशियों के आकार, प्रकृति और कार्य पर निर्भर करती है। उपवर्गीकरण के आधार का निर्णय लेने के लिए प्रतिष्ठान अनुच्छेद 58 में वर्णित घटकों का भी उपयोग करता है। प्रत्येक मद के लिए प्रकटन भिन्न-भिन्न हो सकते हैं उदाहरणार्थ :
 - (क) सम्पत्ति, संयंत्र और उपकरणों की मदों को भारतीय लेखा मानक 16 के अनुसार विभिन्न श्रेणियों में विभाजित किया जाता है।
 - (ख) प्राप्य राशियों को व्यापारिक ग्राहकों से प्राप्य राशियों, सम्बद्ध पक्षों से प्राप्य राशियों, पूर्वभुगतानों और अन्य राशियों में विभाजित किया जाता है ;
 - (ग) सूचीबद्ध सामान को भारतीय लेखा मानक 2 'सूचीबद्ध सामान' के अनुसार, बिक्री माल, उत्पादन आपूर्तियों, सामग्री, निर्माणाधीन सामग्री और तैयार माल जैसे वर्गों में विभाजित किया जाता है ;
 - (घ) प्रावधानों को कर्मचारी लाभों और अन्य मदों के लिए प्रावधानों में विभाजित किया जाता है ;
 - (ङ) 'ईक्विटी' पूंजी तथा प्रारक्षित राशियों को विभिन्न श्रेणियों जैसे कि प्रदत्त पूंजी, शेयर प्रीमियम और प्रारक्षित राशियों में विभाजित किया जाता है।

79. एक प्रतिष्ठान तुलन-पत्र में या उसके साथ संलग्न 'ईक्विटी' में परिवर्तनों के विवरण या टिप्पणियों में निम्नलिखित को प्रकट करेगा।

(क) शेयर पूंजी की प्रत्येक श्रेणी के लिए :

- (i) अधिकृत शेयरों की संख्या ;
- (ii) निर्गमित तथा पूर्ण प्रदत्त और निर्गमित परन्तु पूर्ण प्रदत्त नहीं, शेयरों की संख्या ;
- (iii) प्रति शेयर सममूल्य, या कि शेयर जिनका कोई सम मूल्य नहीं है ;
- (iv) अवधिके प्रारंभ और अन्त में बकाया शेयरों का मिलान ;
- (v) लाभांश वितरण और पूंजी भुगतान पर प्रतिबंध सहित सम्बद्ध श्रेणी से जुड़े अधिकार, अधिमान और प्रतिबंध ;
- (vi) प्रतिष्ठान में शेयर, प्रतिष्ठान या इसकी अनुषंगियों या सहयोगी प्रतिष्ठानों द्वारा धारित शेयर; और
- (vii) शेयरों की बिक्री हेतु विकल्पों और संविदाओं के अधीन प्रारक्षित शेयर, निबंधनों और राशियों सहित ; और

(ख) प्रत्येक प्रारक्षित की प्रकृति तथा उद्देश्य का वर्णन

80. एक प्रतिष्ठान जिसकी पूंजी शेयरों द्वारा सीमित नहीं की गयी है उदाहरणतया एक कंपनी जो गारंटी द्वारा सीमित है तो वह प्रतिष्ठान अनुच्छेद 79 (क) द्वारा अपेक्षित सूचना के समान सूचना का प्रकटन करेगा जिसमें अवधि के दौरान 'ईक्विटी' हितों की प्रत्येक श्रेणी और अधिकारों, अधिमानों और 'ईक्विटी' हितों की प्रत्येक श्रेणी से सम्बद्ध प्रतिबंधों के परिवर्तनों को प्रकट करेगा।

80(क) यदि एक प्रतिष्ठान ने वित्तीय देयताओं व 'ईक्विटी' के बीच निम्नलिखित का पुनर्वर्गीकरण किया है : -

- (क) एक 'पुट' योग्य वित्तीय लिखत जिसे 'ईक्विटी' लिखत के रूप में वर्गीकृत किया गया हो ; या
- (ख) वह लिखत जो प्रतिष्ठान पर यह दायित्व सौंपती हो कि वह प्रतिष्ठान उस की निवल आस्तियों का आनुपातिक अंश परिसमापन पर दूसरे प्रतिष्ठान को सौंपेगा और इस लिखत को एक 'ईक्विटी' या वित्तीय देयता के बीच में इक्विटी लिखत के रूप में ही वर्गीकृत किया गया है

तो वह प्रतिष्ठान प्रत्येक श्रेणी (वित्तीय देयताएं या ईक्विटी) में आपस में अन्तरित पुनर्वर्गीकृत राशि और पुनर्वर्गीकरण की समय-सारणी व कारण को प्रकट करेगा।

लाभ - हानि विवरण

81. एक प्रतिष्ठान लाभ एवं हानि का एकल विवरण प्रस्तुत करेगा जिसमें आय-व्यय की सभी मदों और एक अवधि में मान्य अन्य व्यापक आय के सभी घटकों को प्रस्तुत किया जाएगा।

लाभ -हानि विवरण में दी जाने वाली सूचना

82. कम से कम, लाभ एवं हानि का विवरण निम्नलिखित रेखीय मदों का समावेश करेगा और इस की अवधि की राशियां प्रस्तुत की जाएंगी :-

- (क) राजस्व ;
- (ख) वित्त की लागतें;
- (ग) सहयोगी प्रतिष्ठानों और संयुक्त प्रतिष्ठानों की लाभ या हानि का अंश जो कि 'ईक्विटी' विधि के प्रयोग द्वारा लेखांकित किया गया है।
- (घ) कर व्यय
- (ङ) एक एकल राशि जो निम्नलिखित का योग हो ;
 - (i) बंद परिचालनों का कर-पश्चात् लाभ या हानि ; और
 - (ii) कर पश्चात् लाभ या हानि जो कि उचित मूल्य से बिक्री लागतें घटाकर माप के लिए मान्य की गई हैं या आस्तियों के निपटान या निपटान समूहों, जोकि बंद परिचालन हैं, में मान्य हुई हैं।
- (च) लाभ या हानि ;
- (छ) स्वरूप के आधार पर वर्गीकृत अन्य व्यापक आय का प्रत्येक घटक [(ज) में उल्लिखित राशि रहित] ;
- (ज) 'ईक्विटी' विधि के उपयोग करते हुए सहयोगी प्रतिष्ठानों, और संयुक्त प्रतिष्ठानों की अन्य व्यापक आय का अंश ; और
- (झ) कुल व्यापक आय

83. एक प्रतिष्ठान लाभ और हानि विवरण में अवधि हेतु आवंटनों के रूप में निम्नलिखित मदों का प्रकटन करेगा :

- (क) निम्नलिखित को अवधि के लिए लाभ या हानि ;
 - (i) गैर-नियंत्रक हित, और
 - (ii) मूल प्रतिष्ठान के स्वामी
- (ख) निम्नलिखित को अवधि के लिए कुल व्यापक आय ;

(i) गैर-नियंत्रक हित, और

(ii) मूल प्रतिष्ठान-के स्वामी

84. [देखिये परिशिष्ट 1] ;

85. एक प्रतिष्ठान लाभ और हानि विवरण में अतिरिक्त रेखीय मदों, शीर्षकों और उप-योगों का प्रस्तुतिकरण करेगा जब ऐसा प्रस्तुतिकरण प्रतिष्ठान के वित्तीय निष्पादन को समझने हेतु प्रासंगिक है।

86. क्योंकि एक प्रतिष्ठान की विभिन्न गतिविधियों, लेन-देनों और घटनाओं के प्रभाव आवृत्ति, लाभ या हानि की समभाव्यता एवं अनुमान अलग-अलग हैं, वित्तीय कार्य निष्पादन के घटकों का प्रकटन, वित्तीय विवरण के प्रयोगकर्ताओं को वित्तीय निष्पादन समझने और भविष्य के कार्य निष्पादन का पूर्वानुमान लगाने के लिए सहायता करता है। एक प्रतिष्ठान लाभ और हानि विवरण में अतिरिक्त रेखीय मदों को सम्मिलित करता है और यह प्रयोग में लाये गये वर्णनों तथा मदों के अनुक्रम को भी संशोधित करता है जब ऐसा करना वित्तीय निष्पादन के घटकों को स्पष्ट करने के लिए आवश्यक हो। एक प्रतिष्ठान सारवानता और आय एवं व्यय की मदों की प्रकृति और कार्य सहित कारकों पर विचार करता है। उदाहरणार्थ, एक वित्तीय संस्थान परिचालनों के लिए प्रासंगिक सूचना को प्रदान करने के लिए वर्णनों को संशोधित कर सकता है। एक प्रतिष्ठान आय और व्यय की मदों को परस्पर समायोजित (ऑफसेट) नहीं करता जब तक कि अनुच्छेद 32 में दिये गये मानदंडों का पालन हो न रहा हो।

87. एक प्रतिष्ठान आय या व्यय की किन्हीं मदों को असाधारण लाभ और हानि विवरण या टिप्पणियों में असाधारण मदों के रूप में प्रकट नहीं कर सकता।

अवधि का लाभ या हानि

88. एक प्रतिष्ठान अवधि में आय और व्यय की सभी मदों को लाभ या हानि के रूप में मान्यता देगा जब तक कि कोई भारतीय लेखा मानक कोई अन्यथा अनुमति न दे या मांग न करे।

89. कुछ भारतीय लेखा मानक उन परिस्थितियों को विनिर्दिष्ट करते हैं जब एक प्रतिष्ठान वर्तमान अवधि में खास मदों को लाभ या हानि के बाहर मान्यता देता है। भारतीय लेखा मानक 8 दो ऐसी ही परिस्थितियों को विनिर्दिष्ट करता है अर्थात् त्रुटियों का सुधार और लेखा नीतियों में परिवर्तनों का प्रभाव। अन्य भारतीय लेखा मानक, अन्य व्यापक आय के उन घटकों की अपेक्षा करते हैं या अनुमति देते हैं, जो कि मूलभूत संरचना (ढांचे) में दी गयी आय या व्यय की परिभाषा से मेल खाते हों जो कि लाभ या हानि से बाहर रखे जाते हैं (देखिये अनुच्छेद 7)।

अवधि की अन्य व्यापक आय

90. एक प्रतिष्ठान या तो लाभ और हानि विवरण में या फिर टिप्पणियों में अन्य व्यापक आय से संबंधित प्रत्येक घटक, पुनर्वर्गीकृत समायोजनों को सम्मिलित करते हुए, आय कर की राशि का प्रकटन करेगा।
91. एक प्रतिष्ठान अन्य व्यापक आय के घटकों का प्रस्तुतिकरण कर सकता है, चाहे
 - (क) सम्बद्ध कर प्रभावों का निवल, या
 - (ख) सम्बद्ध कर प्रभावों से पूर्व एक इक्वठी राशि जो उन अन्य व्यापक आय के सारे घटकों से संबद्ध है।
92. एक प्रतिष्ठान अन्य व्यापक आय के घटकों से सम्बद्ध पुनर्वर्गीकरण समायोजनों का प्रकटन करेगा।
93. अन्य भारतीय लेखा मानक यह विनिर्दिष्ट करते हैं कि पूर्व में अन्य व्यापक आय के रूप में मान्य राशियां क्यों और कब लाभ या हानि के लिए पुनर्वर्गीकृत की जाती हैं। इस मानक में ऐसे पुनर्वर्गीकरणों को पुनर्वर्गीकरण समायोजनों के रूप में संदर्भित किया गया है। एक पुनर्वर्गीकरण समायोजन अवधि विशेष के अन्य व्यापक आय के सम्बद्ध घटक के साथ सम्मिलित किया जाता है यह बताते हुए कि समायोजन लाभ या हानि के लिए पुनर्वर्गीकृत है। उदाहरणार्थ, बिक्री हेतु उपलब्ध वित्तीय आस्तियों के निपटान पर वसूल लाभों को वर्तमान अवधि के लाभ या हानि में सम्मिलित किया जाता है। इन राशियों को वर्तमान या पूर्व अवधियों में वसूल न की गयी आय के रूप में मान्य किया गया हो। उस अवधि की कुल व्यापक आय में से वसूल न किये गये लाभों को अनिवार्यतः घटाना चाहिए जिस अवधि में कि वसूली लाभों को लाभ या हानि हेतु पुनर्वर्गीकृत किया जाता है, ताकि उन्हें व्यापक आय में दोबारा जोड़ा न जा सके।
94. एक प्रतिष्ठान लाभ और हानि विवरण या टिप्पणियों में पुनर्वर्गीकरण समायोजनों को प्रस्तुत कर सकता है। एक प्रतिष्ठान टिप्पणियों में पुनर्वर्गीकरण समायोजनों को प्रस्तुत करते हुए किसी भी सम्बद्ध पुनर्वर्गीकरण समायोजनों के पश्चात् अन्य व्यापक आय के घटकों को प्रस्तुत करता है।
95. पुनर्वर्गीकरण समायोजन तब उत्पन्न होते हैं जब, उदाहरणार्थ, विदेशी परिचालन के निपटान पर [देखिये भारतीय लेखा मानक 21], बिक्री के लिए उपलब्ध वित्तीय आस्तियों की गैर-मान्यता पर [देखिये भारतीय लेखा मानक 39] और जब नकदी प्रवाह प्रतिरक्षा के संबंध में एक प्रतिरक्षित पूर्वानुमान लेन-देन लाभ या हानि को प्रभावित करता है [देखिये भारतीय लेखा मानक 39 का अनुच्छेद 100 नकदी प्रवाह प्रतिरक्षा के संबंध में]।
96. पुनर्वर्गीकरण समायोजन भारतीय लेखा मानक 16 या भारतीय लेखा मानक 38 के अनुसार मान्य पुनर्मूल्यांकन आधिक्य में परिवर्तनों या भारतीय लेखा मानक 19 के अनुच्छेद 92 और 129 क के अनुसार पारिभाषित कर्मचारी लाभ योजनाओं पर एकचूरियल लाभ एवं हानि उत्पन्न नहीं होते। इन घटकों को अन्य व्यापक आय में मान्य किया जाता और बाद की अवधियों में लाभ या हानि के रूप में पुनर्वर्गीकृत नहीं किया जाता। पुनर्मूल्यांकन आधिक्य में परिवर्तनों को बाद की अवधियों में धारित अर्जन में, जब सम्पत्ति प्रयोग में है या जब यह गैर-मान्य है, अंतरित

किया जा सकता है। [देखिये भारतीय लेखा मानक 16 और भारतीय लेखा मानक 38] ; बीमांकिक (एकचूरियल) लाभ और हानियों को उसी अवधि में जब कि उन्हें अन्य व्यापक आय की तरह मान्य किया जाता है, प्रतिधारित में सूचित किया जाता है [देखिये भारतीय लेखा मानक 19]

लाभ - हानि विवरण या टिप्पणियों में दी जाने वाली सूचना

97. जब आय या व्यय की मदें सारवान हों, एक प्रतिष्ठान उनके स्वरूप और राशि को अलग-से प्रकट करेगा।
98. उन परिस्थितियों जिनमें आय और व्यय की मदों को अलग-से प्रकट करना पड़ता है, इस प्रकार हो सकती हैं ;
 - (क) सूचीबद्ध सामान (इनवेंट्री) को शुद्ध नकदीकरण योग्य मूल्य या सम्पत्ति, संयंत्र और उपस्कर की वसूलयोग्य राशि पर अवमूल्यित करना और इसके साथ ही ऐसी अवमूल्यित राशियों का विपर्यास (उलटाया जाना) करना ;
 - (ख) एक प्रतिष्ठान की गतिविधियों की पुनर्संरचना और पुनर्संरचना लागतों के लिए किये गये किसी भी प्रावधान का विपर्यास ;
 - (ग) सम्पत्ति, संयंत्र और उपस्कर की मदों का निपटान ;
 - (घ) निवेशों का निपटान ;
 - (ङ) बंद परिचालन
 - (च) मुकद्दमों का निपटान ; और
 - (छ) अन्य प्रावधानों के विपर्यास
99. एक प्रतिष्ठान लाभ या हानि में मान्य व्ययों का व्यय विधि के स्वरूप पर आधारित वर्गीकरण का उपयोग करते हुए विश्लेषण प्रस्तुत करेगा।
100. अनुच्छेद 99 के अनुसार, लाभ और हानि विवरण में विश्लेषण प्रस्तुत करने हेतु प्रतिष्ठानों को प्रोत्साहित किया गया है।
101. व्ययों का उपवर्गीकरण वित्तीय निष्पादन घटकों पर प्रकाश डालने हेतु किया जाता है जो आवृत्ति, लाभ या हानि की संभाव्यता और पूर्व अनुमान योग्यता से भिन्न हो सकते हैं। यह विश्लेषण अनुच्छेद 102 में दिये गये प्रारूप अनुसार किया जाता है।
102. 'व्यय की प्रकृति' विधि पर आधारित विश्लेषण में, एक प्रतिष्ठान व्ययों को उनके स्वरूप अनुसार (उदाहरणार्थ, मूल्यहास, सामग्री का क्रय, परिवहन लागतें, कर्मचारी लाभ और विज्ञापन लागतें) लाभ या हानि के अंतर्गत ही एकीकृत करता है, और प्रतिष्ठान के अंदर कार्यों में पुनरावंटित नहीं करता। यह विधि लागू करने में आसान है क्योंकि व्ययों के किसी भी क्रियात्मक आंबटन की आवश्यकता नहीं होती। व्यय की प्रकृति विधि आधारित वर्गीकरण का एक उदाहरण नीचे दिया गया है:

राजस्व		X
अन्य आय		X
तैयार माल और निर्माणाधीन माल में परिवर्तन	X	
कच्चा माल और इस्तेमाल में सामग्री	X	
कर्मचारी लाभ व्यय	X	
मूल्यह्रास और परिशोध्य व्यय	X	
अन्य व्यय	X	
कुल व्यय		(X)
कर पूर्व लाभ		X

103. [देखिये परिशिष्ट 1] ;

104. [देखिये परिशिष्ट 1] ;

105. [देखिये परिशिष्ट 1] ;

'ईक्विटी' में परिवर्तन का विवरण

106. एक प्रतिष्ठान अनुच्छेद 10 द्वारा अपेक्षित 'ईक्विटी' में परिवर्तनों का विवरण प्रस्तुत करेगा। 'ईक्विटी' में परिवर्तनों के विवरण में निम्नलिखित सम्मिलित किये जाएंगे।

- (क) अवधि विशेष की कुल व्यापक आय, जिसे मूल प्रतिष्ठान के स्वामियों और गैर-नियंत्रक हितों में अलग-अलग दिखाया जाएगा ;
- (ख) 'ईक्विटी' के प्रत्येक घटक के लिए, भारतीय लेखा मानक 16 के अनुसार मान्य पूर्व प्रभावी उपयोग के प्रभाव या पूर्व प्रभावी पुनर्कथन ;
- (ग) [देखिये परिशिष्ट 1] ;
- (घ) 'ईक्विटी' के प्रत्येक घटक हेतु अवधि विशेष के प्रारंभ और अंत में अग्रणीत राशि के बीच मिलान। निम्नलिखित से उत्पन्न प्रत्येक परिवर्तन को पृथक-पृथक प्रकट किया जाएगा :
 - (i) लाभ और हानि ;
 - (ii) अन्य व्यापक आय की प्रत्येक मद ;
 - (iii) स्वामियों के साथ स्वामियों की हैसियत से लेन-देन, जिनमें स्वामियों द्वारा किये गये अंशदान और उनको वितरण तथा अनुषंगी प्रतिष्ठानों में स्वामित्व हित परिवर्तन जिसके परिणामतः नियंत्रण नहीं घटता, शामिल है और उन्हें अलग-अलग दिखाया जाएगा ; तथा

- (iv) 'ईक्विटी' में प्रत्यक्ष रूप से मान्य कोई मद जैसे कि भारतीय लेखा मानक 103 के अनुच्छेद 36 क के साथ पूंजीगत प्रारक्षित राशि के रूप में प्रत्यक्ष रूप से मान्य राशि ।

तुलन-पत्र या टिप्पणियों के साथ संलग्न 'ईक्विटी' में परिवर्तनों के विवरण में प्रस्तुत की जाने वाली सूचना

106. (क) 'ईक्विटी' के प्रत्येक घटक हेतु एक प्रतिष्ठान, या तो 'ईक्विटी' में परिवर्तनों के विवरण में या टिप्पणियों में; अन्य व्यापक आय का मदवार विश्लेषण प्रस्तुत करेगा । [देखिये अनुच्छेद 106 (घ) (ii)]
107. एक प्रतिष्ठान या तो 'ईक्विटी' में परिवर्तन विवरण या टिप्पणियों में अवधि विशेष में लाभांश की राशि जो कि स्वामियों को वितरण की तरह मान्य हो, और प्रति शेयर लाभांश की संबद्ध राशि प्रस्तुत करेगा ।
108. अनुच्छेद 106 में 'ईक्विटी' के घटकों में, उदाहरणार्थ, अंशदान की गई 'ईक्विटी' के प्रत्येक श्रेणी, अन्य व्यापक आय की प्रत्येक श्रेणी का संचयित शेष और धारित अर्जन सम्मिलित है।
109. रिपोर्टिंग अवधि विशेष के प्रारंभ और अन्त के बीच एक प्रतिष्ठान की 'ईक्विटी' में प्रत्येक अवधि विशेष के दौरान निवल आस्तियों में कमी या वृद्धि दर्शाती है। स्वामियों के साथ उनकी स्वामी की हैसियत से लेन-देन (जैसे कि 'ईक्विटी' अंशदान, प्रतिष्ठान द्वारा प्रतिष्ठान के स्वयं के 'ईक्विटी' लिखतों का पुनः अधिग्रहण, और लाभांश) और ऐसे लेन-देनों से सम्बद्ध प्रत्यक्ष लेन-देन लागतों को छोड़कर एक अवधि में 'ईक्विटी' में कुल मिलाकर परिवर्तन उस अवधि में प्रतिष्ठान की गतिविधियों से उत्पन्न लाभ और हानि को मिलाकर आय और व्यय की सम्पूर्ण धनराशि को दर्शाता है।
110. भारतीय लेखा मानक 8 लेखा नीतियों में परिवर्तनों को प्रभावी बनाने हेतु पूर्व प्रभावी समायोजनों की मांग करता है, जहां तक व्यवहार्य हो, सिवाय जब कि अन्य भारतीय लेखा मानक के संक्रमणकालीन प्रावधान अन्यथा मांग करते हैं। भारतीय लेखा मानक 8 पूर्व प्रभावी अवधि से त्रुटियों के सुधार के पुनर्कर्तन की भी मांग करता है, जहां तक व्यवहार्य हो । पूर्व प्रभावी समायोजन और पुनर्कर्तन ईक्विटी में परिवर्तन नहीं है बल्कि वे धारित अर्जन के प्रारंभिक शेष हेतु समायोजन है, सिवाय इसके जब एक भारतीय लेखा मानक ईक्विटी के अन्य घटक के पश्चोन्मुखी समायोजन की मांग करता है। अनुच्छेद 106 (ख) लेखा नीतियों में परिवर्तन के फलस्वरूप ईक्विटी के प्रत्येक घटक के सम्पूर्ण समायोजन तथा पृथक रूप में त्रुटियों के सुधार को ईक्विटी में परिवर्तन विवरण में प्रकटन की मांग करता है। ये समायोजन प्रत्येक पूर्व अवधि और अवधि के प्रारंभ में प्रकट किये जाते हैं।

नकदी प्रवाह विवरण

111. नकदी प्रवाह सूचना वित्तीय विवरणों के उपयोगकर्ताओं को प्रतिष्ठान के नकदी या नकदी तुल्य उत्पन्न करने की योग्यता और उन नकदी प्रवाहों को प्रतिष्ठान की आवश्यकताओं के उपयोग के निर्धारण का आधार प्रदान करता है। भारतीय लेखा मानक 7 नकदी प्रवाह सूचना के प्रस्तुतिकरण व प्रकटन हेतु अपेक्षाएं निर्धारित करता है।

टिप्पणियां

संरचना

112. टिप्पणियां निम्नलिखित के बारे में की जाएंगी :
- (क) वित्तीय विवरणों के तैयार करने के बारे में सूचना प्रदान और अनुच्छेद 117-124 के अनुसार प्रयुक्त विशिष्ट लेखा नीतियां ;
 - (ख) भारतीय लेखा मानकों द्वारा मांगी गयी सूचना का प्रकटन जो कि वित्तीय विवरणों में अन्यत्र प्रस्तुत नहीं की गई है ; और
 - (ग) वित्तीय विवरणों में सूचना जो अन्यत्र प्रस्तुत न हो लेकिन जो उनको समझने के लिए प्रासंगिक है।
113. एक प्रतिष्ठान, जहां तक व्यवहार्य हो, सुव्यवस्थित तरीके से टिप्पणियां प्रस्तुत करेगा। तुलन-पत्र से परिशिष्टित 'ईक्विटी' में परिवर्तन विवरण में और लाभ तथा हानि विवरण में, और नकदी प्रवाह विवरण में प्रत्येक मद का टिप्पणियों में वर्णित सम्बद्ध सूचना का क्रॉस संदर्भ देगा।
114. एक प्रतिष्ठान, वित्तीय विवरणों को समझने और उनकी अन्य प्रतिष्ठान के वित्तीय विवरणों से तुलना हेतु उपयोगकर्ताओं की सहायतार्थ टिप्पणियों को निम्न क्रम में प्रस्तुत करेगा :
- (क) भारतीय लेखा मानकों के साथ अनुपालन विवरण (देखिये अनुच्छेद 16) ;
 - (ख) लागू की गई महत्वपूर्ण लेखा नीतियों का सार (देखिये अनुच्छेद 117) ;
 - (ग) तुलन-पत्र में, तुलन-पत्र के साथ परिशिष्टित 'ईक्विटी' में परिवर्तनों के विवरण में और लाभ तथा हानि विवरण में, और नकदी प्रवाह विवरण में प्रस्तुत मदों के लिए सहायक सूचना ठीक उसी क्रम में जिसमें कि प्रत्येक विवरण व प्रत्येक रेखीय मद प्रस्तुत किया जाता है : और
 - (घ) निम्न को सम्मिलित करते हुए अन्य प्रकटन :
 - (i) संयोगिक देयता [देखिये भारतीय लेखा मानक 37] और गैर-मान्य संविदात्मक वचनबद्धता ; और
 - (ii) गैर-वित्तीय प्रकटन, उदाहरणार्थ, प्रतिष्ठान के वित्तीय जोखिम प्रबन्धन उद्देश्य और नीतियां [देखिये भारतीय लेखा मानक 107] ;

115. कुछ परिस्थितियों में टिप्पणियों में विशिष्ट मदों के क्रम में विचलन आवश्यक या इच्छित हो सकता है। उदाहरणार्थ, एक प्रतिष्ठान लाभ या हानि में मान्य उचित मूल्य में परिवर्तन सूचना को वित्तीय लिखतों की परिपक्वता सूचना के साथ मिला सकता है, यद्यपि पहला प्रकटन लाभ और हानि विवरण से सम्बद्ध है और बाद वाला तुलन-पत्र से सम्बद्ध। तथापि, एक प्रतिष्ठान जहां तक व्यवहार्य हो टिप्पणियों के लिए एक सुव्यवस्थित संरचना ही धारित करता है।
116. एक प्रतिष्ठान वित्तीय विवरणों के पृथक भाग के रूप में वित्तीय विवरणों के निर्माण के आधार और विशिष्ट लेखा नीतियों के बारे में अलग अनुभाग में सूचना प्रदान करने हेतु टिप्पणियां प्रस्तुत कर सकता है।

लेखा नीतियों का प्रकटन

117. एक प्रतिष्ठान महत्वपूर्ण लेखा नीतियों के सारांश में प्रकट करेगा :

(क) वित्तीय विवरणों के निर्माण में प्रयुक्त माप आधार(ों), और

(ख) वित्तीय विवरणों को समझने के लिए प्रासंगिक प्रयुक्त अन्य लेखा नीतियां

118. एक प्रतिष्ठान के लिए यह महत्वपूर्ण है कि वह उपयोगकर्ताओं को वित्तीय विवरणों में प्रयुक्त माप आधार या आधारों (उदाहरणार्थ, ऐतिहासिक लागत, वर्तमान लागत, निवल वसूलीयोग्य मूल्य, उचित मूल्य, या प्राप्त हो सकने वाली राशि) की जानकारी दे, क्योंकि प्रतिष्ठान जिस आधार पर वित्तीय विवरणों का निर्माण करता है उससे उपयोगकर्ताओं का विश्लेषण महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित होता है। जब एक प्रतिष्ठान वित्तीय विवरणों में एक से अधिक मापदंड प्रयोग में लाता है उदाहरणार्थ जब विशेष श्रेणी की आस्तियां पुनर्मूल्यांकित की जाती हैं तो यह एक पर्याप्त संकेत देता है कि किस श्रेणी की आस्तियों और देयताओं को कौन सा मापदंड आधार अपनाया है।
119. यह निश्चित करते समय कि क्या किसी लेखा नीति विशेष का प्रकटन किया जाये, तो प्रबन्ध विचार करता है कि क्या प्रकटन उपयोगकर्ताओं को समझने में सहायक होगा कि किस प्रकार लेन-देन, अन्य घटनाएं और दशाएं रिपोर्टिंग वित्तीय निष्पादन और वित्तीय स्थिति को प्रतिबिंबित करते हैं। विशिष्ट वित्तीय लेखा नीतियों का प्रकटन उपयोगकर्ताओं के लिए तब विशेष उपयोगी हो जाता है, जब वे नीतियां भारतीय लेखा मानकों द्वारा स्वीकृत विकल्पों में से चयनित हों। एक उद्यमी संयुक्त रूप से नियंत्रित प्रतिष्ठान में अपने हित को मान्य के लिए क्या आनुपातिक समेकन या ईक्विटी विधि [देखिये भारतीय लेखा मानक 31 संयुक्त उपक्रमों में हित] के प्रयोज्य द्वारा प्रकटन कर रहा है, इसका उदाहरण है। विशेष रूप से खास लेखा नीतियों के कुछ भारतीय लेखा मानक अनुमत विभिन्न लेखा नीतियों में प्रबन्धन द्वारा किये गये चयनों सहित प्रकटन की मांग करते हैं। उदाहरणार्थ, भारतीय लेखा मानक 16 सम्पत्ति, संयंत्र और उपस्कर की श्रेणियों में प्रयुक्त माप आधारों के प्रकटन की मांग करता है।
120. प्रत्येक प्रतिष्ठान अपने परिचालनों की प्रकृति तथा वित्तीय विवरण के उपयोगकर्ताओं द्वारा उस प्रकार के प्रतिष्ठान हेतु अपेक्षित नीतियों के प्रकटन पर विचार करता है। उदाहरणार्थ, उपयोगकर्ता एक प्रतिष्ठान जिसे आयकर देना होता है उसे आयकर संबंधी लेखा नीतियों में

स्थगित कर देयताओं और आस्तियों पर लागू नीतियों सहित, के प्रकटन की अपेक्षा रखेंगे। जब एक प्रतिष्ठान का महत्वपूर्ण विदेशी परिचालन हो या विदेशी विनिमय लेन-देन हों, तो उपयोगकर्ता विदेशी विनिमय लाभ और हानि संबंधी लेखा नीतियों के प्रकटन की अपेक्षा रखेंगे।

121. भले ही धनराशियां वर्तमान या पूर्व अवधियों के लिए सारवान न हों लेकिन एक लेखा नीति प्रतिष्ठान के परिचालन की प्रकृति के कारण महत्वपूर्ण हो सकती है। यह प्रकट करना भी उपर्युक्त होगा कि प्रत्येक महत्वपूर्ण का लेखा नीति भारतीय लेखा मानक द्वारा विशिष्टतः आवश्यक नहीं है परन्तु प्रतिष्ठान भारतीय लेखा मानक 8 के अनुरूप इसे चयनित और लागू करता है।
122. एक प्रतिष्ठान प्रबन्धन द्वारा प्रतिष्ठान को लेखा नीतियों के लागू करने की प्रक्रिया में लिये गये फैसलों, पूर्वानुमान सम्बद्ध के अतिरिक्त, (देखिये अनुच्छेद 125), जो कि वित्तीय विवरणों में मान्य धनराशियों पर सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रभाव रखते हुए महत्वपूर्ण लेखा नीतियों या अन्य टिप्पणियों के सारांश में प्रकट करेगा।
123. प्रतिष्ठान विशेष की लेखा नीतियों को लागू करने की प्रक्रिया में, प्रबंधन अनेक फैसले करता है, पूर्वानुमान सम्बद्ध के अतिरिक्त, जो कि वित्तीय विवरणों में मान्य धनराशियों को महत्वपूर्ण प्रभावित कर सकती है। उदाहरणार्थ, प्रबंधन निम्न के निर्धारण हेतु फैसले करता है :
 - (क) वित्तीय आस्तियां क्या परिपक्वता-तक-धारित निवेश है,
 - (ख) वित्तीय आस्तियों और पट्टे पर आस्तियों के स्वामित्व सम्बद्ध महत्वपूर्ण जोखिम और पुरस्कार कब अन्य प्रतिष्ठानों को हस्तांतरित किये जाते हैं ;
 - (ग) क्या, वास्तविक अर्थ में, माल की विशिष्ट बिक्रियां वित्तपोषण व्यवस्थाएं हैं और इसलिए राजस्व उत्पन्न नहीं करते ; और
 - (घ) प्रतिष्ठान और एक विशेष प्रयोजन प्रतिष्ठान के बीच संबंध का सार क्या यह बताता है कि प्रतिष्ठान विशेष प्रयोजन प्रतिष्ठान को नियंत्रित करता है।
124. अनुच्छेद 122 के अनुसार किये गये कुछ प्रकटन अन्य भारतीय लेखा मानक भी अपेक्षा करते हैं। उदाहरणार्थ, भारतीय लेखा मानक 27 से उन कारणों के प्रकटन की मांग करता है कि वह विनियोगी जो सहायक प्रतिष्ठान नहीं है यद्यपि आधे से अधिक इसकी मंतशक्ति या संभाव्य मंतशक्ति प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से सहायक प्रतिष्ठान के माध्यम से जिसके पास हो, उसके बाद भी क्यों प्रतिष्ठान के स्वामित्व हित से नियन्त्रण संविहित नहीं होता। भारतीय लेखा मानक 40 निवेश सम्पत्ति, जब सम्पत्ति का वर्गीकरण कठिन हो, तो स्वामी-धारित सम्पत्ति और व्यवसाय के सामान्य प्रसरण में बिक्री हेतु धारित सम्पत्ति में अन्तरभेद के लिए विकसित मानदंडों के प्रकटन की मांग करता है।

अनिश्चितता का अनुमान लगाने के स्रोत

125. एक प्रतिष्ठान, भविष्य के बारे में की गई उन पूर्व धारणाओं और रिपोर्टिंग अवधि के अंत पर पूर्वानुमान के अन्य महत्वपूर्ण स्रोतों की सूचना प्रकट करेगा जिनमें निहित महत्वपूर्ण जोखिम

के परिणाम स्वरूप अगले वित्तीय वर्ष के भीतर आस्तियों और देयताओं की धनराशियों को ले जाये जाने की भी समायोजन जरूरत होती है। उन आस्तियों और देयताओं के संबंध में टिप्पणियां जानकारीयां सम्मिलित करेंगी।

(क) उनकी प्रवृत्ति, और

(ख) रिपोर्टिंग अवधि के अंत पर उनकी अग्रणीत राशि।

126. कुछ आस्तियों और देयताओं की अग्रणीत (कैरिंग) धनराशियों का निर्धारण उन संपत्तियों और देयताओं के रिपोर्टिंग अवधि के अंत पर अनिश्चित भावी घटनाओं के प्रभावों के पूर्वानुमान की मांग करता है। उदाहरणार्थ, हाल ही में पर्यवेक्षित बाजार कीमतों की अनुपस्थिति में, संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर की विभिन्न श्रेणियों की वसूलीयोग्य धनराशि, सामग्रियों पर तकनीकी अप्रचलन के प्रभाव, चल रहे मुकदमों के भावी परिणाम के विषय में प्रावधानों, और दीर्घकालीन कर्मचारी लाभों जैसे कि पेंशन दायित्व का पूर्वानुमान आवश्यक है। इन पूर्वानुमान में ऐसी मदों, जैसे कि नकदी प्रवाहों या बट्टा दरों के लिए जोखिम समायोजन, वेतनों में भावी परिवर्तन और अन्य लागतों के प्रभावित करने वाले भावी परिवर्तन, के बारे में पूर्वधारणाओं हेतु पूर्वानुमान अन्तर्निहित है।
127. अनुच्छेद 125 के अनुसार प्रकटित पूर्वधारणाएं और अनिश्चितता पूर्वानुमान के अन्य स्रोत उन पूर्वानुमानों से सम्बद्ध हैं जो कि प्रबन्धन से सर्वाधिक कठिन, विषयनिष्ठ और जटिल निर्णयों की मांग करते हैं। अनिश्चितताओं के संभाव्य भावी निपटान को प्रभावित करने वाले परिवर्तनशील घटकों और पूर्वधारणाओं की संख्या में जैसे वृद्धि होती है, वे निर्णय और अधिक विषयनिष्ठ तथा जटिल हो जाते हैं, और आस्तियों तथा देयताओं की अग्रणीत (कैरिंग) राशियों की परिणामतः सारवान समायोजनों की संभाव्यता सामान्यतः यथानुसार बढ़ जाती है।
128. अनुच्छेद 125 उन भारी जोखिम वाली आस्तियों और देयता जिनकी आगे ले जायी जाने वाली धनराशि अगले वित्त वर्ष में सारवान रूप में बदल सकती है, यदि रिपोर्टिंग अवधि के अंत पर, उनके उचित मूल्य का माप हाल ही में पर्यवेक्षित बाजार कीमतों पर किया गया हो, के प्रकटन की मांग नहीं करता। ऐसे उचित मूल्यांकन अगले ही वित्त वर्ष के भीतर सारवान रूप में बदल सकते हैं, परन्तु ये परिवर्तन रिपोर्टिंग अवधि के अंत पर पूर्वधारणाओं या अनिश्चितता पूर्वानुमानों के कारण उत्पन्न नहीं होंगे।
129. एक प्रतिष्ठान अनुच्छेद 125 में प्रकटन इस प्रकार करता है जोकि वित्तीय विवरणों के उपयोगकर्ताओं को प्रबन्धन द्वारा भविष्य के बारे में और अनिश्चितता अनुमान के अन्य स्रोतों के बारे में किये गये फैसलों को समझने में सहायक हो। प्रदत्त सूचना की प्रकृति और विस्तार पूर्वानुमान की प्रकृति और परिस्थितियों के अनुसार बदलती रहती है। एक प्रतिष्ठान द्वारा किये जाने वाले प्रकटनों के प्रकारों के उदाहरण हैं :
 - (क) पूर्वधारणाओं या अन्य पूर्वानुमान अनिश्चितता की प्रकृति ;
 - (ख) आगे ले जायी गयी राशियों की परिगणना की विधियों, पूर्वधारणाओं और पूर्वानुमानों के प्रति संवेदनशीलता, संवेदनशीलता के कारणों सहित ;

- (ग) एक अनिश्चितता के संभावित निपटान और अगले वित्त वर्ष में प्रभावित आस्तियों तथा देयताओं से सम्बद्ध में समुचित संभाव्य परिणामों की सीमा ; और
- (घ) अगर अनिश्चितता अभी भी अनिर्णीत हो तो, उन आस्तियों तथा देयताओं से सम्बद्ध अतीतगत पूर्वधारणाओं में परिवर्तन का वर्णन ।
130. यह मानक प्रतिष्ठान अनुच्छेद 125 के अधीन प्रकटन हेतु बजट सूचना या पूर्वानुमानों के प्रकटन की मांग नहीं करता ।
131. कभी-कभी रिपोर्टिंग अवधि के अंत पर किसी पूर्वधारणा या अनिश्चितता पूर्वानुमान के अन्य स्रोत के संभावित प्रभावों की सीमा का प्रकटन अव्यवहार्य होता है। ऐसे मामलों में, प्रतिष्ठान प्रकटन करता है कि वर्तमान जानकारी के आधार पर, यह समुचित संभव है कि अगले ही वित्त वर्ष में परिणाम उस पूर्वधारणा से प्रभावित आस्तियों और देयताओं के लिए ले जाये जाने वाली राशि में सारवान समायोजन आवश्यक हो । सभी मामलों में, प्रतिष्ठान पूर्वधारणा से प्रभावित विशिष्ट आस्ति या देयता की प्रकृति (या आस्तियों व देयताओं की श्रेणी) और अग्रणीत (कैरिंग) राशि का प्रकटन करता है।
132. अनुच्छेद 122 के अन्तर्गत प्रकटित विशिष्ट निर्णय जो कि प्रबन्ध ने लेखा नीतियों के परिपालन की प्रक्रिया में किये हैं वे अनुच्छेद 125 के अधीन अनिश्चितता अनुमान के स्रोतों के प्रकटन से संबंधित नहीं है।
133. भारतीय लेखा मानक उन कुछ पूर्वधारणाओं के प्रकटन की मांग करते हैं जो अन्यथा अनुच्छेद 125 के अनुसार आवश्यक हैं। उदाहरणार्थ भारतीय लेखा मानक 37, विशिष्ट परिस्थितियों में, प्रावधानों की श्रेणियों को प्रभावित करने वाली भावी घटनाओं से सम्बद्ध प्रधान पूर्वधारणाओं के प्रकटन की अपेक्षा करता है। भारतीय लेखा मानक 107 प्रतिष्ठान द्वारा उचित मूल्य पर दिखाये जाने वाली वित्तीय देयताओं के उचित मूल्य के पूर्वानुमान हेतु उपयोजित महत्वपूर्ण पूर्वधारणाओं के प्रकटन की मांग करता है। भारतीय लेखा मानक 16 सम्पत्ति, संयंत्र और उपकरण के पुनर्मूल्यांकित मर्दों के उचित मूल्यों के पूर्वानुमान हेतु प्रतिष्ठान द्वारा उपयोजित महत्वपूर्ण पूर्वधारणाओं के प्रकटन की मांग करता है।

पूंजी

134. एक प्रतिष्ठान इसके वित्तीय विवरणों के उपयोगकर्ताओं को पूंजी प्रबंध हेतु प्रतिष्ठान के उद्देश्यों, नीतियों और प्रक्रियाओं के मूल्यांकन में सहायता के लिए सूचना का प्रकटन करेगा ।
135. अनुच्छेद 134 के अनुपालन हेतु, प्रतिष्ठान निम्नलिखित प्रकट करता है :
- (क) पूंजी के प्रबंधनार्थ इसके उद्देश्यों, नीतियों और प्रक्रियाओं को गुण तक सूचना जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं :-
- (i) इसका वर्णन कि यह पूंजी के रूप में क्या प्रबंध करता है ;

- (ii) जब एक प्रतिष्ठान बाहर से थोपी गयी पूंजी आवश्यकताओं के वशीभूत हो, तो उन आवश्यकताओं को पूंजी प्रबन्ध में कैसे सम्मिलित किया गया है ; और
- (iii) पूंजी प्रबंधनार्थ अपने उद्देश्यों को यह कैसे पूरा कर रहा है।
- (ख) यह पूंजी के रूप में क्या प्रबंध कर रहा है इसके बारे में परिमाणात्मक आकड़ों का सारांश। कुछ प्रतिष्ठान, कुछ वित्तीय देयताओं (जैसे कि सहायक ऋणों के कुछ प्रकार) को पूंजी के भाग के रूप में मानते हैं। अन्य प्रतिष्ठान पूंजी को ईक्विटी के कुछ घटकों (जैसे कि नकदी प्रवाह प्रतिरक्षाओं (हैजज) से उत्पन्न घटकों) से परे मानते हैं ;
- (ग) पूर्व अवधि से (क) और (ख) में कोई परिवर्तन।
- (घ) क्या अवधि विशेष में इसने बाहर से थोपी गयी पूंजी आवश्यकताओं, जिसके विषयान्तर्गत यह है, का अनुपालन किया।
- (ङ) कब प्रतिष्ठान इस प्रकार से बाहर से थोपी गयी पूंजी आवश्यकताओं का अनुपालन नहीं किया, ऐसे अनुपालन अवज्ञा के परिणाम।

प्रतिष्ठान ऐसे प्रकटनों के लिए मुख्य प्रबंधकीय कर्मचारियों को आन्तरिक रूप से प्रदत्त सूचना पर आधारित रहती है।

136. एक प्रतिष्ठान पूंजी का प्रबंध कई तरीकों से कर सकता है और पूंजी आवश्यकताओं के विभिन्न तरीकों के वशीभूत हो सकता है। उदाहरणार्थ, एक व्यवसाय समूह में बीमा गतिविधियों और बैंकिंग गतिविधियों को चलाने वाले प्रतिष्ठान समाविष्ट हो सकते हैं और वे प्रतिष्ठान अनेक क्षेत्राधिकारों के अन्तर्गत परिचालन कर सकते हैं। जब पूंजी आवश्यकताओं का एकीकृत प्रकटन और पूंजी का किस प्रकार प्रबंधन किया जाता है, एक प्रतिष्ठान के पूंजी संसाधनों को समझने के लिए वित्तीय विवरण के उपयोगकर्ता को उपयोगी सूचना न प्रदान करें या भ्रमित करें तो प्रतिष्ठान प्रत्येक पूंजी आवश्यकता के बारे में प्रतिष्ठान जिसके विषयान्तर्गत है, अलग प्रकटन करेगा।

'ईक्विटी' के रूप में वर्णित 'पुट' योग्य वित्तीय लिखतें

- 136 (क) 'ईक्विटी' लिखतें के रूप में वर्गीकृत 'पुट' योग्य वित्तीय लिखतों के लिए एक प्रतिष्ठान प्रकट करेगा (उस सीमा तक कि अन्यत्र प्रकट नहीं किया गया है)

- (क) 'ईक्विटी' के रूप में वर्गीकृत राशि के बारे में परिमाणात्मक आकड़ों का सारांश।
- (ख) पुनर्क्रय या लिखतों के परिशोधन, जब लिखतों के धारकों द्वारा ऐसा चाहा जाये, पूर्व अवधि से किये गये किसी भी परिवर्तन सहित, दायित्व के प्रबंधनार्थ इसके उद्देश्य, नीतियां और प्रक्रियाएं ;
- (ग) वित्तीय लिखतों की उस श्रेणी के परिशोधन या पुनर्क्रय पर निर्धारित अपेक्षित नकदी बाह्य प्रवाह ; और

(घ) परिशोधन या पुनर्क्रय पर निर्धारित अपेक्षित नकदी बाह्य प्रवाह कैसे निर्धारित किया गया के बारे में सूचना ।

अन्य प्रकटन

137. एक प्रतिष्ठान टिप्पणियों में प्रकट करेगा
- (क) वित्तीय विवरणों के जारी करने के अनुमोदन पूर्व प्रस्तावित या घोषित लाभांश की धनराशि परन्तु अवधि विशेष के दौरान स्वामियों के वितरण के लिए अमान्य, और प्रति अंश सम्बद्ध धनराशि ; और
 - (ख) गैर-मान्य संचित पूर्वाधिकार लाभांश की राशि ;
138. एक प्रतिष्ठान निम्नलिखित प्रकट करेगा, यदि वित्तीय विवरणों में प्रकाशित सूचना में अन्य कहीं प्रकट न किया हुआ हो ;
- (क) प्रतिष्ठान विशेष की निवास स्थिति और वैधानिक स्वरूप, इसके सम्मेलन का देश और पंजीकृत कार्यालय (या प्रधान व्यवसायिक स्थान, अगर पंजीकृत कार्यालय से यह भिन्न हो) का पता ;
 - (ख) प्रतिष्ठान के परिचालन की प्रकृति और इसकी मुख्य गतिविधियों का वर्णन ;
 - (ग) सूत्रधारी प्रतिष्ठान और समूह विशेष की अन्तिम सूत्रधारी प्रतिष्ठान का नाम ; और
 - (घ) यदि यह एक सीमित जीवन प्रतिष्ठान है, तो इसके जीवन की दीर्घता के बारे में सूचना ।

परिशिष्ट 'क'

अन्य भारतीय लेखा मानकों के समाविष्ट मामलों के संदर्भ

यह परिशिष्ट भारतीय लेखा मानक (इंड ए एस) 1 का अभिन्न अंग है।

यह परिशिष्ट विभिन्न परिशिष्टों की सूची प्रस्तुत करता है जो अन्य भारतीय लेखा मानकों के अंग हैं और भारतीय लेखा मानकों 1 के लिए भी संदर्भ का कार्य करते हैं।

- 1 परिशिष्ट 'क' स्वामियों को गैर नकद आस्तियों का वितरण ----- भारतीय लेखा मानक 10 रिपोर्टिंग अवधि के बाद की घटनाएं में समाविष्ट
- 2 परिशिष्ट 'क' मौजूदा विस्थापन, पुनर्बहाली एवं इसी तरह की देयताओं में परिवर्तन ---- भारतीय लेखा मानक 16 सम्पत्ति संयंत्र व उपस्कर में समाविष्ट
- 3 परिशिष्ट 'क' अंतरराष्ट्रीय लेखा मानक 19 ---- निश्चित लाभ आस्ति की सीमा, वित्तपोषण की न्यूनतम अपेक्षाएं और उनका अंतव्यवहार ---- भारतीय लेखा मानक 19 कर्मचारी लाभ में समाविष्ट
- 4 परिशिष्ट 'क' अमूर्त आस्तियां - वेबसाईट लागतें भारतीय लेखा मानक 38 अमूर्त आस्तियां में समाविष्ट
- 5 परिशिष्ट 'ड' इक्विटी लिखतों के साथ वित्तीय देयताओं का समापन ---- भारतीय लेखा मानक 39 वित्तीय लिखतें : मान्यता एवं माप में समाविष्ट

परिशिष्ट 1

टिप्पणी : यह परिशिष्ट भारतीय लेखा मानक का अंग नहीं है। इस परिशिष्ट का प्रयोजन मात्र इतना है कि भारतीय लेखा मानक (इंड ए एस) 1 और तदनुसूची अन्तरराष्ट्रीय लेखा मानक (आई ए एस) 1 ' वित्तीय विवरणों का प्रस्तुतिकरण ' के बीच, यदि कोई अंतर हो, तो उन्हें स्पष्ट किया जाए।

अन्तरराष्ट्रीय भारतीय लेखा मानक 1, वित्तीय विवरणों का प्रस्तुतिकरण के साथ तुलना

1. लाभ और हानि विवरणों को तैयार करने के संबंध में, अन्तरराष्ट्रीय लेखा मानक 1, वित्तीय विवरणों का प्रस्तुतिकरण, एकल-विवरण दृष्टिकोण या द्वि-विवरण दृष्टिकोण के अनुगमन का विकल्प प्रदान करता है। एकल-विवरण दृष्टिकोण में आय और व्यय की सभी मदों को लाभ और हानि विवरण में मान्यता दी जाती है, जबकि द्वि-विवरण दृष्टिकोण में दो विवरण तैयार किये जाते हैं, एक लाभ या हानि (पृथक आय विवरण) के घटकों को दर्शाता है और दूसरा लाभ या हानि के साथ शुरु होता है और अन्य व्यापक आय के घटकों को दर्शाता है। भारतीय लेखा मानक 1 केवल एकल-विवरण की अनुमति देता है। अन्तरराष्ट्रीय भारतीय लेखा मानक 1 का अनुच्छेद 84 द्वि-विवरण दृष्टिकोण के संदर्भ में है। जैसे कि भारतीय लेखा मानक 1 इस विकल्प की अनुमति नहीं देता है अतः इसमें से अनुच्छेद 84 को हटा दिया गया है। फिर भी, भारतीय लेखा मानक 1 और अन्तरराष्ट्रीय लेखा मानक 1 की अनुच्छेद संख्याओं में क्रमबद्धता बनी रहे, अतः भारतीय लेखा मानक 1 में अनुच्छेद संख्या 84 को रहने दिया गया है।
2. अन्तरराष्ट्रीय भारतीय लेखा मानक 1, 'ईक्विटी' में परिवर्तन के एक विवरण की अपेक्षा करता है। भारतीय लेखा मानक 1 में ईक्विटी परिवर्तन विवरण तुलन-पत्र के एक अंग के रूप में प्रदर्शित किया जाना अपेक्षित है। अन्तरराष्ट्रीय लेखा मानक 1 का अनुच्छेद 10 (ग) 'ईक्विटी' में परिवर्तन के पृथक विवरण के संदर्भ में है। चूंकि भारतीय लेखा मानक 1 में इसकी आवश्यकता नहीं है, अतः इसमें से इसे हटा दिया गया है। लेकिन, अन्तरराष्ट्रीय लेखा मानक 1 और भारतीय लेखा मानक 1 की अनुच्छेद संख्याओं की परस्पर क्रमबद्धता बनी रहे, अतः इस आशय से अनुच्छेद 10 (ग) को भारतीय लेखा मानक में रहने दिया गया है।
3. भारतीय लेखा मानक 1 में भिन्न शब्दावली का प्रयोग किया गया है, उदाहरणार्थ, शब्दों 'वित्तीय स्थिति का विवरण' के स्थान पर शब्द 'तुलन-पत्र' और शब्दों 'व्यापक आय विवरण' के स्थान पर शब्दों 'लाभ-हानि विवरण' का प्रयोग किया गया है। रिपोर्टिंग अवधि के बाद की घटनाओं के प्रयोजन के संदर्भ में 'वित्तीय विवरणों को जारी करने के लिए प्राधिकारिता' के स्थान पर शब्दों 'वित्तीय विवरणों को जारी करने के लिए अनुमोदन' का प्रयोग किया गया है।

4. अन्तरराष्ट्रीय भारतीय लेखा मानक 1, का अनुच्छेद 8 प्रतिष्ठानों को वित्तीय विवरणों के शीर्षकों हेतु विभिन्न शब्दावली का विकल्प देता है। भारतीय लेखा मानक 1 को परिवर्तित किया गया है ताकि विकल्पों को हटाकर सभी प्रतिष्ठानों द्वारा एक ही शब्दावली का प्रयोग करने की अपेक्षा करता है। लेकिन, भारतीय लेखा मानक 1 में अनुच्छेद 8 को इस आशय के साथ रहने दिया गया है ताकि इस मानक के अनुच्छेदों की संख्या की क्रमबद्धता अन्तरराष्ट्रीय लेखा मानक की अनुच्छेद संख्याओं के साथ बनी रहे।
5. अन्तरराष्ट्रीय लेखा मानक 1 का अनुच्छेद 37 एक विशेष अवधि की अनुमति देता है। उदाहरणार्थ, वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए 52 सप्ताह की अवधि प्रदान करता है। चूंकि भारतीय लेखा मानक 1 ऐसी कोई अनुमति नहीं देता, अतः इसमें से इसे हटा दिया गया है। फिर भी, अनुच्छेद 37 को भारतीय लेखा मानक में इस आशय से रहने दिया गया है ताकि उसकी अनुच्छेद अन्तरराष्ट्रीय लेखा मानक की अनुच्छेद की संख्याओं के साथ क्रमबद्धता बनी रहे।
6. अन्तरराष्ट्रीय भारतीय लेखा मानक का अनुच्छेद 99 एक प्रतिष्ठान से लाभ या हानि में मान्य व्यय के विश्लेषण की अपेक्षा करता है जो कि प्रतिष्ठान के भीतर उनकी प्रकृति या उनके कार्य पर आधारित वर्गीकरण का उपयोग करता है। भारतीय लेखा मानक 1 केवल प्रकृति-आधारित व्यय वर्गीकरण की अपेक्षा करता है। अन्तरराष्ट्रीय लेखा मानक 1 में निम्नलिखित अनुच्छेद के कार्य अनुसार व्यय वर्गीकरण के संदर्भ में हैं। भारतीय लेखा मानक 1 में इन अनुच्छेदों को इस आशय से रहने दिया गया है ताकि इस मानक के अनुच्छेदों की संख्या की क्रमबद्धता अन्तरराष्ट्रीय लेखा मानक 1 की अनुच्छेद संख्याओं के साथ बनी रहे :-
 - (i) अनुच्छेद 103
 - (ii) अनुच्छेद 104
 - (iii) अनुच्छेद 105
7. अन्तरराष्ट्रीय लेखा मानक 1 में कार्यान्वयन-संबंधी मार्गदर्शन का समावेश है। भारतीय लेखा मानक 1 में इसे सम्मिलित नहीं किया गया है क्योंकि अलग-अलग अधिनियम अलग-अलग फार्मेट निर्धारित करते हैं, जैसे कि, उदाहरणार्थ, कंपनी अधिनियम 1956 में अनुसूची VI.
8. अन्तरराष्ट्रीय लेखा मानक 1 में अनुच्छेद 106 (ग) 'हटाया गया' के रूप में उल्लिखित है। लेकिन, अन्तरराष्ट्रीय लेखा मानक की अनुच्छेद संख्याओं की भारतीय लेखा मानक 1 की अनुच्छेद संख्याओं के साथ क्रमबद्धता बनी रहे, इस आशय से इस संख्या को भारतीय लेखा मानक 1 में रहने दिया गया है।
9. अन्तरराष्ट्रीय लेखा मानक 19 की तुलना में भारतीय लेखा मानक 19 में कुछ परिवर्तनों के परिणामस्वरूप, अन्तरराष्ट्रीय लेखा मानक 19 के अनुच्छेद 93 'क' का क्रॉस संदर्भ भारतीय लेखा मानक के अनुच्छेद 92 व 129 'क' के क्रॉस संदर्भ के रूप में संशोधित कर दिया गया है।

भारतीय लेखा मानक (इंड ए एस) 16

सम्पत्ति, संयंत्र और उपस्कर

(इस भारतीय लेखा मानक में **मोटे टाइप व सामान्य टाइप में अनुच्छेद हैं। इन दोनों तरह के अनुच्छेदों का समान प्राधिकार है। मोटे टाइप में अनुच्छेद मुख्य सिद्धान्तों के सूचक हैं।**)

उद्देश्य

1. इस मानक का उद्देश्य, एक प्रतिष्ठान की सम्पत्ति, संयंत्र और उपस्कर के लिए लेखा प्रक्रिया निर्धारित करना है ताकि वित्तीय विवरणों के उपयोगकर्ताओं को उसकी सम्पत्ति, संयंत्र और उपस्कर में निवेश और ऐसे निवेश में परिवर्तनों के बारे में सूचना की आवश्यक जानकारी प्राप्त हो सके। सम्पत्ति, संयंत्र और उपस्कर के लेखों के प्रमुख मुद्दे हैं : आस्तियों की मान्यता, उनकी अग्रणीत (कैरिंग) राशियों का निर्धारण और मूल्यहास प्रभार तथा उनके संबंध में मान्य की जाने वाली क्षतिग्रस्तता हानियाँ।

कार्यक्षेत्र

2. यह मानक सम्पत्ति, संयंत्र और उपस्कर के लेखों में लागू किया जाएगा, सिवाय इसके, जब लेखों के लिए कोई अन्य भारतीय लेखा मानक अलग लेखा विधि की अपेक्षा करता है या इसकी अनुमति देता है।
3. यह मानक निम्नलिखित पर लागू नहीं होता है :-
 - क) भारतीय लेखा मानक (इंड ए एस) 105 बिक्री हेतु धारित के रूप में गैर चालू आस्तियाँ और बन्द परिचालन के अनुसरण में बिक्री के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत सम्पत्ति, संयंत्र और उपस्कर ;
 - ख) कृषि कार्य-कलापों से संबंधित जैविक आस्तियाँ [देखें भारतीय लेखा मानक (इंड ए एस) 41 'कृषि']¹ ;
 - ग) खोज और मूल्यांकन आस्तियों की मान्यता और माप [देखें भारतीय लेखा मानक (इंड ए एस) 106 खनिज संसाधनों की खोज और मूल्यांकन ; अथवा
 - घ) खनिज अधिकार और खनिज रिजर्व, जैसे कि तेल, प्राकृतिक गैस और इससे मिलते-जुलते पुनरुत्पादन-रहित संसाधन ।

¹ भारतीय लेखा मानक (इंड ए एस) 41 'कृषि' तैयार किया जा रहा है।

लेकिन, यह लेखा मानक उन सम्पत्तियों, संयंत्रों और उपस्करों पर लागू होता है जो उपर्युक्त (ख)-(घ) में वर्णित आस्तियों के विकास या रखरखाव में प्रयोग होते हैं।

4. अन्य भारतीय लेखा मानक सम्पत्ति, संयंत्र और उपस्कर की किसी मद की मान्यता के लिए इस मानक से भिन्न किसी अलग दृष्टिकोण की अपेक्षा कर सकते हैं। उदाहरणार्थ, भारतीय लेखा मानक 17 'पट्टे' एक प्रतिष्ठान से यह अपेक्षा करता है कि वह किसी पट्टाशुदा सम्पत्ति, संयंत्र और उपस्कर की किसी एक मद की मान्यता का मूल्यांकन जोखिमों व पुरस्कारों के अन्तरण के आधार पर करे। हालांकि, ऐसे मामलों में इन आस्तियों की लेखा विधि के अन्य पहलु, जिनमें मूल्यहास भी शामिल है, इस मानक द्वारा निर्धारित किये जाते हैं।
5. भारतीय लेखा मानक 40 'निवेश सम्पत्ति' के अनुसरण में, एक प्रतिष्ठान निवेश सम्पत्ति के लेखा के लिए इस लेखा मानक में दिये गये लागत मॉडल का प्रयोग करेगा।

परिभाषाएं

6. इस मानक में निम्नलिखित शब्दावली का प्रयोग यहां विनिर्दिष्ट अर्थों में किया गया है :

अग्रणीत (कैरिंग) राशि : यह वह राशि है, जिस पर किसी आस्ति की मान्यता कुल संचित मूल्यहास तथा संचित क्षतिग्रस्तता हानि को घटाकर की जाती है।

लागत : यह एक नकद या नकदी तुल्य राशि है जिसे किसी आस्ति के अधिग्रहण या निर्माण के लिए भुगतान किया जाता है अथवा अन्य प्रतिफल द्वारा उचित मूल्य के रूप में दिया जाता है, या जहां लागू है, अन्य भारतीय लेखा मानकों जैसे भारतीय लेखा मानक 102 'शेयर आधारित भुगतान' की विभिन्न अपेक्षाओं के अनुसार प्रारम्भ में मान्य आस्ति की राशि के रूप में होता है।

मूल्यहासयोग्य राशि : यह वह राशि है जो किसी आस्ति की लागत है या लागत हेतु वह वैकल्पिक अन्य राशि है जिनमें से उसका अवशिष्ट मूल्य घटा दिया जाता है।

मूल्यहास : यह किसी आस्ति के उपयोगी जीवन के दौरान मूल्यहासयोग्य राशि का एक व्यवस्थित आबंटन है।

प्रतिष्ठान - विशेष मूल्य : यह वह मूल्य है जिसे प्रतिष्ठान किसी आस्ति के निरन्तर उपयोग से नकद प्रवाह (कैश फ्लो) के वर्तमान मूल्य के रूप में पाने की आशा करता है व इसके उपयोगी जीवन के बाद निपटान पर या फिर किसी देयता के भुगतान के समय खर्च करने की आशा करता है।

उचित मूल्य : यह वह राशि है, जिस पर किसी आस्ति का जानकार व इच्छुक पक्षों के बीच स्वतंत्र विनिमय किया जा सकता हो।

क्षतिग्रस्तता हानि : किसी आस्ति की अग्रणीत (कैरिंग) राशि उसकी वसूलीयोग्य राशि से जितनी अधिक है।

सम्पत्ति, संयंत्र और उपस्कर वे मूर्त मदें हैं, जो -

- (क) वस्तुओं या सेवाओं के उत्पादन या आपूर्ति के उपयोग के लिए अन्य को किराये के लिए, या फिर प्रशासनिक उपयोग के लिए धारित की जाती हैं ; और
- (ख) जिनकी एक-से अधिक अवधियों के दौरान, इस्तेमाल किये जाने की संभावना हो ।

वसूलीयोग्य राशि : किसी आस्ति (परिसम्पत्ति) के उचित मूल्य से बिक्री लागत घटाकर जो राशि शेष रहती है और उपयोग में इसके मूल्य की राशि, इन दो में से जो राशि अधिक है उसे वसूलीयोग्य राशि कहा जाता है।

अवशिष्ट मूल्य : किसी आस्ति का अवशिष्ट मूल्य वह अनुमानित राशि है जो कोई प्रतिष्ठान वर्तमान में आस्ति की आयु पूरी होने और उपयोगी जीवन के अन्त में उसके निपटान पर अनुमानित लागतों को घटाने के पश्चात् प्राप्त करने की आशा करता है।

उपयोगी जीवन : किसी आस्ति के उपयोगी जीवन से तात्पर्य है -

- (क) वह अवधि जिसमें कोई आस्ति किसी प्रतिष्ठान द्वारा इस्तेमाल के लिए उपलब्ध रहती है ;
- (ख) किसी प्रतिष्ठान द्वारा उस आस्ति से उत्पादन की संख्या या इससे मिलती-जुलती इकाईयों के प्राप्त होने की आशा ।

मान्यता

7. किसी सम्पत्ति, संयंत्र, और उपस्कर की एक मद की लागत को किसी आस्ति के रूप में मान्यता तभी दी जायेगी, यदि और केवल यदि :
 - (क) यह संभव है कि इस मद के साथ जुड़े भावी आर्थिक लाभ प्रतिष्ठान को प्राप्त होते रहेंगे।
 - (ख) इस मद की लागत को ठीक-ठीक मापा जा सकता हो।
8. अतिरिक्त पुर्जों और सर्विसिंग में प्रयुक्त होने वाले उपस्करों को सामान्यतया सूचीबद्ध सामान (इन्वेंट्री) के रूप में लिया जाता है और लाभ या हानि में उसकी मान्यता उपभोग में की जाती है। लेकिन, बड़े अतिरिक्त पुर्जों, सहायक उपस्कर और सर्विसिंग उपस्कर तभी सम्पत्ति, संयंत्र और उपस्कर के रूप में मान्य होंगे, जब प्रतिष्ठान यह आशा करता है कि ये मदें एक से अधिक अवधियों के दौरान उपयोग में लायी जाएंगी।
9. यह मानक मान्यता के माप की किसी इकाई को निर्धारित नहीं करता है अर्थात् सम्पत्ति, संयंत्र और उपस्कर की मद कैसे बनती है। अतः किसी प्रतिष्ठान की विशेष परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए मान्यता के मानदण्ड का निर्णय लिया जा सकता है। यह उपयुक्त होगा कि गैर-महत्वपूर्ण मदों जैसे कि सांचों, औजारों और इकाईयों की अलग-अलग मदों को एक-साथ लिया जाए तथा उनके समूचे मूल्य पर मानदण्ड को लागू किया जाए ।

10. इस मान्यता सिद्धान्त के अन्तर्गत, एक प्रतिष्ठान द्वारा अपनी समस्त सम्पत्ति, संयंत्र और उपस्कर लागतों का मूल्यांकन उस समय करता है जब उन पर वह व्यय करता है। इन लागतों में सम्पत्ति, संयंत्र और उपस्कर की किसी मद को प्राप्त करने या उसके निर्माण करने के लिए खर्च किये गये प्रारम्भिक व्यय के अलावा वह व्यय भी शामिल होता है जो बाद में इसके किसी भाग को जोड़ने/बदलने या उसकी सर्विसिंग के लिए खर्च किया जाता है।

प्रारम्भिक लागतें

11. सम्पत्ति, संयंत्र और उपस्कर की मदों को सुरक्षा या पर्यावरण कारणों से भी प्राप्त किया जा सकता है। इस प्रकार की सम्पत्ति, संयंत्र और उपस्कर के अधिग्रहण से भले ही किसी वर्तमान मद से भविष्य में सीधे कोई आर्थिक लाभ प्राप्त नहीं भी हो, लेकिन, यह संभव है कि अन्य आस्तियों से भविष्य में प्रतिष्ठान को ये आर्थिक लाभ मिलें। सम्पत्ति, संयंत्र और उपस्कर की ऐसी मदें आस्तियों की मान्यता के लिए योग्यता प्राप्त करती हैं, क्योंकि प्रतिष्ठान को भविष्य में ऐसे आर्थिक लाभ मिल सकते हैं जो निस्सन्देह उससे अधिक होंगे जो उनके न होने पर होते हैं। उदाहरणार्थ, कोई रासायनिक विनिर्माता खतरनाक रसायनों के उत्पादन और भण्डारण के लिए एक नई रसायन विस्थापन की प्रक्रिया स्थापित करता है जो पर्यावरणी अपेक्षाओं को पूरा करने हेतु आवश्यक है। इस व्यवस्था में लगाये गये अतिरिक्त संयंत्र की मान्यता आस्ति के रूप में की जाती है, क्योंकि उसके बिना वह प्रतिष्ठान रसायनों का विनिर्माण और विक्रय नहीं कर सकता। इस प्रकार की ऐसी किसी आस्ति और इससे सम्बद्ध किसी अन्य आस्ति की परिणामस्वरूप अग्रणीत (कैरिंग) राशि की क्षतिग्रस्तता के लिए समीक्षा भारतीय लेखा मानक 36 'आस्तियों की क्षतिग्रस्तता' के अनुसार की जाएगी।

उत्तरवर्ती लागतें

12. अनुच्छेद 7 में दिये गये मान्यता सिद्धान्त के अन्तर्गत, कोई भी प्रतिष्ठान सम्पत्ति, संयंत्र और उपस्कर की किसी मद की अग्रणीत राशि में मद की दिन-प्रतिदिन की सर्विस लागतों को मान्यता में शामिल नहीं करता है। इसकी बजाय, खर्च की गयी ये लागतें लाभ या हानि में मान्य होती हैं। दिन-प्रतिदिन की सर्विसिंग लागतों में मुख्यतया श्रम तथा उपभोग्य वस्तुओं (खपत) पर खर्च होने वाली लागतें आती हैं। इनमें छोटे पुर्जों की लागतें शामिल रहती हैं। इस प्रयोजन से किये गये सभी खर्च प्रायः सम्पत्ति, संयंत्र और उपस्कर की संबंधित मद के 'मरम्मत और रखरखाव' व्यय की श्रेणी में आते हैं।
13. सम्पत्ति, संयंत्र और उपस्कर की कुछ मदों के पुर्जों को नियमित रूप से एक अवधि के बाद बदलना जरूरी हो जाता है। उदाहरणार्थ, भट्टी (फर्नेस) को निश्चित कुछ घण्टा के प्रयोग के बाद रिलाइनिंग की आवश्यकता होती है या वायुयान की आंतरिक मदों जैसे कि सीटों और गेली को एयरफ्रेम के जीवन काल के दौरान कई बार बदलना पड़ता है। सम्पत्ति, संयंत्र और उपस्कर की कुछ मदों को इस तरह से भी लिया जाता है कि उन्हें बार-बार या बहुत जल्दी न बदलना पड़े। जैसे कि भवन की आंतरिक दीवारों को बार-बार नहीं बदला जाता है या कभी-कभी बदला जाता है। मान्यता सिद्धान्त के अनुच्छेद 7 के अन्तर्गत एक प्रतिष्ठान सम्पत्ति, संयंत्र और उपस्कर की किसी

मद की अग्रणीत राशि में ऐसी मद के पुर्जों को बदलने की लागत तभी शामिल करता है जब कि लागत खर्च करने में मान्यता कसौटी पूरी होती है। जिन पुर्जों को बदल दिया गया है उनकी अग्रणीत राशि को इस मानक (देखें अनुच्छेद 67-72) के गैर-मान्यता प्रावधानों के अनुसार अमान्य कर दिया जाता है।

14. सम्पत्ति, संयंत्र और उपस्कर (उदाहरणार्थ एक वायुयान) की कोई मद परिचालन में जारी रहे इसके लिए नियमित मुख्य निरीक्षण किये जाते हैं ताकि दोषों या कमियों का पता चलता रहे और उन्हें समय पर दूर किया जा सके, इसमें यह जरूरी नहीं कि उस मद के पुर्जों को बदला भी जाए। जब कोई मुख्य निरीक्षण किया जाता है तो सम्पत्ति, संयंत्र और उपस्कर की मद की अग्रणीत राशि में उसकी लागत को बदलने की लागत के रूप में मान्यता दी जाती है बशर्ते जब मान्यता प्रदान करने की कसौटी पूरी हो। पूर्व निरीक्षण की लागत की किसी शेष अग्रणीत राशि (भौतिक पुर्जों से भिन्न) को अमान्य कर दिया जाता है। यह पूर्व निरीक्षण की लागत को लेन-देन में विनिर्दिष्ट न किये जाने की स्थिति में भी हो सकता है जिसके दौरान मद को प्राप्त किया गया या निर्मित किया गया था। यदि आवश्यक हो तो इसी भांति के भावी निरीक्षण की अनुमानित लागत को इस संकेत के रूप में भी प्रयोग में लाया जा सकता है कि जब मद को प्राप्त या निर्मित किया गया था तो वर्तमान निरीक्षण के घटक की लागत क्या थी।

मान्यता का माप

15. सम्पत्ति, संयंत्र और उपस्कर की वह मद जो किसी आस्ति के रूप में मान्यता के लिए अहर्ता प्राप्त करती है तो उसका माप उसकी लागत पर ही किया जाएगा।

लागत के घटक

16. सम्पत्ति, संयंत्र और उपस्कर की एक मद की लागत में निम्नलिखित शामिल रहते हैं :-
 - क) मद का खरीद मूल्य जिसमें आयात शुल्क, गैर-वापसीयोग्य खरीद कर लेकिन व्यापार बढ़ा और छूट को घटाने के पश्चात्।
 - ख) किसी भी आस्ति को स्थल विशेष तक लाने या प्रबन्धन द्वारा वांछित तरीके से परिचालन योग्य बनाने के लिए आवश्यक प्रत्यक्ष रूप से खर्च की जाने वाली सभी लागतें।
 - ग) मद को विखण्डित करने, हटाने और स्थल विशेष को, जिस पर इसे लगाया गया था, वापस करने की प्रारंभिक अनुमानित लागतें जिनके लिए प्रतिष्ठान मद के अधिग्रहण या प्रयोग के दौरान खर्च करने के लिए बाध्यकारी रहा है, लेकिन, जो माल (स्टॉक) की उत्पादन से भिन्न हो।
17. प्रत्यक्ष रूप से संबंधित लागतों के उदाहरण इस प्रकार हैं -

- क) सम्पत्ति, संयंत्र और उपस्कर की मद के निर्माण या प्राप्ति से सीधे उत्पन्न कर्मचारियों के लाभों की लागत [भारतीय लेखा मानक 19 'कर्मचारियों के लाभ' में यथा परिभाषित] ;
- ख) स्थल की तैयारी की लागतें ;
- ग) प्रारंभिक सुपुर्दगी और लदाई-उतराई की लागतें ;
- घ) संस्थापना व जोड़-जुड़ाई की लागतें ;
- ङ) क्या आस्ति ठीक से कार्य कर रही है, इसकी परीक्षण जांच करवाने की लागतें जिनमें स्थल पर आस्ति को लाने और कार्य योग्य बनाने के समय जो [जैसे कि नमूना (सैम्पल) के रूप में] उत्पाद किया गया है उसकी बिक्री को घटाया जाएगा ।
- (च) व्यावसायिक फीस
18. प्रतिष्ठान भारतीय लेखा मानक 2 'सूचीबद्ध सामान' को उन लागतों पर लागू करता है जो उसके लिए मद को विखंडित करने, हटाने तथा स्थल को प्रयोग के बाद वापस सुपुर्द करने के लिए बाध्यकारी हैं और ये लागतें उस अवधि के दौरान मद के प्रयोग के परिणामस्वरूप सूचीबद्ध सामान के उत्पादन पर खर्च की गयी हैं। इन लागतों के दायित्वों का लेखा भारतीय लेखा मानक 2 या भारतीय लेखा मानक 16 के अनुसार और इनकी मान्यता व माप भारतीय लेखा मानक 37 'प्रावधान, आकस्मिक देयताएं एवं आकस्मिक आस्तियां' के अनुसरण में किया जाता है।
19. जो लागतें सम्पत्ति, संयंत्र तथा उपस्कर की एक मद की लागतें नहीं मानी जाती हैं उनके उदाहरण इस प्रकार हैं :-
- क) नई सुविधा प्रारंभ करने की लागतें ;
- ख) नया उत्पाद अथवा सेवा शुरू करने की लागतें (विज्ञापन तथा प्रोन्नति के क्रियाकलापों की लागतों सहित) ;
- ग) नये स्थान पर अथवा ग्राहकों की नयी श्रेणी के साथ व्यवसाय शुरू करने की लागतें (स्टाफ प्रशिक्षण की लागतों सहित) ; और
- घ) प्रशासनिक तथा अन्य सामान्य उपरि-व्यय ।
20. संपत्ति, संयंत्र तथा उपस्कर की मद की अग्रणीत राशि में लागतों की मान्यता तब समाप्त हो जाती है जब मद ऐसे स्थल तथा स्थिति में हो, जो प्रबंधन द्वारा वांछित तरीके से परिचालन के योग्य हो । अतः एक मद को प्रयोग में लाने अथवा पुनः स्थापित करने की लागत को उस मद की अग्रणीत लागत में शामिल नहीं किया जाता । उदाहरणतया संपत्ति, संयंत्र तथा उपस्कर की मद की अग्रणीत राशि में निम्नलिखित लागतों को शामिल नहीं किया जाएगा :-
- (क) जहां मद प्रबंधन द्वारा वांछित तरीके के अनुसार परिचालन के योग्य तो है लेकिन उसका अभी उपयोग किया जाना है अथवा उसका उपयोग पूर्ण क्षमता से नहीं किया जा रहा है, इससे सम्बंधित खर्च की गयी लागतें ;
- (ख) प्रारंभिक परिचालनगत हानियाँ, उदाहरणतया जब मद के उत्पादन की मांग उत्पन्न हो रही हो, उस बीच हुई हानियाँ ;

(ग) प्रतिष्ठान के कुछ अथवा सभी परिचालनों को अन्यत्र ले जाने अथवा पुनर्गठित करने की लागतें ।

21. संपत्ति संयंत्र तथा उपस्कर की एक मद के निर्माण अथवा विकास के समय कुछ परिचालन-कार्य ऐसे हो सकते हैं जो कि आवश्यक नहीं हैं कि उस मद को उस स्थल तथा स्थिति में ला सकें, जो कि प्रबंधन द्वारा वांछित तरीके के अनुसार वे परिचालन के योग्य हों। ऐसे स्थितिबश परिचालन कार्य निर्माण अथवा विकास संबंधी क्रियाकलापों के दौरान अथवा पहले हो सकते हैं। उदाहरणतया जब तक भवन का निर्माण-कार्य शुरू न हो, स्थल का उपयोग कार पार्किंग के लिए करना और आय अर्जित करना। चूंकि स्थितिबश परिचालन-कार्य मद को प्रबंधन द्वारा वांछित तरीके के अनुसार ऐसे स्थल तथा स्थिति में लाने के लिए आवश्यक नहीं है, स्थितिबश परिचालन-कार्य से संबंधित आय तथा व्यय को लाभ अथवा हानि में मान्यता दी जाएगी तथा उसे आय व व्यय के संबंधित वर्गीकरण में डाला जाएगा।
22. स्वनिर्मित आस्ति की लागत का निर्धारण खरीदी आस्ति के सिद्धान्तों के अनुसार ही किया जाता है। यदि कोई प्रतिष्ठान सामान्य कारोबार के दौरान, समरूप आस्तियों की बिक्री करता है तो आस्ति की लागत सामान्यतः वैसा ही माना जाएगा जैसे कि आस्ति का निर्माण बिक्री के लिए हो। [देखें भारतीय लेखा मानक 2] अतः ऐसी लागतों का निर्धारण करते समय आंतरिक लाभों को नहीं घटाया जाता है। इसी प्रकार स्वनिर्मित की जाने वाली आस्ति के निर्माण को समय फालतू सामग्री, श्रम तथा अन्य संसाधनों में राशियों को आस्ति की लागत में शामिल नहीं किया जाएगा। भारतीय लेखा मानक 23 ' उधार की लागतें ' द्वारा स्वनिर्मित संपत्ति, संयंत्र तथा उपस्कर की अग्रणीत राशि में ब्याज की श्रेणी को एक घटक के रूप में माना गया है।

लागत का माप

23. किसी संपत्ति, संयंत्र तथा उपस्कर की लागत, निश्चित तारीख को उसकी नकद कीमत के बराबर होता है। यदि भुगतान सामान्य ऋण शर्तों से आस्थगित होता है तो समान नकद कीमत व कुल भुगतान के अंतर को ऋण अवधि के दौरान ब्याज के रूप में मान्यता दी जाती है जब तक उसे भारतीय लेखा मानक 23 के अनुसार पूंजीकृत न किया गया हो।
24. संपत्ति, संयंत्र तथा उपस्कर की एक या एक से अधिक मदों को गैर-मौद्रिक आस्ति/यों अथवा मौद्रिक एवं गैर-मौद्रिक दोनों आस्तियों के बदले अधिगृहीत किया जा सकता है। आगे की चर्चा एक गैर-मौद्रिक आस्ति को दूसरी गैर-मौद्रिक आस्ति के साथ विनिमय से अधिगृहीत करने पर की गई है, परन्तु यह पिछले वाक्य में दिए गए सभी विनिमयों पर भी लागू है। ऐसी संपत्ति, संयंत्र तथा उपस्कर की लागत उचित मूल्य पर निर्धारित की जाती है, बशर्ते -

(क) विनिमय द्वारा लेन-देन में वाणिज्यिक तत्व का अभाव हो ; अथवा

(ख) प्रदान की गई आस्ति अथवा प्राप्त की गई आस्ति का उचित मूल्य विश्वसनीय रूप से माप योग्य न हो।

उपार्जित मद की लागत का निर्धारण इसी प्रकार किया जाता है, भले ही प्रतिष्ठान बदले में दी गयी आस्ति को तत्काल अमान्य न कर पाए। यदि उपार्जित मद की लागत का निर्धारण उचित मूल्य पर न हो पाए, तो उसकी लागत का निर्धारण बदले में दी गयी आस्ति की अग्रणीत राशि पर किया जाएगा।

25. एक प्रतिष्ठान यह निर्धारित करता है कि किसी विनिमय द्वारा लेन-देन में क्या कोई वाणिज्यिक सार है या नहीं और इसके लिए वह इस बात पर विचार करता है कि लेनदेन से उसके भावी नकदी प्रवाह पर किस सीमा तक प्रभाव पड़ेगा। विनिमय द्वारा लेनदेन में वाणिज्यिक तत्व होता है, यदि :
- (क) प्राप्त की गयी आस्ति का उसके नकदी प्रवाह विन्यास (जोखिम, समय तथा राशि) अन्तरित की गयी आस्ति से भिन्न हो,
 - (ख) विनिमय लेन-देन के परिणामस्वरूप प्रतिष्ठान के परिचालन के प्रभावित विशिष्ट भाग के मूल्य में परिवर्तन हुआ हो ; तथा
 - (ग) उपरोक्त (क) अथवा (ख) में अंतर विनिमय की गई आस्तियों के उचित मूल्य के संबंध में महत्वपूर्ण हो।

यह निर्धारित करने के प्रयोजन से कि एक विनिमय लेनदेन का क्या कोई वाणिज्यिक सार है, लेनदेन से प्रभावित प्रतिष्ठान के परिचालनों के भाग का प्रतिष्ठान विशिष्ट मूल्य करोपरान्त नकदी प्रवाहों को परिलक्षित करेगा। इन विश्लेषणों का परिणाम विस्तृत गणनाएं किए बिना भी स्पष्ट हो सकता है।

26. एक आस्ति का उचित मूल्य, जिसके लिए बाजार के तुलनात्मक लेनदेन नहीं हैं, जिसे विश्वसनीय रूप से मापा जा सकता है, यदि
- (क) युक्तिपूर्ण उचित मूल्य की परिवर्तनशीलता का अनुमान उस आस्ति के संबंध में महत्वपूर्ण न हो ; अथवा
 - (ख) सीमा (रेंज) के अंदर विभिन्न प्रावधानों की संभाव्यताओं का युक्तिपूर्ण आकलन करके उचित मूल्य ज्ञात करने के लिए प्रयोग किया जा सकता है। यदि एक प्रतिष्ठान प्राप्त आस्ति या बदले में दी हुई आस्ति के उचित मूल्य को विश्वसनीय रूप से निर्धारित कर सकता है तो बदले में दी हुई आस्ति का उचित मूल्य प्राप्त आस्ति की लागत के माप के लिए प्रयोग किया जा सकता है बशर्ते जब प्राप्त आस्ति का उचित मूल्य ज्यादा स्पष्ट न हो।
27. वित्तीय पट्टे के अधीन पट्टेदार द्वारा धारित सम्पत्ति, संयंत्र तथा उपस्कर की लागत भारतीय लेखा मानक 17 के अनुसार निर्धारित की जाएगी।
28. [देखिये परिशिष्ट 1]।

मान्यता के पश्चात् माप

29. प्रतिष्ठान अपनी लेखा नीति के लिए, अनुच्छेद 30 के अनुसार लागत मॉडल अथवा अनुच्छेद 31 के अनुसार पुनर्मूल्यांकन मॉडल को चुनेगा तथा उस नीति को सम्पूर्ण श्रेणी की सम्पत्ति, संयंत्र तथा उपस्कर के लिए अपनाएगा।

लागत मॉडल

30. आस्ति के रूप में मान्य होने के पश्चात् सम्पत्ति, संयंत्र तथा उपस्कर की किसी मद की लागत से संचित मूल्यहास तथा संचित क्षतिग्रस्तता हानियों को घटाकर अग्रणीत (कैरी) की जाएगी।

पुनर्मूल्यांकन मॉडल

31. आस्ति के रूप में मान्य होने के पश्चात् सम्पत्ति, संयंत्र तथा उपस्कर की किसी मद जिसका उचित मूल्य विश्वसनीय रूप से जा सकता है उसे पुनर्मूल्यांकित राशि पर अग्रणीत किया जाएगा जो मूल्यांकन की तिथि का उचित मूल्य होगा लेकिन उसमें से उत्तरवर्ती संचित मूल्यहास और उत्तरवर्ती संचित क्षतिग्रस्तता हानियां घटायी जाएगी। पुनर्मूल्यांकन को पर्याप्त रूप से नियमित किया जाएगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि रिपोर्टिंग अवधि के अंत में उचित मूल्य द्वारा निर्धारित राशि से अधिक भिन्न न हो।
32. भूमि तथा भवन का उचित मूल्य सामान्यतः व्यावसायिक योग्यता रखने वाले मूल्यांकन कर्त्ताओं द्वारा समीक्षा करके बाजार आधारित साक्ष्यों के आधार पर निर्धारित किया जाता है। संयंत्र तथा उपस्कर का उचित मूल्य सामान्यतः उनका बाजार मूल्य होता है जिसका निर्धारण समीक्षा द्वारा होता है।
33. सम्पत्ति, संयंत्र तथा उपस्कर की किसी मद की विशिष्ट प्रकृति के कारण उचित मूल्य ज्ञात करने के लिए यदि बाजार आधारित साक्ष्य उपलब्ध न हों तथा उसकी बिक्री यदा-कदा ही होती हो, सिवाय जारी व्यवसाय के तौर पर, तो प्रतिष्ठान उसके उचित मूल्य का प्राक्कलन आय अथवा मूल्यहासित प्रतिस्थापन लागत दृष्टिकोण द्वारा कर सकता है।
34. पुनर्मूल्यांकित सम्पत्ति, संयंत्र तथा उपस्कर के उचित मूल्य के पुनर्मूल्यांकन के आवृत्ति उसके उचित मूल्यों में परिवर्तनों पर निर्भर करती है। जब पुनर्मूल्यांकित आस्ति का उचित मूल्य अग्रणीत मूल्य से भिन्न हो तो उसका दोबारा पुनर्मूल्यांकन कराया जाना चाहिए। सम्पत्ति, संयंत्र तथा उपस्कर की कुछ मदों के उचित मूल्य में अस्थिर तथा महत्वपूर्ण बदलाव होते हैं, अतः उनका वार्षिक पुनर्मूल्यांकन कराया जाना आवश्यक है। सम्पत्ति, संयंत्र तथा उपस्कर की ऐसी मदें जिनके उचित मूल्य में मामूली बदलाव होते हैं उनका पुनर्मूल्यांकन इतनी शीघ्रता से कराया जाना आवश्यक नहीं है। बल्कि, ऐसी मदों का तीन या पाँच वर्ष के अंतराल पर पुनर्मूल्यांकन कराया जाना आवश्यक हो सकता है।

35. जब सम्पत्ति, संयंत्र तथा उपस्कर की किसी एक मद का पुनर्मूल्यांकन किया जाता है तो पुनर्मूल्यांकन की तारीख को संचित मूल्यहास को निम्न में से किसी एक प्रकार से लिया जाएगा :

(क) आस्ति की सकल अग्रणीत राशि के परिवर्तन से आनुपातिक रूप से पुनर्कथन निर्धारित किया जाएगा ताकि पुनर्मूल्यांकन के पश्चात् आस्ति की अग्रणीत राशि पुनर्मूल्यांकित राशि के बराबर रहे। इस पद्धति का प्रयोग प्रायः तभी किया जाता है जब एक आस्ति के मूल्यहास प्रतिस्थापन लागत के निर्धारण के लिए आस्ति का पुनर्मूल्यांकन सूचकांक के प्रयोग द्वारा किया जाता है।

(ख) पुनर्मूल्यांकित राशि की सकल अग्रणीत राशि से समाप्त किया जाता है और आस्ति की पुनर्मूल्यांकित राशि का निवल राशि के रूप में पुनर्कथन किया जाता है। प्रायः यह पद्धति भवनों पर लागू होती है।

संचित मूल्यहास के पुनर्कथन या समापन से उत्पन्न समायोजन की राशि अग्रणीत राशि की वृद्धि या कमी का भाग बनती है और इसका लेखा अनुच्छेद 39 व 40 के अनुसार किया जाता है।

36. जब सम्पत्ति, संयंत्र तथा उपस्कर की किसी एक मद का पुनर्मूल्यांकन किया जाता है तो उस सम्पत्ति, संयंत्र तथा उपस्कर की सम्पूर्ण श्रेणी का पुनर्मूल्यांकन किया जाएगा ।

37. सम्पत्ति, संयंत्र तथा उपस्कर की सम्पूर्ण श्रेणी का तात्पर्य समान प्रकृति तथा प्रतिष्ठान द्वारा परिचालन हेतु प्रयोग में लायी जाने वाली आस्तियों के समूह से है। अलग-अलग श्रेणियों के उदाहरण इस प्रकार हैं :

- I. भूमि
- II. भूमि तथा भवन
- III. मशीनरी
- IV. जहाज
- V. वायुयान
- VI. मोटर वाहन
- VII. फर्नीचर तथा फिक्सचर, और
- VIII. कार्यालय उपस्कर

38. आस्तियों का चुनिन्दा पुनर्मूल्यांकन और वित्तीय विवरणों की राशियों जो कि भिन्न-भिन्न तिथियों की लागतों व मूल्यों के मिश्रण की रिपोर्टिंग से बचने के लिए सम्पत्ति, संयंत्र तथा उपस्कर की एक श्रेणी की मदों का पुनर्मूल्यांकन एक-साथ किया जाता है। फिर भी, एक श्रेणी की आस्तियों का पुनर्मूल्यांकन रोलिंग आधार पर किया सकता है बशर्ते, उन आस्तियों का पुनर्मूल्यांकन लघु अवधि में पूरा कर लिया जाए तथा पुनर्मूल्यांकन अद्यतन भी बना रहे ।

39. यदि पुनर्मूल्यांकन के परिणामस्वरूप किसी आस्ति की अग्रणीत राशि में वृद्धि होती है तो ऐसी वृद्धि अन्य व्यापक आय में मान्य होगी तथा ईक्विटी में पुनर्मूल्यांकन अधिशेष शीर्ष में संचित की जाएगी। परन्तु, यह वृद्धि लाभ या हानि में उस सीमा तक ही मान्य होगी जितनी उस आस्ति की पूर्व में मान्य लाभ हानि पुनर्मूल्यांकन कमी को उलटाती हो।
40. यदि पुनर्मूल्यांकन के परिणामस्वरूप किसी आस्ति की अग्रणीत राशि में कमी होती है तो इस कमी को लाभ अथवा हानि में मान्यता दी जाएगी। परन्तु, यह कमी अन्य व्यापक आय में उसी सीमा तक मान्य होगी जितना कि उस आस्ति के लिए पुनर्मूल्यांकन अधिशेष में क्रेडिट शेष हो। अन्य व्यापक आय में मान्य कमी ईक्विटी पुनर्मूल्यांकन अधिशेष शीर्ष में संचित राशि को कम कर देगी।
41. सम्पत्ति, संयंत्र तथा उपस्कर की किसी एक मद के लिए ईक्विटी में सम्मिलित पुनर्मूल्यांकन अधिशेष को आस्ति की अमान्यता पर सीधे प्राप्त आय में अंतरित किया जाएगा। आस्ति का उपयोग समाप्त होने अथवा उसका निपटारा होने पर सम्पूर्ण अधिशेष को अंतरित किया जा सकता है। परन्तु, यदि प्रतिष्ठान द्वारा आस्ति का उपयोग किया जा रहा हो तो अधिशेष का कुछ भाग ही अंतरित किया जाएगा। ऐसे मामले में, अंतरित अधिशेष की राशि आस्ति की पुनर्मूल्यांकित अग्रणीत राशि पर आधारित मूल्यहास तथा मूल लागत पर आधारित मूल्यहास की राशि का अंतर होगी। पुनर्मूल्यांकित अधिशेष से प्राप्त आय में अंतरण लाभ अथवा हानि के माध्यम से नहीं किया जाता है।
42. सम्पत्ति, संयंत्र तथा उपस्कर के पुनर्मूल्यांकन के परिणामस्वरूप, आय पर कर के प्रभाव को, यदि कोई हो, भारतीय लेखा मानक 12 आयकर के अनुसार मान्यता दी जाएगी तथा उसे प्रकट किया जाएगा।

मूल्यहास

43. सम्पत्ति, संयंत्र तथा उपस्कर की मद के प्रत्येक भाग की लागत यदि मद की कुल लागत में महत्वपूर्ण है तो उसका मूल्यहास अलग-से लगाया जाएगा।
44. प्रतिष्ठान द्वारा सम्पत्ति, संयंत्र तथा उपस्कर की एक मद की मान्य प्रारंभिक लागत को उसके महत्वपूर्ण भागों में आवंटित किया जाता है तथा इसके प्रत्येक भाग का अलग-से मूल्यहास लगाया जाता है। उदाहरणतया, एयरक्राफ्ट के इंजन तथा एयरफ्रेम का अलग-अलग मूल्यहास लगाया जाना उचित होगा चाहे, वह स्वाधिकृत हो अथवा वित्तीय पदटे (लीज) पर हो। इसी प्रकार, यदि किसी प्रतिष्ठान द्वारा परिचालन पदटे (लीज) के अंतर्गत संपत्ति अधिगृहीत की गई हो, जिसमें वह पदटाकर्ता हो, उस मद की दर्शायी गई लागत का, जिनकी पदटे (लीज) की शर्तें बाजार की स्थिति के अनुकूल अथवा प्रतिकूल हो सकती हैं, अलग-से मूल्यहास किया जाना उचित होगा।
45. सम्पत्ति, संयंत्र तथा उपस्कर की एक मद के महत्वपूर्ण भाग का एक उपयोगी जीवनकाल तथा मूल्यहास की पद्धति हो सकती है और उसी मद के दूसरे महत्वपूर्ण भाग का जीवनकाल व मूल्यहास पद्धति भी वैसी ही हो सकती है। ऐसे भागों का मूल्यहास प्रभारित करने के लिए उनका समूह बनाया जा सकता है।

46. प्रतिष्ठान सम्पत्ति, संयंत्र तथा उपस्कर की एक मद के कुछ भागों का जहां अलग-से मूल्यहास लगाता है वहीं वह उस मद के शेष भाग का भी अलग से मूल्यहास लगाता है। मद के शेष भागों का व्यक्तिगत तौर पर कोई महत्त्व नहीं होता। यदि प्रतिष्ठान इन भागों के लिए अलग-अलग प्रत्याशा रखता तो शेष भाग का मूल्यहास लगाने के लिए सन्निकटता तकनीकों को अपनाया जा सकता है जो उसके भागों की उपभोग प्रणाली तथा / अथवा उपयोगी जीवनकाल का सही-सही चित्रण हो।
47. प्रतिष्ठान किसी मद के अलग-अलग भागों का अलग-से मूल्यहास लगा सकता है जिनकी लागत उस मद की कुल लागत में महत्वपूर्ण न हो।
48. प्रत्येक अवधि के मूल्यहास को लाभ अथवा हानि में मान्यता दी जाएगी बशर्ते उसे अन्य आस्ति की अग्रणीत राशि में शामिल न किया गया हो।
49. एक अवधि के मूल्यहास को सामान्यतः लाभ अथवा हानि में मान्यता दी जाती है। परंतु कभी-कभी आस्ति में निहित भावी आर्थिक लाभों को अन्य आस्ति की उत्पत्ति में इस्तेमाल कर लिया जाता है। ऐसी स्थिति में मूल्यहास प्रभार अन्य आस्ति की लागत का भाग बन जाता है तथा उसे इसकी अग्रणीत राशि में शामिल कर लिया जाता है। उदाहरणतया, विनिर्माण करने वाले संयंत्र तथा उपस्कर के मूल्यहास को सूचीबद्ध सामान (इंवेन्ट्री) के परिवर्तन की लागत में शामिल करना। (देखें भारतीय लेखा मानक 2) इसी प्रकार, विकास गतिविधियों में शामिल सम्पत्ति, संयंत्र तथा उपस्कर के मूल्यहास को भारतीय लेखा मानक 38 'अमूर्त आस्तियां' के अनुसरण में मान्य अमूर्त आस्ति की लागत में शामिल किया जा सकता है।

मूल्यहास-योग्य राशि तथा मूल्यहास अवधि

50. एक आस्ति की मूल्यहासयोग्य राशि उसके उपयोगी जीवनकाल के दौरान व्यवस्थित ढंग से आवंटित की जाएगी।
51. एक आस्ति के अवशिष्ट मूल्य तथा उपयोगी जीवन को कम-से-कम प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर समीक्षा की जाएगी। यदि आशाएं पूर्व के अनुमानों से भिन्न हों तो परिवर्तन / परिवर्तनों का लेखा उसी प्रकार किया जाएगा जैसे कि भारतीय लेखा मानक 8 *लेखा नीतियाँ, लेखा प्राक्कलनों में परिवर्तन एवं त्रुटियाँ* के अनुसरण में एक प्राक्कलन में परिवर्तन का किया जाता है।
52. मूल्यहास को तब तक मान्यता दी जाती है भले आस्ति का उचित मूल्य उसकी अग्रणीत राशि से भी बढ़ जाए, जब तक आस्ति का अवशिष्ट मूल्य उसकी अग्रणीत राशि से अधिक न हो। आस्ति की मरम्मत व रखरखाव इस बात का सूचक नहीं है कि आस्ति के मूल्यहास की जरूरत नहीं है।
53. एक आस्ति के मूल्यहासयोग्य राशि का निर्धारण उसके अवशिष्ट मूल्य को घटाकर किया जाता है। व्यवहार में चूंकि आस्ति का अवशिष्ट मूल्य प्रायः नाममात्र ही होता है अतः मूल्यहासयोग्य राशि की गणना में उसका कोई महत्त्व नहीं है।

54. एक आस्ति का अवशिष्ट मूल्य बढ़कर अग्रणीत राशि के बराबर अथवा उससे अधिक हो सकता है। यदि ऐसा होता है तो उसका मूल्यहास शून्य होगा। यह तब तक शून्य ही रहेगा जब तक कि अवशिष्ट मूल्य घटकर आस्ति की अग्रणीत की राशि से कम नहीं हो जाता।
55. आस्ति का मूल्यहास तभी शुरू होता है जब वह आस्ति उसके उपयोग के लिए उपलब्ध होती है अर्थात् जब वह उस स्थल तथा स्थिति में हो जब वह प्रबंधन द्वारा वांछित तरीके से परिचालन योग्य हो। भारतीय लेखा मानक 105 के अनुसरण में आस्ति का मूल्यहास उस तिथि से बन्द हो जाता है जिस तिथि को आस्ति बिक्री के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत कर दी जाती है या फिर उस निपटान समूह में शामिल की जाती है जिसे बिक्री के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, या उस तिथि से जब आस्ति अमान्य हो जाती है। अतः जब आस्ति प्रयोग में न हो अथवा उसका सक्रिय उपयोग न किया जा रहा हो तब भी आस्ति के पूर्णतः मूल्यहासित होने तक उसका मूल्यहास लगाया जाना जारी रहता है। फिर भी, मूल्यहास की उपयोग की विधियों के अनुसार जब उत्पादन बन्द हो जाता है तब मूल्यहास शून्य हो सकता है।
56. प्रतिष्ठान को किसी आस्ति में अन्तर्निहित भावी आर्थिक लाभ मुख्य रूप से उसके उपयोग द्वारा प्राप्त होते हैं। परंतु, अन्य कारणों से जैसे कि तकनीकी अथवा वाणिज्यिक रूप से अप्रचलित होने और टूट-फूट के परिणामस्वरूप प्रयोग में न रहने से आस्ति से जो आर्थिक लाभ प्राप्त किए जा सकते थे, वे कम हो जाते हैं। अतः आस्ति के उपयोगी जीवनकाल का निर्धारण करने के लिए निम्नलिखित सभी घटकों पर विचार किया जाता है -
- (क) आस्ति का प्रत्याशित उपयोग। उपयोग का मूल्यांकन आस्ति की प्रत्याशित क्षमता अथवा भौतिक उत्पादन पर निर्भर करता है ;
 - (ख) प्रत्याशित भौतिक टूट-फूट, जोकि उसके परिचालन कारकों पर निर्भर करती है, जैसे कि आस्ति का उपयोग कितनी शिफ्टों के लिए किया जाना है, उसकी मरम्मत तथा रख-रखाव का क्या कार्यक्रम है और जब आस्ति प्रयोग में नहीं है तो उसकी देख-रेख व रखरखाव कैसे होगा ;
 - (ग) उत्पादन में परिवर्तन अथवा सुधार होने अथवा उत्पाद की बाजार की मांग में परिवर्तन होने अथवा आस्ति की उत्पादन सेवा में परिवर्तन होने के परिणामस्वरूप तकनीकी अथवा वाणिज्यिक अप्रयुक्तता ;
 - (घ) आस्ति के प्रयोग की कानूनी अथवा इसी तरह की अन्य सीमाएं, जैसे कि संबंधित पट्टों (लीजों) की तिथियों का समापन।
57. किसी आस्ति का उपयोगी जीवनकाल प्रतिष्ठान द्वारा उसके प्रत्याशित उपयोग के आधार पर परिभाषित किया जाता है। प्रतिष्ठान की आस्ति प्रबंधन नीति में निर्दिष्ट अवधि के बाद अथवा भावी आर्थिक लाभों के निर्दिष्ट अंश तक उपभोग के बाद आस्ति के निपटान का निर्णय लिया जा सकता है। अतः आस्ति का उपयोगी जीवनकाल उसके आर्थिक जीवनकाल से कम हो सकता है। किसी आस्ति के उपयोगी जीवनकाल का निर्धारण प्रतिष्ठान की उसी प्रकार की आस्तियों के प्रयोग के अनुभव के आधार पर किया जा सकता है।

58. भूमि तथा भवन पृथक्योग्य आस्तियां हैं तथा उनका लेखा भी पृथक् रूप से किया जाता है भले उन्हें एक-साथ अधिगृहीत क्यों न किया गया हो । कुछेक अपवादों को छोड़कर जैसे कि उत्खनन तथा वह स्थान जिसका प्रयोग फिलिंग के लिए है, भूमि का असीमित उपयोगी जीवनकाल होता है अतः उसका मूल्यहास नहीं लगाया जाता है। भवनों का उपयोगी जीवनकाल सीमित होता है, अतः वे मूल्यहासयोग्य आस्तियां हैं, जिस भूमि पर भवन बना हो उसके मूल्य में वृद्धि हो तो उस वृद्धि का प्रभाव भवन की मूल्यहास राशि निर्धारित करने पर नहीं पड़ता है।
59. यदि भूमि की लागत में स्थान (साइट) को विखंडित करने, हटाने तथा पूर्व की स्थिति में लाने की लागत भी शामिल हो, तो इन लागतों से अर्जित लाभ की अवधि के दौरान भू-आस्ति के ऐसे भाग का मूल्यहास लगाया जाना चाहिए । कुछ मामलों में भूमि का स्वयं सीमित उपयोगी जीवनकाल हो सकता है। ऐसी स्थिति में, उससे व्युत्पन्न लाभों के आधार पर मूल्यहास प्रभारित किया जाना चाहिए ।

मूल्यहास की विधि

60. किसी आस्ति के मूल्यहास के लिए अपनाई गई विधि द्वारा उस तरीके का पता चलता है कि प्रतिष्ठान भावी आर्थिक लाभों का किस तरह से उपभोग करने की आशा करता है।
61. एक आस्ति पर जो भी मूल्यहास विधि लागू की जाती है उसकी कम-से-कम प्रत्येक वित्त वर्ष की समाप्ति पर समीक्षा की जानी चाहिए । आस्ति में अन्तर्निहित भावी आर्थिक लाभों के प्रत्याशित उपभोग के तरीके में यदि महत्वपूर्ण परिवर्तन हो तो मूल्यहास विधि में परिवर्तन कर देना चाहिए ताकि परिवर्तित तरीका परिलक्षित हो सके । ऐसे परिवर्तन को भारतीय लेखा मानक 8 के अनुसरण में प्राक्कलन में परिवर्तन के तौर पर लेखांकित किया जाएगा ।
62. एक आस्ति के उपयोगी जीवनकाल के दौरान मूल्यहासयोग्य राशि आवंटित करने के लिए विभिन्न प्रकार की मूल्यहास विधियों का प्रयोग किया जा सकता है, जैसे कि सीधी रेखा विधि, घटता शेष विधि तथा उत्पादन इकाई विधि । सीधी रेखा विधि के अंतर्गत यदि आस्ति के अवशिष्ट मूल्य में कोई परिवर्तन न हो तो आस्ति के उपयोगी जीवनकाल पर हमेशा एक-सा प्रभार लगाया जाता है। घटता शेष विधि के अंतर्गत आस्ति के उपयोगी जीवनकाल में प्रभार क्रमशः कम होता जाता है। उत्पादन इकाई विधि के अंतर्गत आस्ति के प्रत्याशित प्रयोग अथवा उत्पादन के आधार पर मूल्यहास लगाया जाता है। प्रतिष्ठान द्वारा ऐसी विधि का चयन किया जाता है जो आस्ति में सन्निहित भावी आर्थिक लाभ के प्रत्याक्षित उपभोग तरीके को परिलक्षित करता है उस विधि को सभी अवधियों के लिए समान रूप से लागू किया जाता है और तब तक जब तक कि प्रत्याक्षित उपभोग के तरीके में कोई परिवर्तन स्पष्ट न हो ।

क्षतिग्रस्तता

63. यह निर्धारित करने के लिए कि सम्पत्ति, संयंत्र तथा उपस्कर की कोई मद क्षतिग्रस्त है, प्रतिष्ठान द्वारा भारतीय लेखा मानक 36 आस्तियों की क्षतिग्रस्तता का अनुसरण किया जाता है। इस मानक

द्वारा स्पष्ट किया गया है कि प्रतिष्ठान द्वारा आस्ति की अग्रणीत राशि की समीक्षा किस प्रकार की जानी चाहिए, आस्ति की वसूली योग्य राशि का निर्धारण किस प्रकार किया जाना चाहिए और क्षतिग्रस्तता हानि को वह कब मान्यता देता है या दी गयी मान्यता को कब वापस लेता है।

64. [देखिये परिशिष्ट 1]

क्षतिग्रस्तता की प्रतिपूर्ति

65. सम्पत्ति, संयंत्र तथा उपस्करों की मदों के क्षतिग्रस्त होने, खोने अथवा छोड़ने से हुए नुकसान की तृतीय पक्ष से प्रतिपूर्ति को तब लाभ अथवा हानि खाते में डाला जाता है जब वह प्रतिपूर्ति प्राप्य हो जाती है।
66. सम्पत्ति, संयंत्र तथा उपस्करों की मदों की क्षतिग्रस्तता या हानियों, तृतीय पक्षों (थर्ड पार्टिज) से दावे या प्रतिपूर्ति का भुगतान उत्तरवर्ती किसी क्रय अथवा निर्माण द्वारा आस्तियों का प्रतिस्थापन पृथक आर्थिक घटनाएं हैं तथा उनका लेखा अलग-से निम्नलिखित रूप से किया जाएगा -
 - (क) सम्पत्ति, संयंत्र तथा उपस्करों की क्षतिग्रस्तता को भारतीय लेखा मानक 36 के अनुसरण में मान्यता दी जाती है।
 - (ख) सम्पत्ति, संयंत्र तथा उपस्करों का उपयोग समाप्त हो जाने अथवा उनका निपटान कर देने पर उन्हे इस भारतीय लेखा मानक के अनुसरण में अमान्य किया जाता है।
 - (ग) सम्पत्ति, संयंत्र तथा उपस्करों की मदों के क्षतिग्रस्त होने, खोने अथवा छोड़ने से हुए नुकसान की तृतीय पक्ष से प्राप्य प्रतिपूर्ति को, जब वह प्राप्य हो, लाभ अथवा हानि खाते में डाला जाता है।
 - (घ) प्रतिस्थापना के रूप में सम्पत्ति, संयंत्र तथा उपस्करों की मदों की पुनर्बहाली, खरीद या निर्माण की लागत का निर्धारण इस मानक के अनुसरण में किया जायेगा।

अमान्यता

67. सम्पत्ति, संयंत्र तथा उपस्करों की किसी एक मद की अग्रणीत राशि की मान्यता निम्नलिखित परिस्थितियों में अमान्य हो जाएगी :
 - (क) निपटान पर, अथवा
 - (ख) जब उसके उपयोग अथवा निपटान से भावी आर्थिक लाभों की प्रत्याक्षा न हो।
68. सम्पत्ति, संयंत्र तथा उपस्करों की किसी मद की मान्यता समाप्त होने से लाभ अथवा हानि को उस समय लाभ अथवा हानि में शामिल किया जाएगा, जब उस मद की मान्यता समाप्त होती है। (जब तक भारतीय लेखा मानक 17 के अनुसार बिक्री और पट्टे पर वापसी (लीज बैक) से अन्यथा कोई अपेक्षा न हो) लाभों को राजस्व के अंतर्गत वर्गीकृत नहीं किया जाएगा।

68. (क) लेकिन, यदि प्रतिष्ठान द्वारा अपने सामान्य क्रियाकलापों के अंतर्गत और नेमी (रूटीन) रूप में, ऐसी सम्पत्ति, संयंत्र तथा उपस्करों की मदों की बिक्री की जाती है जो उसने दूसरों को किराए पर देने के लिए धारित की थीं, अब उन्हें किराए पर न देकर बिक्री के लिए धारित करता है तो ऐसी आस्तियों को अग्रणीत मूल्य पर सूचीबद्ध सामान (इंवेंट्री) में अंतरित करेगा। ऐसी आस्तियों की बिक्री से प्राप्त राशियों को भारतीय लेखा मानक 18 'राजस्व' के अनुसरण में राजस्व के रूप में मान्यता दी जाएगी। जब व्यवसाय के सामान्य क्रियाकलापों के अंतर्गत बिक्री के लिए रखी आस्तियों को सूचीबद्ध सामान (इंवेंट्री) में अंतरित किया जाता है तो इस स्थिति में भारतीय लेखा मानक 105 लागू नहीं होगा।
69. सम्पत्ति, संयंत्र तथा उपस्करों की किसी मद का निपटान विभिन्न तरीकों से किया जा सकता है [उदाहरणतया बिक्री द्वारा, वित्तीय पट्टे (लीज) द्वारा अथवा दान द्वारा]। किसी मद के निपटान की तिथि निर्धारित करने के लिए, प्रतिष्ठान भारतीय लेखा मानक 18 माल की बिक्री से प्राप्त राजस्व की मान्यता के मानदंड को लागू करता है। भारतीय लेखा मानक 17 बिक्री तथा पट्टे पर वापसी (लीज बैक) द्वारा निपटान की स्थिति में लागू होता है।
70. अनुच्छेद 7 में दिये गये मान्यता सिद्धान्त के अंतर्गत यदि एक प्रतिष्ठान संपत्ति, संयंत्र तथा उपस्कर की मद की अग्रणीत राशि में मद के भाग के लिए प्रतिस्थापन की लागत को मान्यता देता है तो यह प्रतिस्थापित भाग की अग्रणीत राशि को अमान्य कर देता है इस बात को ध्यान किए बिना कि प्रतिस्थापित भाग की लागत का अलग से मूल्यहास किया गया था या नहीं। यदि प्रतिष्ठान के लिए प्रतिस्थापित भाग की अग्रणीत राशि को निर्धारित करना व्यवहारिक नहीं है तो यह संकेतक के रूप में उस प्रतिस्थापन की लागत का प्रयोग कर सकता है जो उस समय क्या थी जब इसे अर्जित या निर्मित किया गया था।
71. सम्पत्ति, संयंत्र तथा उपस्कर की मद की गैर-मान्यता से उद्भूत लाभ या हानि को निवल निपटान प्राप्तियों, यदि कोई है, तथा मद की अग्रणीत राशि के बीच अन्तर के रूप में निर्धारित किया जायेगा।
72. सम्पत्ति, संयंत्र तथा मशीनरी की मद के निपटान पर प्राप्य प्रतिफल प्रारंभ में इसके उचित मूल्य पर मान्य होता है। यदि मद का भुगतान अस्थगित होता है तो प्राप्त प्रतिफल प्रारंभ में नकद कीमत पर मान्य होता है। प्रतिफल की नामित राशि तथा समतुल्य नकद के बीच अंतर भारतीय लेखा मानक 18 के अनुसार ब्याज राजस्व के रूप में मान्य होता है जो प्राप्य पर प्रभावी प्राप्ति द्वारा प्रतिबिंबित होता है।

प्रकटन

73. सम्पत्ति, संयंत्र तथा उपस्कर की प्रत्येक श्रेणी के लिए वित्तीय विवरणों में निम्नलिखित को प्रकट किया जाएगा :

(क) सकल अग्रणीत राशि के निर्धारण के लिए प्रयुक्त माप आधार ;

- (ख) प्रयुक्त मूल्यहास पद्धतियां ;
- (ग) उपयोगी जीवन या प्रयुक्त मूल्यहास दरें ;
- (घ) अवधि के आरंभ तथा अंत में सकल अग्रणीत राशि तथा संचित मूल्यहास (संचित क्षतिग्रस्तता हानियों को मिलाकर) और
- (ङ) अवधि के आरंभ तथा अंत में अग्रणीत राशि का मिलान जिस में निम्नलिखित को दर्शाया जाएगा :

- i. अभिवृद्धियां ;
- ii. भारतीय लेखा मानक 105 के अनुसरण में, बिक्री के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत या निपटान समूह में सम्मिलित के रूप में वर्गीकृत आस्तियां और अन्य निपटान ;
- iii. व्यवसायिक संयोजनों के माध्यम से अधिग्रहण ;
- iv. अनुच्छेद 31, 39 व 40 के अंतर्गत पुनर्मूल्यांकनों से और भारतीय लेखा मानक 36 के अनुसार अन्य व्यापक आय में मान्य या उल्टायी गयी क्षतिग्रस्तता हानियों के परिणामस्वरूप वृद्धियां या कमियां ;
- v. भारतीय लेखा मानक 36 के अनुसार लाभ या हानि में मान्य क्षतिग्रस्तता हानियां ;
- vi. भारतीय लेखा मानक 36 के अनुसार लाभ या हानि में उल्टायी गयी क्षतिग्रस्तता हानियां ;
- vii. मूल्यहास ;
- viii. रिपोर्टिंग प्रतिष्ठान के प्रस्तुति मुद्रा में विदेशी परिचालन के रूपांतरण सहित कार्यकारी मुद्रा (फंक्शनल करेंसी) से विभिन्न प्रस्तुति मुद्रा में वित्तीय विवरणों के रूपांतरण से उद्भूत निवल विनिमय अन्तर, और
- ix. अन्य परिवर्तन

74. वित्तीय विवरणों में निम्नलिखित को भी प्रकट किया जाएगा :

- (क) स्वत्व पर प्रतिबंधों का आस्तित्व व राशियां, तथा देयताओं के लिए प्रतिभूति के रूप में गिरवी रखी गई सम्पत्ति, संयंत्र तथा उपस्कर
- (ख) इसके निर्माण की अवधि में सम्पत्ति, संयंत्र तथा उपस्कर की मद की अग्रणीत राशि में मान्य व्ययों की राशि ;
- (ग) सम्पत्ति, संयंत्र तथा उपस्कर के अधिग्रहण के लिए संविदात्मक प्रतिबद्धताओं की राशि, और
- (घ) यदि इसे लाभ एवं हानि विवरणों में अलग से नहीं प्रकट किया जाता है तो सम्पत्ति, संयंत्र तथा उपस्कर की मदों के लिए तृतीय पक्ष से क्षतिपूर्ति की राशि जिसकी क्षति हुई थी या खो गयी थी अथवा छोड़ी गई थी उसे लाभ या हानि में शामिल कर लिया गया है।

75. मूल्यहास पद्धति के चयन तथा आस्तियों के उपयोगी जीवनकाल के अनुमान का निर्णय एक आकलन का विषय है। इसलिए, अपनाई गई पद्धतियों और अनुमानित उपयोगी जीवनकाल या मूल्यहास दरों का प्रकटन वित्तीय विवरण के उपयोगकर्ताओं को सूचना उपलब्ध करवाता है जिससे उन्हें प्रबंधन द्वारा चुनी गई नीतियों की समीक्षा करने और अन्य प्रतिष्ठानों के साथ की जाने वाली तुलनाओं के लिए मदद मिलती है। इसी प्रकार के कारणों के लिए, निम्नलिखित प्रकटन भी आवश्यक है :
- (क) एक अवधि के दौरान मूल्यहास, भले ही इसे लाभ या हानि में या अन्य आस्तियों की लागत के भाग में मान्यता दी गई हो ; और
 - (ख) अवधि के अंत में संचित मूल्यहास ।
76. भारतीय लेखा मानक 8 के अनुसार एक प्रतिष्ठान लेखा प्राक्कलन में उस परिवर्तन की किस्म व प्रभाव को प्रकट करता है जिस का चालू अवधि में या बाद की अवधियों में प्रभाव पड़ने की आशा है। सम्पत्ति, संयंत्र तथा उपस्कर के लिए ऐसे प्रकटन निम्नलिखित से संबंधित प्राक्कलनों में परिवर्तनों से उत्पन्न हो सकते हैं :
- (क) अवशिष्ट मूल्य ;
 - (ख) सम्पत्ति, संयंत्र तथा उपस्करों के विखंडन, हटाने या पुनर्बहाली मदों की अनुमानित लागतें ;
 - (ग) उपयोगी जीवन ; और
 - (घ) मूल्यहास पद्धतियां ।
77. यदि सम्पत्ति, संयंत्र तथा उपस्करों की मदों की पुनर्मूल्यांकित राशियों में वर्णन किया गया है तो निम्नलिखित को प्रकट किया जाएगा :
- (क) पुनर्मूल्यांकन की प्रभावी तारीख ;
 - (ख) क्या किसी स्वतंत्र मूल्यांकनकर्ता को शामिल किया गया था ;
 - (ग) मदों के उचित मूल्यों के अनुमान में प्रयुक्त पद्धतियां एवं महत्त्वपूर्ण परिकल्पनाएं ;
 - (घ) वह सीमा जिस के लिए मदों का उचित मूल्य सक्रिय बाजार में अवलोकनीय कीमतों के संदर्भ में सीधे निर्धारित किया गया था, या हाल ही में बाजार के स्वतंत्र लेन-देनों से निर्धारित किया गया था या फिर अन्य मूल्यांकन तकनीकों का प्रयोग करते हुए अनुमानित किया गया था ;
 - (ङ) सम्पत्ति, संयंत्र तथा उपस्कर की प्रत्येक पुनर्मूल्यांकित श्रेणी के लिए, मान्य की जाने वाली अग्रणीत राशि यदि आस्तियों को लागत मॉडल के अंतर्गत लिया जाता ; और
 - (च) पुनर्मूल्यांकन अधिशेष जिसमें अवधि के लिए परिवर्तन एवं शेषरधारकों को शेष के संवितरण पर किन्हीं प्रतिबंधों का संकेत है।
78. भारतीय लेखा मानक 36 के अनुसार, एक प्रतिष्ठान अनुच्छेद 73 (ङ) (IV) - (VI) द्वारा अपेक्षित सूचना के अलावा सम्पत्ति, संयंत्र व उपस्करों की क्षतिग्रस्तता की सूचना को भी प्रकट करेगा ।

79. वित्तीय विवरणों के प्रयोगकर्ताओं को निम्नलिखित सूचना भी उनकी आवश्यकताओं के लिए प्रासंगिक हो सकती है :

- (क) अस्थायी रूप से बेकार पड़ी सम्पत्ति, संयंत्र तथा उपस्करों की अग्रणीत राशि ;
- (ख) किसी पूर्णतया मूल्यहासित सम्पत्ति, संयंत्र तथा उपस्करों की, जो अभी भी प्रयोग में है ; सकल अग्रणीत राशि ;
- (ग) सक्रिय प्रयोग से निवृत्त तथा भारतीय लेखा मानक 105 के अनुसार बिक्री के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत न की गयी सम्पत्ति, संयंत्र तथा उपस्करों की अग्रणीत राशि ; और
- (घ) जब लागत मॉडल प्रयोग किया है, सम्पत्ति, संयंत्र तथा उपस्करों का उचित मूल्य जब यह अग्रणीत राशि से बहुत अधिक भिन्न है।

अतः, प्रतिष्ठानों को इन राशियों को प्रकट करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

परिशिष्ट 'क' :

मौजूदा विस्थापन, पुनर्बहाली और इसी प्रकार की अन्य देयताओं में परिवर्तन

यह परिशिष्ट भारतीय लेखा मानक 16 का अभिन्न अंग है।

पृष्ठभूमि

1. बहुत-से प्रतिष्ठानों पर सम्पत्ति, संयंत्र तथा उपस्करों की मदों को विखंडित करने, हटाने तथा पुनर्बहाली का दायित्व होता है। इस परिशिष्ट में, ऐसे दायित्वों को विस्थापन, पुनर्बहाली तथा इसी प्रकार की देयताओं के रूप में उल्लिखित किया गया है। भारतीय लेखा मानक 16 के अंतर्गत सम्पत्ति, संयंत्र तथा उपस्करों की मदों की लागतों में मद के विखंडन एवं हटाने और जिस स्थान पर मद स्थित है उसकी पुनर्बहाली की लागतों का आंशिक प्राक्कलन (अनुमान) शामिल होता है, इसके लिए, प्रतिष्ठान अपने ऊपर बाध्यता लेता है, जब मद को अर्जित करता है या सूचीबद्ध सामान (इंवेंट्री) को उत्पन्न करने से भिन्न प्रयोजनों के लिए उस अवधि में मद के प्रयोग परिणामस्वरूप ऐसा होता है। भारतीय लेखा मानक 37 में ये अपेक्षाएं हैं कि विस्थापन, पुनर्बहाली तथा इसी प्रकार की देयताओं का किस प्रकार से माप किया जाए। इस परिशिष्ट में इस मार्गदर्शन की व्यवस्था है कि मौजूदा विस्थापन, पुनर्बहाली और इसी प्रकार की देयताओं के माप में परिवर्तनों के प्रभाव का लेखा किस प्रकार किया जाए।

कार्यक्षेत्र

2. यह परिशिष्ट एक मौजूदा विस्थापन, पुनर्बहाली और इसी प्रकार की देयताओं के माप में परिवर्तनों पर लागू होता है जिसमें ये दोनों सम्मिलित हैं -

- (क) भारतीय लेखा मानक 16 के अनुसार सम्पत्ति, संयंत्र तथा उपस्कर की मद की लागत के भाग के रूप में मान्य ; और
- (ख) भारतीय लेखा मानक 37 के अनुसार, देयता के रूप में मान्य।

उदाहरण के लिए, विस्थापन, पुनर्बहाली या इसी प्रकार की देयता संयंत्र के विस्थापन, खननीय उद्योगों में पर्यावरणीय क्षति की पुनर्बहाली या उपस्कर को हटाने के रूप में हो सकती है।

मुद्दा

3. इस परिशिष्ट से पता चलता है कि निम्नलिखित घटनाओं का मौजूदा विस्थापन, पुनर्बहाली या इसी प्रकार की देयता के माप पर क्या परिवर्तन होता है और इस का किस प्रकार से लेखा किया जाए :
 - (क) आर्थिक लाभों से संपन्न संसाधनों के अनुमानित वहिर्प्रवाह (जैसे कि नकदी प्रवाह) में परिवर्तन जो दायित्व के निर्वाह के लिए अपेक्षित है।
 - (ख) भारतीय लेखा मानक 37 के अनुच्छेद 47 में यथा परिभाषित चालू बाजार-आधारित बट्टा-दर में परिवर्तन (जिसमें धन के समय मूल्य और देयता विशेष के जोखिम में परिवर्तन शामिल हैं) और
 - (ग) वृद्धि जिससे समय व्यतीत होने का बोध होता है (और इसे बट्टे की वापसी भी कहा जाता है)।

लेखा सिद्धान्त

4. मौजूदा विस्थापन, पुनर्बहाली और इसी प्रकार की देयता के माप में परिवर्तन, जो अनुमान समय या दायित्वों के निर्वहन के लिए अपेक्षित आर्थिक लाभों से संपन्न संसाधनों के वहिर्प्रवाह की मात्रा में परिवर्तनों के परिणामस्वरूप होते हैं, या बट्टा-दर में परिवर्तन को नीचे दिए गए अनुच्छेद 5-7 के अनुसार लेखांकित किया जाएगा।
5. यदि संबंधित आस्ति का माप लागत मॉडल का प्रयोग करते हुए किया गया है :
 - (क) नीचे (ख) के अंतर्गत, देयता में परिवर्तनों को चालू अवधि में संबंधित आस्ति की लागत में या तो जोड़ा जाएगा या फिन् उससे घटाया जाएगा।
 - (ख) आस्ति की लागत से घटायी गयी राशि इसकी अग्रणीत राशि से अधिक नहीं होगी। यदि देयता में कमी आस्ति की अग्रणीत राशि से अधिक होती है तो आधिक्य को लाभ या हानि में तत्काल मान्यता दी जाएगी।
 - (ग) यदि समायोजन से आस्ति की लागत में वृद्धि होती है, तो प्रतिष्ठान इस बात पर विचार करेगा कि क्या यह एक ऐसा संकेत है कि आस्ति की अग्रणीत नई राशि की पूरी तरह से वसूली नहीं हो सकती है। यदि यह ऐसा ही संकेत है तो प्रतिष्ठान इसकी वसूली योग्य राशि का अनुमान लगाते हुए क्षतिग्रस्तता के लिए आस्ति की जांच करेगा और भारतीय लेखा मानक 36 के अनुसरण में किसी भी क्षतिग्रस्तता हानि का लेखा करेगा।
6. यदि संबंधित आस्ति का माप पुनर्मूल्यांकन मॉडल का प्रयोग करते हुए किया जाता है : -
 - (क) देयता में परिवर्तन, उस आस्ति पर पहले मान्य पुनर्मूल्यांकन अधिशेष या घाटे में निम्नलिखित के रूप में बदलाव कर सकते हैं, अर्थात् -
 - (i) देयता में कमी [नीचे (ख) के अंतर्गत] अन्य व्यापक आय में मान्य होगी और 'ईक्विटी' के अन्दर पुनर्मूल्यांकन अधिशेष में वृद्धि करेगी सिवाय इसके कि यह उस सीमा तक लाभ या हानि में मान्य होगी कि यह आस्ति पर पुनर्मूल्यांकन घाटे को उलटाता है जो पहले लाभ या हानि में मान्य था ;

- (ii) देयता में वृद्धि लाभ या हानि में मान्य होगी सिवाय इसके कि यह अन्य व्यापक आय में मान्य होगी और उस आस्ति के संबंध में पुनर्मूल्यांकन अधिशेष में मौजूद किसी क्रेडिट शेष की सीमा तक ईक्विटी के अन्दर पुनर्मूल्यांकन अधिशेष को कम करेगी।
- (ख) यदि आस्ति को लागत मॉडल पर अग्रणीत किया जाता है और देयता में कमी अग्रणीत राशि से बढ़ जाती है तो उस आधिक्य को लाभ या हानि में तत्काल मान्यता दी जाएगी।
- (ग) देयता में परिवर्तन इस बात का संकेत देता है कि आस्ति को पुनर्मूल्यांकित किया जाए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि अग्रणीत राशि उस राशि में ज्यादा भिन्न न हो जाए जो रिपोर्टिंग अवधि के अंत में उचित मूल्य का प्रयोग करते हुए निर्धारित की गयी थी। इस प्रकार का कोई पुनर्मूल्यांकन (क) के अंतर्गत लाभ या हानि या अन्य व्यापक आय में मान्य राशियों को निर्धारित करने में हिसाब में लिया जाएगा। यदि पुनर्मूल्यांकन आवश्यक है तो उस श्रेणी की सभी आस्तियों को पुनर्मूल्यांकित किया जाएगा।
- (घ) भारतीय लेखा मानक 1 की अपेक्षा है कि अन्य व्यापक आय या व्यय के प्रत्येक घटक का लाभ या हानि के विवरण में प्रकटन किया जाए। इस अपेक्षा का पालन करने में, देयता में परिवर्तन से उद्भूत पुनर्मूल्यांकन अधिशेष में परिवर्तन की अलग से पहचान की जाएगी और उसका प्रकटन किया जाएगा।
7. आस्ति की समायोजित मूल्यहास योग्य राशि का हास इसके उपयोगी जीवन में होता है। इसलिए, जब एक बार संबंधित आस्ति अपने उपयोगी जीवन के अंत तक पहुँच जाती है, देयता में सभी उत्तरवर्ती परिवर्तन वैसे ही लाभ या हानि में मान्य होंगे जैसे-जैसे वे घटित होते हैं। यह लागत मॉडल तथा पुनर्मूल्यांकन मॉडल दोनों के अंतर्गत ही लागू होता है।
8. बट्टे की आवधिक वापसी (अनवाइडिंग) जैसे-जैसे घटित होती है वित्त लागत के रूप में लाभ या हानि में मान्य होगी। भारतीय लेखा मानक 23 के अंतर्गत पूंजीकरण की अनुमति नहीं है।

मौजूदा विस्थापन, पुनर्बहाली एवं इसी प्रकार की देयताओं में परिवर्तनों के दृउदा उदाहरण

[ये दृष्टांत उदाहरण (दृउदा) परिशिष्ट 'क' के साथ संलग्न हैं, परन्तु ये इसके अंग नहीं हैं]

सामान्य तथ्य

- दृउदा 1. प्रतिष्ठान के पास एक आणविक शक्ति संयंत्र है और इसमें संबंधित विस्थापन की देयता है। आणविक शक्ति संयंत्र का परिचालन 1 जनवरी, 2000 को प्रारम्भ हुआ था। इस संयंत्र का 40 वर्ष का उपयोगी जीवन है। इसकी प्रारंभिक लागत 1,20,000 रुपये थी जिसमें 10,000 रुपये की विस्थापन संबंधी लागतों की राशि सम्मिलित है। यह 40 वर्षों में अनुमानित नकदी प्रवाहों की 70,400 रुपये की राशि प्रस्तुत करती है जो कि 5 प्रतिशत की जोखिम-समायोजित दर पर भुनाई गई है। प्रतिष्ठान का वित्तीय वर्ष 31 दिसम्बर को समाप्त होता है।

उदाहरण 1: लागत मॉडल

- दृउदा 2. 31 दिसम्बर 2009 को यह संयंत्र 10 वर्ष पुराना है। इसका संचित मूल्यहास 30,000 रुपये है (यानि रु. $1,20,000 \times 10/40$ वर्ष) चूंकि 10 वर्षों में वापसी बढ़ा दर (5 प्रतिशत) विस्थापन देयता 10,000 रुपये से बढ़कर 16,300 रुपये हो गई है।

- दृउदा 3. 31 दिसम्बर 2009 को बट्टा दर में परिवर्तन नहीं हुआ है तथापि, प्रतिष्ठान यह अनुमान लगाता है कि तकनीकी प्रगति के परिणामस्वरूप, विस्थापन देयता का निवल वर्तमान मूल्य 8,000 रुपये कम हो जाएगा। तदनुसार, प्रतिष्ठान विस्थापन देयता 16,300 रुपये से 8,300 रुपये का समायोजित करता है। उस तिथि को प्रतिष्ठान परिवर्तनों को प्रतिबिंबित करने के लिए निम्नलिखित जर्नल प्रविष्टि करता है -

	रुपये	रुपये
नामे (विस्थापन) देयता	8000	
जमा आस्ति की लागत		8000

- दृउदा 4. इस समायोजन के बाद आस्ति की अग्रणीत राशि 82,000 रुपये (रु. 1,20,000 - रु. 8,000 - रु. 30,000) है जो कि अगले वर्ष के लिए रुपये 2733 (यानि 82,000 रु. ÷ 30) मूल्यह्रास खर्च देते हुए आस्ति के जीवनकाल के शेष 30 वर्ष में मूल्यह्रासित की जाएगी। बट्टा की वापसी के संबंध में अगले वर्ष की वित्तीय लागत 415 रुपये (यानि रु. 8,300 x 5 प्रतिशत) होगी।

- दृउदा 5. यदि देयता में परिवर्तन, अनुमानित नकदी प्रवाहों में परिवर्तन के बजाय बट्टा दर में परिवर्तन के कारण हुआ है तो परिवर्तन के लिए लेखांकन वही रहेगा परन्तु अगले वर्ष की वित्तीय लागत में नयी बट्टा दर परिलक्षित होगी।

उदाहरण 2: पुनर्मूल्यांकन मॉडल

- दृउदा 6. प्रतिष्ठान भारतीय लेखा मानक 16 में पुनर्मूल्यांकन मॉडल को अपनाता है जिससे संयंत्र पर्याप्त नियमितता के साथ इस तरह से पुनर्मूल्यांकित होता है कि आस्ति की अग्रणीत राशि में उचित मूल्य से बहुत अधिक परिवर्तन नहीं होता। प्रतिष्ठान की नीति है कि पुनर्मूल्यांकन की तिथि को संचित मूल्यह्रास को आस्ति की सकल अग्रणीत राशि द्वारा समायोजित कर दिया जाए।

- दृउदा 7. जब विस्थापन देयता से संबद्ध पुनर्मूल्यांकित आस्तियों का लेखा किया जाता है तो यह आवश्यक है कि प्राप्त किये गये मूल्यांकन के आधार को समझा जाये। उदाहरण के लिए :

(क) यदि किसी आस्ति का मूल्यांकन बट्टागत प्राप्त नकदी प्रवाह के आधार पर किया जाता है तो कुछ मूल्यांकनकर्ता विस्थापन लागतों (एक सकल मूल्यांकन) की कटौती किये बिना आस्ति का मूल्यांकन कर सकते हैं जबकि अन्य मूल्यांकनकर्ता विस्थापन लागतों (एक निवल मूल्यांकन) की कटौती के पश्चात् आस्ति का मूल्यांकन कर सकते हैं, क्योंकि आस्ति का अधिग्रहणकर्ता प्रतिष्ठान आमतौर पर विस्थापन दायित्व को भी परिकल्पित करता है। वित्तीय रिपोर्टिंग के प्रयोजनों के लिए विस्थापन दायित्व को एक अलग देयता के रूप में मान्यता दी जाती है और उसकी कटौती आस्ति से नहीं की जाती। तदनुसार, यदि आस्ति का मूल्यांकन निवल आधार पर किया जाता है तो यह आवश्यक है कि विस्थापन देयता को वापस जोड़ते हुए प्राप्त किये मूल्यांकन को समायोजित किया जाए ताकि देयता की गणना दोबारा से न हो।²

(ख) यदि किसी आस्ति का मूल्यांकन मूल्यह्रासित प्रतिस्थापन लागत के आधार पर किया जाता है तो प्राप्त किये गये मूल्यांकन में वह राशि सम्मिलित नहीं की जाएगी जो आस्ति के विस्थापन के अवयव के रूप में है। यदि यह राशि सम्मिलित नहीं की जाती तो एक उपयुक्त राशि को मूल्यांकन में सम्मिलित किये जाने की आवश्यकता होगी ताकि उस अवयव के मूल्यह्रासित प्रतिस्थापन लागत को प्रतिबिंबित किया जा सके।

दृउदा 8. मान लो कि 31 दिसम्बर, 2002 को एक बाजार आधारित बट्टागत नकदी प्रवाह के रूप में 1,15,000 रुपये मूल्यांकन प्राप्त किया जाता है उसमें विस्थापन लागतों के लिए 11,600 रुपये का भत्ता भी सम्मिलित है जो कि 3 साल की बट्टा वापसी दिये जाने के पश्चात् मूल प्राक्कलन में किसी परिवर्तन को प्रतिनिधित्व नहीं करता। अतः 31 दिसम्बर 2002 की स्थिति अनुसार तुलन-पत्र में सम्मिलित की गई राशियां इस प्रकार होंगी।

² इस सिद्धान्त के उदाहरणों के लिए, देखें भारतीय लेखा मानक (इंड ए एस) 36 आस्तियों की क्षतिग्रस्तता

	रुपये
मूल्यांकन पर आस्ति (1)	1,26,600
संचित मूल्यह्रास	शून्य
विस्थापन देयता	(11,600) ²
निवल आस्तियां	1,15,000
प्रतिधारित आय (2)	(10,600)
पुनर्मूल्यांकन अधिक्य (3)	15,600

टिप्पणियां :

- (1) प्राप्त मूल्यांकन 1,15,000 रुपये जमा (+) विस्थापन लागतें 11,600 रुपये जिसकी मूल्यांकन के लिए अनुमति दी गई है परन्तु उसे एक पृथक देयता के रूप में मान्यता दी गयी है = 1,26,600 रुपये
- (2) मूल लागत रुपये 1,20,000 x 3/40 पर 3 वर्ष का मूल्यह्रास = रुपये 9,000 जमा (+) 5 प्रतिशत की मिश्रित दर से 10,000 रुपये पर संचित बट्टा = रुपये 1,600 कुल रुपये = 10,600
- (3) पुनर्मूल्यांकित राशि रुपये 1,26,600 में से घटाइए (-) पूर्ववर्ती 1,11,000 रुपये का निवल पुस्तक मूल्य (लागत 1,20,000 रुपये में से 9,000 रुपये का संचित मूल्यह्रास घटाने के बाद)

दृउदा 9. अतः 2003 का मूल्यह्रास खर्च रुपये 3420 (रुपये 1,26,600 x 1/37) है। 2003 का बट्टा खर्च रुपये 600 (11,600 का 5 प्रतिशत) है। 31 दिसम्बर 03 की स्थिति के अनुसार, विस्थापन देयता (किसी समायोजन पूर्व) 12,200 रुपये है। बट्टा दर में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। तथापि, उस तिथि को, प्रतिष्ठान यह अनुमान लगाता है कि तकनीकी प्रगति के परिणामस्वरूप, विस्थापन देयता का वर्तमान मूल्य 5,000 कम हो गया है। तदनुसार, प्रतिष्ठान की समायोजित विस्थापन देयता रुपये 12,200 से रुपये 7,200 है।

दृउदा 10. इस सम्पूर्ण समायोजन को पुनर्मूल्यांकन अधिशेष में ले जाएगा क्योंकि यदि आस्ति को लागत मॉडल पर ले जाया जाता तो यह मान्य अग्रणीत राशि से अधिक नहीं होती है यदि ऐसा होता तो आधिक्य को अनुच्छेद 6 (ख) के अनुसार लाभ अथवा हानि में ले जाया गया होता। प्रतिष्ठान परिवर्तन को प्रतिबिंबित करने के लिए जर्नल में निम्नलिखित प्रविष्टि करता है -

	रुपये	रुपये
नामे विस्थापन देयता	5,000	
जमा पुनर्मूल्यांकन आधिक्य		5,000

दृउदा 11. प्रतिष्ठान यह निर्णय लेता है कि 31 दिसम्बर 2003 को आस्ति के पूर्ण मूल्यांकन की आवश्यकता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ले जायी जाने वाली राशि में अंकित मूल्य से अधिक फेर-बदल न हो। कल्पना करें कि आस्ति का अब मूल्य रुपये 1,07,000 पर किया गया है जो कि घटाये गये विस्थापन दायित्व के लिए 7,200 रुपये की निवल छूट है जिसे एक पृथक देयता के रूप में मान्यता दी जाये। अतः वित्तीय रिपोर्टिंग के प्रयोजनों के लिए आस्ति का मूल्यांकन छूट घटाने से पूर्व, रुपये 14,200 है। इसके लिए निम्नलिखित अतिरिक्त जर्नल प्रविष्टि की जाएगी :

	रुपये	रुपये
नामे संचित मूल्यहास (1)	3420	
जमा पुनर्मूल्यांकन पर आस्ति		3420
नामे पुनर्मूल्यांकन आधिक्य (2)	8980	
जमा पुनर्मूल्यांकन पर आस्ति (3)		8980

टिप्पणियां :

- (1) प्रतिष्ठान की लेखा नीति के अनुसार रुपये 3420 का संचित मूल्यहास समाप्त करना।
- (2) नामे पुनर्मूल्यांकन आधिक्य के लिए है क्योंकि पुनर्मूल्यांकन पर आयी कमी आस्ति के संबंध में पुनर्मूल्यांकन आधिक्य में मौजूदा जमा (क्रेडिट) शेष से अधिक न हो।
- (3) पूर्व मूल्यांकन (विस्थापन लागतों के लिए छूट से पूर्व) रुपये 1,26,600, घटाये (-) संचित मूल्यहास रुपये 3420, घटाये नव मूल्यांकन (विस्थापन लागतों के लिए छूट से पूर्व) रुपये 1,14,200.

दृउदा 12. इस मूल्यांकन का पालन करने के बाद, तुलन-पत्र में सम्मिलित की गई राशियां इस प्रकार हैं :

	रुपये
पुनर्मूल्यांकन पर आस्ति	1,14,200
संचित मूल्यहास	शून्य
विस्थापन देयता	(7,200)
निवल आस्तियां	<u>1,07,000</u>
प्रतिधारित आय (1)	(14,620)
पुनर्मूल्यांकन आधिक्य (2)	11,620

टिप्पणियां :

- (1) 31 दिसम्बर 2002 को रुपये 10,600 जमा (+) 2003 का रुपये 3420 का मूल्यहास खर्च और रुपये 600 का बटटा खर्च = रुपये 14,620
- (2) 31 दिसम्बर 2002 की स्थिति अनुसार रुपये 15,600 जमा (+) रुपये 5000, जोकि देयता में आई कमी के फलस्वरूप हैं, घटाइये (-) पुनर्मूल्यांकन पर कमी रुपये 8980 = रुपये 11620

परिशिष्ट 'ख' :**अन्य भारतीय लेखा मानकों में समाविष्ट मामलों के संदर्भ**

यह परिशिष्ट भारतीय लेखा मानक 16 का अभिन्न अंग है।

इस परिशिष्ट में उन परिशिष्टों को सूचीबद्ध किया गया है जो अन्य भारतीय लेखा मानकों के अंग हैं तथा भारतीय लेखा मानक (इंड ए एस) 16, सम्पत्ति संयंत्र व उपस्कर के लिए भी संदर्भ का कार्य करते हैं।

- 1 परिशिष्ट 'क' आयकर — भारतीय लेखा मानक 12 में समाविष्ट पुनर्मूल्यांकित गैर मूल्यहास योग्य आस्तियों की वसूली ।
- 2 परिशिष्ट 'क' सेवा रियायत व्यवस्थाएं भारतीय लेखा मानक 11, निर्माण संविदाएं में समाविष्ट।
- 3 परिशिष्ट 'ख' सेवा रियायत व्यवस्थाएं : प्रकटन भारतीय लेखा मानक 11 निर्माण संविदाएं में समाविष्ट ।
- 4 परिशिष्ट 'ग' यह निर्धारित करना कि की गयी व्यवस्था में कोई पट्टा है, — भारतीय लेखा मानक 17 पट्टे में समाविष्ट ।
- 5 परिशिष्ट 'क' अमूर्त आस्तियां — वेबसाईट लागतें — भारतीय लेखा मानक 38 अमूर्त आस्तियां में समाविष्ट ।
- 6 परिशिष्ट 'ग' ग्राहकों से हस्तांतरित आस्तियां — भारतीय लेखा मानक 18 राजस्व में समाविष्ट ।

परिशिष्ट 1

टिप्पणी - यह परिशिष्ट भारतीय लेखा मानक का अंग नहीं है। इस परिशिष्ट का प्रयोजन मात्र भारतीय लेखा मानक (इंड ए एस) 16 तथा तदनुरूपी अन्तरराष्ट्रीय लेखा मानक (आई ए एस) 16 सम्पत्ति, संयंत्र व उपस्कर और 'आई एफ आर आई सी' 1, 'मौजूदा विस्थापन, पुनर्बहाली तथा ऐसी देयताओं में परिवर्तन' के बीच, यदि कोई अन्तर हों, तो उन्हें स्पष्ट करना है।

अन्तरराष्ट्रीय लेखा मानक (आई ए एस) 16 सम्पत्ति, संयंत्र व उपस्कर और 'आई एफ आर आई सी' 1, मौजूदा विस्थापन, पुनर्बहाली एवं इसी प्रकार की देयताएं के साथ तुलना

1. अन्तरराष्ट्रीय लेखा मानक (आई ए एस) 16 एवं 'आई एफ आर आई सी' 1 में दिये गये संक्रमणकालीन प्रावधान भारतीय लेखा मानक (इंड ए एस) 16 में नहीं दिये गये हैं, क्योंकि भारतीय लेखा मानकों के सभी संक्रमणकालीन प्रावधान, जहां उचित समझा गया है, 'आई एफ आर आई सी' 1 अन्तरराष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग मानकों का प्रथमवार अंगीकरण के तदनुरूपी भारतीय लेखा मानक 101 'भारतीय लेखा मानकों का प्रथमवार अंगीकरण' में सम्मिलित कर लिये गये हैं।
2. इस मानक में भिन्न शब्दावली का प्रयोग किया गया है, उदाहरणतया शब्दों 'वित्तीय स्थिति का विवरण' के स्थान पर शब्द 'तुलन-पत्र' और शब्दों 'व्यापक आय का विवरण' के स्थान पर शब्द 'लाभ-हानि विवरण' का प्रयोग किया गया है।
3. अनुच्छेद 28 को हटा दिया गया है क्योंकि भारतीय लेखा मानक 20 'सरकारी अनुदान एवं सरकारी सहायता का प्रकटन' सम्पत्ति, संयंत्र व उपस्कर की किसी मद की अग्रणीत राशि को उस सीमा तक कम करने के विकल्प की अनुमति नहीं देता, जितना उस मद के संबंध में सरकारी अनुदान प्राप्त हुआ है जबकि अन्तरराष्ट्रीय लेखा मानक 20 इसकी अनुमति देता है। लेकिन, अन्तरराष्ट्रीय लेखा मानक 16 के साथ क्रमबद्धता रखने के लिए भारतीय लेखा मानक 16 में इन अनुच्छेद को जारी रखा गया है।
4. अन्तरराष्ट्रीय लेखा मानक 16 में अनुच्छेद संख्या 64 'हटाया गया' के रूप में उल्लिखित है। लेकिन अन्तरराष्ट्रीय लेखा मानक 16 के साथ क्रमबद्धता रखने के लिए इस अनुच्छेद संख्या को भारतीय लेखा मानक 16 में जारी रखा गया है।
5. चूंकि, भारतीय लेखा मानक (इंड ए एस) 40 निवेश सम्पत्ति उचित मूल्य के प्रयोग के लिए प्रतिषिद्ध करता है अतः भारतीय लेखा मानक 16 का अनुच्छेद 5 और भारतीय लेखा मानक 16 के परिशिष्ट 'क' का दृष्टांत उदाहरण 7 संशोधित कर दिया गया है।

भारतीय लेखा मानक (इंड ए एस) 29

उच्च मुद्रास्फीतिशील अर्थव्यवस्थाओं में वित्तीय रिपोर्टिंग

(इस प्रस्तुत भारतीय लेखा मानक में मोटे टाइप एवं सामान्य टाइप में अनुच्छेद दिए गए हैं, इन दोनों तरह के अनुच्छेदों का प्राधिकार समान है। मोटे टाइप में दिये गये अनुच्छेद मुख्य सिद्धांतों के सूचक हैं)

कार्यक्षेत्र

1. प्रस्तुत मानक एक प्रतिष्ठान के समेकित विवरणों सहित उन वित्तीय विवरणों पर लागू किया जाएगा जिसकी कार्यात्मक मुद्रा उच्च मुद्रास्फीतिशील अर्थव्यवस्था की मुद्रा है।
2. एक उच्च मुद्रास्फीतिशील अर्थव्यवस्था में, बिना पुनर्कथन के स्थानीय मुद्रा में परिचालन परिणामों और वित्तीय स्थिति की रिपोर्टिंग लाभदायक नहीं है। धन एक ऐसी दर पर अपनी क्रय शक्ति इस हद तक खो देता है कि अलग अलग समय में हुए लेनदेनों और घटित घटनाओं और यहां तक कि एक ही लेखा अवधि में राशियों की तुलना भ्रामक हो जाती है।
3. यह मानक एक ऐसी समग्र दर निर्धारित नहीं करता जिससे यह पता चले कि यह दर उच्च मुद्रास्फीति उत्पन्न करती है। यह केवल विवेक पर ही निर्भर करता है कि इस लेखा मानक के अनुसरण में वित्तीय विवरणों का पुनर्कथन कब आवश्यक हो। उच्च मुद्रास्फीति की स्थिति के संकेत एक देश के आर्थिक परिवेश की विशेषताओं से इंगित हो जाते हैं जिनमें निम्नलिखित तो सम्मिलित हो सकते हैं लेकिन ये इन्हीं तक सीमित नहीं हैं :-
 - क) साधारण जनता अपने धन को गैर मौद्रिक आस्तियों अथवा किसी अपेक्षया अधिक मजबूत विदेशी मुद्रा में रखना पसंद करती है। धारित स्थानीय मुद्रा की राशियों को तत्काल निवेशित कर दिया जाता है ताकि उनकी क्रय शक्ति बनी रहे ;
 - ख) साधारण जनता राशियों को स्थानीय मुद्रा में न रखकर अपेक्षया अधिक मजबूत विदेशी मुद्रा में रखना पसंद करती है। मूल्यों को भी उसी मुद्रा में बताया जाता है ;
 - ग) उधार पर बिक्री और खरीद की कीमतों को इस प्रकार से रखा जाता है कि उधार की अवधि के बीच क्रय शक्ति की संभावित हानि की क्षतिपूर्ति हो जाए भले वह अवधि कम क्यों न हो ;
 - घ) ब्याज दरें, वेतन और कीमतें सूचकांक से संबद्ध रहती हैं ; तथा
 - ड.) तीन वर्षों के दौरान, संचित मुद्रा स्फीति की दर 100 प्रतिशत के आसपास हो जाती है या फिर इससे भी अधिक हो जाती है।

4. यह अधिक उचित होगा कि सभी प्रतिष्ठान, जोकि उच्च मुद्रास्फीतिशील अर्थव्यवस्था की ही मुद्रा में रिपोर्ट करते हैं, इस मानक को उसी तिथि से लागू करें। फिर भी, यह मानक किसी प्रतिष्ठान की रिपोर्टिंग अवधि के आरंभ से ही लागू हो जायेगा, जिस अवधि में वह उस देश में उच्च मुद्रास्फीतिशील की विद्यमानता की पहचान करता है जिस देश की मुद्रा में वह रिपोर्ट करता है।

वित्तीय विवरणों का पुनर्कथन

5. समय-समय पर विभिन्न प्रकार के सामान्य या विशेष राजनैतिक, आर्थिक अथवा सामाजिक दबावों से मूल्यों में परिवर्तन होते रहते हैं। विशेष दबावों में, जैसे कि, मांग एवं पूर्ति तथा प्रौद्योगिकीकरण के परिवर्तनों से वस्तु विशेष की कीमतों में वृद्धि या कमी होती है जो काफी अधिक और एक-दूसरे से स्वतंत्र रूप से हो सकती है जबकि सामान्य दबावों में मूल्यों में सामान्य परिवर्तन हो सकता है और इससे रुपये की सामान्य क्रय शक्ति भी प्रभावित होती है।
6. प्रतिष्ठान, जोकि अपने वित्तीय विवरण लेखे की ऐतिहासिक लागत के आधार पर तैयार करते हैं वे ऐसा मूल्यों के सामान्य स्तर में परिवर्तन अथवा मान्य आस्तियों या देयताओं के विशेष मूल्य की वृद्धि पर ध्यान नहीं देते हैं। इसका अपवाद, केवल वही आस्तियां व देयताएं हैं जिन्हें प्रतिष्ठान के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि वह उनके मूल्यों का अंकन उचित मूल्यों के आधार पर करे या ऐसा करने के लिए वह स्वयं चयन करता है। उदाहरणतया, संयंत्र और उपकरणों का पुनर्मूल्यांकन उचित मूल्यों के आधार पर किया जा सकता है जबकि अन्य जैविक आस्तियों के मूल्यों का आंकलन सामान्यतया उचित मूल्य के आधार पर किया जाना आवश्यक है। लेकिन, कुछ प्रतिष्ठान अपने वित्तीय विवरणों को चालू लागत दृष्टिकोण के आधार पर प्रस्तुत करते हैं जोकि धारित आस्तियों के विशेष मूल्यों में परिवर्तनों को प्रलक्षित करते हैं।
7. उच्च मुद्रास्फीतिशील अर्थव्यवस्था में तैयार किए गए वित्तीय विवरण, चाहे वे ऐतिहासिक लागत दृष्टिकोण के आधार पर हों या फिर चालू लागत दृष्टिकोण के आधार पर तभी लाभदायक हो सकते हैं जबकि उन्हें रिपोर्टिंग अवधि के अंत में चालू माप ईकाई के संदर्भ में स्पष्ट किया जाए। इसके फलस्वरूप, यह मानक उन्हीं प्रतिष्ठानों के वित्तीय विवरणों पर लागू होगा जोकि उच्च मुद्रास्फीतिशील अर्थव्यवस्था की मुद्रा में रिपोर्ट करते हैं। इस मानक द्वारा अपेक्षित जानकारी की गैर-पुनर्कथित विवरणों के पूरक के रूप में प्रस्तुति की अनुमति नहीं है। इसके अलावा, पुनर्कथन से पूर्व वित्तीय विवरणों की अलग से प्रस्तुति को भी हतोत्साहित किया जाता है।
8. एक प्रतिष्ठान के वित्तीय विवरण जिसकी कार्यात्मक मुद्रा एक उच्च मुद्रास्फीतिशील अर्थव्यवस्था की मुद्रा है, चाहे वे विवरण ऐतिहासिक लागत दृष्टिकोण पर आधारित हैं या चालू लागत दृष्टिकोण पर उन्हें रिपोर्टिंग अवधि के अंत में चालू माप ईकाई पर वर्णित किया जायेगा। भारतीय लेखा मानक 1 'वित्तीय विवरणों का प्रस्तुतिकरण' के अनुसरण में अपेक्षित गत अवधियों के तदनुरूपी आंकड़ों और अन्य कोई सूचना भी रिपोर्टिंग अवधि के अंत में चालू माप ईकाई पर ही वर्णित की जाएगी। भिन्न-भिन्न प्रस्तुति मुद्रा में तुलनात्मक राशियों को प्रस्तुत करने के प्रयोजन से लेखा मानक 21 'विदेशी विनिमय दरों के परिवर्तन के प्रभाव' के अनुच्छेद 42 (ख) और 43 लागू होते हैं।

9. निवल मौद्रिक स्थिति पर हुआ लाभ अथवा हानि, लाभ अथवा हानि में सम्मिलित किया जाएगा और उसका अलग से उल्लेख किया जायेगा।
10. इस मानक के अनुसार वित्तीय विवरणों का पुनर्कथन कुछ प्रक्रियाओं और निर्णयों की अपेक्षा करता है। पुनर्कथित वित्तीय विवरणों में सम्मिलित परिणाम स्वरूप राशियों की उपयुक्तता की बजाय इन प्रक्रियाओं और निर्णय का निरंतर प्रयोग अधिक महत्वपूर्ण है।

ऐतिहासिक लागत आधारित वित्तीय विवरण

तुलन पत्र

11. तुलन पत्र में यदि रिपोर्टिंग अवधि के अंत में, चालू माप ईकाई में तुलन पत्र की जिन राशियों का उल्लेख नहीं किया गया है, उन्हें सामान्य मूल्य सूचकांक को प्रयोग करते हुए पुनर्कथन किया जाता है।
12. मौद्रिक मदों का पुनर्कथन नहीं किया जाता है क्योंकि उन्हें रिपोर्टिंग अवधि के अंत में चालू मौद्रिक ईकाई के रूप में वर्णित किया जाता है। मौद्रिक मदें वे होती हैं जो राशि धन के रूप में धारित (रखी हुई) होती हैं और धन के रूप में ही या तो प्राप्त होती हैं या अदा की जाती हैं।
13. आस्तियां और देयताएँ, जो मूल्यों में परिवर्तन के करार से संबद्ध होती हैं, जैसे कि मूल्य सूचकांक से संबद्ध बांड और ऋण का समायोजन करार के अनुसार किया जाता है ताकि रिपोर्टिंग अवधि के अंत में उपलब्ध बकाया राशि का पता लगाया जा सके। इन मदों को पुनर्कथित तुलन पत्र में समायोजित राशि के रूप में आगे ले जाया जाता है।
14. शेष अन्य सभी आस्तियां तथा देयताएं गैर मौद्रिक मद होती हैं। कुछ गैर मौद्रिक मदें रिपोर्टिंग अवधि के अंत में चालू राशियों के रूप में आगे ले जायी जाती हैं जैसे कि वसूली योग्य निवल मूल्य और उचित मूल्य इसलिए इनका पुनर्कथन नहीं किया जाता है। अन्य सभी गैर मौद्रिक आस्तियों तथा देयताओं का पुनर्कथन किया जाता है।
15. अधिकतर, गैर मौद्रिक मदें लागत पर या मूल्यहास घटा कर लागत पर आगे ले जायी जाती हैं अतः उन्हें अधिग्रहण किये जाने की तिथि की चालू राशियों पर संदर्भित किया जाता है। प्रत्येक मद की पुनर्कथित लागत या मूल्यहास घटाकर लागत का निर्धारण ऐतिहासिक लागत और संचित मूल्यहास, मूल्य सूचकांक में परिवर्तन को लागू करके किया जाता है जो अधिग्रहण की तिथि से रिपोर्टिंग अवधि के अंत तक होता है। उदाहरण के लिए, संपत्ति, संयंत्र और उपकरण, कच्चे माल का सूचीबद्ध सामान, माल व प्रतिष्ठा (गुडविल), पेटेंट, ट्रेडमार्क और इसी प्रकार की आस्तियों का पुनर्कथन उनकी क्रय तिथि से किया जाता है। पूरी तरह से तैयार व आंशिक रूप से तैयार माल के सूचीबद्ध सामान (इन्वेन्ट्री) का पुनर्कथन उन तिथियों से किया जाता है जिन पर खरीद और परिवर्तन (कनवर्जन) की लागतों पर खर्च किया जाता है।
16. संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों की मदों के अधिग्रहण का तिथिवार विस्तृत रिकार्ड शायद उपलब्ध नहीं हो सकते और न ही उसका अनुमान लगाया जा सकता है। ऐसी दुर्लभ परिस्थितियों में, यह आवश्यक हो

जाता है कि इस मानक को लागू करने की पहली अवधि में स्वतंत्र व्यावसायिक आकलन द्वारा मदों का मूल्य पुनर्कथन के लिए प्रयोग करें।

17. इस मानक की अपेक्षानुसार संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के पुनर्कथन के लिए शायद सामान्य मूल्य सूचकांक इन अवधियों में उपलब्ध न हो। इन परिस्थितियों में, यह आवश्यक है कि मूल्यों का आकलन, उदाहरण के लिए, कार्यात्मक मुद्रा और सापेक्षतया स्थिर विदेशी मुद्रा की विनिमय दर में आये परिवर्तनों के आनुमानित आधार पर किया जाए।
18. कुछ गैर मौद्रिक मदों को अधिग्रहण या तुलन-पत्र की तिथि के अलावा अन्य तिथियों की विद्यमान राशियों पर अग्रणीत किया जाता है, उदाहरणार्थ, संपत्ति, संयंत्र और उपकरण का पुनर्मूल्यांकन कुछ पहले की तिथि पर किया जाता है। इन मामलों में, अग्रणीत राशियों का पुनर्कथन पुनर्मूल्यांकन की तिथि से किया जाएगा।
19. एक गैर मौद्रिक मद की पुनर्कथित राशि समुचित भारतीय लेखा मानकों के अनुसरण में कम भी की जाती है जब वह वसूली योग्य मूल्य से अधिक हो जाती है। उदाहरण के लिए, संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों, प्रतिष्ठा (गुडविल) और ट्रेडमार्कों के पुनर्कथन की राशियां वसूली होने योग्य मूल्य के अनुसार कम कर दी जाती हैं और सूचीबद्ध सामान (इन्वेंट्री) की पुनर्कथन राशियां निवल वसूली योग्य मूल्य तक कम कर दी जाती हैं।
20. उच्च मुद्रास्फीतिशील अर्थव्यवस्था में एक निवेशति जिसका लेखा 'इक्वीटी' विधि के आधार पर किया जाता है वह उच्च मुद्रास्फीतिशील की मुद्रा में रिपोर्ट कर सकता है। इस प्रकार के निवेशति का तुलन पत्र तथा लाभ और हानि विवरण इस लेखा मानक के अनुसार पुनर्कथित किया जाता है ताकि निवल आस्तियों और लाभ या हानि में निवेशक का हिस्सा पता चल सके। जब निवेशति के पुनर्कथित वित्तीय विवरणों को विदेशी मुद्रा में संदर्भित किया जाता है तो उन्हें अंतिम दरों पर ही रूपांतरित किया जाता है।
21. आमतौर पर मुद्रास्फीति के प्रभाव को उधार लागतों में मान्यता दी जाती है। यह उचित नहीं होगा कि उधार द्वारा वित्तपोषित पूंजीगत खर्चों और उधार लागतों के उस भाग को पूंजीकृत करने जो उस अवधि को मुद्रास्फीति की क्षतिपूर्ति करे, इन दोनों का पुनर्कथन करना उचित नहीं होगा। उधार लागतों का वह भाग जो मुद्रा स्फीति की क्षतिपूर्ति करे उस अवधि के खर्चों के रूप में माना जाता है जिसमें कि वे लागतें खर्च हुई हैं।
22. एक प्रतिष्ठान किसी व्यवस्था के तहत आस्तियों का अर्जन कर सकता है जिसके अंतर्गत उसे स्पष्ट ब्याज प्रभार के बिना ही भुगतान को स्थगित करने की अनुमति होती है। जिन मामलों में ब्याज की निहित राशि का आकलन करना अव्यवहार्य हो, ऐसी आस्तियों की खरीद की तिथि की बजाय भुगतान की तिथि से पुनर्कथित किया जाता है।
23. [देखिये परिशिष्ट 1]
24. इस मानक के लागू किये जाने की प्रथम अवधि के आरंभ में प्रतिधारित आधिक्य व पुनर्मूल्यांकन को छोड़कर स्वामी की इक्वीटी के घटकों का पुनर्कथन सामान्य मूल्य सूचकांक के प्रयोग द्वारा उस तिथि से किया जाता है जिसको ये घटक अंशदान हुए हैं या अन्यथा उत्पन्न हुए हैं। पुनर्कथित प्रतिधारित आय को पुनर्कथित तुलन पत्र में अन्य समस्त राशियों से लिया जाता है।

25. प्रथम अवधि के अंत और उसके पश्चात की अवधियों में, स्वामी की इक्वीटी के सभी घटकों का पुनर्कथन सामान्य मूल्य सूचकांक के द्वारा अवधि के प्रारंभ से या अंशदान की तिथि से, यदि वह बाद की है, से पुनर्कथन किया जाता है। इस अवधि के दौरान स्वामी को इक्वीटी में परिवर्तनों का प्रकटन भारतीय लेखा मानक 1 के अनुसार किया जाता है।

लाभ - हानि विवरण

26. प्रस्तुत मानक की यह अपेक्षा है कि लाभ-हानि विवरण में सभी मदें रिपोर्टिंग अवधि के अंत में चालू माप ईकाई के रूप में वर्णित हों। अतः सभी राशियों को उन तिथियों से सामान्य मूल्य सूचकांक परिवर्तन के अनुसार सभी राशियों का पुनर्कथन करना आवश्यक है जब आय व व्यय की मदें प्रारंभ में वित्तीय विवरणों में रिकार्ड की जाती हैं।

निवल मौद्रिक स्थिति पर लाभ अथवा हानि :

27. मुद्रास्फीति की अवधि में एक प्रतिष्ठान जोकि वित्तीय देयताओं से अधिक वित्तीय आस्तियां अपने पास रखता है अपनी क्रय शक्ति को खो देता है, जबकि इसके विपरीत एक प्रतिष्ठान जिसकी वित्तीय देयताएं उपलब्ध आस्तियों से अधिक हैं, क्रय शक्ति उस हद तक ग्रहण करता है, जहां तक कि आस्तियां और देयताएं मूल्य स्तर से संबद्ध न हों। निवल मौद्रिक स्थिति पर लाभ अथवा हानि, गैर मौद्रिक आस्तियों, स्वामी की इक्वीटी, लाभ एवं हानि विवरण की मदों, आस्तियों व देयताओं से संबद्ध सूचकांक के समायोजन के परिणामस्वरूप अंतर से उत्पन्न हो सकती है। लाभ व हानि का अनुमान अवधि में मौद्रिक आस्तियों व देयताओं के अंतर को भारित औसत आधार पर सामान्य मूल्य सूचकांक में परिवर्तन का प्रयोग करते हुए किया जा सकता है।
28. निवल मौद्रिक स्थिति पर लाभ या हानि, लाभ या हानि में सम्मिलित होती है। अनुच्छेद 13 के अनुसरण में मूल्यों में परिवर्तन करार से संबद्ध आस्तियों एवं देयताओं का समायोजन निवल मौद्रिक स्थिति पर लाभ या हानि द्वारा परस्पर समायोजित (आफसेट) हो जाता है। अन्य आय व व्यय मदें, जैसे कि ब्याज स्वरूप आय व व्यय और निवेशित या उधार निधियों से संबद्ध विदेशी विनिमय अंतर भी निवल मौद्रिक स्थिति से संबद्ध हैं। हालांकि, ये मदें अलग से प्रकट की जाती हैं परन्तु इस संदर्भ में यह सहायक होगा कि इन्हें लाभ हानि विवरण में निवल मौद्रिक स्थिति में लाभ या हानि के साथ प्रस्तुत किया जाए।

चालू लागत आधारित वित्तीय विवरण

तुलन-पत्र

29. चालू लागत पर कथित मदों का पुनर्कथन नहीं किया जाता है क्योंकि उन्हें पहले ही रिपोर्टिंग अवधि के अंत में चालू माप ईकाई के संदर्भ में दर्शाया जा चुका है। तुलन-पत्र में अन्य मदों को अनुच्छेद 11 से 25 के अनुसरण में पुनर्कथित की जाती है।

लाभ-हानि विवरण

30. लाभ-हानि विवरण का चालू लागत पर, पुनर्कथन से पूर्व, सामान्यता उन लागतों को रिपोर्ट करता है जो ऐसे समय रहती हैं जिस पर अन्तर्निहित लेन-देन होते हैं या घटनाएं घटती हैं। बिक्रियों की लागत और मूल्यहास उपभोग के समय चालू लागतों पर रिकार्ड किया जाता है। बिक्रियां व अन्य व्यय राशियां जब वे घटती हैं तब रिकार्ड की जाती हैं। अतः सभी राशियों को चालू माप ईकाई पर और रिपोर्टिंग अवधि के अंत में सामान्य मूल्य सूचकांक लागू करके पुनर्कथित किया जाना आवश्यक है।

निवल वित्तीय स्थिति पर लाभ अथवा हानि

31. निवल मौद्रिक स्थिति पर लाभ अथवा हानि का लेखा अनुच्छेद 27 और 28 के अनुसार किया जाएगा।

कर

32. इस मानक के अनुसार पुनर्कथित वित्तीय विवरणों में तुलन-पत्र में आस्तियों और देयताओं की अग्रणीत राशि में व उनके कर आधारों के बीच अंतर हो सकता है। भारतीय लेखा मानक 12 'आय कर' के अनुसार इन अंतरों का लेखा किया जाता है।

नकदी प्रवाहों का विवरण

33. यह मानक अपेक्षा करता है कि नकदी प्रवाहों के विवरण की सभी मदें रिपोर्टिंग अवधि के अंत में चालू माप ईकाई पर वर्णित की जाती हैं।

तदनुरूपी आंकड़े

34. पिछली रिपोर्टिंग अवधि के तदनुरूपी आंकड़ों को, चाहे वे ऐतिहासिक लागत दृष्टिकोण पर आधारित हों अथवा चालू लागत दृष्टिकोण पर, सामान्य मूल्य सूचकांक के आधार पर पुनर्कथित किया जाता है ताकि रिपोर्टिंग अवधि के अंत में चालू माप ईकाई के अनुसार तुलनात्मक वित्तीय विवरण प्रस्तुत किये जा सकें। पूर्व अवधियों की प्रकट सूचना भी अवधि के अंत पर चालू माप ईकाई पर वर्णित की जाती है। अलग प्रस्तुति मुद्रा में आंकड़ों की तुलनात्मक प्रस्तुति के लिए भारतीय लेखा मानक 21 के अनुच्छेद 42 (ख) और 43 लागू होते हैं।

समेकित वित्तीय विवरण

35. एक मूल प्रतिष्ठान जो उच्च मुद्रास्फीतिशील अर्थव्यवस्था की मुद्रा में रिपोर्ट करता है उसकी कुछ अनुषंगी प्रतिष्ठान हो सकते हैं और वे भी उच्च मुद्रास्फीतिशील अर्थव्यवस्थाओं की मुद्रा में रिपोर्ट करते हैं। इस प्रकार के किसी अनुषंगी प्रतिष्ठान के वित्तीय विवरण को उस देश के, जिसकी मुद्रा में वह रिपोर्ट करता है, सामान्य मूल्य सूचकांक के अनुसार पुनर्कथित किया जाता है और उसके बाद ही मूल प्रतिष्ठान द्वारा जारी अपनी समेकित विवरण में उसे सम्मिलित किया जाता है। यदि ऐसा कोई अनुषंगी प्रतिष्ठान विदेशी हो तो उसके पुनर्कथित वित्तीय विवरण अंतिम दरों पर रूपांतरित किये जाएंगे। ऐसे अनुषंगी प्रतिष्ठानों के वित्तीय विवरण जो उच्च मुद्रा स्फीतिशील अर्थव्यवस्थाओं की मुद्राओं में रिपोर्ट नहीं करते हैं, उन्हें भारतीय लेखा मानक 21 के अनुसार व्यवहार में लिया जाता है।
36. यदि रिपोर्टिंग अवधि के अंत की भिन्न-भिन्न अवधियों के वित्तीय विवरण को समेकित किया जाता है तो सभी मदों को चाहे वे गैर मौद्रिक हों अथवा मौद्रिक उन्हें वित्तीय विवरणों को समेकित किये जाने की तिथि पर चालू माप ईकाई पर पुनर्कथित करना आवश्यक हो जाता है।

सामान्य मूल्य सूचकांक का चयन और उसका प्रयोग

37. इस मानक के अनुसार वित्तीय विवरणों के पुनर्कथन की यह अपेक्षा रहती है कि वे ऐसे सामान्य मूल्य सूचकांक का प्रयोग करें जो सामान्य क्रय शक्ति में हुए परिवर्तनों को परिलक्षित करें। यह और भी अधिक उचित होगा कि वे सभी प्रतिष्ठान जो एकजैसी अर्थव्यवस्था की मुद्रा में रिपोर्ट करते हैं वे एक जैसे मूल्य सूचकांक का प्रयोग करें।

उच्च मुद्रा स्फीतिशील अर्थव्यवस्थाएं न रहना

38. जब एक अर्थव्यवस्था इस तरह उच्च मुद्रास्फीतिशील न रहे और प्रतिष्ठान इस भारतीय मानक के तहत वित्तीय विवरण तैयार करना और प्रस्तुत करना बंद कर देता है तो उस स्थिति में प्रतिष्ठान गत रिपोर्टिंग अवधि के अंत में चालू माप ईकाई में अभिव्यक्त राशियों को उसके बाद के वित्तीय विवरणों में अग्रणीत राशियों को आधार के रूप में व्यवहार में लाएगा।

प्रकटन

39. निम्नलिखित प्रकटन किए जाएंगे :

क) यह तथ्य कि गत अवधियों के वित्तीय विवरण और तदनुरूपी आंकड़े कार्यात्मक मुद्रा की सामान्य क्रय शक्ति में परिवर्तनों के रूप में पुनर्कथित किये गये हैं और जिसके फलस्वरूप रिपोर्टिंग अवधि के अंत में चालू माप ईकाई के अनुरूप वर्णित किये गये हैं ;

- ख) यह कि, क्या वित्तीय विवरण ऐतिहासिक लागत दृष्टिकोण पर आधारित हैं या कि चालू लागत दृष्टिकोण पर,
- ग) रिपोर्टिंग अवधि के अंत में मूल्य सूचकांक की पहचान और उसका स्तर और चालू तथा गत अवधियों के दौरान मूल्य सूचकांक में हुए परिवर्तन ; और
- (घ) अर्थव्यवस्था में विद्यमान उच्च मुद्रास्फीति स्थिति की समयावधि ।
40. प्रस्तुत मानक द्वारा अपेक्षित प्रकटनों का आशय वित्तीय विवरणों में मुद्रास्फीति के प्रभाव और उसके आधार को स्पष्ट करना है। उनका आशय उस अन्य जानकारी को भी प्रदान करना है जिसे उसके आधार तथा फलस्वरूप राशियों को समझने के लिए आवश्यक है।

परिशिष्ट 'क'

उच्च मुद्रा स्फीतिशील अर्थव्यवस्थाओं में भारतीय लेखा मानक 29 के अधीन वित्तीय विवरणों का पुनर्कथन दृष्टिकोण को लागू करना

प्रस्तुत परिशिष्ट भारतीय लेखा मानक 29 उच्च मुद्रास्फीतिशील अर्थव्यवस्थाओं में वित्तीय रिपोर्टिंग का अभिन्न अंग है।

पृष्ठभूमि

- यह परिशिष्ट यह मार्गदर्शन देता है कि भारतीय लेखा मानक 29 की अपेक्षाओं को उस रिपोर्टिंग अवधि में कैसे लागू किया जाए जिसमें प्रतिष्ठान अपनी कार्यात्मक मुद्रा की अर्थव्यवस्था में उच्च मुद्रास्फीति की स्थिति* की मौजूदगी महसूस करता है जबकि पिछली अवधि में वह अर्थव्यवस्था उच्च-मुद्रास्फीति के दौर में नहीं थी। इस तरह, प्रतिष्ठान वित्तीय विवरणों को भारतीय लेखा मानक 29 के अनुसरण में पुनर्कथित करता है।

मुद्दे

- इस परिशिष्ट में जिन प्रश्नों को उठाया गया है उनका समाधान इस प्रकार है :
 - भारतीय लेखा मानक 29 के अनुच्छेद 8 में दी गयी यह अपेक्षा कि 'रिपोर्टिंग अवधि के अंत में चालू माप ईकाई के संदर्भ में कथित' की व्याख्या उस समय कैसी की जाए जब प्रतिष्ठान इस लेखा मानक को लागू करता है।
 - प्रतिष्ठान द्वारा अपने पुनर्कथित वित्तीय विवरणों में प्रारंभिक आस्थगित कर मदों का लेखा कैसे किया जाए।

लेखा प्रक्रिया

3. उस रिपोर्टिंग अवधि में जिसमें प्रतिष्ठान अपनी कार्यात्मक मुद्रा की अर्थव्यवस्था में उच्च मुद्रा स्फीति की मौजूदगी की पहचान करता है जबकि पूर्व अवधि में वह उच्च मुद्रास्फीति में नहीं थी तो प्रतिष्ठान भारतीय

* प्रतिष्ठान मुद्रास्फीति की स्थिति का पता भारतीय लेखा मानक 29 के अनुच्छेद 3 में दिये गये मानदंड के निर्णय के आधार पर लगाता है।

लेखा मानक 29 की अपेक्षाओं को इस तरह से लागू करेगा कि मानों अर्थव्यवस्था हमेशा से ही उच्च मुद्रास्फीतिशील रही है। अतः गैर मौद्रिक मदों के ऐतिहासिक लागत के संदर्भ में मापने पर पुरानी-से-पुरानी अवधि के प्रस्तुत वित्तीय विवरणों के तुलन पत्र का आदि शेष इस तरह से पुनर्कथित किया जाएगा ताकि जिस तिथि को आस्तियां अधिगृहीत की गयी थीं अथवा देयताएं उत्पन्न हुई थीं या परिकल्पित की गयी थीं उस तिथि से मुद्रास्फीति के प्रभाव को रिपोर्टिंग अवधि के अंत तक परिलक्षित किया जाएगा। अधिग्रहण या घटना से भिन्न तिथियों में चालू राशियों पर प्रारंभिक तुलन पत्र की गैर मौद्रिक मदें पुनर्कथन में, रिपोर्टिंग अवधि के अंत तक मुद्रास्फीति का प्रभाव उस तिथि से लिया जाएगा जिस पर इनको अग्रणीत चालू राशियों पर माप किया गया था न कि उस तिथि से जब ये खरीदी गई थीं या घटित हुई थीं।

4. रिपोर्टिंग अवधि के अंत में, आस्थगित कर की मदों को मान्यता दी जाती है और भारतीय लेखा मानक 12 के अंतर्गत उनका माप किया जाता है। फिर भी प्रारंभिक तुलन पत्र आस्थगित करों के आंकड़े निम्नलिखित के अनुसार निर्धारित किये जाएंगे :-

क) प्रतिष्ठान रिपोर्टिंग अवधि के प्रारंभिक तुलन पत्र की तिथि पर गैर-मौद्रिक मदों की नाममात्र अग्रणीत राशि का पुनर्कथन करके भारतीय लेखा मानक 29 के अनुसरण में आस्थगित कर मदों का पुनर्माप करता है जिसके लिए वह उस तिथि की माप ईकाई का प्रयोग करता है।

ख) उपर्युक्त (क) के अनुसार, फिर से मापी गयी आस्थगित कर मदों का पुनर्कथन प्रारंभिक तुलन पत्र की तिथि से रिपोर्टिंग अवधि के अंत तक माप ईकाई में परिवर्तन से किया जाएगा।

प्रतिष्ठान भारतीय लेखा मानक 29 का प्रयोग करते हुए रिपोर्टिंग अवधि की पुनर्कथित वित्तीय विवरण की किसी तुलनात्मक अवधि को प्रस्तुत प्रारंभिक तुलन पत्र में की आस्थगित कर मदों के पुनर्कथन के लिए उपर्युक्त (क) तथा (ख) में दिये गये दृष्टिकोण का प्रयोग करता है।

5. प्रतिष्ठान द्वारा अपने वित्तीय विवरणों को पुनर्कथित करने के उपरांत, उत्तरवर्ती वित्तीय विवरणों जिन में आस्थगित कर की मदें भी सम्मिलित हैं, तदनुरूपी आंकड़ों का पुनर्कथन रिपोर्टिंग अवधि में माप ईकाई में परिवर्तन द्वारा किया जायेगा जिसका पुनर्कथन पूर्व की रिपोर्टिंग अवधि की वित्तीय विवरणों में पहले ही किया जा चुका हो।

दृष्टांत उदाहरण

यह उदाहरण परिशिष्ट 'क' के साथ संलग्न है किन्तु यह इसका अंग नहीं है।

दृष्टांत उदाहरण 1

निम्नलिखित उदाहरण में उन आस्थगित कर मदों को पुनर्कथित किया गया है जोकि भारतीय लेखा मानक 29 'उच्च मुद्रास्फीतिशील अर्थव्यवस्थाओं में वित्तीय रिपोर्टिंग' के अंतर्गत प्रतिष्ठान द्वारा मुद्रास्फीति के प्रभावों का पुनर्कथन से संबंधित है। इस उदाहरण का आशय केवल भारतीय लेखा मानक 29 में पुनर्कथित दृष्टिकोण के तंत्र का उल्लेख करता है जो आस्थगित कर मदों के संबंध में है। यह प्रतिष्ठान के समस्त वित्तीय विवरणों का उल्लेख नहीं करता है।

तथ्य

दृष्टांत उदाहरण 2

एक प्रतिष्ठान का 31 दिसम्बर 20x2 का तुलन-पत्र (पुनर्कथन से पूर्व) इस प्रकार है:

टिप्पणी	तुलन पत्र	20x2 (रु.) मिलियन	20x1 (रु.) मिलियन
	आस्तियां		
1.	संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर	300	400
	अन्य आस्तियां	xxx	xxx
	कुल आस्तियां	xxx	xxx
	इक्वीटी और देयताएं		
	कुल इक्वीटी	xxx	xxx
	देयताएं		
2.	आस्थगित कर देयता	30	20
	अन्य देयताएं	xxx	xxx
	कुल देयताएं	xxx	xxx
	कुल इक्वीटी तथा देयताएं	xxx	xxx

टिप्पणी**1. संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर**

संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर की सभी मदें दिसम्बर 20X0 में अर्जित की गई थीं। संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर को उनके उपयोगी जीवन में मूल्यहास करते हैं जो 5 वर्षों का है।

2. आस्थगित कर देयताएं :

31 दिसम्बर 20X2 को आस्थगित कर देयताओं का मूल्यांकन रुपये 30 मिलियन किया गया जोकि संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की 300/- रुपये की राशि और रु.200/- के अपने आयकर आधार के तौर पर कर योग्य बीच का अस्थाई अंतर है। कर लागू योग्य दर 30 प्रतिशत है।

इसी प्रकार, 31 दिसम्बर 20X1 को कर देयताओं का आंकलन रु.20 मिलियन किया गया है जो संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की अग्रणीत राशि के करयोग्य अस्थाई अंतर का आंकलन रु.400/- दर्शाती है जबकि उनका कर आधार रु.333 है।

दृष्टांत उदाहरण 3

उदाहरण के लिए मान लो प्रतिष्ठान अप्रैल 2002 में उच्च मुद्रास्फीतिशील अर्थव्यवस्था की मौजूदगी महसूस करता है। अतः वह 20X2 के प्रारंभ से भारतीय लेखा मानक 29 लागू करता है। प्रतिष्ठान अपने वित्तीय विवरणों का निम्नलिखित सामान्य मूल्य सूचकांक और परिवर्तन गुणकों के आधार पर पुनर्कथन करता है :

सामान्य मूल्य सूचकांक		31 दिसम्बर 20x2 के अनुसार परिवर्तन गुणक
दिसम्बर 20x0 (क)	95	2.347
दिसम्बर 20X1	135	1.652
दिसम्बर 20X2	223	1.000
क) उदाहरण के लिए दिसम्बर 20X0 का परिवर्तन गुणक 2.347 है $= 223/95$		

पुनर्कथन

दृष्टांत उदाहरण 4 : प्रतिष्ठान का 20X2 के वित्तीय विवरण का पुनर्कथन निम्नलिखित अपेक्षाओं पर आधारित है:

- संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर के मूल्यों का पुनर्कथन सामान्य मूल्य सूचकांक में हुए परिवर्तन को, जो अर्जित अवधि से रिपोर्टिंग अवधि के अंत तक, ऐतिहासिक लागत और संचित मूल्यहास पर लागू करके किया जाता है।
- आस्थगित करों का लेखा भारतीय लेखा मानक 12 'आयकर' के अनुसार किया जाएगा।
- संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर के पिछली रिपोर्टिंग अवधि के तुलनात्मक आंकड़ों को रिपोर्टिंग अवधि के अंत में चालू माप ईकाई लागत पर प्रस्तुत किया जाता है।
- आस्थगित करों के तुलनात्मक आंकड़ों को परिशिष्ट 'क' के अनुच्छेद 4 के अनुसार मापा जाना चाहिए।

दृष्टांत उदाहरण 5 : अतः प्रतिष्ठान 31 दिसम्बर 20X2 की स्थिति के अपने तुलन पत्र को इस प्रकार पुनर्कथित करता है :-

टिप्पणी : तुलन पत्र (पुनर्कथित)

	20X2	20X1
	(रु.) मिलियन	(रु.) मिलियन
आस्तियां		
1. संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर	704	939
अन्य आस्तियां	XXX	XXX
कुल आस्तियां	XXX	XXX
इक्वीटी और देयताएं		
कुल इक्वीटी	XXX	XXX
देयताएं		

2. आस्थगित कर देयतायें	151	117
अन्य देयताएं	<u>XXX</u>	<u>XXX</u>
कुल देयताएं	<u>XXX</u>	<u>XXX</u>
कुल इक्वीटी तथा देयताएं	<u>XXX</u>	<u>XXX</u>

टिप्पणियां

1. संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर

संपत्ति, संयंत्र और उपस्करों की सभी मदें, दिसम्बर 20X0 में खरीदी गई थीं और उन पर पांच वर्षों तक मूल्यहास लगाया जाना था। संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर की लागत का पुनर्कथन सामान्य मूल्य सूचकांक में हुए परिवर्तन के अनुसार किया जायेगा जिसे मदों के अर्जित किये जाने की तिथि से लिया जाएगा अर्थात् परिवर्तन गुणक 2.347 (223/95) होगा।

	ऐतिहासिक लागत रु. मिलियन	पुनर्कथित रु. मिलियन
संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर	500	1,174
मूल्यहास 20x1	<u>(100)</u>	<u>(235)</u>
31 दिसम्बर 20x1 को अग्रणीत राशि	<u>400</u>	<u>939</u>
मूल्यहास 20x2	<u>(100)</u>	<u>(235)</u>
31 दिसम्बर 20x2 को अग्रणीत राशि	<u>300</u>	<u>704</u>

2. आस्थगित कर देयता :

31 दिसम्बर 2002 को नाममात्र आस्थगित कर देयता का माप 30 मिलियन रुपये किया गया है जो संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर की अग्रणीत राशि 300 रुपये और उनके कर आधार के लिए 200 रुपये के बीच कर योग्य अस्थायी अंतर के रूप में है। इसी प्रकार 31 दिसम्बर 20X1 को आस्थगित कर देयताओं का आंकलन 20 मिलियन है जो संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के लिए अग्रणीत राशि 400 रुपये और उनके कर आधार 333 रुपये के बीच करयोग्य अस्थायी अन्तर के माप पर है। लागू कर की दर 30 प्रतिशत है।

प्रतिष्ठान द्वारा रिपोर्टिंग अवधि के अंत में पुनर्कथित वित्तीय विवरणों में आस्थगित कर मदों का पुनर्माप भारतीय लेखा मानक 12 के सामान्य प्रावधानों के तहत किया जाता है अर्थात् पुनर्कथित वित्तीय विवरणों पर। लेकिन, आस्थगित कर मदें अस्तियों व देयताओं के अग्रणीत राशियों और उनके कर के आधारों पर एक प्रक्रिया है अतः प्रतिष्ठान सामान्य मूल्य सूचकांक को लागू करके आस्थगित कर मदों का तुलनात्मक आधार पर पुनर्कथन नहीं कर सकता है। इसकी बजाय, उस

रिपोर्टिंग अवधि में, जिसमें कि भारतीय लेखा मानक 29 के अनुसार प्रतिष्ठान पुनर्कथन दृष्टिकोण का प्रयोग करती है। (क) यह चालू रिपोर्टिंग अवधि के प्रारंभिक तुलन पत्र की तिथि पर गैर मौद्रिक मदों की नाममात्र अग्रणीत राशियों के पुनर्कथन के बाद उस तिथि की माप ईकाई का प्रयोग करने पर अपनी आस्थगित कर की तुलनात्मक मदों का भारतीय लेखा मानक 12 के अनुसरण में पुनर्माप करता है। (ख) यह चालू अवधि के प्रारंभिक तुलन पत्र की तारीख से और रिपोर्टिंग अवधि के अंत तक माप ईकाई के परिवर्तन से पुनर्मापित आस्थगित कर मदों का पुनर्कथन करता है।

इस उदाहरण में आस्थगित कर देयता की गणना इस प्रकार की गई है :

रु. मिलियन

रिपोर्टिंग अवधि के अंत में :

संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर की पुनर्कथित अग्रणीत राशि (देखें टिप्पणी 1)	704
कर आधार	(200)
अस्थाई अंतर	504
30 प्रतिशत की दर से कर 31 दिसम्बर 20x2 को पुनर्कथित आस्थगित कर देयताएं	151

तुलनात्मक आस्थगित कर आंकड़े :

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की राशि पुनर्कथित अग्रणीत [या 400x 1.421 (परिवर्तन गुणक 1.421 = 135/95) या फिर 939/1.652 (परिवर्तन गुणक 1.652 = 223/135)]	568
कर आधार	(333)
अस्थाई अंतर	235

30 प्रतिशत की कर दर पर = दिसम्बर 20x1 की पुनर्कथित आस्थगित कर देयता जो 20x1 के अंत के सामान्य मूल्य स्तर के अनुसार है। 71

20x2 के अंत के सामान्य मूल्य स्तर के अनुसार 31 दिसम्बर 20x1 को पुनर्कथित आस्थगित (परिवर्तन गुणक 1.652 = 223/135) देयता 117

दृष्टांत उदाहरण 6

इस उदाहरण में, आस्थगित कर देयतायें 31 दिसम्बर 20x1 की स्थिति के अनुसार 34 रुपये बढ़कर वर्ष 31 दिसम्बर 20x2 को 151 रुपये हो गई हैं। वह वृद्धि जोकि 20x2 के लाभ या हानि के विवरण में सम्मिलित की गयी है यह परिलक्षित करती है (क) संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर के कर योग्य अस्थाई अंतर में हुए परिवर्तन के प्रभाव और (ख) संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर के कर आधार पर क्रय शक्ति में हुई हानि। इन दोनों घटकों का विश्लेषण इस प्रकार किया जा सकता है:-

	रु. मिलियन
संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर आस्थगित करयोग्य अस्थायी अंतर की कमी के कारण कर देयता पर प्रभाव (रु.235+रु.133)x 30%)	31
अवधि 20x2 में मुद्रास्फीति के कारण कर आधार में (रु.33x1.652 - रु.333)x30% हुई हानि	(65)
आस्थगित कर देयता में हुई निवल वृद्धि	(34)
20x2 में लाभ अथवा हानि के नामे	34

कर आधार पर हुई हानि एक मौद्रिक हानि है। भारतीय लेखा मानक 29 के अनुच्छेद 28 इसकी व्याख्या निम्न प्रकार से करता है :

शुद्ध आय में निवल मौद्रिक स्थिति पर लाभ व हानि को भी शामिल किया जाता है। अनुच्छेद 13 के अनुसरण में मूल्यों में परिवर्तनों के करार से संबद्ध आस्तियों और देयताओं का समायोजन निवल मौद्रिक स्थिति के लाभ या हानि द्वारा परस्पर समायोजित (आफसेट) किया जाता है। अन्य आय व व्यय मदें जैसे कि ब्याज आय व व्यय, निवेशित अथवा उधार दी गयी निधियों से संबंधित विदेशी मुद्रा अंतर भी निवल मौद्रिक स्थिति के साथ संबद्ध है। हालांकि वे इस प्रकार की मदों का अलग से प्रकटन किया जाता है फिर भी यह सुविधाजनक होगा यदि इन्हें लाभ हानि विवरण में निवल मौद्रिक स्थिति पर लाभ या हानि के साथ प्रस्तुत किया जाए।

परिशिष्ट 1

टिप्पणी : यह परिशिष्ट भारतीय लेखा मानक 29 'उच्च मुद्रास्फीतिशील अर्थव्यवस्थाओं की वित्तीय रिपोर्टिंग' का अंग नहीं है। इस परिशिष्ट का प्रयोजन मात्र इतना है कि इस भारतीय लेखा मानक और तदनुरूपी अन्तरराष्ट्रीय लेखा मानक (आई ए एस) 29 'उच्च मुद्रास्फीतिशील अर्थव्यवस्थाओं में वित्तीय रिपोर्टिंग' के बीच, यदि कोई अंतर हों, तो उन्हें स्पष्ट किया जाए।

अन्तरराष्ट्रीय भारतीय लेखा मानक 29, उच्च मुद्रास्फीतिशील अर्थव्यवस्थाओं में वित्तीय रिपोर्टिंग के साथ तुलना

1. भारतीय लेखा मानक (इंड ए एस) अन्तरराष्ट्रीय लेखा मानक (आई ए एस) 29 की तुलना में अर्थव्यवस्था में मौजूद उच्च मुद्रास्फीतिशील स्थिति की अवधि के बारे में अतिरिक्त प्रकटन की अपेक्षा करता है।
2. अन्तरराष्ट्रीय लेखा मानक 29 में अनुच्छेद 23 'हटाया गया' के रूप में उल्लिखित है। अतः अन्तरराष्ट्रीय लेखा मानक 29 के साथ भारतीय लेखा मानक 29 की अनुच्छेद संख्याओं की क्रमबद्धता बनी रहे, इस अनुच्छेद संख्या को भारतीय लेखा मानक 29 में जारी रखा गया है।
3. भारतीय लेखा मानक में भिन्न शब्दावली का प्रयोग किया गया है, उदाहरणार्थ, शब्दों 'वित्तीय स्थिति का विवरण' के स्थान पर शब्द 'तुलन-पत्र' और शब्दों 'व्यापक आय विवरण' के स्थान पर शब्द 'लाभ-हानि विवरण' का प्रयोग किया गया है।

भारतीय लेखा मानक (इंड ए एस) 105

बिक्री के लिए धारित गैर-चालू आस्तियां एवं बन्द परिचालन

(इस भारतीय लेखा मानक में मोटे टाइप व सामान्य टाइप में अनुच्छेद हैं। इन दोनों तरह के अनुच्छेदों का समान प्राधिकार है। मोटे टाइप में अनुच्छेद मुख्य सिद्धान्तों के सूचक हैं)।

उद्देश्य

1. इस भारतीय लेखा मानक का उद्देश्य, बिक्री के लिए धारित आस्तियों के लेखा तथा बन्द परिचालनों के प्रस्तुतिकरण तथा प्रकटन को विनिर्दिष्ट करना है। विशेषकर, भारतीय लेखा मानक यह अपेक्षा करता है कि :-
 - (क) आस्तियां जो बिक्री के लिए धारित वर्गीकरण के मानदंडों को पूरा करती हैं, उन्हें अग्रणीत (कैरिंग) राशि तथा बिक्री की लागत को कम कर उचित मूल्य, इन दोनों में जो भी कम है, उस पर मापा जायेगा तथा इस प्रकार की आस्तियों पर मूल्यह्रास लगना बन्द हो जाता है।
 - (ख) आस्तियां जो बिक्री के लिए धारित के रूप में वर्गीकरण के मापदंड को पूरा करती हैं उन्हें तुलन-पत्र में अलग-से प्रस्तुत किया जाता है तथा बन्द परिचालनों के परिमाणों को लाभ तथा हानि के विवरण में अलग-से प्रस्तुत किया जाता है।

कार्यक्षेत्र

2. इस भारतीय लेखा मानक के वर्गीकरण तथा प्रस्तुतिकरण की अपेक्षाएं प्रतिष्ठान की सभी मान्यताप्राप्त गैर-चालू आस्तियों तथा सभी निपटान समूहों पर लागू होती हैं। इस भारतीय लेखा मानक की माप अपेक्षाएं सभी मान्यताप्राप्त गैर-चालू आस्तियों तथा निपटान समूहों पर लागू होती हैं, [जैसा कि अनुच्छेद 4 में निर्धारित किया गया है।] लेकिन, अनुच्छेद 5 में सूचीबद्ध आस्तियों पर यह लागू नहीं होती है और उन्हें उल्लिखित मानक के अनुसार ही मापा जाना जारी रहेगा।
3. भारतीय लेखा मानक 1 *वित्तीय विवरण की प्रस्तुतिकरण* के अनुसार गैर-चालू वर्गीकृत आस्तियों को चालू आस्तियों के रूप में पुनः वर्गीकृत नहीं किया जायेगा जब तक वे इस भारतीय लेखा मानक के अनुसार बिक्री के लिए धारित वर्गीकरण के मानदंड को पूरा नहीं करती। इसी तरह, एक ही श्रेणी की आस्तियां एवं जिन्हें एक प्रतिष्ठान सामान्यतः गैर-चालू मानता है और जिन्हें एकनिष्ट रूप से पुनः बिक्री के लिए अधिगृहीत किया गया है, उन्हें चालू आस्तियों के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जाएगा, जब तक कि वे इस भारतीय लेखा मानक के अनुसार बिक्री के लिए धारित वर्गीकरण के मानदंड को पूरा नहीं करती हैं।

1. तरलता प्रस्तुति के अनुसार वर्गीकृत आस्तियों की गैर-चालू आस्तियों में वे आस्तियां सम्मिलित हैं जिनकी रिपोर्टिंग अवधि के बाद 12 माह से अधिक समय के बाद वसूल होने की आशा है। अनुच्छेद 3 इस प्रकार की आस्तियों के वर्गीकरण पर लागू होता है।

4. कभी-कभी एक प्रतिष्ठान आस्तियों के एक समूह का निपटान संभवतः किसी प्रत्यक्ष देयता के साथ जोड़कर एकल लेनदेन (सौदे) में करता है। इस प्रकार का निपटान-समूह नकद सृजन इकाईयों का समूह, एक एकल नकद सृजन इकाई अथवा नकद सृजन इकाई का एक भाग² हो सकता है। समूह में प्रतिष्ठान की कोई भी आस्तियां या देयताएं और चालू आस्तियां व चालू देयताएं तथा अनुच्छेद 5 में इस भारतीय लेखा मानक की माप अपेक्षाओं से छोड़ी गयीं आस्तियां सम्मिलित हो सकती हैं। यदि इस भारतीय लेखा मानक की माप अपेक्षाओं के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत कोई गैर चालू आस्ति निपटान समूह का भाग बनती है तो इस भारतीय लेखा मानक की माप अपेक्षाएं पूरे समूह पर लागू होती हैं, ऐसे में समूह को अग्रणीत (कैरिंग) राशि तथा बिक्री की लागत घटाकर उचित मूल्य में, इनमें जो कम है उस पर मापा जाता है। निपटान समूह के अंदर व्यक्तिगत आस्तियों तथा देयताओं को मापने की अपेक्षाएं अनुच्छेद 18, 19 तथा 23 में निर्धारित की गयी हैं।
5. इस भारतीय लेखा मानक³ के माप प्रावधान निम्नलिखित आस्तियों पर लागू नहीं होते हैं, जो संबन्ध भारतीय लेखा मानकों में, व्यक्तिगत आस्तियां अथवा निपटान समूह के भाग के रूप में सूचीबद्ध किए गये हैं :-
- (क) आस्थगित कर आस्तियां [भारतीय लेखा मानक 12 आय कर]
 - (ख) कर्मचारी लाभों से उत्पन्न आस्तियां [भारतीय लेखा मानक 19 कर्मचारी लाभ]
 - (ग) भारतीय लेखा मानक 39 वित्तीय प्रलेख : मान्यता और माप के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत वित्तीय आस्तियां ।
 - (घ) [देखिये परिशिष्ट 1] ।
 - (ङ) गैर-चालू आस्तियां जिन्हें भारतीय लेखा मानक 41 कृषि⁴ के अनुसार बिक्री की लागत को घटाकर उचित मूल्य पर मापा जाता है।
 - (च) बीमा संविदाओं के अन्तर्गत संविदात्मक अधिकार जिन्हें भारतीय लेखा मानक 104 'बीमा संविदाएं' में परिभाषित किया गया है।
- 5 क. इस भारतीय लेखा मानक की वर्गीकरण, प्रस्तुति तथा माप की अपेक्षाएं उस एक गैर-चालू आस्ति (अथवा निपटान समूह) पर लागू होती हैं, जिसे बिक्री के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत किया गया है। वे स्वामित्व की हैसियत से (स्वामियों को वितरण के लिए धारित) इस भारतीय लेखा मानक की वर्गीकरण, प्रस्तुति तथा माप की अपेक्षाएं गैर-चालू आस्ति (अथवा निपटान समूह) पर भी लागू होंगी जिन्हें स्वामियों के वितरण के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

² यद्यपि एक बार एक आस्ति अथवा आस्तियों के समूह से नकद प्रवाह मुख्यतया लगातार उपयोग की बजाय बिक्री से उत्पन्न होने की आशा है, वे अन्य आस्तियों से उत्पन्न नकद प्रवाह पर कम निर्भर हो जाता है तथा एक निपटान समूह जो एक नकद सृजक इकाई का अंग था एक पृथक नकद सृजक इकाई बन जाता है।

³ अनुच्छेद 18 और 19 के अतिरिक्त, जो प्रश्नगत आस्तियों को अन्य लागू भारतीय लेखा मानकों के अनुसार माप की अपेक्षा करता है।

⁴ यह मानक अभी तैयार किया जा रहा है।

5 ख. यह भारतीय लेखा मानक बंद परिचालनों अथवा बिक्री के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत गैर चालू आस्तियों (अथवा निपटान समूहों) के संबंध में अपेक्षित प्रकटन को विनिर्दिष्ट करता है। अन्य भारतीय लेखा मानकों के प्रकटन इस प्रकार की आस्तियों (अथवा निपटान समूहों) पर लागू नहीं होते हैं, जब तक कि उन भारतीय लेखा मानकों की ऐसी अपेक्षा न हों।

(क) बंद परिचालनों अथवा बिक्री के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत गैर-चालू आस्तियों (अथवा निपटान समूहों) के संदर्भ में विशिष्ट प्रकटन ; अथवा

(ख) एक निपटान समूह के अंदर आस्तियों तथा देयताओं के माप के बारे में प्रकटन जो भारतीय लेखा मानक 105 की माप अपेक्षाओं के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत नहीं हैं तथा इस प्रकार के प्रकटन को वित्तीय विवरणों की अन्य टिप्पणियों में पहले से प्रावधान नहीं किया गया है।

बिक्री के लिए धारित या बंद परिचालनों के रूप में वर्गीकृत गैर-चालू आस्तियों (अथवा निपटान समूहों) के बारे में अतिरिक्त प्रकटन भारतीय लेखा मानक 1 की सामान्य अपेक्षाओं, और विशेषकर उस मानक के अनुच्छेद 15 तथा 125 की अपेक्षाओं, के अनुपालन के लिए आवश्यक हो सकता है।

बिक्री के लिए धारित अथवा स्वामियों को वितरण के लिए धारित के रूप में गैर चालू आस्तियों (अथवा निपटान समूहों) का वर्गीकरण

6. एक प्रतिष्ठान एक गैर-चालू आस्ति (अथवा निपटान समूहों) को बिक्री के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत करेगा यदि इसकी अग्रणीत (कैरिंग) राशि मुख्य रूप से लगातार उपयोग की बजाय बिक्री के लेनदेन (सौदे) के द्वारा वसूल होगी।

7. ऐसे इस मामले में, आस्ति (अथवा निपटान समूह) वर्तमान स्थिति में तुरन्त बिक्री के लिए उपलब्ध होना चाहिए। साथ ही, वह केवल उन शर्तों के तहत हो जो इस प्रकार की आस्तियों (निपटान समूहों) की बिक्री के लिए सामान्य तथा पारंपारिक है तथा बिक्री अति संभावित रूप से होनी चाहिए। इस तरह, एक आस्ति (या निपटान समूह) को बिक्री के लिए धारित गैर-चालू आस्ति (या निपटान समूह) के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता यदि प्रतिष्ठान इसे दूर भविष्य में बिक्री करना चाहता है।

8. बिक्री की अति संभावना के लिए, प्रबन्धन का उपयुक्त स्तर आस्ति (अथवा निपटान समूह) की बिक्री की योजना के लिए प्रतिबद्ध होना चाहिए तथा क्रेता की खोज के लिए एक सक्रिय कार्यक्रम द्वारा योजना को पूरा करने के लिए प्रयास आरंभ करें। साथ ही, आस्ति (अथवा निपटान समूह) की बिक्री के लिए सक्रिय रूप से विपणन करना चाहिए ताकि उसे ऐसी कीमत पर बेचा जा सके जो चालू उचित मूल्य के संबंध में उचित हों। इसके अतिरिक्त, (आस्ति निपटान समूह) को बिक्री के रूप में वर्गीकृत करने की तिथि से एक वर्ष के अंदर पूर्ण बिक्री के रूप में मान्यता की अहर्ता प्राप्त होनी चाहिए, सिवाय ऐसी स्थिति जो अनुच्छेद 9 के द्वारा अनुयेय है, जब योजना को पूर्ण करने के लिए योजना पर कार्यवाही के शायद ही संकेत हों कि योजना में उल्लेखनीय बदलाव किया जा सकता है अथवा कि योजना को वापिस ले लिया जा सकता है। शेयरधारकों की अनुमति (जिस क्षेत्र में यह आवश्यक है) की संभावना पर विचार इस आशय से करना चाहिए कि क्या बिक्री अति संभावित है।

- 8क. एक प्रतिष्ठान जो ऐसी उस बिक्री योजना के लिए प्रतिबद्ध है जो अनुषंगी पर नियंत्रण खो देने से संबंधित है तो वह उस अनुषंगी की सभी आस्तियों तथा देयताओं को बिक्री के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत करेगा जब उसमें अनुच्छेद 6-8 में निर्धारित मानदंडों को पूरा कर लिया है यद्यपि चाहे वह प्रतिष्ठान बिक्री के पश्चात् भी भूतपूर्व अनुषंगी में गैर-नियंत्रित हित बरकरार रखे रहेगा ।
9. घटनाओं और परिस्थितियों के अनुसार बिक्री को पूर्ण करने के लिए अवधि को एक वर्ष से आगे बढ़ाया जा सकता है। एक बिक्री को पूर्ण करने के लिए अपेक्षित अवधि का विस्तार एक आस्ति (अथवा निपटान समूह) को बिक्री के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत होने से नहीं रोकता बशर्ते देरी प्रतिष्ठान की उस घटना अथवा परिस्थिति के कारण हुई जिस पर उसका कोई वेश न था और इस बात का पर्याप्त साक्ष्य है कि प्रतिष्ठान आस्ति (अथवा निपटान समूह) को बेचने की अपनी योजना के प्रति प्रतिबद्ध है। यह मामला तब होगा जब परिशिष्ट 'ख' में दिया गया मानदंड पूरा होगा ।
10. बिक्री लेन-देनों (सौदों) में अन्य गैर चालू आस्तियों के लिए गैर चालू आस्तियों का विनिमय सम्मिलित है जब विनिमय का भारतीय लेखा मानक 16 *आस्तियां, संयंत्र और उपस्कर* के अनुसार वाणिज्यिक सारत्व है।
11. जब एक प्रतिष्ठान केवल बाद में निपटान के आशय से गैर चालू आस्ति (अथवा निपटान समूह) का अधिग्रहण करता है, तो वह अधिग्रहण तिथि पर बिक्री के लिए धारित के रूप में गैर चालू आस्ति (अथवा निपटान समूह) का वर्गीकरण करेगा बशर्ते अनुच्छेद 8 में दी गयी एक वर्ष की अपेक्षा पूरी हो जाती है (लेकिन अनुच्छेद 9 के द्वारा अनुमति को छोड़कर) तथा इसकी बहुत संभावना है कि अनुच्छेद 7 तथा 8 में किसी अन्य मानदंड को जिसे उस तिथि तक पूरा नहीं किया गया है, अधिग्रहण (प्रायः तीन माह के अंदर) के बाद अल्प अवधि में पूरा कर लिया जायेगा ।
12. यदि अनुच्छेद 7 तथा 8 में दिये गये मानदंडों को रिपोर्टिंग अवधि के पश्चात् पूरा किया जाता है तो प्रतिष्ठान बिक्री के लिए धारित एक गैर चालू आस्ति को उन वित्तीय विवरणों में, जब वे जारी किये जाते हैं, बिक्री के लिए धारित गैर-चालू आस्ति के रूप में वर्गीकृत नहीं करेगा । लेकिन जब रिपोर्टिंग अवधि के बाद और वित्तीय विवरणों के अनुमोदन से पूर्व मानदंडों को पूरा किया जाता है तो प्रतिष्ठान टिप्पणियों के अनुच्छेद 41 (क), (ख) तथा (ग) में निर्दिष्ट सूचना को प्रकट करेगा ।
- 12 क. एक गैर-चालू आस्ति (अथवा निपटान समूह) को स्वामियों को वितरण के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, जब प्रतिष्ठान स्वामियों को आस्ति (अथवा निपटान समूह) को वितरित करने के लिए प्रतिबद्ध है। इस मामले के लिए, एक आस्ति को अपनी वर्तमान स्थिति में तुरन्त वितरण के उपलब्ध होना चाहिए तथा वितरण की अच्छी संभावना हो और वितरण को पूर्ण करने के लिए कार्यवाही को तुरन्त आरंभ कर देना चाहिए तथा यह कार्यवाही वर्गीकरण की तिथि से एक वर्ष के अंदर पूर्ण हो जानी चाहिए । वितरण को पूर्ण करने के लिए की जा रही अपेक्षित कार्यवाही में यह शायद ही संकेत होना चाहिए कि वितरण में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन किया जायेगा अथवा वितरण को वापस ले लिया जायेगा । शेयरधारकों की अनुमति (यदि क्षेत्र में यह अपेक्षित है) की संभावना पर विचार इस आशय से करना चाहिए कि क्या वितरण अति संभावक है।

गैर चालू आस्तियां जिनका परित्याग किया जाना है

13. एक प्रतिष्ठान एक गैर चालू आस्ति (अथवा निपटान समूह) को बिक्री के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत नहीं करेगा यदि उसका परित्याग किया जाना है। यह इसलिए है कि इसकी अग्रणीत (कैरिंग) राशि को मुख्यतः निरन्तर उपयोग के द्वारा वसूल किया जायेगा। लेकिन, यदि परित्याग किये जाने वाला निपटान-समूह अनुच्छेद 32 (क) - (ग) में दिये गये मानदंडों को पूरा करता है तो प्रतिष्ठान निपटान-समूह के परिणामों तथा नकद प्रवाहों को अनुच्छेद 33 तथा 34 के अनुसार बंद परिचालन के रूप में प्रस्तुत करेगा और यह उस तिथि पर करेगा जिस पर उसे प्रयोग में बंद कर दिया गया था। परित्याग की जाने वाली गैर चालू आस्तियों (अथवा निपटान समूहों) में वे गैर चालू आस्तियां (अथवा निपटान समूह) भी सम्मिलित हैं जिन्हें उनके आर्थिक जीवन के अंत तक प्रयुक्त किया जाना है और गैर चालू आस्तियां (अथवा निपटान समूह) जिन्हें बेचने की बजाय बंद किया जाना है।
14. एक प्रतिष्ठान एक गैर चालू आस्ति को उस स्थिति में लेखांकित नहीं करेगा जिसे अस्थायी रूप से उपयोग से हटाया गया है, जैसे कि, मानो इसका परित्याग कर दिया हो।

बिक्री के लिए धारित गैर चालू आस्तियां (अथवा निपटान समूहों) का माप

गैर-चालू आस्ति (अथवा निपटान समूह) का माप

15. एक प्रतिष्ठान बिक्री के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत एक गैर चालू आस्ति (अथवा निपटान समूह) का माप उसकी अग्रणीत (कैरिंग) राशि तथा बिक्री की लागत घटाकर उसके उचित मूल्य इनमें से जो भी राशि कम है उस पर करेगा।
- 15 क. एक प्रतिष्ठान स्वामियों को वितरण के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत एक गैर चालू आस्ति (अथवा निपटान समूह) का माप उसकी अग्रणीत (कैरिंग) राशि तथा वितरण की लागत घटाकर उचित मूल्य, इनमें जो भी राशि कम है उस पर करेगा।⁵
16. यदि नयी अधिगृहीत आस्ति (अथवा निपटान समूह) बिक्री के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत होने के मानदंड (अनुच्छेद 11 देखें) को पूरा करती है, तो अनुच्छेद 15 का प्रयोग यह परिणाम देगा कि आस्ति को आरंभिक मान्यता पर अग्रणीत (कैरिंग) राशि पर, जैसे कि उसका वर्गीकरण किया ही नहीं गया है, (उदाहरण के लिए, लागत) तथा बिक्री की लागत को घटाकर उचित मूल्य, इन दोनों में जो भी राशि कम है उस पर मापा जायेगा। अतः यदि आस्ति (अथवा निपटान समूह) को व्यवसाय के संयोजन के रूप में अधिगृहीत किया गया है, तो इसका माप बिक्री लागत घटाकर उचित मूल्य पर किया जायेगा।
17. जब बिक्री की एक वर्ष के बाद होने की आशा है तब प्रतिष्ठान बिक्री की लागतों को उनके वर्तमान मूल्य पर मापेगा। समय बीतने के बाद यदि बिक्री की लागतों के वर्तमान मूल्य में कोई वृद्धि होती है, तो उसे वित्त पोषण लागत के रूप में लाभ अथवा हानि में प्रस्तुत किया जाएगा।

⁵ वितरण के लिए लागतें वे वृद्धिशील लागतें हैं जो वितरण से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित हैं और इनमें वित्तीय लागतें व आयकर संबंधी व्यय सम्मिलित नहीं हैं।

18. बिक्री के लिए धारित आस्ति (अथवा निपटान समूह) के आरंभिक वर्गीकरण से एकदम पूर्व आस्ति (अथवा समूह की आस्तियों या देयताओं) की अग्रणीत (कैरिंग) राशियों को लागू योग्य भारतीय लेखा मानकों के अनुसार मापा जायेगा।
19. एक निपटान समूह के बाद में पुनः माप पर, किसी आस्ति तथा देयता की अग्रणीत (कैरिंग) राशियों को जो इस भारतीय लेखा मानक की माप अपेक्षाओं के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत नहीं हैं, परन्तु बिक्री के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत निपटान समूह में सम्मिलित हैं, निपटान समूह की बिक्री की लागत को घटाकर उचित मूल्य पर पुनः माप से पूर्व लागू योग्य भारतीय लेखा मानकों के अनुसार पुनः मापा जाएगा।

क्षतिग्रस्तता हानियों की मान्यता तथा उलटाव

20. एक प्रतिष्ठान आस्ति (अथवा निपटान समूह) के किसी आरंभ के अथवा बाद के अपलेखन के लिए क्षतिग्रस्तता हानि को बिक्री लागतें घटाकर उचित मूल्य पर उस हद तक मान्यता देगा जहां तक अनुच्छेद 19 के अनुसार मान्यता नहीं दी गयी है।
21. एक प्रतिष्ठान एक आस्ति को बेचने की लागत को घटाकर उचित मूल्य में किसी बाद की वृद्धि से लाभ को मान्यता देगा परन्तु संग्रहीत क्षतिग्रस्तता हानि से अधिक नहीं है जिसे इस भारतीय लेखा मानक के अनुसार अथवा पहले भारतीय लेखा मानक 36 क्षतिग्रस्तता की हानि के अनुसार मान्यता दी गयी है।
22. एक प्रतिष्ठान एक निपटान समूह की बिक्री लागत को घटाकर उचित मूल्य में बाद की वृद्धि के लिए लाभ को निम्नलिखित अनुसार मान्यता देगा :-
 - (क) जिस हद तक इसे अनुच्छेद 19 के अनुसार मान्यता नहीं दी गयी है ; परन्तु
 - (ख) संग्रहीत क्षतिग्रस्तता हानि, जिसे इस भारतीय लेखा मानक अथवा पहले भारतीय लेखा मानक 36 के अनुसार, गैर चालू आस्ति पर मान्यता दी है और जो इस भारतीय लेखा मानक के माप की अपेक्षाओं के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत है।
23. एक निपटान समूह के लिए मान्य क्षतिग्रस्तता हानि (अथवा बाद का कोई लाभ) समूह में गैर चालू आस्ति की अग्रणीत (कैरिंग) राशि को कम करेगा (अथवा बढ़ाएगा) जो भारतीय लेखा मानक 36 के अनुच्छेद 104 (क) तथा (ख) और अनुच्छेद 122 में निर्धारित किए गए आबंटन के क्रम में इस भारतीय लेखा मानक की माप अपेक्षाओं के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत है।
24. एक लाभ अथवा हानि को जिसे गैर चालू आस्ति (अथवा निपटान समूह) की बिक्री पर पहले मान्यता नहीं दी गयी है, गैर मान्यता की तिथि पर मान्यता दी जायेगी। गैर मान्यता से संबंधित अपेक्षाएं इस प्रकार से निर्धारित की गयी हैं :-
 - (क) संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर के लिए भारतीय लेखा मानक 10 के अनुच्छेद 67-72, तथा
 - (ख) अमूर्त आस्तियों के लिए भारतीय लेखा मानक 38 अमूर्त आस्तियों के अनुच्छेद 112-117।
25. एक प्रतिष्ठान उस गैर चालू आस्ति को ह्रासित (अथवा परिशोधित) नहीं करेगा जिसे किसी बिक्री के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत किया गया है अथवा यह बिक्री के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत निपटान

समूह का एक भाग है। बिक्री के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत एक निपटान समूह की देयताओं से जुड़े ब्याज तथा अन्य व्यय को मान्यता जारी रहेगी।

बिक्री की योजना में परिवर्तन

26. यदि प्रतिष्ठान ने एक आस्ति (अथवा निपटान समूह) को बिक्री में धारित के रूप में वर्गीकृत किया है परन्तु अनुच्छेद 7-9 में दिये गये मानदंड अब पूरे नहीं होते हैं तो प्रतिष्ठान आस्ति (अथवा निपटान समूह) को बिक्री के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत करना बंद कर देगा।
27. प्रतिष्ठान एक गैर-चालू आस्ति को, जो बिक्री के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत करना बंद कर दी गयी है, (अथवा बिक्री के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत निपटान समूह में शामिल होने से बंद कर दी गयी है), निम्नलिखित में जो कम है उस पर माप करेगा :-
 - (क) आस्ति (अथवा निपटान समूह) को बिक्री के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत किया था, उससे पूर्व की अग्रणीत (कैरिंग) राशि जिसमें किसी ह्रास, परिशोधन अथवा पुनर्मूल्यांकन के समायोजन की मान्यता दी गयी है जैसे कि आस्ति (अथवा निपटान समूह) को बिक्री के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत किया ही नहीं गया था ;
 - (ख) बिक्री न करने पर निर्णय की तिथि के बाद इसकी वसूली योग्य राशि ⁶।
28. प्रतिष्ठान गैर चालू आस्ति की अग्रणीत (कैरिंग) राशि के अपेक्षित समायोजन को, जो उस अवधि में जिसमें अनुच्छेद 7-9 के मानदंड पूरे नहीं हुए हैं, बिक्री के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत होने से बंद हो जाती है, उसे गैर-चालू आस्ति में जारी परिचालन से लाभ अथवा हानि को सम्मिलित करेगा।⁷ प्रतिष्ठान अनुच्छेद 37 के अनुसार मान्य एक लाभ अथवा हानि को, यदि कोई है, प्रस्तुत करने के लिए प्रयुक्त लाभ तथा हानि के विवरण में उसी शीर्ष में उस समायोजन को प्रस्तुत करेगा।
29. यदि प्रतिष्ठान बिक्री के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत एक निपटान समूह से एक व्यक्तिगत आस्ति अथवा देयता को हटाती है, तो निपटान समूह की शेष आस्ति तथा देयता, जिसे बेचा जाना है, एक समूह के रूप में माप जारी रहेगा यदि समूह अनुच्छेद 7-9 के मानदंड को पूरा करता है। अन्यथा, समूह की बाकी गैर चालू आस्ति, जो व्यक्तिगत रूप से बिक्री के लिए धारित आस्ति के रूप में वर्गीकृत मानदंड को पूरा करती है उस तिथि से उसे व्यक्तिगत रूप से उसकी अग्रणीत (कैरिंग) राशि तथा बिक्री की लागत को घटाकर उचित मूल्य इन दोनों में जो कम है उस पर मापा जायेगा। कोई गैर चालू आस्ति, जो मानदंड को पूरा नहीं करती, अनुच्छेद 26 के अनुसार बिक्री के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत होने से बंद हो जायेगी।

⁶ यदि गैर चालू आस्ति एक नकद सृजन इकाई का भाग है, इसकी वसूली योग्य राशि ही अग्रणीत (कैरिंग) राशि है जिसे भारतीय लेखा मानक 36 के अनुसार उस नकद सृजन इकाई से उत्पन्न किसी क्षतिग्रस्तता हानि के आवंटन के पश्चात् मान्यता दी गयी है।

⁷ जब तक आस्ति, एक सम्पत्ति, संयंत्र तथा उपस्कर अथवा अमूर्त आस्ति न हो जिसे भारतीय लेखा मानक 16 अथवा भारतीय लेखा मानक 38 के अनुसरण में बिक्री के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत से पूर्व पुनः मूल्यांकित किया गया है, उस मामले में समायोजन को पुनः मूल्यांकन की वृद्धि अथवा कमी के रूप में माना जायेगा।

प्रस्तुतिकरण तथा प्रकटन

30. एक प्रतिष्ठान उस सूचना को प्रस्तुत तथा प्रकट करेगा जो वित्तीय विवरणों के उपयोगकर्ताओं को बंद परिचालनों तथा गैर चालू आस्तियों के निपटानों (अथवा निपटान समूहों) के वित्तीय प्रभावों का आकलन करने में समर्थ करती है।

बंद परिचालनों को प्रस्तुति

31. एक प्रतिष्ठान का घटक परिचालनों तथा नकद प्रवाहों से मिल कर बना होता है जिन्हें स्पष्ट रूप से शेष प्रतिष्ठान से परिचालन तथा वित्तीय रिपोर्टिंग के प्रयोजन के लिए अलग किया जा सकता है। अन्य शब्दों में, एक प्रतिष्ठान का घटक एक नकद सृजक इकाई अथवा नकद सृजक इकाइयों का समूह होगा जब इसे उपयोग के लिए धारित किया है।
32. एक बंद परिचालन, एक प्रतिष्ठान का वह घटक है जिसका या तो निपटान किया गया है अथवा उसे बिक्री के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत किया गया है, तथा
- (क) वह व्यवसाय की एक पृथक मुख्य रेखा है अथवा परिचालनों के पृथक भौगोलिक क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है।
 - (ख) परिचालनों का एक भौगोलिक क्षेत्र है अथवा व्यवसाय की मुख्य रेखा की एक एकल समन्वित निपटान योजना का एक भाग है ; अथवा
 - (ग) जो केवल पुनः बिक्री के आशय से एक अधिगृहीत एक अनुषंगी प्रतिष्ठान है।

33. एक प्रतिष्ठान निम्नलिखित को प्रकट करेगा -

(क) निम्नलिखित के योग से मिलकर बनी लाभ एवं हानि के विवरण में एक एकल राशि : -

- (i) बंद परिचालनों का करोपरांत लाभ अथवा हानि, तथा
- (ii) बंद परिचालन के रूप में गठित आस्तियों या निपटान समूह (समूहों) के निपटान पर अथवा बिक्री की लागत को घटाकर उचित मूल्य के माप पर मान्य करोपरांत लाभ अथवा हानि।

(ख) उपर्युक्त 'क' में एकल राशि का निम्नलिखित में विश्लेषण : -

- (i) बंद परिचालनों का राजस्व, व्यय तथा करपूर्व लाभ अथवा हानि
- (ii) भारतीय लेखा मानक 12 के अनुच्छेद 81 (झ) के द्वारा अपेक्षित संबंधित आयकर व्यय
- (iii) बंद परिचालन के रूप में गठित आस्तियों या निपटान समूह (समूहों) के निपटान पर या बिक्री की लागतों को घटा कर उचित मूल्य के माप पर मान्य लाभ अथवा हानि ; तथा
- (iv) भारतीय लेखा मानक 12 के अनुच्छेद 81 (झ) द्वारा अपेक्षित संबंधित आयकर व्यय।

विश्लेषण को टिप्पणियों में अथवा लाभ तथा हानि के विवरण में प्रस्तुत किया जा सकता है। यदि इसे लाभ तथा हानि के विवरण में प्रस्तुत किया जाता है तो इसे बंद परिचालनों से संबंधित एक अलग खंड में प्रस्तुत किया जायेगा अर्थात् जारी परिचालनों से पृथक। विश्लेषण निपटान समूह

उन नयी अधिगृहीत अनुषंगियों के लिए आवश्यक नहीं है जो अधिग्रहण पर बिक्री के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत होने के मानदंड को पूरा करती है। (देखें अनुच्छेद 11)।

- (ग) बंद परिचालनों की परिचालन, निवेश तथा वित्तपोषण गतिविधियों से जुड़े निवल नकद प्रवाह। इन प्रकटनों को वित्तीय विवरणों में या टिप्पणियों में प्रस्तुत किया जा सकता है। इन प्रकटनों की निपटान समूह के लिए अवश्यकता नहीं है जो अधिग्रहण पर बिक्री के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत होने के मानदंड को पूरा करती है। (अनुच्छेद 11 देखें)
- (घ) मूल प्रतिष्ठान के स्वामियों से संबंधित चालू तथा बंद परिचालनों से आय की राशि। ये प्रकटन टिप्पणियों में अथवा लाभ तथा हानि के विवरणों में प्रस्तुत किये जा सकते हैं।

33.क [देखिये परिशिष्ट 1]।

- 34. एक प्रतिष्ठान वित्तीय विवरणों में प्रस्तुत गत अवधि के लिए अनुच्छेद 33 में प्रकटन को पुनः प्रस्तुत करेगा ताकि प्रकटन उन सभी परिचालनों से प्रस्तुत नवीनतम अवधि के लिए संबंधित रहें जो रिपोर्टिंग अवधि के अंत तक बंद हो गये हैं।
- 35. बंद परिचालन में पहले से प्रस्तुत राशि की चालू अवधि में समायोजन जो गत अवधि में बंद परिचालन के निपटान से सीधा रूप से संबंधित का बंद परिचालन में पृथक रूप से वर्गीकृत किया जायेगा। इस प्रकार के समायोजन की प्रकृति तथा राशि को प्रकट किया जायेगा। इस प्रकार की परिस्थिति के उदाहरण, जिसमें समायोजन उत्पन्न हो सकता है, इस प्रकार हैं :-
 - (क) अनिश्चितता का समाधान जो निपटान लेनदेन की शर्त से उत्पन्न होता है जैसे क्रय कीमत समायोजन का समाधान तथा क्रेता के साथ क्षतिपूर्ति का मुद्दा।
 - (ख) अनिश्चितताओं का समाधान जो निपटान से पूर्व घटक के परिचालन से उत्पन्न होता है तथा सीधे रूप से संबंधित है, जैसे विक्रेता द्वारा रखे गये पर्यायवरण तथा उत्पाद वारंटी संबंधी दायित्व।
 - (ग) कर्मचारी लाभ योजना के दायित्वों का निपटान बशर्ते निपटान सीधे रूप से निपटान लेन-देनों या सौदों से संबंधित है।
- 36. यदि एक प्रतिष्ठान, प्रतिष्ठान के एक घटक को बिक्री हेतु वर्गीकरण में बंद करता है, अनुच्छेद 33-35 के अनुसार बंद परिचालन में पहले से प्रस्तुत घटक का परिचालन का परिणाम को पुनः वर्गीकृत किया जाएगा तथा प्रस्तुत सभी अवधि के लिए जारी परिचालन से आय में सम्मिलित किया जाएगा। पूर्व अवधि के लिए राशि को इस तरह से वर्णित किया जायेगा कि पुनः प्रस्तुत की गई है।
- 36 क. एक प्रतिष्ठान जो कि एक बिक्री योजना के लिए प्रतिबद्ध है जिससे एक अनुषंगी का प्रतिष्ठान से नियंत्रण समाप्त होता है, तो प्रतिष्ठान अनुच्छेद 33-36 में आवश्यक सूचना को प्रकट करेगा, बशर्ते कि अनुषंगी एक निपटान समूह है जो अनुच्छेद 32 के अनुसार बंद परिचालन की परिभाषा को पूरा करता है।

जारी परिचालनों से संबंधित लाभ अथवा हानियां

- 37. बिक्री के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत गैर चालू आस्ति (अथवा निपटान समूह) के, जो एक बंद परिचालन की परिभाषा को पूरा नहीं करती है पुनः माप पर लाभ अथवा हानि को जारी परिचालन से लाभ अथवा हानि में सम्मिलित किया जायेगा।

बिक्री के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत एक गैर चालू आस्ति अथवा निपटान समूह की प्रस्तुति

38. एक प्रतिष्ठान बिक्री के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत गैर चालू आस्ति तथा बिक्री के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत एक निपटान समूह की आस्तियों को तुलन पत्र में अन्य आस्तियों से पृथक प्रस्तुत किया जायेगा। बिक्री के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत एक निपटान समूह की देयताओं से पृथक प्रस्तुत किया जायेगा। उन आस्तियों तथा देयताओं के परस्पर समायोजन (ऑफसेट) तथा एक एकल राशि के रूप में प्रस्तुत नहीं किया जायेगा। बिक्री के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत आस्तियाँ तथा देयताओं की प्रमुख श्रेणी को अनुच्छेद 39 द्वारा अनुमति के सिवाय या तो तुलन पत्र में अथवा टिप्पणियों में पृथक रूप से प्रकट किया जायेगा। एक प्रतिष्ठान बिक्री के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत एक चालू आस्ति (अथवा निपटान समूह) से संबंधित किसी संग्रहीत आय अथवा व्यय को जिसे अन्य व्यापक आय में मान्यता दी गयी है, पृथक रूप से प्रस्तुत करेगा।
39. यदि निपटान समूह एक नयी अधिगृहीत अनुषंगी है जो अधिग्रहण पर बिक्री के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत होने के मानदंड को पूरा करती है, (अनुच्छेद 11 देखें) तो आस्तियों तथा देयताओं की प्रमुख श्रेणी के प्रकटन की आवश्यकता नहीं है।
40. एक प्रतिष्ठान प्रस्तुत नवीनतम अवधि के लिए तुलन पत्र में वर्गीकृत को परिलक्षित करने के लिए पूर्व अवधि के लिए तुलन पत्र में बिक्री के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत एक निपटान समूह की आस्ति तथा देयताओं अथवा गैर चालू आस्ति बिक्री के धारित के लिए राशि को पुनः वर्गीकृत अथवा पुनः प्रस्तुत नहीं करेगा।

अतिरिक्त प्रकटन

41. एक प्रतिष्ठान अवधि में जिसमें, एक गैर चालू आस्ति (अथवा निपटान समूह) को बिक्री के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत किया गया है अथवा बेचा गया है, निम्नलिखित सूचना को टिप्पणियों में प्रकट करेगा :
- (क) गैर चालू आस्ति (अथवा निपटान समूह) का विवरण ;
 - (ख) बिक्री के तथ्यों तथा परिस्थितियों अथवा प्रत्याशित निपटान की तरफ ले जाने वाले तथ्यों व परिस्थितियों का वर्णन तथा उस निपटान की प्रत्याशित विधि तथा समय ;
 - (ग) अनुच्छेद 20-22 के अनुसार मान्य लाभ अथवा हानि तथा, यदि इसे लाभ तथा हानि के विवरण में अलग-से प्रस्तुत नहीं किया गया है, तो लाभ अथवा हानि के विवरण में लाभ या हानि का शीर्ष जिसमें ये लाभ व हानि सम्मिलित हैं।
 - (घ) यदि लागू है, रिपोर्ट योग्य खंड जिसमें गैर चालू आस्ति (अथवा निपटान समूह) को भारतीय लेखा मानक 108 परिचालन खंड के अनुसार प्रस्तुत किया गया है।
42. यदि अनुच्छेद 26 अथवा 29 लागू होता है तो एक प्रतिष्ठान उस अवधि के दौरान, जिसमें कि गैर-चालू आस्ति (या निपटान समूह) की बिक्री की योजना को बदलने का निर्णय लेता है, निर्णय लेने के तथ्यों व परिस्थितियों का वर्णन और उस अवधि और पूर्व की प्रस्तुत किसी अवधि के परिचालनों के परिणामों के निर्णय के प्रभाव को प्रकट करेगा।

परिशिष्ट 'क'**परिभाषित शब्दावली**

यह परिशिष्ट इस भारतीय लेखा मानक का अभिन्न अंग है।

नकद सृजक इकाई : आस्तियों का सबसे छोटा पहचानयोग्य समूह जो नकद अन्तर्प्रवाहों को सृजित करता है और जो मुख्यतया अन्य आस्ति अथवा आस्तियों के समूह के नकद प्रवाहों से स्वतंत्र है।

एक प्रतिष्ठान का घटक : नकद प्रवाह तथा परिचालन जिन्हें स्पष्ट रूप से परिचालन तथा वित्तीय रिपोर्टिंग के प्रयोजन के लिए, प्रतिष्ठान के भाग से अलग किया जा सकता है।

बिक्री लागतें : वित्त लागतों तथा आयकर व्ययों को छोड़कर आस्ति (अथवा निपटान समूह) के निपटान से प्रत्यक्षतया संबंधित वृद्धिशील लागतें।

चालू आस्ति : एक प्रतिष्ठान एक आस्ति को चालू आस्ति के रूप में तब वर्गीकृत करेगा जब :

- (क) यह सामान्य परिचालन चक्र में, आस्ति से राशियां प्राप्त करने अथवा इसकी बिक्री करने अथवा इसका उपभोग करने की आशा करता है।
- (ख) यह व्यापार के उद्देश्य के लिए आस्ति को मुख्यतः धारित करता है।
- (ग) यह रिपोर्टिंग अवधि के पश्चात् बारह माह के अंदर आस्ति के निपटान से राशि प्राप्त करने की आशा करता है।
- (घ) आस्ति नकद अथवा नकद समतुल्य है, [जैसा कि भारतीय लेखा मानक 7 में परिभाषित है] जब तक आस्ति को रिपोर्टिंग अवधि के पश्चात् कम से कम बारह माह के लिए विनिमय करने अथवा देयता के निपटान करने के लिए परिसीमित न किया गया हो।

बंद परिचालन : एक प्रतिष्ठान का एक घटक जिसका या तो निपटान कर दिया गया है अथवा उसे बिक्री के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत किया गया है तथा :-

- (क) जो व्यवसाय की प्रमुख रेखा अथवा परिचालन के एक भौगोलिक क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है,
- (ख) व्यापार की पृथक प्रमुख रेखा अथवा परिचालनों का एक भौगोलिक क्षेत्र के निपटान की एकल समन्वित योजना का एक भाग ; अथवा
- (ग) केवल पुनः बिक्री के आशय के रूप में अधिगृहीत एक अनुषंगी प्रतिष्ठान है।

निपटान समूह : एक एकल लेन-देन या सौदा में एक समूह के रूप में बिक्री अथवा अन्यथा के द्वारा निपटान की जाने वाली आस्ति का समूह तथा उन आस्तियों के साथ प्रत्यक्षतया से

संबंधित देयताएं जिन्हें लेन-देन में अंतरित किया जायेगा। समूह में एक व्यावसायिक संयोजन में अधिगृहीत ख्याति (गुडविल) भी इसमें सम्मिलित है यदि समूह एक नकद सृजक इकाई है जिसमें ख्याति (गुडविल) को भारतीय लेखा मानक 36 आस्तियों की क्षतिग्रस्तता के अनुच्छेद 80-87 की अपेक्षा के अनुसार आबंटित किया गया है या यह नकद सृजक इकाई में एक परिचालन है।

- उचित मूल्य** : राशि जिसके लिए आस्ति को स्वतंत्र लेन-देन में ज्ञानवान एवं इच्छुक पक्षों के मध्य विनिमय किया जा सकता है, अथवा देयता का निपटान किया जा सकता है।
- पक्की क्रय प्रतिबद्धता** : असंबद्ध पक्ष के साथ एक ऐसा समझौता, जो दोनों पक्षों पर बाध्य है तथा प्रायः कानूनी रूप से प्रवर्तनीय है तथा (क) लेन-देनों के समय तथा कीमत सहित सभी महत्वपूर्ण उल्लेखनीय शर्तों को विनिर्दिष्ट करता है तथा (ख) गैर निष्पादन को निरुत्साहित करता है जो निष्पादन की अधिक संभावना के लिए विशेष रूप से संभावक है।
- अति संभावक** : संभावक से अधिक संभव।
- गैर चालू आस्ति** : एक आस्ति जो चालू आस्ति की परिभाषा को पूरा नहीं करती।
- संभावक** : जिसके होने की संभावना न होने से अधिक हो।
- वसूली-योग्य राशि** : आस्ति का बिक्री की लागत को घटाकर उचित मूल्य तथा इसके उपयोग का मूल्य, इनमें से जो राशि अधिक है।
- उपयोग का मूल्य** : एक आस्ति के निरन्तर उपयोग से उत्पन्न होने तथा इसके उपयोगी जीवन के अंत पर निपटान से अपेक्षित अनुमानित भावी नकद प्रवाह का वर्तमान मूल्य।

परिशिष्ट 'ख'

प्रयोग-संबंधी पूरक

यह परिशिष्ट इस भारतीय लेखा मानक का अभिन्न अंग है।

एक बिक्री को पूर्ण करने के लिए अपेक्षित अवधि का विस्तार

ख 1. जैसा कि अनुच्छेद 9 में नोट किया गया है, एक बिक्री को पूर्ण करने के लिए अपेक्षित अवधि का विस्तार एक आस्ति (अथवा निपटान समूह) को बिक्री के लिए धारित के रूप में रोकता नहीं है यदि देरी प्रतिष्ठान के नियंत्रण के बाहर परिस्थिति अथवा घटना के कारण हुई है तथा इस बात का पर्याप्त साक्ष्य है कि प्रतिष्ठान आस्ति (अथवा निपटान समूह) को बेचने की अपनी योजना के प्रति प्रतिबद्ध है। अनुच्छेद 8 में एक वर्ष की अपेक्षा का अपवाद इसलिए निम्न स्थितियों में लागू होता है, जिसमें इस प्रकार की घटनाएं अथवा परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं :-

(क) जिस तिथि पर एक प्रतिष्ठान स्वयं गैर चालू आस्ति (अथवा निपटान समूह) को बेचने की योजना के प्रति प्रतिबद्ध है, यह उचित रूप से आशा करता है कि अन्य (लेकिन क्रेता नहीं) आस्ति (अथवा निपटान समूह) के अंतरण पर शर्तें लगाएंगे जो बिक्री को पूर्ण करने के लिए अपेक्षित अवधि को बढ़ायेगा, तथा

(ii) उन शर्तों के प्रत्युत्तर के लिए आवश्यक कार्यवाही जिसे एक मजबूत क्रय प्रतिबद्धता के प्राप्त होने तक आरंभ नहीं किया जा सकता ;

(ii) एक पक्की क्रय प्रतिबद्धता जो एक वर्ष के भीतर अति संभावक है।

(ख) एक प्रतिष्ठान एक पक्की क्रय प्रतिबद्धता को प्राप्त करता है तथा परिणामस्वरूप एक क्रेता अथवा अन्य अप्रत्याशित रूप से पहले से बिक्री के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत गैर चालू आस्ति (अथवा निपटान समूह) के अंतरण पर शर्त लगाता है जो बिक्री को पूर्ण करने के लिए अपेक्षित अवधि को बढ़ायेगा।

(i) उन शर्तों के प्रत्युत्तर में आवश्यक और समय रहते कार्यवाही कर ली गयी है ;

(ii) विलम्ब के कारणों का अनुकूल समाधान प्रत्याशित।

(ग) आरंभिक एक वर्ष की अवधि के दौरान, ऐसे हालात उत्पन्न होते हैं जिन्हें पहले संभव नहीं माना गया था तथा परिणामस्वरूप, बिक्री के लिए धारित के रूप में पहले से वर्गीकृत एक गैर चालू आस्ति (अथवा निपटान समूह) को इस अवधि के अंत तक बेचा नहीं गया, तथा :

(i) आरंभिक एक वर्ष अवधि के दौरान प्रतिष्ठान ने परिस्थिति में परिवर्तन के प्रत्युत्तर के लिए आवश्यक कार्यवाही की ;

(ii) गैर चालू आस्ति (अथवा निपटान समूह) का एक कीमत पर सक्रिय रूप से विपणन जो परिस्थिति के परिवर्तन में उचित है ;

(iii) अनुच्छेद 7 तथा 8 में मानदंडों को पूरा किया गया।

परिशिष्ट ' ग '

अन्य भारतीय लेखा मानकों में समाविष्ट मामलों के संदर्भ

यह परिशिष्ट भारतीय लेखा मानक 105 का एक अभिन्न अंग है।

यह परिशिष्ट भारतीय लेखा मानक 10 रिपोर्टिंग अवधि के पश्चात् की घटनाएं में समाविष्ट परिशिष्ट 'क' स्वामियों को गैर नकद आस्तियों का वितरण के लिए एक संदर्भ का कार्य करता है।

परिशिष्ट ' घ '

विषय वस्तु

भारतीय लेखा मानक 105 बिक्री के लिए धारित गैर चालू आस्तियां तथा बंद परिचालन के कार्यान्वयन पर मार्गदर्शन

तुरन्त बिक्री के लिए उपलब्धता (अनुच्छेद 7)	उदाहरण 1 - 3
एक वर्ष के अंदर प्रत्याशित बिक्री की पूर्णता (अनुच्छेद 8)	उदाहरण 4
एक वर्ष के अंदर प्रत्याशित बिक्री की पूर्णता (अनुच्छेद 8 और ख 1) के मानदंड के अपवाद	उदाहरण 5- 7
यह निर्धारित करना कि क्या आस्ति का परित्याग कर दिया गया है (अनुच्छेद 13 तथा 14)	उदाहरण 8
परित्याग किये गये बन्द परिचालन की प्रस्तुति (अनुच्छेद 13)	उदाहरण 9

निपटान समूह पर क्षतिग्रस्तता हानि का आबंटन (अनुच्छेद 23)	उदाहरण 10
लाभ तथा हानि के विवरण में बंद परिचालनों की प्रस्तुति (अनुच्छेद 38)	उदाहरण 11
गैर चालू आस्ति अथवा निपटान समूह की, जो बिक्री के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत है, प्रस्तुति (अनुच्छेद 38)	उदाहरण 12
पुनः बिक्री के विचार से अधिगृहीत और बिक्री के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत अनुषंगियों का माप एवं प्रस्तुति (अनुच्छेद 11 - 38)	उदाहरण 13
भारतीय लेखा मानक 105 बिक्री के लिए धारित गैर चालू आस्तियां तथा बंद परिचालन के कार्यान्वयन पर मार्गदर्शन	

यह मार्गदर्शन भारतीय लेखा मानक 105 का संलग्नक है परन्तु इसका अंग नहीं है

तुरन्त बिक्री के लिए उपलब्धता (अनुच्छेद 7)

बिक्री के लिए धारित के रूप में वर्गीकरण की अहर्ता के लिए, एक गैर चालू आस्ति (अथवा निपटान समूह) वर्तमान स्थिति में तुरन्त बिक्री के लिए उपलब्ध होना चाहिए, जो केवल उन शर्तों के तहत हो जो इस प्रकार की आस्ति (अथवा निपटान समूह) की बिक्री के लिए प्रचलित तथा पारम्परिक हैं (अनुच्छेद 7)। एक गैर चालू आस्ति (अथवा निपटान समूह) तुरन्त बिक्री के लिए तब उपलब्ध है यदि एक प्रतिष्ठान वर्तमान समय में इस स्थिति में है कि एक क्रेता को आस्ति (अथवा निपटान समूह) का अंतरण के लिए इच्छुक व योग्य हो। उदाहरण 1-3 उन स्थितियों के उदाहरण हैं जिनमें अनुच्छेद 7 में दिये गये मानदंड पूरे होते हैं या पूरे नहीं भी होते हैं।

उदाहरण 1

एक प्रतिष्ठान अपने मुख्य कार्यालय के भवन को बेचने की योजना के लिए प्रतिबद्ध है तथा उसने क्रेता को खोजने के लिए कार्यवाही आरंभ कर दी है।

- (क) प्रतिष्ठान भवन को खाली करने के पश्चात् क्रेता को उसे अंतरित करने की इच्छा रखता है। भवन को खाली करने के लिए आवश्यक समय इस प्रकार की आस्तियों की बिक्री के लिए प्रचलित तथा पारम्परिक है। अनुच्छेद 7 का मानदंड योजना की प्रतिबद्धता तिथि को पूरा किया जायेगा।
- (ख) प्रतिष्ठान भवन को नये कार्यालय भवन के पूरा होने तक प्रयुक्त करना जारी रखेगा। प्रतिष्ठान एक क्रेता को नये भवन की निर्माण की पूर्णता तक (तथा मौजूदा भवन को खाली करने तक) मौजूदा भवन को अंतरित करने का इरादा नहीं रखता है। प्रतिष्ठान (विक्रेता) द्वारा मौजूदा भवन को खाली करने के लिए विलम्ब का समय यह प्रदर्शित करता है कि भवन तुरन्त बिक्री के लिए उपलब्ध नहीं है। अनुच्छेद 7 का मानदंड पूरा नहीं होगा जब तक नये भवन का निर्माण पूरा नहीं हो जाता यहां तक कि यदि मौजूदा भवन भविष्य में अंतरण के लिए पक्की क्रय प्रतिबद्धता पहले ही प्राप्त कर ली है।

उदाहरण 2

एक प्रतिष्ठान एक निर्माण सुविधा को बेचने के लिए प्रतिबद्ध है तथा उसने एक क्रेता को खोजने के लिए कार्यवाही आरंभ कर दी है। योजना प्रतिबद्धता तिथि पर, ग्राहकों के कुछ ऐसे आर्डर बकाया है जो अभी पूरे नहीं किये गये हैं।

- (क) प्रतिष्ठान अपने परिचालनों के साथ निर्माणी सुविधा की बिक्री में इच्छुक है। बिक्री तिथि पर किसी ग्राहक का यदि कोई भी अपूर्ण आर्डर है तो उन्हें क्रेता को अंतरित कर दिया जायेगा। बिक्री तिथि पर अपूर्ण ग्राहक आर्डरों का अंतरण सुविधा के अंतरण के समय को प्रभावित नहीं करेगा। इस तरह से, अनुच्छेद 7 में दिये गये मानदंड, योजना की प्रतिबद्धता तिथि को पूरे होंगे।
- (ख) प्रतिष्ठान अपने परिचालनों के बिना निर्माणी सुविधा को बेचने का इरादा रखता है। प्रतिष्ठान सुविधा के सभी परिचालनों की समाप्ति तथा ग्राहकों के अपूर्ण आर्डरों को पूरा करने तक क्रेता को सुविधा अंतरित करने का इरादा नहीं रखता। प्रतिष्ठान (विक्रेता) के द्वारा लगायी सुविधा तुरन्त बिक्री के लिए उपलब्ध नहीं है। अनुच्छेद 7 में दिये गये मानदंड पूरा नहीं होंगे जब तक कि सुविधा का परिचालन बंद नहीं हो जाता चाहे सुविधा को भविष्य में अंतरित करने का पक्की क्रय प्रतिबद्धता पहले से ही प्राप्त कर ली थी।

उदाहरण 3

एक प्रतिष्ठान 'फोरक्लोसर' द्वारा एक सम्पत्ति का अधिग्रहण करता है जिसमें वह भूमि व भवन है जिसे वह बेचने का इरादा रखता है।

- (क) प्रतिष्ठान एक क्रेता को आस्ति के हस्तांतरण का इरादा तब तक नहीं रखता, जब तक कि वह उसका पुनरुद्धार न कर ले चूंकि इससे उसका बिक्री मूल्य बढ़ जायेगा। प्रतिष्ठान (विक्रेता) द्वारा लगायी जा रही आस्ति के हस्तांतरण में समय में देरी यह प्रदर्शित करती है कि आस्ति तुरन्त बिक्री के लिए उपलब्ध नहीं है। अनुच्छेद 7 में दिये गये मानदंड पुनरुद्धार के पूरा होने तक पूरे नहीं होंगे।
- (ख) पुनरुद्धार का कार्य पूरा होने के पश्चात् तथा आस्ति के बिक्री के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत करने पर है परन्तु पक्की क्रय प्रतिबद्धता को प्राप्त करने से पूर्व प्रतिष्ठान को पर्यायवरण क्षति के बारे में पता चलता है। जिसे ठीक करना आवश्यक हो जाता है और प्रतिष्ठान फिर भी आस्ति को बेचने का इरादा रखता है यद्यपि, प्रतिष्ठान ठीक होने तक क्रेता को आस्ति को अंतरण करने की योग्यता नहीं रखता है। पक्की क्रय प्रतिबद्धता को प्राप्त करने से पूर्व अन्य द्वारा लगायी आस्ति के अंतरण के समय में देरी प्रदर्शित करती है कि आस्ति तुरन्त बिक्री के लिए उपलब्ध नहीं है। इस तरह, अनुच्छेद 7 में दिये गये मानदंड पूरे नहीं होंगे। आस्ति को धारित तथा प्रयुक्त पुनः वर्गीकृत अनुच्छेद 26 के अनुसार, किया जायेगा।

एक वर्ष के अंदर प्रत्याशित अपेक्षित बिक्री की पूर्णता (अनुच्छेद 8)

उदाहरण 4

बिक्री के लिए धारित के रूप में वर्गीकरण की अहर्ता के लिए, गैर-चालू आस्ति (अथवा निपटान समूह) की बिक्री बहुत संभावित होनी चाहिए (अनुच्छेद 7) तथा आस्ति (अथवा निपटान समूह) का अंतरण एक वर्ष के अंदर पूर्ण बिक्री के रूप में मान्यता की अहर्ता के लिए प्रत्याशित होना चाहिए (अनुच्छेद 8)। महत्वपूर्ण उक्त मानदंड तब तक पूरा नहीं होगा जब तक, उदाहरणतया :

- (क) एक प्रतिष्ठान वाणिज्यिक पट्टा तथा वित्त कंपनी है। इसके पास बिक्री अथवा पट्टा के लिए एक यंत्र जिस पर हाल में पट्टा समाप्त हो गया है तथा भविष्य में इसके लेन-देन (बिक्री अथवा पट्टा) के अंतिम स्वरूप का अभी निर्धारण नहीं किया गया है।
- (ख) प्रतिष्ठान की एक आस्ति है जो उपयोग में है। प्रतिष्ठान इसकी 'बिक्री' की योजना के लिए प्रतिबद्ध है तथा आस्ति का अंतरण बिक्री तथा वित्तीय लीज बैंक के रूप में लेखांकित किया जायेगा।

अनुच्छेद 8 में दिये गये मानदंड के अपवाद

अनुच्छेद 8 में एक वर्ष की अपेक्षा का एक अपवाद सीमित स्थितियों में लागू होता है जिनमें एक गैर चालू आस्ति (अथवा निपटान समूह) की बिक्री को पूरा करने के लिए अपेक्षित अवधि को, प्रतिष्ठान के नियंत्रण से बाहर की घटनाओं अथवा परिस्थितियों के मामले में, और आगे बढ़ाया जायेगा यदि विनिर्दिष्ट शर्तें पूरी होती हैं (अनुच्छेद 9 तथा ख 1) उदाहरण 5-7 में उन स्थितियों का वर्णन करते हैं।

उदाहरण 5

विद्युत उत्पादन उद्योग में एक प्रतिष्ठान एक निपटान समूह की बिक्री की योजना के लिए प्रतिबद्ध है जो विनियमित परिचालनों का एक उल्लेखनीय अंग का प्रतिनिधित्व करता है। बिक्री विनियम प्राधिकरण के अनुमोदन की अपेक्षा है जिससे बिक्री को पूरा होने की अवधि एक वर्ष आगे बढ़ जायेगी। उस अनुमोदन को प्राप्त करने की आवश्यक कार्यवाही को तब तक आरंभ नहीं किया जा सकता जब तक क्रेता उपलब्ध न हो तथा पक्की क्रय प्रतिबद्धता प्राप्त न हो गयी हो। यद्यपि, पक्की क्रय प्रतिबद्धता एक वर्ष के अंदर अति संभावित है। उस स्थिति में, एक वर्ष की अपेक्षा के अपवाद के लिए अनुच्छेद ख 1 (क) में दी गयी शर्त को पूरा किया जायेगा।

उदाहरण 6

एक प्रतिष्ठान मौजूदा स्थिति में एक निर्माणी सुविधा को बेचने की योजना के लिए प्रतिबद्ध है तथा उस तिथि पर इस सुविधा को बिक्री के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत करता है। पक्की क्रय प्रतिबद्धता को प्राप्त करने के पश्चात् क्रेता द्वारा आस्ति का निरीक्षण करने पर यह पाया गया कि उसमें पर्यावरण संबंधी क्षति है और इस संबंध में प्रतिष्ठान को पूर्व में कोई जानकारी नहीं थी। क्रेता प्रतिष्ठान से यह भी अपेक्षा करता है कि वह क्षति को सही करने के लिए कार्यवाही करे, जिससे बिक्री को एक वर्ष से अधिक की अवधि के लिए बढ़ाया जाएगा यद्यपि, प्रतिष्ठान ने क्षतिपूर्ति के लिए कार्यवाही शुरू कर दी है तथा क्षति के संतोषजनक सुधार के प्रति अति संभावक है। उस स्थिति में, अनुच्छेद 8 के एक वर्ष के अपवाद की अपेक्षा के लिए, अनुच्छेद ख 1(ख) की शर्तें पूरी की जाएंगी।

उदाहरण 7

एक प्रतिष्ठान एक गैर चालू आस्ति की बिक्री की योजना के लिए प्रतिबद्ध है तथा उस तिथि पर बिक्री के लिए आस्ति को वर्गीकृत करता है।

- (क) आरंभ की एक वर्ष की अवधि के दौरान, जिस तिथि पर आस्ति को प्रारम्भ में बिक्री के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत किया गया था, बाजार की मौजूदा परिस्थितियों में जब गिरावट आ गयी है तथा इसके परिणामस्वरूप आस्ति को उस अवधि के अंत तक बेचा नहीं गया था। उस अवधि के दौरान हालांकि प्रतिष्ठान ने सक्रिय रूप से आग्रह भी किया था परन्तु आस्ति के क्रय के लिए कोई उचित प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ और इस कारण कीमत को कम करना पड़ा। एक ऐसी कीमत पर आस्ति का सक्रिय रूप से विपणन करना जारी रहा, जो कि बाजार की स्थिति को देखते हुए उचित है और इस तरह अनुच्छेद 7 तथा 8 में दिया गया मानदंड पूरा हो जाता है। उस स्थिति में, अनुच्छेद 8 की एक वर्ष की अपेक्षा का

अपवाद अनुच्छेद ख 1 (ग) की शर्तों को पूरा करता है। आरंभ के एक वर्ष की अवधि के अंत पर, आस्ति को बिक्री के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत किया जाना जारी रहेगा।

- (ख) बाद की एक वर्ष की अवधि के दौरान बाजार की परिस्थितियां आगे और खराब हो जाती हैं, तथा आस्ति को उस अवधि के अंत तक भी बेचा नहीं जाता है। प्रतिष्ठान विश्वास करता है कि बाजार की परिस्थिति सुधर जाएगी तथा इस आशा में वह आस्ति की कीमत को आगे और कम नहीं करता है। आस्ति बिक्री के लिए धारित के रूप में जारी रहती है परन्तु इसके वर्तमान उचित मूल्य से अधिक की कीमत पर। उस स्थिति में, कीमत में कमी का अभाव यह प्रदर्शित करता है कि आस्ति तुरन्त बिक्री के लिए उपलब्ध नहीं है, जैसा कि अनुच्छेद 7 के द्वारा अपेक्षित है। इसके अतिरिक्त, अनुच्छेद 8 एक आस्ति को एक कीमत पर विपणन करने की अपेक्षा करता है जो इसके वर्तमान उचित मूल्य के संबंध में उचित है। इसलिए, अनुच्छेद 8 का एक वर्ष की अपेक्षा का अपवाद अनुच्छेद ख 1 (ग) की शर्तों को पूरा नहीं करता। आस्ति को अनुच्छेद 26 के अनुसार प्रयुक्त तथा धारित के रूप में पुनः वर्गीकृत किया जायेगा।

यह निर्धारित करना कि क्या आस्ति का परित्याग कर दिया गया है।

इस भारतीय लेखा मानक के अनुच्छेद 13 तथा 14 उन अपेक्षाओं को विनिर्दिष्ट करते हैं कि आस्तियों को कब परित्याग के रूप में माना जाएगा। उदाहरण 8 यह दृष्टांत देता है कि कब आस्ति का परित्याग नहीं हुआ है।

उदाहरण 8

एक प्रतिष्ठान एक निर्माणी संयंत्र का उपयोग को बंद करता है, क्योंकि इसके उत्पाद की मांग में कमी आ गयी है। लेकिन, संयंत्र को कार्य-योग्य स्थिति में रखा गया है। इस आशा के साथ कि जैसे ही मांग में वृद्धि होगी इसे वापस उपयोग में लाया जायेगा। ऐसे में संयंत्र को परित्याग के रूप में नहीं माना जाता।

बंद परिचालन की प्रस्तुति जिसका परित्याग कर दिया गया है।

इस भारतीय लेखा मानक का अनुच्छेद 13 उन आस्तियों के परित्याग के लिए प्रतिषेद्ध करता है जो बिक्री के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत हैं। फिर भी, यदि परित्याग की जाने वाली आस्तियां व्यवसाय की प्रमुख लाइन अथवा परिचालनों का भौगोलिक क्षेत्र हैं तो उन्हें परित्याग की तिथि को बंद परिचालनों के रूप में रिपोर्ट किया जाता है। उदाहरण 9 में इसका दृष्टांत दिया गया है :-

उदाहरण 9

अक्टूबर 20 x 5 में एक प्रतिष्ठान अपनी सभी सूती कपड़े के कारखानों का परित्याग करने का निर्णय लेता है। यह व्यवसाय की प्रमुख लाइन है, 31 दिसम्बर 20 x 6 की समाप्ति पर सूती कपड़े के कारखानों के सभी कार्य बंद हो जाते हैं। 31 दिसम्बर 2005 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरणों में सूती कपड़े के कारखानों के परिणामों तथा नकदी प्रवाहों को जारी परिचालनों के रूप में माना जाता है। लेकिन, 31 दिसम्बर 20 x 6 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरणों में, सूती कपड़े के कारखानों के परिणामों तथा नकदी प्रवाहों को बंद परिचालनों के रूप में माना जाएगा तथा प्रतिष्ठान इसे भारतीय लेखा मानक के अनुच्छेद 33 तथा 34 की अपेक्षानुसार प्रकट करता है।

निपटान समूह की क्षतिग्रस्तता हानि का आबंटन

इस भारतीय लेखा मानक का अनुच्छेद 23 यह अपेक्षा करता है कि एक क्षतिग्रस्तता हानि (या कोई उत्तरवर्ती लाभ) जिसे एक निपटान समूह के लिए, गैर चालू आस्तियों, जो कि समूह की अग्रणीत (कैरिंग) राशि को कम (या ज्यादा) पर मान्यता देता है और इस भारतीय लेखा मानक की माप अपेक्षाओं के कार्य क्षेत्र में ही है और यह भारतीय लेखा मानक 36 के अनुच्छेद 104 तथा 122 के निर्धारित आवंटन क्रम में है। नीचे दिया गया उदाहरण 10 निपटान समूह पर क्षतिग्रस्तता हानि के आबंटन का दृष्टांत है।

उदाहरण 10

एक प्रतिष्ठान अपनी आस्तियों (एक आस्ति को बिक्री के रूप में) के समूह के निपटान की योजना बनाता है। आस्तियां एक निपटान समूह बनाती हैं तथा इन्हें इस तरह मापा जाता है :-

	बिक्री के लिए धारित वर्गीकरण से पूर्व रिपोर्टिंग अवधि के अंत की अग्रणीत (कैरिंग) राशि	बिक्री के लिए धारित वर्गीकरण से एक दम पूर्व पुनः मापी गयी अग्रणीत (कैरिंग) राशि
	रुपये	रुपये
ख्याति (गुडविल)	1,500	1,500
संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर (पुनः मूल्यांकित राशि पर लिया गया)	4,600	4,000
संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर [लागत पर अग्रणीत (कैरिंग) राशि]	5,700	5,700
सूचीबद्ध सामान (इंवेन्टरी)	2,400	2,200
बिक्री के लिए उपलब्ध वित्तीय आस्तियां	1,800	1,500
कुल योग	16,000	14,900

प्रतिष्ठान 1100 रुपये (रुपये 16000 - 14900 रुपये) की हानि बिक्री के लिए धारित के रूप में निपटान समूह के वर्गीकरण के एकदम पूर्व मान्यता देता है।

प्रतिष्ठान निपटान समूह की बिक्री की लागत को घटाकर उचित मूल्य रुपये 13000 पर अनुमान लगाती है। क्योंकि, प्रतिष्ठान अग्रणीत बिक्री के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत निपटान समूह को अग्रणीत (कैरिंग) राशि और बिक्री लागतें घटाकर उचित मूल्य, इनमें जो भी कम है उस पर मापता है। प्रतिष्ठान 1900 रुपये (14900

- 13000 रुपये) की क्षतिग्रस्तता हानि को मान्यता देता है जब समूह बिक्री के लिए धारित के रूप में आरंभ में वर्गीकृत किया गया है।

क्षतिग्रस्तता हानि, गैर चालू आस्ति को आबंटित किया गया है जिसमें भारतीय लेखा मानक की माप अपेक्षाएं लागू हैं। इसलिए, किसी क्षतिग्रस्तता हानि को इन्वेन्टरी तथा बिक्री के लिए उपलब्ध वित्तीय आस्तियों पर आबंटित नहीं किया गया। हानि को भारतीय लेखा मानक 36 के अनुच्छेद 104 तथा 122 में निर्धारित आबंटन के क्रम में अन्य आस्ति को आबंटित किया गया है। आबंटन को निम्नलिखित दृष्टांत के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है।

	बिक्री के लिए धारित वर्गीकरण से एक दम पहले पुनः माप के रूप में अग्रणीत (कैरिंग) राशि	आबंटित क्षतिग्रस्तता हानि	क्षतिग्रस्तता हानि के आबंटन के पश्चात् अग्रणीत (कैरिंग) राशि
	रुपये	रुपये	रुपये
ख्याति (गुडविल)	1,500	(1500)	0
संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर (पुनः मूल्यांकित राशि पर लिया गया)	4,000	(165)	3,835
संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर लागत पर लिया गया)	5,700	(235)	5,465
सूचीबद्ध माल (इन्वेन्टरी)	2,200	-	2,200
बिक्री के लिए उपलब्ध वित्तीय आस्तियां	1,500	-	1,500
कुल योग	14,900	(1900)	13,000

पहले, क्षतिग्रस्तता हानि प्रतिष्ठा (गुडविल) की किसी राशि को कम करती है। तब, बाकी हानि को उन आस्तियों की अग्रणीत (कैरिंग) राशि पर आनुपातिक आधार पर अन्य आस्तियों में आबंटित किया जाता है।

लाभ तथा हानि के विवरण में बंद परिचालनों की प्रस्तुति

भारतीय लेखा मानक का अनुच्छेद 33 एक प्रतिष्ठान को बंद परिचालनों के मामले में लाभ तथा हानि के विवरण में एक राशि में और टिप्पणियों में विश्लेषण के साथ अथवा लाभ तथा हानि के विवरण में एक खंड में जारी परिचालनों से पृथक प्रकट करने की अपेक्षा करता है। उदाहरण 11 इन अपेक्षाओं को पूरा करने का दृष्टांत प्रस्तुत करता है।

उदाहरण 11

'एक्स बाई जेड' समूह का 31 दिसम्बर 20x2 को समाप्त वर्ष का लाभ तथा हानि विवरण (कार्य के द्वारा व्यय के वर्गीकरण का उदाहरण)

	(रुपये हजार में)	
	20x2	20x1
जारी परिचालन		
राजस्व	X	X
बिक्री लागतें	<u>(X)</u>	<u>(X)</u>
सकल लाभ	X	X
अन्य आय	X	X
वितरण लागतें	(X)	(X)
प्रशासकीय व्यय	(X)	(X)
अन्य व्यय	(X)	(X)
वित्तीय लागतें	(X)	(X)
सहयोगी प्रतिष्ठानों के लाभ का हिस्सा	<u>X</u>	<u>X</u>
कर पूर्व लाभ	X	X
आय कर व्यय	<u>(X)</u>	<u>(X)</u>
जारी परिचालनों से अवधि का लाभ	<u>X</u>	<u>X</u>
बंद परिचालन		
बंद परिचालनों से अवधि का लाभ ⁸	<u>X</u>	<u>X</u>
अवधि का लाभ	<u><u>X</u></u>	<u><u>X</u></u>
 निम्नलिखित से संबंधित :		
मूल प्रतिष्ठान के स्वामी		
जारी परिचालनों से अवधि का लाभ	X	X
बंद परिचालनों से अवधि का लाभ	<u>X</u>	<u>X</u>

⁸ आवश्यक विश्लेषण टिप्पणियों में दिया जाएगा।

मूल प्रतिष्ठान के स्वामी का संबंधित अवधि का लाभ	X	X
गैर नियंत्रित हित		
चालू परिचालनों से अवधि का लाभ	X	X
बंद परिचालनों से अवधि का लाभ	<u>X</u>	<u>X</u>
गैर नियंत्रित हित से संबंधित अवधि का लाभ	<u>X</u>	<u>X</u>
	<u><u>X</u></u>	<u><u>X</u></u>

बिक्री के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत गैर चालू आस्तियों अथवा निपटान समूहों की प्रस्तुति

भारतीय लेखा मानक अनुच्छेद 38 एक प्रतिष्ठान के तुलन पत्र में अन्य आस्तियों से पृथक रूप में बिक्री के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत एक निपटान समूह की आस्ति तथा बिक्री के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत गैर चालू आस्ति का प्रस्तुत करने की अपेक्षा करता है। बिक्री के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत निपटान समूह की देयता पृथक रूप से प्रस्तुत की जाती है। उन आस्तियों तथा देयताओं को परस्पर समायोजित (ऑफसेट) तथा, एक एकल राशि के रूप में प्रस्तुत नहीं किया जाता। उदाहरण 12 इस अपेक्षा का दृष्टांत प्रस्तुत करता है।

उदाहरण 12

20 x 5 के अंत पर, एक प्रतिष्ठान अपनी आस्तियों (तथा प्रत्यक्ष संबंधित देयताओं) के एक भाग के निपटान का निर्णय लेता है। निपटान, जो अनुच्छेद 7 तथा 8 में दिये गये मानदंड को पूरा करता है, बिक्री के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत, दो निपटान समूहों का स्वरूप लेता है जो इस प्रकार है :

	बिक्री के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत के पश्चात् अग्रणीत (कैरिंग) राशि	
	निपटान समूह I	निपटान समूह II
संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर	4,900	1,700
बिक्री के लिए उपलब्ध वित्तीय आस्ति	1,400 ⁹	-
देयताएं	(2,400)	(9,00)
निपटान समूह की निवल अग्रणीत (कैरिंग) राशि	3,900	8,00

⁹ इन आस्तियों से संबंधित 400 रुपये की राशि को अन्य व्यापक आय में मान्यता दी गयी है और इसे 'इक्विटी' में संचित किया गया है।

बिक्री के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत निपटान समूह की प्रतिष्ठान के तुलन-पत्र में प्रस्तुति

	20x5	20x4
आस्तियां		
गैर चालू आस्तियां		
क क क	X	X
ख ख ख	X	X
ग ग ग	<u>X</u>	<u>X</u>
	<u>X</u>	<u>X</u>
चालू आस्तियां		
घ घ घ	X	X
ङ ङ ङ	<u>X</u>	<u>X</u>
	X	X
बिक्री के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत गैर चालू आस्तियां	<u>8,000</u>	<u>-</u>
	X	X
कुल आस्तियां	<u><u>X</u></u>	<u><u>X</u></u>
'इक्विटी' तथा देयताएं		
मूल प्रतिष्ठान के स्वामियों से संबंधित 'इक्विटी'		
च च च	X	X
छ छ छ	X	X
अन्य व्यापक आय में मान्य तथा बिक्री के लिए धारित गैर चालू आस्तियों से संबंधित 'इक्विटी' में संचित राशियां	<u>400</u>	<u>-</u>
	X	X
गैर नियंत्रित हित	<u>X</u>	<u>X</u>
कुल 'इक्विटी'	<u>X</u>	<u>X</u>
गैर चालू देयताएं	X	X
ज ज ज	X	X

झ झ झ	X	X
ट ट ट	X	X
चालू देयताएं		
ठ ठ ठ	X	X
ड ड ड	X	X
ढ ढ ढ	X	X
बिक्री के लिए धारित के रुप में वर्गीकृत गैर चालू आस्तियों के साथ प्रत्यक्ष रुप से संबंधित देयताएं	3,300	-
	X	X
कुल देयताएं	X	X
कुल 'इक्विटी' तथा देयताएं	X	X

रिपोर्टिंग अवधि के अंत में, बिक्री के लिए धारित के रुप में वर्गीकृत आस्तियां (अथवा निपटान समूह) की प्रस्तुति संबंधी अपेक्षाएं पूर्ववर्ती प्रभाव से लागू नहीं होती ! किन्हीं पूर्व अवधियों के तुलनात्मक तुलन पत्र इसलिए पुनः प्रस्तुत नहीं किये गये हैं।

पुनः बिक्री के आशय से तथा बिक्री के लिए धारित के रुप में वर्गीकृत अधिगृहीत अनुषंगियों का माप तथा प्रस्तुति ।

बिक्री के आशय से अधिगृहीत एक अनुषंगी भारतीय लेखा मानक 27 समेकित एवं पृथक वित्तीय विवरण के अनुसार समेकन से मुक्त नहीं है। यद्यपि यदि यह अनुच्छेद 11 के मानदंड को पूरा करती है, तो इसे बिक्री के लिए धारित के रुप में वर्गीकृत निपटान समूह के रुप में प्रस्तुत किया जाएगा । उदाहरण 13 इन अपेक्षाओं का वर्णन करता है।

उदाहरण 13

एक प्रतिष्ठान 'क' दूसरे प्रतिष्ठान 'ज' को अधिगृहीत करता है, जो एक धारक कंपनी है और एस 1 तथा एस 2 उसकी दो अनुषंगी कंपनियां हैं। एस 2 को केवल बिक्री के आशय के साथ अधिगृहीत किया गया है तथा यह कंपनी बिक्री के लिए धारित के रुप में वर्गीकरण के मानदंड को पूरा करती है। अनुच्छेद 32 (ग) के अनुसार, एस 2 एक बंद परिचालन भी है।

एस 2 का अनुमानित उचित मूल्य बिक्री लागत को घटाने के बाद 135 रुपये है। प्रतिष्ठान 'क' अनुषंगी एस 2 का लेखा इस प्रकार करता है : -

- आरंभ में, प्रतिष्ठान 'क' एस 2 की पहचानयोग्य देयताओं को उचित मूल्य पर मापता है, मान लें 40 रुपये में।
- आरंभ में, प्रतिष्ठान 'क' एस 2 की अधिगृहीत आस्तियों को बिक्री की लागत को घटाकर उचित मूल्य (135 रुपये) जमा पहचानयोग्य देयताओं के उचित मूल्य (40 रुपये) अर्थात् 175 रुपये पर मापता है।
- रिपोर्टिंग अवधि की अंत पर, 'क' निपटान समूह को इसकी लागत या बिक्री की लागत को घटाकर उचित मूल्य, इनमें से जो राशि कम है उस पर पुनः मापता है, मानो यह 130 रुपये है। देयता को लागू भारतीय लेखा मानक के अनुसार मापा जाता है, मान लो 35 रुपये पर। कुल आस्तियों को 130 रुपये + 35 रुपये अर्थात् 165 रुपये पर मापा जाता है।
- रिपोर्टिंग की अवधि पर, 'क' अपने समेकित वित्तीय विवरणों में अन्य आस्तियों तथा देयताओं से पृथक आस्तियां तथा देयताओं को प्रस्तुत करता है जैसा उदाहरण 12 बिक्री धारित के रूप में वर्गीकृत गैर चालू आस्तियों अथवा निपटान समूह की प्रस्तुति में दिया गया है, तथा
- लाभ तथा हानि के विवरण में, 'क' एस 2 की करोपरांत लाभ अथवा हानि तथा एस 2 की बाद के पुनः माप पर मान्यता करोपरांत लाभ अथवा हानि के योग को प्रस्तुत करता है जो निपटान समूह का 135 रुपये से 130 रुपये का पुनः माप के बराबर है।

आस्तियों तथा देयताओं का अथवा निपटान समूह के मूल्य में परिवर्तन के आगे विश्लेषण की कोई आवश्यकता नहीं है।

परिशिष्ट 1

'आई एफ आर एस' 5 बिक्री के लिए धारित गैर-चालू आस्तियां एवं बन्द परिचालन के साथ तुलना

टिप्पणी - यह परिशिष्ट भारतीय लेखा मानक का अंग नहीं है। इस परिशिष्ट का प्रयोजन मात्र भारतीय लेखा मानक (इंड ए एस) 105 तथा अन्तरराष्ट्रीय लेखा मानक बोर्ड द्वारा जारी तदनुसूची 'आई एफ आर एस' 5, 'बिक्री के लिए धारित गैर-चालू आस्तियां एवं बन्द परिचालन' के बीच, यदि कोई अन्तर हों, तो उन्हें स्पष्ट करना है।

1. 'आई एफ आर एस' 5 में दिये गये संक्रमणकालीन प्रावधान भारतीय लेखा मानक (इंड ए एस) 105 में नहीं दिये गये हैं, क्योंकि भारतीय लेखा मानकों के सभी संक्रमणकालीन प्रावधान, जहां उचित समझा गया है, 'आई एफ आर एस 1 अन्तरराष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग मानकों का प्रथमवार अंगीकरण' के तदनुसूची भारतीय लेखा मानक (इंड ए एस) 101 'भारतीय लेखा मानकों का प्रथमवार अंगीकरण' में सम्मिलित कर दिये गये हैं।
2. इस मानक में भिन्न शब्दावली का प्रयोग किया गया है, उदाहरणतया शब्दों 'वित्तीय स्थिति का विवरण' के स्थान पर शब्द 'तुलन-पत्र' और शब्दों 'व्यापक आय का विवरण' के स्थान पर शब्द 'लाभ-हानि विवरण' का प्रयोग किया गया है। इसी तरह, शब्दों 'वित्तीय विवरण जारी करने का प्राधिकार' के स्थान पर शब्दों 'वित्तीय विवरण जारी करने का अनुमोदन' का प्रयोग किया गया है।

3. जहां 'आई एफ आर आई एस' 5 के अनुच्छेद 33 क के अधीन अलग आय विवरण प्रस्तुत किया जाता है, अन्य आय विवरण में बन्द परिचालनों की प्रस्तुति विषयक अपेक्षाएं हटा दी गयी हैं। यह परिवर्तन भारतीय लेखा मानक 1 की द्वि-विवरण दृष्टिकोण के विकल्प को हटाने के परिणामस्वरूप है। भारतीय लेखा मानक 1 यह अपेक्षा करता है कि लाभ-हानि घटकों और अन्य व्यापक आय के घटकों को लाभ-हानि विवरण के एक अंग के रूप में प्रस्तुत किया जाएगा। हालांकि भारतीय लेखा मानक 105 का अनुच्छेद संख्या 33 क इस आशय से रहने दिया गया है ताकि 'आई एफ आर आई एस' 5 के साथ क्रमबद्धता बनी रहे।
4. 'आई एफ आर एस' 5 का अनुच्छेद (घ) गैर-चालू आस्तियों पर चर्चा करता है। इन आस्तियों का लेखा अन्तरराष्ट्रीय लेखा मानक 40 'निवेश संपत्ति' के अनुसरण में किया जाता है। चूंकि भारतीय लेखा मानक 40 उचित मूल्य मॉडल के प्रयोग को प्रतिषिद्ध करता है, अतः यह अनुच्छेद भारतीय लेखा मानक 105 से हटा दिया गया है।

भारतीय लेखा मानक (इंड ए एस) 106¹

खनिज संसाधनों की खोज और उनका मूल्यांकन

(इस भारतीय लेखा-मानक में मोटे टाइप व सामान्य टाइप में अनुच्छेद हैं। इन दोनों तरह के अनुच्छेदों का समान प्राधिकार है। मोटे टाइप में अनुच्छेद, मुख्य सिद्धान्तों के सूचक हैं)

उद्देश्य:

1. इस भारतीय लेखा मानक का उद्देश्य खनिज संसाधनों की खोज और उनके मूल्यांकन की वित्तीय रिपोर्टिंग को विनिर्दिष्ट करना है।
2. विशेष रूप से, यह भारतीय लेखा मानक निम्नलिखित की अपेक्षा करता है --
 - (क) खोज एवं मूल्यांकन व्यय के लिए मौजूदा लेखा व्यवहारों में सीमित सुधार।
 - (ख) प्रतिष्ठान जो खोज एवं मूल्यांकन आस्तियों का मूल्यांकन करते समय क्षतिग्रस्तता को इस भारतीय लेखा मानक के अनुसरण में मान्यता देते हैं और क्षतिग्रस्तता का माप भारतीय लेखा मानक 36 आस्तियों की क्षतिग्रस्तता के अनुसरण में करते हैं।
 - (ग) प्रकटन जो खनिज संसाधनों की खोज एवं मूल्यांकन से उत्पन्न प्रतिष्ठान के वित्तीय विवरणों की राशियों का पता लगाते हैं और उनकी व्याख्या करते हैं तथा उन वित्तीय विवरणों के उपयोगकर्ताओं की किन्हीं मान्यताप्राप्त खोज एवं मूल्यांकन आस्तियों की राशि, समय और भविष्य में सुनिश्चित प्रवाहों का समझने के लिए सहायक होते ह

कार्य-क्षेत्र:

3. एक प्रतिष्ठान इस भारतीय लेखा मानक का प्रयोग खर्च किये गये खोज एवं मूल्यांकन सम्बंधी व्यय पर करेगा।
4. यह भारतीय लेखा मानक खनिज संसाधनों की खोज एवं मूल्यांकन में संलग्न प्रतिष्ठानों के लेखे के अन्य पहलुओं पर चर्चा नहीं करता।

5. प्रतिष्ठान, इस भारतीय लेखा मानक को खर्च किये निम्नलिखित व्ययों पर लागू नहीं करेगा -

- (क) खनिज संसाधनों की खोज एवं मूल्यांकन से पूर्व प्रतिष्ठान द्वारा खर्च किये गये व्यय जैसे प्रतिष्ठान एक विशेष क्षेत्र में खोज करने से पूर्व कानूनी अधिकार ग्रहण करने के लिए खर्च करता है ;

¹ भारतीय लेखा मानक 106 खनिज संसाधनों की खोज और उनका मूल्यांकन को संशोधनों के साथ लागू किया जाएगा तथा जिसकी तिथि बाद में अधिसूचित की जाएगी ।

- (ख) खनिज संसाधनों को निकालने से पूर्व तकनीकी व्यवहार्यता और वाणिज्यिक अर्थ सुलभता के पश्चात के व्यय ।

खोज एवं मूल्यांकन आस्तियों की मान्यता

भारतीय लेखा मानक 8, अनुच्छेद 11 व 12 से अस्थायी छूट

6. एक प्रतिष्ठान अपनी लेखा नीतियों का विकास करते समय खोज एवं मूल्यांकन आस्तियों को मान्यता देने पर भारतीय लेखा मानक 8, *लेखा नीतियां, लेखा प्राक्कलनों में परिवर्तन एवं त्रुटियां* के अनुच्छेद 10 का प्रयोग करेगा ।
7. यदि एक मद के लिए कोई एक लेखा मानक विशेष रूप से लागू नहीं होता है तो उस मद के लिए एक उपयुक्त लेखा नीति के विकास के लिए प्रबंधन को जिन बातों पर विचार करना चाहिए उसके लिए भारतीय लेखा मानक 8 के अनुच्छेद 11 व 12 प्राधिकारपूर्ण अपेक्षित स्रोतों और मार्गदर्शन को विनिर्दिष्ट करते हैं। यह लेखा मानक एक प्रतिष्ठान को आस्तियों की खोज व मूल्यांकन की मान्यता एवं माप के लिए लेखा नीतियों के उन अनुच्छेदों के प्रयोग से छूट देता है । लेकिन, इसके लिए नीचे अनुच्छेद 9 व 10 का पालन करना होगा ।

खोज एवं मूल्यांकन आस्तियों का माप

मान्यता पर माप

8. खोज एवं मूल्यांकन आस्तियों का माप लागत पर किया जाएगा ।

खोज एवं मूल्यांकन आस्तियों की लागत के तत्व

9. प्रतिष्ठान एक लेखा नीति निर्धारित करेगा जिसमें वह यह विनिर्दिष्ट करेगा कि खोज और मूल्यांकन आस्तियों के लिए किस प्रकार के व्यय को मान्यता देगा और इस तरह की लेखा नीति को एक समान रूप से लागू करेगा । इस निर्णय में प्रतिष्ठान उस स्तर का भी विचार करेगा जिस पर व्यय को किसी विशेष खनिज संसाधन के साथ जोड़ा जा सके । यहां व्यय के कुछ उदाहरण दिये जा रहे हैं जिन्हें खोज एवं मूल्यांकन आस्तियों के प्रारम्भिक माप में शामिल किया जा सकता है (सूची विस्तृत नहीं है) --

- (क) खोज या दोहन के लिए अधिकार प्राप्त करना ;
- (ख) स्थलीय आकार, भूविज्ञानीय, भूरसायनीय एवं भूभौतिकी का अध्ययन ;
- (ग) खोज या दोहन से संबंधित खुदाई ;
- (घ) खुदाई/खाइयां खोदना ;
- (ङ) नमूने एकत्र करना ;

- (च) एक खनिज संसाधन की खोज या खुदाई से सम्बंधित तकनीकी व्यवहार्यता व वाणिज्यिक अर्थ-सुलभता के मूल्यांकन सम्बंधी गतिविधियां ।
10. खनिज संसाधनों के विकास पर किये गये खर्च की मान्यता खोज एवं मूल्यांकन आस्तियों के रूप में नहीं की जायेगी । भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी वित्तीय विवरण तैयार करना एवं उनके प्रस्तुतिकरण विषयक मूलभूत कार्यपद्धति तथा भारतीय लेखा मानक 38 अमूर्त आस्तियां विकास से उत्पन्न आस्तियों की मान्यता के लिए दिशा निर्देश देते हैं।
 11. भारतीय लेखा मानक 37 प्रावधान, आकस्मिक देयताएं एवं आकस्मिक आस्तियां के अनुसरण में संसाधनों की खोज एवं मूल्यांकन के फलस्वरूप 'हटाने या पुनः बहाल करने' के लिए कोई भी व्यय दायित्व बनता है तो उसको प्रतिष्ठान मान्यता देता है।

मान्यता के पश्चात माप :

12. मान्यता के पश्चात्, प्रतिष्ठान खोज एवं मूल्यांकन आस्तियों के लिए लागत मॉडल या पुनर्मूल्यांकन मॉडल का प्रयोग करेगा । यदि पुनर्मूल्यांकन मॉडल का प्रयोग किया जाता है [या तो भारतीय लेखा मानक 16 संपत्ति, संयंत्र एवं उपस्कर में मॉडल या भारतीय लेखा मानक 38 में मॉडल] तो वह आस्तियों के वर्गीकरण पर भी निरंतर रूप से लागू होंगे. (देखिए अनुच्छेद 15) ।

लेखा नीतियों में परिवर्तन

13. एक प्रतिष्ठान खोज और मूल्यांकन पर अपने खर्च के बारे में अपनी लेखा नीतियों में परिवर्तन कर सकता है ताकि इन परिवर्तनों से वित्तीय विवरणों के उपयोगकर्ताओं द्वारा आर्थिक निर्णय लेने की आवश्यकताओं में अधिक तर्कसंगतता और अधिक विश्वसनीयता हो जाए। प्रतिष्ठान द्वारा भारतीय लेखा मानक 8 में दिये गये मानदण्ड का प्रयोग करते हुए तर्कसंगतता तथा विश्वसनीयता के बारे में निर्णय लिया जाएगा ।
14. प्रतिष्ठान खोज एवं मूल्यांकन पर हुए व्यय के सम्बंध में लेखा नीतियों में किये गये परिवर्तनों को न्यायसंगत बनाने के लिए प्रतिष्ठान यह प्रदर्शित करेगा कि वे परिवर्तन भारतीय लेखा मानक 8 के मानदंडों को पूरा करते हैं। किन्तु, यह जरूरी नहीं है कि ये परिवर्तन उन मानदंडों का अक्षरशः पालन करते हों ।

प्रस्तुतीकरण

खोज एवं मूल्यांकन आस्तियों का वर्गीकरण

15. प्रतिष्ठान ग्रहण की गई आस्तियों की प्रकृति के अनुसार उन्हें मूर्त अथवा अमूर्त आस्तियों के रूप में वर्गीकृत करेगा और यह वर्गीकरण एक निरंतर रूप से जारी रहेगा ।
16. खोज एवं मूल्यांकन से सम्बंधित कुछ आस्तियां अमूर्त हो सकती हैं (जैसे खोज अथवा खुदाई के अधिकार) जब कि कुछ आस्तियां मूर्त हो सकती हैं, (जैसे वाहन और खुदाई उपकरण) । अमूर्त आस्ति के विकास में जितना मूर्त आस्ति का प्रयोग किया गया है, उतनी राशि जितनी मूर्त आस्ति के उपभोग में खर्च हुई है, वह अमूर्त आस्ति की लागत का भाग होगी । फिर भी, अमूर्त आस्ति के विकास में प्रयोग लाई गई मूर्त आस्ति को अमूर्त आस्ति के रूप में परिवर्तित नहीं माना जायेगा ।

खोज एवं मूल्यांकन आस्तियों का पुनर्वर्गीकरण

17. एक खोज एवं मूल्यांकन आस्ति को तब तक इस तरह की आस्ति के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जाएगा जब तक कि इस प्रकार की आस्ति अथवा खनिज संसाधन की तकनीकी व्यवहार्यता और वाणिज्यिक अर्थ सुलभता प्रत्यक्ष रूप से प्रदर्शित न हो। खोज एवं मूल्यांकन आस्तियों को क्षतिग्रस्तता के लिए परखा जाएगा तथा पुनर्वर्गीकरण से पूर्व क्षतिग्रस्तता हानि मान्य की जाती है।

क्षतिग्रस्तता**मान्यता और माप :**

18. खोज एवं मूल्यांकन आस्तियों को क्षतिग्रस्तता के लिए परखा जाएगा जब तथ्यों व परिस्थितियों से यह पता चलता है कि किसी ऐसी आस्ति की अग्रणीत राशि उससे प्राप्य राशि से अधिक हो गयी है। जब ऐसा पता लगता है कि अग्रणीत राशि उससे प्राप्य राशि से अधिक है तो प्रतिष्ठान, जैसा कि नीचे अनुच्छेद 21 के प्रावधानों में है, को छोड़कर भारतीय लेखा मानक 36 के अनुसरण में क्षतिग्रस्तता से होने वाली हानि का माप करेगा, उसे प्रस्तुत करेगा व उसका प्रकटन करेगा।
19. जब यह पहचान होती है कि खोज एवं मूल्यांकन की कोई आस्ति क्षतिग्रस्त है या हो सकती है तो इस प्रयोजन के लिए इस भारतीय लेखा मानक का अनुच्छेद 20 लागू होगा, न कि भारतीय लेखा मानक 36 के अनुच्छेद 8 - 17। अनुच्छेद 20 'आस्तियां' शब्द का प्रयोग करता है लेकिन यह खोज एवं मूल्यांकन की अलग आस्तियों या नगदी - सृजक ईकाई पर भी समान रूप से लागू होता है।
20. निम्नलिखित में से कोई एक अथवा एक से अधिक तथ्य व परिस्थितियां ऐसी हो सकती हैं, जिनमें खोज और मूल्यांकन आस्तियों की क्षतिग्रस्तता की जांच करनी चाहिए। (सूची विस्तृत नहीं है):—
- (क) अवधि जिसके लिए, प्रतिष्ठान को उस क्षेत्र विशेष में खोज करने की अधिकार है, किन्तु, वह अवधि समाप्त हो गई हो अथवा निकट भविष्य में समाप्त होने वाली हो, और उस अवधि के नवीकरण की संभावना न हो।
- (ख) एक विशेष क्षेत्र में खनिज संसाधनों की खोज और उसके मूल्यांकन पर आने वाली लागत काफी अधिक हो, जिसका प्रावधान न तो बजट में किया गया हो और न ही वह नियोजित हो।
- (ग) एक क्षेत्र विशेष में खनिज संसाधनों की खोज (दोहन) और उसका मूल्यांकन से यह पता चलता है कि खनिज संसाधनों की मात्रा वाणिज्यिक अर्थ सुलभता की दृष्टि से व्यावहारिक नहीं है और प्रतिष्ठान उस क्षेत्र विशेष में आगे इस प्रकार के खोज व मूल्यांकन कार्यों को बन्द करने का निर्णय ले लेता है।
- (घ) इस बात की पर्याप्त सूचना या आंकड़े उपलब्ध हों कि उक्त क्षेत्र विशेष में विकास के कार्य जारी तो रह सकते हैं लेकिन खोज एवं मूल्यांकन आस्ति उस सफल विकास या बिक्री से अग्रणीत राशि शायद ही पूरी तरह से वसूल नहीं कर पाएगी।

इस प्रकार के मामलों अथवा ऐसे ही अन्य मामलों में, प्रतिष्ठान द्वारा भारतीय लेखा मानक 36 के अनुसार संभावित क्षति का परीक्षण किया जायेगा। कोई भी क्षतिग्रस्तता हानि को व्यय के रूप में मान्यता भारतीय लेखा मानक 36 के अनुसरण में की जायेगी।

उस स्तर का उल्लेख जिस पर खोज एवं मूल्यांकन आस्तियों का निर्धारण क्षतिग्रस्तता के लिए किया जाना है।

21. प्रतिष्ठान द्वारा खोज एवं मूल्यांकन आस्तियों को नकदी सृजित ईकाइयों या ऐसे ही नकदी सृजित समूहों में क्षतिग्रस्तता के मूल्यांकन के आवंटन के लिए एक लेखा नीति निर्धारित करेगा। ऐसी कोई ईकाई या समूह जिसमें खोज एवं मूल्यांकन आस्ति का आवंटन होता है वह उस परिचालन खंड से बड़ा नहीं होगा जिसे भारतीय लेखा मानक 108 *परिचालनात्मक खण्ड* तय करता है।
22. खोज एवं मूल्यांकन आस्तियों की जांच के लिए प्रतिष्ठान के क्षतिग्रस्तता परीक्षण (जांच) के प्रयोजन के लिए एक प्रतिष्ठान जिस स्तर की पहचान करता है उसमें एक या एक से अधिक नकदी सृजक ईकाइयां हो सकती हैं।

प्रकटन

23. एक प्रतिष्ठान अपने वित्तीय विवरणों में उस सूचना को प्रकट करेगा जो खनिज संसाधनों की खोज (दोहन) और उनके मूल्यांकन की मान्य राशियों की पहचान और व्याख्या करता हो।
24. अनुच्छेद 23 के अनुपालन के लिए प्रतिष्ठान द्वारा निम्नलिखित जानकारी प्रकट की जायेगी:-
 - (क) खोज (दोहन) और मूल्यांकन आस्तियों की मान्यता सहित खोज एवं मूल्यांकन व्यय पर इसकी लेखा नीतियां ;
 - (ख) खनिज संसाधनों की खोज (दोहन) एवं मूल्यांकन से उत्पन्न आस्तियों, देयताओं, आय व व्यय तथा परिचालन निवेश व नकदी प्रवाहों की राशियां।
25. प्रतिष्ठान खोज (दोहन) और मूल्यांकन आस्तियों को एक अलग किस्म की आस्तियां मानेगा और उनका प्रकटन भारतीय लेखा मानक 16 अथवा भारतीय लेखा मानक 38 के अनुसरण में करेगा और साथ ही इस बात का भी उल्लेख करेगा कि इन आस्तियों का वर्गीकरण किस आधार पर किया गया है।

परिशिष्ट 'क'**परिभाषित शब्दावली:**

यह परिशिष्ट इस भारतीय लेखा मानक का अभिन्न अंग है ।

खोज एवं मूल्यांकन आस्तियां

प्रतिष्ठान की लेखा नीति के अनुसरण में खोज एवं मूल्यांकन पर मान्य व्यय

खोज एवं मूल्यांकन पर व्यय

प्रतिष्ठान द्वारा खनिज संसाधन की खोज तकनीकी व्यवहार्यता व वाणिज्यिक अर्थ सुलभता प्रदर्शित होने से पूर्व खनिज संसाधनों की खोज एवं मूल्यांकन पर किया गया व्यय

खनिज संसाधनों की खोज (दोहन) एवं मूल्यांकन

खनिज संसाधनों की खोज, जिनमें खनिज, तेल, प्राकृतिक गैस तथा उसी प्रकार के गैर पुनः उत्पादित संसाधन सम्मिलित हों, जो प्रतिष्ठान द्वारा किसी क्षेत्र विशेष में खोज (दोहन) से संबंधित कार्यों के लिये कानूनी अधिकारों की प्राप्ति के साथ-साथ इन खनिज संसाधनों की खोज की तकनीकी व्यवहार्यता और वाणिज्यिक अर्थ सुलभता के निर्धारण के बाद किया गया हो ।

परिशिष्ट 1

टिप्पणी - यह परिशिष्ट भारतीय लेखा मानक का अंग नहीं है। इस परिशिष्ट का प्रयोजन मात्र इतना है कि भारतीय लेखा मानक (इंड ए एस) 106 और तदनुरूपी अन्तरराष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग मानक (आई एफ आर एस) 6 खनिज संसाधनों की खोज और उनका मूल्यांकन के बीच यदि कोई अंतर हों तो उन्हें स्पष्ट किया जाए।

अन्तरराष्ट्रीय लेखा मानक (आई एफ आर एस) 6 खनिज संसाधनों की खोज और उनका मूल्यांकन के साथ तुलना

1. (आई एफ आर एस) 6 में दिये गये संक्रमणकालीन प्रावधान भारतीय लेखा मानक (इंड ए एस) 106 में इस आशय से नहीं दिये गये हैं कि भारतीय लेखा मानकों के सभी संक्रमणकालीन प्रावधान जहां उचित समझा गया, आई एफ आर एस 1 'अंतरराष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग मानकों' का प्रथमवार अंगीकरण' के अनुरूप भारतीय लेखा मानक (इंड ए एस) 101 'भारतीय लेखा मानकों की प्रथमवार अंगीकरण' में सम्मिलित किये गये हैं।

[फा. सं. 17/228/2010 सी.एल. V]

रेणुका कुमार, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i), सा.का.नि. 739(अ), तारीख 7 दिसम्बर, 2006 द्वारा प्रकाशित की गई थीं और पश्चात्पूर्वी निम्नलिखित द्वारा संशोधित की गई :—

- (1) सा.का.नि. 212(अ) तारीख 27 मार्च, 2008
- (2) सा.का.नि. 225(अ) तारीख 31 मार्च, 2009

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd March, 2011

G.S.R. 179(E).—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (1) of section 642 read with sub-section (1) of section 210A and sub-section (3C) of section 211 of the Companies Act, 1956 (1 of 1956), the Central Government in consultation with the National Advisory Committee on Accounting Standards, hereby makes the following rules to amend the Companies (Accounting Standards) Rules, 2006, namely: -

1. (1) These rules may be called the Companies (Accounting Standards) (Amendment) Rules, 2011.

(2) It shall come into force on such date as the Central Government may, by notification in the official Gazette, appoint and different dates may be appointed for different classes of companies.

2 In the Companies (Accounting Standards) Rules, 2006, (hereinafter called as principal rules), in the Definition for clause 'C', the following shall be substituted, namely,-

“Annexure means Annexure to the rules”

3. In the Principal rules, in rule 3,

(i) the existing sub-rules (1) and (2) shall be re-numbered as sub-rules (3) and (4) respectively;

(ii) in re-numbered sub-rule (3), for the word ‘Annexure’, the word “Annexure “B” shall be substituted;

(iii) before the re-numbered sub-rule (3), the following sub-rules shall be inserted, namely:-

“(1) The Central Government hereby prescribes Accounting Standards for application by companies specified in sub-rule 4 to be called Indian Accounting Standards (Ind ASs), which are specified in the Annexure A to these rules which shall apply to the following class of companies:-

(I) Companies other than Insurance companies, Banking companies and Non-Banking Finance companies

- (A) a. Companies which are part of NSE - Nifty 50
 b. Companies which are part of BSE - Sensex 30
 c. Companies whose shares or other securities are listed on stock exchanges outside India
 d. Companies, whether listed or not, which have a net worth in excess of Rs.1,000 crores.
 (B) Companies, whether listed or not, having a net worth exceeding Rs. 500 crores but not exceeding Rs. 1,000 crores
 (C) Listed companies which have a net worth of Rs. 500 crores or less

(II) Insurance companies, Banking companies and Non-Banking Finance companies

- (A) Insurance companies
 (B) (a) All scheduled commercial banks and those urban co-operative banks (UCBs) which have a net worth in excess of Rs. 300 crores
 (b) Urban co-operative banks which have a net worth in excess of Rs. 200 crores but not exceeding Rs. 300 crores
 (C) a. Non-Banking Finance Companies which are part of NSE - Nifty 50
 b. Non-Banking Finance Companies which are part of BSE - Sensex 30
 c. Non-Banking Finance Companies, whether listed or not, which have a net worth in excess of Rs.1,000 crores.
 (D) All listed Non-Banking Finance companies and those unlisted Non-Banking Finance companies which do not fall in the above categories and which have a net worth in excess of Rs. 500 crores

(2) A company which follows accounting standards specified in Annexure "A" shall follow such standards only and not the standards specified in Annexure "B". A company which follows accounting standards specified in Annexure "B" shall follow such standards only and not the standards specified in Annexure "A".

(iv) after sub-rule (4), following shall be inserted:-

" Provided that IFRIC -4 and IFRIC-12, wherever referred to in any of the Indian Accounting Standards (INDAS), shall be applied from a date to be notified."

(4) In the Principal rules, the existing Annexure shall be named as Annexure "B" and before the Annexure 'B' so renamed the following shall be inserted, namely,-

**"Annexure 'A'
 (See rule 3)**

[Indian Accounting Standards (Ind AS)]"

Indian Accounting Standard (Ind AS) 2

Inventories

(This Indian Accounting Standard includes paragraphs set in bold type and plain type, which have equal authority. Paragraphs in bold italic type indicate the main principles.)

Objective

1. The objective of this Standard is to prescribe the accounting treatment for inventories. A primary issue in accounting for inventories is the amount of cost to be recognised as an asset and carried forward until the related revenues are recognised. This Standard deals with the determination of cost and its subsequent recognition as an expense, including any write-down to net realisable value. It also deals with the cost formulas that are used to assign costs to inventories.

Scope

2. This Standard applies to all inventories, except:
- (a) work in progress arising under construction contracts, including directly related service contracts (see Ind AS 11, Construction Contracts;
 - (b) financial instruments (see Ind AS 39, Financial Instruments: Recognition and Measurement and Ind AS 32, Financial Instruments: Presentation); and
 - (c) biological assets (i.e., living animals or plants) related to agricultural activity and agricultural produce at the point of harvest (See Ind AS 41, Agriculture¹)
3. This Standard does not apply to the measurement of inventories held by:
- (a) producers of agricultural and forest products, agricultural produce after harvest, and minerals and mineral products, to the extent that they are measured at net realisable value in accordance with well-established practices in those industries. When such inventories are measured at net realisable value, changes in that value are recognised in profit or loss in the period of the change.
 - (b) commodity broker-traders who measure their inventories at fair value less costs to sell. When such inventories are measured at fair

¹ Indian Accounting Standard (Ind AS) 41, Agriculture, is under formulation.

value less costs to sell, changes in fair value less costs to sell are recognised in profit or loss in the period of the change.

4. The inventories referred to in paragraph 3(a) are measured at net realisable value at certain stages of production. This occurs, for example, when agricultural crops have been harvested or minerals have been extracted and sale is assured under a forward contract or a government guarantee, or when an active market exists and there is a negligible risk of failure to sell. These inventories are excluded from only the measurement requirements of this Standard.

5. Broker-traders are those who buy or sell commodities for others or on their own account. The inventories referred to in paragraph 3(b) are principally acquired with the purpose of selling in the near future and generating a profit from fluctuations in price or broker-traders' margin. When these inventories are measured at fair value less costs to sell, they are excluded from only the measurement requirements of this Standard.

Definitions

6. The following terms are used in this Standard with the meanings specified:

Inventories are assets:

- (a) held for sale in the ordinary course of business;
- (b) in the process of production for such sale; or
- (c) in the form of materials or supplies to be consumed in the production process or in the rendering of services.

Net realisable value is the estimated selling price in the ordinary course of business less the estimated costs of completion and the estimated costs necessary to make the sale.

Fair value is the amount for which an asset could be exchanged, or a liability settled, between knowledgeable, willing parties in an arm's length transaction.

7. Net realisable value refers to the net amount that an entity expects to realise from the sale of inventory in the ordinary course of business. Fair value reflects the amount for which the same inventory could be exchanged between knowledgeable and willing buyers and sellers in the marketplace. The former is an entity-specific value; the latter is not. Net realisable value for inventories may not equal fair value less costs to sell.

8. Inventories encompass goods purchased and held for resale including, for example, merchandise purchased by a retailer and held for resale, or land and other property held for resale. Inventories also encompass finished goods produced, or work in progress being produced, by the entity and include materials and supplies awaiting use in the production process. In the case of a service provider, inventories include the costs of the service, as described in paragraph 19, for which the entity has not yet recognised the related revenue (*see* Ind AS 18, *Revenue*).

Measurement of inventories

9. Inventories shall be measured at the lower of cost and net realisable value.

Cost of inventories

10. The cost of inventories shall comprise all costs of purchase, costs of conversion and other costs incurred in bringing the inventories to their present location and condition.

Costs of purchase

11. The costs of purchase of inventories comprise the purchase price, import duties and other taxes (other than those subsequently recoverable by the entity from the taxing authorities), and transport, handling and other costs directly attributable to the acquisition of finished goods, materials and services. Trade discounts, rebates and other similar items are deducted in determining the costs of purchase.

Costs of conversion

12. The costs of conversion of inventories include costs directly related to the units of production, such as direct labour. They also include a systematic allocation of fixed and variable production overheads that are incurred in converting materials into finished goods. Fixed production overheads are those indirect costs of production that remain relatively constant regardless of the volume of production, such as depreciation and maintenance of factory buildings and equipment, and the cost of factory management and administration. Variable production overheads are those indirect costs of production that vary directly, or nearly directly, with the volume of production, such as indirect materials and indirect labour.

13. The allocation of fixed production overheads to the costs of conversion is based on the normal capacity of the production facilities. Normal capacity is the production expected to be achieved on average over a number of periods or seasons under normal circumstances, taking into account the loss of capacity resulting from planned maintenance. The actual level of production may be used if it approximates normal capacity. The amount of fixed overhead allocated to each unit of production is not increased as a consequence of low production or idle plant. Unallocated overheads are recognised as an expense in the period in which they are incurred. In periods of abnormally high production, the amount of fixed overhead allocated to each unit of production is decreased so that inventories are not measured above cost. Variable production overheads are allocated to each unit of production on the basis of the actual use of the production facilities.

14. A production process may result in more than one product being produced simultaneously. This is the case, for example, when joint products are produced or when there is a main product and a by-product. When the costs of conversion of each product are not separately identifiable, they are allocated between the products on a rational and consistent basis. The allocation may be based, for example, on the relative sales value of each product either at the stage in the production process when the products become separately identifiable, or at the completion of production. Most by-products, by their nature, are immaterial. When this is the case, they are often measured at net realisable value and this value is deducted from the cost of the main product. As a result, the carrying amount of the main product is not materially different from its cost.

Other costs

15. Other costs are included in the cost of inventories only to the extent that they are incurred in bringing the inventories to their present location and condition. For example, it may be appropriate to include non-production overheads or the costs of designing products for specific customers in the cost of inventories.

16. Examples of costs excluded from the cost of inventories and recognised as expenses in the period in which they are incurred are:

- (a) abnormal amounts of wasted materials, labour or other production costs;
- (b) storage costs, unless those costs are necessary in the production process before a further production stage;
- (c) administrative overheads that do not contribute to bringing inventories to their present location and condition; and
- (d) selling costs.

17. Ind AS 23, *Borrowing Costs*, identifies limited circumstances where borrowing costs are included in the cost of inventories.

18. An entity may purchase inventories on deferred settlement terms. When the arrangement effectively contains a financing element, that element, for example a difference between the purchase price for normal credit terms and the amount paid, is recognised as interest expense over the period of the financing.

Cost of inventories of a service provider

19. To the extent that service providers have inventories, they measure them at the costs of their production. These costs consist primarily of the labour and other costs of personnel directly engaged in providing the service, including supervisory personnel, and attributable overheads. Labour and other costs relating to sales and general administrative personnel are not included but are recognised as expenses in the period in which they are incurred. The cost of inventories of a service provider

does not include profit margins or non-attributable overheads that are often factored into prices charged by service providers.

Cost of agricultural produce harvested from biological assets²

20. In accordance with Ind AS 41, *Agriculture*, inventories comprising agricultural produce that an entity has harvested from its biological assets are measured on initial recognition at their fair value less costs to sell at the point of harvest. This is the cost of the inventories at that date for application of this Standard.

Techniques for the measurement of cost

21. Techniques for the measurement of the cost of inventories, such as the standard cost method or the retail method, may be used for convenience if the results approximate cost. Standard costs take into account normal levels of materials and supplies, labour, efficiency and capacity utilisation. They are regularly reviewed and, if necessary, revised in the light of current conditions.

22. The retail method is often used in the retail industry for measuring inventories of large numbers of rapidly changing items with similar margins for which it is impracticable to use other costing methods. The cost of the inventory is determined by reducing the sales value of the inventory by the appropriate percentage gross margin. The percentage used takes into consideration inventory that has been marked down to below its original selling price. An average percentage for each retail department is often used.

Cost Formulas

23. The cost of inventories of items that are not ordinarily interchangeable and goods or services produced and segregated for specific projects shall be assigned by using specific identification of their individual costs.

24. Specific identification of cost means that specific costs are attributed to identified items of inventory. This is the appropriate treatment for items that are segregated for a specific project, regardless of whether they have been bought or produced. However, specific identification of costs is inappropriate when there are large numbers of items of inventory that are ordinarily interchangeable. In such circumstances, the method of selecting those items that remain in inventories could be used to obtain predetermined effects on profit or loss.

25. The cost of inventories, other than those dealt with in paragraph 23, shall be assigned by using the first-in, first-out (FIFO) or weighted average cost formula. An entity shall use the same cost formula for all inventories having a similar nature and use to the entity. For inventories with a different nature or use, different cost formulas may be justified.

² Indian Accounting Standard (Ind AS) 41, *Agriculture*, is under formulation. Accordingly, this paragraph would be effective from the date Ind AS 41, *Agriculture*, comes into effect.

26. For example, inventories used in one operating segment may have a use to the entity different from the same type of inventories used in another operating segment. However, a difference in geographical location of inventories (or in the respective tax rules), by itself, is not sufficient to justify the use of different cost formulas.

27. The FIFO formula assumes that the items of inventory that were purchased or produced first are sold first, and consequently the items remaining in inventory at the end of the period are those most recently purchased or produced. Under the weighted average cost formula, the cost of each item is determined from the weighted average of the cost of similar items at the beginning of a period and the cost of similar items purchased or produced during the period. The average may be calculated on a periodic basis, or as each additional shipment is received, depending upon the circumstances of the entity.

Net realisable value

28. The cost of inventories may not be recoverable if those inventories are damaged, if they have become wholly or partially obsolete, or if their selling prices have declined. The cost of inventories may also not be recoverable if the estimated costs of completion or the estimated costs to be incurred to make the sale have increased. The practice of writing inventories down below cost to net realisable value is consistent with the view that assets should not be carried in excess of amounts expected to be realised from their sale or use.

29. Inventories are usually written down to net realisable value item by item. In some circumstances, however, it may be appropriate to group similar or related items. This may be the case with items of inventory relating to the same product line that have similar purposes or end uses, are produced and marketed in the same geographical area, and cannot be practicably evaluated separately from other items in that product line. It is not appropriate to write inventories down on the basis of a classification of inventory, for example, finished goods, or all the inventories in a particular operating segment. Service providers generally accumulate costs in respect of each service for which a separate selling price is charged. Therefore, each such service is treated as a separate item.

30. Estimates of net realisable value are based on the most reliable evidence available at the time the estimates are made, of the amount the inventories are expected to realise. These estimates take into consideration fluctuations of price or cost directly relating to events occurring after the end of the period to the extent that such events confirm conditions existing at the end of the period.

31. Estimates of net realisable value also take into consideration the purpose for which the inventory is held. For example, the net realisable value of the quantity of inventory held to satisfy firm sales or service contracts is based on the contract price. If the sales contracts are for less than the inventory quantities held, the net realisable value of the excess is based on general selling prices. Provisions may arise from firm sales contracts in excess of inventory quantities held or from firm purchase contracts. Such provisions are dealt with under Ind AS 37, *Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets*.

32. Materials and other supplies held for use in the production of inventories are not written down below cost if the finished products in which they will be incorporated are expected to be sold at or above cost. However, when a decline in the price of materials indicates that the cost of the finished products exceeds net realisable value, the materials are written down to net realisable value. In such circumstances, the replacement cost of the materials may be the best available measure of their net realisable value.

33. A new assessment is made of net realisable value in each subsequent period. When the circumstances that previously caused inventories to be written down below cost no longer exist or when there is clear evidence of an increase in net realisable value because of changed economic circumstances, the amount of the write-down is reversed (ie the reversal is limited to the amount of the original write-down) so that the new carrying amount is the lower of the cost and the revised net realisable value. This occurs, for example, when an item of inventory that is carried at net realisable value, because its selling price has declined, is still on hand in a subsequent period and its selling price has increased.

Recognition as an expense

34. When inventories are sold, the carrying amount of those inventories shall be recognised as an expense in the period in which the related revenue is recognised. The amount of any write-down of inventories to net realisable value and all losses of inventories shall be recognised as an expense in the period the write-down or loss occurs. The amount of any reversal of any write-down of inventories, arising from an increase in net realisable value, shall be recognised as a reduction in the amount of inventories recognised as an expense in the period in which the reversal occurs.

35. Some inventories may be allocated to other asset accounts, for example, inventory used as a component of self-constructed property, plant or equipment. Inventories allocated to another asset in this way are recognised as an expense during the useful life of that asset.

Disclosure

36. The financial statements shall disclose:

- (a) the accounting policies adopted in measuring inventories, including the cost formula used;
- (b) the total carrying amount of inventories and the carrying amount in classifications appropriate to the entity;
- (c) the carrying amount of inventories carried at fair value less costs to sell;
- (d) the amount of inventories recognised as an expense during the period;
- (e) the amount of any write-down of inventories recognised as an expense in the period in accordance with paragraph 34;

- (f) the amount of any reversal of any write-down that is recognised as a reduction in the amount of inventories recognised as expense in the period in accordance with paragraph 34;
- (g) the circumstances or events that led to the reversal of a write-down of inventories in accordance with paragraph 34; and
- (h) the carrying amount of inventories pledged as security for liabilities.

37. Information about the carrying amounts held in different classifications of inventories and the extent of the changes in these assets is useful to financial statement users. Common classifications of inventories are merchandise, production supplies, materials, work in progress and finished goods. The inventories of a service provider may be described as work in progress.

38. [Refer to Appendix 1]

39. An entity adopts a format for profit or loss that results in amounts being disclosed other than the cost of inventories recognised as an expense during the period. Under this format, the entity presents an analysis of expenses using a classification based on the nature of expenses. In this case, the entity discloses the costs recognised as an expense for raw materials and consumables, labour costs and other costs together with the amount of the net change in inventories for the period.

Appendix A

References to matters contained in other Indian Accounting Standards

This Appendix is an integral part of Indian Accounting Standard (Ind AS) 2.

This appendix lists the appendix which is a part of another Indian Accounting Standard and makes reference to Ind AS 2, *Inventories*

1. Appendix A, *Intangible Assets-Web site Costs* contained in Ind AS 38, *Intangible Assets*.

Appendix 1

Note: This Appendix is not a part of Indian Accounting Standard (Ind AS) 2, Inventories. The purpose of this Appendix is only to bring out the differences between Indian Accounting Standard and the corresponding International Accounting Standard (IAS) 2, Inventories.

Comparison with IAS 2, *Inventories*

1. Paragraph 38 of IAS 2 dealing with recognition of inventories as an expense based on function-wise classification, has been deleted keeping in view the fact that option provided in IAS 1 to present an analysis of expenses recognised in profit or loss using a classification based on their function within the entity has been removed and Ind AS 1 requires only nature-wise classification of expenses. However, in order to maintain consistency with paragraph numbers of IAS 2, the paragraph number is retained in Ind AS 2.

Indian Accounting Standard (Ind AS) 7

Statement of Cash Flows

(This Indian Accounting Standard includes paragraphs set in bold type and plain type, which have equal authority. Paragraphs in bold type indicate the main principles.)

Objective

Information about the cash flows of an entity is useful in providing users of financial statements with a basis to assess the ability of the entity to generate cash and cash equivalents and the needs of the entity to utilise those cash flows. The economic decisions that are taken by users require an evaluation of the ability of an entity to generate cash and cash equivalents and the timing and certainty of their generation.

The objective of this Standard is to require the provision of information about the historical changes in cash and cash equivalents of an entity by means of a statement of cash flows which classifies cash flows during the period from operating, investing and financing activities.

Scope

- 1 **An entity shall prepare a statement of cash flows in accordance with the requirements of this Standard and shall present it as an integral part of its financial statements for each period for which financial statements are presented.**
- 2 [Refer to Appendix 1]
- 3 Users of an entity's financial statements are interested in how the entity generates and uses cash and cash equivalents. This is the case regardless of the nature of the entity's activities and irrespective of whether cash can be viewed as the product of the entity, as may be the case with a financial institution. Entities need cash for essentially the same reasons however different their principal revenue-producing activities might be. They need cash to conduct their operations, to pay their obligations, and to provide returns to their investors. Accordingly, this Standard requires all entities to present a statement of cash flows.

Benefits of cash flow information

- 4 A statement of cash flows, when used in conjunction with the rest of the financial statements, provides information that enables users to evaluate the changes in net assets of an entity, its financial structure (including its liquidity and solvency) and its ability to

affect the amounts and timing of cash flows in order to adapt to changing circumstances and opportunities. Cash flow information is useful in assessing the ability of the entity to generate cash and cash equivalents and enables users to develop models to assess and compare the present value of the future cash flows of different entities. It also enhances the comparability of the reporting of operating performance by different entities because it eliminates the effects of using different accounting treatments for the same transactions and events.

- 5 Historical cash flow information is often used as an indicator of the amount, timing and certainty of future cash flows. It is also useful in checking the accuracy of past assessments of future cash flows and in examining the relationship between profitability and net cash flow and the impact of changing prices.

Definitions

- 6 The following terms are used in this Standard with the meanings specified:

Cash comprises cash on hand and demand deposits.

Cash equivalents are short-term, highly liquid investments that are readily convertible to known amounts of cash and which are subject to an insignificant risk of changes in value.

Cash flows are inflows and outflows of cash and cash equivalents.

Operating activities are the principal revenue-producing activities of the entity and other activities that are not investing or financing activities.

Investing activities are the acquisition and disposal of long-term assets and other investments not included in cash equivalents.

Financing activities are activities that result in changes in the size and composition of the contributed equity and borrowings of the entity.

Cash and cash equivalents

- 7 Cash equivalents are held for the purpose of meeting short-term cash commitments rather than for investment or other purposes. For an investment to qualify as a cash equivalent it must be readily convertible to a known amount of cash and be subject to an insignificant risk of changes in value. Therefore, an investment normally qualifies as a cash equivalent only when it has a short maturity of, say, three months or less from the date of acquisition. Equity investments are excluded from cash equivalents unless they are, in substance, cash equivalents, for example in the case of preference shares acquired within a short period of their maturity and with a specified redemption date.

- 8 Bank borrowings are generally considered to be financing activities. However, where bank overdrafts which are repayable on demand form an integral part of an entity's cash

management, bank overdrafts are included as a component of cash and cash equivalents. A characteristic of such banking arrangements is that the bank balance often fluctuates from being positive to overdrawn.

- 9 Cash flows exclude movements between items that constitute cash or cash equivalents because these components are part of the cash management of an entity rather than part of its operating, investing and financing activities. Cash management includes the investment of excess cash in cash equivalents.

Presentation of a statement of cash flows

- 10 **The statement of cash flows shall report cash flows during the period classified by operating, investing and financing activities.**
- 11 An entity presents its cash flows from operating, investing and financing activities in a manner which is most appropriate to its business. Classification by activity provides information that allows users to assess the impact of those activities on the financial position of the entity and the amount of its cash and cash equivalents. This information may also be used to evaluate the relationships among those activities.
- 12 A single transaction may include cash flows that are classified differently. For example, when the instalment paid in respect of a fixed asset acquired on deferred payment basis includes both interest and loan, the interest element is classified under financing activities and the loan element is classified under investing activities.

Operating activities

- 13 The amount of cash flows arising from operating activities is a key indicator of the extent to which the operations of the entity have generated sufficient cash flows to repay loans, maintain the operating capability of the entity, pay dividends and make new investments without recourse to external sources of financing. Information about the specific components of historical operating cash flows is useful, in conjunction with other information, in forecasting future operating cash flows.
- 14 Cash flows from operating activities are primarily derived from the principal revenue-producing activities of the entity. Therefore, they generally result from the transactions and other events that enter into the determination of profit or loss. Examples of cash flows from operating activities are:
- (a) cash receipts from the sale of goods and the rendering of services;
 - (b) cash receipts from royalties, fees, commissions and other revenue;
 - (c) cash payments to suppliers for goods and services;
 - (d) cash payments to and on behalf of employees;

- (e) cash receipts and cash payments of an insurance entity for premiums and claims, annuities and other policy benefits;
- (f) cash payments or refunds of income taxes unless they can be specifically identified with financing and investing activities; and
- (g) cash receipts and payments from contracts held for dealing or trading purposes.

Some transactions, such as the sale of an item of plant, may give rise to a gain or loss that is included in recognised profit or loss. The cash flows relating to such transactions are cash flows from investing activities. However, cash payments to manufacture or acquire assets held for rental to others and subsequently held for rental to others and subsequently held for sale as described in paragraph 68A of Ind AS 16 *Property, Plant and Equipment* are cash flows from operating activities. The cash receipts from rents and subsequent sales of such assets are also cash flows from operating activities.

- 15 An entity may hold securities and loans for dealing or trading purposes, in which case they are similar to inventory acquired specifically for resale. Therefore, cash flows arising from the purchase and sale of dealing or trading securities are classified as operating activities. Similarly, cash advances and loans made by financial institutions are usually classified as operating activities since they relate to the main revenue-producing activity of that entity.

Investing activities

- 16 The separate disclosure of cash flows arising from investing activities is important because the cash flows represent the extent to which expenditures have been made for resources intended to generate future income and cash flows. Only expenditures that result in a recognized asset in the balance sheet are eligible for classification as investing activities. Examples of cash flows arising from investing activities are:
- (a) cash payments to acquire property, plant and equipment, intangibles and other long-term assets. These payments include those relating to capitalised development costs and self-constructed property, plant and equipment;
 - (b) cash receipts from sales of property, plant and equipment, intangibles and other long-term assets;
 - (c) cash payments to acquire equity or debt instruments of other entities and interests in joint ventures (other than payments for those instruments considered to be cash equivalents or those held for dealing or trading purposes);
 - (d) cash receipts from sales of equity or debt instruments of other entities and interests in joint ventures (other than receipts for those instruments considered to be cash equivalents and those held for dealing or trading purposes);
 - (e) cash advances and loans made to other parties (other than advances and loans made by a financial institution);

- (f) cash receipts from the repayment of advances and loans made to other parties (other than advances and loans of a financial institution);
- (g) cash payments for futures contracts, forward contracts, option contracts and swap contracts except when the contracts are held for dealing or trading purposes, or the payments are classified as financing activities; and
- (h) cash receipts from futures contracts, forward contracts, option contracts and swap contracts except when the contracts are held for dealing or trading purposes, or the receipts are classified as financing activities.

When a contract is accounted for as a hedge of an identifiable position the cash flows of the contract are classified in the same manner as the cash flows of the position being hedged.

Financing activities

- 17 The separate disclosure of cash flows arising from financing activities is important because it is useful in predicting claims on future cash flows by providers of capital to the entity. Examples of cash flows arising from financing activities are:
- (a) cash proceeds from issuing shares or other equity instruments;
 - (b) cash payments to owners to acquire or redeem the entity's shares;
 - (c) cash proceeds from issuing debentures, loans, notes, bonds, mortgages and other short-term or long-term borrowings;
 - (d) cash repayments of amounts borrowed; and
 - (e) cash payments by a lessee for the reduction of the outstanding liability relating to a finance lease.

Reporting cash flows from operating activities

- 18 An entity shall report cash flows from operating activities using either:
- (a) the direct method, whereby major classes of gross cash receipts and gross cash payments are disclosed; or
 - (b) the indirect method, whereby profit or loss is adjusted for the effects of transactions of a non-cash nature, any deferrals or accruals of past or future operating cash receipts or payments, and items of income or expense associated with investing or financing cash flows.

- 19 Entities are encouraged to report cash flows from operating activities using the direct method. The direct method provides information which may be useful in estimating future cash flows and which is not available under the indirect method. Under the direct method, information about major classes of gross cash receipts and gross cash payments may be obtained either:
- (a) from the accounting records of the entity; or
 - (b) by adjusting sales, cost of sales (interest and similar income and interest expense and similar charges for a financial institution) and other items in the statement of profit and loss for:
 - (i) changes during the period in inventories and operating receivables and payables;
 - (ii) other non-cash items; and
 - (iii) other items for which the cash effects are investing or financing cash flows.
- 20 Under the indirect method, the net cash flow from operating activities is determined by adjusting profit or loss for the effects of:
- (a) changes during the period in inventories and operating receivables and payables;
 - (b) non-cash items such as depreciation, provisions, deferred taxes, unrealised foreign currency gains and losses, and undistributed profits of associates; and
 - (c) all other items for which the cash effects are investing or financing cash flows.

Alternatively, the net cash flow from operating activities may be presented under the indirect method by showing the revenues and expenses disclosed in the statement of profit and loss and the changes during the period in inventories and operating receivables and payables.

Reporting cash flows from investing and financing activities

- 21 An entity shall report separately major classes of gross cash receipts and gross cash payments arising from investing and financing activities, except to the extent that cash flows described in paragraphs 22 and 24 are reported on a net basis.

Reporting cash flows on a net basis

- 22 Cash flows arising from the following operating, investing or financing activities may be reported on a net basis:

- (a) cash receipts and payments on behalf of customers when the cash flows reflect the activities of the customer rather than those of the entity; and
- (b) cash receipts and payments for items in which the turnover is quick, the amounts are large, and the maturities are short.

23 Examples of cash receipts and payments referred to in paragraph 22(a) are:

- (a) the acceptance and repayment of demand deposits of a bank;
- (b) funds held for customers by an investment entity; and
- (c) rents collected on behalf of, and paid over to, the owners of properties.

23A Examples of cash receipts and payments referred to in paragraph 22(b) are advances made for, and the repayment of:

- (a) principal amounts relating to credit card customers;
- (b) the purchase and sale of investments; and
- (c) other short-term borrowings, for example, those which have a maturity period of three months or less.

24 Cash flows arising from each of the following activities of a financial institution may be reported on a net basis:

- (a) cash receipts and payments for the acceptance and repayment of deposits with a fixed maturity date;
- (b) the placement of deposits with and withdrawal of deposits from other financial institutions; and
- (c) cash advances and loans made to customers and the repayment of those advances and loans.

Foreign currency cash flows

25 Cash flows arising from transactions in a foreign currency shall be recorded in an entity's functional currency by applying to the foreign currency amount the exchange rate between the functional currency and the foreign currency at the date of the cash flow.

26 The cash flows of a foreign subsidiary shall be translated at the exchange rates between the functional currency and the foreign currency at the dates of the cash flows.

- 27 Cash flows denominated in a foreign currency are reported in a manner consistent with Ind AS 21 *The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates*. This permits the use of an exchange rate that approximates the actual rate. For example, a weighted average exchange rate for a period may be used for recording foreign currency transactions or the translation of the cash flows of a foreign subsidiary. However, Ind AS 21 does not permit use of the exchange rate at the end of the reporting period when translating the cash flows of a foreign subsidiary.
- 28 Unrealised gains and losses arising from changes in foreign currency exchange rates are not cash flows. However, the effect of exchange rate changes on cash and cash equivalents held or due in a foreign currency is reported in the statement of cash flows in order to reconcile cash and cash equivalents at the beginning and the end of the period. This amount is presented separately from cash flows from operating, investing and financing activities and includes the differences, if any, had those cash flows been reported at end of period exchange rates.
- 29 [Refer to Appendix 1]
- 30 [Refer to Appendix 1]

Interest and dividends

- 31 Cash flows from interest and dividends received and paid shall each be disclosed separately. Cash flows arising from interest paid and interest and dividends received in the case of a financial institution should be classified as cash flows arising from operating activities. In the case of other entities, cash flows arising from interest paid should be classified as cash flows from financing activities while interest and dividends received should be classified as cash flows from investing activities. Dividends paid should be classified as cash flows from financing activities.
- 32 The total amount of interest paid during a period is disclosed in the statement of cash flows whether it has been recognised as an expense in profit or loss or capitalised in accordance with Ind AS 23 *Borrowing Costs*.
- 33 Interest paid and interest and dividends received are usually classified as operating cash flows for a financial institution. However, there is no consensus on the classification of these cash flows for other entities. Some argue that interest paid and interest and dividends received may be classified as operating cash flows because they enter into the determination of profit or loss. However, it is more appropriate that interest paid and interest and dividends received are classified as financing cash flows and investing cash flows respectively, because they are costs of obtaining financial resources or returns on investments.
- 34 Some argue that dividends paid may be classified as a component of cash flows from operating activities in order to assist users to determine the ability of an entity to pay dividends out of operating cash flows. However, it is considered more appropriate that dividends paid should be classified as cash flows from financing activities because they are cost of obtaining financial resources.

Taxes on income

- 35 **Cash flows arising from taxes on income shall be separately disclosed and shall be classified as cash flows from operating activities unless they can be specifically identified with financing and investing activities.**
- 36 Taxes on income arise on transactions that give rise to cash flows that are classified as operating, investing or financing activities in a statement of cash flows. While tax expense may be readily identifiable with investing or financing activities, the related tax cash flows are often impracticable to identify and may arise in a different period from the cash flows of the underlying transaction. Therefore, taxes paid are usually classified as cash flows from operating activities. However, when it is practicable to identify the tax cash flow with an individual transaction that gives rise to cash flows that are classified as investing or financing activities the tax cash flow is classified as an investing or financing activity as appropriate. When tax cash flows are allocated over more than one class of activity, the total amount of taxes paid is disclosed.

Investments in subsidiaries, associates and joint ventures

- 37 When accounting for an investment in an associate or a subsidiary accounted for by use of the equity or cost method, an investor restricts its reporting in the statement of cash flows to the cash flows between itself and the investee, for example, to dividends and advances.
- 38 An entity which reports its interest in a jointly controlled entity (see Ind AS 31 *Interests in Joint Ventures*) using proportionate consolidation, includes in its consolidated statement of cash flows its proportionate share of the jointly controlled entity's cash flows. An entity which reports such an interest using the equity method includes in its statement of cash flows the cash flows in respect of its investments in the jointly controlled entity, and distributions and other payments or receipts between it and the jointly controlled entity.

Changes in ownership interests in subsidiaries and other businesses

- 39 **The aggregate cash flows arising from obtaining or losing control of subsidiaries or other businesses shall be presented separately and classified as investing activities.**
- 40 **An entity shall disclose, in aggregate, in respect of both obtaining and losing control of subsidiaries or other businesses during the period each of the following:**
- (a) **the total consideration paid or received;**
 - (b) **the portion of the consideration consisting of cash and cash equivalents;**

- (c) **the amount of cash and cash equivalents in the subsidiaries or other businesses over which control is obtained or lost; and**
 - (d) **the amount of the assets and liabilities other than cash or cash equivalents in the subsidiaries or other businesses over which control is obtained or lost, summarised by each major category.**
- 41 The separate presentation of the cash flow effects of obtaining or losing control of subsidiaries or other businesses as single line items, together with the separate disclosure of the amounts of assets and liabilities acquired or disposed of, helps to distinguish those cash flows from the cash flows arising from the other operating, investing and financing activities. The cash flow effects of losing control are not deducted from those of obtaining control.
- 42 The aggregate amount of the cash paid or received as consideration for obtaining or losing control of subsidiaries or other businesses is reported in the statement of cash flows net of cash and cash equivalents acquired or disposed of as part of such transactions, events or changes in circumstances.
- 42A Cash flows arising from changes in ownership interests in a subsidiary that do not result in a loss of control shall be classified as cash flows from financing activities.
- 42B Changes in ownership interests in a subsidiary that do not result in a loss of control, such as the subsequent purchase or sale by a parent of a subsidiary's equity instruments, are accounted for as equity transactions (see Ind AS 27, *Consolidated and Separate Financial Statements*). Accordingly, the resulting cash flows are classified in the same way as other transactions with owners described in paragraph 17.

Non-cash transactions

- 43 **Investing and financing transactions that do not require the use of cash or cash equivalents shall be excluded from a statement of cash flows. Such transactions shall be disclosed elsewhere in the financial statements in a way that provides all the relevant information about these investing and financing activities.**
- 44 Many investing and financing activities do not have a direct impact on current cash flows although they do affect the capital and asset structure of an entity. The exclusion of non-cash transactions from the statement of cash flows is consistent with the objective of a statement of cash flows as these items do not involve cash flows in the current period. Examples of non-cash transactions are:
- (a) the acquisition of assets either by assuming directly related liabilities or by means of a finance lease;
 - (b) the acquisition of an entity by means of an equity issue; and

- (c) the conversion of debt to equity.

Components of cash and cash equivalents

- 45 An entity shall disclose the components of cash and cash equivalents and shall present a reconciliation of the amounts in its statement of cash flows with the equivalent items reported in the balance sheet.
- 46 In view of the variety of cash management practices and banking arrangements around the world and in order to comply with Ind AS 1 *Presentation of Financial Statements*, an entity discloses the policy which it adopts in determining the composition of cash and cash equivalents.
- 47 The effect of any change in the policy for determining components of cash and cash equivalents, for example, a change in the classification of financial instruments previously considered to be part of an entity's investment portfolio, is reported in accordance with Ind AS 8, *Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors*.

Other disclosures

- 48 An entity shall disclose, together with a commentary by management, the amount of significant cash and cash equivalent balances held by the entity that are not available for use by the group¹.
- 49 There are various circumstances in which cash and cash equivalent balances held by an entity are not available for use by the group². Examples include cash and cash equivalent balances held by a subsidiary that operates in a country where exchange controls or other legal restrictions apply when the balances are not available for general use by the parent or other subsidiaries.
- 50 Additional information may be relevant to users in understanding the financial position and liquidity of an entity. Disclosure of this information, together with a commentary by management, is encouraged and may include:
- (a) the amount of undrawn borrowing facilities that may be available for future operating activities and to settle capital commitments, indicating any restrictions on the use of these facilities;
 - (b) the aggregate amounts of the cash flows from each of operating, investing and financing activities related to interests in joint ventures reported using proportionate consolidation;

¹ The requirements shall be equally applicable to the entities in case of separate financial statements also.

² Ibid.

- (c) the aggregate amount of cash flows that represent increases in operating capacity separately from those cash flows that are required to maintain operating capacity; and
- (d) the amount of the cash flows arising from the operating, investing and financing activities of each reportable segment (see Ind AS 108 *Operating Segments*).

- 51 The separate disclosure of cash flows that represent increases in operating capacity and cash flows that are required to maintain operating capacity is useful in enabling the user to determine whether the entity is investing adequately in the maintenance of its operating capacity. An entity that does not invest adequately in the maintenance of its operating capacity may be prejudicing future profitability for the sake of current liquidity and distributions to owners.
- 52 The disclosure of segmental cash flows enables users to obtain a better understanding of the relationship between the cash flows of the business as a whole and those of its component parts and the availability and variability of segmental cash flows.

Appendix A

Illustrative Examples

Statement of cash flows for an entity other than a financial institution

This appendix accompanies, but is not part of, Ind AS 7.

1. The examples show only current period amounts. Corresponding amounts for the preceding period are required to be presented in accordance with Ind AS 1 *Presentation of Financial Statements*.
2. Information from the statement of profit and loss and balance sheet is provided to show how the statements of cash flows under the direct method and indirect method have been derived. Neither the statement of profit and loss nor the balance sheet is presented in conformity with the disclosure and presentation requirements of other Standards.
3. The following additional information is also relevant for the preparation of the statements of cash flows:

- all of the shares of a subsidiary were acquired for 590. The fair values of assets acquired and liabilities assumed were as follows:

Inventories	100
Accounts receivable	100
Cash	40
Property, plant and equipment	650
Trade payables	100
Long-term debt	200

- 250 was raised from the issue of share capital and a further 150 was raised from long-term borrowings and 100 was raised from short-term borrowing.
- interest expense was 400, of which 170 was paid during the period. Also, 100 relating to interest expense of the prior period was paid during the period.
- dividends paid were 1,200.
- the liability for tax at the beginning and end of the period was 1,000 and 400 respectively. During the period, a further 200 tax was provided for. Withholding tax on dividends received amounted to 100.
- during the period, the group acquired property, plant and equipment with an aggregate cost of 1,250 of which 900 was acquired by means of finance leases. Cash payments of 350 were made to purchase property, plant and equipment.
- plant with original cost of 80 and accumulated depreciation of 60 was sold for 20.
- accounts receivable as at the end of 20X2 include 100 of interest receivable.

Consolidated statement of profit and loss for the period ended 20X2^(a)

Sales	30,650
Cost of sales	(26,000)
Gross profit	4,650
Depreciation	(450)
Administrative and selling expenses	(910)
Interest expense	(400)
Investment income	500
Foreign exchange loss	(40)
Profit before taxation	3,350
Taxes on income	(300)
Profit	3,050

(a) The entity did not recognise any components of other comprehensive income in the period ended 20X2

Consolidated balance sheet as at end of 20X2

	20X2	20X1
Assets		
Cash and cash equivalents	230	160
Accounts receivable	1,900	1,200
Inventory	1,000	1,950
Portfolio investments	2,500	2,500
Property, plant and equipment at cost	3,730	1,910
Accumulated depreciation	(1,450)	(1,060)

Property, plant and equipment net	2,280	850
Total assets	7,910	6,660
Liabilities		
Trade payables	250	1,890
Interest payable	230	100
Income taxes payable	400	1,000
Long-term debt	2200	1,040
Short-term borrowing	100	—
Total liabilities	3,180	4,030
Shareholders' equity		
Share capital	1,500	1,250
Retained earnings	3,230	1,380
Total shareholders' equity	4,730	2,630
Total liabilities and shareholders' equity	7,910	6,660

Direct method statement of cash flows (paragraph 18(a))

20X2

Cash flows from operating activities

Cash receipts from customers	30,150
Cash paid to suppliers and employees	(27,600)
Cash generated from operations	2,550
Income taxes paid	(900)

Net cash from operating activities

1,650

Cash flows from investing activities

Acquisition of subsidiary X, net of cash acquired (Note A)	(550)
Purchase of property, plant and equipment (Note B)	(350)

Proceeds from sale of equipment	20	
Interest received	200	
Dividends received	200	
<i>Net cash used in investing activities</i>		(480)
Cash flows from financing activities		
Proceeds from issue of share capital	250	
Proceeds from long-term borrowings	150	
Proceeds from short term borrowings	100	
Payment of finance lease liabilities	(90)	
Interest paid	(270)	
Dividends paid	(1,200)	
<i>Net cash used in financing activities</i>		(1,060)
Net increase in cash and cash equivalents		110
Cash and cash equivalents at beginning of period (Note C)		120
Cash and cash equivalents at end of period (Note C)		230

Indirect method statement of cash flows (paragraph 18(b))

20X2

Cash flows from operating activities

Profit before taxation	3,350
Adjustments for:	
Depreciation	450
Foreign exchange loss	40

Investment income	(500)	
Interest expense	400	
	<u>3,740</u>	
Increase in trade and other receivables	(500)	
Decrease in inventories	1,050	
Decrease in trade payables	<u>(1,740)</u>	
Cash generated from operations	2,550	
Income taxes paid	<u>(900)</u>	
<i>Net cash from operating activities</i>		1,650
Cash flows from investing activities		
Acquisition of subsidiary X net of cash acquired (Note A)	(550)	
Purchase of property, plant and equipment (Note B)	(350)	
Proceeds from sale of equipment	20	
Interest received	200	
Dividends received	<u>200</u>	
<i>Net cash used in investing activities</i>		(480)
Cash flows from financing activities		
Proceeds from issue of share capital	250	
Proceeds from long-term borrowings	150	
Proceeds from short-term borrowings	100	
Payment of finance lease liabilities	(90)	
Interest paid	(270)	
Dividends paid	<u>(1,200)</u>	
<i>Net cash used in financing activities</i>		<u>(1,060)</u>

Net increase in cash and cash equivalents	110
Cash and cash equivalents at beginning of period (Note C)	120
Cash and cash equivalents at end of period (Note C)	230

Notes to the statement of cash flows (direct method and indirect method)

A. Obtaining control of subsidiary

During the period the Group obtained control of subsidiary X. The fair values of assets acquired and liabilities assumed were as follows:

Cash	40
Inventories	100
Accounts receivable	100
Property, plant and equipment	650
Trade payables	(100)
Long-term debt	(200)
Total purchase price paid in cash	590
Less: Cash of subsidiary X acquired	(40)
Cash paid to obtain control net of cash acquired	550

B. Property, plant and equipment

During the period, the Group acquired property, plant and equipment with an aggregate cost of 1,250 of which 900 was acquired by means of finance leases. Cash payments of 350 were made to purchase property, plant and equipment.

C. Cash and cash equivalents

Cash and cash equivalents consist of cash on hand and balances with banks, and investments in money market instruments. Cash and cash equivalents included in the statement of cash flows comprise the following amounts in the balance sheet:

	20X2	20X1
Cash on hand and balances with banks	40	25
Short-term investments	190	135
Cash and cash equivalents as previously reported	230	160
Effect of exchange rate changes	—	(40)
Cash and cash equivalents as restated	230	120

Cash and cash equivalents at the end of the period include deposits with banks of 100 held by a subsidiary which are not freely remissible to the holding company because of currency exchange restrictions.

The Group has undrawn borrowing facilities of 2,000 of which 700 may be used only for future expansion.

D. Segment information

	Segment A	Segment B	Total
Cash flows from:			
Operating activities	1,790	(140)	1,650
Investing activities	(640)	160	(480)
Financing activities	(840)	(220)	(1,060)
	310	(200)	110

Alternative presentation (indirect method)

As an alternative, in an indirect method statement of cash flows, operating profit before working capital changes is sometimes presented as follows:

Revenues excluding investment income	30,650
Operating expense excluding depreciation	(26,910)
Operating profit before working capital changes	3,740

Appendix B

Illustrative Examples

Statement of cash flows for a financial institution

This appendix accompanies, but is not part of Ind AS 7.

1. The example shows only current period amounts. Comparative amounts for the preceding period are required to be presented in accordance with Ind AS 1 *Presentation of Financial Statements*.
2. The example is presented using the direct method.

20X2

Cash flows from operating activities

Interest and commission receipts	28,447
Interest payments	(23,463)
Recoveries on loans previously written off	237
Cash payments to employees and suppliers	(997)
	<hr/> 4,224

(Increase) decrease in operating assets:

Short-term funds	(650)
Deposits held for regulatory or monetary control purposes	234
Funds advanced to customers	(288)
Net increase in credit card receivables	(360)
Other short-term negotiable securities	(120)

Increase (decrease) in operating liabilities:

Deposits from customers	600
Negotiable certificates of deposit	(200)

Net cash from operating activities before income tax	3,440	
Income taxes paid	(100)	
<i>Net cash from operating activities</i>		3,340

Cash flows from investing activities

Disposal of subsidiary Y	50	
Dividends received	200	
Interest received	300	
Proceeds from sales of non-dealing securities	1,200	
Purchase of non-dealing securities	(600)	
Purchase of property, plant and equipment	(500)	
<i>Net cash from investing activities</i>		650

Cash flows from financing activities

Issue of loan capital	1,000	
Issue of preference shares by subsidiary undertaking	800	
Repayment of long-term borrowings	(200)	
Net decrease in other borrowings	(1,000)	
Dividends paid	(400)	
<i>Net cash from financing activities</i>		200
Effects of exchange rate changes on cash and cash equivalents	600	
Net increase in cash and cash equivalents	4,790	
Cash and cash equivalents at beginning of period	4,050	
Cash and cash equivalents at end of period	8,840	

Appendix 1

Note: This Appendix is not a part of the Indian Accounting Standard. The purpose of this Appendix is only to bring out the differences, if any, between Indian Accounting Standard (Ind AS) 7 and the corresponding International Accounting Standard (IAS) 7, Statement of Cash Flows.

Comparison with IAS 7, *Statement of Cash Flows*

Ind AS 7 differs from International Accounting Standard (IAS) 7, *Statement of Cash Flows*, in the following major respects:

1. In case of other than financial entities, IAS 7 gives an option to classify the interest paid and interest and dividends received as item of operating cash flows. Ind AS 7 does not provide such an option and requires these item to be classified as item of financing activity and investing activity, respectively (refer to the paragraph 33).
2. IAS 7 gives an option to classify the dividend paid as an item of operating activity. However, Ind AS 7 requires it to be classified as a part of financing activity only.
3. Different terminology is used in this standard, e.g., the term 'balance sheet' is used instead of 'Statement of financial position' and 'Statement of profit and loss' is used instead of 'Statement of comprehensive income'.
4. Paragraph 2 of IAS 7 which states that IAS 7 supersedes the earlier version IAS 7 is deleted in Ind AS 7 as this is not relevant in Ind AS 7. However, paragraph number 2 is retained in Ind AS 7 to maintain consistency with paragraph numbers of IAS 7.
5. The following paragraph numbers appear as 'Deleted' in IAS 7. In order to maintain consistency with paragraph numbers of IAS 7, the paragraph numbers are retained in Ind AS 7:
 - (i) paragraph 29
 - (ii) paragraph 30

Indian Accounting Standard (Ind AS) 8

Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors

*(This Indian Accounting Standard includes paragraphs set in **bold type** and plain type, which have equal authority. Paragraphs in bold type indicate the main principles.)*

Objective

- 1 The objective of this Standard is to prescribe the criteria for selecting and changing accounting policies, together with the accounting treatment and disclosure of changes in accounting policies, changes in accounting estimates and corrections of errors. The Standard is intended to enhance the relevance and reliability of an entity's financial statements, and the comparability of those financial statements over time and with the financial statements of other entities.
- 2 Disclosure requirements for accounting policies, except those for changes in accounting policies, are set out in Ind AS 1 *Presentation of Financial Statements*.

Scope

- 3 **This Standard shall be applied in selecting and applying accounting policies, and accounting for changes in accounting policies, changes in accounting estimates and corrections of prior period errors.**
- 4 The tax effects of corrections of prior period errors and of retrospective adjustments made to apply changes in accounting policies are accounted for and disclosed in accordance with Ind AS 12 *Income Taxes*.

Definitions

- 5 **The following terms are used in this Standard with the meanings specified:**

Accounting policies are the specific principles, bases, conventions, rules and practices applied by an entity in preparing and presenting financial statements.

A change in accounting estimate is an adjustment of the carrying amount of an asset or a liability, or the amount of the periodic consumption of an

asset, that results from the assessment of the present status of, and expected future benefits and obligations associated with, assets and liabilities. Changes in accounting estimates result from new information or new developments and, accordingly, are not corrections of errors.

Indian Accounting Standards Ind ASs are Standards prescribed under Section 211(3C) of the Companies Act, 1956.

Material Omissions or misstatements of items are material if they could, individually or collectively, influence the economic decisions that users make on the basis of the financial statements. Materiality depends on the size and nature of the omission or misstatement judged in the surrounding circumstances. The size or nature of the item, or a combination of both, could be the determining factor.

Prior period errors are omissions from, and misstatements in, the entity's financial statements for one or more prior periods arising from a failure to use, or misuse of, reliable information that:

- (a) was available when financial statements for those periods were approved for issue; and
- (b) could reasonably be expected to have been obtained and taken into account in the preparation and presentation of those financial statements.

Such errors include the effects of mathematical mistakes, mistakes in applying accounting policies, oversights or misinterpretations of facts, and fraud.

Retrospective application is applying a new accounting policy to transactions, other events and conditions as if that policy had always been applied.

Retrospective restatement is correcting the recognition, measurement and disclosure of amounts of elements of financial statements as if a prior period error had never occurred.

Impracticable Applying a requirement is impracticable when the entity cannot apply it after making every reasonable effort to do so. For a particular prior period, it is impracticable to apply a change in an accounting policy retrospectively or to make a retrospective restatement to correct an error if:

- (a) the effects of the retrospective application or retrospective restatement are not determinable;
- (b) the retrospective application or retrospective restatement requires assumptions about what management's intent would have been in that period; or

- (c) **the retrospective application or retrospective restatement requires significant estimates of amounts and it is impossible to distinguish objectively information about those estimates that:**
 - (i) **provides evidence of circumstances that existed on the date(s) as at which those amounts are to be recognised, measured or disclosed; and**
 - (ii) **would have been available when the financial statements for that prior period were approved for issue from other information.**

Prospective application of a change in accounting policy and of recognising the effect of a change in an accounting estimate, respectively, are:

- (a) **applying the new accounting policy to transactions, other events and conditions occurring after the date as at which the policy is changed; and**
 - (b) **recognising the effect of the change in the accounting estimate in the current and future periods affected by the change.**
- 6 Assessing whether an omission or misstatement could influence economic decisions of users, and so be material, requires consideration of the characteristics of those users. The *Framework for the Preparation and Presentation of Financial Statements* issued by the Institute of Chartered Accountants of India states in paragraph 26 that 'It is assumed that users have a reasonable knowledge of business and economic activities and accounting and study the information with reasonable diligence.' Therefore, the assessment needs to take into account how users with such attributes could reasonably be expected to be influenced in making economic decisions.

Accounting policies

Selection and application of accounting policies

- 7 **When an Ind AS specifically applies to a transaction, other event or condition, the accounting policy or policies applied to that item shall be determined by applying the Ind AS.**
- 8 Ind ASs set out accounting policies that result in financial statements containing relevant and reliable information about the transactions, other events and conditions to which they apply. Those policies need not be applied when the effect of applying them is immaterial. However, it is inappropriate to make, or leave uncorrected, immaterial departures from Ind ASs to achieve a particular presentation of an entity's financial position, financial performance or cash flows.
- 9 Ind ASs are accompanied by guidance to assist entities in applying their requirements. All such guidance states whether it is an integral part of Ind ASs. Guidance that is an integral part of the Ind ASs is mandatory. Guidance that is

not an integral part of the Ind ASs does not contain requirements for financial statements.

- 10** In the absence of an Ind AS that specifically applies to a transaction, other event or condition, management shall use its judgement in developing and applying an accounting policy that results in information that is:

(a) relevant to the economic decision-making needs of users; and

(b) reliable, in that the financial statements:

- (i) represent faithfully the financial position, financial performance and cash flows of the entity;
- (ii) reflect the economic substance of transactions, other events and conditions, and not merely the legal form;
- (iii) are neutral, ie free from bias;
- (iv) are prudent; and
- (v) are complete in all material respects.

- 11** In making the judgement described in paragraph 10, management shall refer to, and consider the applicability of, the following sources in descending order:

- (a) the requirements in Ind ASs dealing with similar and related issues; and
- (b) the definitions, recognition criteria and measurement concepts for assets, liabilities, income and expenses in the *Framework*.

- 12** In making the judgement described in paragraph 10, management may also first consider the most recent pronouncements of International Accounting Standards Board and in absence thereof those of the other standard-setting bodies that use a similar conceptual framework to develop accounting standards, other accounting literature and accepted industry practices, to the extent that these do not conflict with the sources in paragraph 11.

Consistency of accounting policies

- 13** An entity shall select and apply its accounting policies consistently for similar transactions, other events and conditions, unless an Ind AS specifically requires or permits categorisation of items for which different policies may be appropriate. If an Ind AS requires or permits such categorisation, an appropriate accounting policy shall be selected and applied consistently to each category.

Changes in accounting policies

- 14 An entity shall change an accounting policy only if the change:**
- (a) is required by an Ind AS; or**
 - (b) results in the financial statements providing reliable and more relevant information about the effects of transactions, other events or conditions on the entity's financial position, financial performance or cash flows.**
- 15 Users of financial statements need to be able to compare the financial statements of an entity over time to identify trends in its financial position, financial performance and cash flows. Therefore, the same accounting policies are applied within each period and from one period to the next unless a change in accounting policy meets one of the criteria in paragraph 14.**
- 16 The following are not changes in accounting policies:**
- (a) the application of an accounting policy for transactions, other events or conditions that differ in substance from those previously occurring; and**
 - (b) the application of a new accounting policy for transactions, other events or conditions that did not occur previously or were immaterial.**
- 17 The initial application of a policy to revalue assets in accordance with Ind AS 16 *Property, Plant and Equipment* or Ind AS 38 *Intangible Assets* is a change in an accounting policy to be dealt with as a revaluation in accordance with Ind AS 16 or Ind AS 38, rather than in accordance with this Standard.**
- 18 Paragraphs 19–31 do not apply to the change in accounting policy described in paragraph 17.**

Applying changes in accounting policies

- 19 Subject to paragraph 23:**
- (a) an entity shall account for a change in accounting policy resulting from the initial application of an Ind AS in accordance with the specific transitional provisions, if any, in that Ind AS; and**
 - (b) when an entity changes an accounting policy upon initial application of an Ind AS that does not include specific transitional provisions applying to that change, or changes an accounting policy voluntarily, it shall apply the change retrospectively.**
- 20 For the purpose of this Standard, early application of an Ind AS is not a voluntary change in accounting policy.**

- 21 In the absence of an Ind AS that specifically applies to a transaction, other event or condition, management may, in accordance with paragraph 12, apply an accounting policy from the most recent pronouncements of International Accounting Standards Board and in absence thereof those of the other standard-setting bodies that use a similar conceptual framework to develop accounting standards. If, following an amendment of such a pronouncement, the entity chooses to change an accounting policy, that change is accounted for and disclosed as a voluntary change in accounting policy.

Retrospective application

- 22 Subject to paragraph 23, when a change in accounting policy is applied retrospectively in accordance with paragraph 19(a) or (b), the entity shall adjust the opening balance of each affected component of equity for the earliest prior period presented and the other comparative amounts disclosed for each prior period presented as if the new accounting policy had always been applied.

Limitations on retrospective application

- 23 When retrospective application is required by paragraph 19(a) or (b), a change in accounting policy shall be applied retrospectively except to the extent that it is impracticable to determine either the period-specific effects or the cumulative effect of the change.
- 24 When it is impracticable to determine the period-specific effects of changing an accounting policy on comparative information for one or more prior periods presented, the entity shall apply the new accounting policy to the carrying amounts of assets and liabilities as at the beginning of the earliest period for which retrospective application is practicable, which may be the current period, and shall make a corresponding adjustment to the opening balance of each affected component of equity for that period.
- 25 When it is impracticable to determine the cumulative effect, at the beginning of the current period, of applying a new accounting policy to all prior periods, the entity shall adjust the comparative information to apply the new accounting policy prospectively from the earliest date practicable.
- 26 When an entity applies a new accounting policy retrospectively, it applies the new accounting policy to comparative information for prior periods as far back as is practicable. Retrospective application to a prior period is not practicable unless it is practicable to determine the cumulative effect on the amounts in both the opening and closing balance sheets for that period. The amount of the resulting adjustment relating to periods before those presented in the financial statements is made to the opening balance of each affected component of equity of the earliest prior period presented. Usually the adjustment is made to retained earnings. However, the adjustment may be made to another component of equity (for example, to comply with an Ind AS). Any other information about prior periods, such as historical summaries of financial data, is also adjusted as far back as is practicable.

- 27 When it is impracticable for an entity to apply a new accounting policy retrospectively, because it cannot determine the cumulative effect of applying the policy to all prior periods, the entity, in accordance with paragraph 25, applies the new policy prospectively from the start of the earliest period practicable. It therefore disregards the portion of the cumulative adjustment to assets, liabilities and equity arising before that date. Changing an accounting policy is permitted even if it is impracticable to apply the policy prospectively for any prior period. Paragraphs 50–53 provide guidance on when it is impracticable to apply a new accounting policy to one or more prior periods.

Disclosure

- 28 When initial application of an Ind AS has an effect on the current period or any prior period, would have such an effect except that it is impracticable to determine the amount of the adjustment, or might have an effect on future periods, an entity shall disclose:
- (a) the title of the Ind AS;
 - (b) when applicable, that the change in accounting policy is made in accordance with its transitional provisions;
 - (c) the nature of the change in accounting policy;
 - (d) when applicable, a description of the transitional provisions;
 - (e) when applicable, the transitional provisions that might have an effect on future periods;
 - (f) for the current period and each prior period presented, to the extent practicable, the amount of the adjustment:
 - (i) for each financial statement line item affected; and
 - (ii) if Ind AS 33 *Earnings per Share* applies to the entity, for basic and diluted earnings per share;
 - (g) the amount of the adjustment relating to periods before those presented, to the extent practicable; and
 - (h) if retrospective application required by paragraph 19(a) or (b) is impracticable for a particular prior period, or for periods before those presented, the circumstances that led to the existence of that condition and a description of how and from when the change in accounting policy has been applied.

Financial statements of subsequent periods need not repeat these disclosures.

- 29 When a voluntary change in accounting policy has an effect on the current period or any prior period, would have an effect on that period except that it is

impracticable to determine the amount of the adjustment, or might have an effect on future periods, an entity shall disclose:

- (a) the nature of the change in accounting policy;**
- (b) the reasons why applying the new accounting policy provides reliable and more relevant information;**
- (c) for the current period and each prior period presented, to the extent practicable, the amount of the adjustment:**
 - (i) for each financial statement line item affected; and**
 - (ii) if Ind AS 33 applies to the entity, for basic and diluted earnings per share;**
- (d) the amount of the adjustment relating to periods before those presented, to the extent practicable; and**
- (e) if retrospective application is impracticable for a particular prior period, or for periods before those presented, the circumstances that led to the existence of that condition and a description of how and from when the change in accounting policy has been applied.**

Financial statements of subsequent periods need not repeat these disclosures.

- 30 When an entity has not applied a new Ind AS that has been issued but is not yet effective, the entity shall disclose:**

- (a) this fact; and**
- (b) known or reasonably estimable information relevant to assessing the possible impact that application of the new Ind AS will have on the entity's financial statements in the period of initial application.**

- 31 In complying with paragraph 30, an entity considers disclosing:**

- (a) the title of the new Ind AS;**
- (b) the nature of the impending change or changes in accounting policy;**
- (c) the date by which application of the Ind AS is required;**
- (d) the date as at which it plans to apply the Ind AS initially; and**
- (e) either:**
 - (i) a discussion of the impact that initial application of the Ind AS is expected to have on the entity's financial statements; or**

- (ii) if that impact is not known or reasonably estimable, a statement to that effect.

Changes in accounting estimates

- 32 As a result of the uncertainties inherent in business activities, many items in financial statements cannot be measured with precision but can only be estimated. Estimation involves judgements based on the latest available, reliable information. For example, estimates may be required of:
- (a) bad debts;
 - (b) inventory obsolescence;
 - (c) the fair value of financial assets or financial liabilities;
 - (d) the useful lives of, or expected pattern of consumption of the future economic benefits embodied in, depreciable assets; and
 - (e) warranty obligations.
- 33 The use of reasonable estimates is an essential part of the preparation of financial statements and does not undermine their reliability.
- 34 An estimate may need revision if changes occur in the circumstances on which the estimate was based or as a result of new information or more experience. By its nature, the revision of an estimate does not relate to prior periods and is not the correction of an error.
- 35 A change in the measurement basis applied is a change in an accounting policy, and is not a change in an accounting estimate. When it is difficult to distinguish a change in an accounting policy from a change in an accounting estimate, the change is treated as a change in an accounting estimate.
- 36 **The effect of change in an accounting estimate, other than a change to which paragraph 37 applies, shall be recognised prospectively by including it in profit or loss in:**
- (a) the period of the change, if the change affects that period only; or
 - (b) the period of the change and future periods, if the change affects both.
- 37 **To the extent that a change in an accounting estimate gives rise to changes in assets and liabilities, or relates to an item of equity, it shall be recognised by adjusting the carrying amount of the related asset, liability or equity item in the period of the change.**
- 38 Prospective recognition of the effect of a change in an accounting estimate means that the change is applied to transactions, other events and conditions from the date of the change in estimate. A change in an accounting estimate may affect only

the current period's profit or loss, or the profit or loss of both the current period and future periods. For example, a change in the estimate of the amount of bad debts affects only the current period's profit or loss and therefore is recognised in the current period. However, a change in the estimated useful life of, or the expected pattern of consumption of the future economic benefits embodied in, a depreciable asset affects depreciation expense for the current period and for each future period during the asset's remaining useful life. In both cases, the effect of the change relating to the current period is recognised as income or expense in the current period. The effect, if any, on future periods is recognised as income or expense in those future periods

Disclosure

- 39** An entity shall disclose the nature and amount of a change in an accounting estimate that has an effect in the current period or is expected to have an effect in future periods, except for the disclosure of the effect on future periods when it is impracticable to estimate that effect.
- 40** If the amount of the effect in future periods is not disclosed because estimating it is impracticable, an entity shall disclose that fact.

Errors

- 41** Errors can arise in respect of the recognition, measurement, presentation or disclosure of elements of financial statements. Financial statements do not comply with Ind ASs if they contain either material errors or immaterial errors made intentionally to achieve a particular presentation of an entity's financial position, financial performance or cash flows. Potential current period errors discovered in that period are corrected before the financial statements are approved for issue. However, material errors are sometimes not discovered until a subsequent period, and these prior period errors are corrected in the comparative information presented in the financial statements for that subsequent period (see paragraphs 42–47).
- 42** Subject to paragraph 43, an entity shall correct material prior period errors retrospectively in the first set of financial statements approved for issue after their discovery by:
- (a) restating the comparative amounts for the prior period(s) presented in which the error occurred; or
 - (b) if the error occurred before the earliest prior period presented, restating the opening balances of assets, liabilities and equity for the earliest prior period presented.

Limitations on retrospective restatement

- 43** A prior period error shall be corrected by retrospective restatement except to the extent that it is impracticable to determine either the period-specific effects or the cumulative effect of the error.
- 44** When it is impracticable to determine the period-specific effects of an error on comparative information for one or more prior periods presented, the entity shall restate the opening balances of assets, liabilities and equity for the earliest period for which retrospective restatement is practicable (which may be the current period).
- 45** When it is impracticable to determine the cumulative effect, at the beginning of the current period, of an error on all prior periods, the entity shall restate the comparative information to correct the error prospectively from the earliest date practicable.
- 46** The correction of a prior period error is excluded from profit or loss for the period in which the error is discovered. Any information presented about prior periods, including any historical summaries of financial data, is restated as far back as is practicable.
- 47** When it is impracticable to determine the amount of an error (eg a mistake in applying an accounting policy) for all prior periods, the entity, in accordance with paragraph 45, restates the comparative information prospectively from the earliest date practicable. It therefore disregards the portion of the cumulative restatement of assets, liabilities and equity arising before that date. Paragraphs 50–53 provide guidance on when it is impracticable to correct an error for one or more prior periods.
- 48** Corrections of errors are distinguished from changes in accounting estimates. Accounting estimates by their nature are approximations that may need revision as additional information becomes known. For example, the gain or loss recognised on the outcome of a contingency is not the correction of an error.

Disclosure of prior period errors

- 49** In applying paragraph 42, an entity shall disclose the following:
- (a) the nature of the prior period error;
 - (b) for each prior period presented, to the extent practicable, the amount of the correction:
 - (i) for each financial statement line item affected; and
 - (ii) if Ind AS 33 applies to the entity, for basic and diluted earnings per share;
 - (c) the amount of the correction at the beginning of the earliest prior period presented; and

- (d) if retrospective restatement is impracticable for a particular prior period, the circumstances that led to the existence of that condition and a description of how and from when the error has been corrected.

Financial statements of subsequent periods need not repeat these disclosures.

Impracticability in respect of retrospective application and retrospective restatement

- 50 In some circumstances, it is impracticable to adjust comparative information for one or more prior periods to achieve comparability with the current period. For example, data may not have been collected in the prior period(s) in a way that allows either retrospective application of a new accounting policy (including, for the purpose of paragraphs 51–53, its prospective application to prior periods) or retrospective restatement to correct a prior period error, and it may be impracticable to recreate the information.
- 51 It is frequently necessary to make estimates in applying an accounting policy to elements of financial statements recognised or disclosed in respect of transactions, other events or conditions. Estimation is inherently subjective, and estimates may be developed after the reporting period. Developing estimates is potentially more difficult when retrospectively applying an accounting policy or making a retrospective restatement to correct a prior period error, because of the longer period of time that might have passed since the affected transaction, other event or condition occurred. However, the objective of estimates related to prior periods remains the same as for estimates made in the current period, namely, for the estimate to reflect the circumstances that existed when the transaction, other event or condition occurred.
- 52 Therefore, retrospectively applying a new accounting policy or correcting a prior period error requires distinguishing information that
- (a) provides evidence of circumstances that existed on the date(s) as at which the transaction, other event or condition occurred, and
 - (b) would have been available when the financial statements for that prior period were approved for issue
- from other information. For some types of estimates (eg an estimate of fair value not based on an observable price or observable inputs), it is impracticable to distinguish these types of information. When retrospective application or retrospective restatement would require making a significant estimate for which it is impossible to distinguish these two types of information, it is impracticable to apply the new accounting policy or correct the prior period error retrospectively.
- 53 Hindsight should not be used when applying a new accounting policy to, or correcting amounts for, a prior period, either in making assumptions about what management's intentions would have been in a prior period or estimating the

amounts recognised, measured or disclosed in a prior period. For example, when an entity corrects a prior period error in measuring financial assets previously classified as held-to-maturity investments in accordance with Ind AS 39 *Financial Instruments: Recognition and Measurement*, it does not change their basis of measurement for that period if management decided later not to hold them to maturity. In addition, when an entity corrects a prior period error in calculating its liability for employees' accumulated sick leave in accordance with Ind AS 19 *Employee Benefits*, it disregards information about an unusually severe influenza season during the next period that became available after the financial statements for the prior period were approved for issue. The fact that significant estimates are frequently required when amending comparative information presented for prior periods does not prevent reliable adjustment or correction of the comparative information.

Appendix A

References to matters contained in other Indian Accounting Standards

This Appendix is an integral part of Indian Accounting Standard (Ind AS) 8.

Appendix B, Liabilities arising from Participating in a Specific Market— Waste Electrical and Electronic Equipment contained in Ind AS 37 Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets makes reference to (Ind AS) 8

Appendix B

Guidance on implementing Ind AS 8 Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors

(This guidance accompanies, but is not part of, Ind AS 8.)

Example 1 – Retrospective restatement of errors

- 1.1 During 20X2, Beta Co discovered that some products that had been sold during 20X1 were incorrectly included in inventory at 31 December 20X1 at Rs. 6,500.
- 1.2 Beta's accounting records for 20X2 show sales of Rs.104,000, cost of goods sold of Rs. 86,500 (including Rs. 6,500 for the error in opening inventory), and income taxes of Rs. 5,250.
- 1.3 In 20X1, Beta reported:

	Rs.
Sales	73,500
Cost of goods sold	(53,500)
Profit before income taxes	<u>20,000</u>
Income taxes	(6,000)
Profit	<u>14,000</u>

- 1.4 20X1 opening retained earnings was Rs. 20,000 and closing retained earnings was Rs. 34,000.
- 1.5 Beta's income tax rate was 30 per cent for 20X2 and 20X1. It had no other income or expenses.
- 1.6 Beta had Rs.5,000 of share capital throughout, and no other components of equity except for retained earnings. Its shares are not publicly traded and it does not disclose earnings per share.

Beta Co Extract from the statement of profit and loss

	20X2 Rs.	(restated) 20X1 Rs.
Sales	104,000	73,500
Cost of goods sold	(80,000)	(60,000)
Profit before income taxes	24,000	13,500
Income taxes	(7,200)	(4,050)
Profit	16,800	9,450

Beta Co Statement of changes in equity

	Share capital Rs.	Retained earnings Rs.	Total Rs.
Balance at 31 December 20X0	5,000	20,000	25,000
Profit for the year ended 31 December 20X1 as restated	—	9,450	9,450
Balance at 31 December 20X1	5,000	29,450	34,450
Profit for the year ended 31 December 20X2	—	16,800	16,800
Balance at 31 December 20X2	5,000	46,250	51,250

Extracts from the notes

- 1 Some products that had been sold in 20X1 were incorrectly included in inventory at 31 December 20X1 at Rs. 6,500. The financial statements of 20X1 have been restated to correct this error. The effect of the restatement on those financial statements is summarised below. There is no effect in 20X2.

Example 2 – Prospective application of a change in accounting policy when retrospective application is not practicable

- 2.1. During 20X2, Delta Co changed its accounting policy for depreciating property, plant and equipment, so as to apply much more fully a components approach, whilst at the same time adopting the revaluation model.

2.2. In years before 20X2, Delta's asset records were not sufficiently detailed to apply a components approach fully. At the end of 20X1, management commissioned an engineering survey, which provided information on the components held and their fair values, useful lives, estimated residual values and depreciable amounts at the beginning of 20X2. However, the survey did not provide a sufficient basis for reliably estimating the cost of those components that had not previously been accounted for separately, and the existing records before the survey did not permit this information to be reconstructed.

3.3 Delta's management considered how to account for each of the two aspects of the accounting change. They determined that it was not practicable to account for the change to a fuller components approach retrospectively, or to account for that change prospectively from any earlier date than the start of 20X2. Also, the change from a cost model to a revaluation model is required to be accounted for prospectively. Therefore, management concluded that it should apply Delta's new policy prospectively from the start of 20X2.

2.3. Additional information:

Delta's tax rate is 30 per cent

	Rs.
Property, plant and equipment at the end of 20X1:	
Cost	25,000
Depreciation	(14,000)
Net book value	11,000
Prospective depreciation expense for 20X2 (old basis)	1,500
Some results of the engineering survey:	
Valuation	17,000
Estimated residual value	3,000
Average remaining asset life (years)	7
Depreciation expense on existing property, plant and equipment for 20X2 (new basis)	2,000

Extract from the notes

- 1 From the start of 20X2, Delta changed its accounting policy for depreciating property, plant and equipment, so as to apply much more fully a components approach, whilst at the same time adopting the revaluation model. Management takes the view that this policy provides reliable and more relevant information because it deals more accurately with the components of property, plant and equipment and is based on up-to-date values. The policy has been applied prospectively from the start of 20X2 because it was not practicable to estimate the effects of applying the policy either retrospectively, or prospectively from any earlier date. Accordingly, the adoption of the new policy has no effect on prior years. The effect on the current year is to increase the carrying amount of property, plant and equipment at the start of the year by Rs. 6,000; increase the opening deferred tax provision by Rs. 1,800; create a revaluation surplus at the start of the year of Rs. 4,200; increase depreciation expense by Rs. 500; and reduce tax expense by Rs. 150.

Appendix 1

Note: This Appendix is not a part of the Indian Accounting Standard. The purpose of this Appendix is only to bring out the differences, if any, between Indian Accounting Standard (Ind AS) 8 and the corresponding International Accounting Standard (IAS) 8, *Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors*.

Comparison with IAS 8, Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors

1. Different terminology is used in this standard, e.g., the term 'balance sheet' is used instead of 'Statement of financial position' and 'Statement of profit and loss' is used instead of 'Statement of comprehensive income'. The words 'approval of the financial statements for issue have been used instead of 'authorisation of the financial statements for issue' in the context of financial statements considered for the purpose of events after the reporting period.
- 2 In paragraph 12 of Ind AS 8, it is mentioned that in absence of an Ind AS, management may first consider the most recent pronouncements of International Accounting Standards Board.

Indian Accounting Standard (Ind AS) 10 ***Events after the Reporting Period***

*(This Indian Accounting Standard includes paragraphs set in **bold type** and plain type, which have equal authority. Paragraphs in bold type indicate the main principles.)*

Objective

1. The objective of this Standard is to prescribe:
 - (a) When an entity should adjust its financial statements for events after the reporting period; and
 - (b) the disclosures that an entity should give about the date when the financial statements were approved for issue and about events after the reporting period.

The Standard also requires that an entity should not prepare its financial statements on a going concern basis if events after the reporting period indicate that the going concern assumption is not appropriate.

Scope

2. This Standard shall be applied in the accounting for, and disclosure of, events after the reporting period.

Definitions

3. The following terms are used in this Standard with the meanings specified:

Events after the reporting period are those events, favourable and unfavourable, that occur between the end of the reporting period and the date when the financial statements are approved by the Board of Directors in case of a company, and, by the corresponding approving authority in case of any other entity for issue. Two types of events can be identified:

(a) those that provide evidence of conditions that existed at the end of the reporting period (*adjusting events after the reporting period*); and

(b) those that are indicative of conditions that arose after the reporting period (*non-adjusting events after the reporting period*).

4. The process involved in approving the financial statements for issue will vary depending upon the management structure, statutory requirements and procedures followed in preparing and finalising the financial statements.
5. In some cases, an entity is required to submit its financial statements to its shareholders for approval after the financial statements have been approved by the Board for issue. In such cases, the financial statements are approved for issue on the date of approval by the Board, not the date when shareholders approve the financial statements.
6. In some cases, the management of an entity is required to issue its financial statements to a supervisory board (made up solely of non-executives) for approval. In such cases, the financial statements are approved for issue when the management approves them for issue to the supervisory board.

Example

On 18 March 20X2, the management of an entity approves financial statements for issue to its supervisory board. The supervisory board is made up solely of non-executives and may include representatives of employees and other outside interests. The supervisory board approves the financial statements on 26 March 20X2. The financial statements are made available to shareholders and others on 1 April 20X2. The shareholders approve the financial statements at their annual meeting on 15 May 20X2 and the financial statements are then filed with a regulatory body on 17 May 20X2.

The financial statements are approved for issue on 18 March 20X2 (date of management approval for issue to the supervisory board).

7. Events after the reporting period include all events up to the date when the financial statements are approved for issue, even if those events occur after the public announcement of profit or of other selected financial information.

Recognition and measurement

Adjusting events after the reporting period

8. An entity shall adjust the amounts recognised in its financial statements to reflect adjusting events after the reporting period.

9. The following are examples of adjusting events after the reporting period that require an entity to adjust the amounts recognised in its financial statements, or to recognise items that were not previously recognised:
- (a) the settlement after the reporting period of a court case that confirms that the entity had a present obligation at the end of the reporting period. The entity adjusts any previously recognised provision related to this court case in accordance with Ind AS 37 *Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets* or recognises a new provision. The entity does not merely disclose a contingent liability because the settlement provides additional evidence that would be considered in accordance with paragraph 16 of Ind AS 37.
 - (b) the receipt of information after the reporting period indicating that an asset was impaired at the end of the reporting period, or that the amount of a previously recognised impairment loss for that asset needs to be adjusted. For example:
 - (i) the bankruptcy of a customer that occurs after the reporting period usually confirms that a loss existed at the end of the reporting period on a trade receivable and that the entity needs to adjust the carrying amount of the trade receivable; and
 - (ii) the sale of inventories after the reporting period may give evidence about their net realisable value at the end of the reporting period.
 - (c) the determination after the reporting period of the cost of assets purchased, or the proceeds from assets sold, before the end of the reporting period.
 - (d) the determination after the reporting period of the amount of profit-sharing or bonus payments, if the entity had a present legal or constructive obligation at the end of the reporting period to make such payments as a result of events before that date (see Ind AS 19 *Employee Benefits*).
 - (e) the discovery of fraud or errors that show that the financial statements are incorrect.

Non-adjusting events after the reporting period

10. An entity shall not adjust the amounts recognised in its financial statements to reflect non-adjusting events after the reporting period.
11. An example of a non-adjusting event after the reporting period is a decline in market value of investments between the end of the reporting period and the date when the financial statements are approved for issue. The decline in market value does not normally relate to the condition of the investments at the end of the reporting period, but reflects circumstances that have arisen subsequently. Therefore, an entity does not adjust the amounts recognised in its financial statements for the investments. Similarly, the entity does not update the amounts disclosed for the investments as at the end of the reporting period, although it may need to give additional disclosure under paragraph 21.

Dividends

12. If an entity declares dividends to holders of equity instruments (as defined in Ind AS 32 *Financial Instruments: Presentation*) after the reporting period, the entity shall not recognise those dividends as a liability at the end of the reporting period.

13. If dividends are declared after the reporting period but before the financial statements are approved for issue, the dividends are not recognised as a liability at the end of the reporting period because no obligation exists at that time. Such dividends are disclosed in the notes in accordance with Ind AS 1 *Presentation of Financial Statements*.

Going concern

14. An entity shall not prepare its financial statements on a going concern basis if management determines after the reporting period either that it intends to liquidate the entity or to cease trading, or that it has no realistic alternative but to do so.
15. Deterioration in operating results and financial position after the reporting period may indicate a need to consider whether the going concern assumption is still appropriate. If the going concern assumption is no longer appropriate, the effect is so pervasive that this Standard requires a fundamental change in the basis of accounting, rather than an adjustment to the amounts recognised within the original basis of accounting.
16. Ind AS 1 specifies required disclosures if:
- (a) the financial statements are not prepared on a going concern basis; or
 - (b) management is aware of material uncertainties related to events or conditions that may cast significant doubt upon the entity's ability to continue as a going concern. The events or conditions requiring disclosure may arise after the reporting period.

Disclosure

Date of approval for issue

17. An entity shall disclose the date when the financial statements were approved for issue and who gave that approval. If the entity's owners or others have the power to amend the financial statements after issue, the entity shall disclose that fact.
18. It is important for users to know when the financial statements were approved for issue, because the financial statements do not reflect events after this date.

Updating disclosure about conditions at the end of the reporting period

19. If an entity receives information after the reporting period about conditions that existed at the end of the reporting period, it shall update disclosures that relate to those conditions, in the light of the new information.
20. In some cases, an entity needs to update the disclosures in its financial statements to reflect information received after the reporting period, even when the information does not affect the amounts that it recognises in its financial statements. One example of the need to update disclosures is when evidence becomes available after the reporting period about a contingent liability that existed at the end of the reporting period. In addition to

considering whether it should recognise or change a provision under Ind AS 37, an entity updates its disclosures about the contingent liability in the light of that evidence.

Non-adjusting events after the reporting period

21. If non-adjusting events after the reporting period are material, non-disclosure could influence the economic decisions that users make on the basis of the financial statements. Accordingly, an entity shall disclose the following for each material category of non-adjusting event after the reporting period:
 - (a) the nature of the event; and
 - (b) an estimate of its financial effect, or a statement that such an estimate cannot be made.
22. The following are examples of non-adjusting events after the reporting period that would generally result in disclosure:
 - (a) a major business combination after the reporting period (Ind AS 103 *Business Combinations* requires specific disclosures in such cases) or disposing of a major subsidiary;
 - (b) announcing a plan to discontinue an operation;
 - (c) major purchases of assets, classification of assets as held for sale in accordance with Ind AS 105, *Non-current Assets Held for Sale and Discontinued Operations*, other disposals of assets, or expropriation of major assets by government;
 - (d) the destruction of a major production plant by a fire after the reporting period;
 - (e) announcing, or commencing the implementation of, a major restructuring (see Ind AS 37);
 - (f) major ordinary share transactions and potential ordinary share transactions after the reporting period (Ind AS 33 *Earnings per Share* requires an entity to disclose a description of such transactions, other than when such transactions involve capitalisation or bonus issues, share splits or reverse share splits all of which are required to be adjusted under Ind AS 33);
 - (g) abnormally large changes after the reporting period in asset prices or foreign exchange rates;
 - (h) changes in tax rates or tax laws enacted or announced after the reporting period that have a significant effect on current and deferred tax assets and liabilities (see Ind AS 12 *Income Taxes*);
 - (i) entering into significant commitments or contingent liabilities, for example, by issuing significant guarantees; and
 - (j) commencing major litigation arising solely out of events that occurred after the reporting period.

Appendix A

Distribution of Non-cash Assets to Owners¹

This Appendix is an integral part of Ind AS 10.

Background

- 1 Sometimes an entity distributes assets other than cash (non-cash assets) as dividends to its owners² acting in their capacity as owners. In those situations, an entity may also give its owners a choice of receiving either non-cash assets or a cash alternative.
- 2 Indian Accounting Standards (Ind ASs) do not provide guidance on how an entity should measure distributions to its owners (commonly referred to as dividends). Ind AS 1 requires an entity to present details of dividends recognised as distributions to owners either in the statement of changes in equity presented as a part of the balance sheet or in the notes to the financial statements.

Scope

- 3 This Appendix applies to the following types of non-reciprocal distributions of assets by an entity to its owners acting in their capacity as owners:
 - (a) distributions of non-cash assets (eg items of property, plant and equipment, businesses as defined in Ind AS 103, ownership interests in another entity or disposal groups as defined in Ind AS 105; and
 - (b) distributions that give owners a choice of receiving either non-cash assets or a cash alternative.
- 4 This Appendix applies only to distributions in which all owners of the same class of equity instruments are treated equally.
- 5 This Appendix does not apply to a distribution of a non-cash asset that is ultimately controlled by the same party or parties before and after the distribution. This exclusion applies to the separate, individual and consolidated financial statements of an entity that makes the distribution.
- 6 In accordance with paragraph 5, this Appendix does not apply when the non-cash asset is ultimately controlled by the same parties both before and after the distribution. Paragraph B2 of Ind AS 103 states that 'A group of individuals shall be regarded as controlling an entity when, as a result of contractual arrangements, they collectively have the power to govern its financial and operating policies so as to obtain benefits from its activities.' Therefore, for a

¹ This Appendix deals, inter alia, with when to recognise dividends payable to its owners.

² Paragraph 7 of Ind AS 1 defines owners as holders of instruments classified as equity.

distribution to be outside the scope of this Appendix on the basis that the same parties control the asset both before and after the distribution, a group of individual shareholders receiving the distribution must have, as a result of contractual arrangements, such ultimate collective power over the entity making the distribution.

- 7 In accordance with paragraph 5, this Appendix does not apply when an entity distributes some of its ownership interests in a subsidiary but retains control of the subsidiary. The entity making a distribution that results in the entity recognising a non-controlling interest in its subsidiary accounts for the distribution in accordance with Ind AS 27.
- 8 This Appendix addresses only the accounting by an entity that makes a non-cash asset distribution. It does not address the accounting by shareholders who receive such a distribution.

Issues

- 9 When an entity declares a distribution and has an obligation to distribute the assets concerned to its owners, it must recognise a liability for the dividend payable. Consequently, this Appendix addresses the following issues:
 - (a) When should the entity recognise the dividend payable?
 - (b) How should an entity measure the dividend payable?
 - (c) When an entity settles the dividend payable, how should it account for any difference between the carrying amount of the assets distributed and the carrying amount of the dividend payable?

Accounting Principles

When to recognise a dividend payable

- 10 The liability to pay a dividend shall be recognised when the dividend is appropriately authorised and is no longer at the discretion of the entity, which is the date:
 - (a) when declaration of the dividend, eg by management or the board of directors, is approved by the relevant authority, eg the shareholders, if the jurisdiction requires such approval, or
 - (b) when the dividend is declared, eg by management or the board of directors, if the jurisdiction does not require further approval.

Measurement of a dividend payable

- 11 An entity shall measure a liability to distribute non-cash assets as a dividend to its owners at the fair value of the assets to be distributed.

- 12 If an entity gives its owners a choice of receiving either a non-cash asset or a cash alternative, the entity shall estimate the dividend payable by considering both the fair value of each alternative and the associated probability of owners selecting each alternative.
- 13 At the end of each reporting period and at the date of settlement, the entity shall review and adjust the carrying amount of the dividend payable, with any changes in the carrying amount of the dividend payable recognised in equity as adjustments to the amount of the distribution.

Accounting for any difference between the carrying amount of the assets distributed and the carrying amount of the dividend payable when an entity settles the dividend payable

- 14 When an entity settles the dividend payable, it shall recognise the difference, if any, between the carrying amount of the assets distributed and the carrying amount of the dividend payable in profit or loss.

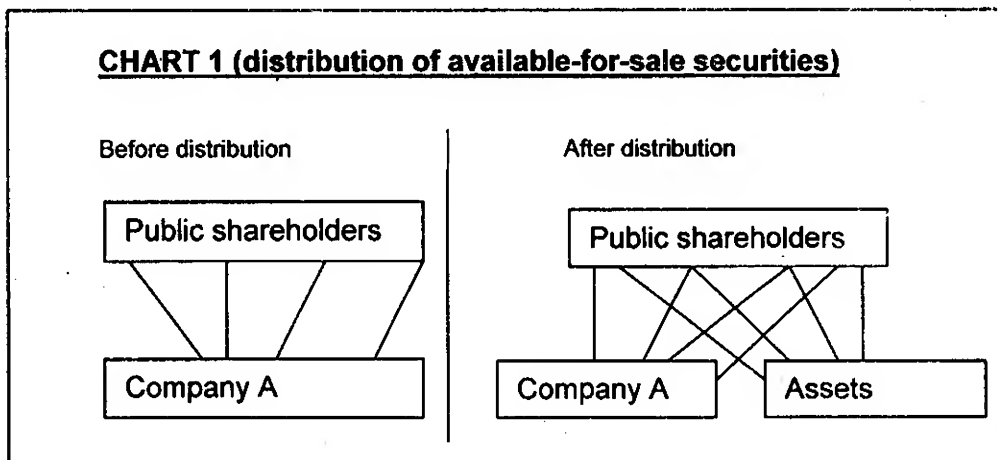
Presentation and disclosures

- 15 An entity shall present the difference described in paragraph 14 as a separate line item in profit or loss.
- 16 An entity shall disclose the following information, if applicable:
- (a) the carrying amount of the dividend payable at the beginning and end of the period; and
 - (b) the increase or decrease in the carrying amount recognised in the period in accordance with paragraph 13 as result of a change in the fair value of the assets to be distributed.
- 17 If, after the end of a reporting period but before the financial statements are approved for issue, an entity declares a dividend to distribute a non-cash asset, it shall disclose:
- (a) the nature of the asset to be distributed;
 - (b) the carrying amount of the asset to be distributed as of the end of the reporting period; and
 - (c) the estimated fair value of the asset to be distributed as of the end of the reporting period, if it is different from its carrying amount, and the information about the method used to determine that fair value required by Ind AS 107 paragraph 27(a) and (b).

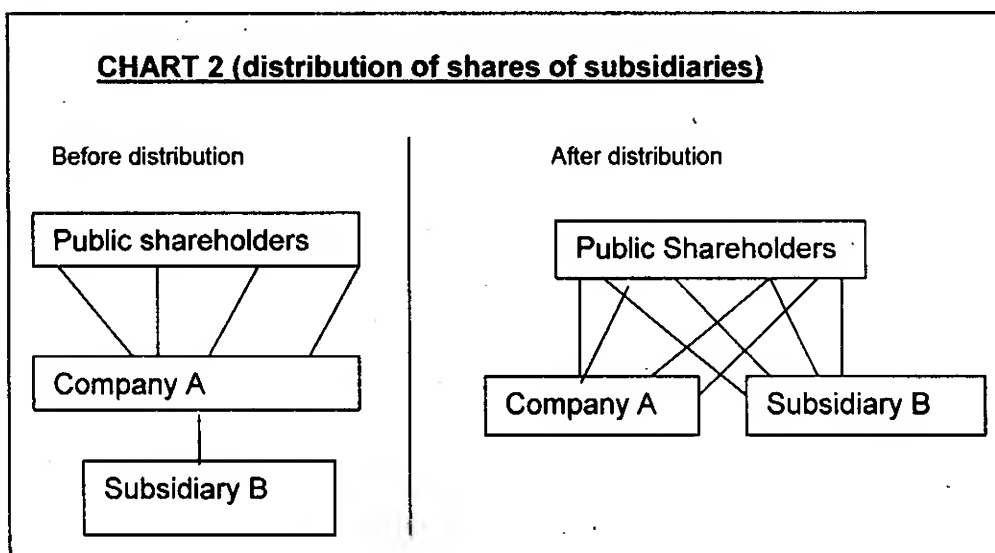
Illustrative examples

These examples accompany, but are not part of this appendix

Scope of the Appendix (paragraphs 3–8)



- IE1 Assume Company A is owned by public shareholders. No single shareholder controls Company A and no group of shareholders is bound by a contractual agreement to act together to control Company A jointly. Company A distributes certain assets (eg available-for-sale securities) pro rata to the shareholders. This transaction is within the scope of the Appendix.
- IE2 However, if one of the shareholders (or a group bound by a contractual agreement to act together) controls Company A both before and after the transaction, the entire transaction (including the distributions to the non-controlling shareholders) is not within the scope of the Appendix. This is because in a pro rata distribution to all owners of the same class of equity instruments, the controlling shareholder (or group of shareholders) will continue to control the non-cash assets after the distribution.



- IE3** Assume Company A is owned by public shareholders. No single shareholder controls Company A and no group of shareholders is bound by a contractual agreement to act together to control Company A jointly. Company A owns all of the shares of Subsidiary B. Company A distributes all of the shares of Subsidiary B pro rata to its shareholders, thereby losing control of Subsidiary B. This transaction is within the scope of the Appendix.
- IE4** However, if Company A distributes to its shareholders shares of Subsidiary B representing only a non-controlling interest in Subsidiary B and retains control of Subsidiary B, the transaction is not within the scope of the Appendix. Company A accounts for the distribution in accordance with Ind AS 27 *Consolidated and Separate Financial Statements*. Company A controls Company B both before and after the transaction.

Appendix 1

Note: This Appendix is not a part of the Indian Accounting Standard. The purpose of this Appendix is only to bring out the differences, if any, between Indian Accounting Standard (Ind AS) 10 and the corresponding International Accounting Standard (IAS) 10, Events after the Reporting Period.

Comparison with IAS 10, Events after the Reporting Period and IFRIC Interpretation 17

- 1 Different terminology is used in this standard, e.g., the term 'balance sheet' is used instead of 'Statement of financial position'. The words 'approval of the financial statements for issue' have been used instead of 'authorisation of the financial statements for issue' in the context of financial statements considered for the purpose of events after the reporting period.

Indian Accounting Standard (Ind AS) 20

Accounting for Government Grants and Disclosure of Government Assistance

(This Indian Accounting Standard includes paragraphs set in bold type and plain type, which have equal authority. Paragraphs in bold type indicate the main principles.)

Scope

- 1 This Standard shall be applied in accounting for, and in the disclosure of, government grants and in the disclosure of other forms of government assistance.
- 2 This Standard does not deal with:
 - (a) the special problems arising in accounting for government grants in financial statements reflecting the effects of changing prices or in supplementary information of a similar nature.
 - (b) government assistance that is provided for an entity in the form of benefits that are available in determining taxable profit or tax loss, or are determined or limited on the basis of income tax liability. Examples of such benefits are income tax holidays, investment tax credits, accelerated depreciation.
 - (c) government participation in the ownership of the entity.
 - (d) government grants covered by Ind AS , *Agriculture*¹.

Definitions

- 3 The following terms are used in this Standard with the meanings specified:

Government refers to government, government agencies and similar bodies whether local, national or international.

Government assistance is action by government designed to provide an economic benefit specific to an entity or range of entities qualifying under certain criteria. Government assistance for the purpose of this Standard does not include benefits provided only indirectly through action affecting general trading conditions, such as the provision of infrastructure in development areas or the imposition of trading constraints on competitors.

¹ This Standard is under formulation.

Government grants are assistance by government in the form of transfers of resources to an entity in return for past or future compliance with certain conditions relating to the operating activities of the entity. They exclude those forms of government assistance which cannot reasonably have a value placed upon them and transactions with government which cannot be distinguished from the normal trading transactions of the entity².

Grants related to assets are government grants whose primary condition is that an entity qualifying for them should purchase, construct or otherwise acquire long-term assets. Subsidiary conditions may also be attached restricting the type or location of the assets or the periods during which they are to be acquired or held.

Grants related to income are government grants other than those related to assets.

Forgivable loans are loans which the lender undertakes to waive repayment of under certain prescribed conditions.

Fair value is the amount for which an asset could be exchanged between a knowledgeable, willing buyer and a knowledgeable, willing seller in an arm's length transaction.

- 4 Government assistance takes many forms varying both in the nature of the assistance given and in the conditions which are usually attached to it. The purpose of the assistance may be to encourage an entity to embark on a course of action which it would not normally have taken if the assistance was not provided.
- 5 The receipt of government assistance by an entity may be significant for the preparation of the financial statements for two reasons. Firstly, if resources have been transferred, an appropriate method of accounting for the transfer must be found. Secondly, it is desirable to give an indication of the extent to which the entity has benefited from such assistance during the reporting period. This facilitates comparison of an entity's financial statements with those of prior periods and with those of other entities.
- 6 Government grants are sometimes called by other names such as subsidies, subventions, or premiums.

Government grants

- 7 Government grants, including non-monetary grants at fair value, shall not be recognised until there is reasonable assurance that:
 - (a) the entity will comply with the conditions attaching to them; and
 - (b) the grants will be received.
- 8 A government grant is not recognised until there is reasonable assurance that the entity will comply with the conditions attaching to it, and that the grant will

² See Appendix A Government Assistance—No Specific Relation to Operating Activities

be received. Receipt of a grant does not of itself provide conclusive evidence that the conditions attaching to the grant have been or will be fulfilled.

- 9 The manner in which a grant is received does not affect the accounting method to be adopted in regard to the grant. Thus a grant is accounted for in the same manner whether it is received in cash or as a reduction of a liability to the government.
- 10 A forgivable loan from government is treated as a government grant when there is reasonable assurance that the entity will meet the terms for forgiveness of the loan.
- 10A The benefit of a government loan at a below-market rate of interest is treated as a government grant. The loan shall be recognised and measured in accordance with Ind AS 39 *Financial Instruments: Recognition and Measurement*. The benefit of the below-market rate of interest shall be measured as the difference between the initial carrying value of the loan determined in accordance with Ind AS 39 and the proceeds received. The benefit is accounted for in accordance with this Standard. The entity shall consider the conditions and obligations that have been, or must be, met when identifying the costs for which the benefit of the loan is intended to compensate.
- 11 Once a government grant is recognised, any related contingent liability or contingent asset is treated in accordance with Ind AS 37, *Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets*.
- 12 **Government grants shall be recognised in profit or loss on a systematic basis over the periods in which the entity recognises as expenses the related costs for which the grants are intended to compensate.**
- 13 There are two broad approaches to the accounting for government grants: the capital approach, under which a grant is recognised outside profit or loss, and the income approach, under which a grant is recognised in profit or loss over one or more periods.
- 14 Those in support of the capital approach argue as follows:
 - (a) government grants are a financing device and should be dealt with as such in the balance sheet rather than be recognised in profit or loss to offset the items of expense that they finance. Because no repayment is expected, such grants should be recognised outside profit or loss.
 - (b) it is inappropriate to recognise government grants in profit or loss, because they are not earned but represent an incentive provided by government without related costs.
- 15 Arguments in support of the income approach are as follows:
 - (a) because government grants are receipts from a source other than shareholders, they should not be recognised directly in equity but should be recognised in profit or loss in appropriate periods.
 - (b) government grants are rarely gratuitous. The entity earns them through compliance with their conditions and meeting the envisaged

obligations. They should therefore be recognised in profit or loss over the periods in which the entity recognises as expenses the related costs for which the grant is intended to compensate.

- (c) because income and other taxes are expenses, it is logical to deal also with government grants, which are an extension of fiscal policies, in profit or loss.
- 16 It is fundamental to the income approach that government grants should be recognised in profit or loss on a systematic basis over the periods in which the entity recognises as expenses the related costs for which the grant is intended to compensate. Recognition of government grants in profit or loss on a receipts basis is not in accordance with the accrual accounting assumption (see Ind AS 1 *Presentation of Financial Statements*) and would be acceptable only if no basis existed for allocating a grant to periods other than the one in which it was received.
- 17 In most cases the periods over which an entity recognises the costs or expenses related to a government grant are readily ascertainable. Thus grants in recognition of specific expenses are recognised in profit or loss in the same period as the relevant expenses. Similarly, grants related to depreciable assets are usually recognised in profit or loss over the periods and in the proportions in which depreciation expense on those assets is recognised.
- 18 Grants related to non-depreciable assets may also require the fulfilment of certain obligations and would then be recognised in profit or loss over the periods that bear the cost of meeting the obligations. As an example, a grant of land may be conditional upon the erection of a building on the site and it may be appropriate to recognise the grant in profit or loss over the life of the building.
- 19 Grants are sometimes received as part of a package of financial or fiscal aids to which a number of conditions are attached. In such cases, care is needed in identifying the conditions giving rise to costs and expenses which determine the periods over which the grant will be earned. It may be appropriate to allocate part of a grant on one basis and part on another.
- 20 A government grant that becomes receivable as compensation for expenses or losses already incurred or for the purpose of giving immediate financial support to the entity with no future related costs shall be recognised in profit or loss of the period in which it becomes receivable.
- 21 In some circumstances, a government grant may be awarded for the purpose of giving immediate financial support to an entity rather than as an incentive to undertake specific expenditures. Such grants may be confined to a particular entity and may not be available to a whole class of beneficiaries. These circumstances may warrant recognising a grant in profit or loss of the period in which the entity qualifies to receive it, with disclosure to ensure that its effect is clearly understood.
- 22 A government grant may become receivable by an entity as compensation for expenses or losses incurred in a previous period. Such a grant is recognised

in profit or loss of the period in which it becomes receivable, with disclosure to ensure that its effect is clearly understood.

Non-monetary government grants

- 23 A government grant may take the form of a transfer of a non-monetary asset, such as land or other resources, for the use of the entity. In these circumstances the fair value of the non-monetary asset is assessed and both grant and asset are accounted for at that fair value.

Presentation of grants related to assets

- 24 Government grants related to assets, including non-monetary grants at fair value, shall be presented in the balance sheet by setting up the grant as deferred income.
- 25 [Refer to Appendix I].
- 26 The grant set up as deferred income is recognised in profit or loss on a systematic basis over the useful life of the asset.
- 27 [Refer to Appendix 1]
- 28 The purchase of assets and the receipt of related grants can cause major movements in the cash flow of an entity. For this reason and in order to show the gross investment in assets, such movements are disclosed as separate items in the statement of cash flows..

Presentation of grants related to income

- 29 Grants related to income are sometimes presented as a credit in the statement of profit and loss, either separately or under a general heading such as 'Other income'; alternatively, they are deducted in reporting the related expense.
- 29A [Refer to Appendix 1]
- 30 Supporters of the first method claim that it is inappropriate to net income and expense items and that separation of the grant from the expense facilitates comparison with other expenses not affected by a grant. For the second method it is argued that the expenses might well not have been incurred by the entity if the grant had not been available and presentation of the expense without offsetting the grant may therefore be misleading.
- 31 Both methods are regarded as acceptable for the presentation of grants related to income. Disclosure of the grant may be necessary for a proper understanding of the financial statements. Disclosure of the effect of the grants on any item of income or expense which is required to be separately disclosed is usually appropriate.

Repayment of government grants

- 32 A government grant that becomes repayable shall be accounted for as a change in accounting estimate (see Ind AS 8 *Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors*). Repayment of a grant related to income shall be applied first against any unamortised deferred credit recognised in respect of the grant. To the extent that the repayment exceeds any such deferred credit, or when no deferred credit exists, the repayment shall be recognised immediately in profit or loss. Repayment of a grant related to an asset shall be recognised by reducing the deferred income balance by the amount repayable.
- 33 [Refer to Appendix 1]

Government assistance

- 34 Excluded from the definition of government grants in paragraph 3 are certain forms of government assistance which cannot reasonably have a value placed upon them and transactions with government which cannot be distinguished from the normal trading transactions of the entity.
- 35 Examples of assistance that cannot reasonably have a value placed upon them are free technical or marketing advice and the provision of guarantees. An example of assistance that cannot be distinguished from the normal trading transactions of the entity is a government procurement policy that is responsible for a portion of the entity's sales. The existence of the benefit might be unquestioned but any attempt to segregate the trading activities from government assistance could well be arbitrary.
- 36 The significance of the benefit in the above examples may be such that disclosure of the nature, extent and duration of the assistance is necessary in order that the financial statements may not be misleading.
- 37 [Refer to Appendix 1]
- 38 In this Standard, government assistance does not include the provision of infrastructure by improvement to the general transport and communication network and the supply of improved facilities such as irrigation or water reticulation which is available on an ongoing indeterminate basis for the benefit of an entire local community.

Disclosure

- 39 The following matters shall be disclosed:
- (a) the accounting policy adopted for government grants, including the methods of presentation adopted in the financial statements;
 - (b) the nature and extent of government grants recognised in the financial statements and an indication of other forms of government assistance from which the entity has directly benefited; and
 - (c) unfulfilled conditions and other contingencies attaching to government assistance that has been recognised.

Appendix A

Government Assistance—No Specific Relation to Operating Activities

This Appendix is an integral part of Indian Accounting Standard (Ind AS) 20.

Issue

- 1 In some countries government assistance to entities may be aimed at encouragement or long-term support of business activities either in certain regions or industry sectors. Conditions to receive such assistance may not be specifically related to the operating activities of the entity. Examples of such assistance are transfers of resources by governments to entities which:
 - (a) operate in a particular industry;
 - (b) continue operating in recently privatised industries; or
 - (c) start or continue to run their business in underdeveloped areas.
- 2 The issue is whether such government assistance is a 'government grant' within the scope of Ind AS 20 and, therefore, should be accounted for in accordance with this Standard.

Accounting Principle

- 3 Government assistance to entities meets the definition of government grants in Ind AS 20, even if there are no conditions specifically relating to the operating activities of the entity other than the requirement to operate in certain regions or industry sectors. Such grants shall therefore not be credited directly to shareholders' interests.

Appendix 1

Note: This Appendix is not a part of the Indian Accounting Standard. The purpose of this Appendix is only to bring out the differences, if any, between Indian Accounting Standard (Ind AS) 20 and the corresponding International Accounting Standard (IAS) 20, Accounting for Government Grants and Disclosure of Government Assistance

Comparison with IAS 20, Accounting for Government Grants and Disclosure of Government Assistance

1. IAS 20 gives an option to measure non-monetary government grants either at their fair value or at nominal value. Ind AS 20 requires measurement of such grants only at their fair value. Thus, the option to measure these grants at nominal value is not available under Ind AS 20.
2. IAS 20 gives an option to present the grants related to assets, including non-monetary grants at fair value in the balance sheet either by setting up the grant as deferred income or by deducting the grant in arriving at the carrying amount of the asset. Ind AS 20 requires presentation of such grants in balance sheet only by setting up the grant as deferred income. Thus, the option to present such grants by deduction of the grant in arriving at the carrying amount of the asset is not available under Ind AS 20. As a consequence thereof paragraph 32 has been modified and the following paragraphs of IAS 20 which are with reference to the options for presentation of grants related to assets have been deleted in Ind AS 20. In order to maintain consistency with paragraph numbers of IAS 20, the paragraph numbers are retained in Ind AS 20:
 - (i) Paragraph 25
 - (ii) Paragraph 27
 - (iii) Paragraph 33
3. Requirements regarding presentation of grants related to income in the separate income statement, where separate income statement is presented under paragraph 29A of IAS 20 have been deleted. This change is consequential to the removal of option regarding two statement approach in Ind AS 1. Ind AS 1 requires that the components of profit or loss and components of other comprehensive income shall be presented as a part of the statement of profit and loss. However, paragraph number 29A has been retained in Ind AS 20 to maintain consistency with paragraph numbers of IAS 20.
4. Different terminology is used in this standard, e.g., the term 'balance sheet' is used instead of 'Statement of financial position' and 'Statement of profit and loss' is used instead of 'Statement of comprehensive income'.
5. Paragraph number 37 appear as 'Deleted' in IAS 20. In order to maintain consistency with paragraph numbers of IAS 20, the paragraph number is retained in Ind AS 20.

Indian Accounting Standard (Ind AS) 21

The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates

*(This Indian Accounting Standard includes paragraphs set in **bold type** and plain type, which have equal authority. Paragraphs in bold type indicate the main principles.)*

Objective

- 1** An entity may carry on foreign activities in two ways. It may have transactions in foreign currencies or it may have foreign operations. In addition, an entity may present its financial statements in a foreign currency. The objective of this Standard is to prescribe how to include foreign currency transactions and foreign operations in the financial statements of an entity and how to translate financial statements into a presentation currency.
- 2** The principal issues are which exchange rate(s) to use and how to report the effects of changes in exchange rates in the financial statements.

Scope

- 3** This Standard shall be applied
 - (a)** in accounting for transactions and balances in foreign currencies, except for those derivative transactions and balances that are within the scope of Ind AS 39 *Financial Instruments: Recognition and Measurement*;
 - (b)** in translating the results and financial position of foreign operations that are included in the financial statements of the entity by consolidation, proportionate consolidation or the equity method; and
 - (c)** in translating an entity's results and financial position into a presentation currency.
- 4** Ind AS 39 applies to many foreign currency derivatives and, accordingly, these are excluded from the scope of this Standard. However, those foreign currency derivatives that are not within the scope of Ind AS 39 (eg some foreign currency derivatives that are embedded in other contracts) are within the scope of this Standard. In addition, this Standard applies when an entity translates amounts relating to derivatives from its functional currency to its presentation currency.
- 5** This Standard does not apply to hedge accounting for foreign currency items, including the hedging of a net investment in a foreign operation. Ind AS 39

applies to hedge accounting.

- 6 This Standard applies to the presentation of an entity's financial statements in a foreign currency and sets out requirements for the resulting financial statements to be described as complying with Indian Accounting Standards. For translations of financial information into a foreign currency that do not meet these requirements, this Standard specifies information to be disclosed.
- 7 This Standard does not apply to the presentation in a statement of cash flows of the cash flows arising from transactions in a foreign currency, or to the translation of cash flows of a foreign operation (see Ind AS 7 *Statement of Cash Flows*).

Definitions

- 8 The following terms are used in this Standard with the meanings specified:

Closing rate is the spot exchange rate at the end of the reporting period.

Exchange difference is the difference resulting from translating a given number of units of one currency into another currency at different exchange rates.

Exchange rate is the ratio of exchange for two currencies.

Fair value is the amount for which an asset could be exchanged, or a liability settled, between knowledgeable, willing parties in an arm's length transaction.

Foreign currency is a currency other than the functional currency of the entity.

Foreign operation is an entity that is a subsidiary, associate, joint venture or branch of a reporting entity, the activities of which are based or conducted in a country or currency other than those of the reporting entity.

Functional currency is the currency of the primary economic environment in which the entity operates.

A group is a parent and all its subsidiaries.

Monetary items are units of currency held and assets and liabilities to be received or paid in a fixed or determinable number of units of currency.

Net investment in a foreign operation is the amount of the reporting entity's interest in the net assets of that operation.

Presentation currency is the currency in which the financial statements are presented.

Spot exchange rate is the exchange rate for immediate delivery.

Elaboration on the definitions

Functional currency

- 9 The primary economic environment in which an entity operates is normally the one in which it primarily generates and expends cash. An entity considers the following factors in determining its functional currency:
- (a) the currency:
 - (i) that mainly influences sales prices for goods and services (this will often be the currency in which sales prices for its goods and services are denominated and settled); and
 - (ii) of the country whose competitive forces and regulations mainly determine the sales prices of its goods and services.
 - (b) the currency that mainly influences labour, material and other costs of providing goods or services (this will often be the currency in which such costs are denominated and settled).
- 10 The following factors may also provide evidence of an entity's functional currency:
- (a) the currency in which funds from financing activities (ie issuing debt and equity instruments) are generated.
 - (b) the currency in which receipts from operating activities are usually retained.
- 11 The following additional factors are considered in determining the functional currency of a foreign operation, and whether its functional currency is the same as that of the reporting entity (the reporting entity, in this context, being the entity that has the foreign operation as its subsidiary, branch, associate or joint venture):
- (a) whether the activities of the foreign operation are carried out as an extension of the reporting entity, rather than being carried out with a significant degree of autonomy. An example of the former is when the foreign operation only sells goods imported from the reporting entity and remits the proceeds to it. An example of the latter is when the operation accumulates cash and other monetary items, incurs expenses, generates income and arranges borrowings, all substantially in its local currency.
 - (b) whether transactions with the reporting entity are a high or a low proportion of the foreign operation's activities

- (c) whether cash flows from the activities of the foreign operation directly affect the cash flows of the reporting entity and are readily available for remittance to it.
 - (d) whether cash flows from the activities of the foreign operation are sufficient to service existing and normally expected debt obligations without funds being made available by the reporting entity.
- 12 When the above indicators are mixed and the functional currency is not obvious, management uses its judgement to determine the functional currency that most faithfully represents the economic effects of the underlying transactions, events and conditions. As part of this approach, management gives priority to the primary indicators in paragraph 9 before considering the indicators in paragraphs 10 and 11, which are designed to provide additional supporting evidence to determine an entity's functional currency.
- 13 An entity's functional currency reflects the underlying transactions, events and conditions that are relevant to it. Accordingly, once determined, the functional currency is not changed unless there is a change in those underlying transactions, events and conditions.
- 14 If the functional currency is the currency of a hyperinflationary economy, the entity's financial statements are restated in accordance with Ind AS 29 *Financial Reporting in Hyperinflationary Economies*. An entity cannot avoid restatement in accordance with Ind AS 29 by, for example, adopting as its functional currency a currency other than the functional currency determined in accordance with this Standard (such as the functional currency of its parent).

Net investment in a foreign operation

- 15 An entity may have a monetary item that is receivable from or payable to a foreign operation. An item for which settlement is neither planned nor likely to occur in the foreseeable future is, in substance, a part of the entity's net investment in that foreign operation, and is accounted for in accordance with paragraphs 32 and 33. Such monetary items may include long-term receivables or loans. They do not include trade receivables or trade payables.
- 15A The entity that has a monetary item receivable from or payable to a foreign operation described in paragraph 15 may be any subsidiary of the group. For example, an entity has two subsidiaries, A and B. Subsidiary B is a foreign operation. Subsidiary A grants a loan to Subsidiary B. Subsidiary A's loan receivable from Subsidiary B would be part of the entity's net investment in Subsidiary B if settlement of the loan is neither planned nor likely to occur in the foreseeable future. This would also be true if Subsidiary A were itself a foreign operation.

Monetary items

- 16 The essential feature of a monetary item is a right to receive (or an obligation to deliver) a fixed or determinable number of units of currency. Examples include: pensions and other employee benefits to be paid in cash; provisions that are to be settled in cash; and cash dividends that are recognised as a liability. Similarly, a contract to receive (or deliver) a variable number of the entity's own equity instruments or a variable amount of assets in which the fair value to be received (or delivered) equals a fixed or determinable number of units of currency is a monetary item. Conversely, the essential feature of a non-monetary item is the absence of a right to receive (or an obligation to deliver) a fixed or determinable number of units of currency. Examples include: amounts prepaid for goods and services (eg prepaid rent); goodwill; intangible assets; inventories; property, plant and equipment; and provisions that are to be settled by the delivery of a non-monetary asset.

Summary of the approach required by this Standard

- 17 In preparing financial statements, each entity—whether a stand-alone entity, an entity with foreign operations (such as a parent) or a foreign operation (such as a subsidiary or branch)—determines its functional currency in accordance with paragraphs 9–14. The entity translates foreign currency items into its functional currency and reports the effects of such translation in accordance with paragraphs 20–37 and 50.
- 18 Many reporting entities comprise a number of individual entities (eg a group is made up of a parent and one or more subsidiaries). Various types of entities, whether members of a group or otherwise, may have investments in associates or joint ventures. They may also have branches. It is necessary for the results and financial position of each individual entity included in the reporting entity to be translated into the currency in which the reporting entity presents its financial statements. This Standard permits the presentation currency of a reporting entity to be any currency (or currencies). The results and financial position of any individual entity within the reporting entity whose functional currency differs from the presentation currency are translated in accordance with paragraphs 38–50.
- 19 This Standard also permits a stand-alone entity preparing financial statements or an entity preparing separate financial statements in accordance with Ind AS 27 *Consolidated and Separate Financial Statements* to present its financial statements in any currency (or currencies). If the entity's presentation currency differs from its functional currency, its results and financial position are also translated into the presentation currency in accordance with paragraphs 38–50.

Reporting foreign currency transactions in the functional currency

Initial recognition

- 20 A foreign currency transaction is a transaction that is denominated or requires settlement in a foreign currency, including transactions arising when an entity:
- (a) buys or sells goods or services whose price is denominated in a foreign currency;
 - (b) borrows or lends funds when the amounts payable or receivable are denominated in a foreign currency; or
 - (c) otherwise acquires or disposes of assets, or incurs or settles liabilities, denominated in a foreign currency.
- 21 A foreign currency transaction shall be recorded, on initial recognition in the functional currency, by applying to the foreign currency amount the spot exchange rate between the functional currency and the foreign currency at the date of the transaction.
- 22 The date of a transaction is the date on which the transaction first qualifies for recognition in accordance with Indian Accounting Standards. For practical reasons, a rate that approximates the actual rate at the date of the transaction is often used, for example, an average rate for a week or a month might be used for all transactions in each foreign currency occurring during that period. However, if exchange rates fluctuate significantly, the use of the average rate for a period is inappropriate.

Reporting at the ends of subsequent reporting periods

- 23 At the end of each reporting period
- (a) foreign currency monetary items shall be translated using the closing rate;
 - (b) non-monetary items that are measured in terms of historical cost in a foreign currency shall be translated using the exchange rate at the date of the transaction; and
 - (c) non-monetary items that are measured at fair value in a foreign currency shall be translated using the exchange rates at the date when the fair value was determined.
- 24 The carrying amount of an item is determined in conjunction with other relevant Standards. For example, property, plant and equipment may be measured in terms of fair value or historical cost in accordance with Ind AS 16 *Property, Plant*

and Equipment. Whether the carrying amount is determined on the basis of historical cost or on the basis of fair value, if the amount is determined in a foreign currency it is then translated into the functional currency in accordance with this Standard.

- 25 The carrying amount of some items is determined by comparing two or more amounts. For example, the carrying amount of inventories is the lower of cost and net realisable value in accordance with Ind AS 2 *Inventories*. Similarly, in accordance with Ind AS 36 *Impairment of Assets*, the carrying amount of an asset for which there is an indication of impairment is the lower of its carrying amount before considering possible impairment losses and its recoverable amount. When such an asset is non-monetary and is measured in a foreign currency, the carrying amount is determined by comparing:

- (a) the cost or carrying amount, as appropriate, translated at the exchange rate at the date when that amount was determined (ie the rate at the date of the transaction for an item measured in terms of historical cost); and
- (b) the net realisable value or recoverable amount, as appropriate, translated at the exchange rate at the date when that value was determined (eg the closing rate at the end of the reporting period).

The effect of this comparison may be that an impairment loss is recognised in the functional currency but would not be recognised in the foreign currency, or vice versa.

- 26 When several exchange rates are available, the rate used is that at which the future cash flows represented by the transaction or balance could have been settled if those cash flows had occurred at the measurement date. If exchangeability between two currencies is temporarily lacking, the rate used is the first subsequent rate at which exchanges could be made.

Recognition of exchange differences

- 27 As noted in paragraph 3 (a) and 5, Ind AS 39 applies to hedge accounting for foreign currency items. The application of hedge accounting requires an entity to account for some exchange differences differently from the treatment of exchange differences required by this Standard. For example, Ind AS 39 requires that exchange differences on monetary items that qualify as hedging instruments in a cash flow hedge are recognised initially in other comprehensive income to the extent that the hedge is effective.

- 28 Exchange differences arising on the settlement of monetary items or on translating monetary items at rates different from those at which they were translated on initial recognition during the period or in previous financial statements shall be recognised in profit or loss in the period in which they arise, except:**
- (i) exchange differences arising on a monetary item that forms part of a reporting entity's net investment in a foreign operation as described in paragraph 32;**
 - (ii) where an entity exercises the option provided in paragraph 29A in respect of long-term monetary items.**
- 29** When monetary items arise from a foreign currency transaction and there is a change in the exchange rate between the transaction date and the date of settlement, an exchange difference results. When the transaction is settled within the same accounting period as that in which it occurred, all the exchange difference is recognised in that period. However, when the transaction is settled in a subsequent accounting period, the exchange difference recognised in each period up to the date of settlement is determined by the change in exchange rates during each period. Paragraph 29A provides an option to recognise unrealised exchange differences arising on translation of certain long-term monetary assets and long-term monetary liabilities from foreign currency to functional currency.
- 29A** An entity may exercise the option in respect of recognition of exchange differences arising on translation of long-term monetary items from foreign currency to functional currency as follows:
- (i)** Unrealised exchange differences arising on long-term monetary assets and long-term-term monetary liabilities denominated in a foreign currency shall be recognised directly in equity and accumulated in a separate component of equity. The amount so accumulated shall be transferred to profit or loss over the period of maturity of such long-term monetary items in an appropriate manner. The separate component of equity shall be distinguished from any other component of equity representing any other exchange difference recognised in other comprehensive income and accumulated in equity.
 - (ii)** The option provided in paragraph 29A(i) is not available for the long-term monetary assets and long-term monetary liabilities during the period they are classified as at fair value through profit or loss in accordance with Ind AS 39, either because they are held for trading or because of their designation as at fair value through profit or loss.
 - (iii)** The option provided in paragraph 29A(i) shall be exercised for the first time when the exchange difference arising on a long-term monetary asset or a long-term monetary liability mentioned in paragraph 29A(i) is recognised. The option, once exercised, shall be irrevocable and shall be exercised in respect of all the long-term monetary assets and long-term monetary liabilities mentioned in paragraph 29A(i).

- (iv) For the purpose of this paragraph, a monetary asset or a monetary liability shall be treated as long-term, if that asset or liability has a maturity period of twelve months or more from the date of the initial recognition of that asset or liability.
- 30 **When a gain or loss on a non-monetary item is recognised in other comprehensive income, any exchange component of that gain or loss shall be recognised in other comprehensive income. Conversely, when a gain or loss on a non-monetary item is recognised in profit or loss, any exchange component of that gain or loss shall be recognised in profit or loss.**
- 31 Other Indian Accounting Standards require some gains and losses to be recognised in other comprehensive income. For example, Ind AS 16 requires some gains and losses arising on a revaluation of property, plant and equipment to be recognised in other comprehensive income. When such an asset is measured in a foreign currency, paragraph 23(c) of this Standard requires the revalued amount to be translated using the rate at the date the value is determined, resulting in an exchange difference that is also recognised in other comprehensive income.
- 32 **Exchange differences arising on a monetary item that forms part of a reporting entity's net investment in a foreign operation (see paragraph 15) shall be recognised in profit or loss in the separate financial statements of the reporting entity or the individual financial statements of the foreign operation, as appropriate. In the financial statements that include the foreign operation and the reporting entity (eg consolidated financial statements when the foreign operation is a subsidiary), such exchange differences shall be recognised initially in other comprehensive income and reclassified from equity to profit or loss on disposal of the net investment in accordance with paragraph 48.**
- 33 When a monetary item forms part of a reporting entity's net investment in a foreign operation and is denominated in the functional currency of the reporting entity, an exchange difference arises in the foreign operation's individual financial statements in accordance with paragraph 28. If such an item is denominated in the functional currency of the foreign operation, an exchange difference arises in the reporting entity's separate financial statements in accordance with paragraph 28. If such an item is denominated in a currency other than the functional currency of either the reporting entity or the foreign operation, an exchange difference arises in the reporting entity's separate financial statements and in the foreign operation's individual financial statements in accordance with paragraph 28. Such exchange differences are recognised in other comprehensive income in the financial statements that include the foreign operation and the reporting entity (ie financial statements in which the foreign operation is consolidated, proportionately consolidated or accounted for using the equity method).
- 34 When an entity keeps its books and records in a currency other than its functional currency, at the time the entity prepares its financial statements all amounts are translated into the functional currency in accordance with

paragraphs 20–26. This produces the same amounts in the functional currency as would have occurred had the items been recorded initially in the functional currency. For example, monetary items are translated into the functional currency using the closing rate, and non-monetary items that are measured on a historical cost basis are translated using the exchange rate at the date of the transaction that resulted in their recognition.

Change in functional currency

- 35 **When there is a change in an entity's functional currency, the entity shall apply the translation procedures applicable to the new functional currency prospectively from the date of the change.**
- 36 As noted in paragraph 13, the functional currency of an entity reflects the underlying transactions, events and conditions that are relevant to the entity. Accordingly, once the functional currency is determined, it can be changed only if there is a change to those underlying transactions, events and conditions. For example, a change in the currency that mainly influences the sales prices of goods and services may lead to a change in an entity's functional currency.
- 37 The effect of a change in functional currency is accounted for prospectively. In other words, an entity translates all items into the new functional currency using the exchange rate at the date of the change. The resulting translated amounts for non-monetary items are treated as their historical cost. Exchange differences arising from the translation of a foreign operation previously recognised in other comprehensive income in accordance with paragraphs 32 and 39(c) are not reclassified from equity to profit or loss until the disposal of the operation. When the option provided in paragraph 29A is exercised, exchange differences previously recognised directly in equity and accumulated in a separate component of equity in accordance with that paragraph are not transferred to profit or loss immediately on change of the entity's functional currency. They shall continue to be transferred to profit or loss in the manner stated in that paragraph.

Use of a presentation currency other than the functional currency

Translation to the presentation currency

- 38 An entity may present its financial statements in any currency (or currencies). If the presentation currency differs from the entity's functional currency, it translates its results and financial position into the presentation currency. For example, when a group contains individual entities with different functional currencies, the results and financial position of each entity are expressed in a common currency so that consolidated financial statements may be presented.
- 39 **The results and financial position of an entity whose functional currency is not the currency of a hyperinflationary economy shall be translated into a different presentation currency using the following procedures:**
- (a) **assets and liabilities for each balance sheet presented (ie including comparatives) shall be translated at the closing rate at the date of that balance sheet;**

- (b) **income and expenses for each statement of profit and loss presented (ie including comparatives) shall be translated at exchange rates at the dates of the transactions; and**
- (c) **all resulting exchange differences shall be recognised in other comprehensive income.**

40 For practical reasons, a rate that approximates the exchange rates at the dates of the transactions, for example an average rate for the period, is often used to translate income and expense items. However, if exchange rates fluctuate significantly, the use of the average rate for a period is inappropriate.

41 The exchange differences referred to in paragraph 39(c) result from:

- (a) translating income and expenses at the exchange rates at the dates of the transactions and assets and liabilities at the closing rate.
- (b) translating the opening net assets at a closing rate that differs from the previous closing rate.

These exchange differences are not recognised in profit or loss because the changes in exchange rates have little or no direct effect on the present and future cash flows from operations. The cumulative amount of the exchange differences is presented in a separate component of equity until disposal of the foreign operation. When the exchange differences relate to a foreign operation that is consolidated but not wholly-owned, accumulated exchange differences arising from translation and attributable to non-controlling interests are allocated to, and recognised as part of, non-controlling interests in the consolidated balance sheet.

42 **The results and financial position of an entity whose functional currency is the currency of a hyperinflationary economy shall be translated into a different presentation currency using the following procedures:**

- (a) **all amounts (ie assets, liabilities, equity items, income and expenses, including comparatives) shall be translated at the closing rate at the date of the most recent balance sheet, except that**
- (b) **when amounts are translated into the currency of a non-hyperinflationary economy, comparative amounts shall be those that were presented as current year amounts in the relevant prior year financial statements (ie not adjusted for subsequent changes in the price level or subsequent changes in exchange rates).**

43 **When an entity's functional currency is the currency of a hyperinflationary economy, the entity shall restate its financial statements in accordance with Ind AS 29 before applying the translation method set out in paragraph 42, except for comparative amounts that are translated into a currency of a non-hyperinflationary economy (see paragraph 42(b)). When the economy ceases to be hyperinflationary and the entity no longer restates its financial statements in accordance with Ind AS 29, it shall use as the historical costs for translation into the presentation currency the amounts restated to the price level at the date the entity ceased restating its financial statements.**

Translation of a foreign operation

- 44** Paragraphs 45–47, in addition to paragraphs 38–43, apply when the results and financial position of a foreign operation are translated into a presentation currency so that the foreign operation can be included in the financial statements of the reporting entity by consolidation, proportionate consolidation or the equity method.
- 45** The incorporation of the results and financial position of a foreign operation with those of the reporting entity follows normal consolidation procedures, such as the elimination of intragroup balances and intragroup transactions of a subsidiary (see Ind AS 27 and Ind AS 31 *Interests in Joint Ventures*). However, an intragroup monetary asset (or liability), whether short-term or long-term, cannot be eliminated against the corresponding intragroup liability (or asset) without showing the results of currency fluctuations in the consolidated financial statements. This is because the monetary item represents a commitment to convert one currency into another and exposes the reporting entity to a gain or loss through currency fluctuations. Accordingly, in the consolidated financial statements of the reporting entity, such an exchange difference is recognised in profit or loss or, if it arises from the circumstances described in paragraph 32, it is recognised in other comprehensive income and accumulated in a separate component of equity until the disposal of the foreign operation. When the option provided in paragraph 29A is exercised, in the consolidated financial statements of the reporting entity, such an exchange difference is directly recognised in equity and disposed of in the manner prescribed in that paragraph.
- 46** When the financial statements of a foreign operation are as of a date different from that of the reporting entity, the foreign operation often prepares additional statements as of the same date as the reporting entity's financial statements. When this is not done, Ind AS 27 allows the use of a different date provided that the difference is no greater than three months and adjustments are made for the effects of any significant transactions or other events that occur between the different dates. In such a case, the assets and liabilities of the foreign operation are translated at the exchange rate at the end of the reporting period of the foreign operation. Adjustments are made for significant changes in exchange rates up to the end of the reporting period of the reporting entity in accordance with Ind AS 27. The same approach is used in applying the equity method to associates and joint ventures and in applying proportionate consolidation to joint ventures in accordance with Ind AS 28 *Investments in Associates* and Ind AS 31.
- 47** Any goodwill arising on the acquisition of a foreign operation and any fair value adjustments to the carrying amounts of assets and liabilities arising on the acquisition of that foreign operation shall be treated as assets and liabilities of the foreign operation. Thus they shall be expressed in the functional currency of the foreign operation and shall be translated at the closing rate in accordance with paragraphs 39 and 42.

Disposal or partial disposal of a foreign operation

- 48** On the disposal of a foreign operation, the cumulative amount of the exchange differences relating to that foreign operation, recognised in other comprehensive income and accumulated in the separate component of equity, shall be reclassified from equity to profit or loss (as a reclassification adjustment) when the gain or loss on disposal is recognised (see Ind AS 1 *Presentation of Financial Statements*).

- 48A** In addition to the disposal of an entity's entire interest in a foreign operation, the following are accounted for as disposals even if the entity retains an interest in the former subsidiary, associate or jointly controlled entity:
- (a) the loss of control of a subsidiary that includes a foreign operation;
 - (b) the loss of significant influence over an associate that includes a foreign operation; and
 - (c) the loss of joint control over a jointly controlled entity that includes a foreign operation.
- 48B** On disposal of a subsidiary that includes a foreign operation, the cumulative amount of the exchange differences relating to that foreign operation that have been attributed to the non-controlling interests shall be derecognised, but shall not be reclassified to profit or loss.
- 48C** On the partial disposal of a subsidiary that includes a foreign operation, the entity shall re-attribute the proportionate share of the cumulative amount of the exchange differences recognised in other comprehensive income to the non-controlling interests in that foreign operation. In any other partial disposal of a foreign operation the entity shall reclassify to profit or loss only the proportionate share of the cumulative amount of the exchange differences recognised in other comprehensive income.
- 48D** A partial disposal of an entity's interest in a foreign operation is any reduction in an entity's ownership interest in a foreign operation, except those reductions in paragraph 48A that are accounted for as disposals.
- 49** An entity may dispose or partially dispose of its interest in a foreign operation through sale, liquidation, repayment of share capital or abandonment of all, or part of, that entity. A write-down of the carrying amount of a foreign operation, either because of its own losses or because of an impairment recognised by the investor, does not constitute a partial disposal. Accordingly, no part of the foreign exchange gain or loss recognised in other comprehensive income is reclassified to profit or loss at the time of a write-down.

Tax effects of all exchange differences

- 50** Gains and losses on foreign currency transactions and exchange differences arising on translating the results and financial position of an entity (including a foreign operation) into a different currency may have tax effects. Ind AS 12 *Income Taxes* applies to these tax effects.

Disclosure

- 51** In paragraphs 53 and 55–57 references to 'functional currency' apply, in the case of a group, to the functional currency of the parent.

52 An entity shall disclose:

- (a) the amount of exchange differences recognised in profit or loss except for those arising on financial instruments measured at fair value through profit or loss in accordance with Ind AS 39;
- (b) net exchange differences recognised in other comprehensive income and accumulated in a separate component of equity, and a reconciliation of the amount of such exchange differences at the beginning and end of the period; and
- (c) net exchange differences recognised directly in equity and accumulated in a separate component of equity in accordance with paragraph 29A, and a reconciliation of the amount of such exchange differences at the beginning and end of the period.

53 When the presentation currency is different from the functional currency, that fact shall be stated, together with disclosure of the functional currency and the reason for using a different presentation currency.

54 When there is a change in the functional currency of either the reporting entity or a significant foreign operation, that fact, the reason for the change in functional currency and the date of change in functional currency shall be disclosed.

55 When an entity presents its financial statements in a currency that is different from its functional currency, it shall describe the financial statements as complying with Indian Accounting Standards only if they comply with all the requirements of each applicable Standard including the translation method set out in paragraphs 39 and 42.

56 An entity sometimes presents its financial statements or other financial information in a currency that is not its functional currency without meeting the requirements of paragraph 55. For example, an entity may convert into another currency only selected items from its financial statements. Or, an entity whose functional currency is not the currency of a hyperinflationary economy may convert the financial statements into another currency by translating all items at the most recent closing rate. Such conversions are not in accordance with Indian Accounting Standards and the disclosures set out in paragraph 57 are required.

57 When an entity displays its financial statements or other financial information in a currency that is different from either its functional currency or its presentation currency and the requirements of paragraph 55 are not met, it shall:

- (a) clearly identify the information as supplementary information to distinguish it from the information that complies with Indian Accounting Standards;
- (b) disclose the currency in which the supplementary information is displayed; and
- (c) disclose the entity's functional currency and the method of translation used to determine the supplementary information.

Appendix A

References to matters contained in other Indian Accounting Standards

This Appendix is an integral part of Indian Accounting Standard 21

This appendix lists the appendix which is a part of another Indian Accounting Standard and makes reference to Ind AS 21, *The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates*.

1. Appendix D *Hedges of a Net Investment in a Foreign Operation* contained in Ind AS 39, *Financial instruments: Recognition and Measurement* makes reference to this Standard also.

Appendix B

This Appendix accompanies, but is not part of Ind AS 21.

Example illustrating paragraph 14

Entity P has a subsidiary Entity S. Functional currencies of Entities P and S determined in accordance with Ind AS 21 are Rupee and CU respectively. Further, currency CU is determined as currency of a hyperinflationary economy within the meaning of Ind AS 29. The financial statements of Entity S should be restated in accordance with Ind AS 29. This requirement cannot be avoided, for example, by adopting Rupee as the functional currency of Entity S.

Example illustrating impairment loss in paragraph 25

Entity A's functional currency is Rupee. It has a building located in US acquired at a cost of US\$ 10,000 when the exchange rate was US\$ 1=Rs.50. The building is carried at cost in the financial statements of Entity A. For the purpose of this example depreciation is ignored. At the balance sheet date, there is an indication of impairment for this building. Consequently, an impairment test has been made in accordance with Ind AS 36 as at the balance sheet date and the recoverable amount of the building is determined to be US\$ 9,500. The exchange rate as at the balance sheet date is US\$ 1=Rs.53.

	Rs.
Cost translated at the exchange rate on the date of acquisition- US\$10,000 @Rs.50 per US\$	500,000
Recoverable amount translated at the exchange rate on the balance sheet date-US\$9,500 @ Rs.53 per US\$	503,500

Though there is an impairment loss of US\$ 500 (US\$10,000-US\$9,500) in terms of foreign currency, there is no impairment loss in terms of functional currency. This is because, recoverable amount in terms of functional currency (Rs.503,500) exceeds carrying amount (ie cost in this example) in terms of functional currency (Rs.500,000). Hence, no impairment loss is recognised for the building.

Example illustrating paragraph 33

Entity P has a foreign subsidiary Entity S1. The functional currencies of Entities P and S1 are Rupee and US\$ respectively. Both the entities follow financial year as accounting year. Accounting Year of both the entities ends on March 31. The presentation currency for Entity P's separate as well as consolidated financial statements is Rupee.

In all the following situations, it is assumed that the loan forms part of the entity's net investment in the foreign operation.

Situation 1:

Entity S1 owes to Entity P US\$1,000 towards a loan obtained some years back. Exchange rates as at 31 March 20X0 and 31 March 20X1 were US\$ 1=Rs.48 and US\$ 1=Rs.50 respectively.

In the above situation, in the individual financial statements of Entity S1, no exchange difference arises on the loan since it is denominated in its own functional currency.

In the separate financial statements of Entity P, an exchange gain of Rs.2,000 arises as shown below:

	Rs.
Loan asset of US\$1,000 translated	
@ exchange rate as at 31 March 20X1 (Rs.50 per US\$)	50,000
@ exchange rate as at 31 March 20X0 (Rs.48 per US\$)	48,000
Exchange gain	2,000

In the consolidated financial statements of Entity P, the exchange gain of Rs.2,000 will be recognised in other comprehensive income and accumulated in equity.

Situation 2:

Entity S1 owes to Entity P Rs. 48,000 towards a loan obtained some years back. For the purpose of this example, it is assumed that the use of the average exchange rate provides a reliable approximation of the spot rates during the year. Exchange rates as at 31 March 20X0 and 31 March 20X1 were US\$ 1=Rs.48 and US\$ 1=Rs.50 respectively. Average exchange rate during the financial year ending 31 March 20X1 was US\$ 1=Rs.49.

In the above situation, in the separate financial statements of Entity P, no exchange difference arises on the loan since it is denominated in its own functional currency.

In the individual financial statements of Entity S1, an exchange gain of US\$40 arises as shown below:

	US\$
Loan liability of Rs.48,000 translated	
@ exchange rate as at 31 March 20X1 (Rs.50 per US\$)	960
@ exchange rate as at 31 March 20X0 (Rs.48 per US\$)	1,000
Exchange gain	40

After translating the financial statements of Entity S1 into Rupees in accordance with paragraphs 38-47 of Ind AS 21, in the consolidated financial statements of Entity P, the exchange gain in terms of Rupee corresponding to US\$40 i.e. Rs.1,960 (US\$40 @ Rs.49) will be recognised in other comprehensive income and accumulated in equity.

Situation 3:

Entity S1 owes to Entity P €1,000 towards a loan obtained some years back.

Exchange rates:

As at 31 March 20X0	As at 31 March 20X1
€1=Rs.60	€1=Rs.61
€1=US\$1.3	€1=US\$1.4

Average exchange rate between US\$ and Rupee during the financial year ending 31 March 20X1 was US\$ 1= Rs.45. For the purpose of this example, it is assumed that the use of the average exchange rate provides a reliable approximation of the spot rates during the year.

In the separate financial statements of Entity P, an exchange gain of Rs.1,000 arises as shown below:

	Rs.
Loan asset of €1,000 translated	
@ exchange rate as at 31 March 20X1(Rs.61 per €)	61,000
@ exchange rate as at 31 March 20X0(Rs.60 per €)	60,000
Exchange gain	1,000

In the consolidated financial statements of Entity P, the exchange gain of Rs.1,000 will be recognised in other comprehensive income and accumulated in equity.

In the individual financial statements of Entity S1, an exchange loss of US\$100 arises as shown below:

	US\$
Loan liability of €1,000 translated	
@ exchange rate as at 31 March 20X1(US\$1.4 per €)	1,400
@ exchange rate as at 31 March 20X0(US\$1.3 per €)	1,300
Exchange loss	100

After translating the financial statements of Entity S1 into Rupees in accordance with paragraphs 38-47 of Ind AS 21, in the consolidated financial statements of Entity P, the exchange loss in terms of Rupee corresponding to US\$100 ie Rs.4,500 (US\$100 @ Rs.45) will be recognised in other comprehensive income and accumulated in equity.

Example illustrating paragraph 37

Right from inception, Entity A's functional currency has been Rupee. It has one foreign operation with Euro as its functional currency. As a result of change in circumstances affecting the operations of the entity, the management determines that with effect from 1 January 20X1, the entity's functional currency will be US\$. The exchange rate on that date is US\$ 1=Rs.50. On that date, the carrying amount of inventories carried at cost in terms of previous functional currency is Rs.100,000. The entity has previously

recognised in other comprehensive income exchange differences arising on translation of its foreign operation and accumulated in equity as Foreign Currency Translation Reserve ('FCTR'). The accumulated FCTR as at 1 January 20X1 in terms of the previous functional currency is Rs.50,000. There is no change in the functional currency of the foreign operation. The entity follows calendar year as accounting year.

Entity A shall apply the translation procedures applicable to the new functional currency ie US\$ prospectively from the date of change in functional currency. Accordingly, all items in its balance sheet as at 1 January 20X1 are translated into US\$ at the exchange rate of US\$ 1=Rs.50.

The carrying amount of the inventories as at 1 January 20X1 in terms of the new functional currency will be US\$2,000 (Rs.100,000 translated @ Rs.50 per US\$). US\$2,000 will be the historical cost of the inventories. This will be so even if the inventories were acquired prior to 1 January 20X1.

The accumulated FCTR as at 1 January 20X1 in terms of the new functional currency will be US\$1,000 (Rs.50,000 translated @ Rs.50 per US\$). This amount is not reclassified from equity to profit or loss until the disposal of the foreign operation.

Appendix 1

Note: This Appendix is not a part of the Indian Accounting Standard. The purpose of this Appendix is only to bring out the differences between Indian Accounting Standard (Ind AS) 21 and the corresponding International Accounting Standard (IAS) 21, The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates.

Comparison with IAS 21, The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates

- 1 The transitional provisions given in IAS 21 have not been given in the Ind AS 21, since all transitional provisions related to Indian ASs, wherever considered appropriate, have been included in Ind AS 101, *First-time Adoption of Indian Accounting Standards* corresponding to IFRS 1, *First-time Adoption of International Financial Reporting Standards*.
- 2 Ind AS 21 permits an option to recognise exchange differences arising on translation of certain long-term monetary items from foreign currency to functional currency directly in equity. In this situation, Ind AS 21 requires the accumulated exchange differences to be transferred to profit or loss in an appropriate manner. IAS 21 does not permit such a treatment. Consequentially a new paragraph 29A has been added in Ind AS 21 as compared to IAS 21.
- 3 Consequent to the optional treatment prescribed for some exchange differences (as mentioned in 2 above), an additional disclosure has been added in paragraph 52 of Ind AS 21.
- 4 Appendix containing examples illustrating application of paragraphs 14, 25, 33 and 37 have been added in Ind AS 21.
- 5 When there is a change in functional currency of either the reporting currency or a significant foreign operation, IAS 21 requires disclosure of that fact and the reason for the change in functional currency. Ind AS 21 requires an additional disclosure of the date of change in functional currency.
- 6 Different terminology is used in this Standard e.g., the term 'balance sheet' is used instead of 'Statement of financial position'.

Indian Accounting Standard (Ind AS) 23

Borrowing Costs

(This Indian Accounting Standard includes paragraphs set in bold type and plain type, which have equal authority. Paragraphs in bold type indicate the main principles.)

Core principle

- 1 **Borrowing costs that are directly attributable to the acquisition, construction or production of a qualifying asset form part of the cost of that asset. Other borrowing costs are recognised as an expense.**

Scope

- 2 **An entity shall apply this Standard in accounting for borrowing costs.**
- 3 The Standard does not deal with the actual or imputed cost of equity, including preferred capital not classified as a liability.
- 4 An entity is not required to apply the Standard to borrowing costs directly attributable to the acquisition, construction or production of:
 - (a) a qualifying asset measured at fair value, for example, a biological asset; or
 - (b) inventories that are manufactured, or otherwise produced, in large quantities on a repetitive basis.

Definitions

- 5 **This Standard uses the following terms with the meanings specified:**

***Borrowing costs* are interest and other costs that an entity incurs in connection with the borrowing of funds.**

***A qualifying asset* is an asset that necessarily takes a substantial period of time to get ready for its intended use or sale.**

6 Borrowing costs may include:

- (a) interest expense calculated using the effective interest method as described in Ind AS 39 *Financial Instruments: Recognition and Measurement*;
- (b) [Refer to Appendix 1]
- (c) [Refer to Appendix 1]
- (d) finance charges in respect of finance leases recognised in accordance with *Leases*; and
- (e) exchange differences arising from foreign currency borrowings to the extent that they are regarded as an adjustment to interest costs.

6A. With regard to exchange difference required to be treated as borrowing costs in accordance with paragraph 6(e), the manner of arriving at the adjustments stated therein shall be as follows:

- (i) *the adjustment should be of an amount which is equivalent to the extent to which the exchange loss does not exceed the difference between the cost of borrowing in functional currency when compared to the cost of borrowing in a foreign currency.*
- (ii) *where there is an unrealised exchange loss which is treated as an adjustment to interest and subsequently there is a realised or unrealised gain in respect of the settlement or translation of the same borrowing, the gain to the extent of the loss previously recognised as an adjustment should also be recognised as an adjustment to interest."*

7 Depending on the circumstances, any of the following may be qualifying assets:

- (a) inventories
- (b) manufacturing plants
- (c) power generation facilities
- (d) intangible assets
- (e) investment properties.

Financial assets, and inventories that are manufactured, or otherwise produced, over a short period of time, are not qualifying assets. Assets that are ready for their intended use or sale when acquired are not qualifying assets.

Recognition

- 8 An entity shall capitalise borrowing costs that are directly attributable to the acquisition, construction or production of a qualifying asset as part of the cost of that asset. An entity shall recognise other borrowing costs as an expense in the period in which it incurs them.
- 9 Borrowing costs that are directly attributable to the acquisition, construction or production of a qualifying asset are included in the cost of that asset. Such borrowing costs are capitalised as part of the cost of the asset when it is probable that they will result in future economic benefits to the entity and the costs can be measured reliably. When an entity applies Ind AS 29 *Financial Reporting in Hyperinflationary Economies*, it recognises as an expense the part of borrowing costs that compensates for inflation during the same period in accordance with paragraph 21 of that Standard.

Borrowing costs eligible for capitalisation

- 10 The borrowing costs that are directly attributable to the acquisition, construction or production of a qualifying asset are those borrowing costs that would have been avoided if the expenditure on the qualifying asset had not been made. When an entity borrows funds specifically for the purpose of obtaining a particular qualifying asset, the borrowing costs that directly relate to that qualifying asset can be readily identified.
- 11 It may be difficult to identify a direct relationship between particular borrowings and a qualifying asset and to determine the borrowings that could otherwise have been avoided. Such a difficulty occurs, for example, when the financing activity of an entity is co-ordinated centrally. Difficulties also arise when a group uses a range of debt instruments to borrow funds at varying rates of interest, and lends those funds on various bases to other entities in the group. Other complications arise through the use of loans denominated in or linked to foreign currencies, when the group operates in highly inflationary economies, and from fluctuations in exchange rates. As a result, the determination of the amount of borrowing costs that are directly attributable to the acquisition of a qualifying asset is difficult and the exercise of judgement is required.
- 12 To the extent that an entity borrows funds specifically for the purpose of obtaining a qualifying asset, the entity shall determine the amount of borrowing costs eligible for capitalisation as the actual borrowing costs incurred on that borrowing during the period less any investment income on the temporary investment of those borrowings.

- 13 The financing arrangements for a qualifying asset may result in an entity obtaining borrowed funds and incurring associated borrowing costs before some or all of the funds are used for expenditures on the qualifying asset. In such circumstances, the funds are often temporarily invested pending their expenditure on the qualifying asset. In determining the amount of borrowing costs eligible for capitalisation during a period, any investment income earned on such funds is deducted from the borrowing costs incurred.
- 14 To the extent that an entity borrows funds generally and uses them for the purpose of obtaining a qualifying asset, the entity shall determine the amount of borrowing costs eligible for capitalisation by applying a capitalisation rate to the expenditures on that asset. The capitalisation rate shall be the weighted average of the borrowing costs applicable to the borrowings of the entity that are outstanding during the period, other than borrowings made specifically for the purpose of obtaining a qualifying asset. The amount of borrowing costs that an entity capitalises during a period shall not exceed the amount of borrowing costs it incurred during that period.
- 15 In some circumstances, it is appropriate to include all borrowings of the parent and its subsidiaries when computing a weighted average of the borrowing costs; in other circumstances, it is appropriate for each subsidiary to use a weighted average of the borrowing costs applicable to its own borrowings.

Excess of the carrying amount of the qualifying asset over recoverable amount

- 16 When the carrying amount or the expected ultimate cost of the qualifying asset exceeds its recoverable amount or net realisable value, the carrying amount is written down or written off in accordance with the requirements of other Standards. In certain circumstances, the amount of the write-down or write-off is written back in accordance with those other Standards.

Commencement of capitalisation

- 17 An entity shall begin capitalising borrowing costs as part of the cost of a qualifying asset on the commencement date. The commencement date for capitalisation is the date when the entity first meets all of the following conditions:
- (a) it incurs expenditures for the asset;
 - (b) it incurs borrowing costs; and
 - (c) it undertakes activities that are necessary to prepare the asset for its intended use or sale.

- 18 Expenditures on a qualifying asset include only those expenditures that have resulted in payments of cash, transfers of other assets or the assumption of interest-bearing liabilities. Expenditures are reduced by any progress payments received and grants received in connection with the asset (see Ind AS 20 *Accounting for Government Grants and Disclosure of Government Assistance*). The average carrying amount of the asset during a period, including borrowing costs previously capitalised, is normally a reasonable approximation of the expenditures to which the capitalisation rate is applied in that period.
- 19 The activities necessary to prepare the asset for its intended use or sale encompass more than the physical construction of the asset. They include technical and administrative work prior to the commencement of physical construction, such as the activities associated with obtaining permits prior to the commencement of the physical construction. However, such activities exclude the holding of an asset when no production or development that changes the asset's condition is taking place. For example, borrowing costs incurred while land is under development are capitalised during the period in which activities related to the development are being undertaken. However, borrowing costs incurred while land acquired for building purposes is held without any associated development activity do not qualify for capitalisation.

Suspension of capitalisation

- 20 **An entity shall suspend capitalisation of borrowing costs during extended periods in which it suspends active development of a qualifying asset.**
- 21 An entity may incur borrowing costs during an extended period in which it suspends the activities necessary to prepare an asset for its intended use or sale. Such costs are costs of holding partially completed assets and do not qualify for capitalisation. However, an entity does not normally suspend capitalising borrowing costs during a period when it carries out substantial technical and administrative work. An entity also does not suspend capitalising borrowing costs when a temporary delay is a necessary part of the process of getting an asset ready for its intended use or sale. For example, capitalisation continues during the extended period that high water levels delay construction of a bridge, if such high water levels are common during the construction period in the geographical region involved.

Cessation of capitalisation

- 22 **An entity shall cease capitalising borrowing costs when substantially all the activities necessary to prepare the qualifying asset for its intended use or sale are complete.**
- 23 An asset is normally ready for its intended use or sale when the physical construction of the asset is complete even though routine administrative work

might still continue. If minor modifications, such as the decoration of a property to the purchaser's or user's specification, are all that are outstanding, this indicates that substantially all the activities are complete.

- 24 When an entity completes the construction of a qualifying asset in parts and each part is capable of being used while construction continues on other parts, the entity shall cease capitalising borrowing costs when it completes substantially all the activities necessary to prepare that part for its intended use or sale.
- 25 A business park comprising several buildings, each of which can be used individually, is an example of a qualifying asset for which each part is capable of being usable while construction continues on other parts. An example of a qualifying asset that needs to be complete before any part can be used is an industrial plant involving several processes which are carried out in sequence at different parts of the plant within the same site, such as a steel mill.

Disclosure

- 26 An entity shall disclose:
- (a) the amount of borrowing costs capitalised during the period; and
 - (b) the capitalisation rate used to determine the amount of borrowing costs eligible for capitalisation.

Appendix A

References to matters contained in other Indian Accounting Standards (Ind ASs)

This Appendix is an integral part of Indian Accounting Standard (Ind AS) 23.

1. Appendix A (*Changes in Existing Decommissioning, Restoration and Similar Liabilities*) contained in Ind AS 16 *Property, Plant and Equipment* makes reference to this Standard also.
2. Appendix A (*Service Concession Arrangements*) contained in Ind AS 11, *Construction Contracts*, makes reference to this Standard also.

Appendix 1

Note: This Appendix is not a part of the Indian Accounting Standard. The purpose of this Appendix is only to bring out the differences, if any, between Indian Accounting Standard (Ind AS) 23 and the corresponding International Accounting Standard (IAS) 23, Borrowing Costs.

Comparison with IAS 23, Borrowing Costs

- 1 IAS 23 provides no guidance as to how the adjustment prescribed in paragraph 6(e) is to be determined. Paragraph 6A is added in Ind AS 23 to provide the guidance.
- 2 The following paragraph numbers appear as 'Deleted' in IAS 23. In order to maintain consistency with paragraph numbers of IAS 23, the paragraph numbers are retained in Ind AS 23:
 - (i) paragraph 6(a)
 - (ii) paragraph 6(b)
- 3 The transitional provisions given in IAS 23 have not been given in Ind AS 23, since all transitional provisions related to Ind ASs, wherever considered appropriate have been included in Ind AS 101, *First-time Adoption of Indian Accounting Standards* corresponding to IFRS 1, *First-time Adoption of International Financial Reporting Standards*.

Indian Accounting Standard (Ind AS) 24

Related Party Disclosures

*(This Indian Accounting Standard includes paragraphs set in **bold type** and plain type, which have equal authority. Paragraphs in **bold type** indicate the main principles.)*

Objective

- 1 The objective of this Standard is to ensure that an entity's financial statements contain the disclosures necessary to draw attention to the possibility that its financial position and profit or loss may have been affected by the existence of related parties and by transactions and outstanding balances, including commitments, with such parties.

Scope

- 2 This Standard shall be applied in:
 - (a) **Identifying related party relationships and transactions;**
 - (b) **Identifying outstanding balances, including commitments, between an entity and its related parties;**

- (c) **identifying the circumstances in which disclosure of the items in (a) and (b) is required; and**
- (d) **determining the disclosures to be made about those items.**
- 3 **This Standard requires disclosure of related party relationships, transactions and outstanding balances, including commitments, in the consolidated and separate financial statements of a parent, venturer or investor presented in accordance with Indian Accounting Standard (Ind AS) 27 *Consolidated and Separate Financial Statements*. This Standard also applies to individual financial statements.**
- 4 Related party transactions and outstanding balances with other entities in a group are disclosed in an entity's financial statements. Intra-group related party transactions and outstanding balances are eliminated in the preparation of consolidated financial statements of the group.
- 4A Related party disclosure requirements as laid down in this Standard do not apply in circumstances where providing such disclosures would conflict with the reporting entity's duties of confidentiality as specifically required in terms of a statute or by any regulator or similar competent authority.
- 4B In case a statute or a regulator or a similar competent authority governing an entity prohibit the entity to disclose certain information which is required to be disclosed as per this Standard, disclosure of such information is not warranted. For example, banks are obliged by law to maintain confidentiality in respect of their customers' transactions and this Standard would not override the obligation to preserve the confidentiality of customers' dealings.

Purpose of related party disclosures

- 5 Related party relationships are a normal feature of commerce and business. For example, entities frequently carry on parts of their activities through subsidiaries, joint ventures and associates. In those circumstances, the entity has the ability to affect the financial and operating policies of the investee through the presence of control, joint control or significant influence.
- 6 A related party relationship could have an effect on the profit or loss and financial position of an entity. Related parties may enter into transactions that unrelated parties would not. For example, an entity that sells goods to its parent at cost might not sell on those terms to another customer. Also, transactions between related parties may not be made at the same amounts as between unrelated parties.
- 7 The profit or loss and financial position of an entity may be affected by a related party relationship even if related party transactions do not occur. The mere existence of the relationship may be sufficient to affect the transactions of the entity with other parties. For example, a subsidiary may terminate relations with a trading partner on acquisition by the parent of a fellow subsidiary engaged in the same activity as the former trading partner. Alternatively, one party may refrain from acting because of the significant influence of another—for example, a subsidiary may be instructed by its parent not to engage in research and development.

- 8 For these reasons, knowledge of an entity's transactions, outstanding balances, including commitments, and relationships with related parties may affect assessments of its operations by users of financial statements, including assessments of the risks and opportunities facing the entity.

Definitions

- 9 The following terms are used in this Standard with the meanings specified:

A related party is a person or entity that is related to the entity that is preparing its financial statements (in this Standard referred to as the 'reporting entity').

- (a) A person or a close member of that person's family is related to a reporting entity if that person:
- (i) has control or joint control over the reporting entity;
 - (ii) has significant influence over the reporting entity; or
 - (iii) is a member of the key management personnel of the reporting entity or of a parent of the reporting entity.
- (b) An entity is related to a reporting entity if any of the following conditions applies:
- (i) The entity and the reporting entity are members of the same group (which means that each parent, subsidiary and fellow subsidiary is related to the others).
 - (ii) One entity is an associate or joint venture of the other entity (or an associate or joint venture of a member of a group of which the other entity is a member).
 - (iii) Both entities are joint ventures of the same third party.
 - (iv) One entity is a joint venture of a third entity and the other entity is an associate of the third entity.
 - (v) The entity is a post-employment benefit plan for the benefit of employees of either the reporting entity or an entity related to the reporting entity. If the reporting entity is itself such a plan, the sponsoring employers are also related to the reporting entity.
 - (vi) The entity is controlled or jointly controlled by a person identified in (a).
 - (vii) A person identified in (a)(i) has significant influence over the entity or is a member of the key management personnel of the entity (or of a parent of the entity).

A related party transaction is a transfer of resources, services or obligations between a reporting entity and a related party, regardless of whether a price is charged.

Close members of the family of a person are the persons specified within meaning of 'relative' under the Companies Act 1956 and that person's domestic partner, children of that person's domestic partner and dependants of that person's domestic partner.

Compensation includes all employee benefits (as defined in Ind AS 19 *Employee Benefits*) including employee benefits to which Ind AS 102 *Share-based Payments* applies. Employee benefits are all forms of consideration paid, payable or provided by the entity, or on behalf of the entity, in exchange for services rendered to the entity. It also includes such consideration paid on behalf of a parent of the entity in respect of the entity. Compensation includes:

- (a) short-term employee benefits, such as wages, salaries and social security contributions, paid annual leave and paid sick leave, profit-sharing and bonuses (if payable within twelve months of the end of the period) and non-monetary benefits (such as medical care, housing, cars and free or subsidised goods or services) for current employees;
- (b) post-employment benefits such as pensions, other retirement benefits, post-employment life insurance and post-employment medical care;
- (c) other long-term employee benefits, including long-service leave or sabbatical leave, jubilee or other long-service benefits, long-term disability benefits and, if they are not payable wholly within twelve months after the end of the period, profit-sharing, bonuses and deferred compensation;
- (d) termination benefits; and
- (e) share-based payment.

Control is the power to govern the financial and operating policies of an entity so as to obtain benefits from its activities.

Joint control is the contractually agreed sharing of control over an economic activity.

Key management personnel are those persons having authority and responsibility for planning, directing and controlling the activities of the entity, directly or indirectly, including any director (whether executive or otherwise) of that entity.

Significant influence is the power to participate in the financial and operating policy decisions of an entity, but is not control over those policies. Significant influence may be gained by share ownership, statute or agreement.

Government refers to government, government agencies and similar bodies whether local, national or international.

A government-related entity is an entity that is controlled, jointly controlled or significantly influenced by a government.

- 10 In considering each possible related party relationship, attention is directed to the substance of the relationship and not merely the legal form.
- 11 In the context of this Standard, the following are not related parties:
- (a) two entities simply because they have a director or other member of key management personnel in common or because a member of key management personnel of one entity has significant influence over the other entity.
 - (b) two venturers simply because they share joint control over a joint venture.
 - (c)
 - (i) providers of finance,
 - (ii) trade unions,
 - (iii) public utilities, and
 - (iv) departments and agencies of a government that does not control, jointly control or significantly influence the reporting entity,

simply by virtue of their normal dealings with an entity (even though they may affect the freedom of action of an entity or participate in its decision-making process).
 - (d) a customer, supplier, franchisor, distributor or general agent with whom an entity transacts a significant volume of business, simply by virtue of the resulting economic dependence.
- 12 In the definition of a related party, an associate includes subsidiaries of the associate and a joint venture includes subsidiaries of the joint venture. Therefore, for example, an associate's subsidiary and the investor that has significant influence over the associate are related to each other.

Disclosures

All entities

- 13 Relationships between a parent and its subsidiaries shall be disclosed irrespective of whether there have been transactions between them. An entity shall disclose the name of its parent and, if different, the ultimate controlling party. If neither the entity's parent nor the ultimate controlling

party produces consolidated financial statements available for public use, the name of the next most senior parent that does so shall also be disclosed.

- 14 To enable users of financial statements to form a view about the effects of related party relationships on an entity, it is appropriate to disclose the related party relationship when control exists, irrespective of whether there have been transactions between the related parties. This is because the existence of control relationship may prevent the reporting entity from being independent in making its financial and operating decisions. The disclosure of the name of the related party and the nature of the related party relationship where control exists may sometimes be at least as relevant in appraising an entity's prospects as are the operating results and the financial position presented in its financial statements. Such a related party may establish the entity's credit standing, determine the source and price of its raw materials, and determine to whom and at what price the product is sold.
- 15 The requirement to disclose related party relationships between a parent and its subsidiaries is in addition to the disclosure requirements in Ind AS 27 *Consolidated and Separate Financial Statements*, Ind AS 28 *Investments in Associates* and Ind AS 31 *Interests in Joint Ventures*.
- 16 Paragraph 13 refers to the next most senior parent. This is the first parent in the group above the immediate parent that produces consolidated financial statements available for public use.
- 17 **An entity shall disclose key management personnel compensation in total and for each of the following categories:**
 - (a) short-term employee benefits;
 - (b) post-employment benefits;
 - (c) other long-term benefits;
 - (d) termination benefits; and
 - (e) share-based payment.
- 18 If an entity has had related party transactions during the periods covered by the financial statements, it shall disclose the nature of the related party relationship as well as information about those transactions and outstanding balances, including commitments, necessary for users to understand the potential effect of the relationship on the financial statements. These disclosure requirements are in addition to those in paragraph 17. At a minimum, disclosures shall include:
 - (a) the amount of the transactions;

- (b) the amount of outstanding balances, including commitments, and:
 - (i) their terms and conditions, including whether they are secured, and the nature of the consideration to be provided in settlement; and
 - (ii) details of any guarantees given or received;
 - (c) provisions for doubtful debts related to the amount of outstanding balances; and
 - (d) the expense recognised during the period in respect of bad or doubtful debts due from related parties.
- 19 The disclosures required by paragraph 18 shall be made separately for each of the following categories:
- (a) the parent;
 - (b) entities with joint control or significant influence over the entity;
 - (c) subsidiaries;
 - (d) associates;
 - (e) joint ventures in which the entity is a venturer;
 - (f) key management personnel of the entity or its parent; and
 - (g) other related parties
- 20 The classification of amounts payable to, and receivable from, related parties in the different categories as required in paragraph 19 is an extension of the disclosure requirement in Ind AS 1 *Presentation of Financial Statements* for information to be presented either in the balance sheet or in the notes. The categories are extended to provide a more comprehensive analysis of related party balances and apply to related party transactions.
- 21 The following are examples of transactions that are disclosed if they are with a related party:
- (a) purchases or sales of goods (finished or unfinished);
 - (b) purchases or sales of property and other assets;
 - (c) rendering or receiving of services;
 - (d) leases;

- (e) transfers of research and development;
 - (f) transfers under licence agreements;
 - (g) transfers under finance arrangements (including loans and equity contributions in cash or in kind);
 - (h) provision of guarantees or collateral;
 - (i) commitments to do something if a particular event occurs or does not occur in the future, including executory contracts¹ (recognized and unrecognised);
 - (j) settlement of liabilities on behalf of the entity or by the entity on behalf of that related party;
 - (k) management contracts including for deputation of employees.
- 22 Participation by a parent or subsidiary in a defined benefit plan that shares risks between group entities is a transaction between related parties. (see paragraph 34B of Ind AS 19).
- 23 Disclosures that related party transactions were made on terms equivalent to those that prevail in arm's length transactions are made only if such terms can be substantiated.
- 24 **Items of a similar nature may be disclosed in aggregate except when separate disclosure is necessary for an understanding of the effects of related party transactions on the financial statements of the entity.**
- 24A Disclosure of details of particular transactions with individual related parties would frequently be too voluminous to be easily understood. Accordingly, items of a similar nature may be disclosed in aggregate by type of related party. However, this is not done in such a way as to obscure the importance of significant transactions. Hence, purchases or sales of goods are not aggregated with purchases or sales of fixed assets. Nor a material related party transaction with an individual party is clubbed in an aggregated disclosure.

Government-related entities

- 25 **A reporting entity is exempt from the disclosure requirements of paragraph 18 in relation to related party transactions and outstanding balances, including commitments, with:**
- (a) **a government that has control, joint control or significant influence over the reporting entity; and**

¹ Ind AS 37 *Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets* defines executory contracts as contracts under which neither party has performed any of its obligations or both parties have partially performed their obligations to an equal extent.

- (b) another entity that is a related party because the same government has control, joint control or significant influence over both the reporting entity and the other entity.

26 If a reporting entity applies the exemption in paragraph 25, it shall disclose the following about the transactions and related outstanding balances referred to in paragraph 25:

- (a) the name of the government and the nature of its relationship with the reporting entity (ie control, joint control or significant influence);

- (b) the following information in sufficient detail to enable users of the entity's financial statements to understand the effect of related party transactions on its financial statements:

- (i) the nature and amount of each individually significant transaction; and

- (ii) for other transactions that are collectively, but not individually, significant, a qualitative or quantitative indication of their extent. Types of transactions include those listed in paragraph 21.

27 In using its judgement to determine the level of detail to be disclosed in accordance with the requirements in paragraph 26(b), the reporting entity shall consider the closeness of the related party relationship and other factors relevant in establishing the level of significance of the transaction such as whether it is:

- (a) significant in terms of size;
- (b) carried out on non-market terms;
- (c) outside normal day-to-day business operations, such as the purchase and sale of businesses;
- (d) disclosed to regulatory or supervisory authorities;
- (e) reported to senior management;
- (f) subject to shareholder approval.

Illustrative examples

The following examples accompany, but are not part of, Ind AS 24 Related Party Disclosures.

They illustrate:

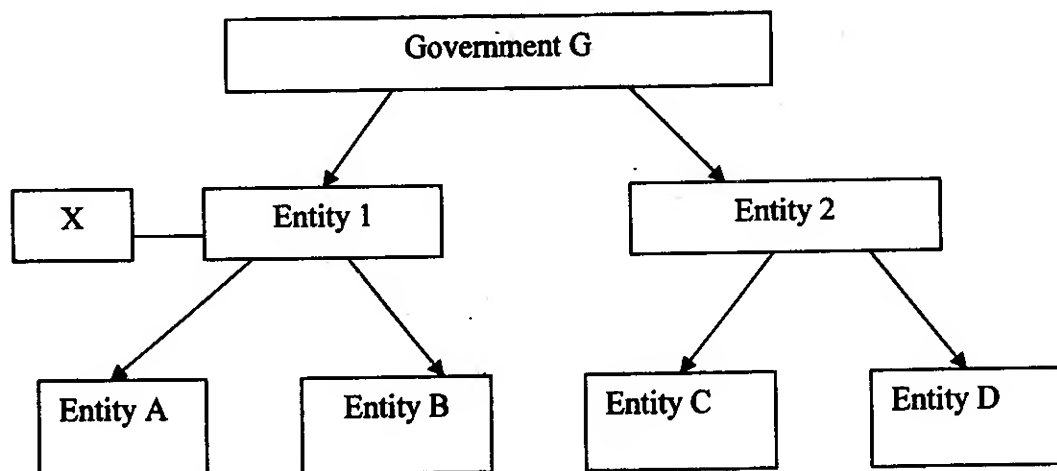
- the partial exemption for government-related entities; and
- how the definition of a related party would apply in specified circumstances.

In the examples, references to 'financial statements' relate to the individual, separate or consolidated financial statements.

Partial exemption for government-related entities

Example 1 – Exemption from disclosure (Paragraph 25)

IE 1 Government G directly or indirectly controls Entities 1 and 2 and Entities A, B, C and D. Person X is a member of the key management personnel of Entity 1.



IE 2 For Entity A's financial statements, the exemption in paragraph 25 applies to:

- transactions with Government G; and
- transactions with Entities 1 and 2 and Entities B, C and D.

However, that exemption does not apply to transactions with Person X.

Disclosure requirements when exemption applies (paragraph 26)

- IE 3 In Entity A's financial statements, an example of disclosure to comply with paragraph 26 (b)(i) for **individually** significant transactions could be:

*Example of disclosure for individually significant transaction carried out on **non-market terms***

On 15 January 20X1 Entity A, a utility company in which Government G indirectly owns 75 per cent of outstanding shares, sold a 10 hectare piece of land to another government-related utility company for Rs 5 million. On 31 December 20X0 a plot of land in a similar location, of a similar size and with similar characteristics, was sold for Rs 3 million. There had not been any appreciation or depreciation of the land in the intervening period. See note X [of the financial statements] for disclosure of government assistance as required by Ind AS 20 *Accounting for Government Grants and Disclosure of Government Assistance* and notes Y and Z [of the financial statements] for compliance with other relevant Accounting Standards.

*Example of disclosure for individually significant transaction because of **size of transaction***

In the year ended December 20X1 Government G provided Entity A, a utility company in which Government G indirectly owns 75 per cent of outstanding shares, with a loan equivalent to 50 per cent of its funding requirement, repayable in quarterly instalments over the next five years. Interest is charged on the loan at a rate of 3 per cent, which is comparable to that charged on Entity A's bank loans.* See notes Y and Z [of the financial statements] for compliance with other relevant Accounting Standards.

Example of disclosure of collectively significant transactions

In Entity A's financial statements, an example of disclosure to comply with paragraph 26(b)(ii) for **collectively** significant transactions could be:

Government G, indirectly, owns 75 per cent of Entity A's outstanding shares. Entity A's significant transactions with Government G and other entities controlled, jointly controlled or significantly influenced by Government G are [a large portion of its sales of goods and purchases of raw materials] or [about 50 per cent of its sales of goods and about 35 per cent of its purchases of raw materials].

The company also benefits from guarantees by Government G of the company's bank borrowing. See note X [of the financial statements] for disclosure of government assistance as required by Ind AS 20 *Accounting for Government Grants and Disclosure of Government Assistance* and notes Y and Z [of the financial statements] for compliance with other relevant Accounting Standards.

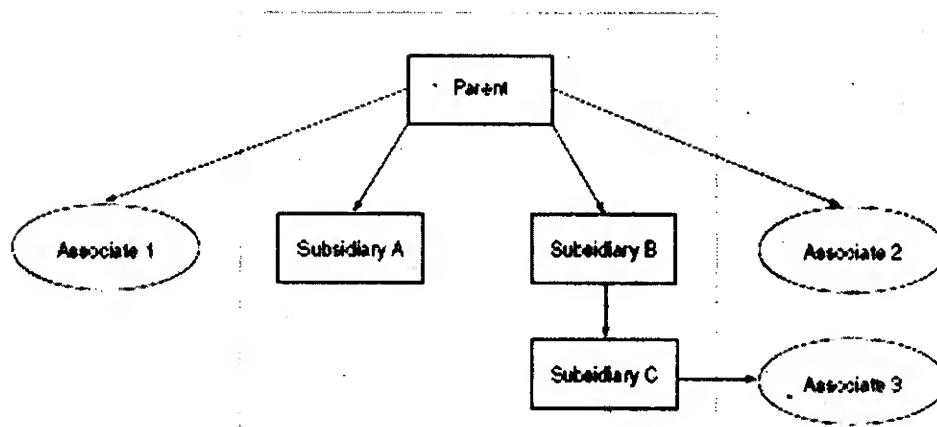
* If the reporting entity had concluded that this transaction constituted government assistance it would have needed to consider the disclosure requirements in Ind AS 20

Definition of a related party

The references are to subparagraphs of the definition of a related party in paragraph 9 of Ind AS 24.

Example 2 – Associates and subsidiaries

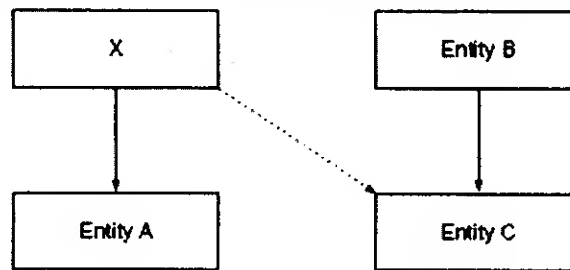
- IE 4 Parent entity has a controlling interest in Subsidiaries A, B and C and has significant influence over Associates 1 and 2. Subsidiary C has significant influence over Associate 3.



- IE 5 For Parent's separate financial statements, Subsidiaries A, B and C and Associates 1, 2 and 3 are related parties. [Paragraph 9(b)(i) and (ii)]
- IE 6 For Subsidiary A's financial statements, Parent, Subsidiaries B and C and Associates 1, 2 and 3 are related parties. For Subsidiary B's separate financial statements, Parent, Subsidiaries A and C and Associates 1, 2 and 3 are related parties. For Subsidiary C's financial statements, Parent, Subsidiaries A and B and Associates 1, 2 and 3 are related parties. [Paragraph 9(b)(i) and (ii)]
- IE 7 For the financial statements of Associates 1, 2 and 3, Parent and Subsidiaries A, B and C are related parties. Associates 1, 2 and 3 are not related to each other. [Paragraph 9(b)(ii)]
- IE 8 For Parent's consolidated financial statements, Associates 1, 2 and 3 are related to the Group. [Paragraph 9(b)(ii)]

Example 3 – Key management personnel

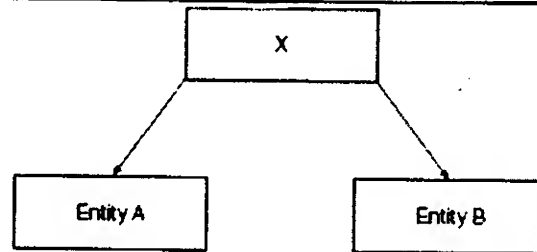
- IE 9 A person, X, has a 100 per cent investment in Entity A and is a member of the key management personnel of Entity C. Entity B has a 100 per cent investment in Entity C.



- IE 10 For Entity C's financial statements, Entity A is related to Entity C because X controls Entity A and is a member of the key management personnel of Entity C. [Paragraph 9(b)(vi)–(a)(iii)]
- IE 11 For Entity C's financial statements, Entity A is also related to Entity C if X is a member of the key management personnel of Entity B and not of Entity C. [Paragraph 9(b)(vi)–(a)(iii)]
- IE 12 Furthermore, the outcome described in paragraphs IE10 and IE11 will be the same if X has joint control over Entity A. [Paragraph 9(b)(vi)–(a)(iii)]
- IE 12A The outcome described in paragraphs IE 10 and IE11 would be different, if X had only significant influence over Entity A and not control or joint control; then Entities A and C would not be related to each other.
- IE 13 For Entity A's financial statements, Entity C is related to Entity A because X controls A and is a member of Entity C's key management personnel. [Paragraph 9(b)(vii)–(a)(i)]
- IE 14 Furthermore, the outcome described in paragraph IE13 will be the same if X has joint control over Entity A.
- IE 14A The outcome described in paragraph IE 13 will also be the same if X is a member of key management personnel of Entity B and not of Entity C. [Paragraph 9(b)(vii)–(a)(i)]
- IE 15 For Entity B's consolidated financial statements, Entity A is a related party of the Group if X is a member of key management personnel of the Group. [Paragraph 9(b)(vi)–(a)(iii)]

Example 4 – Person as investor

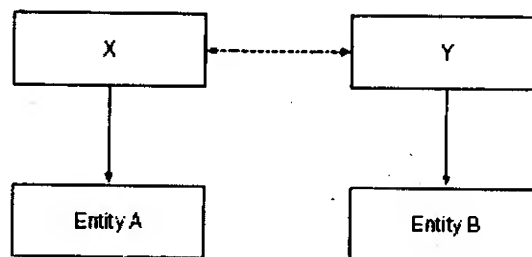
- IE 16 A person, X, has an investment in Entity A and Entity B.



- IE 17 For Entity A's financial statements, if X controls or jointly controls Entity A, Entity B is related to Entity A when X has control, joint control or significant influence over Entity B. [Paragraph 9(b)(vi)–(a)(i) and 9(b)(vii)–(a)(i)]
- IE 18 For Entity B's financial statements, if X controls or jointly controls Entity A, Entity A is related to Entity B when X has control, joint control or significant influence over Entity B. [Paragraph 9(b)(vi)–(a)(i) and 9(b)(vi)–(a)(ii)]
- IE 19 If X has significant influence over both Entity A and Entity B, Entities A and B are not related to each other.

Example 5 – Close members of the family holding investments

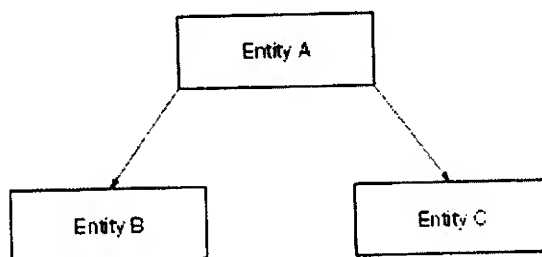
- IE 20 A person, X, is the domestic partner of Y. X has an investment in Entity A and Y has an investment in Entity B.



- IE 21 For Entity A's financial statements, if X controls or jointly controls Entity A, Entity B is related to Entity A when Y has control, joint control or significant influence over Entity B. [Paragraph 9(b)(vi)–(a)(i) and 9(b)(vii)–(a)(i)]
- IE 22 For Entity B's financial statements, if X controls or jointly controls Entity A, Entity A is related to Entity B when Y has control, joint control or significant influence over Entity B. [Paragraph 9(b)(vi)–(a)(i) and 9(b)(vi)–(a)(ii)]
- IE 23 If X has significant influence over Entity A and Y has significant influence over Entity B, Entities A and B are not related to each other.

Example 6 – Entity with joint control

- IE 24 Entity A has both (i) joint control over Entity B and (ii) joint control or significant influence over Entity C.



- IE 25 For Entity B's financial statements, Entity C is related to Entity B. [Paragraph 9(b)(iii) and (iv)]
- IE 26 Similarly, for Entity C's financial statements, Entity B is related to Entity C. [Paragraph 9(b)(iii) and (iv)]

Appendix 1

Note: This appendix is not a part of the Indian Accounting Standard. The purpose of this Appendix is only to bring out the differences, if any, between Indian Accounting Standard (Ind AS) 24 and the corresponding International Accounting Standard (IAS) 24, Related Party Disclosures

Comparison with IAS 24, *Related Party Disclosures*

1. In the Ind AS 24, disclosures which conflict with confidentiality requirements of statute/regulations are not required to be made since Accounting Standards can not override legal/regulatory requirements. (Paragraphs 4A and 4B of Ind AS 24).
2. In the Ind AS 24, relatives as specified under the meaning of relative under the Companies Act, 1956 are included in the definition of the '**close members of the family of a person**'
3. Paragraph 24A has been included in the Ind AS 24. It provides additional clarificatory guidance regarding aggregation of transactions for disclosure.
4. Different terminology is used in this standard, e.g., the term 'balance sheet' is used instead of 'Statement of financial position'.

Indian Accounting Standard (Ind AS) 28

Investments in Associates

(This Indian Accounting Standard includes paragraphs set in bold type and plain type, which have equal authority. Paragraphs in bold type indicate the main principles.)

Scope

1 This Standard shall be applied in accounting for investments in associates. However, it does not apply to investments in associates held by:

a. venture capital organisations

b. [Refer to Appendix 1]

that upon initial recognition are designated as at fair value through profit or loss or are classified as held for trading and accounted for in accordance with Ind AS 39 *Financial Instruments: Recognition and Measurement*. Such investments shall be measured at fair value in accordance with Ind AS 39, with changes in fair value recognised in profit or loss in the period of the change. An entity holding such an investment shall make the disclosures required by paragraph 37(f).

Definitions

2 The following terms are used in this Standard with the meanings specified:

An associate is an entity, including an unincorporated entity such as a partnership, over which the investor has significant influence and that is neither a subsidiary nor an interest in a joint venture.

Consolidated financial statements are the financial statements of a group presented as those of a single economic entity.

Control is the power to govern the financial and operating policies of an entity so as to obtain benefits from its activities.

The equity method is a method of accounting whereby the investment is

initially recognised at cost and adjusted thereafter for the post-acquisition change in the investor's share of net assets of the investee. The profit or loss of the investor includes the investor's share of the profit or loss of the investee.

Joint control is the contractually agreed sharing of control over an economic activity, and exists only when the strategic financial and operating decisions relating to the activity require the unanimous consent of the parties sharing control (the venturers).

Separate financial statements are those presented by a parent, an investor in an associate or a venturer in a jointly controlled entity, in which the investments are accounted for on the basis of the direct equity interest rather than on the basis of the reported results and net assets of the investees.

Significant influence is the power to participate in the financial and operating policy decisions of the investee but is not control or joint control over those policies.

A subsidiary is an entity, including an unincorporated entity such as a partnership, that is controlled by another entity (known as the parent).

- 3 Financial statements in which the equity method is applied are not separate financial statements, nor are the financial statements of an entity that does not have a subsidiary, associate or venturer's interest in a joint venture.
- 4 Separate financial statements are those presented in addition to consolidated financial statements, financial statements in which investments are accounted for using the equity method and financial statements in which venturers' interests in joint ventures are proportionately consolidated. Separate financial statements may or may not be appended to, or accompany, those financial statements, unless required by law.
- 5 [Refer to Appendix 1]

Significant influence

- 6 If an investor holds, directly or indirectly (eg through subsidiaries), 20 per cent or more of the voting power of the investee, it is presumed that the investor has significant influence, unless it can be clearly demonstrated that this is not the case. Conversely, if the investor holds, directly or indirectly (eg through subsidiaries), less than 20 per cent of the voting power of the investee, it is presumed that the investor does not have significant influence, unless such influence can be clearly demonstrated. A substantial or majority ownership by another investor does not necessarily preclude an investor from having significant influence.

- 7 The existence of significant influence by an investor is usually evidenced in one or more of the following ways:
- a. representation on the board of directors or equivalent governing body of the investee;
 - b. participation in policy-making processes, including participation in decisions about dividends or other distributions;
 - c. material transactions between the investor and the investee;
 - d. interchange of managerial personnel; or
 - e. provision of essential technical information.
- 8 An entity may own share warrants, share call options, debt or equity instruments that are convertible into ordinary shares¹, or other similar instruments that have the potential, if exercised or converted, to give the entity additional voting power or reduce another party's voting power over the financial and operating policies of another entity (ie potential voting rights). The existence and effect of potential voting rights that are currently exercisable or convertible, including potential voting rights held by other entities, are considered when assessing whether an entity has significant influence. Potential voting rights are not currently exercisable or convertible when, for example, they cannot be exercised or converted until a future date or until the occurrence of a future event.
- 9 In assessing whether potential voting rights contribute to significant influence, the entity examines all facts and circumstances (including the terms of exercise of the potential voting rights and any other contractual arrangements whether considered individually or in combination) that affect potential rights, except the intention of management and the financial ability to exercise or convert.
- 10 An entity loses significant influence over an investee when it loses the power to participate in the financial and operating policy decisions of that investee. The loss of significant influence can occur with or without a change in absolute or relative ownership levels. It could occur, for example, when an associate becomes subject to the control of a government, court, administrator or regulator. It could also occur as a result of a contractual agreement.

Equity method

- 11 Under the equity method, the investment in an associate is initially recognised at cost and the carrying amount is increased or decreased to recognise the

¹ In Indian context, the term 'ordinary shares' is equivalent to 'equity shares'.

investor's share of the profit or loss of the investee after the date of acquisition. The investor's share of the profit or loss of the investee is recognised in the investor's profit or loss. Distributions received from an investee reduce the carrying amount of the investment. Adjustments to the carrying amount may also be necessary for changes in the investor's proportionate interest in the investee arising from changes in the investee's other comprehensive income. Such changes include those arising from the revaluation of property, plant and equipment and from foreign exchange translation differences. The investor's share of those changes is recognised in other comprehensive income of the investor (see Ind AS 1 *Presentation of Financial Statements*).

- 12 When potential voting rights exist, the investor's share of profit or loss of the investee and of changes in the investee's equity is determined on the basis of present ownership interests and does not reflect the possible exercise or conversion of potential voting rights.

Application of the equity method

- 13 An investment in an associate shall be accounted for using the equity method except when:
- a. the investment is classified as held for sale in accordance with Ind AS 105 *Non-current Assets Held for Sale and Discontinued Operations*;
 - b. [Refer to Appendix 1]
 - c. [Refer to Appendix 1]
- 14 Investments described in paragraph 13(a) shall be accounted for in accordance with Ind AS 105 *Non-current Assets Held for Sale and Discontinued Operations*
- 15 When an investment in an associate previously classified as held for sale no longer meets the criteria to be so classified, it shall be accounted for using the equity method as from the date of its classification as held for sale. Financial statements for the periods since classification as held for sale shall be amended accordingly.
- 16 [Refer to Appendix 1]
- 17 The recognition of income on the basis of distributions received may not be an adequate measure of the income earned by an investor on an investment in an associate because the distributions received may bear little relation to the performance of the associate. Because the investor has significant influence over the associate, the investor has an interest in the associate's performance and, as

a result, the return on its investment. The investor accounts for this interest by extending the scope of its financial statements to include its share of profits or losses of such an associate. As a result, application of the equity method provides more informative reporting of the net assets and profit or loss of the investor.

- 18 An investor shall discontinue the use of the equity method from the date that it ceases to have significant influence over an associate and shall account for the investment in accordance with Ind AS 39 from that date, provided the associate does not become a subsidiary or a joint venture as defined in Ind AS 31. On the loss of significant influence, the investor shall measure at fair value any investment the investor retains in the former associate. The investor shall recognise in profit or loss any difference between:**
- a. the fair value of any retained investment and any proceeds from disposing of the part interest in the associate; and**
 - b. the carrying amount of the investment at the date when significant influence is lost.**
- 19 When an investment ceases to be an associate and is accounted for in accordance with Ind AS 39, the fair value of the investment at the date when it ceases to be an associate shall be regarded as its fair value on initial recognition as a financial asset in accordance with Ind AS 39.**
- 19A If an investor loses significant influence over an associate, the investor shall account for all amounts recognised in other comprehensive income in relation to that associate on the same basis as would be required if the associate had directly disposed of the related assets or liabilities. Therefore, if a gain or loss previously recognised in other comprehensive income by an associate would be reclassified to profit or loss on the disposal of the related assets or liabilities, the investor reclassifies the gain or loss from equity to profit or loss (as a reclassification adjustment) when it loses significant influence over the associate. For example, if an associate has available-for-sale financial assets and the investor loses significant influence over the associate, the investor shall reclassify to profit or loss the gain or loss previously recognised in other comprehensive income in relation to those assets. If an investor's ownership interest in an associate is reduced, but the investment continues to be an associate, the investor shall reclassify to profit or loss only a proportionate amount of the gain or loss previously recognised in other comprehensive income.**
- 20 Many of the procedures appropriate for the application of the equity method are similar to the consolidation procedures described in Ind AS 27. Furthermore, the concepts underlying the procedures used in accounting for the acquisition of a subsidiary are also adopted in accounting for the acquisition of an investment in an associate.**

- 21 A group's share in an associate is the aggregate of the holdings in that associate by the parent and its subsidiaries. The holdings of the group's other associates or joint ventures are ignored for this purpose. When an associate has subsidiaries, associates, or joint ventures, the profits or losses and net assets taken into account in applying the equity method are those recognised in the associate's financial statements (including the associate's share of the profits or losses and net assets of its associates and joint ventures), after any adjustments necessary to give effect to uniform accounting policies (see paragraphs 26 and 27).
- 22 Profits and losses resulting from 'upstream' and 'downstream' transactions between an investor (including its consolidated subsidiaries) and an associate are recognised in the investor's financial statements only to the extent of unrelated investors' interests in the associate. 'Upstream' transactions are, for example, sales of assets from an associate to the investor. 'Downstream' transactions are, for example, sales of assets from the investor to an associate. The investor's share in the associate's profits and losses resulting from these transactions is eliminated.
- 23 An investment in an associate is accounted for using the equity method from the date on which it becomes an associate. On acquisition of the investment any difference between the cost of the investment and the investor's share of the net fair value of the associate's identifiable assets and liabilities is accounted for as follows:
- a. goodwill relating to an associate is included in the carrying amount of the investment. Amortisation of that goodwill is not permitted.
 - b. any excess of the investor's share of the net fair value of the associate's identifiable assets and liabilities over the cost of the investment is recognised directly in equity as capital reserve in the period in which the investment is acquired..
- Appropriate adjustments to the investor's share of the associate's profits or losses after acquisition are also made to account, for example, for depreciation of the depreciable assets based on their fair values at the acquisition date. Similarly, appropriate adjustments to the investor's share of the associate's profits or losses after acquisition are made for impairment losses recognised by the associate, such as for goodwill or property, plant and equipment.
- 24 The most recent available financial statements of the associate are used by the investor in applying the equity method. When the end of the reporting period of the investor is different from that of the associate, the associate prepares, for the use of the investor, financial statements as of the same date as the financial statements of the investor unless it is impracticable to do so.
- 25 When, in accordance with paragraph 24, the financial statements of an associate used in applying the equity method are prepared as of a different date from that of the investor, adjustments shall be made for the effects of

significant transactions or events that occur between that date and the date of the investor's financial statements. In any case, the difference between the end of the reporting period of the associate and that of the investor shall be no more than three months unless it is impracticable to do so. The length of the reporting periods and any difference in the ends of the reporting periods shall be the same from period to period.

- 26 The investor's financial statements shall be prepared using uniform accounting policies for like transactions and events in similar circumstances unless it is impracticable to do so.**
- 27 If an associate uses accounting policies other than those of the investor for like transactions and events in similar circumstances, adjustments shall be made to conform the associate's accounting policies to those of the investor when the associate's financial statements are used by the investor in applying the equity method.**
- 28 If an associate has outstanding cumulative preference shares that are held by parties other than the investor and classified as equity, the investor computes its share of profits or losses after adjusting for the dividends on such shares, whether or not the dividends have been declared.**
- 29 If an investor's share of losses of an associate equals or exceeds its interest in the associate, the investor discontinues recognising its share of further losses. The interest in an associate is the carrying amount of the investment in the associate under the equity method together with any long-term interests that, in substance, form part of the investor's net investment in the associate. For example, an item for which settlement is neither planned nor likely to occur in the foreseeable future is, in substance, an extension of the entity's investment in that associate. Such items may include preference shares and long-term receivables or loans but do not include trade receivables, trade payables or any long-term receivables for which adequate collateral exists, such as secured loans. Losses recognised under the equity method in excess of the investor's investment in ordinary shares are applied to the other components of the investor's interest in an associate in the reverse order of their seniority (ie priority in liquidation).**
- 30 After the investor's interest is reduced to zero, additional losses are provided for, and a liability is recognised, only to the extent that the investor has incurred legal or constructive obligations or made payments on behalf of the associate. If the associate subsequently reports profits, the investor resumes recognising its share of those profits only after its share of the profits equals the share of losses not recognised.**

Impairment losses

- 31 After application of the equity method, including recognising the associate's losses in accordance with paragraph 29, the investor applies the requirements of**

Ind AS 39 to determine whether it is necessary to recognise any additional impairment loss with respect to the investor's net investment in the associate.

- 32 The investor also applies the requirements of Ind AS 39 to determine whether any additional impairment loss is recognised with respect to the investor's interest in the associate that does not constitute part of the net investment and the amount of that impairment loss.
- 33 Because goodwill that forms part of the carrying amount of an investment in an associate is not separately recognised, it is not tested for impairment separately by applying the requirements for impairment testing goodwill in Ind AS 36 *Impairment of Assets*. Instead, the entire carrying amount of the investment is tested for impairment in accordance with Ind AS 36 as a single asset, by comparing its recoverable amount (higher of value in use and fair value less costs to sell) with its carrying amount, whenever application of the requirements in Ind AS 39 indicates that the investment may be impaired. An impairment loss recognised in those circumstances is not allocated to any asset, including goodwill, that forms part of the carrying amount of the investment in the associate. Accordingly, any reversal of that impairment loss is recognised in accordance with Ind AS 36 to the extent that the recoverable amount of the investment subsequently increases. In determining the value in use of the investment, an entity estimates:
- a. its share of the present value of the estimated future cash flows expected to be generated by the associate, including the cash flows from the operations of the associate and the proceeds on the ultimate disposal of the investment; or
 - b. the present value of the estimated future cash flows expected to arise from dividends to be received from the investment and from its ultimate disposal.

Under appropriate assumptions, both methods give the same result.

- 34 The recoverable amount of an investment in an associate is assessed for each associate, unless the associate does not generate cash inflows from continuing use that are largely independent of those from other assets of the entity.

Separate financial statements

- 35 An investment in an associate shall be accounted for in the investor's separate financial statements in accordance with paragraphs 38-43 of Ind AS 27.
- 36 This Standard does not mandate which entities produce separate financial statements available for public use.

Disclosure

37 The following disclosures shall be made:

- a. the fair value of investments in associates for which there are published price quotations;
- b. summarised financial information of associates, including the aggregated amounts of assets, liabilities, revenues and profit or loss;
- c. the reasons why the presumption that an investor does not have significant influence is overcome if the investor holds, directly or indirectly through subsidiaries, less than 20 per cent of the voting or potential voting power of the investee but concludes that it has significant influence;
- d. the reasons why the presumption that an investor has significant influence is overcome if the investor holds, directly or indirectly through subsidiaries, 20 per cent or more of the voting or potential voting power of the investee but concludes that it does not have significant influence;
- e. the end of the reporting period of the financial statements of an associate, when such financial statements are used in applying the equity method and are as of a date or for a period that is different from that of the investor, and the reason for using a different date or different period;
- f. the nature and extent of any significant restrictions (eg resulting from borrowing arrangements or regulatory requirements) on the ability of associates to transfer funds to the investor in the form of cash dividends, or repayment of loans or advances;
- g. the unrecognised share of losses of an associate, both for the period and cumulatively, if an investor has discontinued recognition of its share of losses of an associate;
- h. the fact that an associate is not accounted for using the equity method in accordance with paragraph 13; and
- i. summarised financial information of associates, either individually or in groups, that are not accounted for using the equity method, including the amounts of total assets, total liabilities, revenues and profit or loss.

38 Investments in associates accounted for using the equity method shall be classified as non-current assets. The investor's share of the profit or loss of such associates, and the carrying amount of those investments, shall be separately disclosed. The investor's share of any discontinued operations of such associates shall also be separately disclosed.

- 39 The investor's share of changes recognised in other comprehensive income by the associate shall be recognised by the investor in other comprehensive income.
- 40 In accordance with Ind AS 37 *Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets* the investor shall disclose:
- its share of the contingent liabilities of an associate incurred jointly with other investors; and
 - those contingent liabilities that arise because the investor is severally liable for all or part of the liabilities of the associate.

Appendix A

References to matters contained in other Indian Accounting Standards

This Appendix is an integral part of Indian Accounting Standard (Ind AS) 28.

- Appendix A, *Rights to Interests arising from Decommissioning, Restoration and Environmental Rehabilitation Funds* contained in Ind AS 37 *Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets* makes reference to this Standard also.

Appendix 1

Note: This Appendix is not a part of the Indian Accounting Standard. The purpose of this appendix is only to bring out the differences between Indian Accounting Standard (Ind AS) 28 and the corresponding International Accounting Standard (IAS) 28, Investments in Associates.

Comparison with IAS 28, *Investments in Associates*

- Where the financial statements of an associate used in applying equity method are prepared as of a date different from that of the investor, IAS 28 requires that this difference should not be more than three months. However, paragraph 25 (Ind AS) 28 provides that this difference should not be more than three months, unless impracticable. Similarly, paragraph 26 of Ind AS 28 requires use of uniform accounting policies, unless impracticable, which IAS 28 does not provide. These changes have been made because the investor does not have 'control' over the associate, it may not be able to influence the associate to prepare additional financial statements or to follow the accounting policies that are followed by the investor.

2. Paragraph 1(b) of IAS 28 has been deleted in Ind AS 28 as the Companies Act, 1956, is not applicable to mutual funds, unit trusts and similar entities including investment linked insurance funds and, thus, this standard would not be applicable to such entities. However, paragraph number 1(b) has been retained in Ind AS 28 to maintain consistency with IAS 28.
3. Paragraphs 5, 13(b) and 13(c) have been deleted as the applicability or exemptions to the Indian Accounting Standards is governed by the Companies Act and the Rules made thereunder. However, paragraph numbers have been retained in Ind AS 28 to maintain consistency with IAS 28.
4. Paragraph number 16 appears as 'Deleted' in IAS 28. In order to maintain consistency with paragraph numbers of IAS 28, the paragraph number is retained in Ind AS 28.
5. Paragraph 23 (b) has been modified on the lines of Ind AS 103 to transfer excess of the investor's share of the net fair value of the associate's identifiable assets and liabilities over the cost of investment in capital reserve whereas in IAS 28, it is recognised in profit or loss.

Indian Accounting Standard (Ind AS) 31

Interests in Joint Ventures

*(This Indian Accounting Standard includes paragraphs set in **bold** type and plain type, which have equal authority. Paragraphs in bold type indicate the main principles).*

Scope

- 1 This Standard shall be applied in accounting for interests in joint ventures and the reporting of joint venture assets, liabilities, income and expenses in the financial statements of venturers and investors, regardless of the structures or forms under which the joint venture activities take place. However, it does not apply to venturers' interests in jointly controlled entities held by:
 - (a) venture capital organisations
 - (b) [Refer to Appendix 1]
 that upon initial recognition are designated as at fair value through profit or loss or are classified as held for trading and accounted for in accordance with Ind AS 39 *Financial Instruments: Recognition and Measurement*. Such investments shall be measured at fair value in accordance with Ind AS 39, with changes in fair value recognised in profit or loss in the period of the change. A venturer holding such an interest shall make the disclosures required by paragraphs 55 and 56.
- 2 A venturer with an interest in a jointly controlled entity is exempted from paragraphs 30 (proportionate consolidation) and 38 (equity method) when it meets the following conditions:
 - (a) the interest is classified as held for sale in accordance with Ind AS 105 *Non-current Assets Held for Sale and Discontinued Operations*;
 - (b) [Refer to Appendix 1]
 - (c) [Refer to Appendix 1]

Definitions

- 3 The following terms are used in this Standard with the meanings specified:

Control is the power to govern the financial and operating policies of an economic activity so as to obtain benefits from it.

The **equity method** is a method of accounting whereby an interest in a jointly controlled entity is initially recorded at cost and adjusted thereafter for the post-acquisition change in the venturer's share of net assets of the jointly controlled entity. The profit or loss of the venturer includes the venturer's share of the profit or loss of the jointly controlled entity.

An **investor in a joint venture** is a party to a joint venture and does not have joint control over that joint venture.

Joint control is the contractually agreed sharing of control over an economic activity, and exists only when the strategic financial and operating decisions relating to the activity require the unanimous consent of the parties sharing control (the venturers).

A **joint venture** is a contractual arrangement whereby two or more parties undertake an economic activity that is subject to joint control.

Proportionate consolidation is a method of accounting whereby a venturer's share of each of the assets, liabilities, income and expenses of a jointly controlled entity is combined line by line with similar items in the venturer's financial statements or reported as separate line items in the venturer's financial statements.

Separate financial statements are those presented by a parent, an investor in an associate or a venturer in a jointly controlled entity, in which the investments are accounted for on the basis of the direct equity interest rather than on the basis of the reported results and net assets of the investees.

Significant influence is the power to participate in the financial and operating policy decisions of an economic activity but is not control or joint control over those policies.

A **venturer** is a party to a joint venture and has joint control over that joint venture.

- 4 Financial statements in which proportionate consolidation or the equity method is applied are not separate financial statements, nor are the financial statements of an entity that does not have a subsidiary, associate or venturer's interest in a jointly controlled entity.
- 5 Separate financial statements are those presented in addition to consolidated financial statements, financial statements in which investments are accounted for using the equity method and financial statements in which venturers' interests in joint ventures are proportionately consolidated. Separate financial statements need not be appended to, or accompany, those statements, unless required by law.
- 6 [Refer to Appendix 1]

Forms of joint venture

- 7 Joint ventures take many different forms and structures. This Standard identifies three broad types—jointly controlled operations, jointly controlled assets and jointly controlled entities—that are commonly described as, and meet the

definition of, joint ventures. The following characteristics are common to all joint ventures:

- (a) two or more venturers are bound by a contractual arrangement; and
- (b) the contractual arrangement establishes joint control.

Joint control

- 8 Joint control may be precluded when an investee is in legal reorganisation or in bankruptcy, or operates under severe long-term restrictions on its ability to transfer funds to the venturer. If joint control is continuing, these events are not enough in themselves to justify not accounting for joint ventures in accordance with this Standard.

Contractual arrangement

- 9 The existence of a contractual arrangement distinguishes interests that involve joint control from investments in associates in which the investor has significant influence (see Ind AS 28). Activities that have no contractual arrangement to establish joint control are not joint ventures for the purposes of this Standard.
- 10 The contractual arrangement may be evidenced in a number of ways, for example by a contract between the venturers or minutes of discussions between the venturers. In some cases, the arrangement is incorporated in the articles or other by-laws of the joint venture. Whatever its form, the contractual arrangement is usually in writing and deals with such matters as:
 - (a) the activity, duration and reporting obligations of the joint venture;
 - (b) the appointment of the board of directors or equivalent governing body of the joint venture and the voting rights of the venturers;
 - (c) capital contributions by the venturers; and
 - (d) the sharing by the venturers of the output, income, expenses or results of the joint venture.
- 11 The contractual arrangement establishes joint control over the joint venture. Such a requirement ensures that no single venturer is in a position to control the activity unilaterally.
- 12 The contractual arrangement may identify one venturer as the operator or manager of the joint venture. The operator does not control the joint venture but acts within the financial and operating policies that have been agreed by the venturers in accordance with the contractual arrangement and delegated to the operator. If the operator has the power to govern the financial and operating policies of the economic activity, it controls the venture and the venture is a subsidiary of the operator and not a joint venture.

Jointly controlled operations

- 13 The operation of some joint ventures involves the use of the assets and other resources of the venturers rather than the establishment of a corporation, partnership or other entity, or a financial structure that is separate from the venturers themselves. Each venturer uses its own property, plant and equipment and carries its own inventories. It also incurs its own expenses and liabilities and

- raises its own finance, which represent its own obligations. The joint venture activities may be carried out by the venturer's employees alongside the venturer's similar activities. The joint venture agreement usually provides a means by which the revenue from the sale of the joint product and any expenses incurred in common are shared among the venturers.
- 14 An example of a jointly controlled operation is when two or more venturers combine their operations, resources and expertise to manufacture, market and distribute jointly a particular product, such as an aircraft. Different parts of the manufacturing process are carried out by each of the venturers. Each venturer bears its own costs and takes a share of the revenue from the sale of the aircraft, such share being determined in accordance with the contractual arrangement.
- 15 **In respect of its interests in jointly controlled operations, a venturer shall recognise in its financial statements:**
- (a) **the assets that it controls and the liabilities that it incurs; and**
 - (b) **the expenses that it incurs and its share of the income that it earns from the sale of goods or services by the joint venture.**
- 16 Because the assets, liabilities, income and expenses are recognised in the financial statements of the venturer, no adjustments or other consolidation procedures are required in respect of these items when the venturer presents consolidated financial statements.
- 17 Separate accounting records may not be required for the joint venture itself and financial statements may not be prepared for the joint venture. However, the venturers may prepare management accounts so that they may assess the performance of the joint venture.

Jointly controlled assets

- 18 Some joint ventures involve the joint control, and often the joint ownership, by the venturers of one or more assets contributed to, or acquired for the purpose of, the joint venture and dedicated to the purposes of the joint venture. The assets are used to obtain benefits for the venturers. Each venturer may take a share of the output from the assets and each bears an agreed share of the expenses incurred.
- 19 These joint ventures do not involve the establishment of a corporation, partnership or other entity, or a financial structure that is separate from the venturers themselves. Each venturer has control over its share of future economic benefits through its share of the jointly controlled asset.
- 20 Many activities in the oil, gas and mineral extraction industries involve jointly controlled assets. For example, a number of oil production companies may jointly control and operate an oil pipeline. Each venturer uses the pipeline to transport its own product in return for which it bears an agreed proportion of the expenses of operating the pipeline. Another example of a jointly controlled asset is when two entities jointly control a property, each taking a share of the rents received and bearing a share of the expenses.

- 21 In respect of its interest in jointly controlled assets, a venturer shall recognise in its financial statements:**
- (a) its share of the jointly controlled assets, classified according to the nature of the assets;
 - (b) any liabilities that it has incurred;
 - (c) its share of any liabilities incurred jointly with the other venturers in relation to the joint venture;
 - (d) any income from the sale or use of its share of the output of the joint venture, together with its share of any expenses incurred by the joint venture; and
 - (e) any expenses that it has incurred in respect of its interest in the joint venture.
- 22 In respect of its interest in jointly controlled assets, each venturer includes in its accounting records and recognises in its financial statements:**
- (a) its share of the jointly controlled assets, classified according to the nature of the assets rather than as an investment. For example, a share of a jointly controlled oil pipeline is classified as property, plant and equipment.
 - (b) any liabilities that it has incurred, for example those incurred in financing its share of the assets.
 - (c) its share of any liabilities incurred jointly with other venturers in relation to the joint venture.
 - (d) any income from the sale or use of its share of the output of the joint venture, together with its share of any expenses incurred by the joint venture.
 - (e) any expenses that it has incurred in respect of its interest in the joint venture, for example those related to financing the venturer's interest in the assets and selling its share of the output.

Because the assets, liabilities, income and expenses are recognised in the financial statements of the venturer, no adjustments or other consolidation procedures are required in respect of these items when the venturer presents consolidated financial statements.

- 23 The treatment of jointly controlled assets reflects the substance and economic reality and, usually, the legal form of the joint venture. Separate accounting records for the joint venture itself may be limited to those expenses incurred in common by the venturers and ultimately borne by the venturers according to their agreed shares. Financial statements may not be prepared for the joint venture, although the venturers may prepare management accounts so that they may assess the performance of the joint venture.**

Jointly controlled entities

- 24 A jointly controlled entity is a joint venture that involves the establishment of a corporation, partnership or other entity in which each venturer has an interest. The entity operates in the same way as other entities, except that a contractual**

- arrangement between the venturers establishes joint control over the economic activity of the entity.
- 25 A jointly controlled entity controls the assets of the joint venture, incurs liabilities and expenses and earns income. It may enter into contracts in its own name and raise finance for the purposes of the joint venture activity. Each venturer is entitled to a share of the profits of the jointly controlled entity, although some jointly controlled entities also involve a sharing of the output of the joint venture.
- 26 A common example of a jointly controlled entity is when two entities combine their activities in a particular line of business by transferring the relevant assets and liabilities into a jointly controlled entity. Another example is when an entity commences a business in a foreign country in conjunction with the government or other agency in that country, by establishing a separate entity that is jointly controlled by the entity and the government or agency.
- 27 Many jointly controlled entities are similar in substance to those joint ventures referred to as jointly controlled operations or jointly controlled assets. For example, the venturers may transfer a jointly controlled asset, such as an oil pipeline, into a jointly controlled entity, for tax or other reasons. Similarly, the venturers may contribute into a jointly controlled entity assets that will be operated jointly. Some jointly controlled operations also involve the establishment of a jointly controlled entity to deal with particular aspects of the activity, for example, the design, marketing, distribution or after-sales service of the product.
- 28 A jointly controlled entity maintains its own accounting records and prepares and presents financial statements in the same way as other entities in conformity with Indian Accounting Standards.
- 29 Each venturer usually contributes cash or other resources to the jointly controlled entity. These contributions are included in the accounting records of the venturer and recognised in its financial statements as an investment in the jointly controlled entity.

Financial statements of a venturer

Proportionate consolidation

- 30 A venturer shall recognise its interest in a jointly controlled entity using proportionate consolidation or the alternative method described in paragraph 38. When proportionate consolidation is used, one of the two reporting formats identified below shall be used.
- 31 A venturer recognises its interest in a jointly controlled entity using one of the two reporting formats for proportionate consolidation irrespective of whether it also has investments in subsidiaries or whether it describes its financial statements as consolidated financial statements.
- 32 When recognising an interest in a jointly controlled entity, it is essential that a venturer reflects the substance and economic reality of the arrangement, rather than the joint venture's particular structure or form. In a jointly controlled entity, a venturer has control over its share of future economic benefits through its share of the assets and liabilities of the venture. This substance and economic reality

are reflected in the consolidated financial statements of the venturer when the venturer recognises its interests in the assets, liabilities, income and expenses of the jointly controlled entity by using one of the two reporting formats for proportionate consolidation described in paragraph 34.

- 33 The application of proportionate consolidation means that the balance sheet of the venturer includes its share of the assets that it controls jointly and its share of the liabilities for which it is jointly responsible. The statement of profit and loss of the venturer includes its share of the income and expenses of the jointly controlled entity. Many of the procedures appropriate for the application of proportionate consolidation are similar to the procedures for the consolidation of investments in subsidiaries, which are set out in Ind AS 27.
- 34 Different reporting formats may be used to give effect to proportionate consolidation. The venturer may combine its share of each of the assets, liabilities, income and expenses of the jointly controlled entity with the similar items, line by line, in its financial statements. For example, it may combine its share of the jointly controlled entity's inventory with its inventory and its share of the jointly controlled entity's property, plant and equipment with its property, plant and equipment. Alternatively, the venturer may include separate line items for its share of the assets, liabilities, income and expenses of the jointly controlled entity in its financial statements. For example, it may show its share of a current asset of the jointly controlled entity separately as part of its current assets; it may show its share of the property, plant and equipment of the jointly controlled entity separately as part of its property, plant and equipment. Both these reporting formats result in the reporting of identical amounts of profit or loss and of each major classification of assets, liabilities, income and expenses; both formats are acceptable for the purposes of this Standard.
- 35 Whichever format is used to give effect to proportionate consolidation, it is inappropriate to offset any assets or liabilities by the deduction of other liabilities or assets or any income or expenses by the deduction of other expenses or income, unless a legal right of set-off exists and the offsetting represents the expectation as to the realisation of the asset or the settlement of the liability.
- 36 **A venturer shall discontinue the use of proportionate consolidation from the date on which it ceases to have joint control over a jointly controlled entity.**
- 37 A venturer discontinues the use of proportionate consolidation from the date on which it ceases to share in the control of a jointly controlled entity. This may happen, for example, when the venturer disposes of its interest or when such external restrictions are placed on the jointly controlled entity that the venturer no longer has joint control.

Equity method

- 38 **As an alternative to proportionate consolidation described in paragraph 30, a venturer shall recognise its interest in a jointly controlled entity using the equity method.**
- 39 A venturer recognises its interest in a jointly controlled entity using the equity method irrespective of whether it also has investments in subsidiaries or whether it describes its financial statements as consolidated financial statements.

- 40 Some venturers recognise their interests in jointly controlled entities using the equity method, as described in Ind AS 28. The use of the equity method is supported by those who argue that it is inappropriate to combine controlled items with jointly controlled items and by those who believe that venturers have significant influence, rather than joint control, in a jointly controlled entity. This Standard does not recommend the use of the equity method because proportionate consolidation better reflects the substance and economic reality of a venturer's interest in a jointly controlled entity, that is to say, control over the venturer's share of the future economic benefits. Nevertheless, this Standard permits the use of the equity method, as an alternative treatment, when recognising interests in jointly controlled entities.
- 41 A venturer shall discontinue the use of the equity method from the date on which it ceases to have joint control over, or have significant influence in, a jointly controlled entity.

Exceptions to proportionate consolidation and equity method

- 42 Interests in jointly controlled entities that are classified as held for sale in accordance with Ind AS 105 *Non-current Assets Held for Sale and Discontinued Operations* shall be accounted for in accordance with that Indian Accounting Standard.
- 43 When an interest in a jointly controlled entity previously classified as held for sale no longer meets the criteria to be so classified, it shall be accounted for using proportionate consolidation or the equity method as from the date of its classification as held for sale. Financial statements for the periods since classification as held for sale shall be amended accordingly.
- 44 [Refer to Appendix 1]
- 45 When an investor ceases to have joint control over an entity, it shall account for any remaining investment in accordance with Ind AS 39 from that date, provided that the former jointly controlled entity does not become a subsidiary or associate. From the date when a jointly controlled entity becomes a subsidiary of an investor, the investor shall account for its interest in accordance with Ind AS 27 and Ind AS 103 *Business Combinations*. From the date when a jointly controlled entity becomes an associate of an investor, the investor shall account for its interest in accordance with Ind AS 28. On the loss of joint control, the investor shall measure at fair value any investment the investor retains in the former jointly controlled entity. The investor shall recognise in profit or loss any difference between:
- (a) the fair value of any retained investment and any proceeds from disposing of the part interest in the jointly controlled entity; and
 - (b) the carrying amount of the investment at the date when joint control is lost.
- 45A When an investment ceases to be a jointly controlled entity and is accounted for in accordance with Ind AS 39, the fair value of the investment when it ceases to be a jointly controlled entity shall be regarded as its fair value on initial recognition as a financial asset in accordance with Ind AS 39.

- 45B If an investor loses joint control of an entity, the investor shall account for all amounts recognised in other comprehensive income in relation to that entity on the same basis as would be required if the jointly controlled entity had directly disposed of the related assets or liabilities. Therefore, if a gain or loss previously recognised in other comprehensive income would be reclassified to profit or loss on the disposal of the related assets or liabilities, the investor reclassifies the gain or loss from equity to profit or loss (as a reclassification adjustment) when the investor loses joint control of the entity. For example, if a jointly controlled entity has available-for-sale financial assets and the investor loses joint control of the entity, the investor shall reclassify to profit or loss the gain or loss previously recognised in other comprehensive income in relation to those assets. If an investor's ownership interest in a jointly controlled entity is reduced, but the investment continues to be a jointly controlled entity, the investor shall reclassify to profit or loss only a proportionate amount of the gain or loss previously recognised in other comprehensive income.

Separate financial statements of a venturer

- 46 An interest in a jointly controlled entity shall be accounted for in a venturer's separate financial statements in accordance with paragraphs 38–43 of Ind AS 27.
- 47 This Standard does not mandate which entities produce separate financial statements available for public use.

Transactions between a venturer and a joint venture

- 48 When a venturer contributes or sells assets to a joint venture, recognition of any portion of a gain or loss from the transaction shall reflect the substance of the transaction. While the assets are retained by the joint venture, and provided the venturer has transferred the significant risks and rewards of ownership, the venturer shall recognise only that portion of the gain or loss that is attributable to the interests of the other venturers.¹ The venturer shall recognise the full amount of any loss when the contribution or sale provides evidence of a reduction in the net realisable value of current assets or an impairment loss.
- 49 When a venturer purchases assets from a joint venture, the venturer shall not recognise its share of the profits of the joint venture from the transaction until it resells the assets to an independent party. A venturer shall recognise its share of the losses resulting from these transactions in the same way as profits except that losses shall be recognised immediately when they represent a reduction in the net realisable value of current assets or an impairment loss.
- 50 To assess whether a transaction between a venturer and a joint venture provides evidence of impairment of an asset, the venturer determines the recoverable amount of the asset in accordance with Ind AS 36 *Impairment of Assets*. In determining value in use, the venturer estimates future cash flows

¹ See also Appendix A of this standard *Jointly Controlled Entities—Non-Monetary Contributions by Venturers*.

from the asset on the basis of continuing use of the asset and its ultimate disposal by the joint venture.

Reporting interests in joint ventures in the financial statements of an investor

- 51 An investor in a joint venture that does not have joint control shall account for that investment in accordance with Ind AS 39 or, if it has significant influence in the joint venture, in accordance with Ind AS 28.

Operators of joint ventures

- 52 Operators or managers of a joint venture shall account for any fees in accordance with Ind AS 18 *Revenue*.
- 53 One or more venturers may act as the operator or manager of a joint venture. Operators are usually paid a management fee for such duties. The fees are accounted for by the joint venture as an expense.

Disclosure

- 54 A venturer shall disclose the aggregate amount of the following contingent liabilities, unless the probability of loss is remote, separately from the amount of other contingent liabilities:
- (a) any contingent liabilities that the venturer has incurred in relation to its interests in joint ventures and its share in each of the contingent liabilities that have been incurred jointly with other venturers;
 - (b) its share of the contingent liabilities of the joint ventures themselves for which it is contingently liable; and
 - (c) those contingent liabilities that arise because the venturer is contingently liable for the liabilities of the other venturers of a joint venture.
- 55 A venturer shall disclose the aggregate amount of the following commitments in respect of its interests in joint ventures separately from other commitments:
- (a) any capital commitments of the venturer in relation to its interests in joint ventures and its share in the capital commitments that have been incurred jointly with other venturers; and
 - (b) its share of the capital commitments of the joint ventures themselves.
- 56 A venturer shall disclose a listing and description of interests in significant joint ventures and the proportion of ownership interest held in jointly controlled entities. A venturer that recognises its interests in jointly controlled entities using the line-by-line reporting format for proportionate consolidation or the equity method shall disclose the aggregate amounts of each of current assets, long-term assets, current liabilities, long-term liabilities, income and expenses related to its interests in joint ventures.
- 57 A venturer shall disclose the method it uses to recognise its interests in jointly controlled entities.

APPENDIX A

Jointly Controlled Entities—Non-Monetary Contributions by Venturers

Issue

- 1 Paragraph 48 of Ind AS 31 refers to both contributions and sales between a venturer and a joint venture as follows: 'When a venturer contributes or sells assets to a joint venture, recognition of any portion of a gain or loss from the transaction shall reflect the substance of the transaction'. In addition, paragraph 24 of Ind AS 31 says that 'a jointly controlled entity is a joint venture that involves the establishment of a corporation, partnership or other entity in which each venturer has an interest'. There is no explicit guidance on the recognition of gains and losses resulting from contributions of non-monetary assets to jointly controlled entities ('JCEs').
- 2 Contributions to a JCE are transfers of assets by venturers in exchange for an equity interest in the JCE. Such contributions may take various forms. Contributions may be made simultaneously by the venturers either upon establishing the JCE or subsequently. The consideration received by the venturer(s) in exchange for assets contributed to the JCE may also include cash or other consideration that does not depend on future cash flows of the JCE ('additional consideration').
- 3 The issues are:
 - (a) when the appropriate portion of gains or losses resulting from a contribution of a non-monetary asset to a JCE in exchange for an equity interest in the JCE should be recognised by the venturer in profit or loss;
 - (b) how additional consideration should be accounted for by the venturer; and
 - (c) how any unrealised gain or loss should be presented in the consolidated financial statements of the venturer.
- 4 This Appendix deals with the venturer's accounting for non-monetary contributions to a JCE in exchange for an equity interest in the JCE that is accounted for using either the equity method or proportionate consolidation.

Accounting Principles

- 5 In applying paragraph 48 of Ind AS 31 to non-monetary contributions to a JCE in exchange for an equity interest in the JCE, a venturer shall recognise in profit or loss for the period the portion of a gain or loss attributable to the equity interests of the other venturers except when:
 - (a) the significant risks and rewards of ownership of the contributed non-monetary asset(s) have not been transferred to the JCE; or

- (b) the gain or loss on the non-monetary contribution cannot be measured reliably; or
- (c) the contribution transaction lacks commercial substance, as that term is described in Ind AS 16.

If exception (a), (b) or (c) applies, the gain or loss is regarded as unrealised and therefore is not recognised in profit or loss unless paragraph 6 also applies.

- 6 If, in addition to receiving an equity interest in the JCE, a venturer receives monetary or non-monetary assets, an appropriate portion of gain or loss on the transaction shall be recognised by the venturer in profit or loss.
- 7 Unrealised gains or losses on non-monetary assets contributed to JCEs shall be eliminated against the underlying assets under the proportionate consolidation method or against the investment under the equity method. Such unrealised gains or losses shall not be presented as deferred gains or losses in the venturer's consolidated balance sheet.

Appendix B

References to matters contained in other Indian Accounting Standards

This Appendix is an integral part of Indian Accounting Standard 31.

- 1. Appendix A, *Rights to Interests arising from Decommissioning, Restoration and Environmental Rehabilitation Funds* contained in Ind AS 37 *Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets* makes reference to this Standard also.

Appendix 1

Note: This Appendix is not a part of the Indian Accounting Standard. The purpose of this appendix is only to bring out the differences between Indian Accounting Standard (Ind AS) 31 and the corresponding International Accounting Standard (IAS) 31, Interests in Joint Ventures and SIC 13, Jointly Controlled Entities — Non-Monetary Contributions by Venturers issued by the International Accounting Standards Board.

Comparison with IAS 31, Interests in Joint Ventures

- 1. The transitional provisions given in IAS 31 have not been given in Ind AS 31, since all transitional provisions related to Ind ASs, wherever considered appropriate have been included in Ind AS 101, First-time Adoption of Indian Accounting Standards corresponding to IFRS 1, First-time Adoption of International Financial Reporting Standards.
- 2. Different terminology is used, as used in existing laws e.g., the term 'balance sheet' is used instead of 'Statement of financial position' and 'Statement of profit and loss' is used instead of 'Statement of comprehensive income'.
- 3. Paragraph 1(b) of IAS 31 has been deleted in Ind AS 31 as the Companies Act, 1956, is not applicable to mutual funds, unit trusts and similar entities including investment linked insurance funds and, thus, this standard would not be applicable to such entities. However, paragraph number 1(b) has been retained in Ind AS 31 to maintain consistency with IAS 31

4. Sub-Paragraphs 2(b) and (c) and paragraph 6 have been deleted as the applicability or exemptions to the Indian Accounting Standards is governed by the Companies Act and the Rules made thereunder. However, paragraph number 6 has been retained in Ind AS 31 to maintain consistency with IAS 31.

5. Paragraph 44 has been deleted by IASB. However, the paragraph number has been retained in Ind AS 31 to maintain consistency with IAS 31.

Indian Accounting Standard (Ind AS) 40

Investment Property

*(This Indian Accounting Standard includes paragraphs set in **bold** type and plain type, which have equal authority. Paragraphs in **bold** type indicate the main principles.)*

Objective

- 1 The objective of this Standard is to prescribe the accounting treatment for investment property and related disclosure requirements.

Scope

- 2 This Standard shall be applied in the recognition, measurement and disclosure of investment property.

- 3 Among other things, this Standard applies to the measurement in a lessee's financial statements of investment property interests held under a lease accounted for as a finance lease and to the measurement in a lessor's financial statements of investment property provided to a lessee under an operating lease. This Standard does not deal with matters covered in Ind AS 17 Leases, including:

- (a) classification of leases as finance leases or operating leases;
- (b) recognition of lease income from investment property (see also Ind AS 18 Revenue);
- (c) measurement in a lessee's financial statements of property interests held under a lease accounted for as an operating lease;
- (d) measurement in a lessor's financial statements of its net investment in a finance lease;
- (e) accounting for sale and leaseback transactions; and
- (f) disclosure about finance leases and operating leases.

- 4 This Standard does not apply to:

- (a) biological assets related to agricultural activity (see Ind AS 41 Agriculture¹); and
- (b) mineral rights and mineral reserves such as oil, natural gas and similar non-regenerative resources.

¹ Ind AS 41 Agriculture is under formulation.

Definitions

- 5 The following terms are used in this Standard with the meanings specified:

Carrying amount is the amount at which an asset is recognised in the balance sheet.

Cost is the amount of cash or cash equivalents paid or the fair value of other consideration given to acquire an asset at the time of its acquisition or construction or, where applicable, the amount attributed to that asset when initially recognised in accordance with the specific requirements of other Indian Accounting Standards, eg Ind AS 102 *Share-based Payment*.

Fair value is the amount for which an asset could be exchanged between knowledgeable, willing parties in an arm's length transaction.

Investment property is property (land or a building—or part of a building—or both) held (by the owner or by the lessee under a finance lease) to earn rentals or for capital appreciation or both, rather than for:

- (a) use in the production or supply of goods or services or for administrative purposes; or
- (b) sale in the ordinary course of business.

Owner-occupied property is property held (by the owner or by the lessee under a finance lease) for use in the production or supply of goods or services or for administrative purposes.

- 6 [Refer to Appendix 1]

- 7 Investment property is held to earn rentals or for capital appreciation or both. Therefore, an investment property generates cash flows largely independently of the other assets held by an entity. This distinguishes investment property from owner-occupied property. The production or supply of goods or services (or the use of property for administrative purposes) generates cash flows that are attributable not only to property, but also to other assets used in the production or supply process. Ind AS 16 *Property, Plant and Equipment* applies to owner-occupied property.

- 8 The following are examples of investment property:

- (a) land held for long-term capital appreciation rather than for short-term sale in the ordinary course of business.
- (b) land held for a currently undetermined future use. (If an entity has not determined that it will use the land as owner-occupied property or for short-term sale in the ordinary course of business, the land is regarded as held for capital appreciation.)

- (c) a building owned by the entity (or held by the entity under a finance lease) and leased out under one or more operating leases.
 - (d) a building that is vacant but is held to be leased out under one or more operating leases.
 - (e) property that is being constructed or developed for future use as investment property.
- 9 The following are examples of items that are not investment property and are therefore outside the scope of this Standard:
- (a) property intended for sale in the ordinary course of business or in the process of construction or development for such sale (see Ind AS 2 *Inventories*), for example, property acquired exclusively with a view to subsequent disposal in the near future or for development and resale.
 - (b) property being constructed or developed on behalf of third parties (see Ind AS 11 *Construction Contracts*).
 - (c) owner-occupied property (see Ind AS 16), including (among other things) property held for future use as owner-occupied property, property held for future development and subsequent use as owner-occupied property, property occupied by employees (whether or not the employees pay rent at market rates) and owner-occupied property awaiting disposal.
 - (d) [Refer to Appendix 1]
 - (e) property that is leased to another entity under a finance lease.
- 10 Some properties comprise a portion that is held to earn rentals or for capital appreciation and another portion that is held for use in the production or supply of goods or services or for administrative purposes. If these portions could be sold separately (or leased out separately under a finance lease), an entity accounts for the portions separately. If the portions could not be sold separately, the property is investment property only if an insignificant portion is held for use in the production or supply of goods or services or for administrative purposes.
- 11 In some cases, an entity provides ancillary services to the occupants of a property it holds. An entity treats such a property as investment property if the services are insignificant to the arrangement as a whole. An example is when the owner of an office building provides security and maintenance services to the lessees who occupy the building.
- 12 In other cases, the services provided are significant. For example, if an entity owns and manages a hotel, services provided to guests are significant to the arrangement as a whole. Therefore, an owner-managed hotel is owner-occupied property, rather than investment property.

- 13 It may be difficult to determine whether ancillary services are so significant that a property does not qualify as investment property. For example, the owner of a hotel sometimes transfers some responsibilities to third parties under a management contract. The terms of such contracts vary widely. At one end of the spectrum, the owner's position may, in substance, be that of a passive investor. At the other end of the spectrum, the owner may simply have outsourced day-to-day functions while retaining significant exposure to variation in the cash flows generated by the operations of the hotel.
- 14 Judgement is needed to determine whether a property qualifies as investment property. An entity develops criteria so that it can exercise that judgement consistently in accordance with the definition of investment property and with the related guidance in paragraphs 7–13. Paragraph 75(c) requires an entity to disclose these criteria when classification is difficult.
- 15 In some cases, an entity owns property that is leased to, and occupied by, its parent or another subsidiary. The property does not qualify as investment property in the consolidated financial statements, because the property is owner-occupied from the perspective of the group. However, from the perspective of the entity that owns it, the property is investment property if it meets the definition in paragraph 5. Therefore, the lessor treats the property as investment property in its individual financial statements.

Recognition

- 16 **Investment property shall be recognised as an asset when, and only when:**
- (a) **it is probable that the future economic benefits that are associated with the investment property will flow to the entity; and**
 - (b) **the cost of the investment property can be measured reliably.**
- 17 An entity evaluates under this recognition principle all its investment property costs at the time they are incurred. These costs include costs incurred initially to acquire an investment property and costs incurred subsequently to add to, replace part of, or service a property.
- 18 Under the recognition principle in paragraph 16, an entity does not recognise in the carrying amount of an investment property the costs of the day-to-day servicing of such a property. Rather, these costs are recognised in profit or loss as incurred. Costs of day-to-day servicing are primarily the cost of labour and consumables, and may include the cost of minor parts. The purpose of these expenditures is often described as for the 'repairs and maintenance' of the property.
- 19 Parts of investment properties may have been acquired through replacement. For example, the interior walls may be replacements of original walls. Under the recognition principle, an entity recognises in the carrying amount of an investment property the cost of replacing part of an existing investment property at the time that cost is incurred if the recognition criteria are met. The carrying amount of

those parts that are replaced is derecognised in accordance with the derecognition provisions of this Standard.

Measurement at recognition

- 20** An investment property shall be measured initially at its cost. Transaction costs shall be included in the initial measurement.
- 21** The cost of a purchased investment property comprises its purchase price and any directly attributable expenditure. Directly attributable expenditure includes, for example, professional fees for legal services, property transfer taxes and other transaction costs.
- 22** [Refer to Appendix 1]
- 23** The cost of an investment property is not increased by:
- (a) start-up costs (unless they are necessary to bring the property to the condition necessary for it to be capable of operating in the manner intended by management),
 - (b) operating losses incurred before the investment property achieves the planned level of occupancy, or
 - (c) abnormal amounts of wasted material, labour or other resources incurred in constructing or developing the property.
- 24** If payment for an investment property is deferred, its cost is the cash price equivalent. The difference between this amount and the total payments is recognised as interest expense over the period of credit.
- 25** The initial cost of a property interest held under a lease and classified as an investment property shall be as prescribed for a finance lease by paragraph 20 of Ind AS 17, ie the asset shall be recognised at the lower of the fair value of the property and the present value of the minimum lease payments. An equivalent amount shall be recognised as a liability in accordance with that same paragraph.
- 26** Any premium paid for a lease is treated as part of the minimum lease payments for this purpose, and is therefore included in the cost of the asset, but is excluded from the liability. If a property interest held under a lease is classified as investment property, the item accounted for at fair value is that interest and not the underlying property. Guidance on determining the fair value of a property interest is set out in paragraphs 33–52. That guidance is also relevant to the determination of fair value when that value is used as cost for initial recognition purposes.
- 27** One or more investment properties may be acquired in exchange for a non-monetary asset or assets, or a combination of monetary and non-monetary assets. The following discussion refers to an exchange of one non-monetary asset for another, but it also applies to all exchanges described in the preceding sentence. The cost of such an investment property is measured at fair value unless (a) the

exchange transaction lacks commercial substance or (b) the fair value of neither the asset received nor the asset given up is reliably measurable. The acquired asset is measured in this way even if an entity cannot immediately derecognise the asset given up. If the acquired asset is not measured at fair value, its cost is measured at the carrying amount of the asset given up.

28 An entity determines whether an exchange transaction has commercial substance by considering the extent to which its future cash flows are expected to change as a result of the transaction. An exchange transaction has commercial substance if:

- (a) the configuration (risk, timing and amount) of the cash flows of the asset received differs from the configuration of the cash flows of the asset transferred, or
- (b) the entity-specific value of the portion of the entity's operations affected by the transaction changes as a result of the exchange, and
- (c) the difference in (a) or (b) is significant relative to the fair value of the assets exchanged.

For the purpose of determining whether an exchange transaction has commercial substance, the entity-specific value of the portion of the entity's operations affected by the transaction shall reflect post-tax cash flows. The result of these analyses may be clear without an entity having to perform detailed calculations.

29 The fair value of an asset for which comparable market transactions do not exist is reliably measurable if (a) the variability in the range of reasonable fair value estimates is not significant for that asset or (b) the probabilities of the various estimates within the range can be reasonably assessed and used in estimating fair value. If the entity is able to determine reliably the fair value of either the asset received or the asset given up, then the fair value of the asset given up is used to measure cost unless the fair value of the asset received is more clearly evident.

Measurement after recognition

Accounting policy

30 An entity shall adopt as its accounting policy the cost model prescribed in paragraph 56 to all of its investment property.

31 [Refer to Appendix 1]

32 This Standard requires all entities to determine the fair value of investment property for the purpose of disclosure even though they are required to follow the cost model. An entity is encouraged, but not required, to determine the fair value of investment property on the basis of a valuation by an independent valuer who holds a recognised and relevant professional qualification and has recent experience in the location and category of the investment property being valued.

32A-32C [Refer to Appendix 1]

Fair value determination

33-35 [Refer to Appendix 1]

- 36 The fair value of investment property is the price at which the property could be exchanged between knowledgeable, willing parties in an arm's length transaction (see paragraph 5). Fair value specifically excludes an estimated price inflated or deflated by special terms or circumstances such as atypical financing, sale and leaseback arrangements, special considerations or concessions granted by anyone associated with the sale.
- 37 An entity determines fair value without any deduction for transaction costs it may incur on sale or other disposal.
- 38 **The fair value of investment property shall reflect market conditions at the end of the reporting period.**
- 39 Fair value is time-specific as of a given date. Because market conditions may change, the amount reported as fair value may be incorrect or inappropriate if estimated as of another time. The definition of fair value also assumes simultaneous exchange and completion of the contract for sale without any variation in price that might be made in an arm's length transaction between knowledgeable, willing parties if exchange and completion are not simultaneous.
- 40 The fair value of investment property reflects, among other things, rental income from current leases and reasonable and supportable assumptions that represent what knowledgeable, willing parties would assume about rental income from future leases in the light of current conditions. It also reflects, on a similar basis, any cash outflows (including rental payments and other outflows) that could be expected in respect of the property. Some of those outflows are reflected in the liability whereas others relate to outflows that are not recognised in the financial statements until a later date (eg periodic payments such as contingent rents).
- 41 [Refer to Appendix 1]
- 42 The definition of fair value refers to 'knowledgeable, willing parties'. In this context, 'knowledgeable' means that both the willing buyer and the willing seller are reasonably informed about the nature and characteristics of the investment property, its actual and potential uses, and market conditions at the end of the reporting period. A willing buyer is motivated, but not compelled, to buy. This buyer is neither over-eager nor determined to buy at any price. The assumed buyer would not pay a higher price than a market comprising knowledgeable, willing buyers and sellers would require.
- 43 A willing seller is neither an over-eager nor a forced seller, prepared to sell at any price, nor one prepared to hold out for a price not considered reasonable in current market conditions. The willing seller is motivated to sell the investment property at market terms for the best price obtainable. The factual circumstances of the actual investment property owner are not a part of this consideration because the willing seller is a hypothetical owner (eg a willing seller would not take into account the particular tax circumstances of the actual investment property owner).

- 44 The definition of fair value refers to an arm's length transaction. An arm's length transaction is one between parties that do not have a particular or special relationship that makes prices of transactions uncharacteristic of market conditions. The transaction is presumed to be between unrelated parties, each acting independently.
- 45 The best evidence of fair value is given by current prices in an active market for similar property in the same location and condition and subject to similar lease and other contracts. An entity takes care to identify any differences in the nature, location or condition of the property, or in the contractual terms of the leases and other contracts relating to the property.
- 46 In the absence of current prices in an active market of the kind described in paragraph 45, an entity considers information from a variety of sources, including:
- (a) current prices in an active market for properties of different nature, condition or location (or subject to different lease or other contracts), adjusted to reflect those differences;
 - (b) recent prices of similar properties on less active markets, with adjustments to reflect any changes in economic conditions since the date of the transactions that occurred at those prices; and
 - (c) discounted cash flow projections based on reliable estimates of future cash flows, supported by the terms of any existing lease and other contracts and (when possible) by external evidence such as current market rents for similar properties in the same location and condition, and using discount rates that reflect current market assessments of the uncertainty in the amount and timing of the cash flows.
- 47 In some cases, the various sources listed in the previous paragraph may suggest different conclusions about the fair value of an investment property. An entity considers the reasons for those differences, in order to arrive at the most reliable estimate of fair value within a range of reasonable fair value estimates.
- 48 In exceptional cases, there is clear evidence when an entity first acquires an investment property (or when an existing property first becomes investment property after a change in use) that the variability in the range of reasonable fair value estimates will be so great, and the probabilities of the various outcomes so difficult to assess, that the usefulness of a single estimate of fair value is negated. This may indicate that the fair value of the property will not be reliably determinable on a continuing basis (see paragraph 53).
- 49 Fair value differs from value in use, as defined in Ind AS 36 *Impairment of Assets*. Fair value reflects the knowledge and estimates of knowledgeable, willing buyers and sellers. In contrast, value in use reflects the entity's estimates, including the effects of factors that may be specific to the entity and not applicable to entities in general. For example, fair value does not reflect any of the following factors to the extent that they would not be generally available to knowledgeable, willing buyers and sellers:

- (a) additional value derived from the creation of a portfolio of properties in different locations;
- (b) synergies between investment property and other assets;
- (c) legal rights or legal restrictions that are specific only to the current owner; and
- (d) tax benefits or tax burdens that are specific to the current owner.

50 [Refer to Appendix 1]

51 The fair value of investment property does not reflect future capital expenditure that will improve or enhance the property and does not reflect the related future benefits from this future expenditure.

52 [Refer to Appendix 1]

Inability to determine fair value reliably

53 There is a rebuttable presumption that an entity can reliably determine the fair value of an investment property on a continuing basis. However, in exceptional cases, there is clear evidence when an entity first acquires an investment property (or when an existing property first becomes investment property after a change in use) that the fair value of the investment property is not reliably determinable on a continuing basis. This arises when, and only when, comparable market transactions are infrequent and alternative reliable estimates of fair value (for example, based on discounted cash flow projections) are not available. If an entity determines that the fair value of an investment property under construction is not reliably determinable but expects the fair value of the property to be reliably determinable when construction is complete, it shall determine the fair value of that investment property either when its fair value becomes reliably determinable or construction is completed (whichever is earlier). If an entity determines that the fair value of an investment property (other than an investment property under construction) is not reliably determinable on a continuing basis, the entity shall make the disclosures required by paragraphs 79(e)(i), (ii) and (iii).

53A Once an entity becomes able to measure reliably the fair value of an investment property under construction for which the fair value was not previously determined, it shall determine the fair value of that property. Once construction of that property is complete, it is presumed that fair value can be measured reliably. If this is not the case, in accordance with paragraph 53, the entity shall make the disclosures required by paragraphs 79(e)(i), (ii) and (iii).

53B The presumption that the fair value of investment property under construction can be measured reliably can be rebutted only on initial recognition. An entity that has determined the fair value of an item of investment property under construction may not conclude that the fair value of the completed investment property cannot be determined reliably.

- 54 In the exceptional cases when an entity is compelled, for the reason given in paragraph 53, to make the disclosures required by paragraphs 79(e)(i), (ii) and (iii), it shall determine the fair value of all its other investment property, including investment property under construction. In these cases, although an entity may make the disclosures required by paragraphs 79(e)(i), (ii) and (iii) for one investment property, the entity shall continue to determine the fair value of each of the remaining properties for disclosure required by paragraph 79(e).
- 55 If an entity has previously determined the fair value of an investment property, it shall continue to determine the fair value of that property until disposal (or until the property becomes owner-occupied property or the entity begins to develop the property for subsequent sale in the ordinary course of business) even if comparable market transactions become less frequent or market prices become less readily available.

Cost model

- 56 After initial recognition, an entity shall measure all of its investment properties in accordance with Ind AS 16's requirements for cost model, other than those that meet the criteria to be classified as held for sale (or are included in a disposal group that is classified as held for sale) in accordance with Ind AS 105 *Non-current Assets Held for Sale and Discontinued Operations*. Investment properties that meet the criteria to be classified as held for sale (or are included in a disposal group that is classified as held for sale) shall be measured in accordance with Ind AS 105.

Transfers

- 57 Transfers to, or from, investment property shall be made when, and only when, there is a change in use, evidenced by:
- (a) commencement of owner-occupation, for a transfer from investment property to owner-occupied property;
 - (b) commencement of development with a view to sale, for a transfer from investment property to inventories;
 - (c) end of owner-occupation, for a transfer from owner-occupied property to investment property; or
 - (d) commencement of an operating lease to another party, for a transfer from inventories to investment property.
 - (e) [Refer to Appendix 1]
- 58 Paragraph 57(b) requires an entity to transfer a property from investment property to inventories when, and only when, there is a change in use, evidenced by commencement of development with a view to sale. When an entity decides to dispose of an investment property without development, it continues to treat the property as an investment property until it is derecognised (eliminated from the balance sheet) and does not treat it as inventory. Similarly, if an entity begins to

redevelop an existing investment property for continued future use as investment property, the property remains an investment property and is not reclassified as owner-occupied property during the redevelopment.

59 Transfers between investment property, owner-occupied property and inventories do not change the carrying amount of the property transferred and they do not change the cost of that property for measurement or disclosure purposes.

60-65 [Refer to Appendix 1]

Disposals

66 **An investment property shall be derecognised (eliminated from the balance sheet) on disposal or when the investment property is permanently withdrawn from use and no future economic benefits are expected from its disposal.**

67 The disposal of an investment property may be achieved by sale or by entering into a finance lease. In determining the date of disposal for investment property, an entity applies the criteria in Ind AS 18 for recognising revenue from the sale of goods and considers the related guidance in the Appendix E to Ind AS 18. Ind AS 17 applies to a disposal effected by entering into a finance lease and to a sale and leaseback.

68 If, in accordance with the recognition principle in paragraph 16, an entity recognises in the carrying amount of an asset the cost of a replacement for part of an investment property, it derecognises the carrying amount of the replaced part. A replaced part may not be a part that was depreciated separately. If it is not practicable for an entity to determine the carrying amount of the replaced part, it may use the cost of the replacement as an indication of what the cost of the replaced part was at the time it was acquired or constructed.

69 **Gains or losses arising from the retirement or disposal of investment property shall be determined as the difference between the net disposal proceeds and the carrying amount of the asset and shall be recognised in profit or loss (unless Ind AS 17 requires otherwise on a sale and leaseback) in the period of the retirement or disposal.**

70 The consideration receivable on disposal of an investment property is recognised initially at fair value. In particular, if payment for an investment property is deferred, the consideration received is recognised initially at the cash price equivalent. The difference between the nominal amount of the consideration and the cash price equivalent is recognised as interest revenue in accordance with Ind AS 18 using the effective interest method.

71 An entity applies Ind AS 37 or other Standards, as appropriate, to any liabilities that it retains after disposal of an investment property.

- 72 Compensation from third parties for investment property that was impaired, lost or given up shall be recognised in profit or loss when the compensation becomes receivable.**
- 73** Impairments or losses of investment property, related claims for or payments of compensation from third parties and any subsequent purchase or construction of replacement assets are separate economic events and are accounted for separately as follows:
- (a) impairments of investment property are recognised in accordance with Ind AS 36;
 - (b) retirements or disposals of investment property are recognised in accordance with paragraphs 66–71 of this Standard;
 - (c) compensation from third parties for investment property that was impaired, lost or given up is recognised in profit or loss when it becomes receivable; and
 - (d) the cost of assets restored, purchased or constructed as replacements is determined in accordance with paragraphs 20–29 of this Standard.

Disclosure

- 74** The disclosures below apply in addition to those in Ind AS 17. In accordance with Ind AS 17, the owner of an investment property provides lessors' disclosures about leases into which it has entered. An entity that holds an investment property under a finance lease provides lessees' disclosures for finance leases and lessors' disclosures for any operating leases into which it has entered.
- 75** An entity shall disclose:
- (a) its accounting policy for measurement of investment property.
 - (b) [Refer to Appendix 1]
 - (c) when classification is difficult (see paragraph 14), the criteria it uses to distinguish investment property from owner-occupied property and from property held for sale in the ordinary course of business.
 - (d) the methods and significant assumptions applied in determining the fair value of investment property, including a statement whether the determination of fair value was supported by market evidence or was more heavily based on other factors (which the entity shall disclose) because of the nature of the property and lack of comparable market data.

- (e) the extent to which the fair value of investment property (as measured or disclosed in the financial statements) is based on a valuation by an independent valuer who holds a recognised and relevant professional qualification and has recent experience in the location and category of the investment property being valued. If there has been no such valuation, that fact shall be disclosed.
- (f) the amounts recognised in profit or loss for:
 - (i) rental income from investment property;
 - (ii) direct operating expenses (including repairs and maintenance) arising from investment property that generated rental income during the period; and
 - (iii) direct operating expenses (including repairs and maintenance) arising from investment property that did not generate rental income during the period.
 - (iv) [Refer to Appendix 1]
- (g) the existence and amounts of restrictions on the realisability of investment property or the remittance of income and proceeds of disposal.
- (h) contractual obligations to purchase, construct or develop investment property or for repairs, maintenance or enhancements.

76-78 [Refer to Appendix 1]

79 In addition to the disclosures required by paragraph 75, an entity shall disclose:

- (a) the depreciation methods used;
- (b) the useful lives or the depreciation rates used;
- (c) the gross carrying amount and the accumulated depreciation (aggregated with accumulated impairment losses) at the beginning and end of the period;
- (d) a reconciliation of the carrying amount of investment property at the beginning and end of the period, showing the following:
 - (i) additions, disclosing separately those additions resulting from acquisitions and those resulting from subsequent expenditure recognised as an asset;
 - (ii) additions resulting from acquisitions through business combinations;

- (iii) assets classified as held for sale or included in a disposal group classified as held for sale in accordance with Ind AS 105 and other disposals;
 - (iv) depreciation;
 - (v) the amount of impairment losses recognised, and the amount of impairment losses reversed, during the period in accordance with Ind AS 36;
 - (vi) the net exchange differences arising on the translation of the financial statements into a different presentation currency, and on translation of a foreign operation into the presentation currency of the reporting entity;
 - (vii) transfers to and from inventories and owner-occupied property; and
 - (viii) other changes; and
- (e) the fair value of investment property. In the exceptional cases described in paragraph 53, when an entity cannot determine the fair value of the investment property reliably, it shall disclose:
- (i) a description of the investment property;
 - (ii) an explanation of why fair value cannot be determined reliably; and
 - (iii) if possible, the range of estimates within which fair value is highly likely to lie.

Appendix A

References to matters contained in other Indian Accounting Standards

This Appendix is an integral part of Indian Accounting Standard (Ind AS) 40 Investment Property.

1. Appendix A *Income Taxes-Recovery of Revalued Non-Depreciable Assets* contained in Ind AS 12, *Income Taxes* makes reference to this Standard also.

Appendix 1

Note: This Appendix is not a part of the Indian Accounting Standard. The purpose of this Appendix is only to bring out the differences, if any, between Indian Accounting Standard (Ind AS) 40 and the corresponding International Accounting Standard (IAS) 40, Investment Property.

Comparison with IAS 40, *Investment Property*

- 1 IAS 40 permits both cost model and fair value model (except in some situations) for measurement of investment properties after initial recognition. Ind AS 40 permits only the cost model. The following paragraphs of IAS 40 which deal with fair value model have been deleted in Ind AS 40. In order to maintain consistency with paragraph numbers of IAS 40, the paragraph numbers are retained in Ind AS 40:
 - (i) Paragraph 6
 - (ii) Paragraph 31
 - (iii) Paragraphs 32A-32C
 - (iv) Paragraphs 33-35
 - (v) Paragraph 41
 - (vi) Paragraph 50
 - (vii) Paragraph 52
 - (viii) Paragraphs 60-65
 - (ix) Paragraph 75(b)
 - (x) Paragraph 75(f)(iv)
 - (xi) Paragraphs 76-78
- 2 The transitional provisions given in IAS 40 have not been included in Ind AS 40 since all transitional provisions related to Ind ASs, wherever considered appropriate have been included in Ind AS 101, First-time Adoption of Indian Accounting Standards corresponding to IFRS 1, First-time Adoption of International Financial Reporting Standards.
- 3 IAS 40 requires disclosure of fair values of investment property when cost model is used. Since this requirement is retained in Ind AS 40, paragraphs 53, 53A, 53B, 54 and 55 and certain other paragraphs of IAS 40 have been modified. The modifications include substitution of fair value measurement with fair value determination/disclosure and deletion of reference to use of cost model when fair value determination is unreliable.

- 4 IAS 40 permits treatment of property interest held in an operating lease as investment property, if the definition of investment property is otherwise met and fair value model is applied. In such cases, the operating lease would be accounted as if it were a finance lease. Since Ind AS 40 prohibits the use of fair value model, this treatment is prohibited in Ind AS 40. As a result, paragraph 6 of IAS 40 has been deleted in Ind AS 40 (see point 1(i) above). In addition, the expression 'investment property under a finance or operating lease' appearing in paragraph 74 of IAS 40 has been modified as 'investment property under a finance lease' in Ind AS 40.
- 5 As a result of prohibition of use of fair value model in Ind AS 40, there are some modifications in the wording of paragraph 26 (removal of the words 'for the fair value model'), paragraphs 30 and 32 (Accounting policy), heading above paragraph 33 ('Fair value determination' instead of 'Fair value model'), paragraph 56, paragraph 59 (deletion of portion relating to fair value model), paragraph 68 (deletion of a portion dealing with fair value model), heading above paragraph 74 (deletion of the heading 'Fair value model and cost model') and 75(a) (disclosure of accounting policy) as compared to the wording used in IAS 40.
- 6 Different terminology is used in this Standard e.g., the term 'balance sheet' is used instead of 'Statement of financial position'.
- 7 The following paragraphs appear as 'Deleted' in IAS 40. In order to maintain consistency with paragraph numbers of IAS 40, the paragraph numbers are retained in Ind AS 40:
 - (i) Paragraph 9(d)
 - (ii) Paragraph 22
 - (iii) Paragraph 57(e)

Indian Accounting Standard (Ind AS) 108

Operating Segments

*(This Indian Accounting Standard includes paragraphs set in **bold** type and plain type, which have equal authority. Paragraphs in bold type indicate the main principles.)*

Core principle

- 1 **An entity shall disclose information to enable users of its financial statements to evaluate the nature and financial effects of the business activities in which it engages and the economic environments in which it operates.**

Scope

- 2 This Accounting Standard shall apply to companies to which Accounting Standards notified under Part I of the Companies (Accounting Standards) Rules _____ - apply.
- 3 If an entity that is not required to apply this Indian Accounting Standard chooses to disclose information about segments that does not comply with this Indian Accounting Standard, it shall not describe the information as segment information.

- 4 If a financial report contains both the consolidated financial statements of a parent that is within the scope of this Indian Accounting Standard as well as the parent's separate financial statements, segment information is required only in the consolidated financial statements.

Operating segments

- 5 An operating segment is a component of an entity:
- (a) that engages in business activities from which it may earn revenues and incur expenses (including revenues and expenses relating to transactions with other components of the same entity),
 - (b) whose operating results are regularly reviewed by the entity's chief operating decision maker to make decisions about resources to be allocated to the segment and assess its performance, and
 - (c) for which discrete financial information is available.

An operating segment may engage in business activities for which it has yet to earn revenues, for example, start-up operations may be operating segments before earning revenues.

- 6 Not every part of an entity is necessarily an operating segment or part of an operating segment. For example, a corporate headquarters or some functional departments may not earn revenues or may earn revenues that are only incidental to the activities of the entity and would not be operating segments. For the purposes of this Indian Accounting Standard, an entity's post-employment benefit plans are not operating segments.
- 7 The term 'chief operating decision maker' identifies a function, not necessarily a manager with a specific title. That function is to allocate resources to and assess the performance of the operating segments of an entity. Often the chief operating decision maker of an entity is its chief executive officer or chief operating officer but, for example, it may be a group of executive directors or others.
- 8 For many entities, the three characteristics of operating segments described in paragraph 5 clearly identify its operating segments. However, an entity may produce reports in which its business activities are presented in a variety of ways. If the chief operating decision maker uses more than one set of segment information, other factors may identify a single set of components as constituting an entity's operating segments, including the nature of the business activities of each component, the existence of managers responsible for them, and information presented to the board of directors.
- 9 Generally, an operating segment has a segment manager who is directly accountable to and maintains regular contact with the chief operating decision maker to discuss operating activities, financial results, forecasts, or plans for the segment. The term 'segment manager' identifies a function, not necessarily a manager with a specific title. The chief operating decision maker also may be the segment manager for some operating segments. A single manager may be the segment manager for more than one operating segment. If the characteristics in paragraph 5 apply to more than one set of components of an organisation but there is only one set for which segment managers are held responsible, that set of components constitutes the operating segments.

- 10 The characteristics in paragraph 5 may apply to two or more overlapping sets of components for which managers are held responsible. That structure is sometimes referred to as a matrix form of organisation. For example, in some entities, some managers are responsible for different product and service lines worldwide, whereas other managers are responsible for specific geographical areas. The chief operating decision maker regularly reviews the operating results of both sets of components, and financial information is available for both. In that situation, the entity shall determine which set of components constitutes the operating segments by reference to the core principle.

Reportable segments

- 11 An entity shall report separately information about each operating segment that:
- (a) has been identified in accordance with paragraphs 5–10 or results from aggregating two or more of those segments in accordance with paragraph 12, and
 - (b) exceeds the quantitative thresholds in paragraph 13.

Paragraphs 14–19 specify other situations in which separate information about an operating segment shall be reported.

Aggregation criteria

- 12 Operating segments often exhibit similar long-term financial performance if they have similar economic characteristics. For example, similar long-term average gross margins for two operating segments would be expected if their economic characteristics were similar. Two or more operating segments may be aggregated into a single operating segment if aggregation is consistent with the core principle of this Indian Accounting Standard, the segments have similar economic characteristics, and the segments are similar in each of the following respects:
- (a) the nature of the products and services;
 - (b) the nature of the production processes;
 - (c) the type or class of customer for their products and services;
 - (d) the methods used to distribute their products or provide their services; and
 - (e) if applicable, the nature of the regulatory environment, for example, banking, insurance or public utilities.

Quantitative thresholds

- 13 An entity shall report separately information about an operating segment that meets any of the following quantitative thresholds:
- (a) Its reported revenue, including both sales to external customers and intersegment sales or transfers, is 10 per cent or more of the combined revenue, internal and external, of all operating segments.
 - (b) The absolute amount of its reported profit or loss is 10 per cent or more of the greater, in absolute amount, of (i) the combined reported profit of all

operating segments that did not report a loss and (ii) the combined reported loss of all operating segments that reported a loss.

- (c) Its assets are 10 per cent or more of the combined assets of all operating segments.

Operating segments that do not meet any of the quantitative thresholds may be considered reportable, and separately disclosed, if management believes that information about the segment would be useful to users of the financial statements.

- 14 An entity may combine information about operating segments that do not meet the quantitative thresholds with information about other operating segments that do not meet the quantitative thresholds to produce a reportable segment only if the operating segments have similar economic characteristics and share a majority of the aggregation criteria listed in paragraph 12.
- 15 If the total external revenue reported by operating segments constitutes less than 75 per cent of the entity's revenue, additional operating segments shall be identified as reportable segments (even if they do not meet the criteria in paragraph 13) until at least 75 per cent of the entity's revenue is included in reportable segments.
- 16 Information about other business activities and operating segments that are not reportable shall be combined and disclosed in an 'all other segments' category separately from other reconciling items in the reconciliations required by paragraph 28. The sources of the revenue included in the 'all other segments' category shall be described.
- 17 If management judges that an operating segment identified as a reportable segment in the immediately preceding period is of continuing significance, information about that segment shall continue to be reported separately in the current period even if it no longer meets the criteria for reportability in paragraph 13.
- 18 If an operating segment is identified as a reportable segment in the current period in accordance with the quantitative thresholds, segment data for a prior period presented for comparative purposes shall be restated to reflect the newly reportable segment as a separate segment, even if that segment did not satisfy the criteria for reportability in paragraph 13 in the prior period, unless the necessary information is not available and the cost to develop it would be excessive.
- 19 There may be a practical limit to the number of reportable segments that an entity separately discloses beyond which segment information may become too detailed. Although no precise limit has been determined, as the number of segments that are reportable in accordance with paragraphs 13–18 increases above ten, the entity should consider whether a practical limit has been reached.

Disclosure

- 20 An entity shall disclose information to enable users of its financial statements to evaluate the nature and financial effects of the business activities in which it engages and the economic environments in which it operates.

21 To give effect to the principle in paragraph 20, an entity shall disclose the following for each period for which a statement of profit and loss is presented:

- (a) general information as described in paragraph 22;
- (b) information about reported segment profit or loss, including specified revenues and expenses included in reported segment profit or loss, segment assets, segment liabilities and the basis of measurement, as described in paragraphs 23–27; and
- (c) reconciliations of the totals of segment revenues, reported segment profit or loss, segment assets, segment liabilities and other material segment items to corresponding entity amounts as described in paragraph 28.

Reconciliations of the amounts in the balance sheet for reportable segments to the amounts in the entity's balance sheet are required for each date at which a balance sheet is presented. Information for prior periods shall be restated as described in paragraphs 29 and 30.

General information

22 An entity shall disclose the following general information:

- (a) factors used to identify the entity's reportable segments, including the basis of organisation (for example, whether management has chosen to organise the entity around differences in products and services, geographical areas, regulatory environments, or a combination of factors and whether operating segments have been aggregated), and
- (b) types of products and services from which each reportable segment derives its revenues.

Information about profit or loss, assets and liabilities

23 An entity shall report a measure of profit or loss for each reportable segment. An entity shall report a measure of total assets and liabilities for each reportable segment if such amounts are regularly provided to the chief operating decision maker. An entity shall also disclose the following about each reportable segment if the specified amounts are included in the measure of segment profit or loss reviewed by the chief operating decision maker, or are otherwise regularly provided to the chief operating decision maker, even if not included in that measure of segment profit or loss:

- (a) revenues from external customers;
- (b) revenues from transactions with other operating segments of the same entity;
- (c) interest revenue;
- (d) interest expense;

- (e) depreciation and amortisation;
- (f) material items of income and expense disclosed in accordance with paragraph 97 of Ind AS 1 *Presentation of Financial Statements*;
- (g) the entity's interest in the profit or loss of associates and joint ventures accounted for by the equity method;
- (h) income tax expense or income; and
- (i) material non-cash items other than depreciation and amortisation.

An entity shall report interest revenue separately from interest expense for each reportable segment unless a majority of the segment's revenues are from interest and the chief operating decision maker relies primarily on net interest revenue to assess the performance of the segment and make decisions about resources to be allocated to the segment. In that situation, an entity may report that segment's interest revenue net of its interest expense and disclose that it has done so.

- 24 An entity shall disclose the following about each reportable segment if the specified amounts are included in the measure of segment assets reviewed by the chief operating decision maker or are otherwise regularly provided to the chief operating decision maker, even if not included in the measure of segment assets:
- (a) the amount of investment in associates and joint ventures accounted for by the equity method, and
 - (b) the amounts of additions to non-current assets¹ other than financial instruments, deferred tax assets, post-employment benefit assets (see Ind AS 19 *Employee Benefits* paragraphs 54–58) and rights arising under insurance contracts.

Measurement

- 25 The amount of each segment item reported shall be the measure reported to the chief operating decision maker for the purposes of making decisions about allocating resources to the segment and assessing its performance. Adjustments and eliminations made in preparing an entity's financial statements and allocations of revenues, expenses, and gains or losses shall be included in determining reported segment profit or loss only if they are included in the measure of the segment's profit or loss that is used by the chief operating decision maker. Similarly, only those assets and liabilities that are included in the measures of the segment's assets and segment's liabilities that are used by the chief operating decision maker shall be reported for that segment. If amounts are

¹ For assets classified according to a liquidity presentation, non-current assets are assets that include amounts expected to be recovered more than twelve months after the reporting period.

allocated to reported segment profit or loss, assets or liabilities, those amounts shall be allocated on a reasonable basis.

- 26 If the chief operating decision maker uses only one measure of an operating segment's profit or loss, the segment's assets or the segment's liabilities in assessing segment performance and deciding how to allocate resources, segment profit or loss, assets and liabilities shall be reported at those measures. If the chief operating decision maker uses more than one measure of an operating segment's profit or loss, the segment's assets or the segment's liabilities, the reported measures shall be those that management believes are determined in accordance with the measurement principles most consistent with those used in measuring the corresponding amounts in the entity's financial statements.
- 27 An entity shall provide an explanation of the measurements of segment profit or loss, segment assets and segment liabilities for each reportable segment. At a minimum, an entity shall disclose the following:
- (a) the basis of accounting for any transactions between reportable segments.
 - (b) the nature of any differences between the measurements of the reportable segments' profits or losses and the entity's profit or loss before income tax expense or income and discontinued operations (if not apparent from the reconciliations described in paragraph 28). Those differences could include accounting policies and policies for allocation of centrally incurred costs that are necessary for an understanding of the reported segment information.
 - (c) the nature of any differences between the measurements of the reportable segments' assets and the entity's assets (if not apparent from the reconciliations described in paragraph 28). Those differences could include accounting policies and policies for allocation of jointly used assets that are necessary for an understanding of the reported segment information.
 - (d) the nature of any differences between the measurements of the reportable segments' liabilities and the entity's liabilities (if not apparent from the reconciliations described in paragraph 28). Those differences could include accounting policies and policies for allocation of jointly utilised liabilities that are necessary for an understanding of the reported segment information.
 - (e) the nature of any changes from prior periods in the measurement methods used to determine reported segment profit or loss and the effect, if any, of those changes on the measure of segment profit or loss.
 - (f) the nature and effect of any asymmetrical allocations to reportable segments. For example, an entity might allocate depreciation expense to a segment without allocating the related depreciable assets to that segment.

Reconciliations

- 28 An entity shall provide reconciliations of all of the following:

- (a) the total of the reportable segments' revenues to the entity's revenue.
- (b) the total of the reportable segments' measures of profit or loss to the entity's profit or loss before tax expense (tax income) and discontinued operations. However, if an entity allocates to reportable segments items such as tax expense (tax income), the entity may reconcile the total of the segments' measures of profit or loss to the entity's profit or loss after those items.
- (c) the total of the reportable segments' assets to the entity's assets.
- (d) the total of the reportable segments' liabilities to the entity's liabilities if segment liabilities are reported in accordance with paragraph 23.
- (e) the total of the reportable segments' amounts for every other material item of information disclosed to the corresponding amount for the entity.

All material reconciling items shall be separately identified and described. For example, the amount of each material adjustment needed to reconcile reportable segment profit or loss to the entity's profit or loss arising from different accounting policies shall be separately identified and described.

Restatement of previously reported information

- 29 If an entity changes the structure of its internal organisation in a manner that causes the composition of its reportable segments to change, the corresponding information for earlier periods, including interim periods, shall be restated unless the information is not available and the cost to develop it would be excessive. The determination of whether the information is not available and the cost to develop it would be excessive shall be made for each individual item of disclosure. Following a change in the composition of its reportable segments, an entity shall disclose whether it has restated the corresponding items of segment information for earlier periods.
- 30 If an entity has changed the structure of its internal organisation in a manner that causes the composition of its reportable segments to change and if segment information for earlier periods, including interim periods, is not restated to reflect the change, the entity shall disclose in the year in which the change occurs segment information for the current period on both the old basis and the new basis of segmentation, unless the necessary information is not available and the cost to develop it would be excessive.

Entity-wide disclosures

- 31 Paragraphs 32–34 apply to all entities subject to this Indian Accounting Standard including those entities that have a single reportable segment.

Some entities' business activities are not organised on the basis of differences in related products and services or differences in geographical areas of operations. Such an entity's reportable segments may report revenues from a broad range of

essentially different products and services, or more than one of its reportable segments may provide essentially the same products and services. Similarly, an entity's reportable segments may hold assets in different geographical areas and report revenues from customers in different geographical areas, or more than one of its reportable segments may operate in the same geographical area. Information required by paragraphs 32–34 shall be provided only if it is not provided as part of the reportable segment information required by this Indian Accounting Standard.

Information about products and services

- 32 An entity shall report the revenues from external customers for each product and service, or each group of similar products and services, unless the necessary information is not available and the cost to develop it would be excessive, in which case that fact shall be disclosed. The amounts of revenues reported shall be based on the financial information used to produce the entity's financial statements.

Information about geographical areas

- 33 An entity shall report the following geographical information, unless the necessary information is not available and the cost to develop it would be excessive:
- (a) revenues from external customers (i) attributed to the entity's country of domicile and (ii) attributed to all foreign countries in total from which the entity derives revenues. If revenues from external customers attributed to an individual foreign country are material, those revenues shall be disclosed separately. An entity shall disclose the basis for attributing revenues from external customers to individual countries.
 - (b) non-current assets² other than financial instruments, deferred tax assets, post-employment benefit assets, and rights arising under insurance contracts (i) located in the entity's country of domicile and (ii) located in all foreign countries in total in which the entity holds assets. If assets in an individual foreign country are material, those assets shall be disclosed separately.

The amounts reported shall be based on the financial information that is used to produce the entity's financial statements. If the necessary information is not available and the cost to develop it would be excessive, that fact shall be disclosed. An entity may provide, in addition to the information required by this paragraph, subtotals of geographical information about groups of countries.

Information about major customers

² For assets classified according to a liquidity presentation, non-current assets are assets that include amounts expected to be recovered more than twelve months after the reporting period.

- 34 An entity shall provide information about the extent of its reliance on its major customers. If revenues from transactions with a single external customer amount to 10 per cent or more of an entity's revenues, the entity shall disclose that fact, the total amount of revenues from each such customer, and the identity of the segment or segments reporting the revenues. The entity need not disclose the identity of a major customer or the amount of revenues that each segment reports from that customer. For the purposes of this Indian Accounting Standard, a group of entities known to a reporting entity to be under common control shall be considered a single customer. However, judgement is required to assess whether a government (including government agencies and similar bodies whether local, national or international) and entities known to the reporting entity to be under the control of that government are considered a single customer. In assessing this, the reporting entity shall consider the extent of economic integration between those entities.

Appendix A

Defined term

operating segment

An operating segment is a component of an entity:

- (a) that engages in business activities from which it may earn revenues and incur expenses (including revenues and expenses relating to transactions with other components of the same entity),
- (b) whose operating results are regularly reviewed by the entity's chief operating decision maker to make decisions about resources to be allocated to the segment and assess its performance, and
- (c) for which discrete financial information is available.

Appendix B

Contents

Guidance on implementing Ind AS 108 Operating Segments

Introduction	IG1
Descriptive information about an entity's reportable segments	IG2
Description of the types of products and services from which each reportable segment derives its revenues (paragraph 22(b))	
Measurement of operating segment profit or loss, assets and liabilities (paragraph 27)	

Factors that management used to identify the entity's reportable segments (paragraph 22(a))

Information about reportable segment profit or loss, assets and liabilities IG3

Reconciliations of reportable segment revenues, profit or loss, assets and liabilities IG4

Geographical information IG5

Information about major customers IG6

Diagram to assist in identifying reportable segments IG7

Guidance on implementing Ind AS 108 Operating Segments

This guidance accompanies, but is not part of, Ind AS 108.

Introduction

IG1 This implementation guidance provides examples that illustrate the disclosures required by Ind AS 108 and a diagram to assist in identifying reportable segments. The formats in the illustrations are not requirements. A format that provides the information in the most understandable manner in the specific circumstances is encouraged. The following illustrations are for a single hypothetical entity referred to as Diversified Company.

Descriptive information about an entity's reportable segments

IG2 The following illustrates the disclosure of descriptive information about an entity's reportable segments (the paragraph references are to the relevant requirements in the Indian Accounting Standard).

Description of the types of products and services from which each reportable segment derives its revenues (paragraph 22(b))

Diversified Company has five reportable segments: car parts, motor vessels, software, electronics and finance. The car parts segment produces replacement parts for sale to car parts retailers. The motor vessels segment produces small motor vessels to serve the offshore oil industry and similar businesses. The software segment produces application software for sale to computer manufacturers and retailers. The electronics segment produces integrated circuits and related products for sale to computer manufacturers. The finance segment is responsible for portions of the company's financial operations including financing customer purchases of products from other segments and property lending operations.

Measurement of operating segment profit or loss, assets and liabilities (paragraph 27)

The accounting policies of the operating segments are the same as those described in the summary of significant accounting policies except that pension expense for each operating segment is recognised and measured on the basis of cash payments to the pension plan. Diversified Company evaluates performance on the basis of profit or loss from operations before tax expense not including non-recurring gains and losses and foreign exchange gains and losses.

Diversified Company accounts for intersegment sales and transfers as if the sales or transfers were to third parties, ie at current market prices.

Factors that management used to identify the entity's reportable segments (paragraph 22(a))

Diversified Company's reportable segments are strategic business units that offer different products and services. They are managed separately because each business requires different technology and marketing strategies. Most of the businesses were acquired as individual units, and the management at the time of the acquisition was retained.

Information about reportable segment profit or loss, assets and liabilities

IG3 The following table illustrates a suggested format for disclosing information about reportable segment profit or loss, assets and liabilities (paragraphs 23 and 24). The same type of information is required for each year for which a statement of profit and loss is presented. Diversified Company does not allocate tax expense (tax income) or non-recurring gains and losses to reportable segments. In addition, not all reportable segments have material non-cash items other than depreciation and amortisation in profit or loss. The amounts in this illustration are assumed to be the amounts in reports used by the chief operating decision maker.

	Car parts Rs.	Motor vessels Rs.	Software Rs.	Electronics Rs.	Finance Rs.	All other Rs.	Totals Rs.
Revenues from external customers	3,000	5,000	9,500	12,000	5,000	1,000 ^(a)	35,500
Intersegment revenues	—	1	3,000	1,500	—	—	4,500
Interest revenue	450	800	1,000	1,500	—	—	3,750
Interest expense	350	600	700	1,100	—	—	2,750

Net interest revenue ^(b)	—	—	—	—	1,000	—	1,000
Depreciation and amortization	200	100	50	1,500	1,100	—	2,950
Reportable segment profit	200	70	900	2,300	500	100	4,070
Other material non-cash items:							
Impairment of assets	—	200	—	—	—	—	200
Reportable segment assets	2,000	5,000	3,000	12,000	57,000	2,000	81,000
Expenditures for reportable segment non-current assets	300	700	500	800	600	—	2,900
Reportable segment liabilities	1,050	3,000	1,800	8,000	30,000	—	43,850

(a) Revenues from segments below the quantitative thresholds are attributable to four operating segments of Diversified Company. Those segments include a small property business, an electronics equipment rental business, a software consulting practice and a warehouse leasing operation. None of those segments has ever met any of the quantitative thresholds for determining reportable segments.

(b) The finance segment derives a majority of its revenue from interest. Management primarily relies on net interest revenue, not the gross revenue and expense amounts, in managing that segment. Therefore, as permitted by paragraph 23, only the net amount is disclosed.

Reconciliations of reportable segment revenues, profit or loss, assets and liabilities

IG4 The following illustrate reconciliations of reportable segment revenues, profit or loss, assets and liabilities to the entity's corresponding amounts (paragraph 28(a)–(d)). Reconciliations also are required to be shown for every other material item of information disclosed (paragraph 28(e)). The entity's financial statements are assumed not to include discontinued operations. As discussed in paragraph IG2, the entity recognises and measures pension expense of its reportable

segments on the basis of cash payments to the pension plan, and it does not allocate certain items to its reportable segments.

Revenues	Rs.
Total revenues for reportable segments	39,000
Other revenues	1,000
Elimination of intersegment revenues	(4,500)
Entity's revenues	35,500

Profit or loss	Rs.
Total profit or loss for reportable segments	3,970
Other profit or loss	100
Elimination of intersegment profits	(500)
Unallocated amounts:	
Litigation settlement received	500
Other corporate expenses	(750)
Adjustment to pension expense in consolidation	(250)
Income before income tax expense	3,070

Assets	Rs.
Total assets for reportable segments	79,000
Other assets	2,000
Elimination of receivable from corporate headquarters	(1,000)
Other unallocated amounts	1,500
Entity's assets	81,500

Liabilities	Rs.
Total liabilities for reportable segments	43,850
Unallocated defined benefit pension liabilities	25,000
Entity's liabilities	68,850

Other material items	Reportable segment totals Rs.	Adjustments Rs.	Entity totals Rs.
Interest revenue	3,750	75	3,825
Interest expense	2,750	(50)	2,700
Net interest revenue	1,000	—	1,000

(finance segment only)			
Expenditures for assets	2,900	1,000	3,900
Depreciation and amortization	2,950	—	2,950
Impairment of assets	200	—	200

The reconciling item to adjust expenditures for assets is the amount incurred for the corporate headquarters building, which is not included in segment information. None of the other adjustments are material.

Geographical information

- IG5 The following illustrates the geographical information required by paragraph 33. (Because Diversified Company's reportable segments are based on differences in products and services, no additional disclosures of revenue information about products and services are required (paragraph 32).)

Geographical information	Revenues ^(a)	Non-current assets
	Rs.	Rs.
United States	19,000	11,000
Canada	4,200	—
China	3,400	6,500
Japan	2,900	3,500
Other countries	6,000	3,000
Total	35,500	24,000

(a) Revenues are attributed to countries on the basis of the customer's location.

Information about major customers

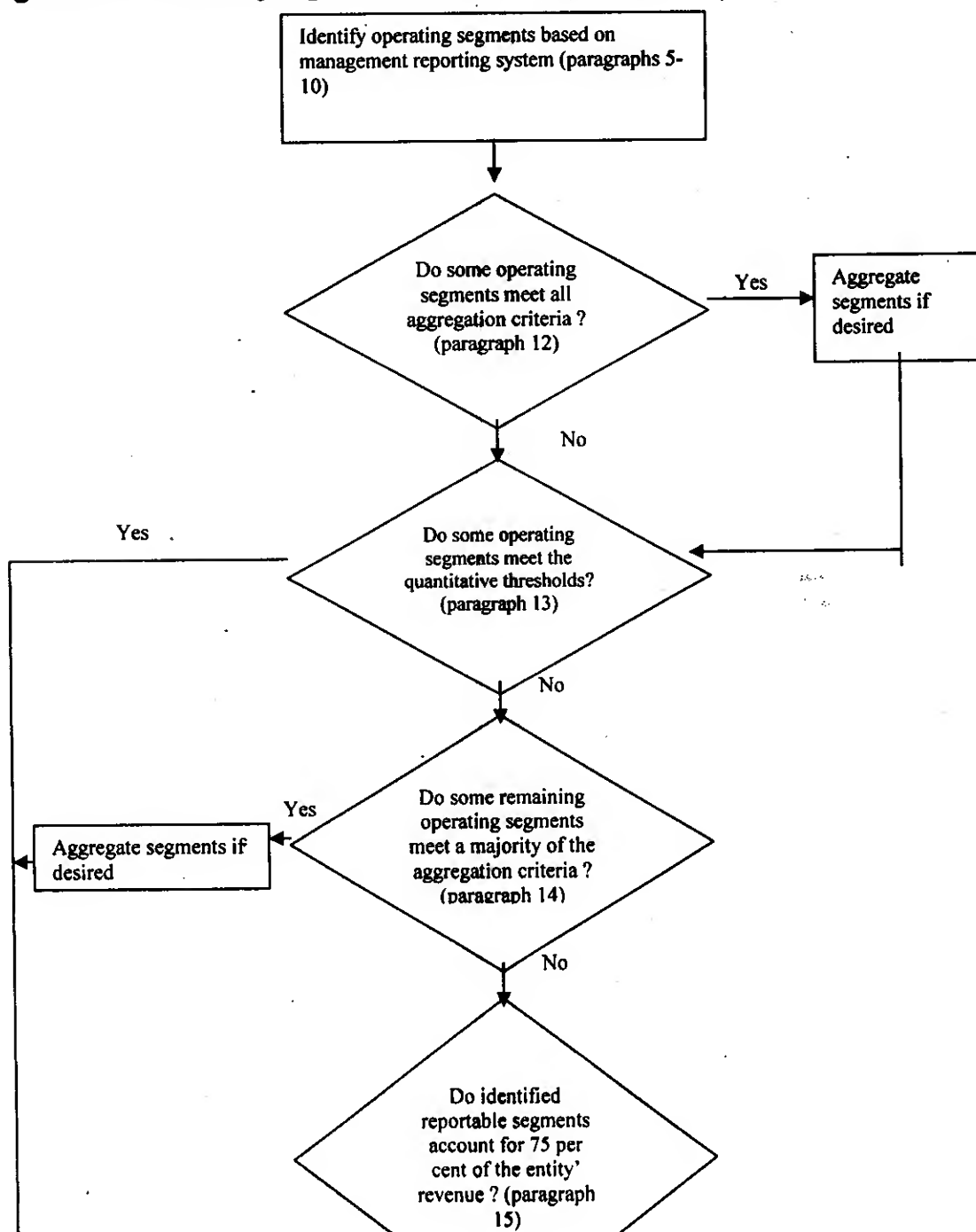
- IG6 The following illustrates the information about major customers required by paragraph 34. Neither the identity of the customer nor the amount of revenues for each operating segment is required.

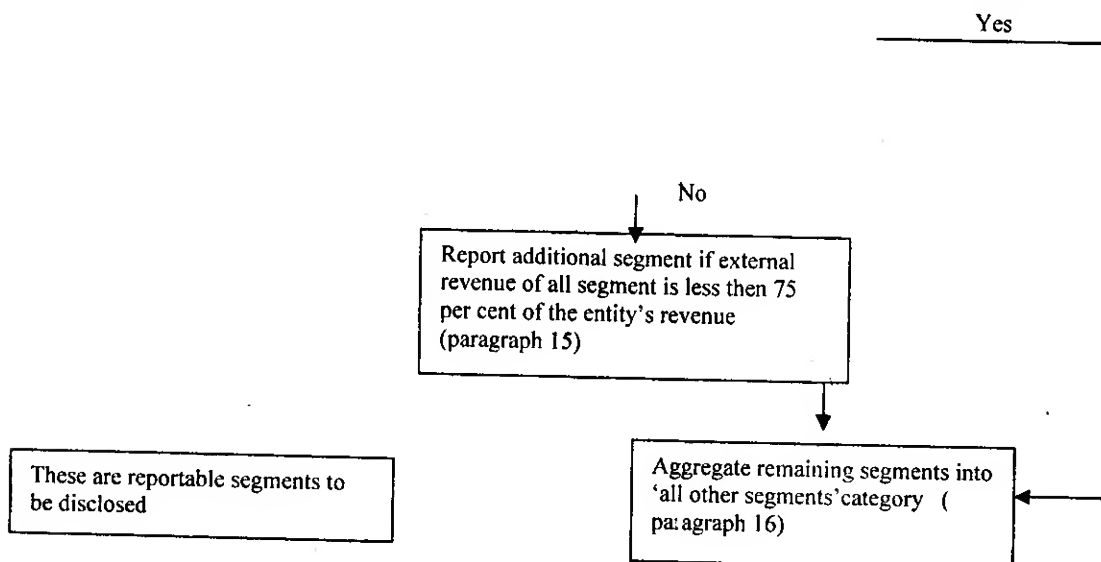
Revenues from one customer of Diversified Company's software and electronics segments represent approximately Rs. 5,000 of the Company's total revenues.

Diagram to assist in identifying reportable segments

IG7 The following diagram illustrates how to apply the main provisions for identifying reportable segments as defined in the Indian Accounting Standard. The diagram is a visual supplement to the Indian Accounting Standard. It should not be interpreted as altering or adding to any requirements of the Indian Accounting Standard nor should it be regarded as a substitute for the requirements.

Diagram for identifying reportable segments





Appendix 1

Note: This appendix is not a part of the Indian Accounting Standard. The purpose of this Appendix is only to bring out the differences between Indian Accounting Standard (Ind AS) 108 and the corresponding International Financial Reporting Standard (IFRS) 8, Operating Segments

Comparison with IFRS 8, Operating Segments

1. The transitional provisions given in IFRS 108 has not been given in Ind AS 108, since all transitional provisions related to Ind ASs, wherever considered appropriate, have been included in Ind AS 101, *First-time Adoption of Indian Accounting Standards* corresponding to IFRS 1, *First-time Adoption of International Financial Reporting Standards*
2. Different terminology is used, as used in existing laws e.g., the term 'balance sheet' is used instead of 'Statement of financial position' and 'Statement of profit and loss' is used instead of 'Statement of comprehensive income'.

[F. No. 17/228/2010-CL. V]

RENUKA KUMAR, Jt. Secy.

Note : The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide number G.S.R. 739(E), dated the 7th December, 2006 and subsequently amended by :—

- (1) G.S.R. 212(E), dated 27th March, 2008
- (2) G.S.R. 225(E), dated 31st March, 2009

Indian Accounting Standard (Ind AS) 1

Presentation of Financial Statements

*(This Indian Accounting Standard includes paragraphs set in **bold type** and plain type, which have equal authority. Paragraphs in bold type indicate the main principles).*

Objective

- 1 This Standard prescribes the basis for presentation of general purpose financial statements to ensure comparability both with the entity's financial statements of previous periods and with the financial statements of other entities. It sets out overall requirements for the presentation of financial statements, guidelines for their structure and minimum requirements for their content.

Scope

- 2 **An entity shall apply this Standard in preparing and presenting general purpose financial statements in accordance with Indian Accounting Standards (Ind ASs).**
- 3 Other Ind ASs set out the recognition, measurement and disclosure requirements for specific transactions and other events.
- 4 This Standard does not apply to the structure and content of condensed interim financial statements prepared in accordance with Ind AS 34 *Interim Financial Reporting*. However, paragraphs 15–35 apply to such financial statements. This Standard applies equally to all entities, including those that present consolidated financial statements and those that present separate financial statements as defined in Ind AS 27 *Consolidated and Separate Financial Statements*.
- 5 This Standard uses terminology that is suitable for profit-oriented entities, including public sector business entities. If entities with not-for-profit activities in the private sector or the public sector apply this Standard, they may need to amend the descriptions used for particular line items in the financial statements and for the financial statements themselves.
- 6 Similarly, entities whose share capital is not equity may need to adapt the financial statement presentation of members' interests.

Definitions

- 7 The following terms are used in this Standard with the meanings specified:

General purpose financial statements (referred to as 'financial statements') are those intended to meet the needs of users who are not in a position to require an entity to prepare reports tailored to their particular information needs.

Impracticable Applying a requirement is impracticable when the entity cannot apply it after making every reasonable effort to do so.

Indian Accounting Standards (Ind ASs) are Standards prescribed under Section 211(3C) of the Companies Act, 1956.

Material Omissions or misstatements of items are material if they could, individually or collectively, influence the economic decisions that users make on the basis of the financial statements. Materiality depends on the size and nature of the omission or misstatement judged in the surrounding circumstances. The size or nature of the item, or a combination of both, could be the determining factor.

Assessing whether an omission or misstatement could influence economic decisions of users, and so be material, requires consideration of the characteristics of those users. The *Framework for the Preparation and Presentation of Financial Statements* issued by the Institute of Chartered Accountants of India states in paragraph 25 that 'users are assumed to have a reasonable knowledge of business and economic activities and accounting and a willingness to study the information with reasonable diligence.' Therefore, the assessment needs to take into account how users with such attributes could reasonably be expected to be influenced in making economic decisions.

Notes contain information in addition to that presented in the balance sheet (including statement of changes in equity which is a part of the balance sheet), statement of profit and loss and statement of cash flows. Notes provide narrative descriptions or disaggregations of items presented in those statements and information about items that do not qualify for recognition in those statements.

Other comprehensive income comprises items of income and expense (including reclassification adjustments) that are not recognised in profit or loss as required or permitted by other Ind ASs.

The components of other comprehensive income include:

- (a) changes in revaluation surplus (see Ind AS 16 *Property, Plant and Equipment* and Ind AS 38) *Intangible Assets*);
- (b) actuarial gains and losses on defined benefit plans recognised in accordance with paragraph 92 and 129A of Ind AS 19 *Employee Benefits*;
- (c) gains and losses arising from translating the financial statements of a foreign operation (see Ind AS 21 *The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates*);
- (d) gains and losses on remeasuring available-for-sale financial assets (see Ind AS 39 *Financial Instruments: Recognition and Measurement*);
- (e) the effective portion of gains and losses on hedging instruments in a cash flow hedge (see Ind AS 39).

Owners are holders of instruments classified as equity.

Profit or loss is the total of income less expenses, excluding the components of other comprehensive income.

Reclassification adjustments are amounts reclassified to profit or loss in the current period that were recognised in other comprehensive income in the current or previous periods.

Total comprehensive income is the change in equity during a period resulting from transactions and other events, other than those changes resulting from transactions with owners in their capacity as owners.

Total comprehensive income comprises all components of 'profit or loss' and of 'other comprehensive income'.

8 [Refer to Appendix 1)]

8A. The following terms are described in Ind AS 32 *Financial Instruments: Presentation* and are used in this Standard with the meaning specified in Ind AS 32:

- (a) puttable financial instrument classified as an equity instrument (described in paragraphs 16A and 16B of Ind AS 32)
- (b) an instrument that imposes on the entity an obligation to deliver to another party a pro rata share of the net assets of the entity only on liquidation and is classified as an equity instrument (described in paragraphs 16C and 16D of Ind AS 32).

Financial statements

Purpose of financial statements

9 Financial statements are a structured representation of the financial position and financial performance of an entity. The objective of financial statements is to provide information about the financial position, financial performance and cash flows of an entity that is useful to a wide range of users in making economic decisions. Financial statements also show the results of the management's stewardship of the resources entrusted to it. To meet this objective, financial statements provide information about an entity's:

- (a) assets;
- (b) liabilities;
- (c) equity;
- (d) income and expenses, including gains and losses;
- (e) contributions by and distributions to owners in their capacity as owners; and
- (f) cash flows.

This information, along with other information in the notes, assists users of financial statements in predicting the entity's future cash flows and, in particular, their timing and certainty.

Complete set of financial statements

- 10 A complete set of financial statements comprises:**
- (a) a balance sheet as at the end of the period (including statement of changes in equity which is presented as a part of the balance sheet);
 - (b) a statement of profit and loss for the period;
 - (c) [Refer to Appendix 1];
 - (d) a statement of cash flows for the period;
 - (e) notes, comprising a summary of significant accounting policies and other explanatory information; and
 - (f) a balance sheet as at the beginning of the earliest comparative period when an entity applies an accounting policy retrospectively or makes a retrospective restatement of items in its financial statements, or when it reclassifies items in its financial statements.
- 11 An entity shall present with equal prominence all of the financial statements in a complete set of financial statements.**
- 12 As per paragraph 81, an entity shall present the components of profit or loss and components of other comprehensive income as part of a single statement of profit and loss.**
- 13 Many entities present, outside the financial statements, a financial review by management that describes and explains the main features of the entity's financial performance and financial position, and the principal uncertainties it faces. Such a report may include a review of:**
- (a) the main factors and influences determining financial performance, including changes in the environment in which the entity operates, the entity's response to those changes and their effect, and the entity's policy for investment to maintain and enhance financial performance, including its dividend policy;
 - (b) the entity's sources of funding and its targeted ratio of liabilities to equity; and
 - (c) the entity's resources not recognised in the balance sheet in accordance with Ind ASs.
- 14 Many entities also present, outside the financial statements, reports and statements such as environmental reports and value added statements, particularly in industries in which environmental factors are significant and when employees are regarded as an important user group. Reports and statements presented outside financial statements are outside the scope of Ind ASs.**

General features

Presentation of True and Fair View and compliance with Ind ASs

- 15 Financial statements shall present a true and fair view of the financial position, financial performance and cash flows of an entity. Presentation of true and fair view requires the faithful representation of the effects of transactions, other events and conditions in accordance with the definitions and recognition criteria for assets, liabilities, income and expenses set out in the *Framework*. The application of Ind ASs, with additional disclosure when necessary, is presumed to result in financial statements that present a true and fair view.
- 16 An entity whose financial statements comply with Ind ASs shall make an explicit and unreserved statement of such compliance in the notes. An entity shall not describe financial statements as complying with Ind ASs unless they comply with all the requirements of Ind ASs.
- 17 In virtually all circumstances, presentation of a true and fair view is achieved by compliance with applicable Ind ASs. Presentation of a true and fair view also requires an entity:
- (a) to select and apply accounting policies in accordance with Ind AS 8 *Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors*. Ind AS 8 sets out a hierarchy of authoritative guidance that management considers in the absence of an Ind AS that specifically applies to an item.
 - (b) to present information, including accounting policies, in a manner that provides relevant, reliable, comparable and understandable information.
 - (c) to provide additional disclosures when compliance with the specific requirements in Ind ASs is insufficient to enable users to understand the impact of particular transactions, other events and conditions on the entity's financial position and financial performance.
- 18 An entity cannot rectify inappropriate accounting policies either by disclosure of the accounting policies used or by notes or explanatory material.
- 19 In the extremely rare circumstances in which management concludes that compliance with a requirement in an Ind AS would be so misleading that it would conflict with the objective of financial statements set out in the *Framework*, the entity shall depart from that requirement in the manner set out in paragraph 20 if the relevant regulatory framework requires, or otherwise does not prohibit, such a departure.
- 20 When an entity departs from a requirement of an Ind AS in accordance with paragraph 19, it shall disclose:
- (a) that management has concluded that the financial statements present a true and fair view of the entity's financial position, financial performance and cash flows;
 - (b) that it has complied with applicable Ind ASs, except that it has departed from a particular requirement to present a true and fair view;
 - (c) the title of the Ind AS from which the entity has departed, the nature of the departure, including the treatment that the Ind AS would require, the reason why that treatment would be so misleading in the

- circumstances that it would conflict with the objective of financial statements set out in the *Framework*, and the treatment adopted; and
- (d) for each period presented, the financial effect of the departure on each item in the financial statements that would have been reported in complying with the requirement.
- 21 When an entity has departed from a requirement of an Ind AS in a prior period, and that departure affects the amounts recognised in the financial statements for the current period, it shall make the disclosures set out in paragraph 20(c) and (d).
- 22 Paragraph 21 applies, for example, when an entity departed in a prior period from a requirement in an Ind AS for the measurement of assets or liabilities and that departure affects the measurement of changes in assets and liabilities recognised in the current period's financial statements.
- 23 In the extremely rare circumstances in which management concludes that compliance with a requirement in an Ind AS would be so misleading that it would conflict with the objective of financial statements set out in the *Framework*, but the relevant regulatory framework prohibits departure from the requirement, the entity shall, to the maximum extent possible, reduce the perceived misleading aspects of compliance by disclosing:
- (a) the title of the Ind AS in question, the nature of the requirement, and the reason why management has concluded that complying with that requirement is so misleading in the circumstances that it conflicts with the objective of financial statements set out in the *Framework*; and
- (b) for each period presented, the adjustments to each item in the financial statements that management has concluded would be necessary to present a true and fair view.
- 24 For the purpose of paragraphs 19–23, an item of information would conflict with the objective of financial statements when it does not represent faithfully the transactions, other events and conditions that it either purports to represent or could reasonably be expected to represent and, consequently, it would be likely to influence economic decisions made by users of financial statements. When assessing whether complying with a specific requirement in an Ind AS would be so misleading that it would conflict with the objective of financial statements set out in the *Framework*, management considers:
- (a) why the objective of financial statements is not achieved in the particular circumstances; and
- (b) how the entity's circumstances differ from those of other entities that comply with the requirement. If other entities in similar circumstances comply with the requirement, there is a rebuttable presumption that the entity's compliance with the requirement would not be so misleading that it would conflict with the objective of financial statements set out in the *Framework*.

Going concern

- 25 When preparing financial statements, management shall make an assessment of an entity's ability to continue as a going concern. An entity shall prepare financial statements on a going concern basis unless management either intends to liquidate the entity or to cease trading, or has no realistic alternative but to do so. When management is aware, in making its assessment, of material uncertainties related to events or conditions that may cast significant doubt upon the entity's ability to continue as a going concern, the entity shall disclose those uncertainties. When an entity does not prepare financial statements on a going concern basis, it shall disclose that fact, together with the basis on which it prepared the financial statements and the reason why the entity is not regarded as a going concern.
- 26 In assessing whether the going concern assumption is appropriate, management takes into account all available information about the future, which is at least, but is not limited to, twelve months from the end of the reporting period. The degree of consideration depends on the facts in each case. When an entity has a history of profitable operations and ready access to financial resources, the entity may reach a conclusion that the going concern basis of accounting is appropriate without detailed analysis. In other cases, management may need to consider a wide range of factors relating to current and expected profitability, debt repayment schedules and potential sources of replacement financing before it can satisfy itself that the going concern basis is appropriate.

Accrual basis of accounting

- 27 An entity shall prepare its financial statements, except for cash flow information, using the accrual basis of accounting.
- 28 When the accrual basis of accounting is used, an entity recognises items as assets, liabilities, equity, income and expenses (the elements of financial statements) when they satisfy the definitions and recognition criteria for those elements in the *Framework*.

Materiality and aggregation

- 29 An entity shall present separately each material class of similar items. An entity shall present separately items of a dissimilar nature or function unless they are immaterial except when required by law.
- 30 Financial statements result from processing large numbers of transactions or other events that are aggregated into classes according to their nature or function. The final stage in the process of aggregation and classification is the presentation of condensed and classified data, which form line items in the financial statements. If a line item is not individually material, it is aggregated with other items either in those statements or in the notes. An item that is not sufficiently material to warrant separate presentation in those statements may warrant separate presentation in the notes.
- 31 An entity need not provide a specific disclosure required by an Ind AS if the information is not material except when required by law.

Offsetting

- 32 An entity shall not offset assets and liabilities or income and expenses, unless required or permitted by an Ind AS.
- 33 An entity reports separately both assets and liabilities, and income and expenses. Offsetting in the statements of profit and loss or balance sheet, except when offsetting reflects the substance of the transaction or other event, detracts from the ability of users both to understand the transactions, other events and conditions that have occurred and to assess the entity's future cash flows. Measuring assets net of valuation allowances—for example, obsolescence allowances on inventories and doubtful debts allowances on receivables—is not offsetting.
- 34 Ind AS 18 *Revenue* defines revenue and requires an entity to measure it at the fair value of the consideration received or receivable, taking into account the amount of any trade discounts and volume rebates the entity allows. An entity undertakes, in the course of its ordinary activities, other transactions that do not generate revenue but are incidental to the main revenue-generating activities. An entity presents the results of such transactions, when this presentation reflects the substance of the transaction or other event, by netting any income with related expenses arising on the same transaction. For example:
- (a) an entity presents gains and losses on the disposal of non-current assets, including investments and operating assets, by deducting from the proceeds on disposal the carrying amount of the asset and related selling expenses; and
 - (b) an entity may net expenditure related to a provision that is recognised in accordance with Ind AS 37 *Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets* and reimbursed under a contractual arrangement with a third party (for example, a supplier's warranty agreement) against the related reimbursement.
- 35 In addition, an entity presents on a net basis gains and losses arising from a group of similar transactions, for example, foreign exchange gains and losses or gains and losses arising on financial instruments held for trading. However, an entity presents such gains and losses separately if they are material.

Frequency of reporting

- 36 An entity shall present a complete set of financial statements (including comparative information) at least annually. When an entity changes the end of its reporting period and presents financial statements for a period longer or shorter than one year, an entity shall disclose, in addition to the period covered by the financial statements:
- (a) the reason for using a longer or shorter period, and
 - (b) the fact that amounts presented in the financial statements are not entirely comparable.
- 37 [Refer to Appendix 1]

Comparative information

- 38 Except when Ind ASs permit or require otherwise, an entity shall disclose comparative information in respect of the previous period for all amounts

reported in the current period's financial statements. An entity shall include comparative information for narrative and descriptive information when it is relevant to an understanding of the current period's financial statements.

- 39 An entity disclosing comparative information shall present, as a minimum, two balance sheets, two of each of the other statements, and related notes. When an entity applies an accounting policy retrospectively or makes a retrospective restatement of items in its financial statements or when it reclassifies items in its financial statements, it shall present, as a minimum, three balance sheets, two of each of the other statements, and related notes. An entity presents balance sheets as at:
- (a) the end of the current period,
 - (b) the end of the previous period (which is the same as the beginning of the current period), and
 - (c) the beginning of the earliest comparative period.
- 40 In some cases, narrative information provided in the financial statements for the previous period(s) continues to be relevant in the current period. For example, an entity discloses in the current period details of a legal dispute whose outcome was uncertain at the end of the immediately preceding reporting period and that is yet to be resolved. Users benefit from information that the uncertainty existed at the end of the immediately preceding reporting period, and about the steps that have been taken during the period to resolve the uncertainty.
- 41 When the entity changes the presentation or classification of items in its financial statements, the entity shall reclassify comparative amounts unless reclassification is impracticable. When the entity reclassifies comparative amounts, the entity shall disclose:
- (a) the nature of the reclassification;
 - (b) the amount of each item or class of items that is reclassified; and
 - (c) the reason for the reclassification.
- 42 When it is impracticable to reclassify comparative amounts, an entity shall disclose:
- (a) the reason for not reclassifying the amounts, and
 - (b) the nature of the adjustments that would have been made if the amounts had been reclassified.
- 43 Enhancing the inter-period comparability of information assists users in making economic decisions, especially by allowing the assessment of trends in financial information for predictive purposes. In some circumstances, it is impracticable to reclassify comparative information for a particular prior period to achieve comparability with the current period. For example, an entity may not have

collected data in the prior period(s) in a way that allows reclassification, and it may be impracticable to recreate the information.

- 44 Ind AS 8 sets out the adjustments to comparative information required when an entity changes an accounting policy or corrects an error.

Consistency of presentation

- 45 An entity shall retain the presentation and classification of items in the financial statements from one period to the next unless:

(a) It is apparent, following a significant change in the nature of the entity's operations or a review of its financial statements, that another presentation or classification would be more appropriate having regard to the criteria for the selection and application of accounting policies in Ind AS 8; or

(b) an Ind AS requires a change in presentation.

- 46 For example, a significant acquisition or disposal, or a review of the presentation of the financial statements, might suggest that the financial statements need to be presented differently. An entity changes the presentation of its financial statements only if the changed presentation provides information that is reliable and more relevant to users of the financial statements and the revised structure is likely to continue, so that comparability is not impaired. When making such changes in presentation, an entity reclassifies its comparative information in accordance with paragraphs 41 and 42.

Structure and content

Introduction

- 47 This Standard requires particular disclosures in the balance sheet (including statement of changes in equity which is a part of the balance sheet) or in the statement of profit and loss and requires disclosure of other line items either in those statements or in the notes. Ind AS 7 *Statement of Cash Flows* sets out requirements for the presentation of cash flow information.
- 48 This Standard sometimes uses the term 'disclosure' in a broad sense, encompassing items presented in the financial statements. Disclosures are also required by other Ind ASs. Unless specified to the contrary elsewhere in this Standard or in another Ind AS, such disclosures may be made in the financial statements.

Identification of the financial statements

- 49 An entity shall clearly identify the financial statements and distinguish them from other information in the same published document.
- 50 Ind ASs apply only to financial statements, and not necessarily to other information presented in an annual report, a regulatory filing, or another document. Therefore, it is important that users can distinguish information that

is prepared using Ind ASs from other information that may be useful to users but is not the subject of those requirements.

- 51 An entity shall clearly identify each financial statement and the notes. In addition, an entity shall display the following information prominently, and repeat it when necessary for the information presented to be understandable:**
- (a) the name of the reporting entity or other means of identification, and any change in that information from the end of the preceding reporting period;
 - (b) whether the financial statements are of an individual entity or a group of entities;
 - (c) the date of the end of the reporting period or the period covered by the set of financial statements or notes;
 - (d) the presentation currency, as defined in Ind AS 21; and
 - (e) the level of rounding used in presenting amounts in the financial statements.
- 52 An entity meets the requirements in paragraph 51 by presenting appropriate headings for pages, statements, notes, columns and the like. Judgement is required in determining the best way of presenting such information. For example, when an entity presents the financial statements electronically, separate pages are not always used; an entity then presents the above items to ensure that the information included in the financial statements can be understood.**
- 53 An entity often makes financial statements more understandable by presenting information in thousands, lakhs, millions or crores of units of the presentation currency. This is acceptable as long as the entity discloses the level of rounding and does not omit material information.**

Balance Sheet

Information to be presented in the balance sheet

- 54 As a minimum, the balance sheet shall include line items that present the following amounts:**
- (a) property, plant and equipment;
 - (b) investment property;
 - (c) intangible assets;
 - (d) financial assets (excluding amounts shown under (e), (h) and (i));
 - (e) investments accounted for using the equity method;
 - (f) biological assets;
 - (g) inventories;
 - (h) trade and other receivables;

- (i) cash and cash equivalents;
 - (j) the total of assets classified as held for sale and assets included in disposal groups classified as held for sale in accordance with Ind AS 105 *Non-current Assets Held for Sale and Discontinued Operations*;
 - (k) trade and other payables;
 - (l) provisions;
 - (m) financial liabilities (excluding amounts shown under (k) and (l));
 - (n) liabilities and assets for current tax, as defined in Ind AS 12 *Income Taxes*;
 - (o) deferred tax liabilities and deferred tax assets, as defined in Ind AS 12;
 - (p) liabilities included in disposal groups classified as held for sale in accordance with Ind AS 105;
 - (q) non-controlling interests, presented within equity; and
 - (r) issued capital and reserves attributable to owners of the parent.
- 55 An entity shall present additional line items, headings and subtotals in the balance sheet when such presentation is relevant to an understanding of the entity's financial position.
- 56 When an entity presents current and non-current assets, and current and non-current liabilities, as separate classifications in its balance sheet, it shall not classify deferred tax assets (liabilities) as current assets (liabilities).
- 57 This Standard does not prescribe the order or format in which an entity presents items. Paragraph 54 simply lists items that are sufficiently different in nature or function to warrant separate presentation in the balance sheet. In addition:
- (a) line items are included when the size, nature or function of an item or aggregation of similar items is such that separate presentation is relevant to an understanding of the entity's financial position; and
 - (b) the descriptions used and the ordering of items or aggregation of similar items may be amended according to the nature of the entity and its transactions, to provide information that is relevant to an understanding of the entity's financial position. For example, a financial institution may amend the above descriptions to provide information that is relevant to the operations of a financial institution.
- 58 An entity makes the judgement about whether to present additional items separately on the basis of an assessment of:
- (a) the nature and liquidity of assets;
 - (b) the function of assets within the entity; and
 - (c) the amounts, nature and timing of liabilities.

- 59 The use of different measurement bases for different classes of assets suggests that their nature or function differs and, therefore, that an entity presents them as separate line items. For example, different classes of property, plant and equipment can be carried at cost or at revalued amounts in accordance with Ind AS 16.

Current/non-current distinction

- 60 An entity shall present current and non-current assets, and current and non-current liabilities, as separate classifications in its balance sheet in accordance with paragraphs 66–76 except when a presentation based on liquidity provides information that is reliable and more relevant. When that exception applies, an entity shall present all assets and liabilities in order of liquidity.
- 61 Whichever method of presentation is adopted, an entity shall disclose the amount expected to be recovered or settled after more than twelve months for each asset and liability line item that combines amounts expected to be recovered or settled:
- (a) no more than twelve months after the reporting period, and
 - (b) more than twelve months after the reporting period.
- 62 When an entity supplies goods or services within a clearly identifiable operating cycle, separate classification of current and non-current assets and liabilities in the balance sheet provides useful information by distinguishing the net assets that are continuously circulating as working capital from those used in the entity's long-term operations. It also highlights assets that are expected to be realised within the current operating cycle, and liabilities that are due for settlement within the same period.
- 63 For some entities, such as financial institutions, a presentation of assets and liabilities in increasing or decreasing order of liquidity provides information that is reliable and more relevant than a current/non-current presentation because the entity does not supply goods or services within a clearly identifiable operating cycle.
- 64 In applying paragraph 60, an entity is permitted to present some of its assets and liabilities using a current/non-current classification and others in order of liquidity when this provides information that is reliable and more relevant. The need for a mixed basis of presentation might arise when an entity has diverse operations.
- 65 Information about expected dates of realisation of assets and liabilities is useful in assessing the liquidity and solvency of an entity. Ind AS 107 *Financial Instruments: Disclosures* requires disclosure of the maturity dates of financial assets and financial liabilities. Financial assets include trade and other receivables, and financial liabilities include trade and other payables. Information on the expected date of recovery of non-monetary assets such as inventories and expected date of settlement for liabilities such as provisions is also useful, whether assets and liabilities are classified as current or as non-current. For example, an entity discloses the amount of inventories that are expected to be recovered more than twelve months after the reporting period.

Current assets

- 66 An entity shall classify an asset as current when:**
- (a) it expects to realise the asset, or intends to sell or consume it, in its normal operating cycle;**
 - (b) it holds the asset primarily for the purpose of trading;**
 - (c) it expects to realise the asset within twelve months after the reporting period; or**
 - (d) the asset is cash or a cash equivalent (as defined in Ind AS 7) unless the asset is restricted from being exchanged or used to settle a liability for at least twelve months after the reporting period.**

An entity shall classify all other assets as non-current.

- 67** This Standard uses the term 'non-current' to include tangible, intangible and financial assets of a long-term nature. It does not prohibit the use of alternative descriptions as long as the meaning is clear.
- 68** The operating cycle of an entity is the time between the acquisition of assets for processing and their realisation in cash or cash equivalents. When the entity's normal operating cycle is not clearly identifiable, it is assumed to be twelve months. Current assets include assets (such as inventories and trade receivables) that are sold, consumed or realised as part of the normal operating cycle even when they are not expected to be realised within twelve months after the reporting period. Current assets also include assets held primarily for the purpose of trading (examples include some financial assets classified as held for trading in accordance with Ind AS 39) and the current portion of non-current financial assets.

Current liabilities

- 69 An entity shall classify a liability as current when:**
- (a) it expects to settle the liability in its normal operating cycle;**
 - (b) it holds the liability primarily for the purpose of trading;**
 - (c) the liability is due to be settled within twelve months after the reporting period; or**
 - (d) it does not have an unconditional right to defer settlement of the liability for at least twelve months after the reporting period (see paragraph 73). Terms of a liability that could, at the option of the counterparty, result in its settlement by the issue of equity instruments do not affect its classification.**

An entity shall classify all other liabilities as non-current.

- 70** Some current liabilities, such as trade payables and some accruals for employee and other operating costs, are part of the working capital used in the entity's normal operating cycle. An entity classifies such operating items as current liabilities even if they are due to be settled more than twelve months after the reporting period. The same normal operating cycle applies to the

classification of an entity's assets and liabilities. When the entity's normal operating cycle is not clearly identifiable, it is assumed to be twelve months.

- 71 Other current liabilities are not settled as part of the normal operating cycle, but are due for settlement within twelve months after the reporting period or held primarily for the purpose of trading. Examples are some financial liabilities classified as held for trading in accordance with Ind AS 39, bank overdrafts, and the current portion of non-current financial liabilities, dividends payable, income taxes and other non-trade payables. Financial liabilities that provide financing on a long-term basis (ie are not part of the working capital used in the entity's normal operating cycle) and are not due for settlement within twelve months after the reporting period are non-current liabilities, subject to paragraphs 74 and 75.
- 72 An entity classifies its financial liabilities as current when they are due to be settled within twelve months after the reporting period, even if:
 - (a) the original term was for a period longer than twelve months, and
 - (b) an agreement to refinance, or to reschedule payments, on a long-term basis is completed after the reporting period and before the financial statements are approved for issue.
- 73 If an entity expects, and has the discretion, to refinance or roll over an obligation for at least twelve months after the reporting period under an existing loan facility, it classifies the obligation as non-current, even if it would otherwise be due within a shorter period. However, when refinancing or rolling over the obligation is not at the discretion of the entity (for example, there is no arrangement for refinancing), the entity does not consider the potential to refinance the obligation and classifies the obligation as current.
- 74 When an entity breaches a provision of a long-term loan arrangement on or before the end of the reporting period with the effect that the liability becomes payable on demand, it classifies the liability as current, even if the lender agreed, after the reporting period and before the approval of the financial statements for issue, not to demand payment as a consequence of the breach. An entity classifies the liability as current because, at the end of the reporting period, it does not have an unconditional right to defer its settlement for at least twelve months after that date.
- 75 However, an entity classifies the liability as non-current if the lender agreed by the end of the reporting period to provide a period of grace ending at least twelve months after the reporting period, within which the entity can rectify the breach and during which the lender cannot demand immediate repayment.
- 76 In respect of loans classified as current liabilities, if the following events occur between the end of the reporting period and the date the financial statements are approved for issue, those events are disclosed as non-adjusting events in accordance with Ind AS 10 Events after the Reporting Period:
 - (a) refinancing on a long-term basis;
 - (b) rectification of a breach of a long-term loan arrangement; and

- (c) the granting by the lender of a period of grace to rectify a breach of a long-term loan arrangement ending at least twelve months after the reporting period.

Information to be presented either in the balance sheet or in the notes

- 77 An entity shall disclose, either in the balance sheet or in the notes, further subclassifications of the line items presented, classified in a manner appropriate to the entity's operations.**
- 78 The detail provided in subclassifications depends on the requirements of Ind ASs and on the size, nature and function of the amounts involved. An entity also uses the factors set out in paragraph 58 to decide the basis of subclassification. The disclosures vary for each item, for example:**
- (a) **items of property, plant and equipment** are disaggregated into classes in accordance with Ind AS 16;
 - (b) **receivables** are disaggregated into amounts receivable from trade customers, receivables from related parties, prepayments and other amounts;
 - (c) **inventories** are disaggregated, in accordance with Ind AS 2 *inventories*, into classifications such as merchandise, production supplies, materials, work in progress and finished goods;
 - (d) **provisions** are disaggregated into provisions for employee benefits and other items; and
 - (e) **equity capital and reserves** are disaggregated into various classes, such as paid-in capital, share premium and reserves.
- 79 An entity shall disclose the following, either in the balance sheet or in the statement of changes in equity which is part of the balance sheet, or in the notes:**
- (a) for each class of share capital:**
 - (i) **the number of shares authorised;**
 - (ii) **the number of shares issued and fully paid, and issued but not fully paid;**
 - (iii) **par value per share, or that the shares have no par value;**
 - (iv) **a reconciliation of the number of shares outstanding at the beginning and at the end of the period;**
 - (v) **the rights, preferences and restrictions attaching to that class including restrictions on the distribution of dividends and the repayment of capital;**
 - (vi) **shares in the entity held by the entity or by its subsidiaries or associates; and**
 - (vii) **shares reserved for issue under options and contracts for the sale of shares, including terms and amounts; and**
 - (b) a description of the nature and purpose of each reserve.**

- 80 An entity whose capital is not limited by shares e.g., a company limited by guarantee, shall disclose information equivalent to that required by paragraph 79(a), showing changes during the period in each category of equity interest, and the rights, preferences and restrictions attaching to each category of equity interest.

80A If an entity has reclassified

- (a) a puttable financial instrument classified as an equity instrument, or
- (b) an instrument that imposes on the entity an obligation to deliver to another party a pro rata share of the net assets of the entity only on liquidation and is classified as an equity instrument

between financial liabilities and equity, it shall disclose the amount reclassified into and out of each category (financial liabilities or equity), and the timing and reason for that reclassification.

Statement of Profit and Loss

- 81 An entity shall present all items of income and expense including components of other comprehensive income recognised in a period in a single statement of profit and loss.

Information to be presented in the statement of profit and loss

- 82 As a minimum, the statement of profit and loss shall include line items that present the following amounts for the period:
- (a) revenue;
 - (b) finance costs;
 - (c) share of the profit or loss of associates and joint ventures accounted for using the equity method;
 - (d) tax expense;
 - (e) a single amount comprising the total of:
 - (i) the post-tax profit or loss of discontinued operations and
 - (ii) the post-tax gain or loss recognised on the measurement to fair value less costs to sell or on the disposal of the assets or disposal group(s) constituting the discontinued operation;
 - (f) profit or loss;
 - (g) each component of other comprehensive income classified by nature (excluding amounts in (h));
 - (h) share of the other comprehensive income of associates and joint ventures accounted for using the equity method; and
 - (i) total comprehensive income.

- 83 An entity shall disclose the following items in the statement of profit and loss as allocations for the period:**
- (a) **profit or loss for the period attributable to:**
 - (i) **non-controlling interests, and**
 - (ii) **owners of the parent.**
 - (b) **total comprehensive income for the period attributable to:**
 - (i) **non-controlling interests, and**
 - (ii) **owners of the parent.**
- 84 [Refer to Appendix 1]**
- 85 An entity shall present additional line items, headings and subtotals in the statement of profit and loss, when such presentation is relevant to an understanding of the entity's financial performance.**
- 86** Because the effects of an entity's various activities, transactions and other events differ in frequency, potential for gain or loss and predictability, disclosing the components of financial performance assists users in understanding the financial performance achieved and in making projections of future financial performance. An entity includes additional line items in the statement of profit and loss, and it amends the descriptions used and the ordering of items when this is necessary to explain the elements of financial performance. An entity considers factors including materiality and the nature and function of the items of income and expense. For example, a financial institution may amend the descriptions to provide information that is relevant to the operations of a financial institution. An entity does not offset income and expense items unless the criteria in paragraph 32 are met.
- 87 An entity shall not present any items of income or expense as extraordinary items, in the statement of profit and loss or in the notes.**

Profit or loss for the period

- 88. An entity shall recognise all items of income and expense in a period in profit or loss unless an Ind AS requires or permits otherwise.**
- 89** Some Ind ASs specify circumstances when an entity recognises particular items outside profit or loss in the current period. Ind AS 8 specifies two such circumstances: the correction of errors and the effect of changes in accounting policies. Other Ind ASs require or permit components of other comprehensive income that meet the *Framework's* definition of income or expense to be excluded from profit or loss (see paragraph 7).

Other comprehensive income for the period

- 90 An entity shall disclose the amount of income tax relating to each component of other comprehensive income, including reclassification adjustments, either in the statement of profit and loss or in the notes.**

- 91 An entity may present components of other comprehensive income either:
- (a) net of related tax effects, or
 - (b) before related tax effects with one amount shown for the aggregate amount of income tax relating to those components.
- 92 An entity shall disclose reclassification adjustments relating to components of other comprehensive income.
- 93 Other Ind ASs specify whether and when amounts previously recognised in other comprehensive income are reclassified to profit or loss. Such reclassifications are referred to in this Standard as reclassification adjustments. A reclassification adjustment is included with the related component of other comprehensive income in the period that the adjustment is reclassified to profit or loss. For example, gains realised on the disposal of available-for-sale financial assets are included in profit or loss of the current period. These amounts may have been recognised in other comprehensive income as unrealised gains in the current or previous periods. Those unrealised gains must be deducted from other comprehensive income in the period in which the realised gains are reclassified to profit or loss to avoid including them in total comprehensive income twice.
- 94 An entity may present reclassification adjustments in the statement of profit and loss or in the notes. An entity presenting reclassification adjustments in the notes presents the components of other comprehensive income after any related reclassification adjustments.
- 95 Reclassification adjustments arise, for example, on disposal of a foreign operation (see Ind AS 21), on derecognition of available-for-sale financial assets (see Ind AS 39) and when a hedged forecast transaction affects profit or loss (see paragraph 100 of Ind AS 39 in relation to cash flow hedges).
- 96 Reclassification adjustments do not arise on changes in revaluation surplus recognised in accordance with Ind AS 16 or Ind AS 38 or on actuarial gains and losses on defined benefit plans recognised in accordance with paragraphs 92 and 129A of Ind AS 19. These components are recognised in other comprehensive income and are not reclassified to profit or loss in subsequent periods. Changes in revaluation surplus may be transferred to retained earnings in subsequent periods as the asset is used or when it is derecognised (see Ind AS 16 and Ind AS 38). Actuarial gains and losses are reported in retained earnings in the period that they are recognised as other comprehensive income (see Ind AS 19).

Information to be presented in the statement of profit and loss or in the notes

- 97 When items of income or expense are material, an entity shall disclose their nature and amount separately.
- 98 Circumstances that would give rise to the separate disclosure of items of income and expense include:
- (a) write-downs of inventories to net realisable value or of property, plant and equipment to recoverable amount, as well as reversals of such write-downs;

- (b) restructurings of the activities of an entity and reversals of any provisions for the costs of restructuring;
- (c) disposals of items of property, plant and equipment;
- (d) disposals of investments;
- (e) discontinued operations;
- (f) litigation settlements; and
- (g) other reversals of provisions.

99 An entity shall present an analysis of expenses recognised in profit or loss using a classification based on the nature of expense method.

100 Entities are encouraged to present the analysis in paragraph 99 in the statement of profit and loss

101 Expenses are subclassified to highlight components of financial performance that may differ in terms of frequency, potential for gain or loss and predictability. This analysis is provided in the form as described in paragraph 102.

102 In the analysis based on the 'nature of expense' method, an entity aggregates expenses within profit or loss according to their nature (for example, depreciation, purchases of materials, transport costs, employee benefits and advertising costs), and does not reallocate them among functions within the entity. This method is simple to apply because no allocations of expenses to functional classifications are necessary. An example of a classification using the nature of expense method is as follows:

Revenue		X
Other income		X
Changes in inventories of finished goods and work in progress	X	
Raw materials and consumables used	X	
Employee benefits expense	X	
Depreciation and amortisation expense	X	
Other expenses	X	
Total expenses		(X)
Profit before tax		X

103 [Refer to Appendix 1]

104 [Refer to Appendix 1].

105 [Refer to Appendix 1].

Statement of changes in equity

106 An entity shall present a statement of changes in equity as a part of balance sheet as required by paragraph 10. The statement of changes in equity includes the following information:

- (a) total comprehensive income for the period, showing separately the total amounts attributable to owners of the parent and to non-controlling interests;
- (b) for each component of equity, the effects of retrospective application or retrospective restatement recognised in accordance with Ind AS 8;
- (c) [Refer to Appendix 1]
- (d) for each component of equity, a reconciliation between the carrying amount at the beginning and the end of the period, separately disclosing each changes resulting from:
 - (i) profit or loss;
 - (ii) each item of other comprehensive income;
 - (iii) transactions with owners in their capacity as owners, showing separately contributions by and distributions to owners and changes in ownership interests in subsidiaries that do not result in a loss of control; and
 - (iv) any item recognised directly in equity such as amount recognised directly in equity as capital reserve with paragraph 36A of Ind AS 103.

Information to be presented in the statement of changes in equity which is a part of the balance sheet or in the notes

- 106A For each component of equity an entity shall present, either in the statement of changes in equity or in the notes, an analysis of other comprehensive income by item (see paragraph 106 (d) (ii)).
- 107 An entity shall present, either in the statement of changes in equity or in the notes, the amount of dividends recognised as distributions to owners during the period, and the related amount of dividends per share.
- 108 In paragraph 106, the components of equity include, for example, each class of contributed equity, the accumulated balance of each class of other comprehensive income and retained earnings.
- 109 Changes in an entity's equity between the beginning and the end of the reporting period reflect the increase or decrease in its net assets during the period. Except for changes resulting from transactions with owners in their capacity as owners (such as equity contributions, reacquisitions of the entity's own equity instruments and dividends) and transaction costs directly related to such transactions, the overall change in equity during a period represents the total amount of income and expense, including gains and losses, generated by the entity's activities during that period.
- 110 Ind AS 8 requires retrospective adjustments to effect changes in accounting policies, to the extent practicable, except when the transition provisions in another Ind AS require otherwise. Ind AS 8 also requires restatements to correct errors to be made retrospectively, to the extent practicable. Retrospective adjustments and retrospective restatements are not changes in

equity but they are adjustments to the opening balance of retained earnings, except when an Ind AS requires retrospective adjustment of another component of equity. Paragraph 106(b) requires disclosure in the statement of changes in equity of the total adjustment to each component of equity resulting from changes in accounting policies and, separately, from corrections of errors. These adjustments are disclosed for each prior period and the beginning of the period.

Statement of cash flows

- 111 Cash flow information provides users of financial statements with a basis to assess the ability of the entity to generate cash and cash equivalents and the needs of the entity to utilise those cash flows. Ind AS 7 sets out requirements for the presentation and disclosure of cash flow information.

Notes

Structure

- 112 The notes shall:
- (a) present information about the basis of preparation of the financial statements and the specific accounting policies used in accordance with paragraphs 117–124;
 - (b) disclose the information required by Ind ASs that is not presented elsewhere in the financial statements; and
 - (c) provide information that is not presented elsewhere in the financial statements, but is relevant to an understanding of any of them.
- 113 An entity shall present notes in a systematic manner. An entity shall cross-reference each item in the balance sheet, in the statement of changes in equity which is a part of the balance sheet and in the statement of profit and loss, and statement of cash flows to any related information in the notes.
- 114 An entity normally presents notes in the following order, to assist users to understand the financial statements and to compare them with financial statements of other entities:
- (a) statement of compliance with Ind ASs (see paragraph 16);
 - (b) summary of significant accounting policies applied (see paragraph 117);
 - (c) supporting information for items presented in the balance sheet, in the statement of changes in equity which is a part of the balance sheet, in the statement of profit and loss, and statement cash flows, in the order in which each statement and each line item is presented; and
 - (d) other disclosures, including:
 - (i) contingent liabilities (see Ind AS 37) and unrecognised contractual commitments, and

- (ii) non-financial disclosures, eg the entity's financial risk management objectives and policies (see Ind AS 107).

- 115 In some circumstances, it may be necessary or desirable to vary the order of specific items within the notes. For example, an entity may combine information on changes in fair value recognised in profit or loss with information on maturities of financial instruments, although the former disclosures relate to the statement of profit and loss and the latter relate to the balance sheet. Nevertheless, an entity retains a systematic structure for the notes as far as practicable.
- 116 An entity may present notes providing information about the basis of preparation of the financial statements and specific accounting policies as a separate section of the financial statements.

Disclosure of accounting policies

- 117 An entity shall disclose in the summary of significant accounting policies:
- (a) the measurement basis (or bases) used in preparing the financial statements, and
 - (b) the other accounting policies used that are relevant to an understanding of the financial statements.
- 118 It is important for an entity to inform users of the measurement basis or bases used in the financial statements (for example, historical cost, current cost, net realisable value, fair value or recoverable amount) because the basis on which an entity prepares the financial statements significantly affects users' analysis. When an entity uses more than one measurement basis in the financial statements, for example when particular classes of assets are revalued, it is sufficient to provide an indication of the categories of assets and liabilities to which each measurement basis is applied.
- 119 In deciding whether a particular accounting policy should be disclosed, management considers whether disclosure would assist users in understanding how transactions, other events and conditions are reflected in reported financial performance and financial position. Disclosure of particular accounting policies is especially useful to users when those policies are selected from alternatives allowed in Ind ASs. An example is disclosure of whether a venturer recognises its interest in a jointly controlled entity using proportionate consolidation or the equity method (see Ind AS 31 *Interests in Joint Ventures*). Some Ind ASs specifically require disclosure of particular accounting policies, including choices made by management between different policies they allow. For example, Ind AS 16 requires disclosure of the measurement bases used for classes of property, plant and equipment.
- 120 Each entity considers the nature of its operations and the policies that the users of its financial statements would expect to be disclosed for that type of entity. For example, users would expect an entity subject to income taxes to disclose its accounting policies for income taxes, including those applicable to deferred tax liabilities and assets. When an entity has significant foreign operations or transactions in foreign currencies, users would expect disclosure

of accounting policies for the recognition of foreign exchange gains and losses.

- 121 An accounting policy may be significant because of the nature of the entity's operations even if amounts for current and prior periods are not material. It is also appropriate to disclose each significant accounting policy that is not specifically required by Ind ASs but the entity selects and applies in accordance with Ind AS 8.
- 122 An entity shall disclose, in the summary of significant accounting policies or other notes, the judgements, apart from those involving estimations (see paragraph 125), that management has made in the process of applying the entity's accounting policies and that have the most significant effect on the amounts recognised in the financial statements.
- 123 In the process of applying the entity's accounting policies, management makes various judgements, apart from those involving estimations, that can significantly affect the amounts it recognises in the financial statements. For example, management makes judgements in determining:
- (a) whether financial assets are held-to-maturity investments;
 - (b) when substantially all the significant risks and rewards of ownership of financial assets and lease assets are transferred to other entities;
 - (c) whether, in substance, particular sales of goods are financing arrangements and therefore do not give rise to revenue; and
 - (d) whether the substance of the relationship between the entity and a special purpose entity indicates that the entity controls the special purpose entity.
- 124 Some of the disclosures made in accordance with paragraph 122 are required by other Ind ASs. For example, Ind AS 27 requires an entity to disclose the reasons why the entity's ownership interest does not constitute control, in respect of an investee that is not a subsidiary even though more than half of its voting or potential voting power is owned directly or indirectly through subsidiaries. Ind AS 40 *Investment Property* requires disclosure of the criteria developed by the entity to distinguish investment property from owner-occupied property and from property held for sale in the ordinary course of business, when classification of the property is difficult.

Sources of estimation uncertainty

- 125 An entity shall disclose information about the assumptions it makes about the future, and other major sources of estimation uncertainty at the end of the reporting period, that have a significant risk of resulting in a material adjustment to the carrying amounts of assets and liabilities within the next financial year. In respect of those assets and liabilities, the notes shall include details of:
- (a) their nature, and
 - (b) their carrying amount as at the end of the reporting period.

- 126 Determining the carrying amounts of some assets and liabilities requires estimation of the effects of uncertain future events on those assets and liabilities at the end of the reporting period. For example, in the absence of recently observed market prices, future-oriented estimates are necessary to measure the recoverable amount of classes of property, plant and equipment, the effect of technological obsolescence on inventories, provisions subject to the future outcome of litigation in progress, and long-term employee benefit liabilities such as pension obligations. These estimates involve assumptions about such items as the risk adjustment to cash flows or discount rates, future changes in salaries and future changes in prices affecting other costs.
- 127 The assumptions and other sources of estimation uncertainty disclosed in accordance with paragraph 125 relate to the estimates that require management's most difficult, subjective or complex judgements. As the number of variables and assumptions affecting the possible future resolution of the uncertainties increases, those judgements become more subjective and complex, and the potential for a consequential material adjustment to the carrying amounts of assets and liabilities normally increases accordingly.
- 128 The disclosures in paragraph 125 are not required for assets and liabilities with a significant risk that their carrying amounts might change materially within the next financial year if, at the end of the reporting period, they are measured at fair value based on recently observed market prices. Such fair values might change materially within the next financial year but these changes would not arise from assumptions or other sources of estimation uncertainty at the end of the reporting period.
- 129 An entity presents the disclosures in paragraph 125 in a manner that helps users of financial statements to understand the judgements that management makes about the future and about other sources of estimation uncertainty. The nature and extent of the information provided vary according to the nature of the assumption and other circumstances. Examples of the types of disclosures an entity makes are:
- (a) the nature of the assumption or other estimation uncertainty;
 - (b) the sensitivity of carrying amounts to the methods, assumptions and estimates underlying their calculation, including the reasons for the sensitivity;
 - (c) the expected resolution of an uncertainty and the range of reasonably possible outcomes within the next financial year in respect of the carrying amounts of the assets and liabilities affected; and
 - (d) an explanation of changes made to past assumptions concerning those assets and liabilities, if the uncertainty remains unresolved.
- 130 This Standard does not require an entity to disclose budget information or forecasts in making the disclosures in paragraph 125.
- 131 Sometimes it is impracticable to disclose the extent of the possible effects of an assumption or another source of estimation uncertainty at the end of the reporting period. In such cases, the entity discloses that it is reasonably possible, on the basis of existing knowledge, that outcomes within the next financial year that are different from the assumption could require a material

adjustment to the carrying amount of the asset or liability affected. In all cases, the entity discloses the nature and carrying amount of the specific asset or liability (or class of assets or liabilities) affected by the assumption.

- 132 The disclosures in paragraph 122 of particular judgements that management made in the process of applying the entity's accounting policies do not relate to the disclosures of sources of estimation uncertainty in paragraph 125.
- 133 Other Ind ASs require the disclosure of some of the assumptions that would otherwise be required in accordance with paragraph 125. For example, Ind AS 37 requires disclosure, in specified circumstances, of major assumptions concerning future events affecting classes of provisions. Ind AS 107 requires disclosure of significant assumptions the entity uses in estimating the fair values of financial assets and financial liabilities that are carried at fair value. Ind AS 16 requires disclosure of significant assumptions that the entity uses in estimating the fair values of revalued items of property, plant and equipment.

Capital

- 134 **An entity shall disclose information that enables users of its financial statements to evaluate the entity's objectives, policies and processes for managing capital.**
- 135 To comply with paragraph 134, the entity discloses the following:
- (a) qualitative information about its objectives, policies and processes for managing capital, including:
 - (i) a description of what it manages as capital;
 - (ii) when an entity is subject to externally imposed capital requirements, the nature of those requirements and how those requirements are incorporated into the management of capital; and
 - (iii) how it is meeting its objectives for managing capital.
 - (b) summary quantitative data about what it manages as capital. Some entities regard some financial liabilities (eg some forms of subordinated debt) as part of capital. Other entities regard capital as excluding some components of equity (eg components arising from cash flow hedges).
 - (c) any changes in (a) and (b) from the previous period.
 - (d) whether during the period it complied with any externally imposed capital requirements to which it is subject.
 - (e) when the entity has not complied with such externally imposed capital requirements, the consequences of such non-compliance.

The entity bases these disclosures on the information provided internally to key management personnel.

- 136 An entity may manage capital in a number of ways and be subject to a number of different capital requirements. For example, a conglomerate may include entities that undertake insurance activities and banking activities and those entities may operate in several jurisdictions. When an aggregate disclosure of

capital requirements and how capital is managed would not provide useful information or distorts a financial statement user's understanding of an entity's capital resources, the entity shall disclose separate information for each capital requirement to which the entity is subject.

Puttable financial instruments classified as equity

136A For puttable financial instruments classified as equity instruments, an entity shall disclose (to the extent not disclosed elsewhere):

- (a) summary quantitative data about the amount classified as equity;
- (b) its objectives, policies and processes for managing its obligation to repurchase or redeem the instruments when required to do so by the instrument holders, including any changes from the previous period;
- (c) the expected cash outflow on redemption or repurchase of that class of financial instruments; and
- (d) information about how the expected cash outflow on redemption or repurchase was determined.

Other disclosures

137 An entity shall disclose in the notes:

- (a) the amount of dividends proposed or declared before the financial statements were approved for issue but not recognised as a distribution to owners during the period, and the related amount per share; and
- (b) the amount of any cumulative preference dividends not recognised.

138 An entity shall disclose the following, if not disclosed elsewhere in information published with the financial statements:

- (a) the domicile and legal form of the entity, its country of incorporation and the address of its registered office (or principal place of business, if different from the registered office);
- (b) a description of the nature of the entity's operations and its principal activities;
- (c) the name of the parent and the ultimate parent of the group; and
- (d) if it is a limited life entity, information regarding the length of its life.

Appendix A

References to matters contained in other Indian Accounting Standards

This Appendix is an integral part of Indian Accounting Standard (Ind AS) 1.

This appendix lists the different appendices which are the part of other Indian Accounting Standards and make reference to Ind AS 1:

1. *Appendix A Distributions of Non-cash Assets to Owners contained in Ind AS 10 Events after the Reporting Period*
2. *Appendix A Changes in Existing Decommissioning, Restoration and Similar Liabilities contained in Ind AS 16, Property, Plant and Equipment*
3. *Appendix A IAS 19—The Limit on a Defined Benefit Asset, Minimum Funding Requirements and their Interaction contained in Ind AS 19 Employee Benefits*
4. *Appendix A Intangible Assets—Web Site Costs contained in Ind AS 38, Intangible Assets*
5. *Appendix E Extinguishing Financial Liabilities with Equity Instruments contained in Ind AS 39 Financial Instruments: Recognition and Measurement.*

Appendix 1

Note: This Appendix is not a part of the Indian Accounting Standard. The purpose of this Appendix is only to bring out the differences, if any, between Indian Accounting Standard (Ind AS) 1 and the corresponding International Accounting Standard (IAS) 1, Presentation of Financial Statements.

Comparison with IAS 1, Presentation of Financial Statements

- 1 With regard to preparation of Statement of profit and loss, International Accounting Standard (IAS) 1, *Presentation of Financial Statements*, provides an option either to follow the single statement approach or to follow the two statement approach. While in the single statement approach, all items of income and expense are recognised in the statement of profit and loss, in the two statements approach, two statements are prepared, one displaying components of profit or loss (separate income statement) and the other beginning with profit or loss and displaying components of other comprehensive income. Ind AS 1 allows only the single statement approach. Paragraph 84 of IAS 1 is with reference to the two statement approach. As Ind

- AS 1 does not allow the aforesaid option, the paragraph 84 is deleted. However, paragraph number 84 has been retained in Ind AS 1 to maintain consistency with paragraph numbers of IAS 1.
- 2 IAS 1 requires preparation of a Statement of Changes in Equity as a separate statement. Ind AS 1 requires the statement of changes in equity to be shown as a part of the balance sheet. Paragraph 10(c) of IAS 1 is with reference to the separate statement of changes in equity. As Ind AS 1 does not require it, the same is deleted. However, paragraph number 10(c) has been retained in Ind AS 1 to maintain consistency with paragraph numbers of IAS 1
 - 3 Different terminology is used in Ind AS 1 e.g., the term 'balance sheet' is used instead of 'Statement of financial position' and 'Statement of Profit and Loss' is used instead of 'Statement of comprehensive income'. The words 'approval of the financial statements for issue' have been used instead of 'authorisation of the financial statements for issue' in the context of financial statements considered for the purpose of events after the reporting period.
 - 4 Paragraph 8 of IAS 1 gives the option to individual entities to follow different terminology for the titles of financial statements. Ind AS 1 is changed to remove alternatives by giving one terminology to be used by all entities. However, paragraph number 8 has been retained in Ind AS 1 to maintain consistency with paragraph numbers of IAS 1.
 - 5 Paragraph 37 of IAS 1 permits the periodicity, for example, of 52 weeks for preparation of financial statements. As Ind AS 1 does not permit it, the same is deleted. However, paragraph number 37 has been retained in Ind AS 1 to maintain consistency with paragraph numbers of IAS 1.
 - 6 Paragraph 99 of IAS 1 requires an entity to present an analysis of expenses recognised in profit or loss using a classification based on either their nature or their function within the equity. Ind AS 1 requires only nature-wise classification of expenses. In IAS 1 the following paragraphs are with reference to function-wise classification of expense. In order to maintain consistency with paragraph numbers of IAS 1, the paragraph numbers are retained in Ind AS 1 :
 - (i) Paragraph 103
 - (ii) Paragraph 104
 - (iii) Paragraph 105
 - 7 IAS 1 contains Implementation Guidance. Ind AS 1 does not include the same because various enactments have prescribed formats, e.g., Schedule VI to the Companies Act, 1956.
 - 8 Paragraph number 106(c) appears as 'Deleted' in IAS 1. In order to maintain consistency with paragraph numbers of IAS 1, the paragraph number is retained in Ind AS 1.
 - 9 Cross-reference to paragraph 93A of IAS 19 has been modified as cross reference to paragraphs 92 and 129A of Ind AS 19 as a result of certain changes in Ind AS 19 as compared to IAS 19.

Indian Accounting Standard (Ind AS) 16

Property, Plant and Equipment

*(This Indian Accounting Standard includes paragraphs set in **bold type** and plain type, which have equal authority. Paragraphs in bold type indicate the main principles.)*

Objective

1. The objective of this Standard is to prescribe the accounting treatment for property, plant and equipment so that users of the financial statements can discern information about an entity's investment in its property, plant and equipment and the changes in such investment. The principal issues in accounting for property, plant and equipment are the recognition of the assets, the determination of their carrying amounts and the depreciation charges and impairment losses to be recognised in relation to them.

Scope

2. **This Standard shall be applied in accounting for property, plant and equipment except when another Standard requires or permits a different accounting treatment.**
3. This Standard does not apply to:
 - (a) property, plant and equipment classified as held for sale in accordance with Ind AS 105 *Non-current Assets Held for Sale and Discontinued Operations*;
 - (b) biological assets related to agricultural activity (See Ind AS 41, *Agriculture*¹);
 - (c) the recognition and measurement of exploration and evaluation assets (see Ind AS 106 *Exploration for and Evaluation of Mineral Resources*); or
 - (d) mineral rights and mineral reserves such as oil, natural gas and similar non-regenerative resources.

However, this Standard applies to property, plant and equipment used to develop or maintain the assets described in (b)–(d).

¹ Indian Accounting Standard (Ind AS) 41, *Agriculture*, is under formulation.

4. Other Indian Accounting Standards may require recognition of an item of property, plant and equipment based on an approach different from that in this Standard. For example, Ind AS 17 *Leases* requires an entity to evaluate its recognition of an item of leased property, plant and equipment on the basis of the transfer of risks and rewards. However, in such cases other aspects of the accounting treatment for these assets, including depreciation, are prescribed by this Standard.
5. An entity accounting for investment property in accordance with Ind AS 40 *Investment Property* shall use the cost model in this Standard.

Definitions

6. The following terms are used in this Standard with the meanings specified:

Carrying amount is the amount at which an asset is recognised after deducting any accumulated depreciation and accumulated impairment losses.

Cost is the amount of cash or cash equivalents paid or the fair value of the other consideration given to acquire an asset at the time of its acquisition or construction or, where applicable, the amount attributed to that asset when initially recognised in accordance with the specific requirements of other Indian Accounting Standards, eg Ind AS 102 *Share-based Payment*.

Depreciable amount is the cost of an asset, or other amount substituted for cost, less its residual value.

Depreciation is the systematic allocation of the depreciable amount of an asset over its useful life.

Entity-specific value is the present value of the cash flows an entity expects to arise from the continuing use of an asset and from its disposal at the end of its useful life or expects to incur when settling a liability.

Fair value is the amount for which an asset could be exchanged between knowledgeable, willing parties in an arm's length transaction.

An impairment loss is the amount by which the carrying amount of an asset exceeds its recoverable amount.

Property, plant and equipment are tangible items that:

- (a) are held for use in the production or supply of goods or services, for rental to others, or for administrative purposes; and
- (b) are expected to be used during more than one period.

Recoverable amount is the higher of an asset's fair value less costs to sell and its value in use.

The residual value of an asset is the estimated amount that an entity would currently obtain from disposal of the asset, after deducting the estimated costs of disposal, if the asset were already of the age and in the condition expected at the end of its useful life.

Useful life is:

- (a) the period over which an asset is expected to be available for use by an entity; or
- (b) the number of production or similar units expected to be obtained from the asset by an entity.

Recognition

- 7. The cost of an item of property, plant and equipment shall be recognised as an asset if, and only if:
 - (a) it is probable that future economic benefits associated with the item will flow to the entity; and
 - (b) the cost of the item can be measured reliably.
- 8. Spare parts and servicing equipment are usually carried as inventory and recognised in profit or loss as consumed. However, major spare parts, stand-by equipment and servicing equipment qualify as property, plant and equipment when an entity expects to use them during more than one period..
- 9. This Standard does not prescribe the unit of measure for recognition, ie what constitutes an item of property, plant and equipment. Thus, judgement is required in applying the recognition criteria to an entity's specific circumstances. It may be appropriate to aggregate individually insignificant items, such as moulds, tools and dies, and to apply the criteria to the aggregate value.
- 10. An entity evaluates under this recognition principle all its property, plant and equipment costs at the time they are incurred. These costs include costs incurred initially to acquire or construct an item of property, plant and equipment and costs incurred subsequently to add to, replace part of, or service it.

Initial costs

- 11. Items of property, plant and equipment may be acquired for safety or environmental reasons. The acquisition of such property, plant and equipment, although not directly increasing the future economic benefits of any particular existing item of property, plant and equipment, may be necessary for an entity to

obtain the future economic benefits from its other assets. Such items of property, plant and equipment qualify for recognition as assets because they enable an entity to derive future economic benefits from related assets in excess of what could be derived had those items not been acquired. For example, a chemical manufacturer may install new chemical handling processes to comply with environmental requirements for the production and storage of dangerous chemicals; related plant enhancements are recognised as an asset because without them the entity is unable to manufacture and sell chemicals. However, the resulting carrying amount of such an asset and related assets is reviewed for impairment in accordance with Ind AS 36 *Impairment of Assets*.

Subsequent costs

12. Under the recognition principle in paragraph 7, an entity does not recognise in the carrying amount of an item of property, plant and equipment the costs of the day-to-day servicing of the item. Rather, these costs are recognised in profit or loss as incurred. Costs of day-to-day servicing are primarily the costs of labour and consumables, and may include the cost of small parts. The purpose of these expenditures is often described as for the 'repairs and maintenance' of the item of property, plant and equipment.
13. Parts of some items of property, plant and equipment may require replacement at regular intervals. For example, a furnace may require relining after a specified number of hours of use, or aircraft interiors such as seats and galleys may require replacement several times during the life of the airframe. Items of property, plant and equipment may also be acquired to make a less frequently recurring replacement, such as replacing the interior walls of a building, or to make a nonrecurring replacement. Under the recognition principle in paragraph 7, an entity recognises in the carrying amount of an item of property, plant and equipment the cost of replacing part of such an item when that cost is incurred if the recognition criteria are met. The carrying amount of those parts that are replaced is derecognised in accordance with the derecognition provisions of this Standard (see paragraphs 67–72).
14. A condition of continuing to operate an item of property, plant and equipment (for example, an aircraft) may be performing regular major inspections for faults regardless of whether parts of the item are replaced. When each major inspection is performed, its cost is recognised in the carrying amount of the item of property, plant and equipment as a replacement if the recognition criteria are satisfied. Any remaining carrying amount of the cost of the previous inspection (as distinct from physical parts) is derecognised. This occurs regardless of whether the cost of the previous inspection was identified in the transaction in which the item was acquired or constructed. If necessary, the estimated cost of a future similar inspection may be used as an indication of what the cost of the existing inspection component was when the item was acquired or constructed.

Measurement at recognition

15. **An item of property, plant and equipment that qualifies for recognition as an asset shall be measured at its cost.**

Elements of cost

16. The cost of an item of property, plant and equipment comprises:
 - (a) its purchase price, including import duties and non-refundable purchase taxes, after deducting trade discounts and rebates.

- (b) any costs directly attributable to bringing the asset to the location and condition necessary for it to be capable of operating in the manner intended by management.
- (c) the initial estimate of the costs of dismantling and removing the item and restoring the site on which it is located, the obligation for which an entity incurs either when the item is acquired or as a consequence of having used the item during a particular period for purposes other than to produce inventories during that period.

17. Examples of directly attributable costs are:

- (a) costs of employee benefits (as defined in Ind AS 19 *Employee Benefits*) arising directly from the construction or acquisition of the item of property, plant and equipment;
- (b) costs of site preparation;
- (c) initial delivery and handling costs;
- (d) installation and assembly costs;
- (e) costs of testing whether the asset is functioning properly, after deducting the net proceeds from selling any items produced while bringing the asset to that location and condition (such as samples produced when testing equipment); and
- (f) professional fees.

18. An entity applies Ind AS 2 *Inventories* to the costs of obligations for dismantling, removing and restoring the site on which an item is located that are incurred during a particular period as a consequence of having used the item to produce inventories during that period. The obligations for costs accounted for in accordance with Ind AS 2 or Ind AS 16 are recognised and measured in accordance with Ind AS 37 *Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets*.

19. Examples of costs that are not costs of an item of property, plant and equipment are:

- (a) costs of opening a new facility;
- (b) costs of introducing a new product or service (including costs of advertising and promotional activities);
- (c) costs of conducting business in a new location or with a new class of customer (including costs of staff training); and

(d) administration and other general overhead costs.

20. Recognition of costs in the carrying amount of an item of property, plant and equipment ceases when the item is in the location and condition necessary for it to be capable of operating in the manner intended by management. Therefore, costs incurred in using or redeploying an item are not included in the carrying amount of that item. For example, the following costs are not included in the carrying amount of an item of property, plant and equipment:

- (a) costs incurred while an item capable of operating in the manner intended by management has yet to be brought into use or is operated at less than full capacity;
- (b) initial operating losses, such as those incurred while demand for the item's output builds up; and
- (c) costs of relocating or reorganising part or all of an entity's operations.

1. Some operations occur in connection with the construction or development of an item of property, plant and equipment, but are not necessary to bring the item to the location and condition necessary for it to be capable of operating in the manner intended by management. These incidental operations may occur before or during the construction or development activities. For example, income may be earned through using a building site as a car park until construction starts. Because incidental operations are not necessary to bring an item to the location and condition necessary for it to be capable of operating in the manner intended by management, the income and related expenses of incidental operations are recognised in profit or loss and included in their respective classifications of income and expense.
22. The cost of a self-constructed asset is determined using the same principles as for an acquired asset. If an entity makes similar assets for sale in the normal course of business, the cost of the asset is usually the same as the cost of constructing an asset for sale (see Ind AS 2). Therefore, any internal profits are eliminated in arriving at such costs. Similarly, the cost of abnormal amounts of wasted material, labour, or other resources incurred in self-constructing an asset is not included in the cost of the asset. Ind AS 23 *Borrowing Costs* establishes criteria for the recognition of interest as a component of the carrying amount of a self-constructed item of property, plant and equipment.

Measurement of cost

23. The cost of an item of property, plant and equipment is the cash price equivalent at the recognition date. If payment is deferred beyond normal credit terms, the difference between the cash price equivalent and the total payment is recognised as interest over the period of credit unless such interest is capitalised in accordance with Ind AS 23.

24. One or more items of property, plant and equipment may be acquired in exchange for a non-monetary asset or assets, or a combination of monetary and non-monetary assets. The following discussion refers simply to an exchange of one non-monetary asset for another, but it also applies to all exchanges described in the preceding sentence. The cost of such an item of property, plant and equipment is measured at fair value unless (a) the exchange transaction lacks commercial substance or (b) the fair value of neither the asset received nor the asset given up is reliably measurable. The acquired item is measured in this way even if an entity cannot immediately derecognise the asset given up. If the acquired item is not measured at fair value, its cost is measured at the carrying amount of the asset given up.
25. An entity determines whether an exchange transaction has commercial substance by considering the extent to which its future cash flows are expected to change as a result of the transaction. An exchange transaction has commercial substance if:
- (a) the configuration (risk, timing and amount) of the cash flows of the asset received differs from the configuration of the cash flows of the asset transferred; or
 - (b) the entity-specific value of the portion of the entity's operations affected by the transaction changes as a result of the exchange; and
 - (c) the difference in (a) or (b) is significant relative to the fair value of the assets exchanged.

For the purpose of determining whether an exchange transaction has commercial substance, the entity-specific value of the portion of the entity's operations affected by the transaction shall reflect post-tax cash flows. The result of these analyses may be clear without an entity having to perform detailed calculations.

26. The fair value of an asset for which comparable market transactions do not exist is reliably measurable if (a) the variability in the range of reasonable fair value estimates is not significant for that asset or (b) the probabilities of the various estimates within the range can be reasonably assessed and used in estimating fair value. If an entity is able to determine reliably the fair value of either the asset received or the asset given up, then the fair value of the asset given up is used to measure the cost of the asset received unless the fair value of the asset received is more clearly evident.
27. The cost of an item of property, plant and equipment held by a lessee under a finance lease is determined in accordance with Ind AS 17.
28. [Refer to Appendix 1].

Measurement after recognition

29. An entity shall choose either the cost model in paragraph 30 or the revaluation model in paragraph 31 as its accounting policy and shall apply that policy to an entire class of property, plant and equipment.

Cost model

30. After recognition as an asset, an item of property, plant and equipment shall be carried at its cost less any accumulated depreciation and any accumulated impairment losses.

Revaluation model

31. After recognition as an asset, an item of property, plant and equipment whose fair value can be measured reliably shall be carried at a revalued amount, being its fair value at the date of the revaluation less any subsequent accumulated depreciation and subsequent accumulated impairment losses. Revaluations shall be made with sufficient regularity to ensure that the carrying amount does not differ materially from that which would be determined using fair value at the end of the reporting period.
32. The fair value of land and buildings is usually determined from market-based evidence by appraisal that is normally undertaken by professionally qualified valuers. The fair value of items of plant and equipment is usually their market value determined by appraisal.
33. If there is no market-based evidence of fair value because of the specialised nature of the item of property, plant and equipment and the item is rarely sold, except as part of a continuing business, an entity may need to estimate fair value using an income or a depreciated replacement cost approach.
34. The frequency of revaluations depends upon the changes in fair values of the items of property, plant and equipment being revalued. When the fair value of a revalued asset differs materially from its carrying amount, a further revaluation is required. Some items of property, plant and equipment experience significant and volatile changes in fair value, thus necessitating annual revaluation. Such frequent revaluations are unnecessary for items of property, plant and equipment with only insignificant changes in fair value. Instead, it may be necessary to revalue the item only every three or five years.
35. When an item of property, plant and equipment is revalued, any accumulated depreciation at the date of the revaluation is treated in one of the following ways:

- (a) restated proportionately with the change in the gross carrying amount of the asset so that the carrying amount of the asset after revaluation equals its revalued amount. This method is often used when an asset is revalued by means of applying an index to determine its depreciated replacement cost.
- (b) eliminated against the gross carrying amount of the asset and the net amount restated to the revalued amount of the asset. This method is often used for buildings.

The amount of the adjustment arising on the restatement or elimination of accumulated depreciation forms part of the increase or decrease in carrying amount that is accounted for in accordance with paragraphs 39 and 40.

- 36. **If an item of property, plant and equipment is revalued, the entire class of property, plant and equipment to which that asset belongs shall be revalued.**
- 37. A class of property, plant and equipment is a grouping of assets of a similar nature and use in an entity's operations. The following are examples of separate classes:
 - (i) land;
 - (ii) land and buildings;
 - (iii) machinery;
 - (iv) ships;
 - (v) aircraft;
 - (vi) motor vehicles;
 - (vii) furniture and fixtures; and
 - (viii) office equipment.
- 38. The items within a class of property, plant and equipment are revalued simultaneously to avoid selective revaluation of assets and the reporting of amounts in the financial statements that are a mixture of costs and values as at different dates. However, a class of assets may be revalued on a rolling basis provided revaluation of the class of assets is completed within a short period and provided the revaluations are kept up to date.
- 39. **If an asset's carrying amount is increased as a result of a revaluation, the increase shall be recognised in other comprehensive income and accumulated in equity under the heading of revaluation surplus. However, the increase shall be recognised in profit or loss to the extent that it reverses a revaluation decrease of the same asset previously recognised in profit or loss.**

40. If an asset's carrying amount is decreased as a result of a revaluation, the decrease shall be recognised in profit or loss. However, the decrease shall be recognised in other comprehensive income to the extent of any credit balance existing in the revaluation surplus in respect of that asset. The decrease recognised in other comprehensive income reduces the amount accumulated in equity under the heading of revaluation surplus.
41. The revaluation surplus included in equity in respect of an item of property, plant and equipment may be transferred directly to retained earnings when the asset is derecognised. This may involve transferring the whole of the surplus when the asset is retired or disposed of. However, some of the surplus may be transferred as the asset is used by an entity. In such a case, the amount of the surplus transferred would be the difference between depreciation based on the revalued carrying amount of the asset and depreciation based on the asset's original cost. Transfers from revaluation surplus to retained earnings are not made through profit or loss.
42. The effects of taxes on income, if any, resulting from the revaluation of property, plant and equipment are recognised and disclosed in accordance with Ind AS 12 *Income Taxes*.

Depreciation

43. Each part of an item of property, plant and equipment with a cost that is significant in relation to the total cost of the item shall be depreciated separately.
44. An entity allocates the amount initially recognised in respect of an item of property, plant and equipment to its significant parts and depreciates separately each such part. For example, it may be appropriate to depreciate separately the airframe and engines of an aircraft, whether owned or subject to a finance lease. Similarly, if an entity acquires property, plant and equipment subject to an operating lease in which it is the lessor, it may be appropriate to depreciate separately amounts reflected in the cost of that item that are attributable to favourable or unfavourable lease terms relative to market terms.
45. A significant part of an item of property, plant and equipment may have a useful life and a depreciation method that are the same as the useful life and the depreciation method of another significant part of that same item. Such parts may be grouped in determining the depreciation charge.
46. To the extent that an entity depreciates separately some parts of an item of property, plant and equipment, it also depreciates separately the remainder of the item. The remainder consists of the parts of the item that are individually not significant. If an entity has varying expectations for these parts, approximation techniques may be necessary to depreciate the remainder in a manner that faithfully represents the consumption pattern and/or useful life of its parts.
47. An entity may choose to depreciate separately the parts of an item that do not have a cost that is significant in relation to the total cost of the item.

48. **The depreciation charge for each period shall be recognised in profit or loss unless it is included in the carrying amount of another asset.**
49. The depreciation charge for a period is usually recognised in profit or loss. However, sometimes, the future economic benefits embodied in an asset are absorbed in producing other assets. In this case, the depreciation charge constitutes part of the cost of the other asset and is included in its carrying amount. For example, the depreciation of manufacturing plant and equipment is included in the costs of conversion of inventories (see Ind AS 2). Similarly, depreciation of property, plant and equipment used for development activities may be included in the cost of an intangible asset recognised in accordance with Ind AS 38 *Intangible Assets*.

Depreciable amount and depreciation period

50. **The depreciable amount of an asset shall be allocated on a systematic basis over its useful life.**
51. **The residual value and the useful life of an asset shall be reviewed at least at each financial year-end and, if expectations differ from previous estimates, the change(s) shall be accounted for as a change in an accounting estimate in accordance with Ind AS 8 *Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors*.**
52. Depreciation is recognised even if the fair value of the asset exceeds its carrying amount, as long as the asset's residual value does not exceed its carrying amount. Repair and maintenance of an asset do not negate the need to depreciate it.
53. The depreciable amount of an asset is determined after deducting its residual value. In practice, the residual value of an asset is often insignificant and therefore immaterial in the calculation of the depreciable amount.
54. The residual value of an asset may increase to an amount equal to or greater than the asset's carrying amount. If it does, the asset's depreciation charge is zero unless and until its residual value subsequently decreases to an amount below the asset's carrying amount.
55. Depreciation of an asset begins when it is available for use, ie when it is in the location and condition necessary for it to be capable of operating in the manner intended by management. Depreciation of an asset ceases at the earlier of the date that the asset is classified as held for sale (or included in a disposal group that is classified as held for sale) in accordance with Ind AS 109 and the date that the asset is derecognised. Therefore, depreciation does not cease when the asset becomes idle or is retired from active use unless the asset is fully depreciated. However, under usage methods of depreciation the depreciation charge can be zero while there is no production.

56. The future economic benefits embodied in an asset are consumed by an entity principally through its use. However, other factors, such as technical or commercial obsolescence and wear and tear while an asset remains idle, often result in the diminution of the economic benefits that might have been obtained from the asset. Consequently, all the following factors are considered in determining the useful life of an asset:
- (a) expected usage of the asset. Usage is assessed by reference to the asset's expected capacity or physical output.
 - (b) expected physical wear and tear, which depends on operational factors such as the number of shifts for which the asset is to be used and the repair and maintenance programme, and the care and maintenance of the asset while idle.
 - (c) technical or commercial obsolescence arising from changes or improvements in production, or from a change in the market demand for the product or service output of the asset.
 - (d) legal or similar limits on the use of the asset, such as the expiry dates of related leases.
57. The useful life of an asset is defined in terms of the asset's expected utility to the entity. The asset management policy of the entity may involve the disposal of assets after a specified time or after consumption of a specified proportion of the future economic benefits embodied in the asset. Therefore, the useful life of an asset may be shorter than its economic life. The estimation of the useful life of the asset is a matter of judgement based on the experience of the entity with similar assets.
58. Land and buildings are separable assets and are accounted for separately, even when they are acquired together. With some exceptions, such as quarries and sites used for landfill, land has an unlimited useful life and therefore is not depreciated. Buildings have a limited useful life and therefore are depreciable assets. An increase in the value of the land on which a building stands does not affect the determination of the depreciable amount of the building.
59. If the cost of land includes the costs of site dismantlement, removal and restoration, that portion of the land asset is depreciated over the period of benefits obtained by incurring those costs. In some cases, the land itself may have a limited useful life, in which case it is depreciated in a manner that reflects the benefits to be derived from it.

Depreciation method

60. The depreciation method used shall reflect the pattern in which the asset's future economic benefits are expected to be consumed by the entity.

61. **The depreciation method applied to an asset shall be reviewed at least at each financial year-end and, if there has been a significant change in the expected pattern of consumption of the future economic benefits embodied in the asset, the method shall be changed to reflect the changed pattern. Such a change shall be accounted for as a change in an accounting estimate in accordance with Ind AS 8.**
62. A variety of depreciation methods can be used to allocate the depreciable amount of an asset on a systematic basis over its useful life. These methods include the straight-line method, the diminishing balance method and the units of production method. Straight-line depreciation results in a constant charge over the useful life if the asset's residual value does not change. The diminishing balance method results in a decreasing charge over the useful life. The units of production method results in a charge based on the expected use or output. The entity selects the method that most closely reflects the expected pattern of consumption of the future economic benefits embodied in the asset. That method is applied consistently from period to period unless there is a change in the expected pattern of consumption of those future economic benefits.

Impairment

63. To determine whether an item of property, plant and equipment is impaired, an entity applies Ind AS 36 *Impairment of Assets*. That Standard explains how an entity reviews the carrying amount of its assets, how it determines the recoverable amount of an asset, and when it recognises, or reverses the recognition of, an impairment loss.
64. [Refer Appendix 1]

Compensation for impairment

65. **Compensation from third parties for items of property, plant and equipment that were impaired, lost or given up shall be included in profit or loss when the compensation becomes receivable.**
66. Impairments or losses of items of property, plant and equipment, related claims for or payments of compensation from third parties and any subsequent purchase or construction of replacement assets are separate economic events and are accounted for separately as follows:
- (a) impairments of items of property, plant and equipment are recognised in accordance with Ind AS 36;
 - (b) derecognition of items of property, plant and equipment retired or disposed of is determined in accordance with this Standard;
 - (c) compensation from third parties for items of property, plant and equipment that were impaired, lost or given up is included in determining profit or loss when it becomes receivable; and

- (d) the cost of items of property, plant and equipment restored, purchased or constructed as replacements is determined in accordance with this Standard.

Derecognition

67. **The carrying amount of an item of property, plant and equipment shall be derecognised:**
- (a) **on disposal; or**
 - (b) **when no future economic benefits are expected from its use or disposal.**
68. **The gain or loss arising from the derecognition of an item of property, plant and equipment shall be included in profit or loss when the item is derecognised (unless Ind AS 17 requires otherwise on a sale and leaseback). Gains shall not be classified as revenue.**
- 68A However, an entity that, in the course of its ordinary activities, routinely sells items of property, plant and equipment that it has held for rental to others shall transfer such assets to inventories at their carrying amount when they cease to be rented and become held for sale. The proceeds from the sale of such assets shall be recognised as revenue in accordance with Ind AS 18 *Revenue*. Ind AS 105 does not apply when assets that are held for sale in the ordinary course of business are transferred to inventories.
69. The disposal of an item of property, plant and equipment may occur in a variety of ways (eg by sale, by entering into a finance lease or by donation). In determining the date of disposal of an item, an entity applies the criteria in Ind AS 18 for recognising revenue from the sale of goods. Ind AS 17 applies to disposal by a sale and leaseback.
70. If, under the recognition principle in paragraph 7, an entity recognises in the carrying amount of an item of property, plant and equipment the cost of a replacement for part of the item, then it derecognises the carrying amount of the replaced part regardless of whether the replaced part had been depreciated separately. If it is not practicable for an entity to determine the carrying amount of the replaced part, it may use the cost of the replacement as an indication of what the cost of the replaced part was at the time it was acquired or constructed.
71. **The gain or loss arising from the derecognition of an item of property, plant and equipment shall be determined as the difference between the net disposal proceeds, if any, and the carrying amount of the item.**
72. The consideration receivable on disposal of an item of property, plant and equipment is recognised initially at its fair value. If payment for the item is deferred, the consideration received is recognised initially at the cash price equivalent. The difference between the nominal amount of the consideration and the cash price equivalent is recognised as interest revenue in accordance with Ind AS 18 reflecting the effective yield on the receivable.

Disclosure

73. The financial statements shall disclose, for each class of property, plant and equipment:
- (a) the measurement bases used for determining the gross carrying amount;
 - (b) the depreciation methods used;
 - (c) the useful lives or the depreciation rates used;
 - (d) the gross carrying amount and the accumulated depreciation (aggregated with accumulated impairment losses) at the beginning and end of the period; and
 - (e) a reconciliation of the carrying amount at the beginning and end of the period showing:
 - (i) additions;
 - (ii) assets classified as held for sale or included in a disposal group classified as held for sale in accordance with Ind AS 105 and other disposals;
 - (iii) acquisitions through business combinations;
 - (iv) increases or decreases resulting from revaluations under paragraphs 31, 39 and 40 and from impairment losses recognised or reversed in other comprehensive income in accordance with Ind AS 36;
 - (v) impairment losses recognised in profit or loss in accordance with Ind AS 36;
 - (vi) impairment losses reversed in profit or loss in accordance with Ind AS 36;
 - (vii) depreciation;
 - (viii) the net exchange differences arising on the translation of the financial statements from the functional currency into a different presentation currency, including the translation of a foreign operation into the presentation currency of the reporting entity; and
 - (ix) other changes.
74. The financial statements shall also disclose:
- (a) the existence and amounts of restrictions on title, and property, plant and equipment pledged as security for liabilities;

- (b) the amount of expenditures recognised in the carrying amount of an item of property, plant and equipment in the course of its construction;**
 - (c) the amount of contractual commitments for the acquisition of property, plant and equipment; and**
 - (d) if it is not disclosed separately in the statement of profit and loss, the amount of compensation from third parties for items of property, plant and equipment that were impaired, lost or given up that is included in profit or loss.**
75. Selection of the depreciation method and estimation of the useful life of assets are matters of judgement. Therefore, disclosure of the methods adopted and the estimated useful lives or depreciation rates provides users of financial statements with information that allows them to review the policies selected by management and enables comparisons to be made with other entities. For similar reasons, it is necessary to disclose:
- (a) depreciation, whether recognised in profit or loss or as a part of the cost of other assets, during a period; and
 - (b) accumulated depreciation at the end of the period.
76. In accordance with Ind AS 8 an entity discloses the nature and effect of a change in an accounting estimate that has an effect in the current period or is expected to have an effect in subsequent periods. For property, plant and equipment, such disclosure may arise from changes in estimates with respect to:
- (a) residual values;
 - (b) the estimated costs of dismantling, removing or restoring items of property, plant and equipment;
 - (c) useful lives; and
 - (d) depreciation methods.
77. If items of property, plant and equipment are stated at revalued amounts, the following shall be disclosed:
- (a) the effective date of the revaluation;
 - (b) whether an independent valuer was involved;
 - (c) the methods and significant assumptions applied in estimating the items' fair values;

- (d) the extent to which the items' fair values were determined directly by reference to observable prices in an active market or recent market transactions on arm's length terms or were estimated using other valuation techniques;
 - (e) for each revalued class of property, plant and equipment, the carrying amount that would have been recognised had the assets been carried under the cost model; and
 - (f) the revaluation surplus, indicating the change for the period and any restrictions on the distribution of the balance to shareholders.
78. In accordance with Ind AS 36 an entity discloses information on impaired property, plant and equipment in addition to the information required by paragraph 73(e)(iv)–(vi).
79. Users of financial statements may also find the following information relevant to their needs:
- (a) the carrying amount of temporarily idle property, plant and equipment;
 - (b) the gross carrying amount of any fully depreciated property, plant and equipment that is still in use;
 - (c) the carrying amount of property, plant and equipment retired from active use and not classified as held for sale in accordance with Ind AS 105; and
 - (d) when the cost model is used, the fair value of property, plant and equipment when this is materially different from the carrying amount.

Therefore, entities are encouraged to disclose these amounts.

Appendix A

Changes in Existing Decommissioning, Restoration and Similar Liabilities

This Appendix is an integral part of Ind AS 16.

Background

1. Many entities have obligations to dismantle, remove and restore items of property, plant and equipment. In this Appendix such obligations are referred to as 'decommissioning, restoration and similar liabilities'. Under Ind AS 16, the cost of an item of property, plant and equipment includes the initial estimate of the costs of dismantling and removing the item and restoring the site on which it is located, the obligation for which an entity incurs either when the item is acquired or as a consequence of having used the item during a particular period for purposes other than to produce inventories during that period. Ind AS 37 contains requirements on how to measure decommissioning, restoration and similar liabilities. This Appendix provides guidance on how to account for the effect of changes in the measurement of existing decommissioning, restoration and similar liabilities.

Scope

2. This Appendix applies to changes in the measurement of any existing decommissioning, restoration or similar liability that is both:

- (a) recognised as part of the cost of an item of property, plant and equipment in accordance with Ind AS 16; and
- (b) recognised as a liability in accordance with Ind AS 37.

For example, a decommissioning, restoration or similar liability may exist for decommissioning a plant, rehabilitating environmental damage in extractive industries, or removing equipment.

Issue

3. This Appendix addresses how the effect of the following events that change the measurement of an existing decommissioning, restoration or similar liability should be accounted for:

- (a) a change in the estimated outflow of resources embodying economic benefits (eg cash flows) required to settle the obligation;
- (b) a change in the current market-based discount rate as defined in paragraph 47 of Ind AS 37 (this includes changes in the time value of money and the risks specific to the liability); and
- (c) an increase that reflects the passage of time (also referred to as the unwinding of the discount).

Accounting Principles

4. Changes in the measurement of an existing decommissioning, restoration and similar liability that result from changes in the estimated timing or amount of the outflow of resources embodying economic benefits required to settle the obligation, or a change in the discount rate, shall be accounted for in accordance with paragraphs 5–7 below.

5. If the related asset is measured using the cost model:

- (a) subject to (b), changes in the liability shall be added to, or deducted from, the cost of the related asset in the current period.
- (b) the amount deducted from the cost of the asset shall not exceed its carrying amount. If a decrease in the liability exceeds the carrying amount of the asset, the excess shall be recognised immediately in profit or loss.

- (c) if the adjustment results in an addition to the cost of an asset, the entity shall consider whether this is an indication that the new carrying amount of the asset may not be fully recoverable. If it is such an indication, the entity shall test the asset for impairment by estimating its recoverable amount, and shall account for any impairment loss, in accordance with Ind AS 36.
6. If the related asset is measured using the revaluation model:
- (a) changes in the liability alter the revaluation surplus or deficit previously recognised on that asset, so that:
- (i) a decrease in the liability shall (subject to (b)) be recognised in other comprehensive income and increase the revaluation surplus within equity, except that it shall be recognised in profit or loss to the extent that it reverses a revaluation deficit on the asset that was previously recognised in profit or loss;
- (ii) an increase in the liability shall be recognised in profit or loss, except that it shall be recognised in other comprehensive income and reduce the revaluation surplus within equity to the extent of any credit balance existing in the revaluation surplus in respect of that asset.
- (b) in the event that a decrease in the liability exceeds the carrying amount that would have been recognised had the asset been carried under the cost model, the excess shall be recognised immediately in profit or loss.
- (c) a change in the liability is an indication that the asset may have to be revalued in order to ensure that the carrying amount does not differ materially from that which would be determined using fair value at the end of the reporting period. Any such revaluation shall be taken into account in determining the amounts to be recognised in profit or loss or in other comprehensive income under (a). If a revaluation is necessary, all assets of that class shall be revalued.
- (d) Ind AS 1 requires disclosure in the statement of profit and loss of each component of other comprehensive income or expense. In complying with this requirement, the change in the revaluation surplus arising from a change in the liability shall be separately identified and disclosed as such.
7. The adjusted depreciable amount of the asset is depreciated over its useful life. Therefore, once the related asset has reached the end of its useful life, all subsequent changes in the liability shall be recognised in profit or loss as they occur. This applies under both the cost model and the revaluation model.
8. The periodic unwinding of the discount shall be recognised in profit or loss as a finance cost as it occurs. Capitalisation under Ind AS 23 is not permitted.

Illustrative examples of Changes in Existing Decommissioning, Restoration and Similar Liabilities

(These examples accompany, but are not part of, Appendix A.)

Common facts

- IE1 An entity has a nuclear power plant and a related decommissioning liability. The nuclear power plant started operating on 1 January 2000. The plant has a useful life of 40 years. Its initial cost was Rs. 120,000; this included an amount for decommissioning costs of Rs. 10,000, which represented Rs. 70,400 in estimated cash flows payable in 40 years discounted at a risk-adjusted rate of 5 per cent. The entity's financial year ends on 31 December.

Example 1: Cost model

- IE2 On 31 December 2009, the plant is 10 years old. Accumulated depreciation is Rs. 30,000 ($\text{Rs. } 120,000 \times \frac{10}{40} \text{ years}$). Because of the unwinding of discount (5 per cent) over the 10 years, the decommissioning liability has grown from Rs. 10,000 to Rs. 16,300.
- IE3 On 31 December 2009, the discount rate has not changed. However, the entity estimates that, as a result of technological advances, the net present value of the decommissioning liability has decreased by Rs. 8,000. Accordingly, the entity adjusts the decommissioning liability from Rs. 16,300 to Rs. 8,300. On this date, the entity makes the following journal entry to reflect the change:

	Rs.	Rs.
Dr decommissioning liability	8,000	
Cr cost of asset		8,000

- IE4 Following this adjustment, the carrying amount of the asset is Rs. 82,000 ($\text{Rs. } 120,000 - \text{Rs. } 8,000 - \text{Rs. } 30,000$), which will be depreciated over the remaining 30 years of the asset's life giving a depreciation expense for the next year of Rs. 2,733 ($\text{Rs. } 82,000 \div 30$). The next year's finance cost for the unwinding of the discount will be Rs. 415 ($\text{Rs. } 8,300 \times 5 \text{ per cent}$).
- IE5 If the change in the liability had resulted from a change in the discount rate, instead of a change in the estimated cash flows, the accounting for the change would have been the same but the next year's finance cost would have reflected the new discount rate.

Example 2: Revaluation model

- IE6 The entity adopts the revaluation model in Ind AS 16 whereby the plant is revalued with sufficient regularity that the carrying amount does not differ materially from fair value. The entity's policy is to eliminate accumulated depreciation at the revaluation date against the gross carrying amount of the asset.
- IE7 When accounting for revalued assets to which decommissioning liabilities attach, it is important to understand the basis of the valuation obtained. For example:
- (a) if an asset is valued on a discounted cash flow basis, some valuers may value the asset without deducting any allowance for decommissioning costs (a 'gross' valuation), whereas others may value the asset after deducting an allowance for decommissioning costs (a 'net' valuation), because an entity acquiring the asset will generally also assume the decommissioning obligation. For financial reporting purposes, the decommissioning obligation is recognised as a separate liability, and is not deducted from the asset. Accordingly, if the asset is valued on a net basis, it is necessary to adjust the valuation obtained by adding back the allowance for the liability, so that the liability is not counted twice.²
 - (b) if an asset is valued on a depreciated replacement cost basis, the valuation obtained may not include an amount for the decommissioning component of the asset. If it does not, an appropriate amount will need to be added to the valuation to reflect the depreciated replacement cost of that component.
- IE8 Assume that a market-based discounted cash flow valuation of Rs. 115,000 is obtained at 31 December 2002. It includes an allowance of Rs. 11,600 for decommissioning costs, which represents no change to the original estimate, after the unwinding of three years' discount. The amounts included in the balance sheet at 31 December 2002 are therefore:

	Rs.
Asset at valuation (1)	126,600
Accumulated depreciation	nil
Decommissioning liability	(11,600)
Net assets	<u>115,000</u>
Retained earnings (2)	<u>(10,600)</u>
Revaluation surplus (3)	15,600

Notes:

² For examples of this principle, see Ind AS 36 *Impairment of Assets*.

- (1) Valuation obtained of Rs. 115,000 plus decommissioning costs of Rs. 11,600, allowed for in the valuation but recognised as a separate liability = Rs. 126,600.
- (2) Three years' depreciation on original cost Rs. 120,000 $\times \frac{3}{40} =$ Rs. 9,000 plus cumulative discount on Rs. 10,000 at 5 per cent compound = Rs. 1,600; total Rs. 10,600.
- (3) Revalued amount Rs. 126,600 less previous net book value of Rs. 111,000 (cost Rs. 120,000 less accumulated depreciation Rs. 9,000).

IE9 The depreciation expense for 2003 is therefore Rs. 3,420 (Rs. 126,600 $\times \frac{1}{37}$) and the discount expense for 2003 is Rs. 600 (5 per cent of Rs. 11,600). On 31 December 2003, the decommissioning liability (before any adjustment) is Rs. 12,200 and the discount rate has not changed. However, on that date, the entity estimates that, as a result of technological advances, the present value of the decommissioning liability has decreased by Rs. 5,000. Accordingly, the entity adjusts the decommissioning liability from Rs. 12,200 to Rs. 7,200.

IE10 The whole of this adjustment is taken to revaluation surplus, because it does not exceed the carrying amount that would have been recognised had the asset been carried under the cost model. If it had done, the excess would have been taken to profit or loss in accordance with paragraph 6(b). The entity makes the following journal entry to reflect the change:

	Rs.	Rs.
Dr decommissioning liability	5,000	
Cr revaluation surplus		5,000

IE11 The entity decides that a full valuation of the asset is needed at 31 December 2003, in order to ensure that the carrying amount does not differ materially from fair value. Suppose that the asset is now valued at Rs. 107,000, which is net of an allowance of Rs. 7,200 for the reduced decommissioning obligation that should be recognised as a separate liability. The valuation of the asset for financial reporting purposes, before deducting this allowance, is therefore Rs. 114,200. The following additional journal entry is needed:

	Rs.	Rs.
Dr accumulated depreciation (1)	3,420	
Cr asset at valuation		3,420
Dr revaluation surplus (2)	8,980	
Cr asset at valuation (3)		8,980

Notes:

- (1) Eliminating accumulated depreciation of Rs. 3,420 in accordance with the entity's accounting policy.

- (2) The debit is to revaluation surplus because the deficit arising on the revaluation does not exceed the credit balance existing in the revaluation surplus in respect of the asset.
- (3) Previous valuation (before allowance for decommissioning costs) Rs.126,600, less cumulative depreciation Rs.3,420, less new valuation (before allowance for decommissioning costs) Rs.114,200.

IE12 Following this valuation, the amounts included in the balance sheet are:

	Rs.
Asset at valuation	114,200
Accumulated depreciation	nil
Decommissioning liability	(7,200)
Net assets	<u>107,000</u>
Retained earnings (1)	(14,620)
Revaluation surplus (2)	11,620

Notes:

- (1) Rs.10,600 at 31 December 2002 plus 2003's depreciation expense of Rs.3,420 and discount expense of Rs.600 = Rs.14,620.
- (2) Rs.15,600 at 31 December 2002, plus Rs.5,000 arising on the decrease in the liability, less Rs.8,980 deficit on revaluation = Rs.11,620.

Appendix B

References to matters contained in other Indian Accounting Standards

This Appendix is an integral part of Ind AS 16.

This appendix lists the appendices which are part of other Indian Accounting Standards and make reference to Ind AS 16, *Property, Plant and Equipment*

1. Appendix A, *Income Taxes—Recovery of Revalued Non-Depreciable Assets* contained in Ind AS 12.
2. Appendix A, *Service Concession Arrangements* contained in Ind AS 11 *Construction Contracts*.
3. Appendix B, *Service Concession Arrangements: Disclosures* contained in Ind AS 11 *Construction Contracts*.
4. Appendix C, *Determining whether an Arrangement contains a Lease* contained in Ind AS 17 *Leases*.
5. Appendix A, *Intangible Assets—Web Site Costs* contained in Ind AS 38 *Intangible Assets*.
6. Appendix C, *Transfers of Assets from Customers* contained in Ind AS 18 *Revenue*.

Appendix 1

Note: This Appendix is not a part of this Indian Accounting Standard. The purpose of this Appendix is only to bring out the differences, if any, between Indian Accounting Standard (Ind AS) 16 and the corresponding International Accounting Standard (IAS) 16, Property, Plant and Equipment and IFRIC 1, Changes in Existing Decommissioning, Restoration and Similar Liabilities.

Comparison with IAS 16, *Property, Plant and Equipment* and IFRIC 1, *Changes in Existing Decommissioning, Restoration and Similar Liabilities*.

1. The transitional provisions given in IAS 16 and IFRIC 1 have not been given in Ind AS 16, since all transitional provisions related to Ind ASs, wherever considered appropriate have been included in Ind AS 101, *First-time Adoption of Indian Accounting Standards* corresponding to IFRS 1, *First-time Adoption of International Financial Reporting Standards*.
2. Different terminology is used in this standard, e.g., the term 'balance sheet' is used instead of 'Statement of financial position' and 'Statement of profit' and loss is used instead of 'Statement of comprehensive income'.
3. Paragraph 28 has been deleted since Ind AS 20, *Accounting for Government Grants and Disclosure of Government Assistance* does not permit the option of reducing the carrying amount of an item of property, plant and equipment by the amount of government grant received in respect of such an item, which is permitted in IAS 20. However, to maintain consistency with paragraph numbers of IAS 16, this paragraph number is retained in Ind AS 16.
4. Paragraph number 64 appears as 'Deleted' in IAS 16. In order to maintain consistency with paragraph numbers of IAS 16, the paragraph number is retained in Ind AS 16.
5. Paragraphs 5 of Ind AS 16 and IE 7 of Appendix A of Ind AS 16 have been modified, since Ind AS 40, *Investment Property*, prohibits the use of fair value model.

Indian Accounting Standard (Ind AS) 29

Financial Reporting in Hyperinflationary Economies

*(This Indian Accounting Standard includes paragraphs set in **bold type** and plain type, which have equal authority. Paragraphs in bold type indicate the main principles.).*

Scope

- 1 **This Standard shall be applied to the financial statements, including the consolidated financial statements, of any entity whose functional currency is the currency of a hyperinflationary economy.**
- 2 In a hyperinflationary economy, reporting of operating results and financial position in the local currency without restatement is not useful. Money loses purchasing power at such a rate that comparison of amounts from transactions and other events that have occurred at different times, even within the same accounting period, is misleading.
- 3 This Standard does not establish an absolute rate at which hyperinflation is deemed to arise. It is a matter of judgement when restatement of financial statements in accordance with this Standard becomes necessary. Hyperinflation is indicated by characteristics of the economic environment of a country which include, but are not limited to, the following:
 - (a) the general population prefers to keep its wealth in non-monetary assets or in a relatively stable foreign currency. Amounts of local currency held are immediately invested to maintain purchasing power;
 - (b) the general population regards monetary amounts not in terms of the local currency but in terms of a relatively stable foreign currency. Prices may be quoted in that currency;
 - (c) sales and purchases on credit take place at prices that compensate for the expected loss of purchasing power during the credit period, even if the period is short;
 - (d) interest rates, wages and prices are linked to a price index; and
 - (e) the cumulative inflation rate over three years is approaching, or exceeds, 100%.
- 4 It is preferable that all entities that report in the currency of the same hyperinflationary economy apply this Standard from the same date.

Nevertheless, this Standard applies to the financial statements of any entity from the beginning of the reporting period in which it identifies the existence of hyperinflation in the country in whose currency it reports.

The restatement of financial statements

- 5 Prices change over time as the result of various specific or general political, economic and social forces. Specific forces such as changes in supply and demand and technological changes may cause individual prices to increase or decrease significantly and independently of each other. In addition, general forces may result in changes in the general level of prices and therefore in the general purchasing power of money.
- 6 Entities that prepare financial statements on the historical cost basis of accounting do so without regard either to changes in the general level of prices or to increases in specific prices of recognised assets or liabilities. The exceptions to this are those assets and liabilities that the entity is required, or chooses, to measure at fair value. For example, property, plant and equipment may be revalued to fair value and biological assets are generally required to be measured at fair value. Some entities, however, present financial statements that are based on a current cost approach that reflects the effects of changes in the specific prices of assets held.
- 7 In a hyperinflationary economy, financial statements, whether they are based on a historical cost approach or a current cost approach, are useful only if they are expressed in terms of the measuring unit current at the end of the reporting period. As a result, this Standard applies to the financial statements of entities reporting in the currency of a hyperinflationary economy. Presentation of the information required by this Standard as a supplement to unrestated financial statements is not permitted. Furthermore, separate presentation of the financial statements before restatement is discouraged.
- 8 **The financial statements of an entity whose functional currency is the currency of a hyperinflationary economy, whether they are based on a historical cost approach or a current cost approach, shall be stated in terms of the measuring unit current at the end of the reporting period. The corresponding figures for the previous period required by Ind AS 1, *Presentation of Financial Statements* and any information in respect of earlier periods shall also be stated in terms of the measuring unit current at the end of the reporting period. For the purpose of presenting comparative amounts in a different presentation currency, paragraphs 42(b) and 43 of Ind AS 21, *The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates* apply.**
- 9 **The gain or loss on the net monetary position shall be included in profit or loss and separately disclosed.**
- 10 The restatement of financial statements in accordance with this Standard requires the application of certain procedures as well as judgement. The consistent application of these procedures and judgements from period to period is more important than the precise accuracy of the resulting amounts included in the restated financial statements.

Historical cost financial statements

Balance sheet

- 11 Balance sheet amounts not already expressed in terms of the measuring unit current at the end of the reporting period are restated by applying a general price index.
- 12 Monetary items are not restated because they are already expressed in terms of the monetary unit current at the end of the reporting period. Monetary items are money held and items to be received or paid in money.
- 13 Assets and liabilities linked by agreement to changes in prices, such as index linked bonds and loans, are adjusted in accordance with the agreement in order to ascertain the amount outstanding at the end of the reporting period. These items are carried at this adjusted amount in the restated balance sheet.
- 14 All other assets and liabilities are non-monetary. Some non-monetary items are carried at amounts current at the end of the reporting period, such as net realisable value and fair value, so they are not restated. All other non-monetary assets and liabilities are restated.
- 15 Most non-monetary items are carried at cost or cost less depreciation; hence they are expressed at amounts current at their date of acquisition. The restated cost, or cost less depreciation, of each item is determined by applying to its historical cost and accumulated depreciation the change in a general price index from the date of acquisition to the end of the reporting period. For example, property, plant and equipment, inventories of raw materials and merchandise, goodwill, patents, trademarks and similar assets are restated from the dates of their purchase. Inventories of partly-finished and finished goods are restated from the dates on which the costs of purchase and of conversion were incurred.
- 16 Detailed records of the acquisition dates of items of property, plant and equipment may not be available or capable of estimation. In these rare circumstances, it may be necessary, in the first period of application of this Standard, to use an independent professional assessment of the value of the items as the basis for their restatement.
- 17 A general price index may not be available for the periods for which the restatement of property, plant and equipment is required by this Standard. In these circumstances, it may be necessary to use an estimate based, for example, on the movements in the exchange rate between the functional currency and a relatively stable foreign currency.
- 18 Some non-monetary items are carried at amounts current at dates other than that of acquisition or that of the balance sheet, for example property, plant and equipment that has been revalued at some earlier date. In these cases, the carrying amounts are restated from the date of the revaluation.
- 19 The restated amount of a non-monetary item is reduced, in accordance with appropriate Indian Accounting Standards, when it exceeds its recoverable

amount. For example, restated amounts of property, plant and equipment, goodwill, patents and trademarks are reduced to recoverable amount and restated amounts of inventories are reduced to net realisable value.

- 20 An investee that is accounted for under the equity method may report in the currency of a hyperinflationary economy. The balance sheet and statement of profit and loss of such an investee are restated in accordance with this Standard in order to calculate the investor's share of its net assets and profit or loss. When the restated financial statements of the investee are expressed in a foreign currency they are translated at closing rates.
- 21 The impact of inflation is usually recognised in borrowing costs. It is not appropriate both to restate the capital expenditure financed by borrowing and to capitalise that part of the borrowing costs that compensates for the inflation during the same period. This part of the borrowing costs is recognised as an expense in the period in which the costs are incurred.
- 22 An entity may acquire assets under an arrangement that permits it to defer payment without incurring an explicit interest charge. Where it is impracticable to impute the amount of interest, such assets are restated from the payment date and not the date of purchase.
- 23 [Refer to Appendix 1]
- 24 At the beginning of the first period of application of this Standard, the components of owners' equity, except retained earnings and any revaluation surplus, are restated by applying a general price index from the dates the components were contributed or otherwise arose. Any revaluation surplus that arose in previous periods is eliminated. Restated retained earnings are derived from all the other amounts in the restated balance sheet.
- 25 At the end of the first period and in subsequent periods, all components of owners' equity are restated by applying a general price index from the beginning of the period or the date of contribution, if later. The movements for the period in owners' equity are disclosed in accordance with Ind AS 1.

Statement of profit and loss

- 26 This Standard requires that all items in the statement of profit and loss are expressed in terms of the measuring unit current at the end of the reporting period. Therefore all amounts need to be restated by applying the change in the general price index from the dates when the items of income and expenses were initially recorded in the financial statements.

Gain or loss on net monetary position

- 27 In a period of inflation, an entity holding an excess of monetary assets over monetary liabilities loses purchasing power and an entity with an excess of monetary liabilities over monetary assets gains purchasing power to the extent the assets and liabilities are not linked to a price level. This gain or loss on the net monetary position may be derived as the difference resulting from the restatement of non-monetary assets, owners' equity and items in the statement of profit and loss and the adjustment of index linked assets and liabilities. The gain or loss may be estimated by applying the change in a

general price index to the weighted average for the period of the difference between monetary assets and monetary liabilities.

- 28 The gain or loss on the net monetary position is included in profit or loss. The adjustment to those assets and liabilities linked by agreement to changes in prices made in accordance with paragraph 13 is offset against the gain or loss on net monetary position. Other income and expense items, such as interest income and expense, and foreign exchange differences related to invested or borrowed funds, are also associated with the net monetary position. Although such items are separately disclosed, it may be helpful if they are presented together with the gain or loss on net monetary position in the statement of profit and loss.

Current cost financial statements

Balance sheet

- 29 Items stated at current cost are not restated because they are already expressed in terms of the measuring unit current at the end of the reporting period. Other items in the balance sheet are restated in accordance with paragraphs 11 to 25.

Statement of profit and loss

- 30 The current cost statement of profit and loss, before restatement, generally reports costs current at the time at which the underlying transactions or events occurred. Cost of sales and depreciation are recorded at current costs at the time of consumption; sales and other expenses are recorded at their money amounts when they occurred. Therefore all amounts need to be restated into the measuring unit current at the end of the reporting period by applying a general price index.

Gain or loss on net monetary position

- 31 The gain or loss on the net monetary position is accounted for in accordance with paragraphs 27 and 28.

Taxes

- 32 The restatement of financial statements in accordance with this Standard may give rise to differences between the carrying amount of individual assets and liabilities in the balance sheet and their tax bases. These differences are accounted for in accordance with Ind AS 12, *Income Taxes*.

Statement of cash flows

- 33 This Standard requires that all items in the statement of cash flows are expressed in terms of the measuring unit current at the end of the reporting period.

Corresponding figures

- 34 Corresponding figures for the previous reporting period, whether they were based on a historical cost approach or a current cost approach, are restated by applying a general price index so that the comparative financial statements ~~are~~ presented in terms of the measuring unit current at the end of the reporting period. Information that is disclosed in respect of earlier periods is also expressed in terms of the measuring unit current at the end of the reporting period. For the purpose of presenting comparative amounts in a different presentation currency, paragraphs 42(b) and 43 of Ind AS 21 apply.

Consolidated financial statements

- 35 A parent that reports in the currency of a hyperinflationary economy may have subsidiaries that also report in the currencies of hyperinflationary economies. The financial statements of any such subsidiary need to be restated by applying a general price index of the country in whose currency it reports before they are included in the consolidated financial statements issued by its parent. Where such a subsidiary is a foreign subsidiary, its restated financial statements are translated at closing rates. The financial statements of subsidiaries that do not report in the currencies of hyperinflationary economies are dealt with in accordance with Ind AS 21.
- 36 If financial statements with different ends of the reporting periods are consolidated, all items, whether non-monetary or monetary, need to be restated into the measuring unit current at the date of the consolidated financial statements.

Selection and use of the general price index

- 37 The restatement of financial statements in accordance with this Standard requires the use of a general price index that reflects changes in general purchasing power. It is preferable that all entities that report in the currency of the same economy use the same index.

Economies ceasing to be hyperinflationary

- 38 When an economy ceases to be hyperinflationary and an entity discontinues the preparation and presentation of financial statements prepared in accordance with this Standard, it shall treat the amounts expressed in the measuring unit current at the end of the previous reporting period as the basis for the carrying amounts in its subsequent financial statements.

Disclosures

- 39 The following disclosures shall be made:
- (a) the fact that the financial statements and the corresponding figures for previous periods have been restated for the changes in the general purchasing power of the functional currency and,

as a result, are stated in terms of the measuring unit current at the end of the reporting period;

- (b) whether the financial statements are based on a historical cost approach or a current cost approach; and
 - (c) the identity and level of the price index at the end of the reporting period and the movement in the index during the current and the previous reporting period.
 - (d) the duration of the hyperinflationary situation existing in the economy.
- 40 The disclosures required by this Standard are needed to make clear the basis of dealing with the effects of inflation in the financial statements. They are also intended to provide other information necessary to understand that basis and the resulting amounts.

Appendix A

Applying the Restatement Approach under Ind AS 29 Financial Reporting in Hyperinflationary Economies

This Appendix is an integral part of the Indian Accounting Standard (Ind AS) 29, Financial Reporting in Hyperinflationary Economies

Background

- 1 This Appendix provides guidance on how to apply the requirements of Ind AS 29 in a reporting period in which an entity identifies the existence of hyperinflation in the economy of its functional currency, when that economy was not hyperinflationary in the prior period, and the entity therefore restates its financial statements in accordance with Ind AS 29.

Issues

- 2 The questions addressed in this Appendix are:
- (a) how should the requirement '... stated in terms of the measuring unit current at the end of the reporting period' in paragraph 8 of Ind AS 29 be interpreted when an entity applies the Standard?
 - (b) how should an entity account for opening deferred tax items in its restated financial statements?

Accounting Treatment

- 3 In the reporting period in which an entity identifies the existence of hyperinflation in the economy of its functional currency, not having been hyperinflationary in the prior period, the entity shall apply the requirements of Ind AS 29 as if the economy had always been hyperinflationary. Therefore, in relation to non-monetary items measured at historical cost, the entity's opening balance sheet at the beginning of the earliest period presented in the

financial statements shall be restated to reflect the effect of inflation from the date the assets were acquired and the liabilities were incurred or assumed until the end of the reporting period. For non-monetary items carried in the opening balance sheet at amounts current at dates other than those of acquisition or incurrence, that restatement shall reflect instead the effect of inflation from the dates those carrying amounts were determined until the end of the reporting period.

- 4 At the end of the reporting period, deferred tax items are recognised and measured in accordance with Ind AS 12. However, the deferred tax figures in the opening balance sheet for the reporting period shall be determined as follows:
- (a) the entity remeasures the deferred tax items in accordance with Ind AS 12 after it has restated the nominal carrying amounts of its non-monetary items at the date of the opening balance sheet of the reporting period by applying the measuring unit at that date.
 - (b) the deferred tax items remeasured in accordance with (a) are restated for the change in the measuring unit from the date of the opening balance sheet of the reporting period to the end of that reporting period.

The entity applies the approach in (a) and (b) in restating the deferred tax items in the opening balance sheet of any comparative periods presented in the restated financial statements for the reporting period in which the entity applies Ind AS 29.

- 5 After an entity has restated its financial statements, all corresponding figures in the financial statements for a subsequent reporting period, including deferred tax items, are restated by applying the change in the measuring unit for that subsequent reporting period only to the restated financial statements for the previous reporting period.

The identification of hyperinflation is based on the entity's judgement of the criteria in paragraph 3 of Ind AS 29

Illustrative example

This example accompanies, but is not part of, Appendix A.

- IE1 This example illustrates the restatement of deferred tax items when an entity restates for the effects of inflation under Ind AS 29 *Financial Reporting in Hyperinflationary Economies*. As the example is intended only to illustrate the mechanics of the restatement approach in Ind AS 29 for deferred tax items, it does not illustrate an entity's complete financial statements.

Facts

- IE2 An entity's balance sheet at 31 December 20X2 (before restatement) is as follows:

Note	Balance Sheet	20X2 (Rs) million	20X1 (Rs) million
	ASSETS		
1	Property, plant and equipment	300	400
	Other assets	XXX	XXX
	Total assets	XXX	XXX
	EQUITY AND LIABILITIES		
	Total equity	XXX	XXX
	Liabilities		
2	Deferred tax liability	30	20
	Other liabilities	XXX	XXX
	Total liabilities	XXX	XXX
	Total equity and liabilities	XXX	XXX
	Notes		
1	<i>Property, plant and equipment</i>		
	All items of property, plant and equipment were acquired in December 20X0. Property, plant and equipment are depreciated over their useful life, which is five years.		
2	<i>Deferred tax liability</i>		
	The deferred tax liability at 31 December 20X2 of Rs 30 million		

is measured as the taxable temporary difference between the carrying amount of property, plant and equipment of Rs.300 and their tax base of Rs.200. The applicable tax rate is 30 per cent.

Similarly, the deferred tax liability at 31 December 20X1 of Rs 20 million is measured as the taxable temporary difference between the carrying amount of property, plant and equipment of Rs 400 and their tax base of Rs 333.

- IE3 Assume that the entity identifies the existence of hyperinflation in, for example, April 20X2 and therefore applies Ind AS 29 from the beginning of 20X2. The entity restates its financial statements on the basis of the following general price indices and conversion factors.

General price indices		Conversion factors at 31 Dec 20X2
December 20X0 (a)	95	2.347
December 20X1	135	1.652
December 20X2	223	1.000

(a) For example, the conversion factor for December 20X0 is $2.347 = 223/95$

Restatement

- IE4 The restatement of the entity's 20X2 financial statements is based on the following requirements:

- Property, plant and equipment are restated by applying the change in a general price index from the date of acquisition to the end of the reporting period to their historical cost and accumulated depreciation.
- Deferred taxes should be accounted for in accordance with Ind AS 12, *Income Taxes*.
- Comparative figures for property, plant and equipment for the previous reporting period are presented in terms of the measuring unit current at the end of the reporting period.
- Comparative deferred tax figures should be measured in accordance with paragraph 4 of the Appendix A.

- IE5 Therefore the entity restates its balance sheet at 31 December 20X2 as follows:

Note	Balance Sheet (restated)	20X2 Rs million	20X1 Rs million
	ASSETS		
1	Property, plant and equipment	704	939
	Other assets	XXX	XXX
	Total assets	XXX	XXX
	EQUITY AND LIABILITIES		
	Total equity	XXX	XXX
	Liabilities		
2	Deferred tax liability	151	117
	Other liabilities	XXX	XXX
	Total liabilities	XXX	XXX
	Total equity and liabilities	XXX	XXX
	Notes		
1	<i>Property, plant and equipment</i>		
	All items of property, plant and equipment were purchased in December 20X0 and depreciated over a five-year period. The cost of property, plant and equipment is restated to reflect the change in the general price level since acquisition, ie the conversion factor is 2.347 (223/95).		
		Historical Rs million	Restated Rs million
	Cost of property, plant and equipment	500	1,174
	Depreciation 20X1	(100)	(235)
	Carrying amount 31 December 20X1	400	939
	Depreciation 20X2	(100)	(235)
	Carrying amount 31 December 20X2	300	704
2	<i>Deferred tax liability</i>		
	The nominal deferred tax liability at 31 December 20X2 of Rs 30 million is measured as the taxable temporary difference between the carrying amount of property, plant and equipment of Rs 300 and their tax base of Rs 200. Similarly, the deferred tax liability at 31 December 20X1 of Rs 20 million is measured as the taxable temporary difference between the carrying amount of property, plant and equipment of Rs 400 and their tax base of Rs 333. The applicable tax rate is 30 per cent.		
	In its restated financial statements, at the end of the reporting period the entity remeasures		

deferred tax items in accordance with the general provisions in Ind AS 12, ie on the basis of its restated financial statements. However, because deferred tax items are a function of carrying amounts of assets or liabilities and their tax bases, an entity cannot restate its comparative deferred tax items by applying a general price index. Instead, in the reporting period in which an entity applies the restatement approach under Ind AS 29, it (a) remeasures its comparative deferred tax items in accordance with Ind AS 12 after it has restated the nominal carrying amounts of its non-monetary items at the date of the opening balance sheet of the current reporting period by applying the measuring unit at that date, and (b) restates the remeasured deferred tax items for the change in the measuring unit from the date of the opening balance sheet of the current period up to the end of the reporting period.

In the example, the restated deferred tax liability is calculated as follows:

	Rs million
At the end of the reporting period:	
Restated carrying amount of property, plant and equipment (see note 1)	704
Tax base	(200)
Temporary difference	504
@ 30 per cent tax rate = Restated deferred tax liability 31 December 20X2	151
Comparative deferred tax figures:	
Restated carrying amount of property, plant and equipment [either 400×1.421 (conversion factor $1.421 = 135/95$), or $939/1.652$ (conversion factor $1.652 = 223/135$)]	568
Tax base	(333)
Temporary difference	235
@ 30 per cent tax rate = Restated deferred tax liability 31 December 20X1 at the general price level at the end of 20X1	71
Restated deferred tax liability 31 December 20X1 at the general price level at the end of 20X2 (conversion factor $1.652 = 223/135$)	117

- IE6 In this example, the restated deferred tax liability is increased by Rs 34 to Rs 151 from 31 December 20X1 to 31 December 20X2. That increase, which is included in profit or loss in 20X2, reflects (a) the effect of a change in the taxable temporary difference of property, plant and equipment, and (b) a loss of purchasing power on the tax base of property, plant and equipment. The two components can be analysed as follows:

	Rs million
Effect on deferred tax liability because of a decrease in the taxable temporary difference of property, plant and equipment $(-Rs\ 235 + Rs133) \times 30\%$	31
Loss on tax base because of inflation in 20X2 $(Rs\ 333 \times 1.652 - Rs\ 333) \times 30\%$	(65)
Net increase of deferred tax liability	(34)
Debit to profit or loss in 20X2	34

The loss on tax base is a monetary loss. Paragraph 28 of Ind AS 29 explains this as follows:

The gain or loss on the net monetary position is included in net income. The adjustment to those assets and liabilities linked by agreement to changes in prices made in accordance with paragraph 13 is offset against the gain or loss on net monetary position. Other income and expense items, such as interest income and expense, and foreign exchange differences related to invested or borrowed funds, are also associated with the net monetary position. Although such items are separately disclosed, it may be helpful if they are presented together with the gain or loss on net monetary position in the statement of profit and loss.

Appendix 1

Note: This Appendix is not a part of the proposed Indian Accounting Standard (Ind AS) 29, Financial Reporting in Hyperinflationary Economies. The purpose of this Appendix is only to bring out the differences between the this Indian Accounting Standard and corresponding International Accounting Standard IAS 29, Financial Reporting in Hyperinflationary Economies.

Comparison with IAS 29, Financial Reporting in Hyperinflationary Economies

- 1 Ind AS 29 requires an additional disclosure regarding the duration of the hyperinflationary situation existing in the economy as compared to IAS 29.
- 2 Paragraph number 23 appears as 'Deleted' in IAS 29. In order to maintain consistency with paragraph numbers of IAS 29, the paragraph number is retained in Ind AS 29.
- 3 Different terminology is used in this standard, e.g., term 'balance sheet' is used instead of 'Statement of financial position' and 'Statement of profit and loss' is used instead of 'Statement of comprehensive income'.

Indian Accounting Standard (Ind AS) 105

Non-current Assets Held for Sale and Discontinued Operations

(This Indian Accounting Standard includes paragraphs set in bold type and plain type, which have equal authority. Paragraphs in bold type indicate the main principles).

Objective

- 1 The objective of this Indian Accounting Standard is to specify the accounting for assets held for sale, and the presentation and disclosure of discontinued operations. In particular, the Indian Accounting Standard requires:
 - (a) assets that meet the criteria to be classified as held for sale to be measured at the lower of carrying amount and fair value less costs to sell, and depreciation on such assets to cease; and
 - (b) assets that meet the criteria to be classified as held for sale to be presented separately in the balance sheet and the results of discontinued operations to be presented separately in the statement of profit and loss.

Scope

- 2 The classification and presentation requirements of this Indian Accounting Standard apply to all recognised non-current assets¹ and to all disposal groups of an entity. The measurement requirements of this Indian Accounting Standard apply to all recognised non-current assets and disposal groups (as set out in paragraph 4), except for those assets listed in paragraph 5 which shall continue to be measured in accordance with the Standard noted.
- 3 Assets classified as non-current in accordance with Ind AS 1 *Presentation of Financial Statements* shall not be reclassified as current assets until they meet the criteria to be classified as held for sale in accordance with this Indian Accounting Standard. Assets of a class that an entity would normally regard as non-current that are acquired exclusively with a view to resale shall not be classified as current unless they meet the criteria to be classified as held for sale in accordance with this Indian Accounting Standard.

¹ For assets classified according to a liquidity presentation, non-current assets are assets that include amounts expected to be recovered more than twelve months after the reporting period. Paragraph 3 applies to the classification of such assets.

- 4 Sometimes an entity disposes of a group of assets, possibly with some directly associated liabilities, together in a single transaction. Such a disposal group may be a group of cash-generating units, a single cash-generating unit, or part of a cash-generating unit.² The group may include any assets and any liabilities of the entity, including current assets, current liabilities and assets excluded by paragraph 5 from the measurement requirements of this Indian Accounting Standard. If a non-current asset within the scope of the measurement requirements of this Indian Accounting Standard is part of a disposal group, the measurement requirements of this Indian Accounting Standard apply to the group as a whole, so that the group is measured at the lower of its carrying amount and fair value less costs to sell. The requirements for measuring the individual assets and liabilities within the disposal group are set out in paragraphs 18, 19 and 23.
- 5 The measurement provisions of this Indian Accounting Standard³ do not apply to the following assets, which are covered by the Indian Accounting Standards listed, either as individual assets or as part of a disposal group:
- (a) deferred tax assets (Ind AS 12 *Income Taxes*).
 - (b) assets arising from employee benefits (Ind AS 19 *Employee Benefits*).
 - (c) financial assets within the scope of Ind AS 39 *Financial Instruments: Recognition and Measurement*.
 - (d) [Refer to Appendix I]
 - (e) non-current assets that are measured at fair value less costs to sell in accordance with Ind AS 41 *Agriculture*⁴.
 - (f) contractual rights under insurance contracts as defined in Ind AS 104 *Insurance Contracts*.
- 5A The classification, presentation and measurement requirements in this Indian Accounting Standard applicable to a non-current asset (or disposal group) that is classified as held for sale apply also to a non-current asset (or disposal group) that is classified as held for distribution to owners acting in their capacity as owners (held for distribution to owners).
- 5B This Indian Accounting Standard specifies the disclosures required in respect of non-current assets (or disposal groups) classified as held for sale or discontinued operations. Disclosures in other Indian Accounting Standards do not apply to such assets (or disposal groups) unless those Indian Accounting Standards require:
- (a) specific disclosures in respect of non-current assets (or disposal groups) classified as held for sale or discontinued operations; or

² However, once the cash flows from an asset or group of assets are expected to arise principally from sale rather than continuing use, they become less dependent on cash flows arising from other assets, and a disposal group that was part of a cash-generating unit becomes a separate cash-generating unit.

³ Other than paragraphs 18 and 19, which require the assets in question to be measured in accordance with other applicable Accounting Standards.

⁴ This standard is under formulation.

- (b) disclosures about measurement of assets and liabilities within a disposal group that are not within the scope of the measurement requirement of Ind AS 105 and such disclosures are not already provided in the other notes to the financial statements.

Additional disclosures about non-current assets (or disposal groups) classified as held for sale or discontinued operations may be necessary to comply with the general requirements of Ind AS 1, in particular paragraphs 15 and 125 of that Standard.

Classification of non-current assets (or disposal groups) as held for sale or as held for distribution to owners

- 6 An entity shall classify a non-current asset (or disposal group) as held for sale if its carrying amount will be recovered principally through a sale transaction rather than through continuing use.
- 7 For this to be the case, the asset (or disposal group) must be available for immediate sale in its present condition subject only to terms that are usual and customary for sales of such assets (or disposal groups) and its sale must be highly probable. Thus, an asset (or disposal group) cannot be classified as a non-current asset (or disposal group) held for sale, if the entity intends to sell it in a distant future.
- 8 For the sale to be highly probable, the appropriate level of management must be committed to a plan to sell the asset (or disposal group), and an active programme to locate a buyer and complete the plan must have been initiated. Further, the asset (or disposal group) must be actively marketed for sale at a price that is reasonable in relation to its current fair value. In addition, the sale should be expected to qualify for recognition as a completed sale within one year from the date of classification, except as permitted by paragraph 9, and actions required to complete the plan should indicate that it is unlikely that significant changes to the plan will be made or that the plan will be withdrawn. The probability of shareholders' approval (if required in the jurisdiction) should be considered as part of the assessment of whether the sale is highly probable.
- 8A An entity that is committed to a sale plan involving loss of control of a subsidiary shall classify all the assets and liabilities of that subsidiary as held for sale when the criteria set out in paragraphs 6–8 are met, regardless of whether the entity will retain a non-controlling interest in its former subsidiary after the sale.
- 9 Events or circumstances may extend the period to complete the sale beyond one year. An extension of the period required to complete a sale does not preclude an asset (or disposal group) from being classified as held for sale if the delay is caused by events or circumstances beyond the entity's control and there is sufficient evidence that the entity remains committed to its plan to sell the asset (or disposal group). This will be the case when the criteria in Appendix B are met.
- 10 Sale transactions include exchanges of non-current assets for other non-current assets when the exchange has commercial substance in accordance with Ind AS 16 *Property, Plant and Equipment*.

- 11 When an entity acquires a non-current asset (or disposal group) exclusively with a view to its subsequent disposal, it shall classify the non-current asset (or disposal group) as held for sale at the acquisition date only if the one-year requirement in paragraph 8 is met (except as permitted by paragraph 9) and it is highly probable that any other criteria in paragraphs 7 and 8 that are not met at that date will be met within a short period following the acquisition (usually within three months).
- 12 If the criteria in paragraphs 7 and 8 are met after the reporting period, an entity shall not classify a non-current asset (or disposal group) as held for sale in those financial statements when issued. However, when those criteria are met after the reporting period but before the approval of the financial statements for issue, the entity shall disclose the information specified in paragraph 41(a), (b) and (d) in the notes.
- 12A A non-current asset (or disposal group) is classified as held for distribution to owners when the entity is committed to distribute the asset (or disposal group) to the owners. For this to be the case, the assets must be available for immediate distribution in their present condition and the distribution must be highly probable. For the distribution to be highly probable, actions to complete the distribution must have been initiated and should be expected to be completed within one year from the date of classification. Actions required to complete the distribution should indicate that it is unlikely that significant changes to the distribution will be made or that the distribution will be withdrawn. The probability of shareholders' approval (if required in the jurisdiction) should be considered as part of the assessment of whether the distribution is highly probable.

Non-current assets that are to be abandoned

- 13 An entity shall not classify as held for sale a non-current asset (or disposal group) that is to be abandoned. This is because its carrying amount will be recovered principally through continuing use. However, if the disposal group to be abandoned meets the criteria in paragraph 32(a)–(c), the entity shall present the results and cash flows of the disposal group as discontinued operations in accordance with paragraphs 33 and 34 at the date on which it ceases to be used. Non-current assets (or disposal groups) to be abandoned include non-current assets (or disposal groups) that are to be used to the end of their economic life and non-current assets (or disposal groups) that are to be closed rather than sold.
- 14 An entity shall not account for a non-current asset that has been temporarily taken out of use as if it had been abandoned.

Measurement of non-current assets (or disposal groups) classified as held for sale

Measurement of a non-current asset (or disposal group)

- 15 An entity shall measure a non-current asset (or disposal group) classified as held for sale at the lower of its carrying amount and fair value less costs to sell.

- 15A An entity shall measure a non-current asset (or disposal group) classified as held for distribution to owners at the lower of its carrying amount and fair value less costs to distribute.⁵
- 16 If a newly acquired asset (or disposal group) meets the criteria to be classified as held for sale (see paragraph 11), applying paragraph 15 will result in the asset (or disposal group) being measured on initial recognition at the lower of its carrying amount had it not been so classified (for example, cost) and fair value less costs to sell. Hence, if the asset (or disposal group) is acquired as part of a business combination, it shall be measured at fair value less costs to sell.
- 17 When the sale is expected to occur beyond one year, the entity shall measure the costs to sell at their present value. Any increase in the present value of the costs to sell that arises from the passage of time shall be presented in profit or loss as a financing cost.
- 18 Immediately before the initial classification of the asset (or disposal group) as held for sale, the carrying amounts of the asset (or all the assets and liabilities in the group) shall be measured in accordance with applicable Indian Accounting Standards.
- 19 On subsequent remeasurement of a disposal group, the carrying amounts of any assets and liabilities that are not within the scope of the measurement requirements of this Indian Accounting Standard, but are included in a disposal group classified as held for sale, shall be remeasured in accordance with applicable Indian Accounting Standards before the fair value less costs to sell of the disposal group is remeasured.

Recognition of impairment losses and reversals

- 20 An entity shall recognise an impairment loss for any initial or subsequent write-down of the asset (or disposal group) to fair value less costs to sell, to the extent that it has not been recognised in accordance with paragraph 19.
- 21 An entity shall recognise a gain for any subsequent increase in fair value less costs to sell of an asset, but not in excess of the cumulative impairment loss that has been recognised either in accordance with this Indian Accounting Standard or previously in accordance with Ind AS 36 *Impairment of Assets*.
- 22 An entity shall recognise a gain for any subsequent increase in fair value less costs to sell of a disposal group:
- (a) to the extent that it has not been recognised in accordance with paragraph 19; but
 - (b) not in excess of the cumulative impairment loss that has been recognised, either in accordance with this Indian Accounting Standard or previously in accordance with Ind AS 36, on the non-current assets that are within the scope of the measurement requirements of this Indian Accounting Standard.

⁵ Costs to distribute are the incremental costs directly attributable to the distribution, excluding finance costs and income tax expense.

- 23 The impairment loss (or any subsequent gain) recognised for a disposal group shall reduce (or increase) the carrying amount of the non-current assets in the group that are within the scope of the measurement requirements of this Indian Accounting Standard, in the order of allocation set out in paragraphs 104(a) and (b) and 122 of Ind AS 36.
- 24 A gain or loss not previously recognised by the date of the sale of a non-current asset (or disposal group) shall be recognised at the date of derecognition. Requirements relating to derecognition are set out in:
- (a) paragraphs 67–72 of Ind AS 16 for property, plant and equipment, and
 - (b) paragraphs 112–117 of Ind AS 38 *Intangible Assets* for intangible assets.
- 25 An entity shall not depreciate (or amortise) a non-current asset while it is classified as held for sale or while it is part of a disposal group classified as held for sale. Interest and other expenses attributable to the liabilities of a disposal group classified as held for sale shall continue to be recognised.

Changes to a plan of sale

- 26 If an entity has classified an asset (or disposal group) as held for sale, but the criteria in paragraphs 7–9 are no longer met, the entity shall cease to classify the asset (or disposal group) as held for sale.
- 27 The entity shall measure a non-current asset that ceases to be classified as held for sale (or ceases to be included in a disposal group classified as held for sale) at the lower of:
- (a) its carrying amount before the asset (or disposal group) was classified as held for sale, adjusted for any depreciation, amortisation or revaluations that would have been recognised had the asset (or disposal group) not been classified as held for sale, and
 - (b) its *recoverable amount* at the date of the subsequent decision not to sell.⁶
- 28 The entity shall include any required adjustment to the carrying amount of a non-current asset that ceases to be classified as held for sale in profit or loss⁷ from continuing operations in the period in which the criteria in paragraphs 7–9 are no longer met. The entity shall present that adjustment in the same caption in the statement of profit and loss used to present a gain or loss, if any, recognised in accordance with paragraph 37.
- 29 If an entity removes an individual asset or liability from a disposal group classified as held for sale, the remaining assets and liabilities of the disposal

⁶ If the non-current asset is part of a cash-generating unit, its recoverable amount is the carrying amount that would have been recognised after the allocation of any impairment loss arising on that cash-generating unit in accordance with Ind AS 36.

⁷ Unless the asset is property, plant and equipment or an intangible asset that had been revalued in accordance with Ind AS 16 or Ind AS 38 before classification as held for sale, in which case the adjustment shall be treated as a revaluation increase or decrease.

group to be sold shall continue to be measured as a group only if the group meets the criteria in paragraphs 7–9. Otherwise, the remaining non-current assets of the group that individually meet the criteria to be classified as held for sale shall be measured individually at the lower of their carrying amounts and fair values less costs to sell at that date. Any non-current assets that do not meet the criteria shall cease to be classified as held for sale in accordance with paragraph 26.

Presentation and disclosure

- 30 An entity shall present and disclose information that enables users of the financial statements to evaluate the financial effects of discontinued operations and disposals of non-current assets (or disposal groups).

Presenting discontinued operations

- 31 A component of an entity comprises operations and cash flows that can be clearly distinguished, operationally and for financial reporting purposes, from the rest of the entity. In other words, a component of an entity will have been a cash-generating unit or a group of cash-generating units while being held for use.
- 32 A discontinued operation is a component of an entity that either has been disposed of, or is classified as held for sale, and
- (a) represents a separate major line of business or geographical area of operations,
 - (b) is part of a single co-ordinated plan to dispose of a separate major line of business or geographical area of operations or
 - (c) is a subsidiary acquired exclusively with a view to resale.
- 33 An entity shall disclose:
- (a) a single amount in the statement of profit and loss comprising the total of:
 - (i) the post-tax profit or loss of discontinued operations and
 - (ii) the post-tax gain or loss recognised on the measurement to fair value less costs to sell or on the disposal of the assets or disposal group(s) constituting the discontinued operation.
 - (b) an analysis of the single amount in (a) into:
 - (i) the revenue, expenses and pre-tax profit or loss of discontinued operations;

- (ii) the related income tax expense as required by paragraph 81(h) of Ind AS 12;
- (iii) the gain or loss recognised on the measurement to fair value less costs to sell or on the disposal of the assets or disposal group(s) constituting the discontinued operation, and
- (iv) the related income tax expense as required by paragraph 81(h) of Ind AS 12.

The analysis may be presented in the notes or in the statement of profit and loss. If it is presented in the statement of profit and loss it shall be presented in a section identified as relating to discontinued operations, ie separately from continuing operations. The analysis is not required for disposal groups that are newly acquired subsidiaries that meet the criteria to be classified as held for sale on acquisition (see paragraph 11).

- (c) the net cash flows attributable to the operating, investing and financing activities of discontinued operations. These disclosures may be presented either in the notes or in the financial statements. These disclosures are not required for disposal groups that are newly acquired subsidiaries that meet the criteria to be classified as held for sale on acquisition (see paragraph 11).
- (d) the amount of income from continuing operations and from discontinued operations attributable to owners of the parent. These disclosures may be presented either in the notes or in the statement of profit and loss.

33A [Refer to Appendix 1]

34 An entity shall re-present the disclosures in paragraph 33 for prior periods presented in the financial statements so that the disclosures relate to all operations that have been discontinued by the end of the reporting period for the latest period presented.

35 Adjustments in the current period to amounts previously presented in discontinued operations that are directly related to the disposal of a discontinued operation in a prior period shall be classified separately in discontinued operations. The nature and amount of such adjustments shall be disclosed. Examples of circumstances in which these adjustments may arise include the following:

- (a) the resolution of uncertainties that arise from the terms of the disposal transaction, such as the resolution of purchase price adjustments and indemnification issues with the purchaser.
- (b) the resolution of uncertainties that arise from and are directly related to the operations of the component before its disposal, such as environmental and product warranty obligations retained by the seller.
- (c) the settlement of employee benefit plan obligations, provided that the settlement is directly related to the disposal transaction.

- 36 If an entity ceases to classify a component of an entity as held for sale, the results of operations of the component previously presented in discontinued operations in accordance with paragraphs 33–35 shall be reclassified and included in income from continuing operations for all periods presented. The amounts for prior periods shall be described as having been re-presented.
- 36A An entity that is committed to a sale plan involving loss of control of a subsidiary shall disclose the information required in paragraphs 33–36 when the subsidiary is a disposal group that meets the definition of a discontinued operation in accordance with paragraph 32.

Gains or losses relating to continuing operations

- 37 Any gain or loss on the remeasurement of a non-current asset (or disposal group) classified as held for sale that does not meet the definition of a discontinued operation shall be included in profit or loss from continuing operations.

Presentation of a non-current asset or disposal group classified as held for sale

- 38 An entity shall present a non-current asset classified as held for sale and the assets of a disposal group classified as held for sale separately from other assets in the balance sheet. The liabilities of a disposal group classified as held for sale shall be presented separately from other liabilities in the balance sheet. Those assets and liabilities shall not be offset and presented as a single amount. The major classes of assets and liabilities classified as held for sale shall be separately disclosed either in the balance sheet or in the notes, except as permitted by paragraph 39. An entity shall present separately any cumulative income or expense recognised in other comprehensive income relating to a non-current asset (or disposal group) classified as held for sale.
- 39 If the disposal group is a newly acquired subsidiary that meets the criteria to be classified as held for sale on acquisition (see paragraph 11), disclosure of the major classes of assets and liabilities is not required.
- 40 An entity shall not reclassify or re-present amounts presented for non-current assets or for the assets and liabilities of disposal groups classified as held for sale in the balance sheet for prior periods to reflect the classification in the balance sheet for the latest period presented.

Additional disclosures

- 41 An entity shall disclose the following information in the notes in the period in which a non-current asset (or disposal group) has been either classified as held for sale or sold:

- (a) a description of the non-current asset (or disposal group);
- (b) a description of the facts and circumstances of the sale, or leading to the expected disposal, and the expected manner and timing of that disposal;
- (c) the gain or loss recognised in accordance with paragraphs 20–22 and, if not separately presented in the statement of profit and loss, the caption in the statement of profit and loss that includes that gain or loss;
- (d) if applicable, the reportable segment in which the non-current asset (or disposal group) is presented in accordance with Ind AS 108 *Operating Segments*.

42 If either paragraph 26 or paragraph 29 applies, an entity shall disclose, in the period of the decision to change the plan to sell the non-current asset (or disposal group), a description of the facts and circumstances leading to the decision and the effect of the decision on the results of operations for the period and any prior periods presented.

Appendix A

Defined terms

This appendix is an integral part of the Indian Accounting Standard.

cash-generating unit	The smallest identifiable group of assets that generates cash inflows that are largely independent of the cash inflows from other assets or groups of assets.
component of an entity	Operations and cash flows that can be clearly distinguished, operationally and for financial reporting purposes, from the rest of the entity.
costs to sell	The incremental costs directly attributable to the disposal of an asset (or disposal group), excluding finance costs and income tax expense.
current asset	An entity shall classify an asset as current when: <ul style="list-style-type: none"> (a) it expects to realise the asset, or intends to sell or consume it, in its normal operating cycle; (b) it holds the asset primarily for the purpose of trading; (c) it expects to realise the asset within twelve months after the reporting period; or (d) the asset is cash or a cash equivalent (as defined in Ind AS 7) unless the asset is restricted from being exchanged or used to settle a liability for at least twelve months after the reporting period.

discontinued operation	<p>A component of an entity that either has been disposed of or is classified as held for sale and:</p> <ul style="list-style-type: none"> (a) represents a separate major line of business or geographical area of operations, (b) is part of a single co-ordinated plan to dispose of a separate major line of business or geographical area of operations or (c) is a subsidiary acquired exclusively with a view to resale.
disposal group	A group of assets to be disposed of, by sale or otherwise, together as a group in a single transaction, and liabilities directly associated with those assets that will be transferred in the transaction. The group includes goodwill acquired in a business combination if the group is a cash-generating unit to which goodwill has been allocated in accordance with the requirements of paragraphs 80–87 of Ind AS 36 <i>Impairment of Assets</i> or if it is an operation within such a cash-generating unit.
fair value	The amount for which an asset could be exchanged, or a liability settled, between knowledgeable, willing parties in an arm's length transaction.
firm purchase commitment	An agreement with an unrelated party, binding on both parties and usually legally enforceable, that (a) specifies all significant terms, including the price and timing ^a of the transactions, and (b) includes a disincentive for non-performance that is sufficiently large to make performance highly probable.
highly probable	Significantly more likely than probable.
non-current asset	An asset that does not meet the definition of a current asset.
probable	More likely than not.
recoverable amount	The higher of an asset's fair value less costs to sell and its value in use.
value in use	The present value of estimated future cash flows expected to arise from the continuing use of an asset and from its disposal at the end of its useful life.

Appendix B

Application supplement

This appendix is an integral part of the Indian Accounting Standard.

Extension of the period required to complete a sale

B1 As noted in paragraph 9, an extension of the period required to complete a sale does not preclude an asset (or disposal group) from being classified as held for sale if the delay is caused by events or circumstances beyond the entity's control and there is sufficient evidence that the entity remains committed to its plan to sell the asset (or disposal group). An exception to the one-year requirement in paragraph 8 shall therefore apply in the following situations in which such events or circumstances arise:

- (a) at the date an entity commits itself to a plan to sell a non-current asset (or disposal group) it reasonably expects that others (not a buyer) will impose conditions on the transfer of the asset (or disposal group) that will extend the period required to complete the sale, and:
 - (i) actions necessary to respond to those conditions cannot be initiated until after a *firm purchase commitment* is obtained, and
 - (ii) a firm purchase commitment is highly probable within one year.
- (b) an entity obtains a firm purchase commitment and, as a result, a buyer or others unexpectedly impose conditions on the transfer of a non-current asset (or disposal group) previously classified as held for sale that will extend the period required to complete the sale, and:
 - (i) timely actions necessary to respond to the conditions have been taken, and
 - (ii) a favourable resolution of the delaying factors is expected.
- (c) during the initial one-year period, circumstances arise that were previously considered unlikely and, as a result, a non-current asset (or disposal group) previously classified as held for sale is not sold by the end of that period, and:
 - (i) during the initial one-year period the entity took action necessary to respond to the change in circumstances,
 - (ii) the non-current asset (or disposal group) is being actively marketed at a price that is reasonable, given the change in circumstances, and
 - (iii) the criteria in paragraphs 7 and 8 are met.

Appendix C

References to matters contained in other Indian Accounting Standards

This Appendix is an integral part of Indian Accounting Standard 105.

This appendix makes reference to Appendix A, *Distributions of Non-cash Assets to Owners* contained in Ind AS 10, *Events after the Reporting Period*.

Appendix D

Contents

Guidance on Implementing Ind AS 105 *Non-current Assets Held for Sale and Discontinued Operations*

Availability for immediate sale (paragraph 7)	Examples 1–3
Completion of sale expected within one year (paragraph 8)	Example 4
Exceptions to the criterion that the sale should be expected to be completed in one year (paragraphs 8 and B1)	Examples 5–7
Determining whether an asset has been abandoned (paragraphs 13 and 14)	Example 8
Presenting a discontinued operation that has been abandoned (paragraph 13)	Example 9
Allocation of an impairment loss on a disposal group (paragraph 23)	Example 10
Presenting discontinued operations in the statement of profit and loss (paragraph 38)	Example 11
Presenting non-current assets or disposal groups classified as held for sale (paragraph 38)	Example 12
Measuring and presenting subsidiaries acquired with a view to resale and classified as held for sale (paragraphs 11 and 38)	Example 13

Guidance on implementing Ind AS 105 *Non-current Assets Held for Sale and Discontinued Operations*

This guidance accompanies, but is not part of, Ind AS 105.

Availability for immediate sale (paragraph 7)

To qualify for classification as held for sale, a non-current asset (or disposal group) must be available for immediate sale in its present condition subject only to terms that are usual and customary for sales of such assets (or disposal groups) (paragraph 7). A non-current asset (or disposal group) is available for immediate sale if an entity currently has the intention and ability to transfer the asset (or disposal group) to a buyer in its present condition. Examples 1–3 illustrate situations in which the criterion in paragraph 7 would or would not be met.

Example 1

An entity is committed to a plan to sell its headquarters building and has initiated actions to locate a buyer.

- (a) The entity intends to transfer the building to a buyer after it vacates the building. The time necessary to vacate the building is usual and customary for sales of such assets. The criterion in paragraph 7 would be met at the plan commitment date.
- (b) The entity will continue to use the building until construction of a new headquarters building is completed. The entity does not intend to transfer the existing building to a buyer until after construction of the new building is completed (and it vacates the existing building). The delay in the timing of the transfer of the existing building imposed by the entity (seller) demonstrates that the building is not available for immediate sale. The criterion in paragraph 7 would not be met until construction of the new building is completed, even if a firm purchase commitment for the future transfer of the existing building is obtained earlier.

Example 2

An entity is committed to a plan to sell a manufacturing facility and has initiated actions to locate a buyer. At the plan commitment date, there is a backlog of uncompleted customer orders.

- (a) The entity intends to sell the manufacturing facility with its operations. Any uncompleted customer orders at the sale date will be transferred to the buyer. The transfer of uncompleted customer orders at the sale date will not affect the timing of the transfer of the facility. The criterion in paragraph 7 would be met at the plan commitment date.
- (b) The entity intends to sell the manufacturing facility, but without its operations. The entity does not intend to transfer the facility to a buyer until after it ceases all operations of the facility and eliminates the backlog of uncompleted customer orders. The delay in the timing of the transfer of the facility imposed by the entity (seller) demonstrates that the facility is not available for immediate sale. The criterion in paragraph 7 would not be met until the

operations of the facility cease, even if a firm purchase commitment for the future transfer of the facility were obtained earlier.

Example 3

An entity acquires through foreclosure a property comprising land and buildings that it intends to sell.

- (a) The entity does not intend to transfer the property to a buyer until after it completes renovations to increase the property's sales value. The delay in the timing of the transfer of the property imposed by the entity (seller) demonstrates that the property is not available for immediate sale. The criterion in paragraph 7 would not be met until the renovations are completed.
- (b) After the renovations are completed and the property is classified as held for sale but before a firm purchase commitment is obtained, the entity becomes aware of environmental damage requiring remediation. The entity still intends to sell the property. However, the entity does not have the ability to transfer the property to a buyer until after the remediation is completed. The delay in the timing of the transfer of the property imposed by others before a firm purchase commitment is obtained demonstrates that the property is not available for immediate sale. The criterion in paragraph 7 would not continue to be met. The property would be reclassified as held and used in accordance with paragraph 26.

Completion of sale expected within one year (paragraph 8)

Example 4

To qualify for classification as held for sale, the sale of a non-current asset (or disposal group) must be highly probable (paragraph 7), and transfer of the asset (or disposal group) must be expected to qualify for recognition as a completed sale within one year (paragraph 8). That criterion would not be met if, for example:

- (a) an entity that is a commercial leasing and finance company is holding for sale or lease equipment that has recently ceased to be leased and the ultimate form of a future transaction (sale or lease) has not yet been determined.
- (b) an entity is committed to a plan to 'sell' a property that is in use, and the transfer of the property will be accounted for as a sale and finance leaseback.

Exceptions to the criterion in paragraph 8

An exception to the one-year requirement in paragraph 8 applies in limited situations in which the period required to complete the sale of a non-current asset (or disposal group) will be (or has been) extended by events or circumstances beyond an entity's control and specified conditions are met (paragraphs 9 and B1). Examples 5–7 illustrate those situations

Example 5

An entity in the power generating industry is committed to a plan to sell a disposal group that represents a significant portion of its regulated operations. The sale requires regulatory approval, which could extend the period required to complete the sale beyond one year. Actions necessary to obtain that approval cannot be initiated

until after a buyer is known and a firm purchase commitment is obtained. However, a firm purchase commitment is highly probable within one year. In that situation, the conditions in paragraph B1(a) for an exception to the one-year requirement in paragraph 8 would be met.

Example 6

An entity is committed to a plan to sell a manufacturing facility in its present condition and classifies the facility as held for sale at that date. After a firm purchase commitment is obtained, the buyer's inspection of the property identifies environmental damage not previously known to exist. The entity is required by the buyer to make good the damage, which will extend the period required to complete the sale beyond one year. However, the entity has initiated actions to make good the damage, and satisfactory rectification of the damage is highly probable. In that situation, the conditions in paragraph B1(b) for an exception to the one-year requirement in paragraph 8 would be met.

Example 7

An entity is committed to a plan to sell a non-current asset and classifies the asset as held for sale at that date.

- (a) During the initial one-year period, the market conditions that existed at the date the asset was classified initially as held for sale deteriorate and, as a result, the asset is not sold by the end of that period. During that period, the entity actively solicited but did not receive any reasonable offers to purchase the asset and, in response, reduced the price. The asset continues to be actively marketed at a price that is reasonable given the change in market conditions, and the criteria in paragraphs 7 and 8 are therefore met. In that situation, the conditions in paragraph B1(c) for an exception to the one-year requirement in paragraph 8 would be met. At the end of the initial one-year period, the asset would continue to be classified as held for sale.
- (b) During the following one-year period, market conditions deteriorate further, and the asset is not sold by the end of that period. The entity believes that the market conditions will improve and has not further reduced the price of the asset. The asset continues to be held for sale, but at a price in excess of its current fair value. In that situation, the absence of a price reduction demonstrates that the asset is not available for immediate sale as required by paragraph 7. In addition, paragraph 8 also requires an asset to be marketed at a price that is reasonable in relation to its current fair value. Therefore, the conditions in paragraph B1(c) for an exception to the one-year requirement in paragraph 8 would not be met. The asset would be reclassified as held and used in accordance with paragraph 26.

Determining whether an asset has been abandoned

Paragraphs 13 and 14 of the Indian Accounting Standard specify requirements for when assets are to be treated as abandoned. Example 8 illustrates when an asset has not been abandoned.

Example 8

An entity ceases to use a manufacturing plant because demand for its product has declined. However, the plant is maintained in workable condition and it is expected that it will be brought back into use if demand picks up. The plant is not regarded as abandoned.

Presenting a discontinued operation that has been abandoned

Paragraph 13 of the Indian Accounting Standard prohibits assets that will be abandoned from being classified as held for sale. However, if the assets to be abandoned are a major line of business or geographical area of operations, they are reported in discontinued operations at the date at which they are abandoned. Example 9 illustrates this.

Example 9

In October 20X5 an entity decides to abandon all of its cotton mills, which constitute a major line of business. All work stops at the cotton mills during the year ended 31 December 20X6. In the financial statements for the year ended 31 December 20X5, results and cash flows of the cotton mills are treated as continuing operations. In the financial statements for the year ended 31 December 20X6, the results and cash flows of the cotton mills are treated as discontinued operations and the entity makes the disclosures required by paragraphs 33 and 34 of the Indian Accounting Standard.

Allocation of an impairment loss on a disposal group

Paragraph 23 of the Indian Accounting Standard requires an impairment loss (or any subsequent gain) recognised for a disposal group to reduce (or increase) the carrying amount of the non-current assets in the group that are within the scope of the measurement requirements of the Indian Accounting Standard, in the order of allocation set out in paragraphs 104 and 122 of Ind AS 36. Example 10 illustrates the allocation of an impairment loss on a disposal group.

Example 10

An entity plans to dispose of a group of its assets (as an asset sale). The assets form a disposal group, and are measured as follows:

	Carrying amount at the end of the reporting period before classification as held for sale	Carrying amount as remeasured immediately before classification as held for sale
	Rs	Rs
Goodwill	1,500	1,500
Property, plant and equipment (carried at revalued amounts)	4,600	4,000
Property, plant and equipment (carried at cost)	5,700	5,700

Inventory	2,400	2,200
AFS financial assets	1,800	1,500
Total	16,000	14,900

The entity recognises the loss of Rs 1,100 (Rs16,000 – Rs14,900) immediately before classifying the disposal group as held for sale.

The entity estimates that fair value less costs to sell of the disposal group amounts to Rs13,000. Because an entity measures a disposal group classified as held for sale at the lower of its carrying amount and fair value less costs to sell, the entity recognises an impairment loss of Rs1,900 (Rs14,900 – Rs13,000) when the group is initially classified as held for sale.

The impairment loss is allocated to non-current assets to which the measurement requirements of the Indian Accounting Standard are applicable. Therefore, no impairment loss is allocated to inventory and AFS financial assets. The loss is allocated to the other assets in the order of allocation set out in paragraphs 104 and 122 of Ind AS 36.

The allocation can be illustrated as follows:

	Carrying amount as remeasured immediately before classification as held for sale	Allocated impairment loss	Carrying amount after allocation of impairment loss
	Rs	Rs	Rs
Goodwill	1,500	(1,500)	0
Property, plant and equipment (carried at revalued amounts)	4,000	(165)	3,835
Property, plant and equipment (carried at cost)	5,700	(235)	5,465
Inventory	2,200	–	2,200
AFS financial assets	1,500	–	1,500
Total	14,900	(1,900)	13,000

First, the impairment loss reduces any amount of goodwill. Then, the residual loss is allocated to other assets pro rata based on the carrying amounts of those assets.

Presenting discontinued operations in the statement of profit and loss

Paragraph 33 of the Indian Accounting Standard requires an entity to disclose a single amount in the statement of profit and loss for discontinued operations with an analysis in the notes or in a section of the statement of profit and loss separate from continuing operations. Example 11 illustrates how these requirements might be met.

Example 11**XYZ GROUP - STATEMENT OF PROFIT AND LOSS FOR THE YEAR ENDED
31 DECEMBER 20X2 (illustrating the classification of expenses by function)**

(Rupees in thousands)	20X2	20X1
Continuing operations		
Revenue	X	X
Cost of sales	<u>(X)</u>	<u>(X)</u>
Gross profit	X	X
Other income	X	X
Distribution costs	(X)	(X)
Administrative expenses	(X)	(X)
Other expenses	(X)	(X)
Finance costs	(X)	(X)
Share of profit of associates	<u>X</u>	<u>X</u>
Profit before tax	X	X
Income tax expense	<u>(X)</u>	<u>(X)</u>
Profit for the period from continuing operations	<u>X</u>	<u>X</u>
Discontinued operations		
Profit for the period from discontinued operations ⁸	<u>X</u>	<u>X</u>
Profit for the period	<u>X</u>	<u>X</u>

Attributable to:

Owners of the parent

Profit for the period from continuing operations	X	X
Profit for the period from discontinued operations	<u>X</u>	<u>X</u>
Profit for the period attributable to owners of the parent	X	X

⁸ The required analysis would be given in the notes.

Non-controlling interests

Profit for the period from continuing operations	X	X
Profit for the period from discontinued operations	<u>X</u>	<u>X</u>
Profit for the period attributable to non-controlling interests	<u>X</u>	<u>X</u>
	<u>X</u>	<u>X</u>

Presenting non-current assets or disposal groups classified as held for sale

Paragraph 38 of the Indian Accounting Standard requires an entity to present a non-current asset classified as held for sale and the assets of a disposal group classified as held for sale separately from other assets in the balance sheet. The liabilities of a disposal group classified as held for sale are also presented separately from other liabilities in the balance sheet. Those assets and liabilities are not offset and presented as a single amount. Example 12 illustrates these requirements.

Example 12

At the end of 20X5, an entity decides to dispose of part of its assets (and directly associated liabilities). The disposal, which meets the criteria in paragraphs 7 and 8 to be classified as held for sale, takes the form of two disposal groups, as follows:

	Carrying amount after classification as held for sale	
	Disposal group I:	Disposal group II:
	Rs	Rs
Property, plant and equipment	4,900	1,700
AFS financial asset	1,400 ⁹	—
Liabilities	(2,400)	(900)
Net carrying amount of disposal group	3,900	800

The presentation in the entity's balance sheet of the disposal groups classified as held for sale can be shown as follows:

	20X5	20X4
ASSETS		
Non-current assets		
AAA	X	X
BBB	X	X
CCC	X	X
	<u>X</u>	<u>X</u>

Current assets

DDD	X	X
-----	---	---

EEE	<u>X</u>	<u>X</u>
-----	----------	----------

	X	X
--	---	---

Non-current assets classified as held for sale	<u>8,000</u>	<u>-</u>
--	--------------	----------

	X	X
--	---	---

Total assets	<u><u>X</u></u>	<u><u>X</u></u>
--------------	-----------------	-----------------

EQUITY AND LIABILITIES**Equity attributable to owners of the parent**

FFF	X	X
-----	---	---

GGG	X	X
-----	---	---

Amounts recognised in other comprehensive income and accumulated in equity relating to non-current assets held for sale

	<u>400</u>	<u>-</u>
--	------------	----------

	X	X
--	---	---

Non-controlling interests	<u>X</u>	<u>X</u>
---------------------------	----------	----------

Total equity	<u><u>X</u></u>	<u><u>X</u></u>
--------------	-----------------	-----------------

⁹ An amount of Rs 400 relating to these assets has been recognised in other comprehensive income and accumulated in equity.

Non-current liabilities

HHH	X	X
-----	---	---

III	X	X
-----	---	---

JJJ	<u>X</u>	<u>X</u>
-----	----------	----------

	<u>X</u>	<u>X</u>
--	----------	----------

Current liabilities

KKK	X	X
-----	---	---

LLL	X	X
-----	---	---

MMM	<u>X</u>	<u>X</u>
-----	----------	----------

Liabilities directly associated with non-current assets classified as held for sale

	<u>3,300</u>	<u>-</u>
--	--------------	----------

	<u>X</u>	<u>X</u>
--	----------	----------

Total liabilities	<u><u>X</u></u>	<u><u>X</u></u>
-------------------	-----------------	-----------------

Total equity and liabilities	<u><u>X</u></u>	<u><u>X</u></u>
------------------------------	-----------------	-----------------

824.GI/11-66

The presentation requirements for assets (or disposal groups) classified as held for sale at the end of the reporting period do not apply retrospectively. The comparative balance sheet for any previous periods are therefore not re-presented.

Measuring and presenting subsidiaries acquired with a view to resale and classified as held for sale

A subsidiary acquired with a view to sale is not exempt from consolidation in accordance with Ind AS 27 *Consolidated and Separate Financial Statements*. However, if it meets the criteria in paragraph 11, it is presented as a disposal group classified as held for sale. Example 13 illustrates these requirements.

Example 13

Entity A acquires an entity H, which is a holding company with two subsidiaries, S1 and S2. S2 is acquired exclusively with a view to sale and meets the criteria to be classified as held for sale. In accordance with paragraph 32(c), S2 is also a discontinued operation.

The estimated fair value less costs to sell of S2 is Rs135. A accounts for S2 as follows:

- initially, A measures the identifiable liabilities of S2 at fair value, say at Rs 40
- initially, A measures the acquired assets as the fair value less costs to sell of S2 (Rs 135) plus the fair value of the identifiable liabilities (Rs40), ie at Rs175
- at the end of the reporting period, A remeasures the disposal group at the lower of its cost and fair value less costs to sell, say at Rs130. The liabilities are remeasured in accordance with applicable Indian Accounting Standards, say at Rs35. The total assets are measured at Rs130 + Rs35, ie at Rs165
- at the end of the reporting period, A presents the assets and liabilities separately from other assets and liabilities in its consolidated financial statements as illustrated in Example 12 *Presenting non-current assets or disposal groups classified as held for sale*, and
- in the statement of profit and loss, A presents the total of the post-tax profit or loss of S2 and the post-tax gain or loss recognised on the subsequent remeasurement of S2, which equals the remeasurement of the disposal group from Rs135 to Rs 130.

Further analysis of the assets and liabilities or of the change in value of the disposal group is not required.

Appendix 1

Comparison with IFRS 5, *Non-current Assets Held for Sale and Discontinued Operations*

Note: This appendix is not a part of the Indian Accounting Standard. The purpose of this Appendix is only to bring out the differences, if any, between Indian Accounting Standard (Ind AS) 105 and the corresponding International Financial Reporting Standard (IFRS) 5, Non-current Assets Held for Sale and Discontinued Operations issued by the International Accounting Standards Board.

1. The transitional provisions given in IFRS 5 have not been given in Ind AS 105, since all transitional provisions related to Ind ASs, wherever considered appropriate have been included in Ind AS 101, *First-time Adoption of Indian Accounting Standards* corresponding to IFRS 1, *First-time Adoption of International Financial Reporting Standards*.
2. Different terminology is used in this standard, e.g., the term 'balance sheet' is used instead of 'Statement of financial position' and 'Statement of profit and loss' is used instead of 'Statement of comprehensive income'. Words 'approval of the financial statements for issue have been used instead of 'authorisation of the financial statements for issue' in the context of financial statements considered for the purpose of events after the reporting period.
3. Requirements regarding presentation of discontinued operations in the separate income statement, where separate income statement is presented under paragraph 33A of IFRS 5 have been deleted. This change is consequential to the removal of option regarding two statement approach in Ind AS 1. Ind AS 1 requires that the components of profit or loss and components of other comprehensive income shall be presented as a part of the statement of profit and loss. However, paragraph number 33A has been retained in Ind AS 105 to maintain consistency with paragraph numbers of IFRS 5.
4. Paragraph 5(d) of IFRS 5 deals with non-current assets that are accounted for in accordance with the fair value model in IAS 40 *Investment Property*. Since Ind AS 40 prohibits the use of fair value model, this paragraph is deleted in Ind AS 105.

Indian Accounting Standard (Ind AS) 106¹

Exploration for and Evaluation of Mineral Resources

(This Indian Accounting Standard includes paragraphs set in bold type and plain type, which have equal authority. Paragraphs in bold type indicate the main principles.).

Objective

- 1 The objective of this Indian Accounting Standard is to specify the financial reporting for the *exploration for and evaluation of mineral resources*.
- 2 In particular, the Indian Accounting Standard requires:
 - (a) limited improvements to existing accounting practices for *exploration and evaluation expenditures*.
 - (b) entities that recognise *exploration and evaluation assets* to assess such assets for impairment in accordance with this Indian Accounting Standard and measure any impairment in accordance with Ind AS 36 *Impairment of Assets*.
 - (c) disclosures that identify and explain the amounts in the entity's financial statements arising from the exploration for and evaluation of mineral resources and help users of those financial statements understand the amount, timing and certainty of future cash flows from any exploration and evaluation assets recognised.

Scope

- 3 An entity shall apply the Indian Accounting Standard to exploration and evaluation expenditures that it incurs.
- 4 The Indian Accounting Standard does not address other aspects of accounting by entities engaged in the exploration for and evaluation of mineral resources.
- 5 An entity shall not apply the Indian Accounting Standard to expenditures incurred:

¹ Ind AS 106, *Exploration for and Evaluation of Mineral Resources* will be applied with modification from a date to be notified later on.

- (a) before the exploration for and evaluation of mineral resources, such as expenditures incurred before the entity has obtained the legal rights to explore a specific area.
- (b) after the technical feasibility and commercial viability of extracting a mineral resource are demonstrable.

Recognition of Exploration and Evaluation Assets

Temporary exemption from Ind AS 8 paragraphs 11 and 12

- 6 When developing its accounting policies, an entity recognising exploration and evaluation assets shall apply paragraph 10 of Ind AS 8 *Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors*.
- 7 Paragraphs 11 and 12 of Ind AS 8 specify sources of authoritative requirements and guidance that management is required to consider in developing an accounting policy for an item if no Accounting Standard applies specifically to that item. Subject to paragraphs 9 and 10 below, this Accounting Standard exempts an entity from applying those paragraphs to its accounting policies for the recognition and measurement of exploration and evaluation assets.

Measurement of Exploration and Evaluation Assets

Measurement at recognition

- 8 Exploration and evaluation assets shall be measured at cost.

Elements of cost of exploration and evaluation assets

- 9 An entity shall determine an accounting policy specifying which expenditures are recognised as exploration and evaluation assets and apply the policy consistently. In making this determination, an entity considers the degree to which the expenditure can be associated with finding specific mineral resources. The following are examples of expenditures that might be included in the initial measurement of exploration and evaluation assets (the list is not exhaustive):
 - (a) acquisition of rights to explore;
 - (b) topographical, geological, geochemical and geophysical studies;
 - (c) exploratory drilling;

- (d) trenching;
 - (e) sampling; and
 - (f) activities in relation to evaluating the technical feasibility and commercial viability of extracting a mineral resource.
- 10 Expenditures related to the development of mineral resources shall not be recognised as exploration and evaluation assets. The *Framework for the Preparation and Presentation of Financial Statements* issued by the Institute of Chartered Accountants of India and Ind AS 38 *Intangible Assets* provide guidance on the recognition of assets arising from development.
- 11 In accordance with Ind AS 37 *Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets* an entity recognises any obligations for removal and restoration that are incurred during a particular period as a consequence of having undertaken the exploration for and evaluation of mineral resources.

Measurement after recognition

- 12 After recognition, an entity shall apply either the cost model or the revaluation model to the exploration and evaluation assets. If the revaluation model is applied (either the model in Ind AS 16 *Property, Plant and Equipment* or the model in Ind AS 38) it shall be consistent with the classification of the assets (see paragraph 15).

Changes in accounting policies

- 13 An entity may change its accounting policies for exploration and evaluation expenditures if the change makes the financial statements more relevant to the economic decision-making needs of users and no less reliable, or more reliable and no less relevant to those needs. An entity shall judge relevance and reliability using the criteria in Ind AS 8.
- 14 To justify changing its accounting policies for exploration and evaluation expenditures, an entity shall demonstrate that the change brings its financial statements closer to meeting the criteria in Ind AS 8, but the change need not achieve full compliance with those criteria.

Presentation

Classification of exploration and evaluation assets

- 15 An entity shall classify exploration and evaluation assets as tangible or intangible according to the nature of the assets acquired and apply the classification consistently.

- 16 Some exploration and evaluation assets are treated as intangible (eg drilling rights), whereas others are tangible (eg vehicles and drilling rigs). To the extent that a tangible asset is consumed in developing an intangible asset, the amount reflecting that consumption is part of the cost of the intangible asset. However, using a tangible asset to develop an intangible asset does not change a tangible asset into an intangible asset.

Reclassification of exploration and evaluation assets

- 17 An exploration and evaluation asset shall no longer be classified as such when the technical feasibility and commercial viability of extracting a mineral resource are demonstrable. Exploration and evaluation assets shall be assessed for impairment, and any impairment loss recognised, before reclassification.

Impairment

Recognition and measurement

- 18 **Exploration and evaluation assets shall be assessed for impairment when facts and circumstances suggest that the carrying amount of an exploration and evaluation asset may exceed its recoverable amount. When facts and circumstances suggest that the carrying amount exceeds the recoverable amount, an entity shall measure, present and disclose any resulting impairment loss in accordance with Ind AS 36, except as provided by paragraph 21 below.**
- 19 For the purposes of exploration and evaluation assets only, paragraph 20 of this Accounting Standard shall be applied rather than paragraphs 8-17 of Ind AS 36 when identifying an exploration and evaluation asset that may be impaired. Paragraph 20 uses the term 'assets' but applies equally to separate exploration and evaluation assets or a cash-generating unit.
- 20 One or more of the following facts and circumstances indicate that an entity should test exploration and evaluation assets for impairment (the list is not exhaustive):
- (a) the period for which the entity has the right to explore in the specific area has expired during the period or will expire in the near future, and is not expected to be renewed.
 - (b) substantive expenditure on further exploration for and evaluation of mineral resources in the specific area is neither budgeted nor planned.

- (c) exploration for and evaluation of mineral resources in the specific area have not led to the discovery of commercially viable quantities of mineral resources and the entity has decided to discontinue such activities in the specific area.
- (d) sufficient data exist to indicate that, although a development in the specific area is likely to proceed, the carrying amount of the exploration and evaluation asset is unlikely to be recovered in full from successful development or by sale.

In any such case, or similar cases, the entity shall perform an impairment test in accordance with Ind AS 36. Any impairment loss is recognised as an expense in accordance with Ind AS 36.

Specifying the level at which exploration and evaluation assets are assessed for impairment

- 21 **An entity shall determine an accounting policy for allocating exploration and evaluation assets to cash-generating units or groups of cash-generating units for the purpose of assessing such assets for impairment. Each cash-generating unit or group of units to which an exploration and evaluation asset is allocated shall not be larger than an operating segment determined in accordance with Ind AS 108 *Operating Segments*.**
- 22 The level identified by the entity for the purposes of testing exploration and evaluation assets for impairment may comprise one or more cash-generating units.

Disclosure

- 23 **An entity shall disclose information that identifies and explains the amounts recognised in its financial statements arising from the exploration for and evaluation of mineral resources.**
- 24 To comply with paragraph 23, an entity shall disclose:
 - (a) its accounting policies for exploration and evaluation expenditures including the recognition of exploration and evaluation assets.
 - (b) the amounts of assets, liabilities, income and expense and operating and investing cash flows arising from the exploration for and evaluation of mineral resources.
- 25 **An entity shall treat exploration and evaluation assets as a separate class of assets and make the disclosures required by either Ind AS 16 or Ind AS 38 consistent with how the assets are classified.**

Appendix A

Defined Terms

This Appendix is an integral part of the Indian Accounting Standard.

exploration and evaluation assets	Exploration and evaluation expenditures recognised as assets in accordance with the entity's accounting policy.
exploration evaluation expenditures	Expenditures incurred by an entity in connection with the exploration for and evaluation of mineral resources before the technical feasibility and commercial viability of extracting a mineral resource are demonstrable.
exploration for and evaluation of mineral resources	The search for mineral resources, including minerals, oil, natural gas and similar non-regenerative resources after the entity has obtained legal rights to explore in a specific area, as well as the determination of the technical feasibility and commercial viability of extracting the mineral resource.

Appendix 1

Note: This Appendix is not a part of the Indian Accounting Standard. The purpose of this Appendix is only to bring out the differences, if any, between Indian Accounting Standard (Ind AS) 106 and the corresponding International Financial Reporting Standard (IFRS) 6, Exploration for and Evaluation of Mineral Resources.

Comparison with IFRS 6, *Exploration for and Evaluation of Mineral Resources*

1. The transitional provisions given in IFRS 6 have not been given in Ind AS 106, since all transitional provisions related to Ind ASs, wherever considered appropriate have been included in Ind AS 101, *First-time Adoption of Indian Accounting Standards* corresponding to IFRS 1, *First-time Adoption of International Financial Reporting Standards*.

[F. No. 17/228/2010-CL. V]

RENUKA KUMAR, Jt. Secy.

Note : The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide number G.S.R. 739(E), dated the 7th December, 2006 and subsequently amended by :—

- (1) G.S.R. 212(E), dated 27th March, 2008
- (2) G.S.R. 225(E), dated 31st March, 2009